

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

मुद्रा तथा बैंकिंग

(MONEY AND BANKING)

[अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय तथा राजस्व सहित]

लेखक

आर० सी० गुप्ता । ए० के० सिंह

व्यावहारिक अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग,

राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

प्रकाशक .
बी. एम. माहेश्वरी
रमेश बुक डिपो,
नयपुर

सर्वाधिकार सुरक्षित

: तेरह रुपये पचास पैसे

मुद्रक .
भूलेत्ताल प्रिन्टर्स,
नयपुर

विषय-सूची

अध्याय

पृष्ठ संख्या

भाग १

मुद्रा

1. मुद्रा का विकास	1
2. मुद्रा की परिभाषा, कार्य तथा महत्व	7
3. मुद्रा का वर्गीकरण	20
4. मौद्रिक मान	35
5. अंशम का नियम	44
6. स्वर्ण मान	56
7. पत्र मान	73
8. मुद्रा का मूल्य (I)—निर्देशांक	84
9. मुद्रा का मूल्य (II)—मुद्रा के सिद्धान्त	102
10. मुद्रा का मूल्य (III)—मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन स्फीति, अल्पस्फीति, विस्फीति आदि	119

भाग २

साख तथा अधिकोपण

11. साख तथा साख-पत्र	143
12. बैंक विकास, परिभाषा तथा कार्य	162
13. बैंको द्वारा साख-सृजन	177
14. आधुनिक बैंको के विभिन्न रूप	189
15. बैंको की कार्य-प्रणाली	201
16. बैंक की विनियोग नीति	209
17. बैंकर और ग्राहक	215
18. केन्द्रीय बैंकिंग (I)—केन्द्रीय बैंकिंग	225
19. केन्द्रीय बैंकिंग (II)—केन्द्रीय बैंक के कार्य	248

भाग ३

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विदेशी विनिमय

20. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार	283
21. विदेशी विनिमय	302
22. भुगतान सतुलन	326
23. विनिमय नियन्त्रण	337

भाग ४

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थायें

24. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	357
25. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक	383
26. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक	400
27. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम	406

भाग ५

भारतीय मुद्रा का इतिहास

28. भारतीय चलन का इतिहास (1)	415
29. भारतीय चलन का इतिहास (2)	429
30. वर्तमान मुद्रा प्रणाली	435
31. रुपये का भवमूल्यन	440

भाग ६

भारतीय बैंक व्यवस्था

32. भारतीय मुद्रा बाजार	455
33. रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया	477
34. स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया	506
35. कृषि वित्त	521
36. सहकारी तथा भूमि-बन्धक बैंक	531
37. औद्योगिक वित्त	550
38. व्यापारिक बैंक	569
39. बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण	579
40. बैंकिंग आयोग	590

भाग १

Part One

"No complaint, however, is more common than that of a scarcity of money. Money, like wine, must always be scarce with those who have neither wherewithal to buy it, nor credit to borrow it"

Adam Smith

मुद्रा
(Money)

मुद्रा का विकास (Evolution of Money)

"The longer history of money has shown an almost unbroken evolution from common place, concrete and simple forms to the representative, incorporeal and abstract"

F.D Graham
C. R. Whittlesey

वस्तु विनिमय का युग :

मुद्रा का विकास मानव समाज के विकास से सम्बद्ध है। मनुष्य जब आत्मनिर्भर अवस्था में था तो उसे मुद्रा की आवश्यकता नहीं थी। अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएँ वह स्वयं उत्पादित करता था एवं उनके उपभोग से सतुष्टि प्राप्त करता था। जनसंख्या बढ़ने तथा सामाजिक संरचना में परिवर्तन होने के कारण मनुष्य की आवश्यकताओं में भी वृद्धि हुई। उत्पादन के क्षेत्र में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण का सूत्रपात हुआ तथा मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं के लेन-देन की आवश्यकता अनुभव हुई। वस्तु विनिमय का युग शुरू हुआ।

वस्तु विनिमय के अन्तर्गत अपेक्षाकृत निरर्थक वस्तु के बदले अपेक्षाकृत आवश्यक वस्तु प्राप्त की जाती है। जेवन्त ने तो सम्पूर्ण विनिमय क्रिया को इसी रूप में परिभाषित किया है, उनके अनुसार— "Exchange is the barter of the comparatively superfluous with the comparatively necessary." वस्तु विनिमय युग में मनुष्य वस्तु विशेष का उत्पादन करता था और उसी के द्वारा अपनी आवश्यकता की अन्य वस्तुएँ प्राप्त करता था। उस समय लेन-देन बड़े-छोट पैमाने पर किया जाता था क्योंकि मनुष्य यथासम्भव आत्मनिर्भर रहने का प्रयत्न करता था। वस्तु विनिमय के लिए कुछ ही वस्तुएँ उपलब्ध होती थीं और वह भी थोड़ी मात्रा में।

वस्तु विनिमय क्रिया के प्रारम्भ होने से लोगों की अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर मिलने लगा। उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई क्योंकि अब उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में विशेष रूप से कुशल व्यक्तियों द्वारा ही उत्पादन होने लगा। व्यक्ति को अपनी रुचि एवं कुशलता के अनुसार कार्य करने एवं दक्षता दिखाने का अवसर मिला। साथ ही उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए

परस्पर निर्भरता बढी और सहयोग एव एकता का युग प्रारम्भ हुआ । अब दूसरो के सहयोग के बिना आवश्यकताओ को पूरा करना कठिन होने लगा ।

इस प्रकार विशिष्टीकरण ने वस्तु विनिमय को जन्म दिया और वस्तु विनिमय ने विशिष्टीकरण के क्षेत्र को विस्तृत एव विकसित किया । परन्तु जहाँ एक तरफ विशिष्टीकरण ने वस्तु विनिमय को जन्म दिया वहाँ दूसरी तरफ उसके विकास ने वस्तु विनिमय में कठिनाइयाँ भी उत्पन्न की । वस्तु विनिमय की अनेक कठिनाइयो में निम्नलिखित उल्लेखनीय है :—

1 पारस्परिक मागों की अनुरूपता सम्बन्धी कठिनाई (Lack of double Coincidence of wants) — वस्तु विनिमय उसी समय सम्भव हो सकता है जब दो पक्ष परस्पर एक दूसरे की वस्तु को इच्छित परिमाण में लेने-देने के लिए तैयार हों । दूसरे शब्दों में वस्तु विनिमय के लिए दो पक्षों की मागों में अनुरूपता होना आवश्यक है । परन्तु इस प्रकार की अनुरूपता व्यवहार में पाना कठिन है । छोटे एव पिछड़े समाज में मांगों की ऐसी अनुरूपता सहज रूप में प्राप्त हो सकती है परन्तु बड़े एव जटिल समाज में ऐसी अनुरूपता प्राप्त करना कठिन हो जाता है ।

2 मूल्यांकन सम्बन्धी कठिनाई (Lack of a Common measure of Value)—वस्तु विनिमय की दूसरी महत्वपूर्ण कठिनाई विनिमय की जाने वाली वस्तुओं के मूल्यांकन की है । दो पक्षों द्वारा आदान-प्रदान की जाने वाली वस्तुओं का मूल्यांकन करने का सर्वमान्य साधन नहीं होता । प्रत्येक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु कितनी मात्रा में दी जायगी यह देन-देन करने वाले पक्षों की एक-दूसरे की वस्तु सम्बन्धी आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करता है । प्रत्येक वस्तु का अलग-अलग वस्तुओं और व्यक्तियों के सन्दर्भ में अलग-अलग मूल्य होता है । इस प्रकार सर्वमान्य मूल्य मापक के अभाव में होने वाली कठिनाइयों का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है ।

3 विभाजन सम्बन्धी कठिनाई (Lack of a means of Sub-division)—वस्तु विनिमय की तीसरी कठिनाई असमान मूल्य या महत्व की वस्तुओं के लेन-देन के सम्बन्ध में उपस्थित होती है । अनेक वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनके टुकड़े नहीं किये जा सकते या टुकड़े करने पर उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है । उदाहरण के लिए घड़ी या पशुओं के बदले छोटी या कम महत्व की वस्तु प्राप्त करना हो तो वस्तु विनिमय असम्भव हो जायगा ।

4. सामान्य ऋय शक्ति के संचय की कठिनाई (Lack of a Store of Value)—वस्तु विनिमय की अवस्था में मूल्य संचय का सामान्य साधन नहीं होता । वस्तुओं के रूप में ही ऋय शक्ति का भी संचय किया जा सकता है । परन्तु वस्तुओं के रूप में ऋय शक्ति संचित करने का दोष यह है कि वस्तुओं के मूल्य में उतार-चढ़ाव

हूँ करता है। इसके लिए संचित करने की कठिनाई भी होती है। वस्तुओं के खराब होने का भी भय रहता है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता के समय शीघ्रता से उसके बदले आवश्यक वस्तु प्राप्त करना भी कठिन होता है।

5 भावी भुगतान के आधार की कठिनाई (Lack of a Standard for deferred payments)—भावी भुगतान सम्बन्धी प्रसविदा विनिमय—प्रधान अर्थ-व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। मजदूरी, ब्याज और किराए इत्यादि सम्बन्धी प्रसविदाएँ इसी प्रकार की श्रेणी में आती हैं। वस्तु विनिमय के युग में जिस किसी वस्तु को ऐसी प्रसविदाओं का आधार बनाया जाता था, भविष्य में उसकी पूर्ति परिवर्तित हो जाने के कारण उसके मूल्य और गुण सम्बन्धी विवाद पैदा हो जाना साधारण बात थी।

आधुनिक युग में वस्तु विनिमय का स्थान (Place of barter in the Present age)

उपरोक्त कठिनाइयों के कारण वस्तु विनिमय प्रणाली आधुनिक अर्थ-व्यवस्था के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। अनन्त आवश्यकताओं वाले जटिल औद्योगिक समाज में जिन असंख्य आर्थिक निर्णयों की आवश्यकता पड़ती है उनको मूल्य के आधार पर ही किया जाता है। इतने बड़े पैमाने पर निर्णय करना अथवा लेन-देन करना बिना किसी सर्वमान्य मूल्यांकन प्रणाली के असंभव है। आधुनिक अर्थ-व्यवस्था का रूप समाजवादी हो अथवा पूँजीवादी, सभी आर्थिक निर्णय मौद्रिक आधार पर किए जाते हैं। मुद्रा के अभाव में आधुनिक उत्पादन प्रणाली एवं व्यापार, तथा श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण इतना विस्तृत एवं जटिल नहीं हो पाता। भावी भुगतान के साधन के अभाव में उधार लेन-देन जो आधुनिक व्यापार की धुरी है, का अन्त हो जाता, व्यवसाय की सार्थकता एवं सफलता अथवा हानि लाभ का अनुमान मुद्रा के अभाव में कठिन होता और पूँजी निर्माण की कल्पना केवल कल्पना रह जाती क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य सचय अत्यन्त कठिन है। स्पष्टतः आधुनिक अर्थ-व्यवस्था में वस्तु विनिमय कोई महत्त्व नहीं रखता। अर्थ व्यवस्था के पिछड़े हुए क्षेत्रों में अभी भी इसका सीमित प्रचलन है परन्तु वह भी वस्तु विनिमय का प्रारम्भिक एवं मौलिक रूप नहीं है वरन् उसका सुधरा हुआ रूप है क्योंकि मूल्यांकन के रूप में मुद्रा की सहायता वहाँ भी ली जाती है। इस प्रकार के सौदे की समस्या आधुनिक युग में नगण्य सी है। वस्तुतः आज की प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था मौद्रिक अर्थ-व्यवस्था है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होने वाले द्विपक्षीय व्यापारिक समझौतों को भी कुछ लोग वस्तु विनिमय का रूप मानते हैं परन्तु यह भ्रम मान है क्योंकि ऐसी समझौतों में भी मूल्यांकन का आधार मुद्रा ही होती है।

पत्र मुद्रा के प्रयोग को भी सीमित कर दिया है और स्वयं मुद्रा का स्थान ग्रहण करते जा रहे हैं ।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संकेत

(1) वस्तु विनिमय में अनुभव की जाने वाली असुविधाओं की व्याख्या कीजिए तथा प्रदर्शित कीजिए कि मुद्रा चलन द्वारा ये कैसे दूर होती हैं ?

(राजस्थान, टी० डी० सी० फाइनल 1966)

[संकेत—प्रथम भाग में वस्तु विनिमय की असुविधाओं जैसे पारस्परिक भागों की अनुरूपता सम्बन्धी कठिनाई, मूल्यांकन सम्बन्धी कठिनाई इत्यादि का वर्णन कीजिए । दूसरे भाग में यह बताइये कि मुद्रा के चलन से वे कठिनाइयाँ किस प्रकार दूर हुई हैं ।]

(2) मुद्रा के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ।

[संकेत—मुद्रा के विकास के क्रमिक इतिहास पर प्रकाश डालिए ।]

मुद्रा की परिभाषा, कार्य तथा महत्व (Definition, Functions and Importance of Money)

"We must neither underestimate nor overestimate the influence of money and monetary policy on the functioning of an economic system."

Lester V. Chandler

मुद्रा क्या है ? (What is Money) :

मौद्रिक समस्याओं और मौद्रिक व्यवस्था की सम्यक् व्याख्या करने के लिए "मुद्रा क्या है" यह जानना आवश्यक है। मुद्रा की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से दी है। कुछ लोग मुद्रा के कार्यों को अपनी परिभाषा का आधार मानते हैं और उन पर विशेष जोर देते हैं, कुछ लोग मुद्रा की सामान्य स्वीकृति की विशेषता को परिभाषा में प्रमुख स्थान देते हैं एवं कुछ लोग मुद्रा के वैधानिक या सरकारी पक्ष पर अधिक जोर देते हैं। यहाँ हम मुद्रा की उचित परिभाषा प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे।

यह सर्वविदित है कि मुद्रा का प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है तथा सामान्यतया इसी में मूल्यों का निर्धारण भी किया जाता है। अतएव कोई वस्तु मुद्रा है या नहीं इसका निर्णय प्रो. एल. व्ही. चैंडलर के अनुसार निम्न-लिखित कसौटियों पर किया जाना चाहिए—

1. क्या वह वस्तु सामान्यतया भुगतान के साधन के रूप में प्रयोग की जाती है ?

2. क्या वह वस्तु सेवाओं और वस्तुओं के बदले सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है ? कोई भी वस्तु जो इन शर्तों को पूरा करती है उसे मुद्रा कहा जायगा।

भुगतान के साधन के रूप में सर्वस्वीकार्यता का गुण वैधानिकता और प्रयोग में सुविधा एवं आदत के कारण उत्पन्न हो सकता है। परन्तु वास्तव में विनिमय या भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतया सभी लोग सहर्ष उसी वस्तु को स्वीकार करेंगे जिसमें लोगों का विश्वास हो। यदि किसी वस्तु में लोगों का विश्वास नहीं है तो सरकार द्वारा कानूनी मुद्रा घोषित किए जाने पर भी उसमें सामान्य स्वीकृति के

गुण का अभाव होगा और वह वस्तु मुद्रा के रूप में चलन में नहीं रह सकती । जर्मनी में प्रथम महायुद्ध के बाद जब अत्यधिक मुद्रा प्रसार हुआ तो वहाँ के लोगो ने वहाँ की वैधानिक मुद्रा मार्क को विनिमय एव भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार करना बन्द कर दिया । इसलिए स्पष्ट है कि मुद्रा के लिए सरकारी घोषणा या कानूनी रूप प्रदान करना केवल सर्वस्वीकार्यता को सहज बना सकता है, सर्वस्वीकार्यता को जन्म नहीं देता । सर्वस्वीकार्यता तो विश्वास से ही आ सकती है । अतः मुद्रा ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो बिना किसी सकोच के विनिमय एव भुगतान में सहर्ष स्वीकार की जाय । जो लोग मुद्रा के राज्य सिद्धांत के पोषक हैं उनमें नैप (Knapp) का नाम प्रमुख है इनके अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाय वह मुद्रा है । परन्तु केवल राज्य की घोषणा सामान्य स्वीकृति पैदा नहीं कर सकती यह बात जर्मनी के उदाहरण से स्पष्ट है ।

मुद्रा का प्रयोग मूल्य मापक के रूप में भी किया जाता है । व्यवहार में एक ही वस्तु का मूल्य मापक और विनिमय का माध्यम होना आवश्यक नहीं है । यदि मूल्य मापक कोई अन्य वस्तु हो तो भी विनिमय किया जा सकता है लेकिन ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि मूल्य मापक वस्तु और विनिमय के माध्यम में एक निश्चित सम्बन्ध हो । उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु का मूल्य माप डालर में किया जाय तो भारत में उसका विनिमय हो सकता है क्योंकि डालर और रुपए का सम्बन्ध ज्ञात है । यह अवश्य है कि यदि मूल्य मापक और विनिमय का माध्यम एक ही वस्तु है तो अधिक सुविधा होगी । अतः स्पष्ट है कि मुद्रा होने के लिए किसी वस्तु का मूल्य मापक भी होना आवश्यक नहीं है । श्री वेनहम ने अपनी पुस्तक “अर्थशास्त्र” (Economics) में इस बात का समर्थन करते हुए लिखा है कि यद्यपि विनिमय के माध्यम और लेखा की इकाई में साधारणतया अन्तर नहीं होता फिर भी यदि दोनों के अनुपात को बनाये रखा जाय तो विनिमय का माध्यम और मूल्य मापक अलग-अलग वस्तुएँ हो सकती हैं ।

उपरोक्त विवरण के आधार पर यह स्पष्ट है कि मुद्रा की प्रकृति के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं ।

1. वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम भुगतान करने की क्षमता होना ।
2. हस्तान्तरण की योग्यता होना ।
3. मूल्यों और ऋणों को व्यक्त करने का साधन होना ।

मुद्रा को उपरोक्त ढंग से परिभाषित करने वाले कुछ अर्थशास्त्रियों को उद्धृत कराना असंगत नहीं होगा :—

1. “Money can be defined as a claim which is generally acceptable in settlement of debts”.
—A. C L. Day.

2 Money.... is that by delivery of which debt contracts and price contracts are discharged and in the shape of which a store of general purchasing power is held." —Keynes

3. "Money.. is any thing which is widely acceptable in discharge of obligations " —Robertson

4 "Money includes all those things which are (at any given time or place) generally current without doubt or special enquiry as a means of purchasing commodities or services and of defraying expenses " —Marshall

5. "Money consists of those things which, within a Society, are of general acceptability " —Ely

6 ' Money is some thing that is widely accepted for the settlement of debts." —Sayers

7. "Money is some thing that is readily and generally accepted by the public in payment for the sale of goods, services and other valuable assets and for the payment of debts " —R. G Thomas

उपरोक्त परिभाषाओं में शब्दों और कुछ हद तक विचारों में भी भिन्नता पाई जाती है। परन्तु सभी परिभाषाएँ मुद्रा में सर्वस्वीकार्यता का गुण होना आवश्यक मानती हैं।

परिभाषाओं का एक अन्य समूह भी है जिसमें मुद्रा के कार्यों पर अधिक जोर दिया गया है।¹ इसमें कोई सन्देह नहीं कि मुद्रा की सभी परिभाषाएँ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मुद्रा के कार्यों को ध्यान में रखकर ही लिखी गई हैं परन्तु परिभाषा को वैज्ञानिक और पूर्ण बनाने के लिए उसके कार्यों का उल्लेख करना ही पर्याप्त नहीं होता। परिभाषा सभी पूर्ण और वैज्ञानिक कही जा सकती है जब मुद्रा की प्रमुख विशेषताओं और गुणों का बोध परिभाषा पढ़ने मात्र से हो सके। इसलिए ट्रेस्काट कोलवोर्न और नोगारो आदि की परिभाषाएँ पूर्ण और वैज्ञानिक नहीं कही जा सकती।² वास्तव में ये परिभाषाएँ केवल मुद्रा के कार्यों का उल्लेख करती हैं।

¹ "Money is one of those concepts which are definable primarily by the use or purpose which they serve".

—R G Hawtrey.

² 1. "Whatever serves as money is money..." —Trescott

2. "Money may be defined as the means of valuation and of payment " —Coulborn

3. Money is a commodity which serves as an intermediary in exchanges and as a common measure of value —Nogaro

4 The word money has been used to designate the medium of exchange as well as the standard of value " —Halm

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि कुछ परिभाषाएँ सङ्कुचित हैं, कुछ परिभाषाएँ विस्तृत हैं और कुछ मध्यमार्गी हैं और उचित हैं। कुछ लोग मुद्रा की वैधानिकता को अनिवार्य बतलाते हैं परन्तु वास्तव में वैधानिकता केवल सर्वस्वीकार्यता को सहज बना देती है इसलिए अनिवार्यता सर्वस्वीकार्यता की ही है, हालाँकि व्यवहार में सामान्यतया सरकार द्वारा घोषित वस्तु ही मुद्रा के रूप में सर्वस्वीकार्य होती है। अतः कोई भी वस्तु जिसमें सर्वस्वीकार्यता का गुण और अन्तिम भुगतान की शक्ति है वह मुद्रा है।

क्या विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र और चेक मुद्रा हैं ?

(Are bills of exchange, Promisory notes and Cheques money ?)

प्रायः सभी देशों में सरकार द्वारा घोषित मुद्रा (सिक्के तथा नोट) के अतिरिक्त विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र और चेको आदि का प्रयोग विनिमय के साधन के रूप में किया जाता है। प्रश्न यह है कि क्या इन सबको मुद्रा की मञ्जा दी जा सकती है ? कोई भी वस्तु मुद्रा तभी कही जा सकती है जब उसमें (1) सामान्य स्वीकृति तथा (2) अन्तिम भुगतान की शक्ति दोनों ही हों।

बिल और प्रतिज्ञा पत्र उपरोक्त कसौटी पर धरे नहीं उतरते क्योंकि सभी लोग इन्हें स्वीकार नहीं करते और जिन देशों में या स्थानों पर इन्हें लोग स्वीकार भी करते हैं वहाँ भी ये केवल सामयिक भुगतान ही करते हैं अन्तिम भुगतान किसी अन्य वस्तु या मुद्रा द्वारा ही किया जाता है।

चेक की स्थिति बिल और प्रतिज्ञा पत्र से कुछ भिन्न है। अल्पविक विकसित देशों में चेक को सामान्य स्वीकृति प्राप्त है और यह अन्तिम भुगतान करने में भी समर्थ है क्योंकि चेक बैंक जमा का प्रमाण है। चेक द्वारा बैंक जमा का हस्तान्तरण किया जाता है। यदि किसी चेक के पीछे बैंक जमा न हो तो उसे सर्वस्वीकार्यता नहीं प्राप्त हो सकती इसलिए चेक उसी हद तक मुद्रा का रूप ग्रहण कर सकता है जिस हद तक वह बैंक जमा का समानार्थी है। वास्तव में बैंक जमा ही मुद्रा का रूप लेती है। चेक केवल बैंक जमा के हस्तान्तरण का आदेश मात्र है। जो देश अभी आर्थिक दृष्टि से विकसित नहीं हैं वहाँ चेको का प्रयोग केवल सीमित क्षेत्र में ही होता है अतः ऐसे देशों के सदस्य में चेक या बैंक जमा को मुद्रा की मञ्जा देना उचित नहीं है क्योंकि इसमें मुद्रा की प्रमुख विशेषता सामान्य स्वीकृति (General acceptability) का अभाव है। इस विवरण से यह भी स्पष्ट है कि कोई वस्तु मुद्रा है या नहीं यह एक विशेष सदस्य और समय पर निर्भर करता है। एक ही वस्तु सदस्य के लिए और सर्वत्र मुद्रा नहीं कही जा सकती।

मुद्रा के ही समान (Near Money) :

कुछ तरल सम्पत्तियों में सामान्य स्वीकृति का गुण न होने पर भी कई अर्थशास्त्री उन्हें मुद्रा के समान ही मानते हैं। इसका कारण यह है कि तरल सम्पत्ति में मुद्रा की अनेक विशेषताएँ पाई जाती हैं। सरकारी वाण्ड या प्रतिभूतियाँ यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से भुगतान के काम नहीं ली जाती और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की सजा नहीं दी जाती लेकिन इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि इन्हें इच्छानुसार तुरन्त मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है और हमारी खर्च की आदतों पर इनका भी वैसे ही प्रभाव पड़ता है जैसा बैंक जमा का। उसी प्रकार समय जमा (Time Deposit) तथा बचत खाता भी लगभग वही प्रभाव रखते हैं जैसा मुद्रा या मांग जमा (Demand Deposit) रखती है। इसलिए अर्थशास्त्री इन्हें “लगभग मुद्रा” (Near money) की सजा देते हैं।

मुद्रा के कार्य (Functions of Money)

सामाजिक अर्थ व्यवस्था मंदव से ही मौद्रिक अर्थ व्यवस्था रही है और सम्भवतः सदैव ही रहेगी। परिवर्तनशील जगत में मुद्रा की निरंतरता इस बात को सहज ही स्पष्ट कर देती है कि सामाजिक अर्थ व्यवस्था में उसके कार्य कितने महत्वपूर्ण हैं। अर्थ विभाजन और विशिष्टीकरण तथा विनिमय पर आधारित अर्थ व्यवस्था मुद्रा के बिना कार्य नहीं कर सकती। जैसे जैसे किसी समाज का आर्थिक, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास होता है वैसे-वैसे मुद्रा के कार्य भी बढ़ते जाते हैं। लेस्टर व्ही चैण्डलर का कथन है कि वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय को सुविधाजनक बनाना ही मुद्रा का मौलिक कार्य है। मुद्रा जो अन्य कार्य करती है वे सब इसी पर आधारित हैं। इस श्रेणी के सभी कार्य मुद्रा के निष्क्रिय या टेक्निकल कार्य कहे जाते हैं। परन्तु अर्थ व्यवस्था की बढ़ती हुई जटिलता ने मुद्रा के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को प्रकाश में लाया है जिन्हें सक्रिय या प्रवेगिक (Dynamic) कार्य कहा गया है। हम मुद्रा के कार्यों की व्याख्या निम्नलिखित वर्गों में करेंगे —

1 निष्क्रिय या स्थितिक कार्य (Passive or Static functions)

2. मुद्रा और कीमत निर्धारण क्रिया (Money and the Price Mechanism)

3 सक्रिय या प्रवेगिक कार्य (Active or Dynamic functions)

1 निष्क्रिय या स्थितिक कार्य :

अ. प्रधान कार्य (Primary Functions)

ब. गौण कार्य (Secondary Functions)

अ प्रधान कार्य— 1-विनिमय का माध्यम (Medium of Exchange)

2-मूल्य का माप (Measure of Value)

ब. गौण कार्य — 1-मूल्य-सचय का साधन (Store of Value)

11-भावी भुगतान का आधार (Standard of deferred payments)

विनिमय का माध्यम (Medium of Exchange) :

मुद्रा अपने विकास की प्रारम्भिक अवस्था में इसी कार्य के लिए प्रयुक्त हुई थी। मुद्रा को सामान्य शक्ति (Generalised purchasing power) कहा जाता है। इसके बदले में कोई भी वस्तु या सेवा प्राप्त की जा सकती है क्योंकि इसमें सर्वस्वीकार्यता का गुण विद्यमान है। केवल क्रय-विक्रय के माध्यम के रूप में ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के भुगतानों के (कर, दान, दण्ड आदि) माध्यम के रूप में भी इसे ही प्रयोग किया जाता है। मुद्रा के इस कार्य में, वस्तु विनिमय में जिस शक्ति और समय का अपव्यय होता था उससे हमें बचा लिया है। आज किसी भी व्यक्ति के सामने किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को तलाश करने की आवश्यकता नहीं है जिसके पास उसकी इच्छित वस्तु है और वह उसके बदले में प्रथम व्यक्ति की वस्तु लेने को तैयार है। अब किसी भी वस्तु के बदले में मुद्रा प्राप्त की जा सकती है और फिर मुद्रा से अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए मुद्रा को “इच्छा वाहक” (Bearer of option) कहा गया है। इससे इस बात का महत्व स्पष्ट हो जाता है कि मुद्रा के प्रयोग ने चुनाव (Choice) की कितनी स्वतन्त्रता प्रदान की है। मुद्रा के इस कार्य ने विनिमय के क्षेत्र को इतना व्यापक बनाया है और उत्पादन तथा श्रम विभाजन की जटिलताओं को आसान बनाकर आर्थिक विनाश को गतिमान बनाया है। इस कार्य ने कीमत निर्धारण की प्रणाली को (Price mechanism) पूर्णता प्रदान की है तथा श्रमिक की उत्पादकता को बढ़ाया है।

मूल्य का माप (Measure of Value) :

मुद्रा के प्रधान कार्यों में मूल्य-माप का कार्य भी है। यद्यपि मूल्य माप एक विषयगत चीज है और उसे परिमाण (Quantity) में व्यक्त नहीं कर सकते¹, अनेक वस्तुओं का तुलनात्मक मूल्य मुद्रा के माध्यम से ही ज्ञात किया जाता है। कोलवोर्न के अनुसार मूल्य-माप का कार्य सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में सर्वप्रधान है। विनिमय की प्रथम आवश्यकता वस्तु या सेवा का मूल्य माप करना ही है। मूल्य की अन्निर्व्याक्त के बिना विनिमय क्रिया सीमित माना में ही सम्भव हो सकती है। मूल्य माप की क्रिया ने लेखा कार्य (Accounting) को भी आसान कर दिया है क्योंकि

1 “The most that any one can say of the value of things is that he assesses the value of one thing more highly than that of another, but he cannot say that the value of any thing is any measurable quantity.”
—J. L. Hanson

इसी के आधार पर लाभ या हानि का अनुमान लगाया जा सकता है। जिस प्रकार जीवन के अन्य क्षेत्रों में मापदण्डों का प्रयोग करना आवश्यक होता है उसी प्रकार वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य (Price) जानने के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। वस्तु विनिमय काल में सर्वमान्य मूल्य का माप न होने के कारण यह जानना कठिन था कि अमुक वस्तु के बदले में अमुक वस्तु कितनी मात्रा में दी जाय और इस कारण विनिमय में एक पक्ष प्रायः अनुचित परिमाण में हानि उठाता था। मूल्य माप मुद्रा में सम्भव होने के कारण विनिमय सतोपप्रद ढंग से होता है। परन्तु इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि मापदण्डों (मीटर, किलो आदि) की भाँति मुद्रा सदैव एक निश्चित माप दण्ड नहीं है क्योंकि मुद्रा का मूल्य स्वयं परिवर्तित होता रहता है। अतः सन्तोषजनक मूल्य मापक होने के लिए स्वयं मुद्रा के मूल्य में अपेक्षाकृत अधिक स्थायित्व होना चाहिए।

मूल्य-संचय का साधन (Store of Value) .

यह मुद्रा का गौण कार्य है क्योंकि यह मुद्रा के प्रधान कार्यों से उत्पन्न हुआ है इसीलिए इसे उत्पन्न (Derived) कार्य भी कहते हैं। जब मुद्रा को विनिमय माध्यम और मूल्य-मापक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो स्वतः ही लोग उसे मूल्य-संचय के साधन के रूप में ग्रहण लेते हैं क्योंकि मुद्रा रखने वाले के पास वास्तव में सामान्य क्रय शक्ति (Generalised purchasing power) संचित होती है जिसका प्रयोग किसी भी समय वस्तु के लिए किया जा सकता है। उसे ज्ञात है कि मुद्रा हर समय वस्तुओं और सेवाओं के बदले जनता द्वारा सहर्ष स्वीकार की जायगी। मुद्रा मूल्य संचय के अच्छे साधन के रूप में इसलिए प्रयोग की जाती है क्योंकि संचयकर्ता का यह विश्वास रहता है कि भविष्य में भी मुद्रा की न्यून शक्ति वर्तमान क्रय शक्ति के समान ही रहेगी। व्यवहार में मुद्रा इस कार्य में पूर्ण रूप से सफल नहीं रही है क्योंकि मुद्रा के मूल्य में पूर्ण स्थायित्व का अभाव रहा है। यह भी याद रखना आवश्यक है कि मुद्रा एक समय में ही विनिमय-माध्यम और मूल्य-संचय के साधन के रूप में कार्य नहीं कर सकती। यदि मूल्य-संचय के रूप में उसका प्रयोग किया जा रहा है तो उस समय वह विनिमय का माध्यम नहीं बन सकती।

भावी भुगतानों का आधार (Standard for Deferred Payments) :

विनिमय माध्यम के रूप में सामान्यतया प्रयोग में आते ही, स्वभाविक रूप से मुद्रा, भावी भुगतानों को व्यक्त करने की इकाई का रूप धारण कर लेती है। उधार लेन-देन आधुनिक अर्थ-व्यवस्था का अपरिहार्य अंग है। भविष्य में जब उधार का भुगतान करना होता है तो मुद्रा को ही आधार बनाया जाता है। उधार के अतिरिक्त कई ऐसे प्रसविद्ध होते हैं जिनमें भविष्य में भुगतान की आवश्यकता होती है जैसे लाभांश, सम्पत्ति कर (Lease) धेतन आदि इनका प्रयोग और भुगतान

मुद्रा द्वारा ही होता है। इस प्रकार स्थगित भुगतान-मान के रूप में मुद्रा का प्राधुनिक युग में अत्यन्त महत्त्व है। परन्तु मुद्रा यह कार्य करने में इसीलिए समर्थ है क्योंकि (i) मुद्रा के मूल्य में अपेक्षाकृत स्थायित्व होता है, (ii) मुद्रा क्षयशील नहीं होती और (iii) मुद्रा में सामान्य ऋय शक्ति और सर्वस्वीकार्यता का गुण होता है। मुद्रा के इस कार्य ने आधुनिक अर्थतन्त्र में आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहन देकर वास्तविक विनियोग की मात्रा में आशातीत वृद्धि का अवसर प्रदान किया है। लेकिन मुद्रा भावी भुगतान का सन्तोषप्रद मान तभी रह सकती है जब उसकी ऋय शक्ति में स्थिरता रहे। ऋय शक्ति में परिवर्तन होने से लेन-देन की क्रिया में अनिश्चितता तथा जोखिम का समावेश हो जायगा और मुद्रा के इस कार्य का महत्त्व कम हो जायगा।

2. मुद्रा और कीमत निर्धारण क्रिया (Money and Price Mechanism) :

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का एक और महत्त्वपूर्ण कार्य है। अर्थशास्त्र का यह आधार भूत सिद्धान्त है कि वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा मांग की अपेक्षा कम होती है क्योंकि उत्पादन के साधन सीमित होते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था में किसी ऐसे तरीके की आवश्यकता होती है जो विभिन्न साधनों का विभिन्न प्रयोगों में आवंटन (allotment) कर सके। उसी प्रकार उत्पादित वस्तुओं की उपभोक्ताओं में वितरित करने की समस्या का सामना करना पड़ता है। यह दोनों ही कार्य कीमत निर्धारण-क्रिया (Price Mechanism) द्वारा होते हैं तथा कीमत निर्धारण- (Price Mechanism) मुद्रा के बिना सम्भव नहीं है। इस कार्य द्वारा उत्पादन के साधनों का विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इस प्रकार बटवारा हो जाता है कि उपभोक्ताओं को इच्छित वस्तुएं इच्छित मात्रा में मिल सकें। किसी भी वस्तु की मांग या पूर्ति का परिवर्तन स्वतः ही कीमतों में परिलक्षित हो जाता है।

3 मुद्रा का सन्विय या प्रवर्गिक कार्य (Active or Dynamic Functions) :

मुद्रा के उपरोक्त कार्य अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने में केवल सहायक होते हैं उनसे अर्थव्यवस्था स्वयं प्रभावित नहीं होती। इन कार्यों से कीमत की गति या आर्थिक क्रियाओं की मात्रा (Price movements or the volume of economic activity) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होती। एक समय था जब इनके अलावा मुद्रा का अन्य कार्य नहीं समझा जाता था। परन्तु आजकल प्रायः सभी देशों की सरकारों का लक्ष्य पूर्ण वृत्ति (Full employment) प्राप्त करना और उसको बनाए रखना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के साधनों में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित और नियमित करना भी एक महत्त्वपूर्ण साधन है जिससे उत्पादन स्तर को प्रभावित किया जाता है। ऋय शक्ति की मात्रा को बढ़ा कर मांग को

प्रोत्साहित (Stimulate) किया जा सकता है तथा कीमती और आर्थिक क्रियाओं को गिरने से रोका जा सकता है। इसकी विपरीत स्थिति में क्रय शक्ति की मात्रा को घटा कर स्थिति पर नियन्त्रण किया जा सकता है। इस प्रकार मुद्रा अपना सक्रिय कार्य (Dynamic function) कीमत (Price) को प्रभावित करके पूरा करती है। पिछले लगभग पचास वर्षों में मौद्रिक सिद्धान्त (Monetary theory) का स्थान अर्थशास्त्र में बहुत बढ़ गया है जो इस बात का प्रमाण है कि मुद्रा को अब निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय माना जाता है। मुद्रा के इस कार्य द्वारा सभी देश और मुद्रा-संस्थाएँ अपने विकास के कार्यक्रमों को संचालित करती हैं।

प्रो० किनले तथा कुछ अन्य लेखकों ने मुद्रा के समाव्य कार्यों (Contingent Functions) का उल्लेख किया है। इन कार्यों में इन लेखकों ने सीमान्त उपयोगिता में समानता लाना, पूँजी में तरलता लाना श्रम विभाजन में सहायक होना तथा साख का आधार होना आदि को सम्मिलित किया है। परन्तु मुद्रा के महत्व की व्याख्या से पाठक को यह स्पष्ट हो जायगा कि उपरोक्त बातें वास्तव में मुद्रा के महत्व को या उसकी उपयोगिता को स्पष्ट करती हैं। इन्हे मुद्रा की उपयोगिता कहना ही उचित होगा क्योंकि ये कोई पृथक कार्य नहीं हैं।

मुद्रा का महत्व (Importance of Money)

विशिष्टीकरण-प्रधान एवं जटिल अर्थ व्यवस्था में सदैव ही मुद्रा को एक महत्वपूर्ण वस्तु माना गया है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि मुद्रा को सभी अर्थ-शास्त्री प्राथमिक महत्व देते रहे हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल (John Stuart Mill) ने कहा है कि मुद्रा केवल समय और श्रम को बचत मात्र करती है। यह किसी समाज की अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वहीन वस्तु है।¹ इनके अलावा कुछ अन्य अर्थ-शास्त्रियों की भी यही धारणा है कि मुद्रा आधुनिक अर्थतन्त्र के लिए अनिवार्य नहीं है तथा किसी अर्थव्यवस्था में अधिकतम उत्पादन के लिए मुद्रा ही पर्याप्त नहीं है। अधिकतम उत्पादन तो उत्पादन के वास्तविक साधनों के अनुकूल एवं उचित संयोग (Combination) पर निर्भर करता है। आधुनिक अर्थशास्त्री प्रो० डी० रावर्टसन ने भी इसी विचारधारा का समर्थन किया है। इनके अनुसार मुद्रा को जितना महत्वपूर्ण समझा जा रहा है वह वास्तव में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है।² प्राचीन

¹. "There cannot..... be intrinsically a more insignificant thing, in the economy of a society, than money, except in the character of a contrivance for sparing time and labour." —J S Mill

² "Money is not such a vital subject as is often supposed .."

काल में जब आत्मनिर्भरता का युग था, जनसंख्या कम थी, और लेन-देन सीमित क्षेत्र में होता था तब मुद्रा का महत्व वास्तव में इतना अधिक नहीं था परन्तु आधुनिक जटिल अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में उपरोक्त दृष्टिकोण तर्क संगत नहीं जान पड़ता। फ्राउडर ने अर्थव्यवस्था में मुद्रा को वही स्थान दिया है जो राजनीति में मत (Vote) का है। मार्शल के अनुसार "मुद्रा वह केन्द्र बिंदु है जिसके चारों ओर अर्थतन्त्र घूमता है।"³ इस प्रकार आधुनिक युग को मुद्रा युग कहा गया है। और इस युग में मुद्रा ही 'राजा' है। एक लेखक के अनुसार 'जिसके पास 6 पेन्स है वह 6 पेन्स की सीमा तक सब मनुष्यों का सार्वभौम राजा है 6 पेन्स की सीमा तक रसोइयो को अपना पेट भरने के लिए, दार्शनिकों को पढ़ाने के लिए, राजाओं को अपनी रक्षा के लिए, अपने अधिकार में रखता है।'⁴ अब हम मानव जीवन में मुद्रा के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे।

पूजीवादी अर्थ व्यवस्था में महत्व

(Importance of Money in Capitalist Economy)

1 मुद्रा और आर्थिक जीवन (Money and Economic Life) : आधुनिक युग में मुद्रा और आर्थिक क्रियाएँ अटूट सम्बन्ध रखती हैं। उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण की सभी क्रियाएँ मुद्रा द्वारा ही चालित होती हैं। पूजीवाद का नेता, साहसी (enterprises) लोगो का माना जाता है और इनका उद्देश्य अधिक मुद्रा प्राप्त करना होता है। चेंडलर ने लिखा है "Their motivation is to 'make money', as much as possible" मुद्रा के असीम महत्व का अन्य कारण विशिष्टीकरण तथा विनिमय के क्षेत्र का अत्यधिक विस्तृत होना है। इसके कारण उत्पादन की प्रक्रिया विस्तृत और सहज हुई है। मुद्रा के प्रयोग ने बचत करने का उत्तम साधन उपलब्ध किया है और उचित समय देखकर विनियोग करने का अवसर प्रदान किया है। पूजी निर्माण और पूजी की गतिशीलता का बढ़ाना में मुद्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। उत्पादनकर्ता मुद्रा के आधार पर ही उत्पादन प्रणाली उत्पादन-साधनों का अनुपात उत्पादन-वस्तु और मात्रा आदि के सम्बन्ध में निश्चय करता है।

उपरोक्त के दृष्टिकोण से भी मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। अधिक सतुष्टि की प्राप्ति मुद्रा के प्रयोग द्वारा ही सम्भव हो सकती है। आवश्यकता की तीव्रता

³ "Money is the pivot around which economic science clusters"

— Marshall in Money, Credit and Commerce

⁴ "Who so has six pence is sovereign (to the length of six pence) over all men, commands cooks to feed him, philosophers to teach him, kings to mount guard over him—to the length of six pence"

—Quoted by W J Weston, Economics for Businessman, P. 152

और उपयोगिता की तुलना का मापदण्ड मुद्रा ही है। एक प्रकार से आर्थिक आवश्यकताओं से सम्बन्ध रखने वाली प्रवृत्तियों को मुद्रा द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। मुद्रा उपभोक्ता को अपनी कय शक्ति को उचित प्रकार से प्रयोग करने में सहायता देती है। प्रो० राबर्टसन ने अपनी पुस्तक 'money' में इस सम्बन्ध में लिखा है "The existence of a monetary economy helps society to discover what people want and how much they want it and so to decide what shall be produced and in what quantities, and to make the best use of its limited productive power. And it helps each member of society to ensure that the means of enjoyment to which he has access, yield him the greatest amount of actual enjoyment which is within his reach."

विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का सर्वाधिक महत्व है। विनिमय का क्षेत्र मुद्रा के प्रयोग के पूर्व अत्यन्त ही सीमित था। परन्तु मुद्रा ने विनिमय-क्षेत्र को आधुनिक युग में अन्तर्राष्ट्रीय बना दिया है। मुद्रा ने श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण सम्भव बनाकर बाजार को विस्तृत किया। मुद्रा के बिना उत्पादन और विनिमय बाजार का इतना विस्तार केवल कल्पना रह जाती। लोग आत्मनिर्भर अर्थ-व्यवस्था में रहकर उपभोग के लिए ही उत्पादन करते परन्तु आज विनिमय के लिए उत्पादन करना मुद्रा ने ही सिखाया है। इस क्षेत्र में मुद्रा के महत्व का वर्णन करते हुए Whittlesey, Freedman and Herman ने अपनी पुस्तक—Money and Banking Analysis and policy, में लिखा है "This contributes to economic efficiency and is essential to the development of regional, national and international markets that have fostered and sustained the mass production methods of modern industrialised countries."

उत्पादन कार्य, उत्पादन के साधनों के सहयोग से ही सम्भव है। उत्पादन के साधनों में उत्पादित पदार्थ को वितरित करने का कार्य मुद्रा के आधार पर किया जाता है। मुद्रा के माध्यम से ही ब्याज, मजदूरी, लगान और लाभ का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार मुद्रा उत्पादन के साधनों का उचित भाग दिलाकर उन्हें उत्पादन कार्य में सहयोग करने को प्रोत्साहित करती है¹ और इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन सम्भव हो पाता है।

राज्यवित्त आधुनिक युग में प्रत्येक देश में सामाजिक न्याय का एक प्रबल साधन माना जाता है। कर आदि मुद्रा में ही निर्धारित और वसूल किये जाते हैं तथा उनका प्रयोग अधिकतम कल्याण के सिद्धांत पर मुद्रा के माध्यम से किया जाता है।

¹ "Money is the indispensable pre-requisite to the assembling of the concrete instruments of production." —H G. Moulton

इस प्रकार मुद्रा आर्थिक और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पीगू ने इस महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है 'In modern world industry is closely enfolded in a garment of money' इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा के महत्व का उल्लेख करते हुए ट्रेसकाट ने इसे अर्थतंत्र का रक्तस्रोत कहा है।³

आर्थिक क्षेत्र में विकास का अवसर प्रदान करने के साथ-साथ मुद्रा ने मनुष्य को आर्थिक स्वतन्त्रता भी दी है। आज लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपना व्यवसाय चुन सकते हैं एवं आर्थिक दासता से मुक्त हैं। प्राचीन काल में जब मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था तो अनाज या जिस वस्तु में मजदूरी का भुगतान होता था, उसी का उपयोग करना होता था चाहे इच्छा मले ही कुछ और ही। आज मुद्रा रखने वाला व्यक्ति पूर्ण स्वतन्त्र है।

2 मुद्रा और सामाजिक जीवन : पीगू के अनुसार मुद्रा एक ऐसा बहु-मूल्य सामाजिक हथियार है जिसने आर्थिक कल्याण में बहुत योगदान किया है। मुद्रा के प्रयोग से पारस्परिक सम्बन्धों में घनिष्ठता आई है क्योंकि विनिमय के लिए लोगों को एक-दूसरे के सम्पर्क में आना होता है। इस सम्पर्क के कारण मानव सभ्यता का विकास अधिक हुआ है क्योंकि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के सम्पर्क में आती है और उनके तत्वों (Traits) का सम्मिश्रण होता रहता है। रुडियो को तोड़ने में भी मुद्रा ने सहायता की है। अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना के विकास में भी मुद्रा ने महत्वपूर्ण योग दिया है। आज विकास की होड़ लगी है। हर देश केवल अपना ही नहीं बरन् दूसरों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने में सहयोग कर रहा है। इस सम्बन्ध में धी डेवनपोर्ट का विचार उद्धरणीय है—

"Almost all great political issues and almost all absorbing social problems, and almost all international complications rest upon a pecuniary standard".

3. मुद्रा और राजनैतिक जीवन : मुद्रा ने जनता में राजनैतिक जागरण लाने का कार्य किया है। आज प्रत्येक नागरिक यह जानता है कि उसके द्वारा चुकाये गये कर द्वारा ही शासन चलाया जाता है। अतः वह राजनीति में दिलचस्पी रखता है। मुद्रा के प्रयोग ने कई दशों में राजनैतिक दलों की स्थापना में मदद की और उनको अपनी शक्ति बढ़ाने में सहायता देकर राजनैतिक वातावरण में परिवर्तन लाया है। मुद्रा के प्रयोग ने राष्ट्रीय एकता को हृदय किया है।

4. मुद्रा तथा अन्य क्षेत्र : मुद्रा का महत्व केवल उपरोक्त क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। वास्तव में मानव जीवन के प्रत्येक व्यवहार और विचार पर आज

³ "If money is not the heart of our economic system, it can certainly be considered its blood stream" —Trescott

मुद्रा की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। गायब, नर्तक या कलाकारों की कृतियों का मूल्यांकन मुद्रा में ही किया जाता है। जिसकी कृतियों को अधिक मुद्रा मिलती है वह बड़ा कलाकार कहलाता है। आज किसी भी कार्य का पारितोषिक भी मुद्रा में दिया जाता है और प्रतियोगिता का स्तर पारितोषिक की मात्रा पर निर्भर करता है। इस प्रकार मुद्रा मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को आच्छादित किये हुए है। यही भाव Horace की निम्न पंक्तियों में निहित है—

All things human and divine, renown,
Honour and worth, at money's shine, go down

समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व कहा जाता है कि पेरू के इन्कस (Incas) ने स्पेनवासियों के आने के पहले पूर्ण नियोजित अर्थ व्यवस्था की स्थापना की थी जिसमें उत्पादन और वितरण राज्य द्वारा नियोजित होता था तथा मुद्रा के बिना भी सुचारु रूप में काम चलता था। प्रारम्भ में साम्यवादियों ने मुद्रा को पूँजीवादी शोषण का यन्त्र और चिन्ह बह कर पुकारा और उनकी यह धारणा थी कि इस अनावश्यक वस्तु को समाप्त कर देने से आर्थिक-बन्धुत्व (Economic Brotherhood) तथा राजनैतिक एकता में वृद्धि होगी। परन्तु आधुनिक साम्यवादी सिद्धान्ततः तथा व्यवहारिक दोनों ही रूपों में नियोजित अर्थ-व्यवस्था में, मुद्रा को प्रयोग में लाते हैं क्योंकि नियोजित अर्थ-व्यवस्था भी मुद्रा के प्रयोग से अधिक सरलता से संचालित की जा सकती है। ट्राटस्की ने कहा है “The blueprints produced by the offices, must demonstrate their economic expediency through commercial calculation Without a firm monetary unit commercial accounting can only increase the chaos.” इसी प्रकार रूसी क्रांति के महान नेता लेनिन ने यह स्वीकार किया है कि साम्यवादी सफलता, गणना और नियंत्रण (Calculation and Control) के बिना सम्भव नहीं है। यद्यपि समाजवादी अर्थ-तन्त्र में उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार होता है और उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में उनका बटवारा भी राज्य द्वारा ही किया जाता है। उत्पादन की मात्रा, बिस्म तथा मजदूरी की दरें आदि योजनाबद्ध तरीके से राज्य द्वारा ही निश्चित की जाती हैं। परन्तु पूर्व निश्चित अनुमान मुद्रा के रूप में ही किया जाता है। मजदूरी मुद्रा में ही चुवाई जाती है हालांकि आर्थिक स्वतन्त्रता उतनी अधिक नहीं होती जितनी पूँजीवाद में। कुछ लोगों का कहना है कि यदि उपभोग की स्वतन्त्रता को समाप्त कर दिया जाय तो मुद्रा की आवश्यकता समाप्त हो सकती है। यह ठीक है कि ऐसा करने से समस्या आसान हो जायगी परन्तु फिर भी मूल्य निर्धारण प्रक्रिया (Price Mechanism) की आवश्यकता अवश्य रहगी। थो ए पी लर्नर ने कहा है कि बिना मुद्रा के किसी भी जटिल अर्थ व्यवस्था का कुशल संचालन असम्भव है— “Without price mechanism it is impossi-

ble for an economic system of any complexity to function with any reasonable degree of efficiency" साधनों की सीमिता के कारण हम जो चाहे वही और उसी मात्रा में नहीं पैदा कर सकते। उनको सर्वोत्तम प्रयोग में (Best use) लाने के लिए कीमत निर्धारण प्रक्रिया (Price mechanism) के आधार पर ही उनकी विभिन्न प्रयोगों की उपयोगिता की तुलना की जा सकती है। श्री जी. एन. हाम ने अपनी पुस्तक 'Monetary Theory' में लिखा है कि एक सामाजिक अर्थ-व्यवस्था सदैव मौद्रिक अर्थ-व्यवस्था रहेगी।

"a social economy will remain a monetary economy."

मुद्रा के दोष (Evils of Money)

1. आर्थिक अस्त-व्यस्तता—जिन प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को महत्वहीन वस्तु कहा है वे भी इस बात को मानते हैं कि अनियन्त्रित एवं अव्यवस्थित मुद्रा स्वतन्त्र और विशेष महत्व रखती है। जान स्टुअर्ट मिल ने लिखा है— "...it only exerts a distinct and independent influence of its own when it gets out of order."। इस वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि आर्थिक अस्त-व्यस्तता को रोकने के लिए मुद्रा को सयत (in order) रखना बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि मुद्रा अधिकांशतः सयत नहीं रहती और इस कारण आर्थिक व्यवस्था दीर्घकालीन साम्यावस्था नहीं प्राप्त कर पाती। मौद्रिक-व्यय में परिवर्तन होने से आर्थिक क्रियाओं में उतार-चढ़ाव होता रहता है। तेजी और मन्दी का चक्र चलता रहता है और इनका समाज पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है—

(i) मौद्रिक व्यय में कमी का प्रभाव—विनिमय के क्षेत्र में जब मुद्रा का प्रयोग किया जाता है तो उपयुक्त वस्तु प्राप्त होने तक उसका व्यय स्थगित किया जाना एक सामान्य बात है परन्तु जब मुद्रा असाधारण कारणों से व्यय नहीं की जाती तो उसका अर्थ-व्यवस्था को पगु बना देने वाला प्रभाव होता है। मन्दी काल के अनुभव इस बात को प्रमाणित करते हैं। आय और रोजगार की स्थिति दयनीय हो जाती है।

(ii) मौद्रिक व्यय में वृद्धि का प्रभाव—मौद्रिक व्यय में वृद्धि होने से आय, रोजगार और कीमत स्तर में वृद्धि होती है। उत्पादन लागत बढ़ती जाती है। अत्यधिक प्रसार का मय रहता है। समाज में निश्चित आय वाले लोगों का वास्तविक उपभोग बहुत कम हो जाता है। एक तरफ पूँजीपति वर्ग का दिनों दिन विकास होता है और दूसरी ओर श्रमिक वर्ग निरन्तर निषण होता जाता है। यह स्थिति कमी-कमी राजनैतिक उबल-पुखल का निम्नग्रण सिद्ध होती है।

मौद्रिक अर्थ-व्यवस्था का सतुलन उपयुक्त (right) मुद्रा की मात्रा के बिना विगड़ जाता है। उपयुक्त मुद्रा की मात्रा का तात्पर्य उस मात्रा से है जो मौद्रिक

कार्यों के लिए पर्याप्त तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दे सके।¹ दुर्भाग्य से ऐसी मौद्रिक पूंति के लिए कोई सरल और आसान कसौटी नहीं है एव व्यवहार में कोई भी मौद्रिक विधि (Monetary System) इन शर्तों की पूर्ति नहीं कर सकी है। इसलिए कीमत स्तर में परिवर्तन होते रहे हैं। कीमतों के गिरने से आकस्मिक हानि (windfall losses) तथा कीमतों के बढ़ने से आकस्मिक लाभ (windfall gains) होते हैं और परिवर्तित कीमत दर की अधिनाश बुराईया इन्हीं के कारण पैदा होती है।

2 सामाजिक बुराईयों को जन्म—लुडविग वान माइजे का कथन है कि मुद्रा को चोरी, धोखा और छून का कारण समझा जाता है। व्यवहार और अर्थशास्त्र मुद्रा की ही देन है।² मुद्रा का प्रेम ही सभी बुराईया को जड़ है। "The love of it is the root of all evil"। आधुनिक मौद्रिक युग में वास्तविक सुख का स्थान भौतिक सुख ने ग्रहण कर लिया है। भौतिक सुखों की प्राप्ति मुद्रा द्वारा ही हो सकती है इसलिए जैसे भी मुद्रा प्राप्त करना ही लक्ष्य बन गया है। आज नैतिकता का वही स्थान नहीं दिखाई देता। आज की राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था उसी को आदर प्रदान करती है जिसके पास मुद्रा है। मुद्रा रहने पर राजनैतिक शक्ति प्राप्त हो सकती है। प्रजातन्त्र में ऐसे उदाहरण अनेक मिल सकते हैं। पैसे से मत और मतदाता खरीदना एक आम बात हो गई है। लगता है पुनः मुद्रा साधन न रहकर साध्य बन गई है।

बुराईयाँ क्यों ? मुद्रा के जो भी दोष हैं वह इसीलिए हैं कि मुद्रा को निरकुश छोड़ दिया जाना है। जिस प्रकार सेवक निरकुश हो जाने पर सेवा के स्थान पर असेवा करने लगता है उसी प्रकार मुद्रा भी मानव समाज की सेवा उसी समय तक करती है जब तक उस पर नियन्त्रण रहता है। प्रो. राबर्टसन का निम्न कथन इस सम्बन्ध में सत्य प्रतीत होता है—“Money which is a source of so many blessings to mankind, becomes also, unless we control it, a source

¹ "In general the right quantity of money is that which fits neatly into the monetary job at hand and encourages sound economic growth and progress" —R G Thomas

² Money is regarded as the cause of theft and murder, of deception and betrayal. Money is blamed when the prostitute sells her body, and when the bribed Judge perverts the law. It is money against which moralists declaim when he wishes to oppose excessive materialism. Significantly enough, avarice is called the love of money and all evil is attributed to it."

of peril and confusion' मुद्रा के दोषों के कारण मुद्रा का प्रयोग आधुनिक जटिल व्यवस्था में छोड़ा नहीं जा सकता। आवश्यकता इस बात की है कि कीमत-स्तर के परिवर्तनों को रोका जाय। ऐसे मौद्रिक परिवर्तन न लाए जाय जो कीमत स्तर को बहुत अधिक प्रभावित करें। मौद्रिक नियंत्रण की नीति का पालन किया जाय जिससे मौद्रिक कारणों से उत्पन्न चक्रीय परिवर्तनों (Cyclical changes) को रोका जा सके। मुद्रा एक बड़ा ही कोमल हथियार है। इसका प्रयोग बड़ी सतर्कता से ही किया जा सकता है।

मुद्रा का स्वभाव (Nature of money)

1 मुद्रा गतिशील है—मुद्रा आधुनिक युग में निष्क्रिय, तटस्थ और निश्चेष्ट साधन नहीं अपितु सत्रिय और सचेष्ट साधन है।

".. Money can no longer be thought of as the drab, utilitarian handmaiden of economic society. Instead it stands forth as a kind of genie with tremendous, all pervading powers over economic good and evil"
— R. G. Thomas

मुद्रा के माध्यम से अर्थ-व्यवस्था के सभी अवयवों को प्रभावित किया जाता है। विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सक्रिय भाग स्पष्ट दिखाई देता है। अब मुद्रा २ पय नहीं जो तिनका नहीं पैदा करता बल्कि एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जो ३ गतिविधियों का स्वयं मार्ग दर्शन करता है।

2 मुद्रा एक पर्दा है (Money is a veil) प्राचीन अर्थ-शास्त्री मुद्रा को एक पर्दा की सजा देते थे। उनके विचार से मुद्रा वह अवगुण्ठन है जिसके पीछे वास्तविक आर्थिक शक्तियां कार्य करती हैं तथा मुद्रा आर्थिक क्रियाओं को स्वतन्त्र रूप से प्रभावित नहीं करती। परन्तु जैसा ऊपर दिये गये विवरण से स्पष्ट है यह कथन अब इतिहास की बात है। वर्तमान युग में मुद्रा एक स्वतन्त्र और महत्वपूर्ण कारक है। वस्तुओं के अपर्याप्त होने पर, मुद्रा होत हुए भी उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता इसलिए श्री रावर्टसन ने मुद्रा को इस अर्थ में आवरण कहा है। परन्तु ऐसी स्थिति असाधारण समय में पैदा होती है जब उपरोक्त की आर्थिक स्वतन्त्रता को नियन्त्रित कर दिया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में यह बात नहीं लागू होती।

3. मुद्रा साधन है साध्य नहीं (Money is a means not end) : मुद्रा का आविष्कार विनिमय क्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए हुआ। इसका प्रयोग मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होना चाहिए। मुद्रा स्वयं मुद्रा के लिए नहीं है। यदि मुद्रा साधन के स्थान पर साध्य बन जाती है तो मुद्रा बुराईयों की

जड़ बन जाती है। मुद्रा पर नियन्त्रण की आवश्यकता होती है। नियन्त्रण न रहने से यह सेवक से स्वामी बन जाती है। 'मुद्रा एक अच्छा सेवक है परन्तु बुरा स्वामी।'²

परीक्षा प्रश्न तथा सकेत

1. मुद्रा के आकस्मिक कार्यों (Contingent functions) को स्पष्ट कीजिए ? उन्हें आकस्मिक क्यों कहा जाता है ? मुद्रा अन्य कौन-कौन से कार्य करती है।

(राजस्थान, टी० डी० सी० फाइनल 1961)

[सकेत : यहाँ पर मुद्रा के आकस्मिक या सम्भाव्य कार्यों (Contingent functions) जैसे सीमान्त उपयोगिता में समानता लाना, पूँजी में तरलता लाना इत्यादि की धारणा कीजिए। इन्हें आकस्मिक कहने के कारण बताते हुए मुद्रा के प्रधान तथा गौण कार्यों की भी व्याख्या कीजिये]

2. मुद्रा की व्याख्या कीजिए। मुद्रा के लाभ एवं हानियों का विवेचन कीजिये।

(राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल 1965)

[सकेत प्रथम भाग में मुद्रा की विभिन्न परिभाषाओं की व्याख्या करते हुए उपयुक्त परिभाषा दीजिए। दूसरे भाग में मुद्रा के लाभ तथा हानियों का वर्णन कीजिए।]

3 निम्नलिखित में से किन्हीं दो को स्पष्ट कीजिये—

(अ) 'आधुनिक जीवन में धातु मुद्रा का महत्व समाप्त हो गया है।'

(ब) "मुद्रा एक अच्छा सेवक है परन्तु बुरा स्वामी।"

(स) "मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ-विज्ञान घूमता है।"

(राजस्थान, टी० डी० सी० फाइनल 1962)

[सकेत : (अ) के स्पष्टीकरण में यह बताइये आधुनिक जीवन में धातु मुद्रा के स्थान पर पत्र मुद्रा का महत्व बढ़ा है। (ब) के स्पष्टीकरण में मुद्रा को नियन्त्रण में रखकर प्राप्त सेवाएँ का उल्लेख कीजिए तथा अनियंत्रित मुद्रा के भयावह परिणामों से अवगत कराइये। (स) भाग में मुद्रा के महत्व पर प्रकाश डालिए]

4. "मुद्रा ही वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ-शास्त्र केन्द्रित है" इसकी विवेचना तथा मुद्रा के अन्य कार्यों का उल्लेख कीजिये।

(राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल)

[सकेत : प्रथम भाग में मुद्रा का महत्व समझाइये। दूसरे भाग में मुद्रा के प्रधान, गौण तथा आकस्मिक कार्यों का वर्णन कीजिये।]

5. मुद्रा के महत्व का वर्णन कीजिए। मुद्रा के क्या दोष हैं ? क्या मुद्रा के दोषों का उन्मूलन सामाजिक व्यवस्था के बदलने से सम्भव है ? संक्षिप्त विवेचन कीजिये।
(राजस्थान, टी० डी० सी० फाइनल 1969)

[सकेत प्रथम भाग में मुद्रा का महत्व बताइये। दूसरे भाग मुद्रा के दोषों तथा हानियों की व्याख्या कीजिये। अन्त में सिद्ध कीजिये कि सामाजिक व्यवस्था के बदलने से मुद्रा के दोषों का उन्मूलन सम्भव नहीं है।]

6. मुद्रा के मुख्य कार्य कौन-कौन से हैं ? समाज को मुद्रा के लाभों का वर्णन कीजिये।
(राजस्थान, टी० डी० सी० फाइनल 1968)

[सकेत प्रथम भाग में मुद्रा के प्रधान, गौण तथा आकस्मिक कार्यों का वर्णन कीजिये। दूसरे भाग में मुद्रा का महत्व समझाइये।]

मुद्रा का वर्गीकरण (Classification of Money)

"Every branch of knowledge has its fundamental discovery. In mechanics, it is the wheel, in Science, fire, in Politics, the vote. Similarly, in Economics in the whole commercial side of man's social existence, money is the essential invention on which all the rest is based"

Crowther

मुद्रा के भौतिक रूप के आधार पर वर्गीकरण (Classification on the basis of physical form of money)

इस आधार पर मुद्रा को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :—

1. धातु मुद्रा (Metallic money)
2. पत्र मुद्रा (Paper money)
3. बैंक जमा (Deposit money)

धातु मुद्रा (Metallic Money)

मुद्रा के इतिहास से पता चलता है कि प्रथम महायुद्ध के पहले सप्ताह के अधिकांश देशों में सोने या चादी के सिक्के चलन में थे। वास्तव में धातु मुद्रा वस्तु मुद्रा का अन्तिम और स्थायी रूप था। धातुओं में सोने या चादी का मुद्रा के रूप में इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि उनमें परिचयता, उपयोगिता, सब-स्वीकार्यता, बहनीयता, विभाजकता, अक्षयता, स्थायित्व (मूल्य में), एकरूपता और टकणशीलता थी। धातु मुद्रा को सिक्का (coin) की संज्ञा दी जाती थी। सिक्के विशेष आकार प्रकार के धातु के ऐसे टुकड़ों को कहते हैं जिनकी विश्वसनीयता, भार तथा शुद्धता प्रमाणित रहती हैं और जा विनिमय के माध्यम के रूप में सर्व-स्वीकार्य होते हैं।

सिक्कों की किस्में (Kinds of Coins)

1. प्रामाणिक सिक्के (Standard Coin)
2. प्रतीक सिक्के (Token Coin)

1 प्रामाणिक सिक्के (Standard Coin) : प्रामाणिक सिक्को में निम्नलिखित विशेषताये होती हैं।

1. अंकित कीमत धात्विक मूल्य के बराबर होती है।
2. यह असीमित विधिग्राह्य होता है।
3. इसकी स्वतन्त्र ढलाई होती है।
4. यह देश की प्रधान मुद्रा होती है।

प्रामाणिक सिक्कों के चलन से मुद्रा का मूल्य एक धातु से सम्बन्ध हो जाता है। आधुनिक युग में प्रामाणिक सिक्को का चलन समाप्त हो चुका है।

2 प्रतीक सिक्के : इनकी निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं

- (i) यह देश की सहायक मुद्रा के रूप में चलन में रहते हैं।
- (ii) धात्विक मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है।
- (iii) इनकी ढलाई सीमित होती है।
- (iv) यह सीमित विधिग्राह्य होते हैं।

प्रायः सभी देशों में प्रतीक सिक्कों का ही चलन है। इनका प्रयोग छोटे-छोटे भुगतानों के लिए किया जाता है।

ढलाई व्यवस्था : ढलाई के दो प्रमुख ढग काम में लाये गये हैं

1. स्वतन्त्र ढलाई (Free Coinage)
- 2- सीमित ढलाई (Restricted Coinage)

1. स्वतन्त्र ढलाई (Free Coinage) : इसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति धातु ले जाकर उसके सिक्के ढलवा सकता है। टंकाल सरकार की होती है परन्तु जनता के प्रयोग के लिए खुली रहती है। यह ढलाई व्यवस्था बहुत समय तक कायम रही। भारत में 1835 से 1893 तक यही व्यवस्था थी।

इस व्यवस्था को चूँकि सरकार चलाती है इसलिए टंकाल चलाने का जो व्यय होता है वह या तो सरकार को सहन करना पड़ता है या टंकाल का प्रयोग करने वाली जनता को। इस प्रकार स्वतन्त्र ढलाई दो प्रकार से हो सकती है—

- (i) सशुल्क स्वतन्त्र ढलाई (Non-gratuitous Coinage)
- (ii) निःशुल्क स्वतन्त्र ढलाई (Gratuitous Coinage)

(i) सशुल्क ढलाई (Non-gratuitous Coinage) : सरकार जब जनता से ढलाई व्यय वसूल करती है तो इसे सशुल्क ढलाई कहते हैं। शुल्क लेने के दो तरीके हैं। यदि सिक्के ढालने का वास्तविक व्यय जनता से वसूल किया जाय तो ऐसे शुल्क को ढलाई व्यय (Mintage or Brassage) कहते हैं। इस शुल्क में लाम का अंश नहीं होता। दूसरा तरीका व्यय के साथ कुछ लाम जोड़कर शुल्क के रूप में वसूल

करने का है इसको 'सलाम शुल्क' (Seigniorage) कहते हैं। शुल्क की प्राप्ति भी दो प्रकार से की जा सकती है। एक तरीका तो यह है कि धातु के पूर्ण मूल्य के सिक्के ढाल दिए जाय और अलग से मुद्रा के रूप में ढलाई व्यय वसूल किया जाय। दूसरा तरीका यह है कि धातु में से ढलाई व्यय के बराबर धातु निकाल ली जाय और उसके बदले सस्ती धातु मिलाकर सिक्के ढाल दिए जाय।

(ii) निःशुल्क स्वतन्त्र ढलाई (Gratuitous Coinage) : जब सरकार सिक्को की ढलाई के लिए जनता से किसी प्रकार का शुल्क वसूल नहीं करती तो उसे निःशुल्क ढलाई व्यवस्था कहा जाता है। टकसाल चलाने का पूरा व्यय सरकार स्वयं सहन करती है।

2. सीमित ढलाई (Restricted Coinage) : इस व्यवस्था में सरकार मध्य आवश्यकतानुसार मुद्रा की ढलाई करती है। जनता को सिक्के ढलाने का अधिकार नहीं होता। सरकार के आदेश पर ही सिक्के ढाले जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में सरकार को मुद्रा की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाने बढ़ाने का अवसर प्राप्त रहता है जिसका प्रयोग मूल्यों को स्थिर रखने के लिए किया जा सकता है। स्वतन्त्र टकस व्यवस्था में मुद्रा की मात्रा व्यावसायिक आवश्यकता या सरकार की नीति पर निर्भर नहीं करती। इसके अतिरिक्त स्वतन्त्र ढलाई खर्चीली होती है। आधुनिक युग में सीमित ढलाई व्यवस्था ही अधिक उपयुक्त है।

धातु मुद्रा के गुण

(Advantages of Metallic Money)

1. धातु का मूल्य : केवल मुद्रा के रूप में ही धातु मुद्रा का मूल्य नहीं होता बल्कि धातु के रूप में भी होता है। यदि मुद्रा के रूप में उसे विमुद्रित (Demonetise) कर दिया जाय तो भी उसका वास्तविक मूल्य होगा। इसी प्रकार घिस जाने पर उसे धातु के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

2. मूल्य में स्थिरता : धातु के उत्पादन में अत्यधिक परिवर्तन न होने के कारण इसका मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर रहता है।

3. अक्षयता : अल्प वस्तुओं और कागजी मुद्रा की तुलना में धातु मुद्रा बहुत अधिक दिनों तक स्थायी रहती है, नष्ट नहीं होती।

4. प्रसार का भय नहीं—धातु मुद्रा का मनमाना प्रसार नहीं किया जा सकता क्योंकि धातु रहने पर ही मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। इसके विपरीत पत्र मुद्रा में अत्यधिक प्रसार का दोष पाया जाता है।

धातु मुद्रा के दोष (Disadvantages of Metallic Money) :

1. अपव्यय : बहुमूल्य धातु, मुद्रा के रूप में बेकार हो जाती है क्योंकि धातु

स्वयं चलन में रहती है, उसके टकराव पर अधिक व्यय होता है और चलन में रहने के कारण धातु घिसती रहती है।

2. भुगतान में कठिनाई अधिक मात्रा में भुगतान करने में बड़ी कठिनाई होती है। समय और शक्ति व्यर्थ की गणना और परख में नष्ट होती है। धातु मुद्रा को रखने के लिए भी अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ती है।

3. स्थानान्तरण में कठिनाई : अधिक भार के कारण धातु मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कठिनाई और जोखिम दोनों ही रहती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में व्यय भी अधिक होता है।

पत्र मुद्रा (Paper Money)

सिक्कों के प्रयोग की असुविधाओं के कारण पत्र मुद्रा का चलन प्रारम्भ हुआ। पत्र मुद्रा के विकास क्रम में पत्र मुद्रा ने कई रूप धारण किया जिनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं—

1. प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा (Representative Paper Money)

2. परिवर्तनीय पत्र मुद्रा (Convertible Paper money)

3. अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा (Inconvertible Paper Money)

1. प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा (Representative Paper Money) . वह मुद्रा जो पूर्ण रूप से धातु कोष पर आधारित हो अर्थात् जिसके पीछे शत प्रतिशत धातु का कोष रखा जाता हो प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कही जाती है। वास्तव में प्रारम्भ में पत्र मुद्रा का वास्तविक मूल्य (intrinsic Value) न होने के कारण जनता के विश्वास को प्राप्त करने के लिए शत प्रतिशत कोष रखना आवश्यक था। पत्र मुद्रा केवल धातु की प्रतिनिधि मानी जाती थी इसलिए लोगों का विश्वास पत्र मुद्रा में कायम हो सका। सब लोग प्रतिनिधि पत्र मुद्रा को सहर्ष बिना संदेह स्वीकार करते थे। लोगों को पत्र मुद्रा के बदले धातु मुद्रा प्राप्त करने की स्वतन्त्रता थी।

प्रतिनिधि पत्र मुद्रा काल में यह अनुभव किया गया कि सभी लोग एक साथ पत्र मुद्रा के बदले धातु मुद्रा की मांग नहीं करते और धातु, मुद्रा कोष में, बेकार पड़ी रहती है।

2. परिवर्तनीय पत्र मुद्रा (Convertible Paper Money) . प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के अनुभव ने परिवर्तनीय पत्र मुद्रा को जन्म दिया। जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए धातु में परिवर्तन करने की सुविधा को बनाए रखते हुए शत प्रतिशत कोष के स्थान पर केवल आंशिक रूप में धातु रखने का सिद्धान्त अपनाया गया। आवश्यकता पड़ने पर जनता नाटों के बदले धातु या सिक्के प्राप्त कर सकती है परन्तु इसमें प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के अपव्यय से बचने का प्रयत्न किया गया है। यह प्रतिनिधि पत्र मुद्रा की अपेक्षा सस्ती होने के साथ, लचीली और सुविधाजनक भी है।

3. अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा (Inconvertible Paper Money) • पत्र मुद्रा का आधुनिक रूप अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा है। इसमें जनता को नोटों के बदले धातु या धातु मुद्रा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। इसलिए नोटों के पीछे धात्विक कोप रखने की भी आवश्यकता नहीं होती। धात्विक कोप यदि रखा भी जाता है तो अत्यधिक प्रसार को रोकने के उद्देश्य से। यह मुद्रा चलन में विधिग्राह्य मुद्रा होने के कारण जनता का विश्वास प्राप्त कर पाती है। इसे प्राविष्ट मुद्रा (Fiat Money) की संज्ञा दी जाती है।¹ यह मुद्रा लोच, मितव्ययिता और सुविधा के दृष्टिकोण से अधिक उपयुक्त है।

पत्र मुद्रा के गुण (Advantages of Paper Money)

1. लोच सिद्धों की अपेक्षा परिवर्तनशील और अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा में लोच की मात्रा अधिक होती है। सरकार की इच्छा और व्यवसाय तथा अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। प्रामाणिक सिद्धों में इस गुण का नितांत अभाव होने के कारण वे कमी-कमी अर्थव्यवस्था के लिए बाधक सिद्ध होते हैं। परन्तु पत्र मुद्रा आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में विशेष रूप से सहायक होती है।

2. मितव्ययिता : धातु मुद्रा की तुलना में पत्र मुद्रा कई दृष्टिकोणों से मितव्ययितापूर्ण है (1) बहुमूल्य धातु की आवश्यकता नहीं पड़ती इसलिए उनका प्रयोग विदेशी भुगतान या कलात्मक वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जा सकता है। धातु मुद्रा व्यर्थ ही धातु को अनुत्पादक रूप में प्रयोग करती है और आर्थिक विकास का माग अवहट्ट करती है। पत्र मुद्रा इस दृष्टि से मितव्ययी है। (2) पत्र मुद्रा जारी करने में बहुत ही कम व्यय होता है। धातु मुद्रा जारी करने में जिस श्रम और धन का व्यय होता है उस बचाकर यह अन्य उत्पादक कार्यों में लगाने का अवसर प्रदान करती है। (3) पत्र मुद्रा में कागजी नोट चलन में रहते हैं। धातु के चलन में रहने पर जो घिसावट होती है वह इसके प्रयोग से बच जाती है। (4) पत्र मुद्रा चालू करने का खर्च बहुत ही कम होता है क्योंकि इसके लिए केवल कुछ कागज इक तथा प्रिंटिंग प्रेस की आवश्यकता होती है।

3. सुविधा • पत्र मुद्रा का प्रयोग बहुत ही सुविधाप्रद है। इसमें वहनीयता का गुण प्रचुर मात्रा में होने के कारण बड़ी से बड़ी रकम एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुविधापूर्वक ले जाई जा सकती है। धातु मुद्रा के स्थानान्तरण में जो जोखिम

¹ "Any thing which is intended to serve as a medium of exchange simply because it is officially sanctioned as money is known as Fiat money."

होती है वह भी पत्र मुद्रा में समाप्त हो जाती है क्योंकि अर्वाहनीय तत्वों को यह पता नहीं लग पाता कि किस व्यक्ति के पास मुद्रा है और कितनी मात्रा में है। बड़े से बड़ा भुगतान शीघ्रता और सरलता से किया जा सकता है क्योंकि पत्र मुद्रा को गिनना तथा उसकी जाँच करना अपेक्षाकृत आसान है।

4. सरकार के लिए उपयुक्त सरकार के दृष्टिकोण से पत्र मुद्रा एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। इसलिए आवश्यकता के समय यह सरकार के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। जब मुद्रा बाजार में लाभप्रद ऋण मिलने में कठिनाई उपस्थित हो जाती है तो सरकार पत्र मुद्रा जारी कर सकती है जो एक प्रकार से बिना व्याज का ऋण है। सकटकालीन परिस्थितियों में पत्र मुद्रा जारी करके बजट सन्तुलित करने के उदाहरण द्वितीय विश्वयुद्ध काल में कई मिलते हैं। विकासशील देशों ने भी यह लाभ अनेक बार उठाया है। इस प्रकार पत्र मुद्रा सरकार के दृष्टिकोण से भी लाभप्रद है।

पत्र मुद्रा के दोष (Disadvantages of Paper Money) :

पत्र मुद्रा में अनेक गुणों के साथ कुछ अशुभ गुण भी हैं जो नोट जारी करने वाली संस्था के असावधान रहने पर भयकर परिणाम ला सकते हैं। नोटों के दोषों का प्रमुख कारण उनके मूल्य की अस्थिरता है। पत्र मुद्रा का निजी मूल्य कुछ भी नहीं होता केवल कानूनी और परम्परागत (Customary) मूल्य होता है। उसकी कानूनी मान्यता समाप्त होते ही उसका मूल्य शून्य हो जाता है। पत्र मुद्रा के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं —

1. मुद्रा प्रसार का भय सकटकालीन और असाधारण स्थितियों में सरकार अत्यधिक नोट जारी कर देती है और अपने बजट को सन्तुलित करने का प्रयत्न करती है। अर्थ-व्यवस्था की वास्तविक आवश्यकता से अधिक नोट जारी करने से मुद्रा का मूल्य गिर जाता है कीमत स्तर बढ़ने लगता है तथा समाज में, विशेषकर व्यवसाय में अनिश्चितता का वातावरण व्याप्त हो जाता है। अर्वाहनीय सट्टों (Speculations) की संख्या बढ़ने से व्यवसायी वर्ग में अशुभ और नैतिकता की कमी होती जाती है। आयातों में वृद्धि और निर्यातों में कमी होने के कारण व्यापार सन्तुलन बिगड़ जाता है। कभी कभी नोटों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाती है कि जनता उन्हें मुद्रा के रूप में स्वीकार करने से इन्कार कर देती है जैसा प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मनी में हुआ।

2. सीमित चलन क्षेत्र : पत्र मुद्रा का अपना निजी मूल्य न होने के कारण इसका चलन किसी देश की सीमाओं तक ही सीमित है। दूसरे देश के लोच इसे स्वीकार नहीं करते इसलिए विदेशी व्यापार में अन्य तरीकों का सहारा लेना पड़ता

है स्वर्ण मुद्रा की तरह पत्र मुद्रा कभी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा का रूप शायद ही ग्रहण कर सकती है।

3. नश्वरता : पत्र मुद्रा धातु मुद्रा के समान टिकाऊ नहीं होती है। यह जल, अग्नि, तेल और समय द्वारा नष्ट हो जाती है। कागज अल्पकालीन प्रयोग में ही गदा होने के साथ-साथ फट जाता है और इसका मूल्य नष्ट हो जाता है। इस दोष के कारण कई अर्थशास्त्री इसे समाज के प्रति एक धोखा (Fraud on Society) की सजा देते हैं।

4. मूल्यहीनता : पत्र मुद्रा का केवल कानूनी या परम्परात्मक मूल्य होता है उसका आन्तरिक मूल्य (Intrinsic value) कुछ भी नहीं होता। धातु मुद्रा का प्रयोग धातु के रूप में भी किया जा सकता है परन्तु पत्र मुद्रा का ऐसा कोई प्रयोग नहीं हो सकता है। विमुद्रीकरण (Demonetisation) कर देने से पत्र मुद्रा केवल मूल्यहीन कागज मात्र रह जाती है। पत्र मुद्रा में जनता सरकारी शक्ति के कारण ही विश्वास रखती है।

जमा मुद्रा (Deposit Money)

उपरोक्त दो प्रकार की मुद्राओं (धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा) को सामान्यतया एक ही नाम '(Currency' or 'hand-to-hand money' or pocket book money') से संबोधित किया जाता है परन्तु व्यापारिक बैंको की चेको द्वारा हस्तान्तरणीय मांग देय (demand liabilities) को 'बैंक-मुद्रा' या 'बैंक-जमा' या 'जमा-मुद्रा' के नाम से जाना जाता है।

सामान्य मुद्रा (common money) सभी लोगों द्वारा निःसंकोच स्वीकार की जाती है परन्तु अनेक बार भुगतान करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम बैंको के द्वारा भुगतान करते हैं और इन बैंको को कभी भी मुद्रा के रूप में परिवर्तित नहीं कराया जाता। सामान्य मुद्रा का लेन-देन न होने पर भी विनिमय माध्यम का कार्य सम्पन्न हो जाता है। इस प्रकार मांग-जमा (Demand deposit) को यदि बिना पूर्व सूचना के बैंक से सामान्य मुद्रा निकालने का अधिकार कहा जाय तो हम यह कह सकते हैं कि सामान्य मुद्रा का अधिकार (Claims on Common money) उतना ही उपयोगी है जितना सामान्य मुद्रा स्वयं है। इसी अधिकार मुद्रा (claim money) को बैंक-मुद्रा या जमा-मुद्रा या बैंक बुक मनी कहा जाता है।

जमा-मुद्रा का निर्माण व्यापारिक बैंको द्वारा किया जाता है। जमा-मुद्रा निर्माण की विधि की व्याख्या "बैंको द्वारा साख सृजन" अध्याय में की गई है। यहाँ केवल यही कहना पर्याप्त होगा कि बैंको द्वारा जमा-मुद्रा का निर्माण असीमित मात्रा में नहीं किया जा सकता। मौद्रिक अधिकारी (monetary Authority) प्रत्यक्ष रूप

से सामान्य मुद्रा (common money) और अप्रत्यक्ष रूप से जमा-मुद्रा (Deposit money) पर नियन्त्रण रखता है।

जमा-मुद्रा, धातु मुद्रा तथा पत्र-मुद्रा की तुलना में अधिक वहनीय है क्योंकि इसका भार नहीं के बराबर है। लोच और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह अन्य प्रकार की मुद्राओं से श्रेष्ठ है। अपने इन्हीं गुणों के कारण आजकल इसने आधुनिक व्यावसायिक जगत को आच्छादित कर रखा है।¹

मुद्रा की वैधानिक मान्यता के आधार पर वर्गीकरण (Classification on the basis of legal recognition of money)

1. विधिग्राह्य मुद्रा (Legal Tender money)
2. ऐच्छिक मुद्रा (Optional money)

विधि ग्राह्य मुद्रा (Legal Tender Money): विधि-ग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा है जिसे वस्तुओं और सेवाओं के बदले स्वीकार करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति कानूनी तौर पर बाध्य होता है। कुछ प्रकार की मुद्राओं को सरकार द्वारा यह शक्ति प्रदान की जाती है। इसके द्वारा मुद्रा की स्वीकार्यता में वृद्धि हो जाती है तथा ऋणी और ऋणदाता के भुगतान सम्बन्धी दायित्वों के बारे में कानूनी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। आधुनिक युग में, जब 'जमा मुद्रा' का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, मुद्रा की कानूनी शक्ति का महत्व कम होता जा रहा है। लोग मुद्रा स्वीकार करते समय उसके कानूनी पक्ष के प्रति सामान्यतया उदासीन रहते हैं। केवल मौद्रिक व्यवस्था की सकटकालीन स्थिति में मुद्रा की कानूनी शक्ति में जन सामान्य की रुचि दिखाई पड़ती है। विधि-ग्राह्य मुद्रा के दो भेद हैं—

1. असीमित विधि ग्राह्य मुद्रा (unlimited legal tender money) ऋणों के अन्तिम भुगतान में किसी भी मात्रा में जिस मुद्रा द्वारा भुगतान स्वीकार करने को बाध्य किया जा सके उसे असीमित विधि ग्राह्य मुद्रा कहते हैं।

2. सीमित विधि-ग्राह्य मुद्रा (limited legal tender money) इस प्रकार की मुद्रा को भी भुगतानों में स्वीकार करने के लिए लोग कानून द्वारा बाध्य होते हैं परन्तु एक निश्चित मात्रा तक ही। निर्धारित सीमा से अधिक मुद्रा स्वीकार करना भुगतान प्राप्त करने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। प्रोफेसर राबर्टसन ने इस प्रकार की मुद्रा को सहायक मुद्रा (subsidiary money) कहा है।

¹ "Because of its flexibility and safety, deposit money is predominant in mediating financial and other business transactions"

—Whittlesey Freedman Herman

—Money and Banking :

—Analysis and Policy 1963 - P. 20.

ऐच्छिक मुद्रा (Optional Money) : ऐच्छिक मुद्रा साधारणतया भुगतान के रूप में स्वीकार की जाती है परन्तु उसे स्वीकार करने के लिए कानूनी बाध्यता नहीं होती। इस प्रकार की मुद्रा के अन्तर्गत साखपत्र, चेक, बिल, ब्राफ, एक्सचेंज, प्रतिज्ञा पत्र आदि को शामिल किया जाता है। इनके पीछे सरकारी शक्ति का सहारा नहीं होता बल्कि इन्हें भुगतान करने वाले की साख में विश्वास के कारण स्वीकार किया जाता है।

प्रोफेसर राबर्टसन ऐच्छिक मुद्रा के अन्तर्गत चेक आदि को शामिल नहीं करते। इसमें वे ऐसी चीजों को शामिल करते हैं जो परम्परागत भुगतान के साधन के रूप में प्रयोग होती हैं (जैसे भारत में बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में सोने की गिरी और बाद में चाँदी के सिक्के वैधानिक मान्यता न होने पर भी भुगतान के लिए प्रयोग होते थे)। राबर्टसन ने विधिग्राह्य मुद्रा, सहायक मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा को सामूहिक रूप से 'साधारण मुद्रा' की सजा दी है।

राबर्टसन के अनुसार असीमित विधिग्राह्य मुद्रा के भी दो भेद हैं (1) परिवर्तनीय विधिग्राह्य और (2) प्रामाणिक विधिग्राह्य। परिवर्तनीय विधिग्राह्य वह मुद्रा है जिसके बदले सरकार से अन्य प्रकार की मुद्रा प्राप्त की जा सके और प्रामाणिक विधिग्राह्य वह है जिसके बदले अन्य प्रकार की मुद्रा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता इनमें सभी दायित्वों का अन्तिम भुगतान हो जाता है।

खाता रखने के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण (Classification of money on the basis of maintenance of account.)—सार्ड कीन्स ने मुद्रा के दो प्रमुख भेदों का उल्लेख किया है (1) लेखा मुद्रा (Money of Account) (2) वास्तविक मुद्रा (Money Proper)। लेखा मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें कीमतों, ऋणों तथा सामान्य क्रय-शक्ति को व्यक्त किया जाता है—“In which debts prices and general purchasing power are expressed.” यह एक प्रकार का नाम है, पद है, जो निरन्तर बना रहता है। वास्तविक मुद्रा वह है जो वास्तव में विनिमय माध्यम के रूप में चलन में रहती है। यह वह रूप है जिसमें सामान्य क्रयशक्ति निहित रहती है। यह वह वस्तु है जो लेखा मुद्रा के पद को ग्रहण करती है। जैसे रुपया भारत की लेखा मुद्रा है, सिक्का, नोट आदि वास्तविक मुद्रा है।

कीन्स ने लेखा मुद्रा के भी दो वर्ग दिए हैं (1) राज्य मुद्रा (State Money) और (2) बैंक मुद्रा (Bank Money)। राज्य मुद्रा राज्य द्वारा जारी की जाती है। इसके अन्तर्गत विधिग्राह्य मुद्रा, बैंक द्वारा जारी किए गए नोट तथा केन्द्रीय बैंक जमा शामिल है। बैंक मुद्रा के अन्तर्गत व्यापारिक बैंकों की जमा मुद्रा शामिल की जाती है। वास्तव में यह व्यक्तिगत ऋणों की स्वीकृति मात्र है। कीन्स ने बैंक नोट तथा

केन्द्रीय बैंक जमा को प्रतिनिधि मुद्रा भी कहा है। वस्तुतः राज्य मुद्रा के तीन रूप बताए जाते हैं। (1) वस्तु मुद्रा—कोई दुर्लभ वस्तु जो मुद्रा के कार्यों के लिए चुनी जाय, (2) प्रबन्धित मुद्रा (Managed Money) में कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता, परन्तु इसके मूल्य को परिवर्तनशीलता के द्वारा या अन्य प्रकार से निश्चित रखा जाता है और (3) प्रादिष्ट मुद्रा (Fiat Money) यह प्रतीक मुद्रा है और विधानतः परिवर्तनीय नहीं होती है। मुद्रा के इन भेदों के अलावा कीन्स ने “चालू मुद्रा” का भी उल्लेख किया है। ‘चालू मुद्रा’ के अन्तर्गत इन्होंने जनता के पास राज्य मुद्रा तथा सदस्य बैंकों की जमा मुद्रा को शामिल किया है। ‘चालू मुद्रा’ के तीन उपभेद बताये हैं (i) आय मुद्रा—वह मुद्रा जो आय प्राप्ति के समयों के बीच के खर्च के लिए जनता के पास हो, (ii) व्यापार मुद्रा—वह मुद्रा जो व्यापारिक कार्यों को जारी रखने के लिए रखी जाय और (iii) सचय मुद्रा—वह मुद्रा जो विनियोग के लिए रखी जाय।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संकेत

(1) विभिन्न प्रकारों के पत्र-मुद्रा की विवेचना कीजिए। इसके गुणों एवं दोषों पर विचार कीजिए। (राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल, 1964)

[संकेत—प्रथम भाग में पत्र मुद्रा के प्रकार—प्रतिनिधि, परिवर्तनीय तथा अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा, बताइये। साथ ही साथ इनके गुणों तथा दोषों पर प्रकाश डालिए।]

(2) निम्न में भेद कीजिए—

(i) वास्तविक मुद्रा तथा हिसाब की मुद्रा।

(ii) पदार्थ मुद्रा तथा प्रतिनिधि पत्र मुद्रा।

(iii) विधिग्राह्य मुद्रा तथा ऐच्छिक मुद्रा।

(राजस्थान वी० काम०, 1960)

[संकेत—विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनमें भेद कीजिए।]

मौद्रिक मान (Monetary Standards)

"It is impossible to have an International financial system alongside a commercial system that is fiercely and jealously national"
Crowther

मौद्रिक मान का सिद्धान्त (Concept) किसी मौद्रिक व्यवस्था की अन्तिम मुद्रा (Ultimate money) के जारी करने में सम्बन्धित शर्तों तथा स्वभाव से संबद्ध है। अन्तिम मुद्रा या प्रामाणिक मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें मौद्रिक अधिकारी (Monetary authority) स्वयं अपने दायित्वों का अन्तिम रूप से निपटारा कर सके। प्रो० हॉम के शब्दों में प्रामाणिक मुद्रा का विनिमय मूल्य तथा परिमाण के नियंत्रित करने की प्रमुख पद्धति (Method) ही मौद्रिक मान है।¹ प्रामाणिक मुद्रा का जो रूप होता है उसी के अनुसार उस मौद्रिक मान का नामकरण होता है। उदाहरणार्थ यदि स्वर्ण को प्रामाणिक मुद्रा की इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे स्वर्णमान कहा जायेगा। परन्तु इसके साथ यह भी स्मरण रखना होगा कि मौद्रिक मान का मुख्य सम्बन्ध प्रामाणिक मुद्रा के आन्तरिक तथा बाह्य मूल्य के नियन्त्रण से है।

आदर्श मौद्रिक मान (Ideal Monetary Standard)

किसी देश और काल के सन्दर्भ में मौद्रिक मान का रूप उसके लक्ष्यों द्वारा निर्धारित होता है। प्रत्येक देश की मौद्रिक व्यवस्था के दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं। प्रथम, मौद्रिक व्यवस्था देश की आन्तरिक आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में मौद्रिक व्यवस्था को देश की प्रगति में साथ देना चाहिए। द्वितीय, चूँकि कोई भी राष्ट्र सतार में अन्य देशों से विलकुल अलग नहीं रह सकता इसलिए

¹ "...We may therefore define monetary standard from the viewpoint of economics as the principal method of regulating the quantity and the exchange value of standard or definitive money."

प्रदेक दग की मौद्रिक व्यवस्था का एक अन्तर्राष्ट्रीय पहलू भी होता है। अन्तर्राष्ट्रीय पहलू की उपेक्षा नही की जा सकती। इन मौद्रिक व्यवस्था को विनिमय दर को स्थिरता देनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। विभिन्न देशों की आर्थिक विपन्नता तथा प्रगति की अनुमानना आन्तरिक तथा बाह्य दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति को जटिल बना देने हैं इसलिए दोनों उद्देश्यों के बीच नामजस्य रखना ही मौद्रिक मान का आदर्श है। किसी भी आदर्श मौद्रिक मान में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है —

1. जनता का विश्वास—जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए मौद्रिक मान का सरल होना आवश्यक है। सरलता का तात्पर्य यह है कि मौद्रिक व्यवस्था के सभी पहलुओं को माधारण जनता समझती हो। जनता के विश्वास के अभाव में कोई भी मौद्रिक मान सफल नहीं हो सकता। दूसरी बात जो जनता के विश्वास को दृढ़ बनानी है वह है मौद्रिक मान की अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं से अनुसृतता। राजनैतिक स्थिरता भी मौद्रिक मान में जन-विश्वास को बढ़ानी है।

2. लोच—कोई भी अर्थ-व्यवस्था तभी प्रगति कर सकती है जब मौद्रिक मान में लोच हो अर्थात् आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा प्रसार या संकुचन की नीति अपनाई जा सके जिनसे व्यापारिक मांग पूरी होती रहे, परन्तु साथ ही अनावश्यक रूप से मुद्रा को मात्रा अधिक या कम न हो।

3. मूल्य में स्थिरत्व—प्रामाणिक मुद्रा के मूल्य में अपेक्षाकृत स्थिरत्व होना चाहिए अन्यथा मुद्रा के कार्य सफलता पूर्वक नहीं किए जा सकते। विनिमय-भाज्यम के रूप में मुद्रा सर्व स्वीकार्य तनी हो सकती है जब वह अपने कार्य सुगमता पूर्वक संचालित कर रही हो। मुद्रा के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने से मुद्रा प्रसार या मुद्रा संकुचन के दृष्टिकोणों से अर्थ-व्यवस्था के विभ्रत जलित होने की आशंका रहती है।

4. मितव्ययिता—मौद्रिक मान को आदर्श तनी कहा जा सकता है जब उसके संचालन में मितव्ययिता हो। यदि मौद्रिक मान खर्चीला हो तो पिछड़े हुए देशों के लिए किसी भी परिस्थिति में उपयुक्त नहीं हो सकता क्योंकि इससे उनकी आर्थिक प्रगति में सहायता के स्थान पर बाधा पहुंचेगी। मितव्ययिता होने से दूसरा नाम यह है कि सस्ते मौद्रिक मान में अधिक स्थिरत्व रहना है। खर्चीला मौद्रिक मान अधिक संकट की परिस्थिति में टूट जाता है परन्तु सस्ता मौद्रिक मान विपन्नता में भी साथ देता रहता है।

5. कम हस्तक्षेप की आवश्यकता : आदर्श मौद्रिक मान की प्रवृत्ति स्वयंचालित हानी चाहिए। पूर्ण स्वयंचालिता तो केवल कल्पना है वास्तव में होना यह चाहिए कि मौद्रिक मान के संचालन में कम से कम हस्तक्षेप की आव-

शक्यता पडे । यथा समव मुद्रा की माना स्वतः व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रहे । मौद्रिक मान का प्रबन्ध एव नियमन भी सरल हो ।

मौद्रिक मान के रूप

(Types of Monetary Standards)

मुख्य रूप से मौद्रिक मानों को दो वर्गों में बाटा जा सकता है ।

1 धातु मान (Metallic Standards)

2 कागज मान (Paper Standards)

धातु मान के निम्नलिखित भेद हो सकते हैं ।

1. एक धातुमान (Monometallism)

2. द्विधातुमान (Bimetallism)

3. मिश्रित धातुमान (Symmetallism)

4 समष्टि वस्तु मान (Composite Commodity Standard)

एक धातुमान

(Monometallism)

एक धातुमान उस मौद्रिक मान को कहते हैं जिसके अन्तर्गत किसी एक धातु को मूल्यमान के रूप में अपनाया जाता है । इस व्यवस्था में किसी एक धातु (मूल्यमान के रूप में अपनाई गई) के सिक्के प्रामाणिक मुद्रा के रूप में चलन में होते हैं या उस धातु में परिवर्तनीय होते हैं । इस मौद्रिक मान की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. किसी एक निश्चित धातु को प्रामाणिक मुद्रा का आधार बनाया जाता है ।

2. प्रामाणिक सिक्का चलन में होता है या प्रामाणिक मुद्रा धातु में परिवर्तनीय होती है ।

3. यदि सिक्को को चलन में रखा जाता है तो उनकी ढलाई भी स्वतन्त्र होती है ।

4. प्रामाणिक मुद्रा असीमित विधिग्राह्य होती है ।

5 सहायक मुद्राएँ भी चलन में होती हैं परन्तु वे केवल सीमित विधि ग्राह्य होती हैं ।

एक धातु मान के लाभ (Advantages of Monometallism) :

1. जनता का विश्वास : एक धातुमान के अन्तर्गत किसी धातु के सिक्के चलन में होते हैं या प्रामाणिक मुद्रा धातु में परिवर्तनीय होती है इसलिए इसमें जनता का विश्वास अधिक होता है ।

2. सरलता : यह व्यवस्था जनता को आसानी से समझ में आ जाती है इसलिए इसका संचालन सुगम होता है ।

3. विदेशी व्यापार में आसानी : विदेशों में मुग्तान करने में आसानी होती है क्योंकि एक धातुमान के रूप में चादी या सोने को प्रामाणिक मुद्रा को आधार माना जाता है जो सभी देशों में स्वीकार की जाती है । इस पद्धति में विनिमय दर की स्थिरता बनाए रखना भी आसान रहता है ।

एक धातुमान के दोष (Disadvantages of Mono-metallism) : एक धातुमान का प्रमुख दोष यह है कि इसमें लोच का अभाव है । किसी भी मौद्रिक मान को आदर्श तमी कहा जा सकता है जब देश की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप उसमें परिवर्तन किया जा सके । एक धातुमान में चूँकि प्रामाणिक मुद्रा का धातु से सम्बन्ध हाता है इसलिए उसको मात्रा में तमी परिवर्तन किया जा सकता है जब धातु की पूर्ति में पूर्ण लोच हो । यह कठिनाई मुद्रा की मात्रा बढ़ाने में अधिक होती है क्योंकि धातु की पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती । दूसरी तरफ यदि धातु की पूर्ति प्रचानक नई खानों की खोज के कारण बढ़ जाय तो उस धातु के मूल्य में वृद्धि कमी आ जाती है और प्रामाणिक मुद्रा के मूल्य तथा निश्चित मात्रा-धातु का मूल्य समान बनाए रखना कठिन हो जाता है ।

एक धातुमान की किस्में (Kinds of mono-metallism) .

एक धातुमान की दो मुख्य किस्में हैं—

1. स्वर्ण धातु मान (Gold Standard)
2. रजत मान (Silver Standard)

स्वर्णमान (Gold Standard) : वह मौद्रिक मान जिसमें मुद्रा के मौद्रिक मूल्य एवं निश्चित मात्रा-स्वर्ण की कीमत स्वतन्त्र बाजार में समान रखने का प्रयत्न किया जाता है । स्वर्णमान का विस्तृत विवेचन अग्रलेख अध्याय में किया जायेगा ।

रजत मान (Silver Standard) — रजत मान के अन्तर्गत मुद्रा के मौद्रिक मूल्य को एक निश्चित मात्रा-रजत की कीमत के बराबर रखा जाता है । इसमें चादी के सिक्के चलाने में होते हैं या मुद्रा चादी में परिवर्तनीय होती है । सिक्कों का चलाने होने पर स्वतन्त्र टलाई होती है । इसी के आधार पर विदेशों में मुग्तान किया जाता है । चादी के आयात-निर्वात पर प्रतिबन्ध नहीं होता ।

रजत मान का प्रयोग 1870 के पूर्व कई देशों में किया गया, परन्तु इसका व्यापक और दीर्घकालीन प्रयोग भारत और चीन में हुआ । भारतवर्ष में रजत मान 1835 से 1893 तक पूर्ण अर्थों में कायम रहा । 1870 के बाद चादी के मूल्य में निरन्तर कमी आने के कारण इसका संचालन कठिन हाता गया । 1870 के

बाद अनेक योरोपीय देशों ने स्वयंमान अपना लिया और भारत को विदेशी व्यापार में बठिनाई होने लगी। अन्त. भारत ने 1893 में रजत मान त्याग दिया परन्तु चादी की प्रामाणिक मुद्रा 1940 तक रखी गई। चीन में रजत मान की व्यवस्था 1935 तक रही।

द्विधातुमान (Bi metallism)

यदि किसी मौद्रिक व्यवस्था में दो धातुओं के सिक्कों की ढलाई की जा रही हो तथा दोनों ही धातुओं के सिक्के सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात में विनिमय के माध्यम के रूप में असीमित विधि ग्राह्य हो तो उसे द्विधातुमान कहा जायेगा।¹ द्विधातुमान उस समय तक सफलतापूर्वक चलता रहता है जब तक कानून द्वारा निर्धारित अनुपात अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित मूल्य अनुपात से भेद खाता है। कानूनी अनुपात एव वास्तविक मूल्य अनुपातों में अन्तर होते ही एक धातु की स्वतन्त्र ढलाई अधिक कराई जाने लगती है और बदले में दूसरी धातु प्राप्त कर उन देशों को भेजी जाने लगती है जहाँ उसका मूल्य अधिक है।

द्विधातुमान की विशेषताएँ (Characteristics of Bi-metallism) —

1 सोने और चादी दोनों ही धातुओं के सिक्के प्रामाणिक एवं असीमित विधिग्राह्य होते हैं।

2. दोनों धातुओं के सिक्कों की स्वतन्त्र ढलाई होती है।

3. दोनों धातुओं के सिक्कों का पारस्परिक विनिमय अनुपात सरकार द्वारा निश्चित कर दिया जाता है। इसी अनुपात में किसी भी धातु के सिक्कों द्वारा मुग्तान किया जा सकता है।

4 दोनों धातुओं के सिक्के पूर्णकाय मुद्रा होती हैं।

द्विधातुमान इस धारणा के कारण व्यवहार में लाया गया कि एक धातु की मुद्रा, (पूर्ति कम होने के कारण) मुद्रा सञ्चयन के दुष्परिणामों को बिना मौद्रिक माँग को पूरी नहीं कर सकती। अठारहवीं सदी के अन्त में अधिकांश योरोपीय देशों में द्विधातुमान का चलन था। जिन देशों में द्विधातुमान अपनाया गया था उनमें फ्रांस, यूनान, इटली, बेल्जियम तथा स्विटजरलैंड उल्लेखनीय हैं। अमेरिका ने भी द्विधातुमान 1792 में अपनाया था जब एक सोने का सिक्का पन्द्रह चाँदी के सिक्कों के बराबर माना गया। अमेरिका में द्विधातुमान 1879 तक चलता रहा। भारत

¹ If two metals can be coined freely as standard money and if the ratio between the value of the two metals in terms of the unit of account is fixed by law..., then we have a bimetallic standard or double standard" — Halm · "Monetary Theory" pp 108 - 109

मे द्विधातुमान 1835 के पूर्व चलन मे था । 1870 के बाद चादी का मूल्य गिरने के कारण दोनो धातुओ के मूल्यों के अनुपात को बनाये रखना कठिन हो गया और स्वर्ण-मान अपनाया जाने लगा । बीसवी सदी के प्रारम्भ तक द्विधातुमान समाप्त हो गया ।

द्विधातुमान के गुण (Merits of Bi metallism)

1. विदेशी व्यापार मे सहायक : द्विधातुमान से विदेशी मुग्तान मे सुगमता आ जाती है क्योंकि प्रत्येक देश को चाहे वे स्वर्णमान पर हो या रजतमान पर आसानी से मुग्तान किया जा सकता है । विदेशी मुग्तान के लिए विनिमय दर निर्धारित करने मे कोई कठिनाई नहीं होती है क्योंकि धातुओ के अनुपात मे दर निर्धारित की जा सकती है । द्विधातुमान के अन्तर्गत आयात-निर्यात स्वतन्त्र होते है इसलिए विनिमय दर मे भी अधिक परिवर्तन नहीं होते ।

2. उचित प्रारक्षित निधि सम्भव : एक धातुमान मे उचित मात्रा मे धातु कोष बनाये रखना कठिन होता है, परन्तु द्विधातुमान मे एक धातु दूसरी धातु की कमी को पूरी कर देती है । धातु की कमी के कारण कभी-कभी मुद्रा की परिवर्तन-शीलता का त्याग करना पडता है जैसा प्रथम महा युद्ध काल मे हुआ और इस कारण जनता का विश्वास उस मुद्रा से उठ जाता है और मौद्रिकमान असफल हो जाता है । द्विधातुमान मे दो धातुओ के होने के कारण परिवर्तनशीलता बनाए रखना आसान है ।

3. कीमत स्तर मे स्थायित्व द्विधातुमान के अन्तर्गत कीमत स्तर को स्थिर रखना आसान होता है क्योंकि एक धातु की पूर्ति के कम अधिक होने से कीमत पर जो प्रभाव पडता है दूसरी धातु की वृद्धि और कमी से वह समाप्त हो जाता है । सरकार भी दोनों के अनुपात को बनाये रखने मे प्रयत्नशील रहती है इसलिए मुद्रा के मूल्यों मे परिवर्तन अधिक नहीं होता । परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जब दोनो धातुओ के मूल्यों मे भिन्न-भिन्न अनुपात होता है तो देश उस धातु को खोने लगता है जिसका दूसरे देशो की तुलना मे कम मूल्य रखा है ।

4. बैंको का कोष निर्धारण कम खर्चीला : द्विधातुमान के अन्तर्गत दोनो ही धातुओ के सिक्के असमीत विधि-ग्राह्य होने के कारण बैंक किसी भी धातु को कोष मे रख सकते हैं । दो धातुओ के सिक्को की ढलाई स्वतन्त्र होने से कुल मुद्रा की मात्रा भी अधिक होती है साथ निर्माण अधिक होता है और उद्योगो तथा व्यापार को सस्ती मुद्रा उपलब्ध होती है ।

द्विधातुमान के दोष

(Demerits of Bi-metallism)

1. प्रेशम का नियम क्रियाशील - द्विधातुमान मे प्रेशम का नियम शीघ्र क्रियाशील हो जाता है क्योंकि सरकार द्वारा धोपित अनुपात और बाजार मे प्रचलित

अनुपात में अन्तर आते ही एक धातु की मुद्रा दूसरी धातु की मुद्रा की अपेक्षा लाभप्रद हो जाती है, जो धातु बाजार में मँहगी है, उसकी मुद्रा चलन के बाहर चली जाती है और उसे गला कर उसका धातु के रूप में विनय होने लगता है।

2. अपव्यय : द्विधातुमान में खर्च बहुत होता है क्योंकि दोनों प्रकार के सिक्कों की ढलाई का व्यय बहन करना पड़ता है तथा सिक्कों के चलन में रहन क कारण उनका ह्रास होता है।

3. सट्टेबाजी को प्रोत्साहन सोने या चादी की पूर्ति में परिवर्तन होते ही उनके मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के अनुमान के आधार पर सट्टेबाजी की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।

4. क्षतिपूर्ति नियम का लागू न होना : वास्तव में द्विधातुमान में जब एक धातु की कमी हो जाती है तो उसकी पूर्ति दूसरी धातु द्वारा नहीं हो पाती। जिस धातु की मात्रा कम हो जाती है उसकी मुद्रा चलन से ही बाहर हो जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जब दो देशों में इन धातुओं के मूल्यों का अनुपात अलग होना है तो द्विधातुमान का बनाये रखना कठिन हो जाता है।

द्विधातुमान के दोषों के दूर करने के सुझाव (Suggestions for removing defects of B-metallism) प्रथम, सुझाव यह दिया जाता है कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय द्विधातुमान ही स्थापना हो जाय जिससे क्षतिपूरक क्रिया सफलता से लागू हो सके और दो धातुओं की टकसाल दर तथा बाजार दर विश्व स्तर पर एक ही अनुपात में होगी। उन्नीसवीं सदी के अन्त में किये गये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलनों में यह सुझाव दिया गया था।

द्वितीय सुझाव यह दिया जाता है कि दोनों धातुओं के बाजार मूल्य में परिवर्तन होने के साथ-साथ घोषित अनुपात में भी उसी प्रकार परिवर्तन कर देना चाहिए। ऐसा करने से प्रेशम के नियम से बचा जा सकता है।

जिस प्रकार के द्विधातुमान का अब तक बणन किया गया है उसे शुद्ध द्विधातुमान कहा जाता है। परन्तु जैसा कि पहले बताया गया है इस प्रकार के द्विधातुमान की प्रमुख कठिनाई दोनों धातुओं के सिक्कों के पारस्परिक विनिमय अनुपात को बनाये रखने की है। प्रायः बाजार में जो इन धातुओं का पारस्परिक अनुपात होता है वह सरकारी अनुपात से भिन्न होता है और कई कारणों से सरकार उस पर नियन्त्रण नहीं रख पाती। इसलिए द्विधातुमान को अन्य रूपों में भी अपनाया गया, जिनका वर्णन नीचे किया गया है।

पगु द्विधातुमान (Limping Standard) : जब किसी देश में सोने और चादी दोनों ही धातुओं के प्रामाणिक सिक्के असीमित विधिग्राह्य मुद्रा के रूप में

चलन में हो और उनका पारस्परिक विनिमय अनुपात सरकार द्वारा निश्चित हो, परन्तु दोनों में से केवल एक धातु की स्वतन्त्र ढलाई की व्यवस्था हो तो उसे पगु द्विधातुमान कहा जाता है। जो धातु सस्ती हो जाती है उसकी स्वतन्त्र ढलाई नहीं की जाती। इसका उद्देश्य सस्ती धातु के सिक्कों की ढलाई बन्द कर विनिमय अनुपात की स्थिरता प्रदान करना होना है। इस प्रकार पगु-द्विधातुमान की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं—

- 1 सोने तथा चादी के सिक्के प्रामाणिक मुद्रा के रूप में चलन में रहते हैं।
- 2 दोनों का धातु मूल्य एवं मौद्रिक मूल्य बराबर रहता है और वे असंमित विधिग्राह्य होते हैं।
- 3 दोनों का पारस्परिक विनिमय अनुपात कानून द्वारा निश्चित कर दिया जाता है।
- 4 दोनों में से अपेक्षाकृत महंगी धातु की स्वतन्त्र ढलाई होती है एवं अपेक्षाकृत सस्ती धातु की सीमित ढलाई होती है।

समानान्तर द्विधातुमान (Parallel Standard) यह द्विधातुमान भी शुद्ध द्विधातुमान का परिवर्तित रूप है। इसमें भी दोनों धातुओं के सिक्के प्रामाणिक मुद्रा के रूप में असंमित विधिग्राह्य होते हैं तथा उनकी स्वतन्त्र ढलाई की व्यवस्था रहती है, परन्तु दोनों धातुओं के सिक्कों का पारस्परिक विनिमय अनुपात सरकार कानून द्वारा निश्चित नहीं करती। दोनों का पारस्परिक विनिमय अनुपात बाजार भाव के अनुसार निश्चित होता है। इसलिए विनिमय अनुपात निरन्तर परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार समानान्तर द्विधातुमान की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

- 1 दोनों धातुओं के सिक्के प्रामाणिक मुद्रा के रूप में चलन में होते हैं।
- 2 दोनों की स्वतन्त्र ढलाई होती है।
- 3 दोनों असंमित विधिग्राह्य एवं पूर्णकाय (full bodied) होते हैं।
- 4 दोनों का पारस्परिक विनिमय अनुपात बाजार भाव के अनुसार निर्धारित होता है।

मिश्रित धातुमान (Symmetallism)

मिश्रित धातुमान एक काल्पनिक मान है क्योंकि इसका किसी देश द्वारा वास्तविक प्रयोग नहीं किया गया। वास्तव में उन्नीसवीं सदी के अन्तिम चरण में सोने और चादी की कमी के कारण तथा द्विधातुमान में लागू होने वाले प्रेशम के नियम से बचने के विकल्प के रूप में अनेक अर्थशास्त्रियों ने, जिनमें माशल का नाम प्रमुख है, यह सुझाव दिया कि दोनों ही धातुओं के मिश्रण को मौद्रिक मान के रूप में अपनाया जाय। इस योजना के अन्तर्गत सरकार एक निश्चित अनुपात में मिलाई

गई सोने व चाँदी की छड़ों को अथवा उसी अनुपात में अलग-अलग धातुओं को मुद्रा की एक दी हुई मात्रा द्वारा खरीदने अथवा बेचने के लिए तैयार रहती है। मिश्रित धातुमान के बारे में मतभेद भी हैं। कई लोगों के अनुसार सोने चाँदी क अलावा अन्य धातुओं के संयोग (combination) की व्यवस्था भी अपनाई जा सकती है।

समष्टि वस्तुमान (Composite Commodity Standard)

यदि मिश्रित धातुमान का सैद्धांतिक प्रसार (Extension) किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि प्रामाणिक मौद्रिक ईकाई में धातुओं को ही नहीं अपितु अर्थ व्यवस्था में उत्पादित सभी चुनी हुई वस्तुएँ सम्मिलित हों। ड्विटलमी, फ्रीडमन, हरमन ने अपनी पुस्तक 'Money and Banking' में लिखा है—

“...Composite commodity money resembles symmetallism, but the standard unit, instead of consisting of metals only would be made up of an assorted list of staple commodities”

परीक्षा प्रश्न और उनके संकेत

1. द्विधातुमान तथा एक धातुमान की विशेषताओं की विवेचना कीजिए और बताइये कि द्विधातुमान, एक धातुमान की अपेक्षा मूल्य-स्तर को स्थायी रखता है।
—(राजस्थान 1955, आगरा बी० काम० 1961)

[संकेत—प्रथम भाग में द्विधातुमान तथा एक धातुमान का अर्थ समझाते हुए उनके मुख्य लक्षण बताइये। दूसरे भाग में द्विधातुमान में दो धातुओं के सिक्के होने के कारण मुद्रा की कुल पूर्ति में अधिक उच्चावचन होने की सम्भावना नहीं होती। अतः द्विधातुमान में मूल्य-स्तर अधिक स्थायी रहता है।]

2. द्विधातुमान से क्या अभिप्राय है? इसके गुणों तथा अवगुणों का विवेचन कीजिए।
—(आगरा 1959, गोरखपुर 1959, विक्रम 1959)

[संकेत—प्रथम भाग में द्विधातुमान की परिभाषा देते हुए इसकी मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में द्विधातुमान के लाभ तथा हानियाँ बताइये।]

5

ग्रेशम का नियम (Gresham's Law)

"May it please your Majesty to understand that the first occasion of the fall of the exchange did grow by the king's Majesty, your late father, in debasing his coin from VI ounces fine to III ounces fine Whereupon, the exchanges fell from XXVI s VIII d to XIII s IV d which was the occasion that all your fine gold conveyed out of this your realm."

Sir Thomas Gresham.

मुद्रा-चलन के सम्बन्ध में मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियम के रूप में प्रतिपादित करने का श्रेय ब्रिटिश अर्थशास्त्री सर थॉमस ग्रेशम को है। इस नियम को ग्रेशम का नियम कहा जाता है जो वास्तव में मुद्रा के चलन का स्वाभाविक नियम है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम अपने शासन काल में निकुष्ट सिक्कों के चलन से बहुत चिन्तित थी क्योंकि इससे कीमतों में वृद्धि हो रही थी और व्यापारी वर्ग इसे तोल कर भुगतान लेने की पद्धति अपनाते लगा था। स्थिति को सुधारने के दृष्टिकोण से नये सिक्कों को ढलवा कर प्रचार में रखने का प्रयत्न किया गया तथा यह आशा की गई कि लोग नए पूर्ण मूल्य सिक्कों का प्रयोग करेंगे तथा पुराने और निकुष्ट सिक्के स्वतः प्रचार से बाहर हा जायेंगे। परन्तु परिणाम इसके ठीक विपरीत हुआ, नए सिक्क प्रचार से गायब होते गए। इस स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए महारानी के आधिक सलाहकार सर थॉमस ग्रेशम ने मानव स्वभाव पर आधारित मुद्रा चलन के नियम की व्याख्या की। इसके अनुसार "बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है परन्तु अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर नहीं कर पाती।" (Bad money drives out good, but good money does not drive out bad.) इस प्रकार इस नियम के अनुसार यदि अच्छी और बुरी मुद्राएँ साथ-साथ चलन में हों तो अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि बुरी मुद्रा का तात्पर्य ऐसी मुद्रा से है जिसका धार्मिक मूल्य अच्छी मुद्रा की अपेक्षा कम है ("Bad money or over valued money is

that which contains less bullion value for a stated face value than the good or undervalued money.”

ग्रेशम के नियम की व्याख्या डा० मार्शल ने भी अपनी पुस्तक Money, Credit and Commerce में की है। मार्शल ने इस नियम की परिभाषा देते समय इसकी सीमाओं का भी उल्लेख किया है। इनके अनुसार “यदि निकृष्ट मुद्रा सीमित मात्रा में न हो तो वह उत्कृष्ट मुद्रा को चलन से बाहर निकाल देती है।”¹

कारण—सर टामस ग्रेशम ने इस नियम की व्याख्या धातु मुद्रा के सदम में ही की थी। धातु मुद्रा में इस नियम के लागू होने के कई कारण हैं—

1 घटिया मुद्रा के चलन में रहने का कारण यह है कि लोग पूर्ण मूल्य मुद्रा को जमा करने लगते हैं इसलिए वह चलन से बाहर हो जाती है तथा घटिया मुद्रा का प्रयोग होता है।

2 पूर्ण मूल्य मुद्रा को गलाकर उसका धातु के रूप में प्रयोग होने लगता है।

3 पूर्ण मूल्य मुद्रा का प्रयोग विदेशी भुगतानों के लिए किया जाने लगता है और घटिया मुद्रा आंतरिक चलन में रह जाती है।

इस प्रकार उपरोक्त कारणों के आधार पर एक धातुमान में इस नियम की व्याख्या की गई, परन्तु वास्तव में यह नियम द्विधातुमान एवं पत्र मान में भी लागू होता है।

द्विधातुमान—द्विधातुमान में दोनों धातुओं के सिक्कों का अनुपात कानून द्वारा निश्चित रहता है परन्तु बाजार में दोनों धातुओं के मूल्य का अनुपात कानून द्वारा निश्चित अनुपात से भिन्न भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में एक धातु का अधि मूल्य हो जाता है और दूसरी का अपेक्षाकृत अधिमूल्य। जिस सिक्के का अधि मूल्य (Overvalued) हो जाता है वह चलन में रहता है और जिसका अधिमूल्य (Undervalued) होता है वह चलन के बाहर चला जाता है। उदाहरण के लिए यदि 1 स्वर्ण मुद्रा को 15 चांदी की मुद्राओं के बराबर घोषित किया गया हो परन्तु बाजार में 1 स्वर्ण मुद्रा का मूल्य 16 चांदी की मुद्राओं के मूल्य के बराबर है तो ऐसी परिस्थिति में 1 स्वर्ण मुद्रा को गलाकर उसका बाजार में 16 चांदी की मुद्रा प्राप्त की जा सकती है और सरकार से 16 चांदी के सिक्कों में से 15 सिक्कों को बदले 1 स्वर्ण का सिक्का प्राप्त किया जा सकता है और 1 चांदी के सिक्के का लाभ उठाया जा सकता है। इस प्रकार स्वर्ण के सिक्के चलन के बाहर चले जायेंगे और चांदी के सिक्के चलन में रह जायेंगे।

¹ “An inferior currency, if not limited in quantity, will drive out the superior currency.”

पत्रमान—पत्र मान में प्रेशम का नियम कोई विशेष महत्व नहीं रखता। परन्तु मानव स्वभाव के कारण यह नियम पत्र मान में भी लागू होता है। सामान्यतया जनता में नए नोटों के प्रति आकर्षण होता है और जब किसी के पास नए तथा पुराने दोनों प्रकार के नोट होते हैं तो वह पहले पुराने नोटों को ही खर्च करना चाहता है इसलिए उनका चलन वेग अधिक होता है। यदि पत्र मान और धातु मुद्रा दोनों चलन में हों तो निःसंदेह पत्र मुद्रा चलन में रहती है और धातु मुद्रा की प्रकृति चलन से बाहर हो जाने की होती है।

नियम के अपवाद (Exceptions to the Law) — यह नियम अर्थ-शास्त्र के अन्य नियमों की तरह केवल सामान्य प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। यह सार्वभौमिक नहीं है, कई परिस्थितियों में अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की मुद्राएँ चलन में होती हैं।

1. यदि निकृष्ट मुद्रा की मात्रा बहुत कम हो तो यह नियम लागू नहीं होता क्योंकि थोड़ी मात्रा में होने के कारण वह उस देश के सभी प्रकार के भुगतानों का माध्यम नहीं बन सकती और अच्छी मुद्रा को आवश्यक रूप से प्रयोग करना होगा।

2. यदि समाज द्वारा निकृष्ट मुद्रा का बहिष्कार कर दिया जाय तो भी वह चलन में नहीं रह सकती तथा अच्छी मुद्रा ही चलन में प्रयोग की जायेगी। निकृष्ट मुद्रा में सर्व स्वीकार्यता का गुण समाप्त हो जायेगा।

3. यदि जनता किसी मुद्रा का दीर्घ काल तक प्रयोग करते रहने के कारण उसकी अभ्यस्त हो और उसकी सामान्य स्वीकार्यता में कोई संदेह न करती हो तथा मुद्रा को विनिमय माध्यम के अतिरिक्त मूल्यहीन समझने की स्थिति में पहुँच गई हो तो भी यह नियम लागू नहीं होगा।

4. यदि देश में बैंकिंग का विकास हो गया हो और लोगों में बैंकिंग भावना घर कर गई हो तो यह नियम प्रभावहीन होगा।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रेशम के नियम के दो पहलू हैं, अच्छी मुद्रा का चलन से बाहर होना और निकृष्ट मुद्रा के चलन वेग में वृद्धि होना। विनिमय माध्यम में अविश्वास पैदा होने की स्थिति में उसका चलन वेग बढ़ जाता है लोग शीघ्रतापूर्वक उसे हस्तान्तरित करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अच्छी मुद्रा निश्चित रूप से चलन से बाहर चली जायेगी। अतः अपवादों के होते हुए भी यह नियम सामान्यतः लागू रहता है।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके सकेत

(1) मुद्रा सम्बन्धी ग्रेशम के नियम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए ।
भारतीय चलन प्रणाली से आवश्यक उदाहरण दीजिए ।

(राजस्थान बी० काम०, 1961)

[सकेत—ग्रेशम के नियम की व्याख्या कीजिए तथा उसकी सीमाओं का सकेत करते हुए यह बताइये कि आधुनिक पत्र मुद्रा व्यवस्था में इसका कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है । भारतीय चलन इतिहास से उदाहरण देकर अपने कथन की पुष्टि कीजिए ।]

(2) निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए —

(i) ग्रेशम का नियम

(ii)

(iii)

(iv)

(राजस्थान बी० काम०, 1968)

(आगरा 1968)

[सकेत — सक्षेप में ग्रेशम के नियम की व्याख्या, लागू होने के कारण, लागू होने के क्षेत्र तथा अपवादों की चर्चा कीजिए ।]

(3) “बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है।” व्याख्या कीजिए ।

(नागपुर 1960)

अथवा

ग्रेशम के नियम पर टिप्पणी लिखिए ।

[सकेत—प्रथम भाग में ग्रेशम के नियम की परिभाषायें देते हुए उसकी व्याख्या कीजिए । दूसरे भाग में नियम के लागू होने का क्षेत्र तथा नियम की सीमायें बताइये ।]

स्वर्ण मान (Gold Standard)

"The Gold Standard is a jealous God It will work, provided it is given exclusive devotion"

Crowther

स्वर्ण मान (Gold Standard) धातु मान के इतिहास में सर्वाधिक प्रचलित रूप स्वर्ण मान का ही रहा है। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में स्वर्णमान का प्रारम्भ व्यापक रूप में हुआ। सर्वप्रथम स्वर्ण मान का प्रारम्भ इंग्लैंड ने 1916 में किया परन्तु उन्नीसवीं सदी के अन्त तक ससार के प्रायः सभी देशों में स्वर्ण मान प्रचलित हो गया था।

स्वर्णमान एक ऐसी मौद्रिक व्यवस्था है जिसमें देश की प्रामाणिक अथवा प्रधान मुद्रा की इकाई का मूल्य किसी न किसी रूप में, स्वर्ण की निश्चित मात्रा के बराबर रखा जाता है। प्रामाणिक मुद्रा या तो निश्चित मात्रा और शुद्धता के बराबर स्वर्ण की बनी होती है या निश्चित मात्रा और शुद्धता के स्वर्ण में परिवर्तनीय होती है। विस्तृत अर्थों में यह भी कहा जा सकता है कि स्वर्णमान के अन्तर्गत स्वर्ण की स्वतन्त्र टलाई होती है परन्तु स्वर्णमान के इतिहास के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्वतन्त्र टलाई इसकी अनिवार्य विशेषता नहीं है। राबर्टसन के अनुसार 'स्वर्ण मान एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई देश अपनी मौद्रिक इकाई और एक निश्चित मात्रा स्वर्ण का मूल्य बराबर रखता है।'¹ इसी प्रकार हाट्टे का मत है कि स्वर्ण मान के अन्तर्गत प्रधान मुद्रा का मूल्य स्वर्ण से जोड़ दिया जाता है। जे. एल. हैन्सन के अनुसार "A country is said to be on the gold standard when the basic unit of its currency consists of a definite weight of gold of a certain degree of fineness."²

¹ "Gold Standard is a state of affairs in which a country keeps the value of its monetary unit and the value of a defined weight of gold at an equality with one another."

² "Monetary theory and Practice" P. 144

स्वर्ण मान की उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि स्वर्ण मान के अन्तर्गत देश की प्रमुख मुद्रा का स्वर्ण के साथ निश्चित सम्बन्ध होता है। स्वर्ण और प्रमुख मुद्रा का यह सम्बन्ध कई प्रकार से रखने का प्रयत्न किया गया जिसके कारण स्वर्ण मान ने कई रूप ग्रहण किया। स्वर्ण मान के कुछ प्रमुख रूपों का वर्णन नीचे दिया गया है।

स्वर्ण मान के प्रमुख रूप (द्वितीय महायुद्ध के पूर्व)

1. स्वर्ण चलन मान (Gold Coin Standard or Gold Currency Standard) :

Br - 5/175

प्रथम महायुद्ध के पूर्व स्वर्ण मान का यही रूप प्रचलित था। इस प्रकार के स्वर्ण मान में निश्चित तौर पर शुद्धता के सिक्के ही देश की प्रमुख एवं प्रामाणिक मुद्रा की इकाई होते हैं। इन सिक्कों का धात्विक एवं मौद्रिक मूल्य एक होता है। इस प्रकार प्रामाणिक मुद्रा का स्वर्ण के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता है। इस प्रकार के सिक्कों की स्वतन्त्र ढलाई होती है, स्वर्ण के निर्यात एवं आयात पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होता। असीमित विधि ग्राह्य होते हैं। यदि स्वर्ण चलन मान के अन्तर्गत अन्य प्रकार की पत्र मुद्रा या माकेतिक मुद्रा चलन में रहती है तो वह प्रामाणिक सिक्के में परिवर्तनीय होती है। किसी को भी स्वर्ण रखने या गलाने या किसी प्रकार प्रयोग करने की पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है। *75845*

इस प्रकार का स्वर्णमान 1914 के पूर्व इंग्लैंड में प्रचलित था। ब्रिटिश 'सावरेन' में 123 27447 ग्रैन का $\frac{1}{10}$ शुद्ध सोना था। अमेरिका में भी 1934 के पूर्व इसी प्रकार का स्वर्णमान था और डालर में 25.8 ग्रैन का $\frac{9}{10}$ शुद्ध सोना था। फ्रांस में भी प्रथम महायुद्ध के पूर्व इसी प्रकार का स्वर्ण मान था।

स्वर्ण मान के इस रूप में प्रचलित रहने का प्रमुख लाम यह था कि मौद्रिक व्यवस्था में सरकार को हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं मिलता था। इसका दूसरा गुण यह था कि इससे स्वर्ण के बाजार मूल्य में स्थिरता रहती थी। अनेक देशों द्वारा इस प्रकार का स्वर्ण मान अपनाने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान की स्थापना हुई और विनिमय दर में स्थायित्व प्राप्त किया जा सका। परन्तु इन गुणों के साथ इसमें अनेक दोष भी थे। इसका सबसे बड़ा दोष इसका अत्यधिक खर्चीला होना था। बहुमूल्य धातु चलन में रहने के कारण घिसती थी। एकसाल का व्यय अनावश्यक था। विदेशी व्यापार की अवस्था के अनुसार मुद्रा की मात्रा में घट बढ़ होती थी अर्थात् मुद्रा पर विदेशों की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता था जिससे आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था अनावश्यक रूप से अस्त-व्यस्त हो जाती थी। यदि देश की आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए अधिक मुद्रा की आवश्यकता महसूस होती थी तो भी सोने के

अभाव में मुद्रा की मात्रा नहीं बढ़ाई जा सकती थी अर्थात् उचित लोच की मात्रा का अभाव था ।

2 A स्वर्ण पिण्डमान (Gold Bullion Standard) :

प्रथम महायुद्ध के बाद 1925 में पुनः जब स्वर्ण मान की पुनर्स्थापना हुई तो उसमें स्वर्ण चलन मान के दोषों से बचने का प्रयास किया गया । स्वर्ण मान का एक नवीन एवं सुधरा हुआ रूप अपनाया गया जो स्वर्ण चलन मान की अपेक्षा अधिक मितव्ययी था । इस रूप में स्वर्ण मान के अन्तर्गत चलन में सोने के सिक्के नहीं थे और न ही उनकी स्वतन्त्र ढलाई की व्यवस्था थी । विनिमय माध्यम के रूप में नोटों और सांकेतिक सिक्कों का प्रयोग किया गया । इन नोटों और सिक्कों के बदले सोने के सिक्के देने की भी व्यवस्था नहीं थी परन्तु प्रामाणिक नोटों के बदले सरकार स्वर्ण पिण्ड देने को तैयार थी बशर्ते वह एक निश्चित परिमाण से कम न हो । इसी प्रकार घोषित दर पर स्वर्ण पिण्ड खरीदने को भी तैयार रहती थी । सोने को बाहर भेजने या मगाने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी ।

इस प्रकार का स्वर्ण पिण्डमान इंग्लैंड में 1925 से 1931 तक प्रचलित था और बैंक ऑफ इंग्लैंड 400 ग्राँटों से अधिक का स्वर्ण पिण्ड बेचने और खरीदने को तैयार रहता था परन्तु इससे कम के नोटों के बदले स्वर्ण पिण्ड नहीं प्राप्त किया जा सकता था । फ्रांस ने भी 1928 में स्वर्ण पिण्डमान अपनाया ।

स्वर्ण पिण्डमान में स्वर्ण चलन मान की अच्छाईयों के साथ साथ मितव्ययिता का गुण भी था । इसमें शत प्रतिशत स्वर्णकोप की आवश्यकता नहीं थी और न ही टक्काल का व्यय था । शत प्रतिशत कोप की आवश्यकता न होने के कारण इसमें लोच की मात्रा भी विद्यमान थी जो एक अच्छे मौद्रिक मान का आवश्यक गुण है । किन्तु स्वर्ण पिण्डमान भी बाह्य कारणों के प्रभाव से अर्थ-व्यवस्था को मुक्त नहीं रख पाता था, यही इसका सबसे बड़ा दोष था ।

2 B सीमित स्वर्ण पिण्डमान (Limited Gold Bullion Standard) :

1934 में अमेरिका में डॉलर का स्वर्ण मूल्य कम कर दिया गया और चलन से स्वर्ण के सिक्के हटा लिये गये तथा सिक्कों की ढलाई बन्द कर दी गई । उसी समय से यह व्यवस्था कर दी गई कि ट्रेजरी, लाइसेंस प्राप्त स्वर्ण रखने वालों से 35 डॉलर प्रति औंस शुद्ध सोना खरीद सकती है और भुगतान के रूप में विक्रेता को ट्रेजरी ड्राफ्ट दिया जाता था । इस प्रकार स्वर्ण पिण्ड मान स्वतन्त्रतापूर्वक जमा मुद्रा में परिवर्तित कराया जा सकता है । परन्तु ब्रिटिश स्वर्ण पिण्डमान की तरह सरकार स्वर्ण बेचने के लिये तैयार नहीं है । ट्रेजरी से केवल औद्योगिक कार्यों या नियति के लिये ही स्वर्ण प्राप्त हो सकता है । अमेरिका का स्वर्ण पिण्डमान अग्रलिखित विशेषताओं से युक्त है :

1. व्यक्ति व्यक्तिगत सचय के लिये स्वर्ण या स्वर्ण सिक्के नहीं प्राप्त कर सकता ।

2. व्यक्ति या बैंक निजी निर्यात (Private Export) के लिए मुद्रा को स्वर्ण में नहीं बदलवा सकते ।

3. ट्रेजरी द्वारा स्वर्ण का ऋय-विक्रय ट्रेजरी सचिव के विवेक (discretion) पर निर्भर करता है ।

3. स्वर्ण विनिमय मान (Gold Exchange Standard) —

स्वर्ण विनिमय मान स्वर्ण पिण्ड मान से मितव्ययी है । इस प्रकार के मान में एक देश अपनी मुद्रा को परोक्ष रूप से स्वर्ण से सम्बन्धित करता है । वह किसी ऐसे देश की मुद्रा को अपने कोष में रखता है जो स्वर्ण मान पर आधारित है । देश की प्रमुख मुद्रा स्वर्ण के सिक्के या पिण्डों में परिवर्तनीय नहीं होती, परन्तु केन्द्रीय बैंक यह उत्तरदायित्व लेता है कि विदेशों में भुगतान करने के लिए अन्य देश की मुद्रा अपने देश की मुद्रा के बदले में उपलब्ध करेगा । इस प्रकार के स्वर्ण मान को स्वर्ण चलन विनिमय मान (Gold currency Exchange Standard) भी कहा जाता है । यदि सम्बन्धित देश कई ऐसे देशों की मुद्रा अपने कोष में रखता है जो स्वर्ण मान पर आधारित हैं और भुगतान के लिए उन्हें देने का उत्तरदायित्व स्वीकार करता है तो उसे स्वर्ण विनिमय मान कहा जाता है । परन्तु मौलिक रूप से दोनों एक ही हैं और स्वर्ण विनिमय मान के नाम से ही जाने जाते हैं ।

इस प्रकार का स्वर्ण मान फिलीपीन में 1903 में अपनाया गया । देश के अन्दर चाँदी का पीसो (Silver Peso) चलन में था परन्तु स्वर्ण पीसो, जिसका वास्तव में कोई सिक्का नहीं था, प्रामाणिक मौद्रिक इकाई बनाया गया और उसका मूल्य अमेरिका की मुद्रा के पचास सप्ट रखा गया । 1934 के बाद इसका रूप बदल कर डालर विनिमय मान हो गया । परन्तु स्वर्ण विनिमय मान का वास्तविक रूप, 1920 के बाद जब स्वर्ण मान को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया गया, स्पष्ट रूप से सामने आया और अनेक देशों में स्वर्ण मान को इस रूप में अपनाया गया । वैसे भारतवर्ष में स्वर्ण विनिमय मान सबसे अधिक कुशलतापूर्वक संचालित किया गया था । 1914 के पूर्व तथा 1924 से 1931 तक भारत में स्वर्ण विनिमय मान ही चलन में था ।

स्वर्ण विनिमय मान जब तक अपेक्षाकृत छोट देशों द्वारा अपनाया गया तब तक यह पूर्ण रूप से स्वर्ण मान पर आधारित देशों के साथ विनिमय दर में स्थायित्व लाने में सफल रहा । लेकिन जब यह योरोप के देशों में विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग होने लगा तो इसकी कई नुटियाँ सामने आईं । इसका एक बड़ा दोष यह था कि राष्ट्रीय मुद्रा विदेशी मुद्राओं पर आधित हो जाती थी । इसके अलावा केन्द्रीय बैंक को

विदेशी मुद्रा की काफी मात्रा कोप में रखनी पड़ती थी। यह कोप सम्बन्धित देश के (विदेशी मुद्रा वाला देश जिसकी मुद्रा से परोक्ष रूप में सम्बन्ध जोड़ा जाता था) केन्द्रीय बैंक के पास ही रखा जाता था और आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग किया जाता था। जो देश स्वर्ण विनिमय मान पर होते थे अपने कोप बढ़ाते जाते और अपने आयातों को सदैव कम रखने की नीति अपनाते। परन्तु इस प्रकार उनका कोप बढ़ने में स्वर्ण मान पर आधारित देश जो डिफाजिटरी का काम करते उनका कठिनाई होती। उनकी मौद्रिक व्यवस्था तथा बैंक व्यवस्था पर स्वर्ण बाहर जाने का (उतनी बड़ी मात्रा में) भयानक प्रभाव पड़े। इंग्लैंड को इसी कठिनाई के कारण 1931 में स्वर्ण मान त्याग देना पड़ा। इसके साथ ही स्वर्ण विनिमयमान पर आधारित देश को उस समय भयानक हानि होती, जब स्वर्ण मान पर आधारित देश स्वर्ण में भुगतान करना बन्द कर देता। 1931 में इंग्लैंड के स्वर्ण मान त्याग देने पर तथा स्वर्ण भुगतान बन्द करने पर फ्रांस को बड़ी मात्रा में हानि उठानी पड़ी।

4 स्वर्ण कोप मान (Gold Reserve Standard) :

स्वर्ण कोप मान की स्थापना का उद्देश्य विनिमय दर में स्थिरता लाना था। 1931 में ब्रिटेन, 1933 में अमरीका तथा 1936 में फ्रांस द्वारा स्वर्ण मान का त्याग कर देने से उन देशों की विनिमय दर की स्थिरता समाप्त हो गई थी। अपनी-अपनी स्थिति को ठीक रखने के लिए इन देशों ने विनिमय समानीकरण कोप (Exchange Equalisation Fund) की स्थापना अलग-अलग समय पर की जिसका उद्देश्य विनिमय दर को स्थिर रखना था। 1936 में इन तीन देशों में (ब्रिटेन, अमरीका, फ्रांस) के बीच एक समझौता हुआ जिसे त्रिपक्षीय समझौता (Tripartite Agreement) कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार तीनों ने विनिमय दर को विनिमय समानीकरण कोपो की सहायता से स्थिर रखने का वचन दिया। बाद में इस समझौते में अन्य देश (वल्जियम, हॉलैंड तथा स्विटजरलैंड) भी सामिल हुए।

इस प्रणाली में स्वर्ण को विनिमय का माध्यम या मूल्य का मापक नहीं बनाया जाता और न ही कागजी नोटों के बदले स्वर्ण देने की व्यवस्था ही की जाती है। स्वर्ण के आयात तथा निर्यात की स्वतन्त्रता नहीं होती। केवल सरकार द्वारा ही मौद्रिक कार्यों के सम्बन्ध में स्वर्ण आयात या निर्यात किया जा सकता है। इस प्रणाली में विनिमय समानीकरण कोप (Exchange Equalisation Fund) की स्थापना प्रत्येक सदस्य देश के लिए आवश्यक है।

इस व्यवस्था के अन्तर्गत जब किसी देश के समानीकरण कोप में विदेशी मुद्रा की पूर्ति बहुत बढ़ जाती तो सम्बन्धित देश से उसकी मुद्रा के बदले स्वर्ण प्राप्त किया जा सकता था। इस प्रकार एक देश में दूसरे देश से सोने का स्थानान्तरण

होता रहता था। परन्तु इस प्रकार के स्थानान्तरणों को गोपनीय रखने का प्रयास किया जाता था।

इस व्यवस्था का एक विशिष्ट लाभ यह था कि विनिमय दर में स्थिरता भी रखी जा सकती थी और आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय हितों के सामन घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं थी। आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था पर विदेशी विनिमय की मांग तथा पूर्ति की घट-बढ़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। परन्तु यह व्यवस्था अधिक दिनों तक कार्य नहीं कर सकी क्योंकि 1939 में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया और असामान्य स्थितियों के कारण समाप्त हो गई।

स्वर्ण मान का रूप (द्वितीय महायुद्ध के बाद)

स्वर्ण समतामान (Gold Parity Standard) इस प्रकार के मान की स्थापना द्वितीय महायुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के साथ हुई। प्रत्येक सदस्य देश को अपनी मुद्रा का स्वर्ण मूल्य घोषित करना पड़ता है तथा सदस्यों के बीच विनिमय दर इन्हीं घोषित मूल्यों के अनुपात में निश्चित होती है। चूंकि विनिमय दर का आधार स्वर्ण समताएँ होनी हैं इसलिए इसे स्वर्ण समता मान कहा जाता है। वास्तव में यह एक प्रकार का विनिमय मान (Exchange Standard) है क्योंकि इसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान स्वर्ण में नहीं किये जाते, बल्कि विदेशी विनिमय द्वारा किये जाते हैं और विनिमय दर को स्थिर रखा जाता है। विभिन्न मुद्राओं की स्वर्ण समता की घोषणा केवल विभिन्न मुद्राओं के सम्बन्ध स्थापित करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

इस व्यवस्था में आन्तरिक क्षेत्र में मुद्रा का स्वर्ण से नाम मात्र का भी सम्बन्ध नहीं होता और प्रत्येक देश अपनी मौद्रिक नीति का स्वतन्त्र रूप से चयन करता है। किसी अन्य देश का इस विषय में कोई हस्तक्षेप नहीं होता।

इस प्रणाली में लोच का भी अभाव नहीं है क्योंकि मौलिक असंतुलन (Fundamental disequilibrium) की स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष स्वर्ण समता में परिवर्तन करने की भी शक्ति देता है। विनिमय दर की स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से सदस्यों को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण भी प्राप्त करने का प्रावधान है।

स्वर्ण मान के उद्देश्य अथवा कार्यों (Objectives of Gold Standard)

स्वर्ण मान चाहे जिस किसी रूप में प्रचलित हो आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में, कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही अपनाया जाता है। इन क्षेत्रों में स्वर्ण मान के क्या उद्देश्य हैं और उनको कैसे प्राप्त किया जाता है इसका वर्णन नीचे किया जायेगा।

आन्तरिक क्षेत्र में स्वणमान—

1. नकद मुद्रा की मात्रा : आन्तरिक क्षेत्र में स्वर्ण मान का प्रमुख उद्देश्य मुद्रा के परिमाण एवं आन्तरिक मूल्य (Internal Value of Money) को नियंत्रित करना है। जब कोई देश स्वर्ण मान पर आधारित होता है तो नकद मुद्रा की मात्रा स्वर्ण के स्टॉक द्वारा निर्धारित होती है। यदि स्वर्ण चलन मान है तो स्वर्ण के सिक्कों की ढलाई के लिए स्वर्ण चाहिए और यदि उस देश में नकद का तात्पर्य केवल सिक्कों में है तो स्वर्ण के प्राप्त स्टॉक पर ही नकद की मात्रा निर्भर करेगी। यदि नकद में नोटों को भी शामिल किया जाता है तो नोट जारी करने वाली संस्था को अपने प्रत्येक नोट के लिए काप में स्वर्ण रखना होगा। यदि स्वर्ण पिण्डमान है तो भी जारी किये नोटों के एक निश्चित अनुपात में स्वर्ण रखना आवश्यक होगा और नोट जारी करने वाली संस्था मनमानी नकद की मात्रा नहीं बढ़ा सकती। उसकी सीमा प्राप्त स्वर्ण-स्टॉक द्वारा ही निर्धारित होगी। स्पष्ट है कि नकद मुद्रा की मात्रा तभी बढ़ाई जा सकती है जब स्वर्ण के स्टॉक में वृद्धि हो और जब स्वर्ण का स्टॉक कम हो जाता है तो नकद मुद्रा की मात्रा को भी कम करना होता है।

2. बैंक मुद्रा की मात्रा स्वर्ण मान के अन्तर्गत स्वर्ण-स्टॉक द्वारा केवल नकद की मात्रा ही निर्धारित नहीं होती वरन् बैंक मुद्रा अथवा जमा भी निर्धारित होती है। व्यापारिक बैंकों की बैंक जमा निर्माण की प्रमुख सीमा उनका नकद अनुपात है। (Cash Ratio) यदि नकद अनुपात (Cash Ratio) में परिवर्तन न किया जाय तो बैंक जमा निर्माण पर देश में नकद मुद्रा की मात्रा का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। देश की कुल नकद मुद्रा की मात्रा स्वर्ण-स्टॉक पर निर्भर करती है इसलिए बैंक जमा की मात्रा भी परोक्ष रूप से इसी पर आधारित है। केन्द्रीय बैंक, बैंकों की ऋण नीति पर बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाओं तथा अन्य उपायों से नियन्त्रण करता है। स्वर्ण मान पर आधारित देश का केन्द्रीय बैंक इन उपायों का प्रयोग अपने स्वर्ण स्टॉक को ध्यान में रख कर ही कर सकता है। इस प्रकार इन परिस्थितियों में मौद्रिक नीति देश की आन्तरिक आर्थिक स्थिति को देख कर नहीं निर्धारित की जाती बल्कि यह स्वर्ण-स्टॉक के परिवर्तनों को ध्यान में रख कर बनाई जाती है। सम्भव है कि विकासशील अर्थ-व्यवस्था के हितों को देखते हुए मुद्रा की मात्रा बढ़ाना आवश्यक हो, फिर भी स्वर्ण-स्टॉक की कमी होने के कारण मुद्रा की मात्रा घटाना पड़े। उसी प्रकार मुद्रास्फीति की स्थिति होते हुए भी यदि स्वर्ण स्टॉक में वृद्धि हो रही है तो आवश्यक नहीं होते हुए भी मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाती है। इस प्रकार स्वर्ण मान के अन्तर्गत मौद्रिक नीति का आधार आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। एक प्रकार से स्वर्ण मान पर आधारित देश द्वारा अपनाई गई मौद्रिक नीति वाह्य परिस्थितियों द्वारा थोप दी जाती है।

3 मुद्रा-मूल्य : स्वर्ण मान के अन्तर्गत मुद्रा का आन्तरिक मूल्य (Internal Value of the Currency) स्थायी रखना भी सम्भव होता है क्योंकि बैंक नोट सदैव ही स्वर्ण की उस मात्रा के मूल्य के बराबर मूल्य रखते हैं जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में स्वर्ण मान अपनाने का सबसे बड़ा प्रलोभन ही यही था कि इसमें मुद्रा के मूल्य को स्थाई रखा जा सकता है। इंग्लैंड ने चांदी के मूल्यों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव एवं द्विधातुमान संचालन में कठिनाई अनुभव की तो स्वर्णमान अपनाने का निश्चय किया क्योंकि इसके मूल्य में स्थिरता थी। वास्तव में जब तक विश्व में स्वर्ण की पूर्ति प्रतिवर्ष बहुत कम मात्रा में बढ़ती रही तब तक स्वर्ण के मूल्य में भी अपेक्षाकृत बहुत अधिक स्थायित्व था। परन्तु स्वर्ण की नई खोजों और प्राप्तियों ने स्वर्ण के मूल्य को घटा दिया और अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ी (क्योंकि मौद्रिक इकाई का सम्बन्ध स्वर्ण की मात्रा से था)। विश्व में 1850-70 के बीच सामान्यतः कीमत स्तर बढ़ा जिसका कारण कैलिफोर्निया और आस्ट्रेलिया में स्वर्ण की नवीन उपलब्धियाँ थीं। परन्तु यह अवश्य कहा जा सकता है कि स्वर्ण मान पर आधारित मुद्राओं के मूल्यों में एकरूपता रहती है तथा उनकी कीमत स्तर में साथ ही और एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। स्वर्ण मान पर आधारित देशों की कीमत स्तर में अधिक परिवर्तन के दोष नहीं आ पाते।

स्वर्ण मान अपने आन्तरिक पक्ष (Domestic aspect) के उद्देश्यों की पूर्ति करने में 1914 के पूर्व प्रायः सफल रहा परन्तु प्रथम महायुद्ध और उसके बाद की गतिविधियों के सदम में यदि स्वर्णमान का अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्ण मान इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका। प्रथम महायुद्ध काल में और उसके बाद स्वर्ण के मूल्य में काफी परिवर्तन हुए एवं कीमत स्तर को स्थिर नहीं रखा जा सका। स्वर्ण के स्टाक का ध्यान रखे बिना ही बड़ी मात्रा में नोट जारी किये गये। फिर भी 1914 के पूर्व का स्वर्ण मान मूल्य की स्थिरता बनाए रखने में तथा मुद्रा की मात्रा नियन्त्रित करने में सफल रहा।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वर्ण मान—

वास्तव में स्वर्ण मान अपने उद्देश्यों के घरेलू पक्ष के लिए उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना अन्तर्राष्ट्रीय पक्ष के लिए। स्वर्ण मान का प्रमुख महत्त्व अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य मान और विनिमय के माध्यम के रूप में ही अधिक है। देश के अन्दर मुद्रा कानूनी विधिग्राह्य होने के कारण मूल्यमान और विनिमय के माध्यम के रूप में सर्वमान्य रहती है परन्तु विदेशों में भुगतान के लिए सभी प्रकार की मुद्राएँ स्वीकार्य नहीं हो सकती। इसलिए स्वर्ण मान का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान के रूप में किया गया। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान-माध्यम के रूप में स्वर्ण मान का संचालन कुछ आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं राजनैतिक शक्तों को पूरा होने की अपेक्षा

करता है। जिन शर्तों या नियमों का पालन अन्तर्राष्ट्रीय स्वरुण मान की सफलता के लिए आवश्यक है उन्हें स्वरुण मान संचालन के नियम (Rules of the Gold Standard Game) के नाम से जाना जाता है। ये नियम निम्नलिखित हैं :—

1. मौद्रिक नीति सम्बन्धी नियम — अन्तर्राष्ट्रीय स्वरुण मान के सदस्यों की मौद्रिक नीति आन्तरिक उद्देश्यों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। जहाँ आन्तरिक उद्देश्यों का अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्यों से विरोध हो वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लार्ड केम्स के शब्दों में—“The main criterion of the banking policy of each country should be the average behaviour of all other members, its own voluntary and independent contribution being a modest one.”

स्वरुण मान के संचालन का एक प्रमुख नियम यह है कि स्वरुण निर्यात वाले देश मुद्रा सकुचन एवं स्वरुण आयात वाले देश मुद्रास्फीति की नीति का अनुसरण करें। यदि स्वरुण प्राप्त होने पर कोई देश मुद्रास्फीति की नीति नहीं अपनाता तो वह इस नियम की अवहेलना करता है। स्वरुण की मात्रा इकट्ठी करके वह अपनी घरेलू मौद्रिक एवं ऋण नीति के द्वारा ही स्वरुण क मूल्य को निर्धारित करने लगेगा, परन्तु स्वरुण मान में स्वरुण-मूल्य अन्य सदस्यों के व्यवहार पर भी निर्भर करना चाहिए। इस नियम का पालन न करने से स्वरुण निर्यात करने वाले देश पर मुद्रा सकुचन का दबाव बढ़ता जाता है जिससे उत्पादन एवं रोजगार में कमी आती जाती है और अन्त में वह देश स्वरुण मान का परित्याग कर देता है।

2. मुक्त व्यापार नीति — उपरोक्त नियम का वास्तविक उद्देश्य मौद्रिक नीति द्वारा मुगलान सतुलन अर्थात् आयात एवं निर्यात में आवश्यक परिवर्तन लाना होता है। अतएव यदि स्वरुण आयात करने वाले देश में मुद्रास्फीति की नीति को अपनाई जाय परन्तु उस देश के कीमत स्तर एवं आय तल में लोच की कमी हो तो कीमत स्तर में परिवर्तन नहीं होगा तथा आयात एवं निर्यात की मात्रा प्रभावित नहीं होगी। उसी प्रकार स्वरुण निर्यात करने वाल देश में भी यदि मुद्रा सकुचन की नीति अपनाने का वावजूद भी कीमत स्तर कम नहीं होता तो निर्यात (वस्तुओं का) नहीं बढ़ेगा। इसी प्रकार यदि स्वरुण प्राप्त करने वाला देश आयातों पर कर की मात्रा बढ़ा दे तो स्वरुण निर्यात करत वाले देश को अपना निर्यात (वस्तुओं का) बढ़ाने के लिए कीमत तल बहुत अधिक गिराना पड़ेगा जो अर्थ-व्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए स्वरुण मान पर आधारित देशों को विशेष रूप से स्वरुण प्राप्त करने वाले देश को मुक्त व्यापार (Free Trade) की नीति अपनानी आवश्यक है। यही स्वरुण मान का दूसरा नियम है जिसका पालन इसकी सफलता के लिए आवश्यक है। प्रो० हाम के शब्दों में—“..... an increasing amount of control

measures and restrictions of international commerce hinder those adjustments which are the very essence of the mechanism "

3. अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी के लेन देन सम्बन्धी नियम—स्वर्ण मान के मफल सचालन का तीसरा नियम यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी का लेन-देन करने वाले देश अपनी नीति में आकस्मिक परिवर्तन न कर। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जायेगा तो भुगतान शेष में साम्यावस्था लाने के लिए काफी मात्रा में स्वर्ण भेजना होता है तथा कीमत तल को हानिकारक स्तर तक नीचे गिराना पड़ता है। जिससे पूर्ण स्वर्ण मान व्यवस्था ही भंग हो सकती है। प्रो० हाम के शब्दों में—“Flight capital movements are entirely heedless of variations in the respective rates of interest and are capable of destroying the whole gold mechanism. —1930 में इस नियम का उलघन कर अमेरिका ने जब जर्मनी का एकाएक ऋण देना बन्द कर दिया तो जर्मनी के लिए भुगतान शेष को सतुलित रखना कठिन हो गया और उसने विनिमय नियन्त्रण की नीति अपनाई।

4 स्वतन्त्र स्वर्ण आयात एव निर्यात—स्वर्ण मान को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सचालित करने के लिए यह भी आवश्यक है कि स्वर्ण के आवागमन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न हो। यदि स्वर्ण प्राप्त करने वाला देश प्रलोभन में आकर स्वर्ण निर्यात पर रोक लगा दे तो स्वर्ण मान सफल नहीं होगा। अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय हितों को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखना आवश्यक है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान की सफलता के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। इन नियमों की अवहेलना होने पर स्वर्ण मान की समाप्ति निश्चित है। इसी विचार से प्रेरित होकर क्राउथर ने कहा है

“The Gold Standard is a jealous God. It will work, provided it is given exclusive devotion.”

अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान की उपलब्धिया

1 विनिमय दर की स्थिरता—अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के अन्तर्गत विनिमय दर की स्थिरता को बनाए रखना सम्भव है। प्रत्येक देश की मौद्रिक इकाई का मूल्य स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा के बराबर घोषित किया गया रहता है और उसी अनुपात में उनके विनिमय दर निर्धारित होते हैं। इसे टकसाली विनिमय दर (Mint Par of Exchange) कहा जाता है। वास्तविक विनिमय दर इसी विनिमय दर के इर्द-गिर्द स्वर्ण आयात एव स्वर्ण निर्यात बिन्दुओं की सीमाओं में घूमा करता है। जब कभी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ने लगता है तो लोग विदेशों में भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के स्थान पर

स्वर्ण धातु में मुग्तान करने लगते हैं क्योंकि स्वर्ण मान में स्वर्ण के आयात-निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता। इसलिए विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की माग कम हो जाती है और विनिमय पुनः टक्काली दर की ओर आने लगती है। स्थायी विनिमय दर होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पूँजी के लेन-देन में एक विश्वास का वातावरण होता है। अपने इस गुण के कारण स्वर्ण मान को अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से एक पूर्ण मौद्रिक व्यवस्था के रूप में माना जाता था और अन्य व्यवस्थाओं से अच्छा समझा जाता था।

2 अन्तर्राष्ट्रीय आय एवं कीमत तलों में सामंजस्य—अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान में स्वर्ण के आयात निर्यात की स्वतन्त्रता होने के कारण न केवल विनिमय दर के परिवर्तनों को सीमा बद्ध करने में सहायता मिलती है वरन् अन्तर्राष्ट्रीय कीमत-तल में सामंजस्य भी स्थापित किया जाता है। स्वर्ण मान के अन्तर्गत थोड़ी मात्रा में मुद्रा प्रसार या मुद्रा सकुचन तो किया जा सकता है परन्तु बड़े पैमाने पर ऐसा करना सम्भव नहीं है। कोई भी एक देश बड़े पैमाने पर और लम्बे समय तक इस प्रकार की नीति नहीं अपना सकता जब तक अन्य सदस्य भी वैसी ही नीति न अपनावें। यदि एक देश मुद्रा प्रसार या सकुचन की नीति अपनाता है तो उसे बाध्य होकर कुछ समय बाद इस नीति का त्याग कर देना होगा। उदाहरणार्थ यदि एक देश कीमत स्तर बढ़ाता है तो उसके निर्यात कम और आयात अधिक होने और भुगतान शेष प्रतिकूल हो जायेगा एवं विनिमय दर स्वर्ण निर्यात बिन्दु की ओर बढ़ेगी। स्वर्ण निर्यात होने के कारण देश में स्वर्ण का स्टॉक कम होगा मुद्रा का परिमाण कम हो जायेगा और कीमत स्तर पुनः अपने पूर्वास्तर पर पहुँच जायेगा। इस प्रकार उस देश की कीमतों और अन्य देशों की कीमतों में पहले जैसा सम्बन्ध स्थापित हो जायेगा। इसीलिए प्रो० हाम ने कहा है— 'The gold flow acts as an automatic brake on credit expansion and credit contraction'

3 स्वयं चालिता—अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान को 'स्वयं चालित मान' (Automatic Standard) के नाम से भी संबोधित किया जाता है। स्वर्ण मान के संचालन में कोई जटिलता नहीं होती और प्रायः किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। सभी सदस्य स्वर्ण मान की-छा-नियमों से प्रवृत्त होते हैं और यदि वे उनका पालन करते रहे तो स्वर्ण मान स्वयं चालित होता रहता है। इससे एक लाभ यह भी है कि किसी देश की मौद्रिक सस्था क्या कदम उठाएगी इसका भी अन्य देशों को पता रहता है जिसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक प्रकार की निश्चितता आ जाती है। फिर भी उपरोक्त बातें सैद्धान्तिक रूप से ही पूर्ण सही कही जा सकती हैं, व्यवहार में बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती है। स्वर्ण के आवागमन का सदस्य देशों की राष्ट्रीय ऋण व्यवस्था पर जटिल प्रभाव पड़ते हैं और उनका

सतर्कता के साथ प्रबन्ध करना आवश्यक हो जाता है। कीमतों में स्वतः ही इतना परिवर्तन हो जिससे आयात और निर्यात प्रभावित हो इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में स्वर्ण का आवागमन होना चाहिए। इसके साथ ही स्वतः सामंजस्य होने में समय भी अधिक लगता है। इतनी बड़ी मात्रा में स्वर्ण के आवागमन होने से स्वर्ण निर्यातक देश को स्वर्ण मान बनाए रखना कठिन हो जाता है इसलिए मौद्रिक सन्स्था हस्तक्षेप करती है और ऐसी नीति अपनाती है कि बिना बड़ी मात्रा में स्वर्ण भेजे ही, स्थिति को ठीक किया जा सके। स्वर्ण मान का इतिहास बताता है कि स्वर्णमान के संचालन में बैंक दर तथा मुद्रा नीति का कितना हाथ रहा है। जब विनिमय दर स्वर्ण निर्यात बिन्दु के निकट होती तो बैंक दर में वृद्धि करके पूँजी आयात को प्रोत्साहित किया जाता एवं आय एवं कीमत तल में कमी आने लगती। स्वर्ण निर्यात के पहले ही स्वर्ण निर्यात से सम्बद्ध परिणाम प्राप्त हो जाते। विनिमय दर के स्वर्ण आयात बिन्दु के निकट होने पर बैंक दर को कम करके अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। इसीलिए कुछ अर्थशास्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान को केवल आंशिक रूप से ही स्वयंचालित (Semi-automatic) कहा है।

4 स्वर्ण-मूल्य की स्थिरता—यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्वर्ण मान के अन्तर्गत एक लम्बी अवधि तक स्वर्ण के मूल्य को स्थिर रखा गया। परन्तु स्वर्ण मूल्य की स्थिरता का कारण प्रायः इसकी पूर्ति की स्थिरता ही थी। चूँकि स्वर्ण के मूल्य में स्थिरता थी इसलिए स्वर्ण पर आधारित मुद्रा की क्रय-शक्ति भी स्वर्ण के मूल्य के बराबर बनी रही।

5 स्वर्ण का उचित वितरण—स्वर्ण मान विश्व के स्वर्ण-स्टॉक का सदस्य देशों में न्यायपूर्ण वितरण करता है। यदि स्वर्ण मान के नियमों का उचित रूप से और निष्ठा के साथ पालन किया जाय तो स्वर्ण के प्रति मोह समाप्त हो जाता है और उसके अन्यायपूर्ण वितरण का भय नहीं रहता है। स्वर्ण मान की प्रक्रिया इस प्रकार की है कि जब स्वर्ण के निर्यात करने से स्वर्ण स्टॉक में कमी होती है तो स्वतः ही, अधिक निर्यात, कम आयात तथा अल्प कालीन पूँजी के आयात के परिणामस्वरूप वह कमी पूरी भी होने लगती है।

6 स्वर्ण-उत्पादक देशों को लाभ : स्वर्ण का विश्व व्यापी मौद्रिक प्रयाग होने के कारण उन देशों को विशेष लाभ होता है जिनको स्वर्ण उत्पादित करने का सौभाग्य प्राप्त है। सभी देशों द्वारा स्वर्ण की भाग होना के कारण इन देशों को स्वर्ण देवने में सुविधा रहती है और अपेक्षाकृत स्वर्ण की कीमत स्थिर रहने के कारण उनकी प्राप्ति निश्चित रहती है। ऐसी अवस्था में वे अपनी आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने में समर्थ होते हैं।

7. अन्तर्राष्ट्रीय तरलता का कोष : अन्तर्राष्ट्रीय स्वरण मान के अन्तर्गत जब आवश्यक कोष स अधिच स्वरण काय की स्थिति आ जाती है तो वह अन्तर्राष्ट्रीय तरलता कोष के रूप में कार्य करता रहता है । यदि अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान सतुलन बिगड़ जाता है तो स्वरण के आवागमन से, इस कोष के कारण, तात्कालिक मुद्रा प्रसार एवं सङ्कुचन की स्थिति पैदा होने से रोका जा सकता है । इस प्रकार यह एक प्रकार से शाक एब्जारबर (Shock absorber) का कार्य करता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्वरण मान के दोष

अन्तर्राष्ट्रीय स्वरण मान की अनेक उपलब्धियों के होते हुए भी इसमें अनेक दोष हैं । दो महायुद्धों के बीच की अवधि में स्वरण मान के अनेक दोष प्रकट रूप से विश्व के सामने आए । यह कहा जा सकता है कि स्वरण मान में इसलिए दोष आ गए क्योंकि सदस्यों ने स्वरण मान संचालन के नियमों की अवहेलना की । परन्तु इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि चाहते हुए भी सदस्य देश इन नियमों का पालन नहीं कर सके । यह इस बात का संकेत है कि स्वयं स्वरण मान में दोष अन्तर्निहित हैं वे केवल उस समय के ऐतिहासिक वातावरण के कारण नहीं पैदा हुए थे । स्वरण मान के निम्नलिखित दोष उल्लेखनीय हैं —

1 केवल अच्छे समय में सफल होने वाला मान प्रो० हाम ने कहा है "It is a far weather craft of doubtful sea worthiness in stormy waters. When the necessary conditions can not be fulfilled, the gold standard is abandoned and it becomes the task of "paper" standards to manage the bad situation" । इस उद्धरण से यह स्पष्ट है कि स्वरण मान केवल शान्त और सामान्य परिस्थितियों में ही सफलतापूर्वक क्रियाशील रह सकता है । परिस्थितियों के कारण जब स्वरणमान की शर्तों का पालन करना कठिन हो जाता है तो स्वरण मान का त्याग कर देना पड़ता है । परिस्थितियों को सामान्य बनाए रखने के लिए विश्व की अर्थ व्यवस्था में लोच एवं स्थायित्व का होना आवश्यक है । यदि सदस्य देशों के बीच के सम्बन्ध बिगड़ जाते हैं तो शका वे वातावरण में स्वरण मान असफल हो जाता है । 1914 के पहले स्वरण मान की वास्तविक परख नहीं की जा सकी क्योंकि विश्व में कोई प्रमुख अशांति की घटना नहीं घटी तथा कीमत स्तर स्वरण मूल्य से सम्बद्ध रखा जा सका । परन्तु प्रथम महायुद्ध के कारण वातावरण में जो उथल पुथल हुई उसके बाद अधिकांश देशों में स्वावलम्बी अर्थ व्यवस्था बनाने की एक लहर सी पैदा हो गई । राष्ट्रीय हितों को सर्वाधिक महत्व दिया जाने लगा और स्वरणमान सम्बन्धी नियमों की खुले रूप से अवहेलना होने लगी । स्वरण मान का त्याग कर दिया गया ।

2 राष्ट्रीय हितों को गौरव स्थान स्वरण मान की सफलता सदस्यों से जिस प्रकार के अनुशासन और त्याग की अपेक्षा करती है वह अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के

असतुलित होने की स्थिति में अत्यन्त कठिन है । एक राष्ट्र द्वारा व्यवस्थित (Managed) मौद्रिक मान को अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक मान के आदर्शों के अनुरूप रखना उस समय कठिन हो जाता है जब उन आदर्शों के पालन से आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था पर बहुत अधिक दबाव पड़े या उसके अस्त-व्यस्त हो जाने का भय हो । पिछड़े हुए राष्ट्रों के लिए इन नियमों और आदर्शों का पालन करना और भी कठिन हो जाता है क्योंकि उन्हें अपने विवास को बढ़ाने के लिए आयातों पर प्रतिबन्ध तथा कीमतों में उचित परिवर्तन लाना आवश्यक होता है ।

3. एक देश की आर्थिक अस्थिरता से दूसरा देश भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहता : स्वर्ण मान के अन्तर्गत स्वर्ण का स्वतन्त्र आयात-निर्यात होने के कारण एक देश की आर्थिक अस्थिरता दूसरे देश में स्थानान्तरित हो जाती है । आर्थिक अस्थिरता राजनैतिक अस्थिरता को भी जन्म देती है । इस प्रकार अगर कुछ देश मुद्रास्फीति या सकुचन की नीति का अनुसरण करें तो अन्य देशों में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति पैदा हो जायेगी ।

आधुनिक युग में मौद्रिक नीति सम्पूर्ण अर्थनीति के सदर्भ में निर्धारित की जाती है । आज की ऋण नीति एवं सरकार का व्यय पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक साधन माने जाते हैं इसलिए इनको विनिमय दर की स्थिरता की बेदी पर बलिदान नहीं किया जा सकता । इसलिए जब कोई देश स्वर्ण मान के नियमों को छोड़कर इस प्रकार के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अपनी नीति बनाता है तो सदस्यों के बीच सामंजस्य नहीं रह पाता और स्वर्ण मान भंग हो जाता है । आज की अर्थ नीति आंतरिक स्थिरता को अधिक महत्व देती है और विनिमय दर की स्थिरता को उसी सीमा तक ध्यान में रखा जाता है जिससे आंतरिक उचल-पुचल न हो सके ।

4 स्वर्ण मान का मुद्रा सकुचन की ओर अधिक झुकाव प्रो० राविन्सन के शब्दों में स्वर्ण मान में सकुचन की ओर निहित झुकाव है ("inherent bias towards deflation) । स्वर्ण निर्यात करने वाले देश को निश्चित रूप से मुद्रा सकुचन करना पड़ता है, परन्तु स्वर्ण आयात करने वाले देश के समक्ष मुद्रा प्रसार करने की उत्तनी अनिवार्यता नहीं है । इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय बैंकों के अधिकार मुद्रा सकुचन के लागू करने में अधिक सशक्त हैं एवं मुद्रा प्रसार के लिए कम सशक्त हैं । जान. एच विलियम्स के अनुसार इस दोष के दो अन्य कारण भी हैं । प्रथम कुछ देशों के लिए विदेशी व्यापार अन्य देशों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है । द्वितीय, कुछ देश बड़े होते हैं कुछ छोटे । परन्तु स्वर्ण मान का सिद्धान्त, एक रूप तथा लगभग एक आकार प्रकार के देशों के सम्बन्धों के आधार पर प्रतिपादित किया गया था ।

5. बेरोजगारी को बढ़ावा : स्वर्ण मान के अन्तर्गत रोजगार को प्रोत्साहन नहीं मिलता । स्वर्ण मान के अन्तर्गत मजदूरी की वृद्धि प्रायः रोजगार को कम करके ही सम्भव है । यदि मजदूरी को रोजगार कम किए बिना बढ़ने दिया जाये तो कीमत स्तर बदलता है परन्तु स्वर्ण मान में कीमत तल में स्थिरता का प्रयत्न किया जाता है । चूँकि मौद्रिक मजदूरी को मौद्रिक उपायो से नियन्त्रित नहीं किया जा सकता इसलिए स्थिर कीमत तल के विरुद्ध मौद्रिक मजदूरी बढ़ने का परिणाम बेरोजगारी के रूप में सामने आयेगा ।

6 स्वर्ण मान में भी प्रबंधित-मुद्रा से छुटकारा नहीं . लार्ड कीन्स के अनुसार आधुनिक युग में जहाँ, पत्र मुद्रा एवं बैंक मुद्रा का वाढल्य है, प्रबंधित मुद्रा (Managed Currency) से छुटकारा नहीं मिल सकता चाहे वह स्वर्ण में परिवर्तनीय ही क्यों न हो क्योंकि स्वर्ण का मूल्य स्वयं केन्द्रीय बैंको की नीति पर निर्भर करता है ।¹ आजकल पूर्ण स्वयंचालित मौद्रिक मान की कल्पना करना व्यावहारिकता से अपरिचित होने के समान है । चुनाव केवल इस बात में करना है कि प्रबन्ध किस अग तक हो । स्वयं चालित मौद्रिक मान द्वारा आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्थिरता प्राप्ति की जा सकती है यह इतिहास द्वारा असत्य प्रमाणित हो चुका है । इसलिए मौद्रिक मान का प्रबन्ध राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय हित में करना आवश्यक है ।

7. खर्चीला मौद्रिक मान स्वर्ण मान अपने प्रारम्भिक रूप में बहुत ही अपव्ययी था । आनुपातिक स्वर्ण कोष भी केवल स्वर्ण मान के अन्तर्गत स्वतः मुद्रा मकुचन की दृष्टि से एवं पत्र मुद्रा में जनता का विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक था । परन्तु जब मौद्रिक एवं ऋण नीतियाँ सस्थाओं के विवेक पर निर्भर करती हैं तो बिना स्वर्ण कोष रखे भी मौद्रिक नीति का सफलता पूर्वक संचालन किया जा सकता है । यदि स्वर्ण का प्रयोग मुद्रा के पीछे कोष रखने के रूप में नहीं किया जाय तो वह अन्तर्राष्ट्रीय तरलता का बहुत बड़ा कोष हो सकता है और अस्थायी भुगतान असन्तुलन को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है तथा आन्तरिक क्षेत्र में आर्थिक नीति निर्धारित करने की प्रत्येक देश को स्वतन्त्रता प्रदान कर सकता है । कुछ अर्थशास्त्रियों ने तो यहां तक कहा है कि स्वर्ण उत्पादन पर लगाई पूँजी और श्रम भी बेकार जाता है । अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान को यदि साल व्यवस्था (Credit Arrangements) द्वारा प्रयत्न बनावटी मौद्रिक इकाई (Artificial

¹ "In the modern world of paper currency and bank credit there is no escape from a managed currency whether we wish it or not;—convertibility into gold will not alter the fact that the value of gold itself depends on the policy of the central banks"

Monetary Unit) द्वारा सम्भव बनाया जा सके तो मौद्रिक प्रयोग के लिए स्वर्ण उत्पादन एक प्रकार का अपव्यय मात्र है। चार्ल्स प्रो० हार्डी ने लिखा है, "When gold no longer performs that service (service of reducing the need for credit management) gold mining becomes sheer waste" परन्तु यह उस अवस्था में सही है जब पूर्ण रोजगार की स्थिति हो और धर्म का अभाव हो। जहाँ धर्म बेकार पड़ा है वहाँ तो बेकार बैठ रहने की अपेक्षा गड्ढा खोदना भी अच्छा है।

स्वर्ण मान का स्वर्णिम युग (1816-1914) (The Golden Period of Gold Standard)

यद्यपि व्यापक रूप से स्वर्णमान को 1870 के बाद ही अपनाया गया। परन्तु इसका सूत्रपात 1816 में इंग्लैण्ड ने कर दिया था। इंग्लैण्ड द्वारा स्वर्ण मान अपनाने का कारण यह था कि रजत के मूल्यों में उतार-चढ़ाव होने के कारण इंग्लैण्ड को द्विधातुमान बनाए रखने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। बढ़ते हुए व्यापार एवं उद्योगों ने ऋणों के लेन-देन को बहुत बढ़ावा दिया परन्तु चादी के मूल्य में अस्थिरता होने के कारण रजत मुद्रा को भावी भुगतान का आधार मानने में लोगों को कठिनाई अनुभव हो रही थी। स्वर्ण का मूल्य अपेक्षाकृत अधिक स्थिर था इसलिए स्वर्ण मान की तरफ ध्यान आकृष्ट होना स्वाभाविक था।

प्रथम महायुद्ध के पूर्व स्वर्ण मान को संचालित करने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं की गई। विश्व में शांति का वातावरण इस अवधि में बना रहा। किसी भी देश को दूसरे देश का आर्थिक दबाव नहीं सहन करना पड़ा। सभी देशों ने स्वर्ण मान क्रीडा नियमों का आस्था और दृढ़ता से पालन किया। इसलिए इस युग में विनिमय दर में स्थिरता रखी जा सकी और अन्तर्राष्ट्रीय आय ६२ कीमत तल में सामंजस्य रखा जा सका। स्वर्ण का आयात एवं निर्यात अबाध गति से होता रहा और आन्तरिक हितों को अन्तर्राष्ट्रीय हितों के समक्ष गौण स्थान दिया जाता रहा। इसी अवधि में वास्तव में स्वर्ण मान अपने पूर्ण रूप में विकसित एवं सफल रहा। इसीलिए इसे स्वर्ण मान का स्वर्णिम युग कहा जाता है।

स्वर्ण मान का स्थगन (1914-1918)

प्रथम महायुद्ध छिड़ने के पूर्व स्वर्ण मान को एक अच्छे मौद्रिक मान के सभी गुणों से सम्पन्न समझा जाता था। लेकिन युद्ध के प्रारम्भ होते ही स्वर्ण मान को इतना गहरा धक्का लगा कि विनियोजकों का विश्वास (इस मौद्रिक मान में) डगमगा गया। अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान समाप्त हो गया। आन्तरिक क्षेत्रों में भी स्वर्ण मान स्थगित कर दिया गया। प्रो० सी. पी. श्रीवास्तव के शब्दों में "It (war)

left behind it a long legacy of financial crises, unprecedented inflation of currencies, abnormal rise in prices, and a complete break down of the domestic and foreign exchange machineries of practically all the countries of the world "

युद्ध की असामान्य परिस्थितियों ने, युद्ध संचालन के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक मुद्रा की आवश्यकता ने, तथा करो द्वारा उचित मात्रा में आय प्राप्त होने की कठिनाईयों ने, युद्ध में सलग्न सभी देशों में अपूर्व मुद्रा स्फीति को जन्म दिया। स्वर्ण के आयात निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए। स्वतन्त्र व्यापार की नीति को त्याग दिया गया। विनिमय दरें परिवर्तित होने लगीं। स्वर्ण तथा वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई। सभी उत्पादक क्रियाओं में वृद्धि हुई एवं व्यापारी वर्ग तथा उद्योग-पतियों ने खूब लाभ उठाया। सट्टे की प्रवृत्ति में आशातीत वृद्धि हुई। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अमेरिका के अलावा सभी देशों में स्वर्ण मान का अन्त हो गया। विनिमय दरों में अस्थिरता आ गई तथा अत्यधिक मुद्रा प्रसार हुआ।

युद्ध के बाद . युद्ध समाप्त होने के बाद एक प्रकार से स्वतन्त्र विनिमय नीति अपनाई गई थी परन्तु यह अनुभव बड़ा ही दुःखद रहा। युद्ध के बाद अनेक देशों को अपनी जर्जरित अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना आवश्यक था और इसके लिए उन्हें विदेशों से भारी मात्रा में सामग्री मंगानी पड़ी। उनके पास अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा का अभाव होने के कारण उनकी मुद्रा का बाह्य मूल्य निरन्तर गिरने लगा। दूसरे देशों ने अल्पावधि ऋण देना बन्द कर दिया तथा पहले से लगी पूर्ण को वापस प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। यही नहीं, स्वयं उन देशों के विनियोजकों ने विदेशों में भूजी लगाना अधिक लाभदायक समझा। इस प्रकार विदेशी विनिमय की निरन्तर बढ़ने वाली मांग के फलस्वरूप इन देशों की आर्थिक स्थिति बड़ी ही शोचनीय हो गई। परन्तु आन्तरिक नियन्त्रणों तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा स्थिति को काबू में रखने का प्रयत्न किया गया।

स्वर्ण मान की पुनर्स्थापना

(Rehabilitation of Gold Standard)

युद्ध समाप्त होने के बाद स्वतन्त्र विनिमय नीति के दुःखद अनुभव के कारण भावी अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था की रूप-रेखा पर शीघ्र ही विचार-विनिमय प्रारम्भ हो गया और यह विचार धारा प्रबल होती गई कि स्वर्ण मान की पुनर्स्थापना ही युद्धोत्तर के कुप्रभावों को दूर कर सकती है। लीग ऑफ नेशन्स के तत्सचिवान में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों ने इस विषय पर विचार विमर्श किया। उस समय दो विचार-धाराएँ सामने आईं। एक विचार धारा के अनुसार स्वर्णमान की पुनर्स्थापना

आवश्यक थी। इसके समर्थकों में प्रो० गुस्टव कंसेल का नाम प्रमुख है। दूसरी विचार धारा, जिसके प्रमुख समर्थकों में लार्ड कोन्स का नाम उल्लेखनीय है, वैज्ञानिक ढंग से नियन्त्रित पत्र मान की स्थापना पर जोर दे रही थी। प्रो० कोन्स ने स्वर्ण को भूतकाल का राक्षसी अवशेष कह कर सम्बोधित किया (Gold is a barbarous relic of the past), परन्तु अन्ततोगत्वा स्वर्ण मान के समर्थकों की विजय हुई और स्वर्णमान को पुनः स्थापित करने का निश्चय किया गया।

स्वर्ण मान की पुनर्स्थापना का निर्णय लेने के बाद दूसरा विवाद इस विषय पर प्रारम्भ हो गया कि मुद्रा के मूल्य को किस दर पर सोने के साथ जोड़ा जाय, अर्थात् (1) युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व की दर अपनाई जाय या (2) प्रचलित दर पर मुद्रा और स्वर्ण की समता निर्धारित की जाय या (3) भविष्य की परिस्थितियों का अनुमान लगा कर कोई अन्य दर अपनाई जाय। युद्ध के पूर्व अधिकांश देशों की मुद्राओं का जो मूल्य था युद्ध के बाद मुद्रा स्फीति के कारण उसमें भारी गिरावट आ गई थी। इसलिए युद्ध के पूर्व की दर अपनाने का तात्पर्य मुद्रा सकुचन द्वारा मुद्रा के मूल्य में वृद्धि करना था परन्तु मुद्रा सकुचन के प्रभाव कितने भयानक हो सकते हैं, यह सर्व विदित था। प्रचलित दर स्वीकार करने का तात्पर्य अवमूल्यन करना था। भविष्य की दर का अनुमान लगाना कठिन था, इसलिए उसे व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सकता था। अतएव मुद्रा सकुचन तथा अवमूल्यन की नीति का विकल्प सदस्यों के समक्ष था। अलग-अलग देशों ने इस सम्बन्ध में अपना स्वतन्त्र निर्णय लिया। अमेरिका ने युद्ध पूर्व की दर को ही कायम रखा। इसके अतिरिक्त हालैंड, स्विटजरलैंड, स्वीडन तथा नार्वे ने भी युद्ध के पूर्व की दर को अपनाया। इंग्लैंड ने, अवमूल्यन के कारण स्टर्लिंग के महत्व में कमी की आशंका के कारण, युद्ध के पूर्व की दर को ही अपनाया, हालांकि यह उसके वर्तमान मूल्य से अधिक था। फ्रांस ने युद्ध के बाद वर्तमान दर को अपनाया। 1928 तक स्वर्ण मान पुनः स्थापित हो चुका था परन्तु इसकी रूप रेखा युद्ध के पूर्व के स्वर्ण मान से भिन्न थी। प्रत्यक्ष स्वर्ण मान का स्थान अप्रत्यक्ष स्वर्ण मान ने ग्रहण कर लिया था। इस नए स्वर्ण मान की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं —

1. स्वर्ण चलन मान का अन्त युद्ध के बाद स्वर्ण चलन मान का परित्याग कर दिया गया तथा इसके स्थान पर स्वर्ण पिण्ड मान तथा स्वर्ण विनिमय मान को अपनाया गया। सोने के सिक्कों का चलन समाप्त हो गया।

2. नए सदस्य युद्ध के बाद जिन देशों ने स्वर्ण मान को अपनाया उनमें कई देश ऐसे थे जो युद्ध के पूर्व स्वर्ण मान पर नहीं थे। दक्षिणी अमेरिका तथा कई योरोपीय देश इसके उदाहरण हैं। अतः नए स्वर्ण मान का क्षेत्र अधिक व्यापक था।

3 अधिक नियंत्रण युद्ध के बाद का वातावरण स्वर्ण मान के नियमों के पालन के लिए अनुकूल न होने के कारण मौद्रिक मस्याओं या सरकारों को स्वर्ण मान को ठीक रखने के लिए नियंत्रण एवं हस्तक्षेप करना पड़ता था। यह स्वयं चालिता वा गुण प्रायः खो बैठा था।

4. कीमत तल की स्थिरता को प्रधानता . युद्ध के पूर्व के स्वर्ण मान की यह विशेषता थी कि राष्ट्रीय हितों को गौण स्थान दिया जाता था तथा अन्तर्राष्ट्रीय हितों को प्रधान। परन्तु युद्ध के बाद सभी देश आन्तरिक कीमत तल की स्थिरता को प्रधान तथा विनिमय दर की स्थिरता को गौण स्थान देने लगे थे।

स्वर्ण मान का पतन (Break-down of Gold Standard)

प्रथम महा युद्ध के बाद जो स्वर्ण मान स्थापित हुआ उसका इतिहास अत्यन्त ही अल्पकालीन एवं असफलताओं से परिपूर्ण है। 1928 तक स्वर्ण मान को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनायने का कार्य समाप्त हुआ, परन्तु शीघ्र ही 1931 में इंग्लैंड के स्वर्ण मान का त्याग करते ही स्वर्ण मान का अन्तःप्रारम्भ हो गया। वैसे 1929 से ही कई छोटे देशों ने स्वर्णमान को त्याग करना शुरू कर दिया था।

वास्तव में 1914 के पूर्व स्वर्ण मान की सफलता का श्रेय इंग्लैंड को ही था। युद्ध के बाद इंग्लैंड ने जब स्वर्ण मान अपनाया तो युद्ध के प्रभाव के कारण आन्तरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और विदेशी बाजार में उसकी श्रेष्ठता (Supremacy) समाप्त होने लगी थी। अमेरिका इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा था। इंग्लैंड द्वारा युद्ध के पूर्व की स्वर्ण समता की दर अपनाने के कारण उसकी प्रतियोगिता शक्ति विदेशी में और कमजोर हो गई थी। विदेशी व्यापार स्थिर हो जाने के कारण उद्योगों की हालत शावनीय होने लगी और बेरोजगारी निरंतर बढ़ने लगी। भुगतान शेष असंतुलित होता गया। 1929 की महान मंदी ने स्थिति को और खराब कर दिया और इंग्लैंड के लिए स्वर्ण मान पर बने रहना कठिन हो गया और अन्त में 1931 में इसने स्वर्ण मान का सर्वद्व के लिए त्याग कर दिया। इंग्लैंड के स्वर्ण मान छोड़ते ही अनेक देशों ने स्वर्णमान का त्याग कर दिया और 1936 में फ्रांस के स्वर्णमान त्यागने के साथ स्वर्ण मान पूर्ण रूप से समाप्त हो गया।

स्वर्ण मान के पतन के कारण

(Causes of the break down of Gold Standard)

1. प्रतिभूल वातावरण (Unsuitable atmosphere) :

युद्ध के बाद स्वर्ण मान की स्थापना द्वारा यह आशा की गई थी कि युद्ध के पूर्व जिन प्रकार विनिमय दर में स्थिरता एवं कीमत तल में सामञ्जस्य बनाए रखा जाता था, उसी प्रकार की स्थिरता पुनः प्राप्त की जा सकती है। परन्तु युद्ध के बाद

का सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनैतिक वातावरण पूर्णतया भिन्न था एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुकूल नहीं था। इस वातावरण की निम्न लिखित विशेषताएँ थी :

(अ) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना का लोप . प्रत्येक देश में राष्ट्रियता की भावना का उदय हुआ था एवं हर देश अपनी आन्तरिक आर्थिक परिस्थितियों के प्रति अधिक जागरूक था। अन्तर्राष्ट्रीय हितों को प्रधानता नहीं दी जाती थी। अन्तर्राष्ट्रीय हितों का वही तक ध्यान रखा जाता है जहाँ तक उनका राष्ट्रीय हितों से कोई विरोध नहीं होता। कीमत-स्तर की स्थिरता तथा विनिमय दर की स्थिरता में जब चुनाव करना होता तो कीमत-स्तर को ही प्रधानता दी जाती थी। अन्तर्राष्ट्रीय प्रत्येक देश बाह्य आर्थिक प्रभावों से आन्तरिक अर्थ व्यवस्था को बचाने में प्रयत्नशील रहता था जबकि स्वर्ण मान की सफलता के लिए बाह्य आर्थिक प्रभावों का आन्तरिक अर्थव्यवस्था पर पूर्ण प्रभाव पड़ना चाहिए इन प्रकार युद्धोपरांत स्वर्ण मान के अनुकूल वातावरण का अभाव था।

(ब) आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों में परिवर्तन युद्ध के पूर्व इंग्लैंड, आर्थिक जगत् का अगुआ था परन्तु युद्ध के बाद अमेरिका की स्थिति सुदृढ़ हुई और इसको प्रथम स्थान प्राप्त हो गया। लन्दन का स्थान न्यूयार्क ने ले लिया। परन्तु अणु-दाता देश के रूप में जिन जिम्मेदारियों का पालन इंग्लैंड ने युद्ध के पूर्व के वर्षों में किया, अमेरिका युद्ध के बाद के वर्षों में उन्हें निभाने में असमर्थ रहा।

(स) स्वर्ण का असमान वितरण : युद्ध का एक प्रमुख प्रभाव यह रहा कि स्वर्ण का विश्व के देशों में असमान वितरण हुआ गया। स्वर्ण का अधिकांश भाग केवल दो देशों — अमेरिका तथा फ्रांस, के पास केंद्रित हुआ गया। अन्य देशों के पास स्वर्ण का भंडार बहुत कम होने के कारण वे स्वर्ण को निर्यात द्वारा उठे और कम करने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने स्वर्ण मान स्थापना ही अधिक उचित समझा।

(द) मौद्रिक मान के सम्बन्ध में स्वर्ण मान के विपरीत विचार : युद्ध के बाद स्वर्ण मान की पुनः स्थापना के विरोधी विचारों का न स्वर्ण के मौद्रिक प्रयोग को बेकार एवं अप्रव्यय बताया। उनके अनुसार पत्र मुद्रा के नियमन द्वारा भी वही उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं जो स्वर्ण मान में प्राप्त करने का दावा करता है। साथ ही इसमें स्वर्ण मान की अपेक्षा अत्यधिक मितन्ययिता है। उनका यह भी कहना था कि जनता पत्र मुद्रा के प्रयोग की युद्ध के दिनों में अभ्यस्त होने के कारण उन अपमानों में नहीं हिचकेगी। इसके अतिरिक्त पत्र मुद्रा लन दन में सुविधाजनक है। इस प्रकार के विचारों के कारण स्वर्ण मान के प्रति वह अन्धभक्ति समाप्त हो चली थी जो युद्ध पूर्व के वर्षों में थी।

इन प्रकार ऐसे प्रतिकूल वातावरण में स्वर्ण मान सफलता नहीं प्राप्त कर सका और अन्त में समाप्त हो गया ।

2. स्वर्ण मान संचालन के नियमों की अवहेलना

(Violation of the Rules of the Gold Standard) :

स्वर्ण मान के पतन का सबसे प्रमुख कारण यह था कि युद्ध के बाद के वर्षों में स्वर्ण मान संचालन के नियमों का पालन नहीं किया गया । स्वर्ण मान के अंतर्गत मध्य देशों से जिस अनुशासन, त्याग तथा सहयोग की अपेक्षा की जाती है, उसका इस अवधि में नितान्त अभाव था । अनेक देशों की आर्थिक स्थिति इतनी अव्यवस्थित हो गई थी कि इन नियमों का पालन करना प्रायः असम्भव था ।

(अ) स्वर्ण मान की सफलता स्वतन्त्र व्यापार की नीति पर निर्भर करती है जिसे सदस्य देश अपने भुगतान संतुलन को ठीक करके विनिमय दर की स्थिरता बनाय रख सके । परन्तु युद्ध के बाद के वर्षों में स्वतन्त्र व्यापार नीति का पालन नहीं किया गया । व्यापार पर नियन्त्रण रखा जाने लगा । जिन देशों में स्वर्ण आयात हो रहा था—फ्रांस और अमेरिका, उन्होंने विदेशी वस्तुओं पर ऊँची दर पर आयात कर लगा दिया । परिणामस्वरूप मोना खोने वाले देश सोना वापस पाने की बजाय खोने ही चले गए । इसने कारण आन्तरिक मुद्रा की मांग पूरी करना भी कठिन हो गया और उन्हें भी आयात-नियन्त्रण की नीति अपनानी पड़ी और स्वर्ण-मान का अन्त होने लगा ।

(ब) स्वर्ण मान संचालन का दूसरा नियम यह है कि सोना पाने वाला देश मुद्रा प्रसार की नीति अपनाए, तथा सोना भेजने वाला देश मुद्रा संकुचन की नीति अपनाए परन्तु युद्ध के बाद के वर्षों में अमेरिका मोना प्राप्त करने के बावजूद भी मुद्रा प्रसार की नीति नहीं अपना रहा था क्योंकि वह आंतरिक स्थिरता को नष्ट नहीं करना चाहता था । उसी प्रकार फ्रांस ने भी यही नीति अपनाई । फलस्वरूप उनकी कीमती में आवश्यक वृद्धि नहीं हुई और उनका निर्यात व्यो का लो बन रहा । सोना खोने वाले देशों में मुद्रा संकुचन का हानिकारक स्तर पर पहुँचने से रोकने के लिए नोट प्रसार एवं सागर निर्माण का बटाने की नीति अपनानी पड़ी । इस प्रकार स्वर्ण मान को समाप्ति के पथ पर अग्रसर किया गया ।

(स) अन्तर्राष्ट्रीय तन-देन में भी आकस्मिक परिवर्तन किये गये जो स्वर्ण मान संचालन के नियमों के विरुद्ध हैं । अमेरिका ने अचानक जर्मनी को ऋण देना बन्द कर दिया और जर्मनी का विश्वास होकर विनिमय नियन्त्रण का सहारा लेता पड़ा और स्वर्ण मान संकट में पड़ गया । इसी प्रकार फ्रांस भी आर्थिक मंदी के कारण सभी देशों से अपनी पूँजी खींचने लगा । यह स्वर्ण मान के लिए और भी घातक सिद्ध हुआ ।

(द) युद्ध के पूर्व बैंक दर के प्रयोग से उचित ऋण नीति द्वारा बिना अधिक मात्रा में स्वर्ण को निर्यात किए ही पूंजी के आयात को प्रास्ताहित किया जाता था तथा भुगतान शेष को ठीक कर लिया जाता था। युद्ध के बाद शकापूर्ण वातावरण में बैंक दर को बटाने का अर्थ यह लगाया जाने लगा कि उस देश की आर्थिक स्थिति विश्वसनीय नहीं है। इसलिए बैंक दर का विपरीत प्रभाव पड़ने लगा और स्वर्ण मान का संचालन कठिन हो गया।

3. 1929 की महान आर्थिक मदी .

अमेरिका का वालस्ट्रीट सिकट जब विश्वव्यापी बन गया तो विश्व के सभी देशों में कीमतों में भारी गिरावट एवं उत्पादन में ह्रास का वातावरण छा गया। स्वर्ण मान के सफल संचालन पर इस व्यापक मदी का बड़ा घुरा प्रभाव पड़ा। स्वर्ण मान पर आधारित अधिकांश देश अपनी स्थिति को ठीक रखने के लिए दीर्घकालीन विदेशी ऋणों का सहारा लेते थे। परन्तु मदी के फलस्वरूप ऋणदाता बैंक्री ने ऋण देना बन्द कर दिया। साथ ही मदी के कारण निर्यातों से प्राप्त होने वाली कुल राशि में भी कमी आने लगी। ऐसी परिस्थितियों में ऐसे देशों के लिए स्वर्ण मान पर कायम रहना कठिन हो गया जिनका स्वर्ण कोष बहुत कम था। यह परेशानी ऋणदाता देशों द्वारा दिए गए पुराने ऋणों की बसूली के कारण और भी बढ गई।

आस्ट्रिया के क्रेडिट अन्स्टाल्ट (Credit Anstalt) जैसे सुदृढ बैंक को भी इस महान मदी के कारण फेल होना पड़ा क्योंकि इस बैंक का अधिकांश विनियोग उद्योगों में लगा हुआ था और हानि के कारण उद्योगों के बन्द होने से इसका माध्य भी उन्ही उद्योगों के साथ सो गया। इस घटना से विदेशी जमाकर्त्ताओं में ही नहीं स्वयं उस देश के जमाकर्त्ताओं में भी बैंकों के प्रति विश्वास उठ गया। आस्ट्रिया को स्वर्ण मान छोड़ना पड़ा। स्वर्ण मान पर विदेशी प्रभाव शीघ्र पडते हैं इसलिए इस घटना से अन्य देशों में भी जनता ने मुद्राओं के बदले स्वर्ण की माग करना प्रारम्भ कर दिया तथा बैंकों से अपनी जमा निकालने लगे। पहले तो आन्स्ट्रिया इसका शिकार हो ही चुका था अब दूसरा नम्बर जर्मनी का था। विदेशों से काफी मात्रा में ऋण लेकर भी जर्मनी निक्षेपों की वापस प्राप्त करने की माग को पूरा नहीं कर सका तथा अन्त में उसे भी स्वर्ण मान का त्याग करना पड़ा। जर्मनी से हटकर यह मकट इंग्लैंड में पहुँचा। बैंक आफ इंग्लैंड ने इस सिकट से बचने के लिए बैंक दर आदि का सहारा लिया परन्तु इससे स्थिति में सुधार आने के स्थान पर और भी जटिलता आ गई। अमेरिका और फ्रांस से बड़ी मात्रा में ऋण लेकर भी इंग्लैंड स्वर्ण मान की रक्षा नहीं कर सका और 1931 में इसने स्वर्ण मान त्याग दिया। इंग्लैंड के स्वर्ण मान छोड़ते ही सभी साम्राज्य देशों ने भी इसका त्याग कर दिया और इस प्रकार स्वर्ण मान महान मदी की चपेट से बच नहीं सका।

4. प्रथम महायुद्ध की क्षतिपूर्ति का भुगतान •

जर्मनी द्वारा स्वर्ण मान का त्याग करने के कारणों में क्षतिपूर्ति-भुगतान का प्रमुख स्थान था। शांति समझौते की शर्तों के अनुसार विजित जर्मनी को अमेरिका तथा फ्रांस को जो क्षति-पूर्ति भुगतान करना था, उसे जर्मनी स्वयं वस्तुओं के रूप में करना चाहता था परन्तु फ्रांस एवं अमेरिका ने स्वर्ण के रूप में भुगतान पाने पर जोर दिया इसलिए जर्मनी को क्षतिपूर्ति-भुगतान करने के लिए बड़ी मात्रा में सोने की आवश्यकता हुई। उसके पास स्वर्ण मान संचालन के लिए स्वर्ण कोप रखने में कठिनाई होने लगी और जर्मनी ने स्वर्ण मान त्याग दिया।

5 अल्पकालीन पूँजी का आतक •

युद्ध के पूर्व के वर्षों में योरोप के अनेक देशों की अल्पकालीन पूँजी विदेशों में लगी हुई थी परन्तु युद्धकाल में अनेक ऋणी देशों ने व्याज तथा मूलधन की वापसी पर प्रतिबन्ध लगा दिए। इसके अतिरिक्त विदेशी विनिमय दर में (युद्ध के बाद) परिवर्तन करने से भी इन विनियोजकों को हानि हुई। परिणाम यह हुआ कि अल्पकालीन विदेशी पूँजी भयभीत होकर उचित आश्रय की तलाश में एक से दूसरे देश में जाने लगी। परन्तु इस शरणार्थी पूँजी के आकस्मिक आवागमन से मध्यन्धिन देशों को अर्थ व्यवस्थाओं में काफी उथल पुथल पैदा हो गई, जिससे स्वर्ण मान बनाए रखना कठिन हो गया।

6 युद्धोपरांत की अर्थ-व्यवस्थाओं में आंतरिक लोच का अभाव

अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान की सफलता के लिए आंतरिक कीमत तल एवं आय में पर्याप्त लोच का होना आवश्यक है। स्वर्ण की मात्रा कम होने पर मुद्रा की मात्रा एवं कीमत स्तर कम करना पड़ता है कीमत को कम करने के लिए लागत को कम करना भी आवश्यक है परन्तु युद्ध के बाद की परिस्थितियों में लागत को कम करना कठिन था क्योंकि लागत का प्रमुख तत्व मजदूरी को कम करने में श्रमिक सघों के घोर विरोध का सामना करना पड़ता था। यह स्थिति स्वर्ण मान के लिए घातक सिद्ध हुई।

इस प्रकार स्पष्ट है कि युद्ध के बाद की आर्थिक व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय राज-नैतिक वातावरण एवं अन्य परिस्थितियाँ स्वर्ण मान के अनुकूल नहीं थी। सभी देश अपनी जर्जरित अवस्था को सुधारने के लिए आर्थिक प्रगति करना चाहते थे इसलिए आवश्यक था कि उनकी मौद्रिक नीति उनकी आर्थिक आशाओं के अनुरूप हो तथा आन्तरिक स्थिति में स्थायित्व हो, जिससे अबाधगति से उनका विकास होता रहे। बढ़ती हुई आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक मुद्रा की आवश्यकता, सोने की पूर्ति कम एवं असमान होने के कारण, पूरी नहीं की जा सकती थी। सभी देश धीरे-धीरे स्वर्ण मान से असंतुष्ट होते गए और स्वर्ण मान का अन्त हो गया।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके सकेत

(1) स्वर्ण मान किसे कहते हैं ? इसके लाभ तथा हानियों का वर्णन कीजिए ।
(राजस्थान बी० काम०, 1962)

[सकेत—प्रथम भाग में स्वर्ण मान की परिभाषा देते हुए उसकी मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए । दूसरे भाग में स्वर्ण मान के लाभ तथा हानियों का वर्णन कीजिए ।]

(2) स्वर्ण पाट प्रमाण की मुख्य विशेषतायें बताइये तथा स्वर्ण विनिमय प्रमाण से इसका मुनाबला कीजिए ।
(राजस्थान बी० काम० 1963)

[सकेत—स्वर्ण पाट मान की परिभाषा देते हुए उसकी मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए । दूसरे भाग में स्वर्ण पाट मान तथा स्वर्ण विनिमय मान के अन्तर की मुख्य बातें बताइये ।]

(3) अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान के पतन के कारणों का विवेचन कीजिए ।
(राजस्थान बी० काम०, 1965)

[सकेत—अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण मान के त्यागने के मुख्य कारणों की सविस्तार व्याख्या कीजिए ।]

(4) स्वर्ण प्रमाण की उत्कृष्टताओं तथा दोषों का विवेचन कीजिए तथा उनके मविष्य के विषय में अपने विचार प्रकट कीजिए ।

(राजस्थान बी० काम, 1966)

[सकेत—प्रथम भाग में स्वर्ण मान के लाभ तथा हानियों की व्याख्या कीजिए । दूसरे भाग में बताइये कि स्वर्ण मान की पुनः स्थापना सम्भव नहीं है ।]

(5) निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—

(i)

(ii)

(iii) स्वर्ण पाट मान

(iv)

(राजस्थान बी० काम, 1968)

[सकेत—स्वर्ण पाट मान की परिभाषा देते हुए उसकी मुख्य विशेषताओं की व्याख्या संक्षेप में करिए तथा उसके लाभ तथा हानियाँ भी संक्षेप में बताइये ।]

(6) स्वर्ण मान के संचालन में कित-कितने नियमों का पालन करना आवश्यक है ? यह बताइये कि इन नियमों का पालन न करने से किम प्रकार सन् 1931 में स्वर्ण मान टूट गया ।

[सकेत—प्रथम भाग में स्वर्ण मान के चार नियमों मौद्रिक नीति सम्बन्धी नियम, मुक्त व्यापार नीति, अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के लेन-देन सम्बन्धी नियम तथा स्वतन्त्र

स्वर्ण आयात तथा निर्यात की व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में यह बताइये कि 1931 में स्वर्ण मान के पतन का मुख्य कारण सप्ताह के देशों द्वारा इन नियमों का उल्लंघन था।]

(7) दो महायुद्धों के बीच के काल में स्वर्ण मान की कार्य प्रणाली में क्या कठिनाइयाँ अनुभव की गईं? निकट भविष्य में स्वर्ण मान के पुनः स्थापन के लिए आवश्यक शर्तों की चर्चा कीजिए।

(राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल 1961)

[संकेत — प्रथम भाग में दो महायुद्धों के बीच के काल में स्वर्ण मान की कार्य प्रणाली में जो कठिनाइयाँ आईं उनका विवेचन कीजिए और बताइये कि इन्हीं कठिनाइयों के कारण स्वर्ण मान का पतन हो गया। द्वितीय भाग में सप्ताह में स्वर्णमान की पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक शर्तों की चर्चा कीजिए। उपसंहार में बताइये कि वे शर्तें आज के सप्ताह में पूरी नहीं हो सकती, अतः स्वर्ण मान का पुनर्स्थापना की कोई सम्भावना नहीं।]

पत्र मान (Paper Standard)

"In modern times, the confidence of the people in currency depends not on what people might get in exchange of currency notes, but on sound economic and financial policies followed by the government and banking authority"

पत्र मान (Paper Standard)

पत्र मुद्रा का इतिहास तो काफी पुराना है परन्तु पत्र मान का प्रारम्भ अपेक्षा कृत कम समय से हुआ है। पत्र मुद्रा का प्रारम्भ धातुमान के युग में ही उसकी असुविधाओं से मुक्ति पाने के उद्देश्य से किया गया। परन्तु इस प्रकार की पत्र मुद्रा को पत्र मान के अन्तर्गत शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इसका नियंत्रण वस्तुतः धातुमान के सिद्धान्तों पर होता था।

पत्र मान के अन्तर्गत पत्र मुद्रा का मूल्य किसी भी वस्तु या धातु के आधार पर नियंत्रित नहीं किया जाता। नोटों में परिवर्तनशीलता का गुण नहीं होता केवल अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा तथा साकेतिक सिक्कों का चलन होता है। ऐसे पत्र मान का विकास प्रथम महायुद्ध के बाद हुआ। युद्ध की कठिन परिस्थितियों से बाध्य होकर अनेक देशों ने पत्र मुद्रा असाधारण मात्रा में जारी की जिसे परिवर्तनीय नहीं रखा जा सका और पत्र मान को अनिच्छा पूर्वक अपनाया गया। युद्ध के बाद धातुमान को अपनाने का पुनः प्रयत्न किया गया जो असफल रहा और पत्र मान का आधिपत्य बढ़ता गया। बाद में ऐसे देशों ने भी पत्र मान अपना लिया जो परिस्थितियों से विवश नहीं थे। इस प्रकार प्रायः सभी देशों में पत्र मान का युग आ गया।

पत्र मान के दो भेद किए जा सकते हैं—

- 1 स्वतंत्र पत्र मान (Free Paper Standard)
- 2 नियंत्रित पत्र मान (Controlled Paper Standard)

(1) स्वतंत्र पत्र मान (Free Paper Standard)—स्वतंत्र पत्र मान के अन्तर्गत एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा से स्वतंत्र सम्बन्ध है। विनियमन पर परिवर्तित होने को स्वतंत्र रहती है। उनके स्थिर बनाए रखने का कानूनी

प्रयत्न नहीं किया जाता। परन्तु विनिमय दर में स्थायित्व लाने के लिए विदेशी विनिमय बाजार को विनिमय स्थिरीकरण कोष (Exchange Stabilisation Fund) आदि के द्वारा प्रभावित करन का प्रयास किया जाता है।

(2) नियंत्रित पत्र मान (Controlled Paper Standard) — नियंत्रित पत्र मान के अन्तर्गत विनिमय दर को पूर्ण रूप से नियंत्रित किया जाता है। विनिमय दर बाजार शक्तियों (Market forces) द्वारा निर्धारित होने के लिए स्वतंत्र नहीं होती। नियंत्रित पत्र मान के अन्तर्गत बहुमुखी विनिमय दर का बोल बाला रहता है। जर्मनी ने 1930 के दशक में रीश मार्क की डालर विनिमय दर अलग-अलग वस्तुओं के सदर्भ में अलग रखी थी। द्वितीय महायुद्ध के बाद विभिन्न अंशों में नियंत्रित पत्र मान चलता रहा।

पत्र मान के अन्तर्गत मुद्रा के परिमाण में मौद्रिक सस्या द्वारा असाधारण रूप से परिवर्तन कर दिया जाता जिसके फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य स्थिर नहीं रह पाता और वह मुद्रा के कार्यों को विशेष रूप से मावी भुगतान के आधार के रूप में कार्य सुचारु रूप से नहीं कर पाती। मुद्रा के मूल्य को स्थिरता प्रदान करने के लिए कई प्रकार के पत्र मान मुभाए गए हैं।

तालिका मान (Tabular Standard) — यद्यपि इस प्रकार के मान का अध्ययन लोव (Lowe) तथा पौलेट स्कूप (Poulett Scrope) द्वारा किया गया था परन्तु इसका सुझाव प्रा० फिशर द्वारा दिया गया तथा यह मान उन्ही के नाम से विशेष रूप से सम्बद्ध है। इस मान का उद्देश्य विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के मद्देन में मुद्रा का मूल्य स्थिर रखना है जिससे विलंबित देनो से सम्बन्धित पक्षों को अनुविधा या हानि न हो। इस सम्बन्ध में यह सुझाव दिया गया था कि विनिमय में अधिकांशतः प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं के आधार पर निर्देशांक बनाया जाना चाहिए जिससे कीमतों के परिवर्तन का बाध हो सक और परिवर्तित कीमतों के आधार पर विलंबित देनो का भुगतान किया जाना चाहिए। ऋण लेते समय यदि निर्देशांक 100 हो और अदायगी के समय यदि निर्देशांक 200 हो तो व्याज के अतिरिक्त ऋण की दुनी रकम भुगतान की जानी चाहिए और यदि भुगतान के समय निर्देशांक 50 है तो व्याज के अतिरिक्त ऋण की आधी रकम भुगतान की जानी चाहिए।

प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार के मान में पर्याप्त औचित्य दिखाई देता है परन्तु व्यावहारिक स्तर पर इसमें अनेक कठिनाइयाँ आ सकती हैं। इसमें पूरी व्यवस्था का आधार निर्देशांको का बनाया जाता है परन्तु निर्देशांको को पूर्ण विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त ऋणी और ऋणदाता बड़ी ही अनिश्चित अवस्था में होंगे क्योंकि किसी को यह मालूम नहीं रहगा कि उस कितनी रकम देनी

है अथवा लेनी है। इसलिए साख-पद्धति जो वर्तमान अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ है घातक रूप से प्रभावित होगी।

स्थिरीकृत पत्र मान (Stabilised Paper Standard)—इस प्रकार के पत्रमान का सुझाव भी इसी उद्देश्य से दिया गया था कि मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव से बचा जा सके। इस सुझाव के अनुसार चलन में पत्र मुद्रा होनी चाहिए परन्तु उसका मूल्य धातु में निश्चित कर दिया जाना चाहिए किन्तु यह धातु मूल्य कीमत स्तर में परिवर्तन हान के साथ घटता बढ़ता रहना चाहिए। कीमत स्तर के परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए इसमें निर्देशांक का प्रयोग किया जायेगा। यदि कीमत स्तर दूना बढ़ा है—दूसरे शब्दों में मुद्रा का मूल्य आधा रह गया है, तो पत्र मुद्रा का धातु मूल्य उसी अनुपात में बढ़ा दिया जायेगा जिससे मुद्रा का मूल्य पूर्ववत् हो जाय।

यह व्यवस्था भी व्यावहारिक स्तर पर दोषपूर्ण है क्योंकि इसमें निर्देशांक का सहारा लेना पड़ता है जो स्वयं दोषपूर्ण होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें प्रत्येक कीमत परिवर्तन के साथ मुद्रा के धातु मूल्य को परिवर्तित करना होगा जो व्यवस्था के दृष्टिकोण से कठिन है। यही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान में भी कठिनाई होगी क्योंकि विनिमय दर निश्चित नहीं रहेगा।

पत्र मान के गुण (Merits of Paper Standard)—

1. लोच—अपने लोच के गुण के कारण पत्र मुद्रा आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ रहती है। प्रगतिशील देशों की आर्थिक आवश्यकताएँ निरंतर बढ़ती रहती हैं और धातु की कमी तथा खर्चीलपन के कारण उनकी पूर्ति का सर्वोत्तम साधन पत्र मान है।

2. प्रबन्ध की सुविधा—पत्र मान का संचालन बड़ा सरल है तथा सरकार इसके प्रबन्ध में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। बाह्य शक्तियों का प्रभाव सरकार की मौद्रिक एवं आर्थिक नीति पर नहीं पड़ता। सरकार अपनी आर्थिक एवं मौद्रिक नीति देश के हितों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित कर सकती है।

पत्र मान के दोष (Demerits of Paper Standard)—

1. अत्यधिक प्रसार का भय—सबसे बड़ा दोष यह है कि पत्र मान पूर्णरूप से सरकार पर आश्रित होता है और सरकार पर किसी प्रकार का अंकुश न होने के कारण मुद्रा की मात्रा के सम्बन्ध में राजनैतिक निर्णय लिए जाने की शका रहती है जो आर्थिक हितों में वृद्धि के स्थान पर कमी कर सकती है। अत्यधिक मुद्रा प्रसार या सकुचन के परिणाम कितने घातक हो सकते हैं फ्रांस एवं जर्मनी इसके ज्वलत उदाहरण हैं।

2. विदेशी भुगतान सम्बन्धी कठिनाई—पत्रमान का दूसरा प्रमुख दोष यह है कि इसमें विनिमय दर निर्धारित करने का कोई आधार नहीं होता है। विनिमय दर में अन्तरिक्ष कीमतों के साथ घटने बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। परन्तु जब कुछ मुद्राओं की साख विश्वव्यापी हो जाती है तो विदेशी व्यापार में कोई कठिनाई नहीं होती क्योंकि अधिकांश देश उन अच्छी साख वाली मुद्राओं को कोप में रखते हैं और उन्हीं के माध्यम से भुगतान करते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नियंत्रण में रहकर ही पत्रमान अन्तरिक्ष अर्थ व्यवस्था का समुचित विकास करने में सहायक हो सकता है एवं विदेशी व्यापार में गतिरोध का कारण बनने से बच सकता है।

पत्र मुद्रा का निर्गमन (Note Issue)

बहु निर्गमन पद्धति (Multiple Issue System) —प्रारम्भ में नोट निर्गमन की इसी पद्धति को अपनाया गया था और इस कार्य को व्यापारिक बैंक सम्पन्न करते थे। भारतवर्ष में यह पद्धति 1861 के पूर्व क्रियाशील थी। परन्तु इस प्रणाली में कई दोष थे जिनका वर्णन नीचे किया गया है :—

1 नोटों में एकरूपता का अभाव :—विभिन्न व्यापारिक बैंकों द्वारा नोट जारी किए जाने के कारण उनके प्रकार-प्रकार, डिजाइन आदि में अन्तर रहता था जिससे उनका चलन-क्षेत्र विस्तृत नहीं होता था।

2 बैंकों में प्रतिप्रोगिता —नोट जारी करने वाले बैंक कभी-कभी होड़ में आकर आवश्यकता से अधिक नोट जारी कर देते थे जो राष्ट्र के हितों के प्रतिकूल होता था।

3 जनता के विश्वास में कमी —बैंकों की माल में सामान्य जनता का अधिक विश्वास न होने के कारण इन नोटों में जनता का विश्वास कम होता था।

4, अधिक कोप की आवश्यकता.—अनेक बैंकों द्वारा नोट जारी किए जाने के कारण कोप के रूप में अपेक्षाकृत अधिक धातु की आवश्यकता पड़ती थी।

5. नोट निर्गमन-नीतियों में अन्तर —अलग-अलग बैंक नोट जारी करने की अलग-अलग नीति अपनाते थे जिससे पूरे देश की एक सुव्यवस्थित मुद्रा-नीति नहीं बन पाती थी।

उपरोक्त कमियों के कारण प्रायः सभी देशों ने एकाकी नोट निर्गमन पद्धति को अपनाया और नोट जारी करने का कार्य स्वयं सरकार या केन्द्रीय बैंक को सौंपा।

एकाकी नोट-निर्गमन पद्धति (Single Issue System) :—इस प्रणाली के अन्तर्गत नोट जारी करने के सम्बन्ध में उचित विधान की व्यवस्था द्वारा नोट जारी

करने का कार्य एक सस्था को सौंप दिया जाता है। वह सस्था केन्द्रीय बैंक हो सकता है या स्वयं सरकार।

नोट बौन जारी करे ? :—यद्यपि एकाकी प्रणाली में सरकार स्वयं भी नोट जारी करने का दायित्व ले सकती है फिर भी अनेक कारणों से केन्द्रीय बैंक द्वारा नोट जारी करना अधिक उपयुक्त है। यहाँ पर सरकार द्वारा नोट जारी करने के गुण दोषों का तथा केन्द्रीय बैंक द्वारा नोट जारी करने के पक्ष में दिए गए तर्कों का उल्लेख करना आवश्यक है।

सरकार द्वारा नोट जारी करने के पक्ष में तर्क :

1. राष्ट्र का हित :—आधुनिक सरकारें कल्याणकारी सरकारें कही जाती हैं और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे जो भी कार्य करेंगी राष्ट्रीय हित का ध्यान में रख कर करेंगी। इसलिए सरकार द्वारा नोट जारी किए जाने पर राष्ट्र हित का समुचित ध्यान रखा जा सकेगा।

2 अधिक विश्वास :—सरकार की साख में जनता का अधिक विश्वास होने के कारण उसके द्वारा जारी किए गए नोटों में भी जनता का विश्वास अधिक होगा।

3. कुशल प्रबन्ध :—सरकार की विशालता एवं साधन सम्पन्नता के कारण योग्य कर्मचारियों की सेवाओं को प्राप्त किया जा सकता है और नोट जारी करने का कार्य कुशलतापूर्वक सम्पादित किया जा सकता है।

4 मौद्रिक नीति का शीघ्रता से पालन :—नीति निर्धारण एवं उसके अनुसार नोट जारी करने का काम दोनों ही सरकार के हाथ में रहने पर नीतियों के अनुसार नोट जारी करने में शीघ्रता से काम लिया जा सकता है।

परन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण से अगर इन तर्कों का विश्लेषण किया जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी तर्क अल्पपूर्ण हैं। सरकार का ध्यान विशेष रूप से राजनैतिक एवं सामाजिक समस्याओं में लगा रहने के कारण कभी-कभी व्यावसायिक आवश्यकताओं एवं समस्याओं की ओर उसका ध्यान उचित मात्रा में नहीं जा पाता और नोट जारी करने की सभी सुविधाएँ नहीं मिल पाती। राजनैतिक प्रभाव कभी-कभी आर्थिक दृष्टि से आधारभूत नीतियों का पालन करने में बाधक सिद्ध हो सकता है एवं अत्यधिक मुद्रा-प्रसार का कारण बन सकता है। जहाँ तक कुशल प्रबन्ध का सम्बन्ध है प्रायः यही देखा जाता है कि सरकारी कार्यों में अत्यन्त शिथिलता होती है; मौद्रिक कार्यों में शिथिलता बड़े भयानक परिणाम का कारण बन सकती है।

केन्द्रीय बैंक द्वारा नोट निर्गमन के पक्ष में तर्क :

1. आर्थिक आवश्यकता के अनुरूप लोच :—केन्द्रीय बैंक किसी भी देश की बैंक व्यवस्था की धुरी होता है और वह देश के व्यापारिक बैंकों के निकट सम्पर्क में होता है। उसे देश की आर्थिक अवस्था का सही सही ज्ञान होना है। इसलिए वह आवश्यकता के अनुसार नोटों की मात्रा परिवर्तित करने की स्थिति में हाता है।

2. केन्द्रीय बैंक राजनैतिक प्रभाव से दूर :—केन्द्रीय बैंक नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है एवं अपने निर्णयों पर पहुँचने में केवल आर्थिक आवश्यकताओं और देश के हित का ध्यान रखता है। उस पर राजनैतिक प्रभाव पड़ने की सम्भावना कम होती है।

3. कुशल प्रबन्ध :—सरकार की अपेक्षा केन्द्रीय बैंक अपनी व्यवस्था एवं प्रशासन में अधिक क्रियाशीलता एवं कुशलता प्राप्त कर सकता है। एक प्रकार का कार्य करने से यह विशेषज्ञ बन जाता है।

नोट निर्गमन के सिद्धान्त (Principles of Note Issue)

नोट जारी करने की आदर्श प्रणाली में कुछ विशेषताओं का होना आवश्यक है। वे विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. अत्याधिक प्रसार हीनता —नोट जारी करने की आदर्श प्रणाली वही हो सकती है जिसके अनुसार नोट जारी करने पर मुद्रा का अधिक प्रसार होने की सम्भावना न रहे।

2. लोच —व्यापार एवं उद्योग का विकास तभी सम्भव है जब मुद्रा की मात्रा व्यावसायिक मांग के अनुरूप परिवर्तित की जा सके अर्थात् उत्तम लोच हो।

3. स्वत. चालिता :—नोटों की मात्रा में बिना किसी हस्तक्षेप के व्यावसायिक मांग के अनुसार स्वतः परिवर्तन होता रहना चाहिए। इसके लिए नोट जारी करने का आधार ऐसा होना चाहिए जो व्यापारिक यतिविधि के परिवर्तित होते ही प्रभावित हो सके। जैसे व्यापारिक बिलों को नोट जारी करने का आधार बनाने से ऐसा हो सकता है।

4. मितव्ययिता .—नोट जारी करने की प्रणाली कम खर्चीली होनी चाहिए। यदि मितव्ययिता नहीं होगी तो इसमें और धातु मुद्रा में कोई अन्तर नहीं।

5. सरलता :—एक मुद्रा को प्रचलन में बनाए रखने के लिए जनता का विश्वास आवश्यक है परन्तु जनता की आस्था नोटों में तभी होगी जब वह उसकी व्यवस्था को समझेगी। इसलिए नोट जारी करने की प्रणाली सरल होनी चाहिए।

नोट जारी करने की अनेक प्रणालियाँ दो सिद्धान्तों में से किसी एक पर निर्भर करती हैं। ये सिद्धान्त हैं—मुद्रा सिद्धान्त तथा बैंकिंग सिद्धान्त (Currency Principle and Banking Principle)। मुद्रा-सिद्धान्त के अन्तर्गत जनता के

विश्वास को बनाए रखने पर अधिक जोर दिया जाता है और इसके लिए शतप्रतिशत कोप रखा जाता है। परन्तु इस सिद्धान्त पर नोट जारी करने में आदर्श प्रणाली में पाए जाने वाले अन्य गुणलोच, मितव्ययिता आदि का अभाव होता है। बैंकिंग सिद्धान्त के अन्तर्गत आवश्यक लोच एवं मितव्ययिता का गुण पाया जाता है क्योंकि इसमें शत प्रतिशत कोप रखने की जरूरत नहीं होती। जिस प्रकार बैंक थोड़े नकद के आधार पर अधिक जमा निर्माण करते हैं वैसे ही थोड़े कोप के आधार पर अधिक नोट जारी किए जाते हैं। परन्तु इस प्रणाली में कमी-कमी अत्यधिक प्रसार की आशंका रहती है तथा इसमें जनता का विश्वास कम रहता है।

नोट निगमन की प्रमुख प्रणालियाँ (Methods of Note Issue) :

1 आनुपातिक कोप प्रणाली (Proportional Reserve System).—

बैंकिंग सिद्धान्त पर आधारित इस प्रणाली के अनुसार जारी किए गए नोटों के एक निश्चित अनुपात में ही कोप रखने की आवश्यकता होती है। जारी किए गए नोटों के एक निश्चित प्रतिशत के बराबर साने-घादी का कोप रखना पड़ता है और शेष के पीछे विशिष्ट कोटि की प्रतिभूतियाँ और व्यापारिक विनिमय पत्र आदि रखे जाते हैं। जैसे यदि जारी किए नोटों के 40% के बराबर धातु का कोप रखा जाय और शेष 60% के बराबर प्रतिभूतियाँ और विनिमय पत्र रखे जाय तो ऐसी प्रणाली आनुपातिक कोप प्रणाली कही जायेगी। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि कोप का प्रतिशत कमी बदला ही नहीं जा सकता। आवश्यकता के अनुसार सरकार इस अनुपात को बदल सकती है।

इस प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मनी में 1875 में हुआ। इसके प्रतिरिक्त फ्रांस तथा अमेरिका में भी प्रथम महायुद्ध के बाद यही प्रणाली अपनाई गई। भारत-वर्ष में भी 1956 के पूर्व इसी प्रणाली के अनुसार नोट जारी किए जाते थे।

गुण —

1. लोच :— इस प्रणाली में चूँकि शत प्रतिशत कोप की आवश्यकता नहीं होती इसलिए इसमें लोच की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है।

2. जनता का विश्वास :— इस प्रणाली के पीछे कोप रखे जाने के कारण जनता का इसमें अधिक विश्वास रहता है। इसके अन्तर्गत परिवर्तनशीलता को बनाए रखना भी सम्भव होता है।

3. अत्याधिक प्रसार हीनता :— इस प्रणाली में कोप रखने की आवश्यकता होती है इसलिए नोटों की मात्रा अत्यधिक नहीं बढ़ाई जा सकती।

दोष—

धातु के कोप की कमी हो जाने पर मुद्रा की मात्रा कम करनी पड़ती है जिससे मुद्रा सकुचन के बुरे परिणाम भुगतने हो सकते हैं। इसके अलावा यह प्रणाली अपेक्षाकृत अधिक खर्चीली है।

2. शत प्रतिशत कोष प्रणाली (Simple Deposit System) .—

यह प्रणाली मुद्रा सिद्धान्त पर आधारित है। इसके अन्तर्गत जारी किए नोटों के पूर्ण मूल्य के बराबर धात्विक कोष रखना पड़ता है। यह प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के जारी करने में प्रयुक्त होती है।

गुण .—

1. जनता का विश्वास—इस प्रणाली में जनता का विश्वास सर्वाधिक होता है तथा नोटों की परिवर्तनशीलता पूर्ण रूप से सुरक्षित रहती है।

2. अत्याधिक प्रसार हीनता—शत प्रतिशत धातु कोष में रखने की आवश्यकता के कारण इसमें मुद्रा की मात्रा अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती।

दोष —

1 लोच का अभाव—व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा की मात्रा में तब तक परिवर्तन सम्भव नहीं होता जब तक मुद्रा के पीछे कोष रखने के लिए धातु की मात्रा में परिवर्तन न हो।

2 खर्चीली प्रणाली—यह प्रणाली अधिक खर्चीली है क्योंकि बहुमूल्य धातु प्रायः बकार पड़ी रहती है। धातु प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त पूंजी एवं श्रम भी एक प्रकार से बेकार जाता है।

3. निश्चित विश्वासाश्रित प्रणाली (Fixed Fiduciary System) -

इस प्रणाली के अनुसार जारी किए गए नोटों के पीछे शत प्रतिशत धात्विक कोष रखने की आवश्यकता नहीं होती। सरकार नोटों की एक सीमा निर्धारित कर देती है और उस सीमा तक नोट जारी करने के लिए कितनी प्रकार का धात्विक कोष नहीं रखा जाता। इस सीमा को निश्चित विश्वासाश्रित सीमा (Fixed Fiduciary Limit) कहते हैं। इस सीमा से अधिक नोट जारी करने पर अनिश्चित नोटों के लिए शत प्रतिशत धात्विक कोष रखना आवश्यक होता है। जिस सीमा तक धात्विक कोष नहीं रखा जाता, उसके पीछे सरकारी प्रतिभूतियों तथा व्यापारिक बिलों की आड़ रहती है। यदि विश्वासाश्रित सीमा 200 करोड़ मौद्रिक इकाई हो तो इस सीमा तक केवल प्रतिभूतियाँ एवं विनिमय विपत्र रखे जाते हैं और इससे अधिक अर्थात् यदि 300 करोड़ इकाई नोट जारी करने हो तो 100 करोड़ के आधिरस्य के पीछे 100 करोड़ इकाई के मूल्य की धातु रखनी होगी।

इस प्रणाली का प्रचलन ब्रिटेन में काफी समय तक रहा। सर्वप्रथम ब्रिटेन ने इसे 1844 में बैंक चार्टर एक्ट के अन्तर्गत अपनाया। ब्रिटेन ने 140 लाख पाउंड की निश्चित विश्वासाश्रित सीमा निर्धारित की परन्तु बाद में इस सीमा में परिवर्तन होते गए। भारत में यह प्रणाली 1861-1920 तक अपनाई गई।

गुण—

1 जनता का विश्वास—यद्यपि इस प्रणाली में शत प्रतिशत प्रणाली से कम धात्विक कोष रहता है परन्तु फिर भी जनता का विश्वास बना रहता है क्योंकि नोटों की परिवर्तनशीलता को कायम रखा जा सकता है।

2 अत्याधिक प्रसार हीनता—इस प्रणाली में एक सीमा के बाद शत प्रतिशत कोष रखने के कारण अत्याधिक प्रसार का कोई भय नहीं रहता।

दोष—

1. लोचहीन—यह प्रणाली लोचहीन है क्योंकि धातु के बिना व्यापारिक आवश्यकताओं की मांग के अनुरूप मुद्रा की मात्रा नहीं बढ़ाई जा सकती।

2. खर्चीली—इस प्रणाली में अधिक धातु की आवश्यकता होती है इसलिए यह प्रणाली मितव्ययी नहीं है।

3. सरलता का अभाव—यह प्रणाली अपेक्षाकृत जटिल है।

4 अधिकतम विश्वासाश्रित सीमा प्रणाली (Maximum Fiduciary System)—

इस पद्धति को सीमित नोट परिमाण प्रणाली (Maximum Note-Limit System) भी कहते हैं। इसमें नोटों की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी जाती है। उस सीमा तक बिना धात्विक कोष के नोट जारी किए जा सकते हैं परन्तु उस सीमा से अधिक नोट जारी किए ही नहीं जा सकते। शत प्रतिशत धात्विक कोष रख कर भी जारी नहीं किए जा सकते। सरकार द्वारा यदि सीमा बढ़ा दी जाती है तो अवश्य अधिक नोट जारी किए जा सकते हैं। यह प्रणाली फ्रांस में 1928 से पूर्व प्रचलित थी।

गुण—

1 अत्याधिक प्रसार हीनता—इस प्रणाली में किसी भी परिस्थिति में एक निश्चित सीमा से अधिक नोट जारी करने की अनुमति नहीं होती इसलिए मुद्रा प्रसार का भय नहीं होता।

2. मितव्ययिता—इसमें धात्विक कोष की विल्कुल आवश्यकता नहीं होती इसलिए यह बहुत मितव्ययी है।

3. लोच—इस प्रणाली में लोच पायी जाती है क्योंकि अधिकतम सीमा व्यापारिक आवश्यकताओं का अनुमान लगा कर निश्चित की जाती है और उस सीमा तक नोटों की मात्रा में वृद्धि करने में कठिनाई नहीं होती है।

दोष—

1. जनता के विश्वास का अभाव—इस प्रणाली में जनता का सबसे कम विश्वास रहता है क्योंकि परिवर्तनशीलता नहीं होती।

2. लोच की कमी—यदि सीमा से अधिक नोट जारी करना व्यावसायिक दृष्टिकोण से आवश्यक हो जाय तो भी इसकी पूर्ति इस प्रणाली में नहीं हो सकती। इसलिए इसमें लोच की कमी है।

5. न्यूनतम कोष प्रणाली (Minimum Reserve System)—

इस प्रणाली के अनुसार धात्विक कोष की एक न्यूनतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है, जिससे कम धात्विक कोष नहीं रखा जाना चाहिए; नोटों की मात्रा चाहे जो भी हो। भारत वर्ष में 1956 के बाद से यही प्रणाली अपनाई गई है।

गुण—

1. लोच—इस प्रणाली में नोटों की मात्रा व्यावसायिक भाग के अनुरूप रखी जा सकती है, इसलिए इसमें लोच है।

2. मितव्ययिता—अधिकतम नोट सीमा प्रणाली के अतिरिक्त अन्य सभी प्रणालियों की अपेक्षा अधिक मितव्ययी है।

दोष—

1. अत्याधिक प्रसार का भय—इस प्रणाली में अत्यधिक मुद्रा प्रसार होने का भय रहता है क्योंकि एक निश्चित कोष के आधार पर असीमित मात्रा में नोट जारी किए जा सकते हैं।

2. जनता के विश्वास का अभाव—इस प्रणाली में जनता का विश्वास कम होता है।

6. कोषागार विपन्न प्रणाली (Bonus Deposit System)—

इसमें नोट जारी करने के लिए धात्विक कोष की आवश्यकता नहीं होती। कोषागार विपन्न अथवा सरकारी बांडों के आधार पर ही नोट जारी किए जाते हैं।

गुण दोष—इस प्रणाली में सरकारी प्रतिज्ञा पत्रों के माध्यम से अत्यधिक प्रसार को नियंत्रण में अवश्य रखा जा सकता है परन्तु सरकार अधिक मात्रा में कोषागार विपन्न जारी करके अधिक प्रसार कर सकती है यही इसका दोष है। मितव्ययिता का गुण पाया जाता है पर जनता के विश्वास का अभाव है।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संकेत

(1) पत्र मुद्रा निर्गमन की विभिन्न प्रणालियों को स्पष्ट कीजिए। इनमें से किसको आप अच्छा समझते हैं और क्यों? (आगरा 1956; सागर 1958)

[संकेत—पत्र मुद्रा निर्गमन की विभिन्न प्रणालियों की व्याख्या कीजिए और बताइये कि निर्गमन पद्धति में लोच के गुण के कारण आनुपातिक कोष प्रणाली या न्यूनतम कोष प्रणाली सर्वोत्तम है।]

(2) सन् 1956 मे भारत मे आनुपातिक कोप प्रणाली को बदल कर न्यूनतम कोप प्रणाली क्यो अपनाई गई ? इसका भारतीय चलन पर क्या प्रभाव पडा ?

(राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल, 1961)

[सकेत—सन् 1956 मे न्यूनतम कोप प्रणाली के अपनाने के कारण लिखिए तथा भारत के चलन पर उसके प्रभाव की विवेचना कीजिए।]

(3) निम्नलिखित मे से किन्ही तीन पर सक्षिप्त टिप्पणिया लिखिए।

(i)

(ii)

(iii)

(iv) पत्र मुद्रा चलन की विश्वासाश्रित पद्धति (Fiduciary System of Note Issue)

(v)

(राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल, 1965)

[सकेत—निश्चित विश्वासाश्रित प्रणाली का चर्चा कीजिए तथा सक्षेप मे उसके लाभ तथा हानिया बताइये।]



8

मुद्रा का मूल्य (I)

मुद्रा का मूल्य-निर्देशांक (Value of Money-Index Numbers)

"Index numbers, in short, are one guide to an understanding of economic problems and indicate general tendencies which are very helpful in solving various socio-economic problems of the country."

मुद्रा के मूल्य का अर्थ :—

वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य मुद्रा में व्यक्त किया जाता है परन्तु मुद्रा का मूल्य किसमें व्यक्त किया जाय। मुद्रा के मूल्य को मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह कहना कि 'एक रुपया एक रुपये के बराबर है' कोई अर्थ नहीं रखता। मुद्रा की माँग मुद्रा के लिए नहीं बल्कि उसकी नयी शक्ति या वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता के कारण होती है। अतः मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य 'दिनिमय-अर्थ' (Value-in-exchange) या सामान्य रूप से वस्तुओं को क्रय करने की शक्ति से होता है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त होकर 'कीमत' (Price) कहलाता है। अतः वस्तुओं और सेवाओं के रूप में ही मुद्रा के मूल्य का व्यक्त किया जा सकता है। इसे सामान्य कीमत तल का व्युत्क्रम (Reciprocal) माना जा सकता है।¹

¹ "Since the purchasing power of money in a given context depends on the quantity of goods and services which a unit of money will purchase, it follows that it can be measured by the price of a composite commodity, made up of the various individual goods and services in proportions corresponding to their importance as objects of expenditure..... The price of a commodity which is representative of some type of expenditure, we shall call a Price Level"

मुद्रा की ऋय शक्ति का आशय है कि मुद्रा की एक इकाई के बदले कितनी वस्तुएँ एव सेवायें प्राप्य हैं। चेंडलर के शब्दों में मुद्रा के मूल्य शब्दों का अर्थ है मुद्रा की ऋय शक्ति—प्रत्येक इकाई की वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने की क्षमता।¹ वस्तुओं और सेवाओं को ऋय करने की शक्ति के कारण ही मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है। वस्तुओं और नवाओं की कीमतों में परिवर्तन होने पर मुद्रा की ऋय शक्ति घट या बढ़ जाती है और मुद्रा का मूल्य कभी अधिक हो जाता है और कभी कम। यदि कीमतें घट जाय तो मुद्रा की एक इकाई अधिक वस्तुएँ तथा सेवायें ऋय करती है अर्थात् मुद्रा की ऋय शक्ति बढ़ जाती है और मुद्रा का मूल्य भी बढ़ जाता है। इसके विपरीत, यदि कीमतें बढ़ जाय तो मुद्रा की एक इकाई पहले से कम वस्तुएँ तथा सेवायें ऋय करती है अर्थात् मुद्रा की ऋय शक्ति घट जाती है और उसका मूल्य भी घट जाता है। इस प्रकार मुद्रा के मूल्य का प्रश्न उसकी ऋय शक्ति से सम्बन्धित है और इसके परिवर्तनों के माप के लिए उन सभी वस्तुओं की कीमतों के परिवर्तनों का आधार ग्रहण करना पड़ता है जिनका मूल्यांकन मुद्रा द्वारा होता है।

मुद्रा मूल्य तथा कीमतों में विपरीत सम्बन्ध है।² जब कीमतें बढ़ती हैं मुद्रा का मूल्य गिरता है और कीमतें घटती हैं तो मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। इस प्रकार मुद्रा का सामान्य मूल्य उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों द्वारा जाना जा सकता है जिनके विनिमय के माध्यम के रूप में वह कार्य करती है। दो विभिन्न समयों में मुद्रा के मूल्य में हुए परिवर्तन को ज्ञात किया जा सकता है परन्तु सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों के आधार पर मुद्रा के 'सामान्य' मूल्य में परिवर्तनों का ज्ञान हो भी जाय तो इसका कोई अर्थ नहीं। समाज के विभिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न वस्तुओं में रुचि रखते हैं और वे उन्हीं वस्तुओं की कीमतों से प्रभावित होते हैं अतः निरपेक्ष रूप में 'मुद्रा का मूल्य' एक अर्थहीन सज्ञा है।³ मुद्रा का मूल्य किसी विशेष प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के सन्दर्भ में व्यक्त होना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न प्रयोगों की दृष्टि से मुद्रा के विभिन्न मूल्य होते हैं और उसका माप विशिष्ट प्रयोग से

¹. 'By the term value of money is meant the purchasing power of money—the ability of each unit to command goods and services in exchange'

—L. V. Chandler *An Introduction to Monetary Theory*, p 10

². "The purchasing power of money is the reciprocal of the level of prices So that the study of purchasing power of money is identical with the study of price levels"

—Irving Fisher *The Purchasing Power of Money*, p 14

³ Objectively, the value of money is a meaningless concept.

सम्बन्धित विशिष्ट कीमत तल द्वारा ही होता है :¹ इस आधार पर मुद्रा के मूल्य तीन प्रकार के होते हैं।²

(1) मुद्रा का थोक मूल्य (Wholesale value) : मुद्रा के थोक मूल्य का निर्धारण वस्तुओं के थोक बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर किया जाता है। इस श्रेणी की वस्तुओं में अधिक माना में क्रय विक्रय होने वाले कच्चे माल आते हैं। व्यापार आदि की दशा का अनुमान मुद्रा के थोक मूल्य द्वारा ही लगाया जाता है।

(2) मुद्रा का फुटकर मूल्य (Retail Value of Money or the Cost of Living) मुद्रा का फुटकर मूल्य उपरोक्त द्वारा अन्तिम उपभोग में प्रयुक्त दैनिक व्यवहार की वस्तुओं की फुटकर कीमतों द्वारा निर्धारित होता है।

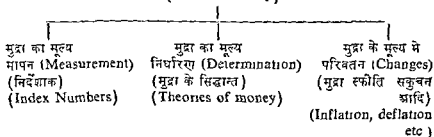
(3) मुद्रा का श्रम मूल्य (Labour Value of Money) : मुद्रा के श्रम मूल्य का तात्पर्य वस्तुओं की इकाईयों के विपरीत मानवीय श्रम की इकाईयों को क्रय करने की शक्ति से है। इसे मानवीय श्रम के कीमत तल—मजदूरी द्वारा नापा जाता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुद्रा का मूल्य सापेक्षिक (Relative) रूप में ही नापा जा सकता है, निरपेक्ष रूप में नहीं।

मुद्रा के मूल्य की समस्या (The Problem of Value of Money)—

मुद्रा के मूल्य की समस्या के तीन निम्नलिखित पक्षों का हमें अध्ययन करना है :—

मुद्रा का मूल्य (Value of Money)



मुद्रा के मूल्य का पहला पक्ष ही इस अध्याय का विषय है।

¹. "Money has a number of different values according to the different uses to which it is put, and is measured by the particular price level which corresponds to that particular use"

— S M Tiwary *Money an analytical study of monetary Theory and Problems*, p. 105

². G. Crowther . *An outline of Money*, p 85

निर्देशांक (Index Numbers)

जैसा कि हम अध्ययन कर चुके हैं कि मुद्रा का मूल्य उसकी क्रय शक्ति है। मुद्रा का मूल्य स्थिर नहीं रहता और इसमें सदा परिवर्तन होते रहते हैं। मुद्रा के मूल्य तथा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में विपरीत सम्बन्ध है, अर्थात् वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के परिवर्तनों के आधार पर मुद्रा का मूल्य मापा जाता है। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तनों को एक गणितीय विधि से मापा जाता है जिसे निर्देशांक या सूचनांक (Index Numbers) कहते हैं।

निर्देशांक की परिभाषा (Definition of Index Numbers)

निर्देशांक कीमत स्तर के अंकों की एक सूची होती है जिन्हे एक तालिका के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के परिवर्तनों को दिखाकर मुद्रा के मूल्य में हुए परिवर्तनों को जाना जा सके।¹

निर्देशांक की कुछ मुख्य परिभाषायें इस प्रकार हैं —

सेविरस्ट . “निर्देशांक से तात्पर्य सख्याओं की उस श्रृंखला से है जो मुद्रा के मूल्य के साथ कीमत स्तर के परिवर्तनों को बतलती है। ये सापेक्षिक अंक होते हैं जो विभिन्न समयों में मुद्रा की क्रय शक्ति की तुलना करने में सहायक होते हैं और कीमत स्तर के उच्चावचनों को मापते हैं।”²

चैन्डलर “कीमत निर्देशांक वह सख्या है जो आधार वर्ष की औसत कीमतों की ऊँचाई की तुलना में किसी अन्य समय में उसकी ऊँचाई को प्रकट करती है।”³

¹. Index numbers are figures of price levels arranged in a table with a view to show the changes in the prices of goods and services for the purpose of showing the fluctuations in the value of money

² “Index Numbers are series of numbers which show variations in price levels with those in the value of money These are relative numbers which enable us to compare the purchasing power of money at different periods of time and measure the movement in the level of prices”

— Secrist : *An Introduction to Statistical Methods*, p 295.

³. “An index number of prices is a figure showing the height of average prices at one time relative to their height at some other time that is taken as the base period”

—L. V Chandler *An Introduction to Monetary Theory*, p 1

घोष तथा चौधरी "निर्देशांक वह सख्या है जो किसी निश्चित तिथि को किसी स्थिति विशेष के स्तर की तुलना किसी आधार तिथि (Standard date) के स्तर से करती है।"¹

यदि किसी निश्चित तिथि की तुलना में निर्देशांक बढ़ा है तो इसका तात्पर्य है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ी हैं और उसी अनुपात में मुद्रा का मूल्य घटा है। इसी प्रकार यदि निर्देशांक घटा है तो इसका अर्थ है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें घटी हैं और उसी अनुपात में मुद्रा का मूल्य बढ़ा है।

निर्देशांक केवल कीमतों की सामान्य प्रवृत्ति की ओर ही संकेत करते हैं
(Index numbers indicate only a general tendency of prices)

सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें एक साथ एक ही दिशा में परिवर्तित नहीं होती। कुछ वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तो कुछ के घटते हैं। इसी प्रकार वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन की दिशा भिन्न होने के साथ साथ परिवर्तन की सीमा (degree) भी भिन्न भिन्न होती है। इसके विपरीत कुछ ऐसी वस्तुएँ भी होती हैं जिनकी कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता। परन्तु कीमतों के इन सभी परिवर्तनों की एक सामान्य दिशा भी होती है। निर्देशांक इसी केन्द्रीय प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हैं। इसकी तुलना मधु मक्खियों के एक झुंड के साथ की जा सकती है जिसमें कुछ मक्खियाँ पूर्व की ओर और कुछ पश्चिम की ओर, कुछ उत्तर की ओर कुछ दक्षिण की ओर जाती हैं परन्तु झुंड की भी एक दिशा होती है। प्रो० टॉसिंग के शब्दों में —

"No index number corresponds to the real thing. It is not like the mean of certain observations in natural sciences whose average will point to a single special fact. This is to repeat only an indication of the general trend of prices. There is no one change in prices, there is a medley of many changes, different in direction and degree. All what we can hope to secure by averaging or summarising is some concise statement of the general drift."

निर्देशांक मुद्रा के मूल्य के निरपेक्ष मापक नहीं हैं
(Index numbers are not absolute measures of the Value of money)

निर्देशांक मुद्रा के मूल्य के निरपेक्ष मापक नहीं हैं। यह कहने का कोई अर्थ नहीं है कि निर्देशांक इस समय 200 या 300 है जब तक यह न ज्ञात हो कि वह

1. "An index number is a number which indicates the level of a certain phenomenon at any given date in comparison with the level of the same phenomenon at some standard date"

प्रयुक्त विधि की तुलना में इतना है। अतः निर्देशक दो विभिन्न समयों के कीमत स्तर की तुलना करने के लिए प्रयुक्त होते हैं इसीलिए वे मुद्रा के मूल्य के निम्नपेक्ष मापक न होकर सापेक्ष मापक (Relative measures) है।

निर्देशक मुद्रा के मूल्य के परिवर्तनों को मापने के काम में ही नहीं आते बल्कि इनका उपयोग आर्थिक जगत के विभिन्न तथ्यों के तुलनात्मक परिवर्तनों को मापने के लिए किया जाता है जैसे उत्पादन, बिक्री, आयात-निर्यात, उपभोग, आय-व्यय इत्यादि की घट बढ़।

निर्देशक बनाने की विधि (Compilation of Index Numbers)

कीमतों के निर्देशक बनाने की विभिन्न विधियाँ हैं और उनमें कौनसा सबसे ठीक है इस सम्बन्ध में बड़ा मतभेद है। इस सम्बन्ध की तकनीकी समस्याओं के समाधान का उत्तरदायित्व सख्ता शास्त्रियों पर छोड़ते हुए यहाँ हम केवल यह अध्ययन करेंगे कि निर्देशकों के निर्माण की मूलभूत विधि क्या है और इनकी सहायता से मुद्रा के मूल्य के तुलनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। सरल निर्देशकों के निर्माण में निम्नलिखित समस्याओं पर विचार किया जाता है—

1. निर्देशक का उद्देश्य (Object of Index Numbers) : सबसे पहले यह निश्चित किया जाना चाहिए कि निर्देशक हम किस उद्देश्य के लिए बनाने जा रहे हैं। किन्हीं भी सांख्यिकीय प्रणाली को अपनाने से पूर्व अपने उद्देश्यों को निर्धारित करना आवश्यक होता है क्योंकि एक प्रणाली जो एक उद्देश्य के लिए उपयुक्त है दूसरे के लिए अनुपयुक्त हो सकती है। यदि व्यापारियों की दृष्टि से हम निर्देशक बना रहे हैं तो हमें 'शोक मूल्य निर्देशक बनाना होगा और उपभोक्ताओं की दृष्टि से हमें 'फुटकर कीमत निर्देशक बनाना होगा। हैबरलर ने ठीक ही कहा है कि "सामान्य मूल्य स्तर कोई स्वतः स्पष्ट तथ्य नहीं बल्कि एक सैद्धांतिक अवास्तविकता है। यह किन्हीं वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक उद्देश्यों की प्राप्ति का वैज्ञानिक उपकरण है। कीमत स्तर की आर्थिक दृष्टिकोण से उपयुक्त परिभाषा मस्तिक म निहित उद्देश्य से स्वतंत्र नहीं हो सकती और प्रत्येक उद्देश्य के लिए पृथक निर्देशक का निर्माण होना चाहिए।"¹

1. "The general price level is not a given, self evident fact, but a theoretical abstraction. It is a scientific tool which has to serve for certain scientific and practical purposes..... An economically relevant definition of price level cannot be independent of the purpose in mind and for each purpose a separate index must be computed."—Haberler : *The Meaning and use of a General Price Index*, *Quarterly Journal of Economics*, 1928. pp 435-36.

2 आधार वर्ष का चुनाव (The Choice of the base year) : निर्देशकों का निर्माण करते समय आधार वर्ष का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। निर्देशकों द्वारा वर्तमान की औसत कीमतों की तुलना किसी निश्चित तिथि या वर्ष की कीमतों से की जाती है और यह पता लगाया जाता है कि उस वर्ष की तुलना में कीमतें बढ़ी हैं या घटी। जिस वर्ष की औसत कीमतों से तुलना की जाती है उसे आधार वर्ष, आधार तिथि या आधार अवधि कहते हैं। आधार वर्ष ऐसा होना चाहिए जो सभी दृष्टियों से साधारण तथा सामान्य वर्ष हो। उस वर्ष कोई राजनैतिक व आर्थिक उथल पुथल और असाधारण घटना जैसे युद्ध, इत्यादि न हुए हो। उस वर्ष कीमतें न बहुत ऊँची रही हो और न बहुत नीची। असाधारण परिस्थितियों वाला वर्ष हमारे निष्कर्ष अशुद्ध कर सकता है। आधार वर्ष किसी युग की चरम सीमा होती है जहाँ से राजनैतिक व आर्थिक प्रवृत्तियों का प्रवाह दूसरी दिशा में मोड़ लेता है। अतः आधार वर्ष एक जल विभाजक की तरह है जो दो आर्थिक युगों का मध्य स्थल होता है। इन बातों को ध्यान में रखकर आधार वर्ष चुना जाना चाहिए। काऊथर के शब्दों में "किसी भी अवधि को आधार बनाया जा सकता है किन्तु किसी ऐसी अवधि को अपनाना, जिससे बाद की कीमतों की तुलना की जा सके, उसी प्रकार आवश्यक होता है जिस प्रकार एक मानचित्र बनाने वाले के लिए आधार रेखा लेना आवश्यक है जिससे वह ऊँचाइयों को उसके सन्दर्भ में नाप सके।"¹

3 वस्तुओं और सेवाओं का चुनाव (Selection of Commodities and Services) निर्देशकों के निर्माण का उद्देश्य निश्चित कर लेने के बाद वस्तुओं और सेवाओं (जिनकी कीमतें निर्देशकों में प्रयुक्त होंगी) के चुनाव का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। व्यावहारिकता में सभी वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जा सकता अतः जिस उद्देश्य के लिए निर्देशक बनाये जा रहे हैं उससे सम्बन्धित प्रतिनिधि वस्तुओं को चुना जाता है। यदि हम सामान्य जीवन स्तर की लागत का निर्देशक बना रहें हैं तो हमें सामान्य उपभोग में आने वाली वस्तुओं और सेवाओं को चुनना होगा। 'थोक भाव निर्देशक' के लिए हमें ऐसी वस्तुओं को चुनना होगा जिनका थोक विनिमय होता है। श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर लागत निर्देशक बनाते समय हमें श्रमिकों के उपभोग में आने वाली वस्तुओं का चुनाव करना होगा। उसमें कारों तथा मोटर साइकिलों का चुनाव किया गया तो वे निर्देशक

¹. "Any period will do, but it is necessary to have some base to which later prices can be compared, just as every map maker must have a datum line to which he can refer altitudes"

श्रमिकों की जीवन स्तर लागत में परिवर्तनों की सही सूचना नहीं दे सकेंगे। वस्तुओं के चुनाव से सम्बन्धित दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्देशांक के निर्माण में चुनी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की संख्या जितनी अधिक होगी निर्देशांक उतना ही प्रामाणिक तथा मयार्थ होगा। परन्तु अधिक वस्तुओं को सम्मिलित करने पर उनकी कीमतें एकत्र करने में कठिनाई, व्यय तथा विलम्ब होता है। अतः सुविधा, मितव्ययिता तथा सरलता के लिए पर्याप्त संख्या में जैसे 40-50 वस्तुओं तथा सेवाओं को चुनना चाहिए। इरविंग फिशर के शब्दों में “जब तक निर्देशांक में 20 से अधिक वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाता जब तक उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता। यदि यह संख्या 50 तक हो तो और अच्छी बात है। 50 के बाद सरया अधिक करने से बहुत थोड़ा सुधार होता है परन्तु यह सदेहपूर्ण है कि 200 से अधिक संख्या में वृद्धि से लाभ, उनके अंकन की अतिरिक्त परेशानी तथा व्यय से अधिक होगा।”¹ मिचेल के अनुसार “जब हमारा उद्देश्य मूल्यों में सामान्य परिवर्तनों की दिशा का ज्ञान करना हो तो चुनी हुई वस्तुओं की संख्या का कोई महत्व नहीं है। परन्तु वस्तु समूहों की संख्या इतनी पर्याप्त हो कि वे सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था का व्यापक चित्र प्रस्तुत कर सकें।”² सोवियत बैंक के निर्देशांक में 37 वस्तुय, ब्रिटिश बोर्ड ऑफ ट्रेड के निर्देशांक में 150, अमेरिकन ग्युरो और लेबर के निर्देशांक में 550 तथा भारत के इकानामिक एडवाइजर के थोक भाव निर्देशांक (Economic Advisor's Wholesale Price Index Number) में 78 वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है।

4. वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का चयन (Collection of Prices of Commodities and Services). प्रतिनिधि वस्तुओं और सेवाओं का चुनाव करने के बाद उन वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य एकत्र करने पड़ते हैं। किस प्रकार की कीमतें निर्देशांक के लिए चुनी जाय यह निर्देशांक बनाने के उद्देश्य पर निर्भर है। यदि हम सामान्य कीमतों का निर्देशांक बना रहे हैं तो थोक कीमतों का प्रयोग करे

¹ Seldom.... are index numbers of much value unless they consist of more than 20 commodities, and 50 is a much better number. After 50 the improvement obtained from increasing the number of commodities is gradual and it is doubtful if the gain from increasing the number beyond 200 is ordinarily worth the extra trouble and expense.”

—Irving Fisher : *The Making of Index Number*, p. 340

² “If the desired end is an indication of broad movements of prices, the number of commodities chosen hardly matters but the number of commodity groups should be large to present a comprehensive picture of the economy.”—Mitchell

क्योंकि माग-पूर्ति के परिवर्तनों का योक् भावो पर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है और इनका एकत्रित करना भी मुनिधाजनक होता है। यदि हम जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक बना रहे हैं तो फुटकर भावो का प्रयोग अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि उप-भोक्ता इन्हीं कीमतों पर वस्तुओं को खरीदता है। जिन कीमतों का हम निर्देशांक बनाने में प्रयोग करें वे विश्वसनीय पत्र-पत्रिकाओं से ली जा सकती है या उन वस्तुओं के उत्पादन व वितरण व प्रमुख केन्द्रों से प्राप्त की जा सकती है। कीमतों को ठीक स्रोतों से प्राप्त करना बड़ा आवश्यक है नहीं तो हमारे निष्कर्ष वास्तविक स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित करना पड़ेगा कि दैनिक, साप्ताहिक या मासिक कौन सी कीमतें एकत्र की जाय।

5 कीमतों को प्रतिशत में दिखाना (To Represent Prices in Percentages) : प्रत्येक वस्तु तथा सेवा की कीमत आधार वर्ष में 100 मान ली जाती है और निर्देशांक निकालने वाले वर्ष की कीमतों को आधार वर्ष की कीमतों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरणार्थ यदि आधार वर्ष (1953) में गेहूँ की कीमत 60 रुपये प्रति क्विंटल थी और निर्देशांक निकालने वाले वर्ष (1969) में गेहूँ की कीमत 90 रुपये प्रति क्विंटल हो गई तो आधार वर्ष की कीमत को 100 मानकर वर्तमान की कीमत को $\frac{90 \times 100}{60} = 150$ दिखाया जायेगा।

6 औसत निकालना (Determination of Averages) अन्न में आधार वर्ष तथा वर्तमान की कीमतों के प्रतिशतों का औसत निकाला जाता है। औसत निकालने की अनेक विधियाँ हैं जैसे गणितीय औसत (Arithmetic Average), मध्यक (Median), भूयिष्ठक (Mode), गुणात्तर माध्य (Geometric Mean) इत्यादि। इनमें से प्रत्येक विधि की अलग-अलग उपादेयता है और निर्देशांक बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर इनका प्रयोग किया जाता है। फिशर ने 96 मुख्य तथा 38 पूरक फार्मूलों की चर्चा की है और उनके अनुसार इन 134 में से 30 सही परिणाम देते हैं।

साधारण निर्देशांक—एक उदाहरण

उपयुक्त क्रियाओं के सम्पन्न हान पर उनके वास्तविक निर्माण का कार्य किया जाता है। यहाँ एक साधारण निर्देशांक का सरल उदाहरण दिया जाता है—

1969 का साधारण जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक (1953=100)

वस्तुयें	1953 आधार वर्ष		1969 चालू वर्ष	
	कीमत	निर्देशांक	कीमतेँ	निर्देशांक
1 गेहूँ	Rs 50 per Quintal	100	Rs 100 per Quintal	200 0
2 चावल	150 „	100	250 „	166 6
3 दाल	75 „	100	125 „	166 6
4 कपडा	2 per Meter	100	5 per Meter	250 0
5 कोयला	20 per Quintal	100	30 per Quintal	150 0
6 चीनी	100 „	100	400 „	400 0
7 दूध	0 60 per Liter	100	1 50 per Liter	250 0
		700		1583 2
		7		7
		=100		=226 18

उपयुक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि 1953 को आधार वर्ष मान कर 1969 का निर्देशांक 226 18 है। अतः 1953 की तुलना में कीमतें लगभग सवा दो गुनी हो गई हैं अर्थात् कीमत स्तर में 126 18% की वृद्धि हो गई है तथा मुद्रा के मूल्य में 126 18% की कमी हुई है।

साधारण तथा भारांकित निर्देशांक (Simple and Weighted Index Number) साधारण निर्देशांक उस निर्देशांक को कहते हैं जिसमें चुनी गई सभी वस्तुओं को समान महत्व दिया जाता है चाहे उनका हमारी उपभोग व्यवस्था में अधिक महत्व हो या कम। उपयुक्त उदाहरण वास्तव में साधारण निर्देशांक का उदाहरण है जिसमें यह मान लिया गया है कि प्रत्येक वस्तु का महत्व अन्य वस्तुओं के समान ही है परन्तु उपभोक्ता की व्यय व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु का महत्व भिन्न होता है जैसे गेहूँ पर जो व्यय किया जाता है उसकी तुलना में नमक पर बहुत कम व्यय होता है। गेहूँ की कीमतों में थोड़ा ही परिवर्तन उसके बजट पर अधिक प्रभाव डालता है तथा नमक की कीमतों में अधिक घट बढ भी उसको अधिक प्रभावित नहीं करती। अतः मुद्रा के मूल्य में परिवर्तनों का सही अनुमान लगाने के लिए निर्देशांक में विभिन्न वस्तुओं का महत्व भी समाविष्ट होना चाहिए। साधारण निर्देशांक के इसी दोष को दूर करने के लिए भारांकित निर्देशांक (Weighted Index Number) बनाये जाते हैं।

भारकित निर्देशांक में वस्तुओं के तुलनात्मक महत्व के अनुसार 'भार' (weights) दे दिये जाते हैं। भार देने का एक तरीका यह है कि महत्वपूर्ण वस्तुओं की कई किस्में चुन ली जाय जैसे 8 किस्म का गेहूँ, 6 किस्म का चावल, 3 किस्म की दालें, 2 किस्म का कपडा। इस प्रकार अधिक महत्व वाली वस्तुओं को तुलनात्मक दृष्टि से अधिक महत्व मिल जाता है। भार देने का दूसरा तरीका यह है कि महत्व के अनुसार प्रत्येक वस्तु को भार के अंक प्रदान कर दिये जाते हैं और आधार वर्ष तथा वर्तमान के निर्देशांको को भारों से गुणा कर दिया जाता है और फिर औसत निकाल लिया जाता है। नीचे हम एक भारकित निर्देशांक (Weighted Index Number) का उदाहरण देते हैं—

1969 का भारकित जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक (1953=100)

वस्तुएँ	भार	1953 आधार वर्ष			1969 चालू वर्ष		
		कीमतेँ	साधारण	भारकित निर्देशांक	कीमतेँ	साधारण निर्देशांक	भारकित निर्देशांक
1. गेहूँ	8	Rs. 50 Q.	100	800	100 Q.	200	1600.0
2. चावल	7	150 „	100	700	250 „	166.6	1166.2
3. दाल	5	75 „	100	500	125 „	166.6	833.0
4. कपडा	4	2 M.	100	400	5 M.	250	1000.0
5. कोयला	3	20 Q.	100	300	30 Q.	150	450.0
6. चीनी	2	100 „	100	200	400 „	400	800.0
7. दूध	1	60 L.	100	100	1.50 L.	250	250.0
	30			3000			6099.2
				30			30
				=100			=203.36

इस प्रकार भारकित निर्देशांक 203.36 है जबकि साधारण निर्देशांक 226.18 है। विभिन्न वस्तुओं को उनके तुलनात्मक महत्व के अनुसार भार देकर निर्मित भारकित निर्देशांक मुद्रा के मूल्य में परिवर्तनों का ज्ञान कराने में अधिक विश्वसनीय होते हैं।

निर्देशांको के निर्माण में कठिनाइयाँ

(Difficulties in the Construction of Index Numbers)

निर्देशांको के निर्माण में बहुत सी कठिनाइयाँ हैं। उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं—

(1) आधार वर्ष के चुनाव सम्बन्धी कठिनाई निर्देशांक का निर्माण करते समय आधार वर्ष का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी वर्ष की कीमतों से हम वर्तमान वर्ष की कीमतों की तुलना करते हैं। हम यह पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि आधार वर्ष एक सामान्य (normal) वर्ष होना चाहिए जिसमें कोई असाधारण आर्थिक या राजनीतिक घटनावर्ष जैसे युद्ध, मदी इत्यादि न घटी हो। ऐसे वर्ष का चुनाव निस्संदेह एक कठिनाई है क्योंकि समय परिवर्तन के साथ आधार वर्ष भी बदलना पड़ता है। जैसे कुछ वर्ष पहले 1939 जो द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ के पहले का वर्ष है आधार वर्ष माना जाता था परन्तु अब यह प्रचलन में बिल्कुल नहीं है। अब 1953 या इसके बाद के किसी वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है। कभी-कभी इस कठिनाई पर विजय प्राप्त करने हेतु कुछ वर्षों के औसत को आधार वर्ष मान लिया जाता है।

(2) प्रतिनिधि वस्तुओं को चुनने में कठिनाई : निर्देशांक का निर्माण करते समय शुद्ध निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए प्रतिनिधि वस्तुओं का चुनाव करना भी बड़ा कठिन कार्य है। प्रतिनिधि वस्तुओं का चुनाव निर्देशांक के निर्माण के उद्देश्य पर निर्भर करता है। यदि हम श्रमिकों का जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक बना रहे हैं तो श्रमिकों द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं का ही चुनाव करना होगा। इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखना होता है कि आधार वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में वस्तुओं के आकार-प्रकार गुण तथा स्वभाव में कोई अन्तर न हो। इसके अतिरिक्त वस्तुओं की संख्या भी पर्याप्त रूप से अधिक होनी चाहिए।

(3) कीमतों के चयन में कठिनाई : वस्तुओं की कीमतों के चयन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। थोक मूल्य लिए जाय या फुटकर मूल्य — यह निर्देशांक के निर्माण के उद्देश्य पर निर्भर करता है। सामान्य कीमत स्तर निर्देशांक में थोक कीमतों का उपयोग होता है परन्तु जीवन स्तर निर्वाह व्यय निर्देशांक में फुटकर कीमतों का। फुटकर कीमतों का इकट्ठा करना तो बड़ा कठिन होता है क्योंकि वस्तुओं की फुटकर कीमत विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न होती है।

(4) औसत की कठिनाई : निर्देशांक बनाते समय एक प्रमुख कठिनाई औसत निकालने की है। औसत निकालने की रीतियाँ अनेक हैं जैसे अकगणितीय औसत (Arithmetical average), गुणोत्तर माध्य (Geometric mean), हरात्मक माध्य (Harmonic mean) इत्यादि। अधिकतर अकगणितीय औसत का ही प्रयोग किया जाता है परन्तु यह सदा औसत निकालने की उपयुक्त पद्धति नहीं है।

(5) भार निश्चित करने की कठिनाई विभिन्न वस्तुओं के लिए बंज्ञानिक रीति से भार निश्चित करना भी बड़ा कठिन कार्य है क्योंकि विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं का महत्व भिन्न-भिन्न होता है। अतः निष्कर्ष भिन्न हो सकते हैं।

कुछ सीमा तक एक वस्तु की अमुक मात्रा को दूसरी वस्तु की अमुक मात्रा के समान मानकर उस कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है परन्तु, “स्पष्ट रूप में इस प्रकार की तुलनायें वास्तव में सतोपजनक नहीं होती और हमें यह मान लेना होगा कि मुद्रा के मूल्य में अन्तर के माप विभिन्न समयों तथा स्थानों में लगभग अनिश्चित तथा असत्य होते हैं।”¹

भार निश्चित करने की कठिनाई को दूर करने के लिए प्रो० मार्शल ने शृंखलाकारी निर्देशांक (Chain Index Numbers) बनाने का सुझाव दिया है। शृंखलाकारी निर्देशांक के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष की कीमतों की उससे अगले वर्ष की कीमतों से तुलना की जाती है। परन्तु यह प्रणाली भी दोषयुक्त नहीं है।

6. सामान्य कीमत स्तर का विचार सैद्धान्तिक रूप से अस्वीकार्य: युद्ध प्रारम्भ होने पर देश की अर्थ व्यवस्था सैनिक उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से परिवर्तित हो जाती है। लगभग सामान्य कीमत स्तर का विचार करते समय उपभोक्ताओं के रूप में प्राप्त आद्य-वस्तुओं के मूल्य तथा सम्पत्ति के स्वामियों के रूप में पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में अन्तर करना चाहिए। अतः इन वस्तुओं को एक ही बार सम्मिलित करने की सावधानी बरतनी चाहिए।

निर्देशांक मुद्रा मूल्य के पूर्णतः सही मापक नहीं (Index Numbers are not absolutely correct measures of Value of Money) .—

निर्देशांक को बनाने में अनेक कठिनाइयाँ हैं और इस कारण पूर्णतः सत्य निर्देशांक नहीं बनाये जा सकते। अतः मुद्रा के मूल्य में परिवर्तनों को ठीक प्रकार से नापा नहीं जा सकता। राबर्टसन के शब्दों में “मुद्रा के मूल्य परिवर्तनों को ठीक-ठीक नापना न तो व्यवहार में और न सैद्धान्तिक दृष्टि से सम्भव है। फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होते हैं और यदि पर्याप्त सावधानी बरती जाय तो व्यावहारिक कार्यों के लिए काफी हद तक ठीक-ठीक माप प्राप्त तथा प्रयोग किए जा सकते हैं।”² यद्यपि निर्देशांक में गणितीय सत्यता (Arithmetical

1. “But clearly no such comparisons are really satisfactory and we must resign ourselves to the fact that any measure of differences in the value of money between times and places will be more or less arbitrary and inaccurate.” — F. Benham *Economics*, p. 409.

2. “Neither in practice nor perhaps even in theory is it possible to measure accurately changes in the value of money. Nevertheless there is no doubt that the value of money does change, and, if sufficient care is taken, measures accurate enough for some practical purposes can be found and used”

—D. H. Robertson · *Money*, p. 27.

Truism) नहीं पाई जाती है परन्तु यह दोष होते हुए भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि निर्देशांक की सहायता से हम मुद्रा के मूल्य परिवर्तनों का अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए प्रो० मार्शल ने कहा है कि "मुद्रा की ऋण-शक्ति को पूर्णतः सही माप लेना न केवल असम्भव है अपितु अविचारणीय भी है।"¹ अतः निर्देशांक मुद्रा के मूल्य परिवर्तनों के अनुमान ही होते हैं। इन्हें मुद्रा के मूल्य परिवर्तनों के पूर्णतः सत्य सूचक नहीं माना जा सकता क्योंकि वे केवल मूल्य परिवर्तनों में केन्द्रीय प्रवृत्ति का हमें ज्ञान कराते हैं।

निर्देशांक के प्रकार (Types of Index Number)

निर्देशांक मुद्रा के मूल्य परिवर्तनों के माप की सांख्यिकीय विधि है। इस विधि का विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है और इन्हीं प्रयोगों के अनुसार उनके कई प्रकार तथा रूप दिखाई पड़ते हैं। निर्देशांक के निम्नलिखित प्रकार उल्लेखनीय हैं —

1 थोक कीमतों के निर्देशांक (The Wholesale Price Index Numbers) — इस प्रकार के निर्देशांक मुख्य मुख्य वस्तुओं की थोक कीमतों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। इनके द्वारा देश के कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों की दिशा तथा मात्रा का संकेत मिलता है। उत्पादन लागत व्यय के तुलनात्मक अध्ययन के लिए यह निर्देशांक बड़े उपयोगी हैं तथा इनकी सहायता से सरकार अपनी मूल्य नियन्त्रण तथा मुद्रा नीति का निर्धारण करती है। भारत में आर्थिक सलाहकार द्वारा निर्मित थोक कीमतों का निर्देशांक (Economic Adviser's Index Number of Wholesale Prices) इस प्रकार के निर्देशांक का उदाहरण है।

2 श्रमिक वर्ग जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक (Working Class Cost of Living Index Numbers) — श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए श्रमिकों द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं के फुटकर मूल्यों के आधार पर यह निर्देशांक बनाये जाते हैं। इन निर्देशांक में सेवाओं के मूल्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इस प्रकार के निर्देशांक श्रमिकों की मजदूरी तथा उनके महंगाई भत्ते को निश्चित करने में बड़े उपयोगी होते हैं। ब्रिटिश श्रम मन्त्रालय (British Labour Ministry) सरकारी श्रमिक वर्ग जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक तैयार करता है। भारत में लेबर ब्यूरो (भारत सरकार) 17 स्थानों के श्रमिक वर्ग जीवन-निर्वाह व्यय निर्देशांक तैयार करता है।

3 औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (Index Numbers of Industrial Production): — औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक किसी आधार वर्ष की तुलना में

1. "A perfectly exact measure of the purchasing power is not only unattainable but even unthinkable."
— Marshall

औद्योगिक उत्पादन में घट वृद्ध की सूचना देते हैं। औद्योगिक उत्पादन तथा व्यापारिक क्रियाओं पर सरकारी नीतियों के प्रभाव का अध्ययन करने में यह निर्देशांक सहायता पहुँचाते हैं। व्यापारियों को अपने उत्पादन की तुलनात्मक समीक्षा करने में सहायता मिलती है। भारत में ईस्टर्न इकोनोमिस्ट उत्पादन निर्देशांक (Eastern Economist Index of Industrial Production), कैपिटल औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (Capital Index of Industrial Production), केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्रालय के औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (Ministry of Commerce Index of Industrial Production) इसके उदाहरण हैं।

4. जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक या उपभोग सूचक निर्देशांक (Cost of Living Index Number or Consumption Index Number):—इन निर्देशांकों का उद्देश्य जीवन निर्वाह-व्यय में परिवर्तनों को मापना होता है। इन निर्देशांकों के निर्माण में जनता द्वारा प्रयुक्त मुख्य मुख्य वस्तुओं तथा सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। यह वस्तुयें व सेवायें प्रतिनिधि स्वरूप (Representative) होती हैं। श्रमिक वर्ग जीवन निर्वाह-व्यय निर्देशांक तथा जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक में मुख्य अन्तर यह है कि प्रथम प्रकार के निर्देशांकों में सेवाओं का मूल्य सम्मिलित नहीं किया जाता जबकि दूसरे प्रकार के निर्देशांकों में सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है।

5 औद्योगिक लाभ निर्देशांक (Index Number of Industrial Profits) — औद्योगिक क्षेत्रों में विनियोजित पूँजी की उत्पादनशीलता के अनुमान लगाने तथा उनकी तुलनात्मक समीक्षा के लिए औद्योगिक लाभ निर्देशांक बनाये जाते हैं। भारत में—मन्त्रालय के कम्पनी प्रशासन विभाग (Department of Company Law Administration) द्वारा औद्योगिक लाभ निर्देशांक बनाये जाते हैं।

6 प्रतिभूति मूल्य निर्देशांक (Index Numbers of Security Prices).—स्टॉक या शेयर बाजार में प्रतिभूतियों तथा अण्डों के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों के माप के लिए प्रतिभूति मूल्य निर्देशांक बनाये जाते हैं। इनसे उद्योगों के विकास का ज्ञान होता है तथा उनमें मन्दी या तेजी की स्थितियों की जानकारी मिलती है।

7. अन्य निर्देशांक (Other Indices) — उपर्युक्त निर्देशांकों के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में निर्देशांकों का निर्माण किया जाता है जैसे कार्यक्षमता निर्देशांक, बिक्री निर्देशांक, कृषि उत्पादन निर्देशांक, विदेशी व्यापार निर्देशांक, विशिष्ट प्रकार की सेवाओं के निर्देशांक। निर्देशांकों की उपयोगिता के कारण सभी प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन के लिए इस सांख्यिकीय विधि का प्रयोग किया जा रहा है।

निर्देशांकों के लाभ तथा उपयोगिता (Utility and Advantages of Index Numbers)

वर्तमान समय में निर्देशांक की उपयोगिता के कारण इनका महत्व बढ़ता जा रहा है। निर्देशांक न केवल जीवननिर्वाह-व्यय में परिवर्तनों की सूचना देते हैं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में दो समयों की गतिविधियों के तुलनात्मक अध्ययन में भी सहायता पहुँचाते हैं। निर्देशांक के निम्नलिखित लाभ हैं।—

1. जीवन निर्वाह व्यय के परिवर्तनों की माप सम्भव (Measurement of changes in the Cost of Living made possible) — निर्देशांक की सहायता से जीवन निर्वाह व्यय के परिवर्तनों को जाना जा सकता है। इससे जनता के विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है।

2. मजदूरी तथा भत्तों के निर्धारण में सहायक (Help in the determination of wages and allowances) — जीवन निर्वाह व्यय के परिवर्तनों की माप कर निर्देशांक मजदूरों की मजदूरी तथा महुगाई भत्ते इत्यादि के निर्धारण में सहायता करते हैं। कुछ देशों में मजदूरों की मजदूरी को निर्देशांक के परिवर्तनों के साथ जोड़ दिया जाता है। भारत सरकार के कर्मचारियों का महुगाई भत्ता निर्देशांक के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार निर्देशांक मालिक तथा मजदूरों के मजदूरी तथा भत्ते सम्बन्धी विवाद तय करने में सहायक होते हैं और औद्योगिक शांति की स्थापना में बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

3. व्यापारियों के लिए लाभदायक (Useful to the Businessmen) — व्यापारियों के लिए निर्देशांक का बड़ा महत्व है क्योंकि व्यापारियों के लिए कीमतों में परिवर्तनों की जानकारी बहुत आवश्यक है और यह जानकारी निर्देशांक से ही मिल सकती है। व्यापारी बिजली, उत्पादन तथा लाभ के निर्देशांक बनाकर अपनी व्यापारिक नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन कर सकते हैं और भावी नीति निर्माण के लिए आधार प्राप्त कर सकते हैं।

4. मौद्रिक नीति के निर्धारण में सहायक (Helpful in the formulation Monetary Policy):— वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तनों के आधार पर केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय बैंक उचित मुद्रा नीति का निर्धारण कर सकती है जिससे मुद्रा के आन्तरिक तथा बाह्य मूल्यों में स्थिरता लाई जा सके तथा दश तीव्र गति से आर्थिक विकास के माग पर अग्रसर होता रहे। मुद्रा प्रसार, मुद्रा संकुचन, हीनार्थ प्रबन्धन इत्यादि विषयों पर उचित नीति के निर्माण में निर्देशांक बहुत सहायक होते हैं। इसी कारण हॉलम (Halm) न मौद्रिक नीतियों के निर्धारण में निर्देशांक को उपयोगी ठहराया है।¹

¹ 'Price levels and index numbers by means of which they are conveniently expressed can be useful for some purposes of monetary policy.'

5 उत्पादनशीलता के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक (Comparative study of Productivity) — निर्देशांक की सहायता से उत्पादन, उत्पादनशीलता तथा लागत व्यय इत्यादि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है। उत्पादन वृद्धि कायदमों के प्रभावा का मूल्यांकन तथा भावी कायरूप के निर्धारण में भी निर्देशांक से सहायता मिलती है।

6 विनिमय दर के निर्धारण में सहायक (Helpful in the determination of foreign exchange rates) — विदेशी विनिमय दरों के निर्धारण तथा भुगतान सतुलन की विषमता दूर करने में निर्देशांक से सहायता मिलती है। पर मुद्रा मान वाले देशों के बीच विनिमय दर का निर्धारण क्रयशक्ति तुल्यता सिद्धान्त (Purchasing Power Parity Theory) के आधार पर होता है और मुद्रा की क्रय शक्ति के बारे में ज्ञान निर्देशांक से प्राप्त होता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निर्देशांक की यह साख्यकीय विधि समाज के सभी क्षेत्रों तथा सभी वर्गों के लिए उपयोगी है। व्यापारी, राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री वैज्ञानिक, ग्रयशास्त्री सभी निर्देशांक से लाभ उठाते हैं। निर्देशांक देश क आर्थिक विकास की प्रगति तथा अन्य देशों से उसकी तुलना में सहायक होते हैं। इसीलिए निर्देशांक को आर्थिक मापन यन्त्र (Economic Barometer) माना जाता है।

निर्देशांक की सीमायें

(Limitations of Index Numbers)

निर्देशांक वे बहुत से लाभ होते के बावजूद निर्देशांक का प्रयोग बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए। निम्नलिखित कारणों से उनको बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए —

1 आंकड़े सदा सय नहीं होते (Statistics are not always accurate) — निर्देशांक को कीमत परिवर्तनों का पूरा सत्य माप नहीं मानना चाहिए। अधिक से अधिक वे अनुमान ही माने जा सकते हैं (They are only approximate indicators of relative levels of a phenomenon) आंकड़ों के इकट्ठा करने में ही त्रुटियों की सम्भावना नहीं रहती बल्कि आधार वष के चयन में भी गलती हो सकती है। गलत आंकड़ों पर आधारित निर्देशांक भ्रामक होते हैं।

2 समय अंतर की कठिनाई (No inference should be drawn by comparing index numbers of years separated by a long period of time) — निर्देशांक में विभिन्न वर्षों में तुलना के आधार में एकरूपता का प्रभाव हो सकता है। समय के अंतर से उपनात्काओं की आदत तथा उनके रहन सहन के दर्जे में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ तक कि उत्पादन रीतिया तथा उत्पादित वस्तुओं की प्रकृति भी स्थिर नहीं रहती। नई वस्तुओं का उदय हो जाता है और पुरानी वस्तुयें गायब हो जाती हैं। इन सभी बातों का अल्पकाल में कोई विशेष महत्व नहीं है परन्तु दीर्घकालीन तुलनात्मक अध्ययन भ्रामक हो सकते हैं।

3. अन्तर्राष्ट्रीय तुलना में कठिनाई (Difficulties in International Comparison):—निर्देशांक की सहायता से विभिन्न देशों के कीमत परिवर्तनों की तुलना करना बड़ा कठिन होता है। प्रत्येक देश में निर्देशांक की निर्माण विधियाँ तथा उनमें प्रयुक्त प्रतिनिधि वस्तुयें भिन्न भिन्न होती हैं जिससे उनकी तुलना नहीं की जा सकती। लन्दन का जीवन निर्वाह-व्यय निर्देशांक में कोयले की कीमतों का महत्वपूर्ण स्थान है जब कि कलकत्ता या बम्बई के निर्देशांक में उसका इतना महत्व नहीं है। अतः इन दो स्थानों के निर्देशांक की तुलना व्यर्थ है।

उपर्युक्त सीमाओं तथा कठिनाइयों के कारण ही निर्देशांकों का सीमित महत्व होता है और इसी रूप में उन पर निर्भर रहना चाहिए।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संकेत

(1) सूचनांक क्या है? सूचनांक की सहायता से मुद्रा के मूल्य परिवर्तन को मापने में जिन असुविधाओं का अनुभव होता है उनका परीक्षण कीजिए।

(राजस्थान बी० काम० 1964)

[संकेत—प्रथम भाग में विभिन्न परिभाषायें देते हुए सूचनांक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दूसरे भाग में सूचनांक के बनाने की कठिनाइयों तथा सूचनांक की परि-सीमाओं का वर्णन कीजिए।]

(2) सूचनांक क्या होते हैं? साधारण सूचनांक की एक सारिणी बनाइये। ऐसी सारिणी बनाते समय किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए? (झागरा 1969)

[संकेत—प्रथम भाग में विभिन्न परिभाषायें देते हुए सूचनांक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। फिर उदाहरण स्वरूप एक साधारण सूचनांक की एक तालिका बनाइये और बताइये कि तालिका बनाते समय आधार वर्ष का चयन, वस्तुओं और सेवाओं का चयन इत्यादि बातों का ध्यान रखना चाहिए।]

(3) सूचनांक की परिभाषा दीजिए। उनके उपयोगों और सीमाओं की विवेचना कीजिए। (विक्रम 1961)

[संकेत—प्रथम भाग में विभिन्न परिभाषाओं का विवेचन करते हुए सूचनांक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दूसरे भाग में सूचनांकों के महत्व तथा उनके विभिन्न उपयोगों को बताइये। तीसरे भाग में सूचनांक की परिसीमाओं का उल्लेख कीजिए।]

(4) साधारण निर्देशांक तथा सप्रभाव निर्देशांक में भेद कीजिए। निर्देशांक का महत्त्व बताइये। (राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल, 1962)

[संकेत—प्रथम भाग में साधारण तथा सप्रभाव या भारित निर्देशांक की तालिकाएँ बना कर दोनों के अन्तर को स्पष्ट कीजिए। दूसरे भाग में निर्देशांक के उपयोग तथा महत्त्व की चर्चा कीजिए।]

मुद्रा के सिद्धान्त (Theories of Money)

"Only one fellow in ten thousand understands the currency question and we meet him every day."

—Kin Hubbard

पिछले अध्याय में हमने मुद्रा की ऋय-शक्ति के माप की विधियों का अध्ययन किया। इस अध्याय में मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करने वाले कारणों तथा तत्सम्बन्धी मौद्रिक सिद्धान्तों का विश्लेषण किया जायेगा। अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के मूल्य-निर्धारण सम्बन्धी निम्न सिद्धान्त बताये हैं :

- (1) मुद्रा का वस्तु सिद्धान्त (Commodity Theory of Money)
- (2) मुद्रा का राजकीय सिद्धान्त (State Theory of Money)
- (3) मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त (Quantity Theory of Money)
- (4) नकद-सचय सम्बन्धी परिमाण सिद्धान्त-कैम्ब्रिज समीकरण (Cash Balances Quantity Theory-Cambridge Equation)
- (5) आय, बचत तथा विनियोग सिद्धान्त (Income, Saving and Investment theory)

मुद्रा का वस्तु सिद्धान्त (Commodity Theory of Money)

मुद्रा का वस्तु सिद्धान्त मुद्रा के मूल्य निर्धारण का सबसे प्राचीन सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा का मूल्य उस धातु के मूल्य पर निर्भर करता है जिसकी वह बनी हुई है। यदि मुद्रा स्वर्ण की बनी है तो मुद्रा का मूल्य स्वर्ण की कीमत पर निर्भर करेगा। प्राचीन काल में जब मुद्रा अधिकतर सोने तथा चांदी के सिक्कों के रूप में होती थी, यह सिद्धान्त सत्य था परन्तु आधुनिक मुद्रा व्यवस्था पर यह सत्य सिद्ध नहीं होता। यह सिद्धान्त हमें केवल यह बताता है कि मुद्रा का मूल्य उसके घात्विक अंश के मूल्य के बराबर होता है परन्तु यह नहीं बताता कि स्वर्ण के आंतरिक मूल्य के अधिक होने के क्या कारण हैं। यह सिद्धान्त इस सम्बन्ध

मे यही स्पष्ट करता है कि स्वर्ण अमौद्रिक प्रयोगों जैसे आभूषण, कला एवं उद्योग में प्रयुक्त होने के कारण अधिक मूल्यवान है। परन्तु क्या स्वर्ण के मौद्रिक प्रयोगों का स्वर्ण की ऊँची कीमत से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

इस सिद्धान्त का सशोधित रूप यह स्वीकार करता है कि स्वर्ण की मांग मुख्यतः मौद्रिक प्रयोगों के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रकार मुद्रा का मूल्य उस स्वर्ण की मात्रा द्वारा निर्धारित होता है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार सामान्य कीमत स्तर तथा स्वर्ण की उत्पादन लागत सम्बन्धित हो जाते हैं। अतः अन्य वस्तुओं के समान स्वर्ण का मूल्य भी उसकी मौद्रिक तथा अमौद्रिक उद्देश्यों के लिए मांग तथा पूर्ति पर निर्भर करता है। राबर्टसन के शब्दों में—

“Once more we can keep on the right lines if we start by remembering that money is only one of many economic things. Its value, therefore, is primarily determined by exactly the same two factors as determine the value of any other thing, namely, the conditions of demand for it and the quantity of it available”

आधुनिक युग में वस्तु सिद्धान्त का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है क्योंकि सभी देशों में अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा प्रचलन में है। इसके साथ-साथ प्रायः सभी देशों में प्रमाणिक मुद्रा का चलन ही नहीं है और धीरे-धीरे नोटों के पीछे निधि रखने की प्रथा भी महत्वहीन होती जा रही है।

मुद्रा का राजकीय सिद्धान्त (State Theory of Money)

इस सिद्धान्त के प्रवक्त प्रो० नैप के अनुसार “चलन की आत्मा उसकी इकाइयों के पदार्थ में नहीं है वरन् उन वैधानिक अध्यादेशों में है जो इसके प्रयोग का नियमन करते हैं।”¹ आधुनिक समय में मुद्रा के चलन तथा नियमन सम्बन्धी सभी नियम सरकार द्वारा लिए जाते हैं अतः सरकार की कानूनी घोषणाओं के कारण ही जनता मुद्रा को निस्कोच स्वीकार करती है। इस सिद्धान्त के शासकीय घोषणाओं को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है। मुद्रा के मूल्य का निर्धारण केवल सरकार के हाथ में नहीं है, इस पर अन्य तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है। अतः मुद्रा का राजकीय सिद्धान्त मुद्रा के मूल्य निर्धारक तत्वों का पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं करता है।

¹ “The soul of currency is not in the material of the pieces, but in the legal ordinances which regulate their use”

—Georg F Knapp, The State Theory of Money, abridged translation by Bonar p 2

मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त (Quantity Theory of Money)

मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का उदय सोलहवीं शताब्दी के वाणिकवादी अर्थशास्त्रियों के लेखों में मिलता है। 1752 में डेविड ह्यूम (David Hume) ने इस सिद्धान्त का विस्तृत विवेचन किया। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा इस सिद्धान्त को बड़ी प्रसिद्धि मिली। किन्तु आधुनिक रूप में इस सिद्धान्त का विस्तृत विवेचन प्रसिद्ध अमेरिकन अर्थशास्त्री प्रो० इरविंग फिशर ने किया है। इस सिद्धान्त के अनुसार किसी अन्य वस्तु के मूल्य की भांति मुद्रा का मूल्य भी मुद्रा की माग तथा पूर्ति द्वारा होता है। मुद्रा की माग उन सब वस्तुओं तथा सेवाओं से होती है जिनका समाज में मुद्रा द्वारा एक निश्चित समय में विनिमय होता है। उत्पादन तथा उपयोग दोनों क्रियाओं में ही वस्तु अथवा सेवा का विनिमय होता है और इसी कारण समाज में मुद्रा की माग होती है। दूसरी ओर मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य मुद्रा की उस मात्रा से है जो मनुष्यों के पास है और जो विनिमय के काम में आती है। इस प्रकार यदि मुद्रा की माग में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने पर मुद्रा के मूल्य में ह्रास होता है, इसके विपरीत मुद्रा की पूर्ति में कमी होने पर मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा कीमतों में कमी होती है। सक्षेप में यही मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त है।

मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त यह बताता है कि मुद्रा का मूल्य मुद्रा के परिमाण (Quantity) द्वारा निर्धारित होता है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों में जे० एस्० मिल ने इस सिद्धान्त को इन शब्दों में परिभाषित किया है, “यदि अन्य बातें यथास्थिर रहे तो मुद्रा के मूल्य में उसके परिमाण की विपरीत दिशा में परिवर्तन होते हैं। परिमाण की प्रत्येक वृद्धि मूल्य को उसी अनुपात में घटाती है तथा प्रत्येक कमी उसे उसी अनुपात में बढ़ाती है।”¹ इस प्रकार मुद्रा की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि या कमी उसके मूल्य में क्रमशः आनुपातिक कमी या वृद्धि उत्पन्न करती है। प्रो० टाज्जिन के शब्दों में “यदि अन्य बातें समान रहे तो मुद्रा के परिमाण को दुगुना करने पर कीमतें पहले से दुगुनी हो जायेंगी तथा मुद्रा का मूल्य आधा रह जायेगा।

1. “The value of money, other things remaining the same, varies inversely as its quantity, every increase of quantity lowers the value and every diminution raising it in a ratio exactly equivalent”

—J. S. Mill : *Principles of Political Economy*, Vol. II p 55.

यदि मुद्रा का परिमाण आधा कर दिया जाय तो, अन्य बातें समान रहने पर, कीमतें पहले की आधी रह जायेगी तथा मुद्रा का मूल्य दुगुना हो जायगा।¹

मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की कुछ अन्य लेखकों ने निम्न व्याख्यायें की हैं :

केन्ट विक्सल (Kent Wicksell) "मुद्रा के मूल्य या क्रयशक्ति में इसके परिमाण की विपरीत दिशा में आनुपातिक परिवर्तन होते हैं जिससे मुद्रा के परिमाण की प्रत्येक वृद्धि या कमी, यदि अन्य बातें समान रहे वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में उसकी क्रय शक्ति में आनुपातिक कमी या वृद्धि उत्पन्न करेगी और इस प्रकार सभी वस्तु कीमतों में वंसी ही वृद्धि या कमी आयेगी।"²

डी० एच० राबर्टसन (D H Robertson) यदि मुद्रा की माग की दशायें वी हो तो इसके मूल्य तथा परिमाण के बीच विपरीत सम्बन्ध होता है : जितनी अधिक मुद्रा इकाइया उपलब्ध होगी उतना ही कम, उसी अनुपात में, प्रत्येक इकाई का मूल्य होगा।³

उपरोक्त परिमाणों का अध्ययन करने से यही ज्ञात होता है कि यदि अन्य बातें यथास्थिर रहे तो द्रव्य की क्रय शक्ति द्रव्य के परिमाण के साथ उल्टे अनुपात में परिवर्तित होती है (Other things remaining the same, the purchasing power of money varies inversely as the quantity of money in circulation) इस प्रकार द्रव्य का परिमाण बढ़ने पर मुद्रा का मूल्य उसी अनुपात में घट जाता है और वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतेँ (General Price

¹ "Double the quantity of money, and other things being equal, prices will be twice as high as before and the value of money one half. Halve the quantity of money and other things being equal, prices will be one half of what they were before and the value of money double."

—F. W. Taussig *Principles of Economics*, Vol I p 250

² "The value or purchasing power of money varies in inverse proportion to its quantity, so that an increase or decrease in the quantity of money, other things being equal, will cause a proportionate decrease or increase in the purchasing power in terms of other goods, and thus a corresponding increase or decrease in all commodity prices."

—Kent Wicksell *Lectures on Political Economy*, Vol II, p 141.

³ "Given the conditions of demand for money, the relation between its value and the quantity of it available is of this peculiar kind - the larger the number of units available, the smaller, in exactly the same proportion, is the value of each unit."

—D H Robertson *Money*, p 31.

Level) बढ जाती है। इसके विपरीत द्रव्य का परिमाण घटने से इसका मूल्य इसी अनुपात में बढ जाता है तथा वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य-स्तर घट जाता है। अतः कीमत-स्तर में द्रव्य के परिमाण से सीधे अनुपात में परिवर्तन होता है। (Other things remaining the same, price level varies directly with quantity of money in circulation.)

एक लेखक के अनुसार 'अन्य बातें समान रहने पर द्रव्य के परिमाण का प्रत्येक परिवर्तन सामान्य मूल्य-स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक (Direct Proportional) परिवर्तन लाता है और मुद्रा के मूल्य में विपरीत आनुपातिक (Inverse Proportional)।' इस प्रकार सामान्य मूल्य-स्तर सदा मुद्रा के मूल्य से विपरीत तथा मुद्रा की पूर्ति से प्रत्यक्ष दिशा में परिवर्तित होता है। अन्य शब्दों में, मुद्रा के परिमाण का वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों से प्रत्यक्ष तथा आनुपातिक (Direct and Proportional) तथा मुद्रा के मूल्य से विपरीत तथा आनुपातिक (Inverse and Proportional) सम्बन्ध हाता है।

'अन्य बातें यथास्थिर रहे'-वाक्यांश का अर्थ (Meaning of-'Other things being equal')

मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त में 'अन्य बातें यथास्थिर रहे' वाक्यांश बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य यह है कि जब कुछ बातें स्थिर रहेगी तभी मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त कार्यशील होगा, अन्यथा नहीं। वे बातें निम्नलिखित हैं:—

(1) व्यापार की मात्रा स्थिर रहनी चाहिए : किसी भी देश में मुद्रा की मांग देश में होने वाले व्यापार की मात्रा से निबन्धित होती है। यदि व्यापार की मात्रा स्थिर रहती है तो मुद्रा की मांग भी स्थिर रहेगी। मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त में इस बात की कल्पना की गई है कि द्रव्य की मांग (या व्यापार की मात्रा) स्थिर रहती है।

(2) वस्तु विनिमय नहीं होना चाहिए : विनिमय का कार्य बिना मुद्रा प्रयोग के वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा भी हो सकता है तब इन सौदों को या तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि या व्यापार की मात्रा में कमी सम्भूता चाहिए। इस सिद्धान्त की यह मान्यता है कि या तो समाज में वस्तु विनिमय होता ही नहीं और यदि होता है तो उसकी मात्रा स्थिर रहती है।

(3) साख मुद्रा तथा चलन का अनुपात स्थिर रहना चाहिए : प्राथमिक समाज में बहुत से व्यापारिक सौदों का भुगतान, बैंक, हुन्डी, बिल आदि साख पत्रों की सहायता से होता है और वे व्यवहार में मुद्रा का ही कार्य करते हैं। अतः इनकी मात्रा में घट बढ हो जाने से देश में द्रव्य की कुल मात्रा में परिवर्तन हो जाता है।

अतः यह सिद्धान्त यह मान लेता है कि साख मुद्रा की मात्रा यथास्थिर रहती है और साख मुद्रा तथा चलन का अनुपात भी स्थिर रहता है।

(4) मुद्रा की भ्रमण गति (Velocity) में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए : मुद्रा की भ्रमण गति से तात्पर्य है कि द्रव्य की एक इकाई का उपयोग विनिमय में कितनी बार होता है। मुद्रा तथा साख मुद्रा की भ्रमण गति में परिवर्तन का प्रभाव मुद्रा की पूर्ति पर पड़ता है। अतः मुद्रा तथा साख मुद्रा की भ्रमण गति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

परिमाणु सिद्धान्त का समीकरण

(Equation of Exchange)

मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त को एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विभिन्न कालों में परिमाण सिद्धान्त के विभिन्न रूप रहे हैं। प्राचीन कालीन अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा परिमाण सिद्धान्त का समीकरण इस प्रकार था :

$$\frac{M}{T} = P \quad \text{or} \quad M = PT$$

जिसमें M = देश में प्रचलित चलन की मात्रा,

T = देश में वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा,

P = वस्तुओं तथा सेवाओं का सामान्य मूल्य स्तर।

इस सूत्र में T स्थिर मान लिया गया है जिससे P में सभी परिवर्तन M के कारण होते हैं तथा P और M में प्रत्यक्ष आनुपातिक सम्बन्ध होता है। परन्तु इस सूत्र का मुख्य दोष यह था कि मुद्रा की भ्रमण गति का ध्यान नहीं रखा गया। द्रव्य की भ्रमण गति का महत्त्व स्वीकार कर समीकरण में निम्न संशोधन किया गया —

$$\frac{MV}{T} = P \quad \text{or} \quad MV = PT$$

परिमाणु सिद्धान्त के इस सूत्र में भी यह दोष रहा कि चलन ही विनिमय माध्यम के रूप में प्रयुक्त होनी है परन्तु विधि ग्राह्य मुद्रा के अतिरिक्त साख मुद्रा का भी विनिमय माध्यम के रूप में उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त साख मुद्रा की भ्रमण गति भी साख मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करती है।

प्रो० इरविंग फिशर का विनिमय समीकरण

(Prof Fisher's Equation of Exchange)

प्रो० इरविंग फिशर ने प्राचीन अर्थशास्त्रियों के परिमाण सिद्धान्त के दोषों को दूर कर अपना समीकरण दिया है जो विनिमय का समीकरण (Equation of Exchange) कहलाता है :—

$$P = \frac{MV + M'V'}{T} \text{ or } PT = MV + M'V'$$

जिसमें, M = देश में प्रचलित चलन की मात्रा,

V = चलन की भ्रमण गति

M' = देश में साख मुद्रा की मात्रा

V' = साख मुद्रा की भ्रमण गति

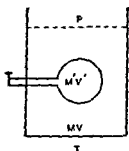
P = वस्तुओं तथा सेवाओं का सामान्य मूल्य स्तर

T = देश में वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा ।

इस प्रकार किसी देश में कुल द्राव्यिक शक्ति बराबर होती है $MV + M'V'$ के । समीकरण का यह एक भाग है जिसमें द्रव्य की पूर्ति बताई गई है । दूसरे भाग में द्रव्य कार्य प्रदर्शित किया गया है जो PT है । इस प्रकार T वस्तुओं और सेवाओं को P मूल्य पर विनिम्न करने के लिए द्रव्य की मात्रा PT के बराबर होती है । अतः समीकरण में द्रव्य की पूर्ति बराबर है $MV + M'V'$ तथा द्रव्य की माँग बराबर है PT ।

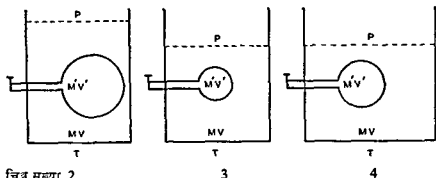
इसी को A. Barker ने अपनी पुस्तक 'Cash and Credit' में निम्न प्रकार समझाया है :

एक बर्तन में जिसकी पेदी घटाई बढ़ाई जा सकती है, MV को पानी मान कर मरा गया है । इसमें साइड से एक थैली लगी है जिससे पानी के अन्दर हवा मरो तथा निकाली जा सकती है और इसमें $M'V'$ है । बर्तन की निचली सतह का T तथा पानी की ऊँचाई को P माना गया है । यदि MV या $M'V'$ को बढ़ाया जाय तो P की सतह ऊँची हो जाती है और T के बढ़ने पर P की सतह नीची हो जाती है । इसके विपरीत MV या $M'V'$ के घटने पर P की सतह नीची हो जाती है और T के घटने पर P की सतह ऊँची हो जाती है । अतः मूल्य स्तर $MV, M'V'$ के अनुकूल तथा T के विपरीत बदलता रहता है । (P varies directly as MV and $M'V'$ and inversely as T)



चित्र संख्या 1

और T के घटने पर P की सतह ऊँची हो जाती है । अतः मूल्य स्तर $MV, M'V'$ के अनुकूल तथा T के विपरीत बदलता रहता है । (P varies directly as MV and $M'V'$ and inversely as T)

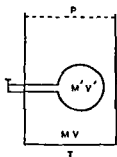


चित्र सख्या 2

3

4

चित्र सख्या 2 में $M'V'$ की मात्रा बढ़ाई गई है और T की मात्रा वही रहती है अतः P ऊपर चला जाता है। चित्र 3 में $M'V'$ की मात्रा घटाई गई है और T की मात्रा वही रहती है अतः P नीचे आ जाता है। चित्र 4 में $M'V'$ की मात्रा यथा स्थिर रखते हुये T बढ़ा दी गई है अतः P नीचे जाता है और चित्र 5 में T घटा दी गई है अतः P ऊपर चला गया है।



चित्र सख्या 5

मुद्रा परिमाण की आलोचनायें (Criticism of the Quantity Theory of Money)

मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त तथा तत्सम्बन्धी समीकरण की अनेक दृष्टिकोणों से आलोचनायें की गई हैं जो निम्नलिखित हैं :

1. फिशर की मान्यतायें अवास्तविक हैं (Fisher's assumptions are imaginary) : प्रो० इरविंग फिशर ने 'अन्य बातें यथास्थिर रहे' के अन्तर्गत जिन मान्यताओं के आधार पर सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है वे इसे अव्यावहारिक तथा अवास्तविक बना देते हैं। परिमाण सिद्धान्त के समीकरण में यह मान लिया गया है कि मुद्रा के परिमाण (M) तथा सामान्य मूल्य स्तर (P) में परिवर्तन होने पर भी मुद्रा की चलन गति (M') तथा व्याणरिक सौदो की मात्रा (T) सभी यथा स्थिर रहते हैं। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता। यह सभी एक दूसरे से स्वतन्त्र (Independent variable) नहीं है जैसा कि फिशर ने माना है। इनमें से किसी एक में परिवर्तन होने पर उसका दूसरे तत्वों पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। लेवेन्सकी का कहना है कि यह सिद्धान्त तो ऐसी मशीन है जिसके समीकरण का प्रत्येक भाग एक दूसरे से सम्बन्धित है और उस मशीन में केवल 'द्रव्य की मात्रा' और 'मूल्य-स्तर' के

ही दो पहिये नहीं हैं बल्कि छोटे छोटे अनेक 'चक्र पहिये' भी हैं। द्रव्य के घटने बढ़ने से केवल मूल्य स्तर का पहिया ही नहीं घूमता बरन् द्रव्य की चलन गति तथा वस्तुओं के लेन देन के सभी 'चक्र पहिये' घूम जाते हैं, और एक तरफ ही नहीं बल्कि दोनों ओर घूमते रहते हैं। इस प्रकार द्रव्य के परिमाण के साथ साथ वस्तुओं के मूल्य स्तर में फेर बदल होना एक साधारण तथा स्वयं सिद्ध बात है। (With the qualification, "Other things remaining the same" the Quantity Theory of Money is a useless truism)

(2) परिणाम सिद्धान्त व्यापार चक्रों में होने वाले मूल्य स्तर के परिवर्तनों की व्याख्या करने में असमर्थ है (Quantity Theory is incapable of explaining the changes in the general price level during Business Cycles) .

प्रो० फ्राउडर के अनुसार परिमाण सिद्धान्त में दो मुख्य दोष हैं। एक तो यह सिद्धान्त मूल्य स्तर के परिवर्तनों के कारण के रूप में मुद्रा के परिमाण के महत्व पर भ्रामक जोर देता है और दूसरे यह सिद्धान्त मूल्य स्तर पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देता है "मानो अर्थ व्यवस्था में मूल्य परिवर्तन ही सर्वाधिक गम्भीर एवं महत्वपूर्ण बात है।" परिमाण सिद्धान्त की दोनों में से कोई भी बात अल्पकाल में तथ्यों के अनुरूप नहीं है। वास्तविक जीवन में मूल्य-स्तर तथा उत्पादन की मात्रा दोनों चक्राकार रूप में बढ़त घटते रहते हैं। इन्हें मन्दीकाल (Depression) तथा तेजीकाल (Boom) के नामों से पुकारा जाता है। मदीकाल में मूल्यों के घटने का कारण मुद्रा की कमी नहीं होता क्योंकि वैकी में बहुत सी मुद्रा बिना उपयोग के पड़ी रहती है। और न तेजीकाल में मूल्यों की वृद्धि का कारण मुद्रा की अधिक पूर्ति होता है क्योंकि ऐसे समय में मुद्रा बाजार में मुद्रा की कमी अनुभव की जाती है। अतः व्यापार चक्रों से सम्बन्धित अल्पकालीन मूल्य परिवर्तन मुद्रा के परिमाण के परिवर्तनों के कारण नहीं होते और इन स्थितियों का पर्याप्त विश्लेषण करने में यह सिद्धान्त असफल रहा है। इस दिशा में यह सिद्धान्त अपूर्ण, अस्पष्ट तथा भ्रामक है। इस सन्दर्भ में श्रीमती राविन्सन ने परिमाण सिद्धान्त को 'दुर्बल तथा विश्वासघातक अस्त' कहा है।

(3) समीकरण के तत्वों का आकलन सम्भव नहीं है (The measurement of the different variables in the equation is not possible) : -
फिशर के समीकरण में विभिन्न तत्वों का किसी भी समय शुद्ध अनुमान लगाना बड़ा कठिन है और इसी कारण इस समीकरण की व्यावहारिक उपादेयता काफी कम हो जाती है। चलन, साख मुद्रा, साख मुद्रा की भ्रमण गति तथा वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा का आकलन उचित रूप में नहीं हो पाता। अतः इस समीकरण द्वारा मूल्य स्तर के परिवर्तनों का अनुमान ठीक प्रकार से नहीं लगाया जा सकता।

4 परिमाण सिद्धान्त उस प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं करता जिसके द्वारा मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन मूल्य स्तर को प्रभावित करते हैं (The theory does not show the process through which the changes in the amount of money affect the price level)

कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि मुद्रा के परिमाण में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव सामान्य मूल्य स्तर पर प्रत्यक्ष एवं सीधा नहीं होता। यह परिवर्तन पहले व्याज की दरों और फिर वस्तुओं के उत्पादन तथा मूल्यों को प्रभावित करता है जिनकी ओर यह सिद्धान्त चाई सनेत नहीं करता। प्रो० केन्स के शब्दों में "मौद्रिक सिद्धान्त की मूलभूत समस्या केवल समानता या सात्त्विकीय सम्बन्ध स्थापित करना ही नहीं है... .. बल्कि समस्या को गतिशील मानकर विभिन्न तरकों का इस प्रकार विश्लेषण करना है कि वे सभी कारण जिनमें मूल्य-स्तर निर्धारित होते हैं तथा जिनसे मूल्य-निर्धारण में सतुलन की स्थिति एक स्थान तक स्थानान्तरित होनी है, स्पष्ट हो जाय।"¹

5. मुद्रा के परिमाण में वृद्धि सदा मूल्यों को नहीं बढ़ाती है। (Increase in the quantity of money does not always increase prices) :

आलोचकों के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि मुद्रा की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि सामान्य मूल्य को बढ़ावे ही। यदि समाज में अप्रयुक्त साधन हैं तो मुद्रा के परिमाण में वृद्धि रोजगार की सुविधायें बढ़ाती है, मूल्य स्तर नहीं। दूसरे शब्दों में मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त 'पूर्ण रोजगार, (Full Employment) की मान्यता पर आधारित है जो व्यावहारिक दृष्टि से दूर की स्थिति ही माना जा सकती है।

6. आधुनिक मौद्रिक तथा बैंकिंग व्यवहार में वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि सदैव मुद्रा की पूर्ति बढ़ाती है। (Under the present monetary and banking practices, increase in the supply of goods almost always leads to an increase in the supply of money) :—

मुद्रा परिमाण सिद्धान्त के अनुसार वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि (T) मूल्य स्तर (P) को गिरानी है लेकिन आधुनिक मौद्रिक तथा बैंकिंग व्यवहार में वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि सदैव साख सृजन तथा अन्य रीतियों द्वारा मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि

1. "The fundamental problem of monetary theory is not merely to establish identities or statistical relation . . .but to treat the problem dynamically, analysing the different elements involved in such a manner as to exhibit the casual processes by which the price level is determined and the method of transition from one position of equilibrium to another."

लाती है। अतः M तथा M' T पर निर्भर है; वे स्वतन्त्र परिवर्ती (Independent Variable) नहीं हैं। यदि ऐसा है तो मुद्रा का मूल्य उसके परिमाण से निर्धारित नहीं होता, वरन् इसके विपरीत मुद्रा का मूल्य उसके परिमाण को नियमित करता है। प्रो० वाउथर के अनुसार :

“The modern tendency in economic thinking, in fact, is to discard the old notion of the quantity of money as a causative factor in the state of business and a determinant of the value of money and to regard it as a consequence”

7. पूर्ति पक्ष पर अधिक बल (Greater emphasis on supply side) — यह सिद्धान्त मुद्रा के माग पक्ष की उपेक्षा कर मुद्रा की पूर्ति पक्ष पर अधिक बल देता है मानो यही मूल्य में परिवर्तन का प्रधान एवं एक मात्र कारण है जब कि मूल्य निर्धारण के लिए माग तथा पूर्ति दोनों का समान महत्त्व है। इसी कारण श्री काक ने ठीक ही कहा है कि “इस सिद्धान्त में मुद्रा के परिमाण पर अनावश्यक महत्त्व दिया गया है जैसे यही आर्थिक परिवर्तनों का एक मात्र या प्रमुख स्रोत हो।”¹

परिमाण सिद्धान्त की उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद भी यह पूर्णतया महत्त्वहीन नहीं है। आर्थिक इतिहास हमें बताता है कि ऊँचे मूल्यों का समय वही था जब मुद्रा की पूर्ति अधिक थी जैसे 1918 के बाद तथा 1939-45 की मुद्रा-स्फीति। हालांकि सिद्धान्त में कई कमियाँ हैं परन्तु यह विवाद से परे है कि यह हमें मुद्रा के परिमाण तथा मूल्यस्तर को प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों में परिवर्तनों के प्रभाव का निर्धारण करने की विधि बताता है। इसीलिए राबर्टसन ने इसे “a Serviceable Platitude” की गज़ा दी है।

नकद सचय सम्बन्धी परिमाण सिद्धान्त—कैम्ब्रिज समीकरण (Cash Balance Quantity Theory—Cambridge Equation)

नकद सचय सम्बन्धी परिमाण सिद्धान्त या कैम्ब्रिज समीकरण फिशर के समीकरण से श्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत किया गया। इस सिद्धान्त का प्रारम्भिक प्रतिपादन पेटी, लाक, कॅन्टीलन तथा एडम स्मिथ ने किया था परन्तु इसका वास्तविक विकास कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों—मार्शल, पीगू, राबर्टसन तथा केन्स द्वारा किया गया। फिशर ने मुद्रा की माँग की वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय विक्रय के माध्यम में स्वीकार किया और उनके अनुसार इन्हीं वस्तुओं और सेवाओं की लेन देन की मात्रा मुद्रा की माग

¹. “There is undue emphasis upon the quantity of money, as if that were the sole or even the main source of economic change”

का निर्धारण करती है। उनके अनुसार द्रव्य केवल विनिमय का साधन है और इसकी तुलना एक रेलवे टिकट से की जा सकती है जो रखने के लिए नयी वरन् रेल यात्रा के लिए खरीदा जाता है। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के अनुसार द्रव्य केवल टिकट की तरह ही प्रयोग में नहीं लाया जाता बल्कि उसको लोग नकद के रूप में अपने पास या बैंक में रखना चाहते हैं। द्रव्य की मांग व्यापार की मात्रा पर निर्भर नहीं करती वरन् लोगों की नकदी रखने की इच्छा (Liquidity preference) पर निर्भर करती है। अतः व्यक्तियों के कोषों का योग ही समाज तरल रूप में रखना चाहता है और यही समाज की मुद्रा की मांग हुई। फिशर के सिद्धान्त में जहाँ मुद्रा की पूर्ति पर अधिक बल दिया गया है वहाँ इस सिद्धान्त में मुद्रा की मांग को अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध किया गया है। अतः इसे मुद्रा का मांग सिद्धान्त (Demand Theory of Money) भी कहते हैं।

उपरोक्त विचार धारा के अनुसार समाज के लोग अपनी आय का एक भाग संचय करते हैं जो आर्थिक अवस्था के अनुसार घटना बढ़ता रहता है। यह तो समाज की मुद्रा की मांग हुई। दूसरी ओर जितनी मुद्रा चलन में रहती है वह किसी न किसी के पास रहती ही है। इस प्रकार मुद्रा का मूल्य एक ओर मुद्रा की इस पूर्ति से ज्ञात होता है और दूसरी ओर मुद्रा की मांग से जो तरलता पसन्दगी का प्रति रूप है [“The value of money is determined on the one side by the supply of money (all the cash and deposits in the hands of the public) and on the other side by the demand for liquidity preference”]

प्रो० मार्शल का समीकरण (Prof Marshall's Cash Balance Equation) :

प्रो० मार्शल का समीकरण निम्नलिखित है --

$$M = KY$$

जिसमें $M =$ मुद्रा की मात्रा,

$K =$ वास्तविक आय का वह अंश जो लोग नकद के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं,

$Y =$ वास्तविक मौद्रिक आय।

प्रो० पीगू का समीकरण (Prof Pigou's Cash Balance Equation) -

$$P = \frac{KR}{M}$$

जिसमें $M =$ नकद मुद्रा का परिमाण,

$R =$ देश की कुल वास्तविक आय,

K = वास्तविक राष्ट्रीय आय का वह अंश जिसे हम अपने पास नकद संचय (Cash Balance) के रूप में रखना चाहते हैं,

P = मुद्रा की एक इकाई का मूल्य।

बैंकों की जमाओं को सम्मिलित करने के लिए समीकरण को इस प्रकार बढ़ाया जाता है—

$$P = \frac{KR}{M} [c + b(1-c)]$$

जहाँ c नकद का वह अनुपात है जिसको जनता विधि ग्राह्य के रूप में रखती है तथा b बैंकों की जमा राशि तथा विधि ग्राह्य का अनुपात है।

P समाज की वास्तविक आय में शामिल होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के कीमत तल को बताता है। इसी प्रकार R वास्तविक आय में शामिल होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा है जो फिशर के वास्तविक सौदे की मात्रा T से निम्न है। इन दोनों समीकरणों में एक मुख्य अन्तर K और V का सम्बन्ध है। वास्तव में K और V एक दूसरे के व्युत्क्रम (Reciprocal) हैं (अर्थात् $K = \frac{1}{V}$ और $V = \frac{1}{K}$)

चूँकि $M = KY$ है इसलिए $K = \frac{M}{Y}$ दूसरी ओर $Y = MV$ क्योंकि Y वास्तविक मौद्रिक आय है तथा वास्तविक मौद्रिक आय, वास्तविक आय (वस्तुएँ और सेवाएँ) को कीमत से गुणा कर देने पर प्राप्त होती है। चूँकि MV निश्चित अवधि के सभी मौद्रिक भुगतानों या प्राप्तियों को व्यक्त करता है इसलिए $MV = PT$ या $MV = Y$ होगा। अतः $V = \frac{Y}{M}$ तथा $K = \frac{M}{Y}$ होगा अर्थात्

$$V = \frac{1}{K} \text{ or } K = \frac{1}{V}$$

यह समीकरण मुद्रा की पूर्ति के साथ साथ मुद्रा की मांग को भी मुद्रा के मूल्य निर्धारण के प्रमुख प्रभावक के रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार इस समीकरण द्वारा मुद्रा मूल्य के सिद्धांत को सामान्य मूल्य सिद्धांत के समान ही स्पष्ट किया गया है और इस बात पर सक्त किया गया है कि मुद्रा के मूल्य में मुद्रा की माँग या पूर्ति किसी भी परिवर्तन होने पर, परिवर्तन होगा। इस दृष्टिकोण में यह समीकरण फिशर के समीकरण से थोड़ा जान पड़ता है। परन्तु इसमें कुल जमा को शामिल किया जाता है जो उचित नहीं माना जाता है। साथ ही यह समीकरण व्यापार चक्रा का स्पष्ट नहीं करता। इस प्रकार इसमें भी वे सामान्य त्रुटियाँ व्याप्त हैं जो फिशर के समीकरण में हैं।

आय, बचत तथा विनियोग सिद्धान्त (Income, Saving and Investment Theory)

मुद्रा के आय सिद्धान्त के विकास का श्रेय प्रो० केन्स को दिया जाता है परन्तु सिद्धान्त का प्रारम्भिक बीज (Thomas Tooke ने 1844 में अपनी पुस्तक "An Enquiry into the Currency Principle" में बोया था। बाद में स्वीडिश अर्थशास्त्री विकसेल ने टुक के विश्लेषण को अपने मुद्रा तथा कीमत सिद्धान्त का आधार बनाया। 1925 में आफतारियो (Aftalion) ने इस सिद्धान्त को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।

इस सिद्धान्त के अनुसार अल्पकाल में कीमत परिवर्तन का मुख्य कारण आय की घट-बढ़ है। मन्दी के समय में कीमत स्तर के घटने का कारण मुद्रा की मात्रा की कमी नहीं होती बल्कि आय के घटने के कारण लोगों की नकदी पसन्दगी बढ़ जाती है और मुद्रा की भ्रमणगति में कमी आती है जिससे मूल्य स्तर गिरता है। इसी प्रकार तेजीकाल में मुद्रा की मात्रा बढ़ने से तेजी नहीं आती बल्कि लोगों की आय बढ़ जाने के कारण लोगों की नकदी पसंदगी घट जाती है तथा मुद्रा की भ्रमणगति बढ़ जाती है जिसके फलस्वरूप कीमत स्तर भी बढ़ जाता है।

संचय विनियोग सिद्धान्त के अनुसार आय में संचय एवं विनियोग में परिवर्तन होने के कारण परिवर्तन होता है और आय के घटने-बढ़ने से मन्दी और तेजी आती है या मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होता है। यहाँ यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि संचय और विनियोग भी आय पर निर्भर करते हैं। निम्नलिखित विवरण में यह सिद्धान्त स्पष्ट हो जाता है।

आय एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मीट्रिक मूल्य है। उत्पादित वस्तुएँ या तो उपभोग्य वस्तुएँ होती हैं या पूंजीगत वस्तुएँ। इन्हीं उपभोग्य वस्तुओं और विनियोग वस्तुओं के विक्रय से आय प्राप्त होती है। अतः आय = उपभोग + विनियोग ($Y = C + I$)

Y = कुल आय, C = उपभोग और I = विनियोग

अब यदि आय पर व्यय की दृष्टि से विचार किया जाय तो आय का एक भाग उपभोग पर खर्च किया जाता है और दूसरा भाग संचय किया जाता है। अतः आय = उपभोग + संचय। यदि संचय = S हो तो

$$Y = C + S$$

उपरोक्त समीकरणों से स्पष्ट है कि विनियोग और संचय दोनों ही आय और उपभोग के अन्तर के बराबर हैं। अतः सम्पूर्ण समाज के दृष्टिकोण से संचय और विनियोग की मात्रा सदैव समान होनी चाहिए क्योंकि आर्थिक प्रयत्नों से जो राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी उसका एक भाग उपभोग वस्तुओं पर किया जायेगा और

एक भाग सचय किया जायेगा अर्थात् $S=Y-C$ । दूसरी ओर यदि आय प्राप्ति के पहलू पर विचार किया जाय तो आय पूंजीगत वस्तुओं (विनियोग) और उपभोग्य वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य है अर्थात् $I=Y-C$

चू कि $S=Y-C$

$I=Y-C$

अतः $S=I$

चू कि सचय और विनियोग को बराबर होना चाहिए इसलिए यदि कोई नया विनियोग किया जाता है तो सचय का उभरना बराबर होना आवश्यक है । वास्तव में लाइ केन्स के अनुसार सचय और विनियोग, उत्पादन के उस हिस्से के दो नाम हैं जिसे उपभोग नहीं किया गया है । समाज का कुल सचय समाज की कुल आय पर निर्भर करता है परन्तु समाज की कुल आय विनियोग के बढ़ने से ही बढ़ सकती है । चू कि सचय और विनियोग के प्रभावक अलग अलग हैं इसलिए सचय स्वयं विनियोग को नहीं बढ़ा सकता । यदि विनियोजक विनियोग नहीं बढ़ाते तो कुछ लोग अधिक सचय का परिणाम दूसरों को आय में कमी हागी तथा आय कम होने से उनका सचय कम होगा । परन्तु यदि विनियोग बढ़ा दिया जाता है तो कुल आय उतनी ही मात्रा में बढ़ जायेगी और अतिरिक्त आय नये विनियोग के बराबर सचय की मात्रा को बढ़ा देगी । इस प्रकार जब सचय विनियोग की अपेक्षा अधिक होने की प्रवृत्ति दिखाता है या विनियोग सचय की अपेक्षा अधिक होने की प्रवृत्ति दिखाता है तो स्वतः ऐसे प्रभावक काम करने लगते हैं जिनसे राष्ट्र के दृष्टिकोण से सचय और विनियोग की समानता बनी रहती है । इस प्रकार सचय और विनियोग की समानता साम्बावस्था की सूचक है । उनमें समानता रहने पर आय तल और कीमत तल अपरिवर्तित रहेंगे तथा उनके असमान होते ही फिर आय तल में ऐसे परिवर्तन होंगे कि समानता पुनः स्थापित हो जायगी । एक बार समानता के समाप्त होने से लेकर पुनः समानता की स्थिति आने तक आय तल, कीमत तल, उत्पादन आदि अर्थशास्त्र के विभिन्न अवयवों में उथल-पुथल हो जाती है । कुछ लोगों का कथन है कि मंदी की स्थिति उस समय पैदा होती है जब सचय विनियोग की अपेक्षा अधिक हो जाता है तथा तेजी (Prosperity) की स्थिति तब आती है जब विनियोग सचय की अपेक्षा अधिक हो जाता है । दूसरा दृष्टिकोण यह है कि विनियोग और सचय अपकर्ष (Slump) तथा पूर्ण रोजगार (Full Employment) की स्थितियों के बीच किसी भी स्तर पर बराबर हो सकते हैं । यदि सचय और विनियोग दोनों ही बहुत कम हैं तो मंदी की स्थिति होती है और यदि दोनों ही अधिक हैं तो तेजी की स्थिति होती है । प्रोफेसर डॉ० एच० राबर्टसन के समय-विश्लेषण (Period Analysis) के अनुसार एक अवधि (Period) में मुद्रा आय के रूप में प्राप्त होती है परन्तु व्यय या सचय के

लिए उसका प्रयोग दूसरी अवधि (Next Period) में ही किया जा सकता है। इसलिए किसी अवधि विशेष में किया जाने वाला सचय और उपभोग उसके पूर्व की अवधि में प्राप्त की गई आय पर निर्भर करता है। इसलिए किसी निश्चित अवधि में विनियोग और सचय में अन्तर हो सकता है। प्रोफेसर ओहलिन तथा स्कैन्डिनेवियन अर्थशास्त्रियों ने भी मूलतः इसी प्रकार की व्याख्या दी है। इनके अनुसार किसी भी स्थिति पर दो प्रकार से विचार किया जा सकता है स्थिति आने के पूर्व (ex ante) तथा स्थिति आने के बाद (ex post)। घटना के पूर्व की स्थिति (ex-ante) यह बताती है कि समाज की उपभोग और सचय तथा विनियोग की योजना के विचार से कितनी आय, सचय और विनियोग की आशा (expectation) है। चूंकि सचय और विनियोग तथा उपभोग के निर्णय पृथक कारणों और पृथक वर्गों पर निर्भर करते हैं इसलिए (ex ante) सचय और (ex ante) विनियोग असमान हो सकते हैं। परन्तु यदि घटना के बाद की स्थिति विचार करें तो जो वास्तविक विनियोग किया जाएगा वह वास्तविक सचय के बराबर होगा।

ऊपर दिए गये विवरण से स्पष्ट है कि सचय और विनियोग सिद्धांत सरल परन्तु तर्कपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत में सभी घटकों (Y, I, S, C) की गणना आसानी से की जा सकती है। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे व्यापार चक्र के स्पष्टीकरण में सहायता मिलती है। क्यों तेजी और फिर पुनः मंदी तथा फिर तेजी तथा मंदी का चक्र चलता रहता है? क्यों मंदी के बाद तेजी आने में अधिक समय लगता है परन्तु तेजी से मंदी आने में कम समय लगता है? यह सभी बातें विनियोग और सचय की असमानता की सहायता से स्पष्ट की जा सकती हैं।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संकेत

(1) मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का क्या अर्थ है? कीमतों के बढ़ने तथा घटने का क्या तर्क यह स्पष्टीकरण है?

(राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल, 1961)

[संकेत—प्रथम भाग में मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की विभिन्न परिभाषाओं सहित विवेचना कीजिए तथा उदाहरण भी दीजिए। दूसरे भाग में सिद्धांत की आलोचना कीजिए।]

(2) मुद्रा परिमाण सिद्धांत की आलोचना कीजिए तथा चलनगति को प्रभावित करने वाले तत्वों पर प्रकाश डालिए।

(राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल, 1963)

[संकेत—प्रथम भाग में परिमाण सिद्धांत की बहुत सक्षिप्त व्याख्या कर, सिद्धांत की आलोचनाओं का विस्तृत विवेचन कीजिए। दूसरे भाग में 'मुद्रा की चलनगति' को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए।]

(3) मुद्रा परिमाण सिद्धात का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए ।

(राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल, 1965)

[सकेत—मुद्रा परिमाण सिद्धात की विभिन्न परिभाषाओं सहित व्याख्या कीजिए । सिद्धात की मुख्य आलोचनाओं का विवेचन कीजिए ।]

(4) “किसी अन्य वस्तु के मूल्य के समान मुद्रा-मूल्य भी मुख्यतः माग और पूर्ति का प्रश्न है।” स्पष्ट कीजिए ।

(राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल, 1967)

[सकेत—मुद्रा परिमाण सिद्धात की विभिन्न परिभाषाओं तथा उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए । सिद्धात की आलोचनाओं का भी विवेचन कीजिए ।]

(5) मुद्रा परिमाण के सिद्धात क ‘केम्ब्रिज समीकरण को स्पष्ट कीजिए । यह समीकरण प्रो० फिशर के विभिन्न समीकरण पर कहा तक सुधार है ?

[सकेत—प्रथम भाग में मुद्रा परिमाण सिद्धात के केम्ब्रिज समीकरण की व्याख्या कीजिए । दूसरे भाग में सिद्ध कीजिए कि केम्ब्रिज समीकरण प्रो० फिशर के समीकरण पर सुधार है ।]

(6) उन कारकों की समीक्षा कीजिए जो ‘मुद्रा की माग’ तथा ‘मुद्रा की पूर्ति’ को प्रभावित करते हैं । मुद्रा का मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है ?

(राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल, 1969)

[सकेत—प्रथम भाग में फिशर तथा आधुनिक अर्थशास्त्रियों जैसे वीन्स के अनुसार मुद्रा की माग का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा केन्स के द्वारा बताये गये मुद्रा की माग के कारणों का विवेचन कीजिए । फिर स्वर्ण मान तथा पत्र मान के अन्तर्गत मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों का विवेचन कीजिए । दूसरे भाग में मुद्रा परिमाण सिद्धान्त तथा अन्य सिद्धान्तों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए ।]

मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन—स्फीति, अपस्फीति, विस्फीति आदि

(Changes in the Value of Money—Inflation,
Deflation, Disinflation etc)

“Thus, money which is a source of so many blessing to mankind, becomes also, unless we control it, a source of peril and confusion”

Robertson

पिछले दो अध्यायों में मुद्रा मूल्य के माप की विधि तथा मुद्रा मूल्य के सिद्धान्तों का विश्लेषण किया जा चुका है। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होते रहना एक सामान्य बात है और इसकी अभिव्यक्ति सामान्य कीमत स्तर के परिवर्तनों में होती रहती है। मुद्रा-मूल्य के परिवर्तनों का महत्व आधुनिक अर्थ तंत्र में बहुत अधिक बढ़ गया है क्योंकि इनका उत्पादन तथा वितरण पर अत्यन्त व्यापक और गहन प्रभाव पड़ता है। मुद्रा मूल्य के परिवर्तनों का प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के सदर्भ में मुद्रा का मूल्य एक ही अनुपात तथा एक ही दिशा में परिवर्तित नहीं होता। मुद्रा-मूल्य के परिवर्तनों के सदर्भ में स्फीति (Inflation) तथा अपस्फीति (Deflation) शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इस अध्याय में इन्हीं का विस्तृत विवेचन किया गया है।

मुद्रा-स्फीति (Inflation)

स्फीति के सम्बन्ध में कई प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं। प्राचीनकाल में चलन तथा साख (Currency and Credit) की प्रत्येक वृद्धि को स्फीति कहा जाता था। प्रथम महायुद्ध-काल में प्रचलित विचार धारा के अनुसार स्फीति का तात्पर्य वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा-पूर्ति की अधिक अनुपातिक वृद्धि द्वारा जनित कीमत-स्तर की वृद्धि से था। सामान्यतया कीमत का बढ़ना स्फीति का लक्षण है परन्तु यह अनिवार्य लक्षण नहीं कहा जा सकता। बिना कीमतों के परिवर्तित हुए भी अथ व्यवस्था में स्फीतिक स्थिति हो सकती है फिर भी कीमतों का बढ़ना स्फीति की इतनी

महत्वपूर्ण विशेषता है कि आधुनिक युग के अर्थशास्त्री श्री क्राउथर ने कहा है :
 “स्फीति ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है, अर्थात् कीमतें बढ़ती हैं।”¹

प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने स्फीति की परिभाषा मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के मदर्म में की। प्रो० केमरर के अनुसार—‘जब विनिमय माध्यम की मात्रा उसकी माग की तुलना में इस प्रकार बढ़ती है कि कीमत-स्तर बढ़ जाता है तो स्फीति की स्थिति आ जाती है।’² फिशर के परिमाण सिद्धान्त के अनुसार जब $M + M^2$ की मात्रा T की अपेक्षा अधिक बढ़ जाती है तथा परिणामस्वरूप कीमत-स्तर बढ़ जाता है तो मुद्रा स्फीति की स्थिति आ जाती है।

वर्तमान विचार धारा के अनुसार मुद्रा-स्फीति की व्याख्या समाज के कुल आय और व्यय (aggregate income and expenditure) तथा उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के सदमं में की जानी चाहिए। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो आय भी बढ़ती है और खर्च भी बढ़ता है। खर्च बढ़ने से कीमत ऊपर बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है। यदि आय बढ़ने के साथ वस्तुएं और सेवाएँ भी उमी अनुपात में बढ़ें तो कीमत स्तर में वृद्धि नहीं होगी। परन्तु यदि बड़ी हुई आय तथा उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं में अन्तर रह जाता है तो कीमत स्तर बढ़ता है यही मुद्रा स्फीति है।

कैम्ब्रिज के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री पीगू के अनुसार स्फीति की व्याख्या देश की कुल मौद्रिक आय तथा उत्पादक साधनों द्वारा किए गए कार्य के सदमं में करनी चाहिए इनके अनुसार,—

“Inflation takes place “when money income is expanding relatively to the output of work done by the productive agents for which it is the payment.”

इस प्रकार इन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि आय प्राप्ति की क्षमता की तुलना में जब मौद्रिक आय अधिक अनुपात में बढ़ती है तो स्फीति की स्थिति आ जाती है। मौद्रिक आय बढ़ने से प्रभावशाली माग (Effective Demand) बढ़ती है तथा ब्याज दर को प्रभावित करती है। यदि रोजगार की वृद्धि हा जाती है और इसका प्रभाव समाप्त हो जाना है तो स्फीति की स्थिति नहीं पंदा होगी। लेकिन इसके फलस्वरूप चूँकि लागत में वृद्धि होती है अतः कीमत-स्तर में भी वृद्धि होती

¹. “.... inflation is a state in which the value of money is falling i. e. prices are rising.”

—Crowther : *An Outline of Money*, p. 107.

². “Inflation is too much money and deposit currency in relation to the physical volume of business being done.”

—Kammerer . *A. B. C. of Inflation*, p. 6.

है जिसे लार्ड कीन्स ने अर्ध-स्फीति (Semi-inflation) कहा है। जब पूर्ण रोजगार बिन्दु के बाद भी प्रभावशाली माँग में मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से वृद्धि होती है तो इसका पूर्ण प्रभाव लागत तथा कीमत पर पड़ता है जिसे स्फीति की स्थिति (Full inflation) कहा जाता है। यहाँ प्रथम इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि मुद्रा-स्फीति का सम्बन्ध मुद्रा की मात्रा से नहीं बल्कि मौद्रिक आय से है। दूसरे, यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक कीमत वृद्धि को स्फीतिक नहीं समझा जाना चाहिए। जब कीमत वृद्धि के साथ रोजगार में वृद्धि न हो तभी उसे स्फीतिक कहा जाता है। लार्ड कीन्स के आधारभूत समीकरण [Fundamental Equation] से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि उत्पादन की तुलना में आय में अधिक वृद्धि होने से ही कीमत स्तर नहीं बढ़ता बल्कि विनियोग लागत (Cost of Investment) एवं सचय में असमानता (discrepancy) होने के कारण भी कीमत-स्तर बढ़ता है। लार्ड कीन्स ने अपने स्फीतिक अन्तर (Inflationary Gap) की व्याख्या से यह स्पष्ट किया है कि कीमतों की स्फीतिक वृद्धि का कारण अनुमानित व्यय एवं उपलब्ध उत्पादन मात्रा में अन्तर होना है। इसी अन्तर को इन्होंने 'स्फीतिक अन्तर' (Inflationary Gap) कहा है। यह अन्तर जितना अधिक होगा स्फीतिक प्रवृत्तियाँ उतनी ही स्पष्ट होंगी। श्री सैमुएलसन ने वस्तुओं और उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ने की स्थिति को स्फीतिक स्थिति कहा है।¹

अमेरिका के फेडरल रिजर्व बोर्ड के अनुसार "The process of making additions to credits not based upon a commensurate increase in the production of goods" स्फीति को जन्म देता है। मौद्रिक अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ डा० पॉल एन्ज़िग (Dr Paul Einzig) ने कहा है "Inflation is an expansionary trend of purchasing power that tends to cause, or to be the effect of, an increase of the price level"

स्फीति की विभिन्न परिभाषाओं में एक समानता अवश्य दिखाई देती है कि स्फीति एक मौद्रिक स्थिति ही है।² स्फीति के प्रधान लक्षणों में उत्पादन में अपेक्षाकृत कम वृद्धि, कीमतों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि, माँग की अपेक्षा उपलब्ध वस्तुओं की मात्रा में कमी, रोजगार तथा आय में अपेक्षाकृत कम वृद्धि, लागत में वृद्धि तथा विनियोगों में वृद्धि प्रमुख हैं।

¹. "By inflation we mean a time of generally rising prices for commodities and factors of production."—Samuelson

². "When an expansion of currency and credit takes place without a corresponding extension of trade and commerce, it is said to be inflation"—C. P. Srivastava

मुद्रा-स्फीति की किस्में (Types of Inflation)

मुद्रा-स्फीति का वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है, जिनमें निम्न-लिखित उल्लेखनीय है —

(अ) स्फीति के कारणों के आधार पर (Classification according to Causes) —

प्रो० पीगू ने स्फीति के कारणों के आधार पर स्फीति के दो भेद बतलाए हैं:-

- 1 घाटा-जनित स्फीति (Deficit Inflation)
- 2 मजदूरी-जनित स्फीति (Wage Inflation)

(1) घाटा-जनित-स्फीति (Deficit Induced Inflation) : इस प्रकार की मुद्रा-स्फीति उस समय पैदा होती है जब सरकार अपनी सामान्य भावना से प्राप्त आय की अपेक्षा अधिक व्यय करने के लिए घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा लेती है। घाटे की अर्थव्यवस्था के कारण मुद्रा प्रसार होता है परन्तु उत्पादन मात्रा में उस तुलना में कम वृद्धि हा पाती है इसलिए स्फीति और फिर भी स्फीति की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसा प्रायः युद्ध काल में या आर्थिक-विकास काल की योजनाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है।

(2) मजदूरी जनित मुद्रा-स्फीति - नरुद मजदूरी (Money Wages) में वृद्धि होने के कारण जो मुद्रा-स्फीति पैदा होती है उसे मजदूरी जनित मुद्रा-स्फीति कहा जाता है। जब किन्हीं कारणों से कीमतों में वृद्धि होती है तो मजदूरी बढ़ाने की माग की जाती है और मजदूरी बढ़ जाने से मजदूरों की आय और उनकी माग में वृद्धि होती है। वस्तुओं की पूर्ति उसी अनुपात में नहीं बढ़ पाती इसलिए फिर कीमतें बढ़ती हैं और फिर मजदूरी बढ़ाने की माग होती है। इस प्रकार कीमत और मजदूरी बढ़ने का चक्र चलने लगता है जिसे कीमत मजदूरी चक्र (Wage Price Spiral) कहते हैं तथा इस स्थिति को मजदूरी जनित मुद्रा स्फीति बहते हैं।

कारणों के आधार पर अन्य विद्वानों ने जो वर्गीकरण किया है उनमें निम्न-लिखित उल्लेखनीय हैं:-

1. चलन स्फीति (Currency Inflation)
2. साख स्फीति (Credit Inflation)
3. बजट जनित स्फीति (Budgetary Inflation)
4. कर स्फीति (Taxation Inflation)
5. अतिनिवेश स्फीति (Over investment Inflation)
6. अधोत्पादन स्फीति (Under production Inflation)

7 असंचय स्फीति (Dis-saving Inflation)

8 आयातित स्फीति (Imported Inflation)

9. लाभ स्फीति (Profit Inflation)

(1) चलन स्फीति (Currency Inflation) पीगू ने जिसे घाटा जनित स्फीति की सजा दी है उस ही चलन स्फीति भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सरकार अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यय करने के निमित्त नोटों की मात्रा चलन में बढ़ा देती है जिसके फलस्वरूप कीमत स्तर बढ़ जाता है। इसे ही बजट-जनित स्फीति (Budgetary Inflation) भी कहते हैं।

(2) साख स्फीति (Credit Inflation) जब सरकारी नीति द्वारा साख निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाता है और फलस्वरूप साख निर्माण बढ़ जाता है तो कीमत स्तर चलन की मात्रा पूर्ववत् रहने पर भी बढ़ने लगता है। इस स्थिति को साख स्फीति कहते हैं।

(3) कर स्फीति (Taxation Inflation) जब कर अधिक लगाने के कारण लागत तथा कीमतों में वृद्धि होनी है तो उसे कर स्फीति करते हैं।

(4) अतिनिवेश स्फीति (Over investment Inflation) जब अति निवेश के कारण वस्तुओं की लागत बढ़ जाती है और लोगों की आय में वृद्धि हानी है तथा परिणाम स्वरूप कीमतें बढ़ती हैं तो अतिनिवेश स्फीति कहा जाता है।

(5) अधोत्पादन स्फीति (Under production Inflation) : किन्हीं कारणों से जब दक्ष में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में कमी हो जाती है तथा मुद्रा की मात्रा पूर्ववत् बनी रहती है तो मूल्यों में वृद्धि होने की प्रवृत्ति रहती है। ऐसी अवस्था का अधोत्पादन-स्फीति कहा जाता है।

(6) असंचय स्फीति (Dis-saving Inflation) जब संचय की मात्रा में कमी आ जाती है और उपयोग पर तथा विनियोगों पर व्यय की मात्रा बढ़ जाती है तो मूल्य में वृद्धि की अवस्था आ जाती है जिसे असंचय स्फीति की सजा दी जाती है।

(7) आयातित स्फीति (Imported Inflation) आयातित स्फीति की अवस्था उस समय उत्पन्न होती है जब किसी देश का भुगतान समतुलन लगातार उसके पक्ष में रहता है। इसके प्रमुख कारण हैं - (1) उस देश से निर्यात अधिक होने के कारण विनियोग के लिए पूंजी की मांग बढ़ती है और विनियोग व्यय बढ़ता है तथा (2) बैंकों की साख निर्माण शक्ति बढ़ जाती है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति विदेशी भुगतानों के फलस्वरूप अच्छी हो जाती है। प्रारम्भ में बचत वाला देश मुद्रा नियन्त्रण और साख नियन्त्रण द्वारा इस अवस्था को रोकने का प्रयत्न

करता है परन्तु अन्तत मुद्रा प्रसार की स्थिति आने लगती है। इसको आयातित स्थिति कहने का कारण यही है कि यह अवस्था घाटे वाले देशों (जहाँ अधिकतर मुद्रा प्रसार रहता है) से आने वाली पूँजी के कारण पैदा होती है।

(8) लाभ स्फीति (Profit Inflation) : जब स्फीति का कारण 'उत्पादकों के लाभ में वृद्धि' होता है तो उसे लाभ-स्फीति कहा जाता है।

मुद्रा स्फीति के कारणों पर आधारित वर्गीकरण से यह स्पष्ट है कि मुद्रा स्फीति के अनेक कारणों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है :

1 मॉड्रिय आय एव माग में वृद्धि करने वाले कारण : इसके अन्तर्गत सरकारी नीतियाँ, घाटे की अर्थव्यवस्था, अधिक साख निर्माण, मुद्रा की माग में वृद्धि, योजना को चलाने के लिए अधिक संच की व्यवस्था आदि कारण आते हैं। इस प्रकार की स्फीति को माग वृद्धि-स्फीति कहा जाता है।

2 उत्पादन की वृद्धि में बाधा डालने वाले कारण : इसके अन्तर्गत उत्पादन के साधनों का अभाव, तकनीकी ज्ञान की कमी, व्यापार नीति, जनसंख्या, कर नीति, प्राकृतिक कारण आदि आते हैं।

3. मनोवैज्ञानिक कारण इसके अन्तर्गत वे कारण सम्मिलित किए जाते हैं जो भविष्य के अनुमानों को प्रभावित करते हैं। कई आर्थिक निर्णयों में भविष्य के अनुमानों का महत्वपूर्ण स्थान होता है।

(ब) मुद्रा स्फीति के कारणों के अलावा स्फीति का वर्गीकरण (Classifications other than according to causes) :

समय के आधार पर मुद्राकालीन स्फीति, शान्ति कालीन स्फीति के रूप में, क्षेत्र के आधार पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्फीति के रूप में तथा सरकारी नियमन (Govt Regulation) के आधार पर—खुला (Open) तथा दबा हुआ (Suppressed) स्फीति के रूप में किया जाता है। पात इजिंग ने (Open) तथा (Suppressed) स्फीति का परिभाषित करते हुए लिखा है —

“When upward pressure on prices brought about by the free interaction of demand & supply is manifestable, it is known as open inflation,.... if it is prevented by government measures such as rationing, price control etc , from producing its effects on prices, it is suppressed inflation ”

(स) गति के आधार पर स्फीति का वर्गीकरण (Classification according to the speed or rapidity in the increase in prices) :

1. रेंगती हुई स्फीति (Creeping Inflation)
2. चलती हुई स्फीति (Walking Inflation)
3. दौड़ती हुई स्फीति (Running Inflation)
4. कूदती हुई स्फीति (Jumping or Galloping or Hyper Inflation)

यदि कीमत स्तर में धीरे-धीरे वृद्धि होती हो और उससे अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल की स्थिति पैदा न हो तो स्फीति की इस दिशा को धीमी स्फीति (Mild Inflation) या रेंगती हुई स्फीति (Creeping Inflation) कहा जाता

कुछ अर्थशास्त्री ऐसी स्फीति पिछड़े, परन्तु विकास-रत देशों के लिए आवश्यक बताते हैं क्योंकि यह अर्थव्यवस्था को गतिहीनता (Stagnation) से बचाती है। परन्तु कुछ लोगों का मत है कि यह बड़ी खतरनाक स्थिति है और यदि इस पर रोक न लगाई जाय तो यह दौड़ती और फिर कूदती हुई स्फीति को जन्म देती है।

चलती हुई स्फीति के अन्तर्गत कीमत वृद्धि अधिक स्पष्ट हो जाती है और वास्तव में यह इस बात का संकेत है कि अल्प स्फीति पर नियन्त्रण करना अर्थव्यवस्था को बनाये रखने के लिए आवश्यक है। पूरा वृत्ति बिन्दु के बाद जब स्फीति और उग्र रूप धारण कर लेती है और व्यापार चक्र तेजी से चलने लगता है तो दौड़ती हुई स्फीति की स्थिति आ जाती है और स्फीति की मात्रा का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। जनता का भविष्य सम्बन्धी अनुमान उसे और अधिक खर्च करने की प्रेरणा देने लगता है। इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण कीमतें बढ़ने लगती हैं और स्फीति की भयंकर स्थिति पैदा हो जाती है तथा उस पर काबू पाना असम्भव हो जाता है। इसे ही कूदती हुई या अति स्फीति (Jumping or Galloping or Hyper Inflation) कहते हैं। इस अवस्था को लाई की-स ने पूरा स्फीति (Full Inflation or Time Inflation) कहा है।

मुद्रा-स्फीति के प्रभाव (Effects of Inflation)

मुद्रा स्फीति अर्थव्यवस्था तथा समाज का व्यापक रूप से प्रभावित करती है। सुविधा के दृष्टिकोण से हम मुद्रा स्फीति के प्रभावों को निम्नलिखित मुख्य श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं

1. व्यावसायिक गतिविधि पर प्रभाव (Effect on Business Activity)
2. आय के वितरण पर प्रभाव (Effects on Distribution of Income)
3. सामाजिक प्रभाव (Social Effects)

(1) व्यावसायिक गतिविधि पर प्रभाव (Effects on Business Activity)

व्यावसायिक गतिविधि का केन्द्र बिन्दु उत्पादन है। उत्पादन कर्त्ता लाभ की आशा में उत्पादन करता है। लाभ की मात्रा उत्पादन व्यय और उत्पादित वस्तुओं की कीमत पर निर्भर करती है। चूंकि मुद्रा स्फीति काल में कीमतें उत्पादन व्यय की अपेक्षा अधिक बढ़ती हैं इसलिए लाभ की मात्रा बड़ जाती है। इससे उत्पादकों में आशा का संचार होता है और वे अधिक उत्पादन करने को प्रोत्साहित होते हैं।

उत्पादन बढ़ने से उत्पादन के साधनों की आय बढ़ती है और माग बढ़ती है। फिर उत्पादन बढ़ता है, आय बढ़ती है तथा माग बढ़ती है। परन्तु कई आधुनिक अर्थ-शास्त्रियों का मत है कि वास्तव में मुद्रा स्फीति की स्थिति पूर्ण रोजगार के विन्दु के पास प्रारम्भ होती है इसलिए मुद्रा स्फीति द्वारा उत्पादन में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि की आशा नहीं की जा सकती। वास्तव में उत्पादन क्रम (Pattern of Production) में जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तित मूल्य सम्बन्धों (Price Relationships) तथा आय एवं सम्पत्ति के पुनर्वितरण का ही परिणाम है क्योंकि मुद्रा स्थिति के प्रभावशाली आय के वितरण में जो परिवर्तन होगा उसमें उपभोग एवं विनियोग भी प्रभावित होंगे। मुद्रा स्फीति के कारण जिनकी आय बढ़नी है तथा जिनकी आय कम होती है दोनों के व्यय-क्रम (Pattern of Expenditure) में अन्तर हो सकता है।

मुद्रा-स्फीति की स्थिति में विभिन्न उद्योगों में लाभ की मात्रा समान मात्रा में नहीं बढ़ती है। इसलिए भी उत्पादन क्रम (Pattern of Production) में परिवर्तन हो जाता है। जिन उद्योगों में वर्तमान औसत लाभ से अधिक लाभ होगा वे उन उद्योगों की अपेक्षा अधिक विकसित होंगे जहाँ औसत लाभ से कम लाभ हो रहा था। परन्तु इस प्रकार का परिवर्तन दीर्घकाल में समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से सन्तुष्ट नहीं कर सकता और सम्भवतः मुद्रा संकुचन और मन्दी की स्थिति लाने में योगदान करेगा।

उत्पादन के अतिरिक्त मुद्रा स्फीति व्याज दर को भी प्रभावित करती है। सट्टे की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है तथा वह मुद्रा स्फीति-क्रम (Process of Inflation) का अंग भी बन सकती है।

(2) आय के वितरण पर प्रभाव (Effect on Distribution of Income):

(1) प्रसविदा पर आधारित आय मौद्रिक प्रसविदा सम्बन्धों पर मुद्रा स्फीति का अत्याधिक प्रभाव पड़ता है। ऋणी वर्ग मुद्रा स्फीति से लाभान्वित होता है तथा ऋणदाता वर्ग हानि उठाता है। प्रसविदा की अवधि जितनी अधिक होती है लाभ तथा हानि की मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है। जिन लोगों के पास दीर्घकालीन बाड होते हैं वे अधिक हानि उठाते हैं। भूकान मालिक और नौकरी पशा लोग अपेक्षाकृत कम हानि उठाते हैं। मजदूर सभों के विकास के कारण अब मजदूरी कीमतों से अधिक पीछे नहीं रहती। इस प्रकार मुद्रा स्फीति उत्पादन के साधनों में वर्तमान आय के वितरण को परिवर्तित कर देती है। जिस साधन की आय का आधार प्रसविदा होता है (भूमि पूँजी, श्रम) उसकी आय मुद्रा स्फीति के समय कम होती है। यही नहीं, मुद्रा स्फीति पूँजी मूल्यों (Capital Value) को भी पुनर्वितरित करती है। मुद्रा स्फीति द्वारा किस प्रकार पूँजी मूल्यों का पुनर्वितरण

किया जाता है यह एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए किसी सम्पत्ति का मूल्य वर्तमान कीमतों के आधार पर 5000 रु० है। यदि उसे 2500 रु० के लिए बन्धक (Mortgage) रखा गया हो तो बन्धक रखने वाले का उस सम्पत्ति में 2500 रु० के बराबर हित है और 2500 रु० के बराबर उस सम्पत्ति के स्वामी का। यदि मुद्रा स्फीति के कारण उक्त सम्पत्ति का मूल्य, स्फीति के कारण बढी हुई कीमतों के आधार पर, 10000 रु० हो जाय तो भी बन्धक रखने वाले का हित बवल 2500 रु० के बराबर ही होगा परन्तु स्वामी का हित 7500 रु० के बराबर हो जावेगा। इस प्रकार मुद्रा स्फीति सम्पत्ति में बन्धक रखने वाले और स्वामी के हितों के अनुपात को बदल देता है। इस उदाहरण के अनुसार हितों का अनुपात 1:1 से बदल कर 1:3 हो जाना है। इसी प्रकार मुद्रा स्फीति स्टॉक रखने वालों (Stock holders) के लिए लाभदायक एवं बाड रखने वालों के लिए हानिकारक है।

(ii) कृषक—मुद्रा स्फीति की स्थिति में कृषकों की आय में वृद्धि होती है क्योंकि कृषि-पदार्थों की कीमत बढ़ जाती है परन्तु उनका उत्पादन व्यय उम अनुपात में नहीं बढ़ता। ऐसी अवस्था में किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है अतः कृषि के क्षेत्र में विकास होता है। कृषक वर्ग अधिकांशतः ऋणी होता है (पिछड़े हुए देशों में) इसलिए मुद्रा स्फीति उनके लिए और लाभदायक होती है। परन्तु पिछड़े हुए देशों में जहाँ कृषि एक व्यवसाय नहीं बल्कि जीवन का तरीका (Mode of living) है, वहाँ मुद्रा-स्फीति जनित लाभ का अधिकांश भाग बिचौलियों (Middlemen) को प्राप्त हो जाता है। साथ ही कृषकों को अपनी आवश्यकता की अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए पहल की अपेक्षा अधिक व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार मुद्रा स्फीति के कारण जो वास्तविक लाभ प्राप्त होता है वह बहुत अधिक नहीं होता।

(iii.) उद्योगपति और व्यापारी वर्ग—मुद्रा-स्फीति की दशा में इस वर्ग की आय में वृद्धि होती है क्योंकि इनके व्यय की अधिकांश मदें प्रसविदा पर आधारित होने के कारण बढ़ती नहीं हैं तथा दूसरी ओर कीमतों के बढ़ने से उन्हें प्राप्त अधिक होती है। मुद्रा स्फीति होने कारण सामान्य जनता की क्रय शक्ति में भी वृद्धि होगी है और वस्तुओं की मांग बढ़नी है। वस्तुओं की कीमत और मांग बढ़ने से इस वर्ग का प्राप्त होने वाले लाभ की दर और मात्रा दोनों में वृद्धि होती है। अतः वे न केवल पुराने उद्योगों में उत्पादन की मात्रा बढ़ाते हैं बल्कि नए उद्योग भी स्थापित कर रहे हैं। औद्योगिक विकास की गति में तीव्रता आती है। व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आ जाती है क्योंकि साख उपलब्ध होने में बाधा नहीं रहती है। परन्तु इस वर्ग को प्राप्त होने वाले लाभ में, मुद्रा स्फीति कास के दीर्घ कालिक और गहन हा जान

पर, कमी होने लगती है क्योंकि श्रमिक सध अपनी मजदूरी बढ़वा कर व्यय में वृद्धि करने में सफल हो जाते हैं ।

(iv) श्रमिक—श्रमिकों का पारिश्रमिक प्रायः प्रसविदा के आधार पर निश्चित किया जाता है । इसलिए कीमतों में वृद्धि होने पर श्रमिकों की आय वस्तुओं और सेवाओं के सदम में कम हो जाती है । मौद्रिक आय यदि बढ़नी भी है तो सामान्य कीमत स्तर की अपेक्षा कम बढ़ती है । सभी श्रमिकों पर भी समान प्रभाव नहीं पड़ता । दैनिक कार्य करते वाले मुद्रा स्फीति की स्थिति देखकर अपनी मौद्रिक आय में अपेक्षाकृत शीघ्र और अधिक वृद्धि कराने में सफल हो जाते हैं परन्तु मामिक ब्रेतन पान वाले शीघ्र सफल नहीं हो पाते । परन्तु श्रमिक वर्ग के लिए सबसे बड़ा नाम मुद्रा स्फीति से यह है कि रोजगार में वृद्धि होती है । इसलिए जिन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा था उन्हें रोजगार मिल जाता है और शून्य आय के स्थान पर उनकी आय घनात्मक हो जाती है ।

(v) सामान्य जनता—सामान्य जनता के अन्तर्गत मध्यम वर्ग और गरीब जनता शामिल है । मुद्रा-स्फीति के समय इस वर्ग की मौद्रिक आय तो अवश्य बढ़ती है परन्तु उसका वास्तविक उपभोग कम हो जाता है क्योंकि जितनी आय बढ़ती है उससे उही अधिक कीमतें बढ़ जाती हैं । इसलिए इस वर्ग में असन्तोष पैदा हो जाता है । सरकार के प्रति विश्वास बनाए रखना कठिन हो जाता है । सामान्य स्फीति की स्थिति को फिर भी उतनी भयावह नहीं होती परन्तु यदि स्फीति की मात्रा अधिक हो तो स्थिति विस्फोटक हो जाती है । राजनैतिक स्थिरता संदिग्ध हो जाती है और मुद्रा अपने सभी कार्यों को सम्पन्न नहीं कर पाती । जर्मनी की 1923 की स्थिति इस बात का पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करती है कि जब मूल्य माप का कार्य स्विस्-फैंक और अमेरिकन डॉलर के द्वारा किया जाता था परन्तु चलन मुद्रा मार्क थी ।

(3) सामाजिक प्रभाव (Social Effects):—

मुद्रास्फीति का प्रभाव आर्थिक गतिविधियों पर ही नहीं पड़ता बल्कि सामाजिक तत्वों पर भी पड़ता है । समाज के विभिन्न वर्गों में धन और आय का जो अन्यायपूर्ण वितरण होने लगता है उसके कारण नैतिक मूल्यों का पतन होने लगता है । मिलावट का बाजार गरम हो जाता है । घूसखोरी और भ्रष्टाचार (Corruptions) सामाजिक जीवन का धग बन जाते हैं । मुद्रास्फीति के कारण जर्मनी में जो नैतिक पतन हुआ उसका आभास प्रो० एस० के० मुरजन द्वारा उद्धृत निम्नलिखित उद्धरण से मिलता है—

“Young girls bragged proudly of their perversion, to be sixteen and under the suspicion of virginity would have been considered disgrace in any school of Berlin at that time; every girl

wanted to be able to tell of her adventures and the more exotic the better”¹

इस प्रकार यदि मुद्रास्फीति लम्बे समय तक चलती रहे तो समस्त सामाजिक तत्त्व परिवर्तित हो जाते हैं और नैतिक मूल्यों में आमूल परिवर्तन हो जाता है।

मुद्रास्फीति का नियन्त्रण (Control of Inflation)

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि मुद्रास्फीति के कारण अनेक प्रकार की आर्थिक, सामाजिक और नैतिक कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं और समाज पर बड़ा ही भयंकर प्रभाव पड़ता है। परन्तु यह भी नहीं भुलाया जा सकता कि इससे उद्योगों के विकास और रोजगार की वृद्धि में बड़ी सहायता मिलती है। वास्तव में मुद्रा स्फीति जब दीर्घकालिक और अधिक मात्रा में होती है तभी इसकी बुराईयाँ इसकी अच्छाईयों को समाप्त करती हैं। यदि मुद्रा स्फीति को नियन्त्रित रखा जाय तो समाज पर इसका प्रभाव अधिक हानिकारक नहीं होगा। मुद्रास्फीति को नियन्त्रित रखने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं

1. मौद्रिक नीति—मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारण मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियन्त्रण में रखकर उससे बढ़ने वाली मांग और कीमतों को नियन्त्रण में रखा जा सकता है। मुद्रा की मात्रा अधिक न बड़े इसके लिए मुद्रा जारी करने वाली संस्था पर ऐसा कानूनी प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए जिससे अतिरिक्त मुद्रा जारी करना अपेक्षाकृत कठिन हो जाय। इसके लिए कोष की मात्रा (नोटों के पीछे रखा जाने वाला स्वर्ण और विदेशी विनिमय) में वृद्धि की जा सकती है। साख पर नियन्त्रण करने के लिए बैंकों द्वारा साख निर्माण की शक्ति को कम करना आवश्यक है जिसे केन्द्रीय बैंक बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएँ तथा अन्य उपायों द्वारा कर सकता है। यदि मुद्रा स्फीति अत्यन्त ही अधिक हो चुकी है तो पुरानी मुद्रा के स्थान पर नयी मुद्रा जारी की जा सकती है जैसा जर्मनी ने प्रथम महायुद्ध के बाद किया था।

मुद्रास्फीति को नियन्त्रित करने के लिए मौद्रिक नीति का साधन अपनाने में अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। यदि मौद्रिक नीति का प्रयोग सामान्य मात्रा में किया जाता है तो यह प्रभावहीन हो सकती है और यदि इसको अधिक मात्रा में अधिक तीव्रता से काम में लिया तो अर्थ व्यवस्था पर बुरा और भयानक असर पड़ सकता है। प्रो० हैनमन के शब्दों में—“Moderately used it (monetary policy) courts the failure of ineffectiveness Pushed to the needed financial extremes, it courts disaster”

1. The World Yesterday—Stefan Zweig—Quoted by S. K. Muranjan in “From Hyper Inflation to Devaluation” p. 13.

2. वित्तीय नीति : मौद्रिक नीति के अतिरिक्त वित्तीय नीति के द्वारा भी मुद्रा स्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त क्रय शक्ति के प्रयोग पर अकुश लगाना आवश्यक है। इसके लिए सरकार कर वृद्धि (Direct Tax) व्यय कर तथा वलात् ऋण (Forced Loan) का प्रयोग कर सकती है। कर्गों की वमूली में कडाई की भी आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ सरकार को अपना बजट सतुलित रखने का प्रयास करना चाहिए जिससे घाट की अर्थ व्यवस्था से बचा जा सके। यदि सम्भव हो तो वचत बजट (Surplus Budget) बनाया जाना चाहिए। सरकार के पूंजी व्ययों तथा अन्य व्ययों में कमी लाकर सम्पूर्ण समाज के व्यय को कम किया जा सकता है।

वास्तव में वित्तीय और मौद्रिक नीतियों का मुद्रा स्फीति के नियंत्रण के लिये माथ-साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। अकेले इनमें से कोई भी नीति अधिक कारगर नहीं हो सकती।

3 अन्य उपाय : मौद्रिक नीति अथवा वित्तीय नीति के द्वारा जनता की प्रभावशाली मांग को कम करना या नियंत्रित करना तथा उसके माध्यम से मुद्रा स्फीति का उपचार करना उस स्थिति में और भी कठिन होता है जब मुद्रा स्फीति बाजार की शक्तियों (Market Power) के क्रियाशील होने के कारण उत्पन्न हुई हो। ऐसी अवस्था में मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपायों का प्रयोग अधिक प्रभावशाली होता है :

(i) मूल्य-नियंत्रण आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली वृद्धि पर रोक लगा देना चाहिए। लोगों को खर्च कम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। राजनिग का भी सहारा लिया जा सकता है परन्तु बाले बाजार को जन्म नहीं लेने दना चाहिए। उपभोक्ता साख पर कड़ी रोक लगा देनी चाहिए।

(ii) मजदूरी नियंत्रण . मुद्रा स्फीति में मजदूरी-कीमत चक्र (Wage Price Spiral) को रोकना अत्यन्त महत्वपूर्ण है इसलिए मजदूरी में निरंतर बढन की प्रवृत्ति पर रोक लगाना आवश्यक है। यदि मजदूरी बन्धन (Wage freeze) की नीति काम में ली जायेगी तो लागत में वृद्धि होना रुक जायेगी और लागत वृद्धि के कारण जो मूल्य वृद्धि होती है वह स्वतः ही रुक जायेगी। कीमतों के स्थिर हा जाने पर अभिक सधों द्वारा भ्रमतोप भी नहीं व्यक्त किया जायेगा। इस प्रकार मुद्रा स्फीति को रोका जा सकता है। लेकिन केवल मजदूरी बन्धन अधिक प्रभाव शाली नहीं होगा। यदि लाभ की दर पर भी रोक लगा दी जाय तो प्रभाव अधिक अच्छा होगा।

(iii) विनिर्भोजन पर नियंत्रण मुद्रा स्फीति की स्थिति में मौद्रिक आय की तुलना में वस्तुओं में कम वृद्धि होती है इसलिए सामान्य जनता को कठिनाई होती

है। विनियोजक विभिन्न ऐसे क्षेत्रों में विनियोग करते हैं जिनसे लोगों की आय बढ़ जानी है परन्तु उत्पादित पदार्थों की मात्रा में तत्काल या काफी समय तक कोई वृद्धि नहीं होती। सरकार को नये विनियोगों को केवल उसी क्षेत्र में छूट देनी चाहिए जहाँ तत्काल उत्पादन सम्भव है। इसके साथ ही वर्तमान संस्थानों में उत्पादन के बढ़ाने का भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिए। एकाधिकारिक प्रवृत्ति वाली औद्योगिक संरचना में विभाजन किया जाना चाहिए। सट्टेबाजी पर नियंत्रण लगाना अति आवश्यक है।

उपरोक्त उपायों में से किसी एक उपाय का सहारा न लेकर यदि सभी उपायों द्वारा मुद्रा स्फीति की समस्या में सुधार लाने का प्रयत्न किया जाय तो निश्चय ही वह अधिक सफल होगा। इनके साथ ही सरकार को चाहिए कि वह जनता को इसके बारे में शिक्षित करे। लोगों में बचत करने की आदत को प्रोत्साहित करे। और उनमें यह भावना भर दे कि "a moderate degree of inflation is less objectionable than effective remedies"¹

मुद्रा संकुचन (Deflation)

मुद्रा संकुचन की स्थिति मुद्रा स्फीति की ठीक विपरीत स्थिति होती है। मुद्रा प्रसार की इस विलोम स्थिति, प्रवृत्ति तथा प्रक्रिया को ही मुद्रा संकुचन की संज्ञा दी जाती है। ऐसी स्थिति में कीमत-स्तर गिरता है, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। आर्थिक क्रियाओं की अपेक्षा मौद्रिक आय में अधिक अनुपात में कमी होती है। प्रत्यावर्तन (Recession) प्रारम्भ हो गया रहता है और सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था मंदी की ओर बढ़ने लगती है। मुद्रा संकुचन सरकार की मौद्रिक नीति का परिणाम हो सकता है। सामान्य कीमत स्तर में, यदि कृत्रिम रूप से, बिना लागत में कमी लाए, कमी लाई जाती है तो यह हानिकारक हो सकता है। परन्तु यदि सामान्य कीमत स्तर में तकनीकी सुधारों के कारण लागत में कमी होने से कमी आती है तो इस प्रकार का मुद्रा संकुचन हानिकारक नहीं होता। सामान्यतया मुद्रा संकुचन की स्थिति उन दशाओं की ओर संकेत करती है जब उत्पादन घटावत रहता है परन्तु मौद्रिक आय कम होती है, जब उत्पादन भी कम होता है परन्तु मौद्रिक आय की तुलना में कम, जब उत्पादन में वृद्धि होती है पर मौद्रिक आय में स्थिरता रहती है, जब मौद्रिक आय भी बढ़ती है परन्तु उत्पादन से कम या जब उत्पादन बढ़ता है परन्तु मौद्रिक आय घटती है।

कारण—मुद्रा संकुचन का कारण सरकार की मौद्रिक नीति होती है। यदि केन्द्रीय बैंक चलन में मुद्रा की मात्रा में कमी कर दे या बँजो द्वारा नास्त मुद्रा के

1. "Money and Banking": Whittlesey, Freedman and Heiman, p. 405.

निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने की नीति अपनाए तो मुद्रासंकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। अधिक मात्रा में कर लगाना या जनता से ऐच्छिक या अनिवायं ऋण लेना भी मुद्रा संकुचन को जन्म देता है। इसके अतिरिक्त यदि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद भी मुद्रा की मात्रा यथावत रखी जाय तो भी संकुचन की स्थिति पैदा हो जाती है।

प्रभाव (Effects of Deflation) :—मुद्रा संकुचन का अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रास्फीति का ठीक विपरीत प्रभाव पड़ता है। वस्तुओं की कीमतें कम होती जाती हैं इसलिए उत्पादकों को हानि होती है। विक्रेता अपने पहले के माल को कम से कम घाटा उठाकर शीघ्र में शीघ्र बेचना चाहता है। खरीददार कीमत और कम होने की उम्मीद में खरीद स्थगित कर देता है। विक्रेताओं का घाटा बढ़ने लगता है। वे और माल की भाग बहुत कम कर देते हैं। ऐसी स्थिति में उत्पादक भी उत्पादन कम कर देते हैं। लोगों को रोजगार से निकाल दिया जाता है। उनकी आय कम हो जाती है एवं बाजार की प्रभावशाली मांग और कम हो जाती है। उत्पादन के सभी साधनों की मांग कम हो जाती है। विनियोग में अत्यधिक ह्रास हो जाता है।

कृषक समुदाय पर भी मुद्रा संकुचन का बड़ा बुरा असर पड़ता है। कृषि पदार्थों की कीमतों में सर्वाधिक और शीघ्र कमी हो जाती है। मजदूरों को कुछ समय तक लाभ हो सकता है क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के रूप में अब उन्हें अधिक प्राप्त होता है परन्तु दीर्घकाल में जब उत्पादन ठप्प हो जाता है और मजदूर बेकार होने लगते हैं तब उनको सर्वाधिक सकट का सामना करना पड़ता है। व्याज और लगान से आय प्राप्त करने वालों को भी वर्तमान प्रसिद्धि से लाभ हो सकता है परन्तु उनका भविष्य भी समाप्त हो जाता है क्योंकि इसी दरें गिरने लगती हैं। उत्पादन के साधन के रूप में भूमि और पूंजी की मांग प्रायः समाप्त हो जाती है। सरकार के स्थायी कर्मचारियों को अवश्य अपेक्षाकृत अधिक समय तक लाभ होता है परन्तु जब उत्पादन अत्यन्त निम्नस्तर पर आ जाता है या कई चीजों का उत्पादन बन्द हो जाना है तो उन्हें भी अपने उपभोग को सीमित करना पड़ता है। आय होते हुए भी वे उसका उपभोग नहीं कर पाते। स्वयं सरकार को भी मुद्रा संकुचन की स्थिति कठिनाई में डाल देती है। सामान्य करों की वसूली भी कठिन हो जाती है तथा सरकार का व्यय चलाना दूसरे हो जाता है।

सत्ते में मुद्रा संकुचन की स्थिति का उद्योग, व्यापार, कृषि, निश्चित आय-वर्ग, मजदूर आदि सभी पर बुरा असर पड़ता है। अर्थ व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है।

नियंत्रण के उपाय (Measures of Control) —

1. सरकार के व्यय में वृद्धि—वास्तव में मुद्रा संकुचन की स्थिति में जनता की आय बहते-बहते कम हो जाती है और निजी क्षेत्र (Private Sector) जो लाभ के

उद्देश्य से कार्य करता है सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं से मुख मोड़ लेता है अतः सरकार को चाहिए कि नये-नये निर्माण कार्य प्रारम्भ करे जिससे लोगों को रोजगार मिले और उनकी आय बढ़े। लोगों की आय में वृद्धि होने से प्रभावशाली माग बढ़ेगी व्यक्तिगत क्षेत्र के उत्पादकों में भी आशा का संचार होगा और अर्थ-व्यवस्था पुनर्जागृत हो जायेगी। 1929 की महान आर्थिक मन्दी का सामना करने के लिए प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने न्यू डील (New Deal) की नीति में यही उपाय काम में लिया था।

2. करों में छूट—करों में छूट देकर पूंजी संचय और विनियोगों को बढ़ावा दिया जा सकता है। विनियोगों के प्रारम्भ होते ही रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होगी और अर्थ-व्यवस्था सुधरने लगेगी।

3. मौद्रिक नीति—चलन में मुद्रा एवं साख की मात्रा को बढ़ाने की नीति अपनाई जानी चाहिए। बैंक दर को कम करना, जनता से प्रतिभूतियों को परीदना आदि उपायों द्वारा बैंकों की साख निर्माण शक्ति को बढ़ाना चाहिए। जनता के हाथ में क्रयशक्ति के बढ़ते ही मूल्य-स्तर में वृद्धि प्रारम्भ हो जायेगी और अर्थ-व्यवस्था गतिशील हो जायेगी।

4. सरकार द्वारा अतिरिक्त माल की खरीद—उत्पादकों और व्यापारियों में विश्वास का संचार करने के लिए सरकार को उत्पादित माल को खरीद लेना चाहिए और इस प्रकार कृत्रिम माग की स्थिति बनाकर उन्हें विनियोग और रोजगार बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए जिससे कालान्तर में कृत्रिम माग वास्तविक माग का रूप ग्रहण कर ले।

5. निर्यात को प्रोत्साहन—सरकार एवं उत्पादकों को अन्य देशों में अपने माल की माग पैदा करनी चाहिए जिससे निर्यात को बढ़ाया जा सके और उत्पादन तथा रोजगार को बढ़ाया जा सके। इसके लिए सरकार द्वारा मौद्रिक सहायता तथा विदेशों में विज्ञापन पर अधिक जोर देना चाहिए।

मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन—तुलनात्मक दृष्टि

हमने मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन के प्रभावों का वृणन पिछले पृष्ठों में किया है। दोनों का ही अर्थ व्यवस्था पर विस्तृत प्रभाव पड़ता है। कभी-कभी यह प्रश्न उठता है कि इन दोनों स्थितियों में कौन उचित है और कौन बुरी है।

मुद्रास्फीति को पिछड़े देशों के विकास के लिए प्रायः अनिवार्य माना जाता है क्योंकि उन्हें विकास के लिए अधिक मात्रा में विनियोजन करना पड़ता है जिससे लोगों की आय में वृद्धि होती है परन्तु उत्पादन की मात्रा प्रारम्भ में उतनी नहीं बढ़ पाती। पिछड़े देशों में उपभोग चूक बिल्कुल निम्न स्तर पर होता है इसलिए बड़ी हुई आय को खर्च किया जाता है। इस क्रिया में डिमास्ट्रेशन प्रभाव (Demonstration Effect) भी अपना प्रभाव दिखाता है। इसलिए बचत विनियोग के बराबर नहीं हो

पाती। सरकार अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए घाटे के बजट का सहारा लेती है एवं विदेशों से ऋण लेती है। सबका प्रभाव स्फीतिक होता है। परन्तु इसका बड़ा लाभ देश के आर्थिक विकास के रूप में प्राप्त होता है। उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि होती है।

परन्तु इसकी हानि यह है कि आय का बटवारा न्यायोचित उग से नहीं होता। लाभ केवल एक सीमित वर्ग में बट जाता है। सामान्य जनता का वास्तविक उपभोग कम हो जाता है उसे हमेशा आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गरीब और अमीर के बीच की दूरी निरन्तर बढ़ती जाती है। इसलिए प्रो० बकील ने कहा है -

“Inflation may be compared to robbery Both deprive the victim of some possession with the difference that the robber is visible, inflation is invisible, the robber's victim may be one or few at a time, the victims of inflation are the whole nation, the robber may be dragged to a court of law, inflation is legal”

वास्तव में मुद्रा स्फीति मध्यम वर्ग के लिए एक अभिशाप बन जाती है क्योंकि उनका जीवन निर्वाह व्यय (Cost of Living) आय की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाता है। बचन समाप्त हो जाती है। उनमें घोर निराशा व्याप्त हो जाती है। यही नहीं यदि मुद्रास्फीति की मात्रा अधिक बढ़ जाती है और यह कूदती हुए तथा अति-स्फीति का रूप ग्रहण कर लेती है तो सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाती है तथा सामाजिक विघटन को जन्म देती है। जर्मनी इस बात का प्रमाण है यही नहीं मुद्रा-स्फीति मदी को भी जन्म दे सकती है। व्हीटिलसे, फ्रीडमैन तथा हरमन के शब्दों में -

“The distortion of the pattern of industrial production that occurs in a period of inflation may also contribute to the post inflation deflation and depression”

दूसरी ओर मुद्रा संकुचन की स्थिति है जिससे कुछ निश्चित आय वाले को प्रारम्भ में लाभ होता है क्योंकि उनकी वास्तविक आय और उपभोग पहले की अपेक्षा अधिक हो जाता है। परन्तु अधिकांश लोगों को हानि होती है। विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है क्योंकि कीमतों के कम होने से उत्पादकों को हानि होती है विनियोग करने का उत्साह समाप्त हो जाता है। लोगों को रोजगार से अलग होना पड़ता है। बेरोजगारी निरन्तर बढ़ती जाती है। उत्पादन निम्नतम स्तर पर पहुँच जाता है। सरकार को भी अपना व्यय चलाने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अन्त में निश्चित आय वर्ग भी उपभोग से वंचित रहने लगता है। बैंक-व्यवस्था फेल होने लगती है। चारों तरफ निराशा और मदी का वातावरण छाया रहता है। आर्थिक गतिविधियाँ समाप्त प्राय हो जाती हैं।

स्पष्ट है कि दोनों ही स्थितियाँ समाज के लिए भयंकर स्थिति पैदा करती हैं परन्तु मुद्रा स्फीति में जीवन है और मुद्रा संकुचन में मूर्दानगी। एक आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है दूसरा इसे अवरुद्ध करता है। एक आय के वितरण में अन्याय करता है तो दूसरा आय को समाप्त कर देता है। वास्तव में देश की आर्थिक एवं भौतिक नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे देश का आर्थिक विकास होना रहे तथा अर्थ व्यवस्था में उथल-पुथल भी न हो। परन्तु इन दोनों में एक के चुनाव का प्रश्न यदि आ ही जाय तो मुद्रा स्फीति निश्चित ही मुद्रा संकुचन से अच्छी स्थिति है। अपस्फीति या मुद्रा संकुचन चुनने का तात्पर्य बेरोजगारी तथा उत्पादन एवं आय की समाप्ति है। मुद्रा स्फीति चुनने से रोजगार नो मिलता है, आय तो जानी है मूल ही वास्तविक आय कम हो। उत्पादन तो होता है चाहे जिस चीन का हा। यदि अनुत्पाद कार्य भी हो तो भी बेकार रहने से अच्छा है क्योंकि बेकार रहकर व्यक्ति सामाजिक शांति के लिए खतरा पैदा कर सकता है। हा यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि मुद्रा अस्फीति का रूप न ले। इस सम्बन्ध में लाड किन्स ने भी कहा है कि "Inflation is unjust and deflation is inexpedient of the two, perhaps deflation is worse"

सस्फीति (Reflation)

मुद्रा-संकुचन के कारण जब आर्थिक मंदी छा जाती है और कीमत तल असामान्य रूप से नीचे गिर जाता है तथा उत्पादन और रोजगार बहुत ही कम हो जाता है तो अर्थ व्यवस्था को पुन सुधारने (Recovery) के उद्देश्य से मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि की जाती है जिससे कीमत स्तर में सामान्य स्तर तक पहुँचन की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। कीमत वृद्धि की इस प्रवृत्ति को सस्फीति (Reflation) कहा जाता है। इससे उत्पादन रोजगार तथा आय में वृद्धि होने लगती है और व्यापारिक मंदी दूर होने लगती है। अर्थ व्यवस्था साम्बन्धिता की धार अग्रसर होने लगती है और अन्ततः उत्पादन के समस्त साधनों का उत्पादन क्रिया में प्रयोग होने लगता है। इस अवस्था में जिस प्रकार कीमतों में वृद्धि होती है उसी प्रकार उत्पादन तथा आय में भी वृद्धि होती है। स्फीति में भी कीमतों तथा उत्पादन एवं आय आदि में वृद्धि होनी है परन्तु वह सस्फीति से भिन्न है क्योंकि स्फीति में कीमत वृद्धि आय की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से होती है। इसी प्रकार सस्फीति का प्रारम्भिक जान बूझकर अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने के लिए किया जाता है परन्तु स्फीति परिस्थितिवश सस्फीति की स्थिति के बाद प्रारम्भ होती है। मुद्रा सस्फीति का अर्थ व्यवस्था पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और देश की क्रियाहीन अर्थ व्यवस्था पुन क्रियाशील होकर विकास के पथ पर अग्रसर होती है।

विस्फीति (Disinflation)

जिस प्रकार कीमत-स्तर के असामान्य रूप से नीचे गिर जाने पर उसे सामान्य स्तर पर लाने की प्रक्रिया सस्फीति कही जाती है उसी प्रकार जब कीमत स्तर असाधारण रूप से अधिक हो जाता है तो जानबूझ कर कीमतों को गिराकर सामान्य स्तर पर लाने की प्रक्रिया को विस्फीति कहते हैं। ऐसा करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि कीमतों की अत्याधिक वृद्धि का अर्थ व्यवस्था पर बड़ा नयानक प्रभाव हो सकता है। इसलिए उसके दुष्परिणामों से बचने का प्रयत्न किया जाता है। इसके लिए जनता की प्रमादशाली माग को कम करने की आवश्यकता होती है, जो चलन में मुद्रा एव सात्व की मात्रा को कम करने से सम्भव है। मुद्रा सकुचन की स्थिति में भी कीमत स्तर गिरता है परन्तु वह स्फीति से भिन्न है क्योंकि विस्फीति में सामान्य रूप से ऊँची कीमतों को सामान्य स्तर पर गिराया जाता है लेकिन सकुचन की स्थिति में कीमत स्तर सामान्य स्तर से नीचे गिरता चला जाता है और असाधारण रूप से नीचे गिर जाता है जिससे बेरोजगारी अत्यधिक बढ़ जाती है। आय और उत्पादन निम्नतम बिन्दु पर पहुँच जाते हैं। विस्फीति से अर्थ-व्यवस्था सामान्य हो जाती है परन्तु सकुचन से मदी का वातावरण बन जाता है।

मुद्रा मूल्य का स्थायित्व (Stable Value of Money)

मुद्रा-मूल्य के घटने-बढ़ने या कीमत स्तर के बढ़ने-घटने का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका आभास मुद्रा स्फीति एव मुद्रा सकुचन के अध्ययन से मिलता है। किस प्रकार अर्थ व्यवस्था विभ्रत खलित होती है और जनता को किन दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो चुका है। इसलिए अर्थशास्त्रियों का मत है कि आर्थिक उन्नति के दृष्टिकोण से मौद्रिक नीति का लक्ष्य मूल्य-स्थायित्व होना चाहिए। समय और परिस्थितियों के अनुसार "मूल्य स्थायित्व" का अर्थ भी कुछ परिवर्तित हुआ है। 1930 के पूर्व स्थायित्व का अन्तर्गत (1) ऋय शक्ति की स्थिरता (2) विनिमय दर की स्थिरता और (3) स्वर्ण परिवर्तनशीलता की स्थिरता को शामिल किया जाता था। परन्तु वर्तमान समय में स्थायित्व के अन्तर्गत पूर्ण वृत्ति तथा अधिकतम विकास के लक्ष्य, ऋयशक्ति का स्थायित्व एव भुगतान श्रेय की साम्यवस्था शामिल है। स्पष्ट है कि अब स्थायित्व की नीति का तात्पर्य केवल मौद्रिक इकाई के मूल्य के स्थायित्व तक ही सीमित नहीं है बल्कि अब इसका सम्बन्ध पूर्ण अर्थ व्यवस्था से है। अब मौद्रिक इकाई के मूल्य को नियन्त्रित करने का ही प्रश्न नहीं है बरन् सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था और आर्थिक क्रियाओं को नियन्त्रित करना है।

उपरोक्त सभी मौद्रिक उद्देश्य स्वयं में वाछनीय हैं परन्तु यदि इन्हें ध्यान से देखा जाय तो वे परस्पर विरोधी भी हैं। यदि कीमत को स्थिर रखने का प्रयत्न किया जाय तो पूर्ण वृत्ति और आर्थिक विकास का लक्ष्य सम्भवतः पूरा नहीं होगा। इसलिए इन विभिन्न उद्देश्यों को उनकी प्राथमिकता और सीमाओं को ध्यान में रखकर मौद्रिक नीति निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। कीमत-स्तर में अग्रर साधारण घट बढ़ होती है जिसका दीर्घकालीन महत्व नहीं है तो वह मूल्य स्थायित्व की सीमा के अन्दर है। प्रश्न अल्पकाल में होने वाले सामान्य परिवर्तनों का नहीं बरन् दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता और विकास क्रिया को जारी रखने का है या विकास को कायम रखने (To sustain growth) का है। यदि इन लक्ष्यों का ध्यान में रखकर मौद्रिक नीति अपनाई गई तो पूंजी निर्माण, बचत एवं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। किसी भी वर्ग को कठिनाई का सामना नहीं करना होगा। जनता का अर्थ व्यवस्था में पूर्ण विश्वास होगा। विज्ञान और तकनीकी विकास की प्रगति अवरूद्ध नहीं होगी। निरन्तर अनुसन्धान और अभिनवीकरण होता रहेगा। आर्थिक शान्ति होने के कारण सामाजिक और राजनैतिक स्थिरता एवं शान्ति को बनाए रखना आसान होगा।

प्रायः स्थायित्व की नीति मौद्रिक एवं वित्तीय साधनों तथा ऋण व्यवस्था एवं प्रत्यक्ष नियन्त्रणों (Direct control) द्वारा व्यवहार में लाई जाती है। विभिन्न देशों में तथा विभिन्न परिस्थितियों में इन उपायों में किसी पर विशेष जोर दिया जाता है और किसी पर अपेक्षाकृत उमसे कम। किम माधन विशेष पर अधिक जोर दिया जाय इस बात का निर्णय वहाँ की राजनैतिक और आर्थिक परिस्थितियों और वातावरण पर निर्भर करता है और इनमें होने वाले परिवर्तनों के अनुसार बदलता रहता है। मौद्रिक साधनों में उन नियन्त्रणों को शामिल किया जाता है जो अर्थ व्यवस्था को मुद्रा की मात्रा एवं प्रयोग के माध्यम से प्रभावित करने हैं। वित्तीय नियन्त्रणों के अन्तर्गत वे उपाय आते हैं जो सरकार की आय और व्यय को परिवर्तित करते हैं तथा इस प्रकार जनता की निर्वर्त्य आय (Disposable Income) तथा व्यय को प्रभावित करते हैं। ऋण व्यवस्था द्वारा सरकार कुल मांग को प्रभावित करती है तथा प्रत्यक्ष नियन्त्रण द्वारा विभिन्न आर्थिक क्रियाओं की सीमा निर्धारित की जाती है। यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि वे सभी उपाय जिनसे कुल व्यय की मात्रा प्रभावित होती है “स्थायित्व” तथा अस्थायित्व दोनों ही प्रकार का प्रभाव डाल सकते हैं तथा अर्थ व्यवस्था के विकास को बढ़ावा भी दे सकते हैं तथा अवरूद्ध भी कर सकते हैं क्योंकि नीति निर्धारण एवं नियन्त्रण तथा उनके प्रभाव के बीच काफी समबन्ध होता है। नीति हमेशा मन्दिप्य की परिस्थितियों के सम्पर्क में आती है जिनका केवल अनुमान लगाया जा सकता है।

इसलिए उद्देश्यों की प्राथमिकता का निर्धारण एव तदनुसृत नीति और साधनों की प्राथमिकता निश्चित करना कठिन कार्य है। परन्तु यदि उचित सावधानी एव दूरदर्शिता से कार्य किया जाय तो निश्चय ही स्थायित्व की नीति अर्थ व्यवस्था को मूल्य के उतार-चढ़ाव के दुष्परिणामों से बचाकर उन्नति के पथ पर अग्रसर करेगी या कायम रहेगी।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके सकेत

(1) अपने देश में द्वितीय महायुद्ध के समय तथा उसके बाद हुए मुद्रा प्रसार के कारणों का विवेचन कीजिए तथा उसके नियन्त्रण के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का वर्णन कीजिए।

(राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल, 1962)

(आगरा 1659)

[सकेत—प्रथम भाग में द्वितीय महायुद्ध काल तथा उसके बाद के समय हुई मुद्रा स्फीतियों के कारणों की व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में स्फीति-नियन्त्रण के लिए प्रयुक्त उपायों का वर्णन कीजिए।]

(2) मुद्रा स्फीति किसे कहते हैं और इसके कारण क्या होते हैं? भारत-वर्ष में युद्धकालीन तथा युद्धोत्तर कालीन मुद्रा स्फीति के समाज की विभिन्न श्रेणियों पर प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

(राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल, 1966)

[सकेत—प्रथम भाग में मुद्रा स्फीति की परिभाषायें देते हुए उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। दूसरे भाग में मुद्रा-स्फीति के कारण बताइये। तीसरे भाग में युद्धकालीन तथा युद्धोत्तरकालीन मुद्रा स्फीति के भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव बताइये।]

(3) निम्नलिखितों की परिभाषा कीजिए—(क) मुद्रा स्फीति (ख) मुद्रा विस्फीति (ग) मुद्रा अपस्फीतिकरण तथा (घ) अवमूल्यन। उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिनमें इन्हें उचित ठहराया जा सके।

(राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल, 1967)

[सकेत—विभिन्न शब्दों की परिभाषायें देते हुए अर्थ स्पष्ट कीजिए। साथ-साथ यह भी बताते चलिए कि किन परिस्थितियों में इन्हें उचित ठहराया जा सकता है।]

(4) “मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है तथा मुद्रा सकुचन अनुपयुक्त। इन दोनों में शायद मुद्रा सकुचन अधिक बुरा है।” (प्रो० कीन्स) विवेचना कीजिए।

(सागर 1968, गोरखपुर 1959)

[संकेत—प्रथम भाग में मुद्रा प्रसार के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करते हुए सिद्ध कीजिए कि मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है क्योंकि इससे कुछ वर्गों को हानि तथा कुछ वर्गों को लाभ हो जाता है। दूसरे भाग में मुद्रा सकुचन के समाज पर प्रभावों की विवेचना करते हुए बताइये कि मुद्रा सकुचन अनुपयुक्त है क्योंकि इससे व्यापार-उद्योग में मन्दी तथा बेरोजगारी फैलती है जो देश के लिए उपयुक्त नहीं। तीसरे भाग में दोनों के प्रभावों के सन्दर्भ में यह उपसंहार दीजिए कि दोनों बुरे हैं और उनमें चुनाव का कोई प्रश्न नहीं। परन्तु दोनों बुराइयों में मुद्रा प्रसार की तुलना में सकुचन अधिक बुरा है।

(5) मुद्रा-मूल्य के उच्चावचनो का प्रभाव देश के विभिन्न वर्गों पर क्या होता है ? समझाकर लिखिए। (आगरा 1968)

[संकेत—मुद्रा प्रसार तथा मुद्रा सकुचन होने पर समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले प्रभाव का ध्योरेवार विवेचन कीजिए।]

भाग २

Part Two

“Credit is the oil of the wheel, the marrow of the bones, the blood in the veins and the spirits in the breast of all trade and commerce of the world”

—Defoe

साख तथा अधिकोषण
(Credit and Banking)

साख तथा साख पत्र (Credit and Credit Instruments)

“Credit has done more—a thousand times more—to enrich nations than all mines of the world It has excited labour, stimulated manufactures, pushed commerce on every sea, and brought every nation, every kingdom and every small tribe among the races of men to be known to all the rest ”

Daniel Webster

आधुनिक व्यापार उद्योग तथा वाणिज्य में साख का महत्वपूर्ण स्थान है। साख के महत्व के कारण में कथन प्रचलित हैं ‘आधुनिक औद्योगिक समाज एक साख समाज है’, ‘साख औद्योगिक व्यवस्था का हृदय तथा महत्वपूर्ण भाग है,’ तथा ‘साख वाणिज्य तथा उद्योग का जीवन रक्त है’¹। साख की प्रकृति तथा आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में उसकी इतनी महत्वपूर्ण स्थिति का क्या कारण है, यही इस अध्याय का विषय है।

साख की परिभाषा (Definition of Credit)

अंग्रेजी के ‘क्रेडिट’ शब्द का उदय लैटिन के ‘क्रेडो’ (Credo) शब्द से हुआ है जिसका अर्थ होता है ‘मैं विश्वास करता हूँ’ (I believe)। सरल व्यापारिक अर्थों में साख का तात्पर्य होता है ‘वर्तमान में कुछ लेना और बाद में भुगतान करना’। साख उधार लेने का पर्यायवाची बन गया है। उधार वस्तु भी ली जा सकती है और कोष भी।

विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने साख की परिभाषा विभिन्न प्रकार से की है। स्टैनली जेवन्स के शब्दों में “साख का अर्थ भुगतान को स्थगित करना है।”² जीड के अनुसार यह एक ऐसा विनिमय कार्य है जो कुछ समय भुगतान करने पर पूरा

¹ ‘Modern industrial society is a credit society’

‘Credit is the heart and core of the industrial system’

‘Credit is the life blood of commerce and industry’

² “Credit means postponement of payment” —Stanley Jevons

हो जाता है।”¹ इन दोनों परिभाषाओं में भुगतान का स्थगन साख का सार माना गया है।

प्रो० जी० डी० एच० कोल के शब्दों में “साख वह क्रयशक्ति है जो आय से प्राप्त नहीं होती बल्कि जिसे वित्त सस्थायें बैंकों में जमाकर्त्ताओं द्वारा रक्खी गई निष्क्रिय आयों के उत्पादन के रूप में अथवा क्रय-शक्ति की कुल राशि में शुद्ध वृद्धि के रूप में उत्पन्न करती है।”² प्रो० टामस ने साख की परिभाषा इस प्रकार दी है “साख शब्द का अभिप्राय किसी व्यक्ति की शोधन क्षमता तथा देनदारी के प्रति एक ऐसे विश्वास से होता है जिसके कारण उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की बहुमूल्य वस्तु मीपी जा सके चाहे यह बहुमूल्य वस्तु मुद्रा हो, अन्य वस्तुयें या सेवायें हों या स्वयं भाख हो जैसे उस दशा में जबकि एक व्यक्ति दूसरे को अपनी व्यावसायिक स्याति या अपने नाम के उपयोग का अधिकार देता है।”³ प्रो० टामस ने एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को बहुमूल्य वस्तु सौंपते समय उसमें विश्वास को साख का आधार माना है। किन्से के शब्दों में “साख से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस शक्ति में है जिससे वह अन्य व्यक्ति को भविष्य में भुगतान की प्रतिज्ञा के आधार पर अपनी आर्थिक वस्तुयें प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है।”⁴ इसी प्रकार हेन्स के अनुसार ‘भविष्य में भुगतान की प्रतिज्ञा के आधार पर वर्तमान में कोई भी मूल्यवान वस्तु जैसे मुद्रा, वस्तुयें या सेवायें प्राप्त करना ही साख है।’⁵

¹ “It is an exchange which is complete after the expiry of a certain period of time after payment.” —Gide

² “It is purchasing power not derived from income, but created by financial institutions either as an offset to idle incomes held by depositors in the banks or as a net addition to the total amount of purchasing power.”

—G. D. H. Cole : *Money, Its Present and Future*, p. 308

³ “The term credit is now applied to that belief in a man's probity and solvency which will permit of his being entrusted with something of value belonging to another whether that something consists of money, goods, services or even credit itself as when one man entrusts to another the use of his good name and reputation.”

—S. E. Thomas *Elements of Economics* p. 398.

⁴ “By credit we mean the power which one person has to induce another to put economic goods at his disposal for a time on promise of future payments.” —David Kinley. *Money*, p. 190

⁵ “Credit is the present acquisition of anything of value (money, commodities or services) in exchange for a promise to return an equivalent at some future time.”

—W. W. Haines : *Money, Prices and Politics*, p. 231.

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि साख एक ऐसी विनिमय क्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे को इस विश्वास पर मुद्रा या वस्तुयें देता है कि वह भविष्य में उसे लौटा देगा।

साख तथा साख-पत्र में अंतर (Difference between Credit and Credit Instruments) - साख का स्पष्ट रूप से आशय समझने के लिए साख तथा साख पत्रों में अंतर समझना आवश्यक है। साख उधार देने की प्रक्रिया है जिसमें भुगतान को स्थगित किया जाता है परन्तु साख-पत्र उन साख प्रक्रियाओं अर्थात् भविष्य में भुगतान करने के समझौते का लिखित रूप है।¹

साख के आधार (Bases of Credit)

साख के आधारों या साख के आवश्यक तत्वों के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। कुछ लेखकों ने विश्वास को साख का आधार माना है। कुछ सम्पत्ति को साख का आधार मानते हैं। कुछ विद्वान् चरित्र को और कुछ चरित्र, पूंजी तथा क्षमता (Character, Capital and Capacity) या मनुष्य तथा साधन (Man and Means) या विश्वास तथा साधन (Reliability and Resources) को साख का आवश्यक तत्व मानते हैं। साख के निम्नलिखित आवश्यक तत्व विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं —

1. विश्वास (Confidence) : साख का सबसे महत्वपूर्ण आधार विश्वास है। यदि ऋणदाता का ऋणी पर विश्वास न हो तो वह कभी भी उसे ऋण नहीं देगा। यह विश्वास ऋणी की आर्थिक स्थिति तथा उसके व्यवहार पर निर्भर करता है।

2. चरित्र (Character) साख मिलने में चरित्र एक महत्वपूर्ण तत्व है। यदि किसी व्यक्ति ने भूतकाल में ऐसा व्यवहार किया है कि उसकी ख्याति नहीं रही तो उसे उधार नहीं मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति ईमानदार तथा सच्चा है और निश्चित समय पर अपने ऋणों का भुगतान करता है तो उसे आसानी से उधार मिल जायेगा।

3. क्षमता (Capacity) . किसी व्यक्ति को साख उसकी चुकाने की क्षमता (Capacity to repay) पर निर्भर करनी है। ऋणदाता किसी व्यक्ति को तभी उधार देता है जब उसे विश्वास होता है कि वह व्यक्ति उधार सी हुई राशि चुकाने की क्षमता रखता है।

4. पूंजी तथा सम्पत्ति (Capital and Property) : किसी व्यक्ति को उधार देते समय ऋणदाता उसकी पूंजी तथा सम्पत्ति का भी विचार करता है।

¹ Credit is a lending operation involving a postponed payment, credit instruments, on the other hand, are written evidences of antecedent credit operations, that is, of agreements to pay at some future date.

वैक ऋण देते समय व्यक्ति की साख का अनुमान उसकी पूँजी तथा सम्पत्ति के आधार पर ही लगात हैं। अधिक पूँजी तथा सम्पत्ति के स्वामी को ऋण मिलने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती।

5 प्रतिभूतियों तथा आदेयों की तरलता (Securities and Liquidity) - ऋण प्राप्त करन के लिए केवल पूँजी तथा सम्पत्ति की आवश्यकता नहीं पडती बरन् अतिरिक्त जमानत की आवश्यकता पडती है। अचल सम्पत्ति को शीघ्र बेचा नहीं जा सकता अतः ऐस ऋणियों की साख कम होती है। प्रतिभूतियों तथा अन्य तरल जमानतों वाले ऋणों की साख अधिक होती है क्योंकि इनको शीघ्र ही बाजार में बेचा जा सकता है।

6 साख की मात्रा तथा समय (Limit and time) किसी व्यक्ति को उधार देते समय ऋण की राशि तथा उसकी अवधि पर भी ध्यान देना होता है। कम राशि तथा अल्पावधि के लिए साख आसानी से प्राप्त हो जाती है परन्तु दीर्घ कालीन तथा अधिक राशि के ऋण कठिनाई से प्राप्त होते हैं।

मौल्टन ने साख को प्रभावित करन वाले तत्वों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है।¹

¹ Pertaining to man	Pertaining to the Business
1 Record for honest dealing	1 Ratio of quick assets to current liabilities
2 Personal attributes	2 Amount of capital invested and property owned
(i) Gambling or drinking tendencies	3 Earnings of the business
(ii) Political and other "out side" activities	4 Character and turnover of stock
(iii) Style of living, including wife's ambitions	5 Location of business
3 Ability	6 Character of business organisation
(i) Common sense and shrewdness	7 Insurance carried
(ii) Education and training	8 Nature and intensity of the competition
(iii) Age and general experience	
(iv) Success already attained	

—Harold G Moulton *Financial Organisation and Economic System*, p 102

व्यक्ति से सम्बन्धित

1. भूतकाल में ईमानदारी का व्यवहार
2. व्यक्तिगत गुण—
 - (i) जुझा तथा शराब पीने की प्रवृत्तियाँ
 - (ii) राजनीतिक तथा अन्य 'बाहरी' व्यवहार
 - (iii) रहन-सहन का ढंग
3. योग्यता—
 - (i) साधारण बुद्धि तथा होशियारी
 - (ii) शिक्षा तथा प्रशिक्षण
 - (iii) आयु तथा सामान्य अनुभव
 - (iv) प्राप्त सफलता

व्यापार से सम्बन्धित

1. वर्तमान देनदारियों तथा लेनदारियों का अनुपात
2. द्विनियोजित पूँजी तथा सम्पत्ति
3. व्यापार से आय
4. स्टॉक की प्रकृति तथा बिक्री
5. व्यापार का स्थान
6. व्यापारिक संगठन का प्रकार
7. बीमा
8. प्रतिस्पर्धा की प्रकृति तथा मात्रा

व्यक्ति तथा व्यापार से सम्बन्धित उपरोक्त तत्वों का अध्ययन कर साख की मात्रा का निर्णय किया जा सकता है। साख देते समय ऋणदाता को (1) ऋणी की चुकाने की क्षमता (Ability of the borrower to pay as promised) तथा (2) चुकाने की इच्छा (Willingness and intention to pay) में विश्वास होना चाहिए। पहली बात का सम्बन्ध सम्पत्ति तथा व्यापारिक योग्यता से है तथा दूसरी बात का सम्बन्ध ईमानदारी तथा व्यापारिक नैतिकता (Honesty and Business Integrity) से है। साख का आधार इस प्रकार समझाया जा सकता है:—

- साख—विश्वास—
- (1) व्यक्ति का चरित्र
(चुकाने की इच्छा)
 - (2) व्यापार की स्थिति
(चुकाने की योग्यता)

साख का वर्गीकरण

(Classification of Credit)

साख का कई दृष्टिकोणों से वर्गीकरण किया गया है। कुछ मुख्य वर्गीकरण इस प्रकार है —

(अ) साख देने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं के दृष्टिकोण से वर्गीकरण (Classification from the point of view of the institutions and individuals utilising Credit)—साख का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं की दृष्टि से साख प्रक्रियाओं को कई भागों में बाटा गया है— (1) सार्वजनिक साख (Public Credit) (2) पूँजी साख या औद्योगिक साख (Capital Credit or Industrial Credit) (3) व्यावसायिक साख (Mercantile Credit) (4) व्यक्तिगत साख (Individual or Personal Credit) तथा (5) बैंकिंग साख (Banking Credit)

1 **सार्वजनिक साख (Public Credit)**—केन्द्रीय, राज्य तथा स्वायत्त सरकारों द्वारा ऋण लेने को सार्वजनिक साख कहते हैं। सार्वजनिक साख का प्रयोग अल्पकाल या दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं के लिए हो सकता है।

2 **पूंजी साख या औद्योगिक साख (Capital Credit or Industrial Credit)**—उत्पादक तथा निर्माण कार्य में लगी सस्याओं द्वारा जो ऋण लिए जाते हैं उन्हें पूंजी साख या औद्योगिक साख कहते हैं। यहाँ तक कि मयुक्त पूंजी कम्पनियों के अग्रधारी भी एक अर्थ में कम्पनी के ऋणदाता हैं जो लामाश के रूप में प्रतिफल प्राप्त करते हैं। साझेदारी फर्मों द्वारा प्राप्त साख को इस श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाता।

3. **व्यावसायिक साख (Mercantile Credit)**—शोक तथा फुटकर व्यापारियों, कमीशन एजेंटों के द्वारा माल को उत्पादक से अन्तिम उपभोक्ता तक पहुँचाने के उद्देश्य से लिए गये ऋणों का व्यावसायिक साख कहते हैं। कमी-कमी इसे वाणिज्यिक साख (Commercial Credit) भी कहा जाता है।

4 **व्यक्तिगत साख (Individual or Personal Credit)**—व्यक्तियों द्वारा उपभोग्य पदार्थों को खरीदने के लिए या सकटकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋणों को व्यक्तिगत साख या उपभोक्ता साख कहते हैं।

5 **बैंकिंग साख (Banking Credit)**—बैंकिंग साख से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा बैंक जमाकर्ताओं से निक्षेप आकर्षित करती हैं और फिर उस राशि को उधार देती हैं।

(ब) ऋण राशि के प्रयोग की प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण (Classification according to the nature of the use to which the funds borrowed are devoted)—साख के प्रयोग के अनुसार साख को तीन भागों में बाँटा जाता है—(1) विनियोग साख (Investment Credit) (2) वाणिज्यिक साख (Commercial Credit) तथा (3) उपभोग-साख (Consumptive Credit)।

1. **विनियोग-साख (Investment Credit)**—रेलो, सड़को, कारखानों, खानों इत्यादि के विकास के लिए जो पूंजी उधार ली जाती है, विनियोग साख कहलाती है। इस साख का प्रयोग स्थायी पूंजी (Fixed Capital) की आवश्यकता पूर्ति के लिए होता है।

2. **वाणिज्यिक साख (Commercial Credit)**—वस्तुओं के उत्पादन तथा विपणन की वित्त-व्यवस्था करने के लिए प्राप्त ऋणों को वाणिज्यिक साख (Commercial Credit) कहते हैं। वाणिज्यिक साख का प्रयोग कार्यशील पूंजी (Working Capital) जुटाने के लिए होता है। ऋणी इस प्रकार की साख को अल्प काल में ही चुका देता है।

3. उपभोग-साख (Consumptive Credit)—उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकतायें सन्तुष्ट करने के लिए जो ऋण स्वीकृत किए जाते हैं या वस्तुयें उधार देची जाती हैं उनको उपभोग-साख कहते हैं। निश्चिन अवधि के बाद भुगतान इसलिए नहीं कर दिया जाता कि ऋण का उपयोग उत्पादक कार्यों के लिए हुआ है बल्कि इसलिए कि ऋणी के आय के अन्य स्रोत हैं। इसीलिए विनियोग या वाणिज्यिक साख की तुलना में उपभोग-साख में जोखिम अधिक रहती है।

(स) ऋण की अवधि के अनुसार वर्गीकरण (Classification according to Usance)—अवधि के अनुसार साख को तीन भागों में बाटा जाता है —

(1) मांग ऋण (Demand Loans) (2) अल्पकालीन ऋण (Short Period Loans) (3) मध्यकालीन ऋण (Medium term Loans) तथा (4) दीर्घकालीन ऋण (Long Period Loans)

1. मांग ऋण (Demand Loans)—जो ऋण अति अल्पकाल के लिए दिए जाते हैं और जिनका भुगतान ऋणदाता द्वारा मांग करने पर तत्काल करना पडता है, मांग ऋण कहलाते हैं।

2. अल्पकालीन ऋण (Short Period Loans) — एक वर्ष तक की अवधि के ऋण अल्पकालीन ऋण कहलाते हैं।

3. मध्यकालीन ऋण (Medium term Loans)—जो ऋण एक वर्ष से अधिक और पाच वर्ष से कम अवधि के लिए दिए जाते हैं, मध्यकालीन ऋण कहलाते हैं।

4. दीर्घकालीन ऋण (Long term Loans)—पाच वर्ष से अधिक अवधि के लिए जो ऋण प्राप्त किए जाते हैं दीर्घकालीन ऋण कहलाते हैं।

(द) धरोहर के अनुसार वर्गीकरण (Classification according to Security) — ऋण देते समय रखी गई जमानत या धरोहर के आधार पर साख को निम्नलिखित भागों में बाटा जाता है .—

1. पूर्ण सुरक्षित ऋण (Fully Secured Loans) — जिन ऋणों के पीछे पर्याप्त मूल्य की जमानत रखी जाती है जिससे ऋण न चुकाने पर ऋणदाता जमानत को धेचकर अपने ऋण की रकम अदा कर ले, पूर्ण सुरक्षित ऋण कहलाते हैं। इस प्रकार के ऋण अपरिचित व्यक्तियों या जोखिम वाले कार्यों के लिए दिए जाते हैं।

2. असुरक्षित ऋण (Unsecured Loans)—जो ऋण बिना किसी जमानत के ऋणी की व्यक्तिगत जमानत पर दिए जाते हैं, असुरक्षित ऋण कहलाते हैं। इस प्रकार के ऋण ऐसे व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो परिचित होते हैं और जिनकी साव बाजार में बहुत अच्छी होती है।

3. अंशतः सुरक्षित ऋण (Partly Secured Loans)—जब ऋण की रकम से कम सम्पत्ति जमानत के रूप में रखी जाती है ता उसे अंशतः सुरक्षित ऋण कहा जाता है ।

क्या साख पूंजी है ? (Is Credit Capital ?)

साख पूंजी है या नहीं, इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है । मेकलियोड के अनुसार साख पूंजी है । उनका विचार है कि “मुद्रा और साख दोनों ही पूंजी हैं । व्यापारिक साख व्यापारिक पूंजी है ।”¹ इस विचार के पीछे यह धारणा है कि मुद्रा की तरह साख भी व्यापारिक क्रियाओं में माध्यम का कार्य करती है और इसलिए पूंजी की तरह साख भी उत्पत्ति का एक पृथक साधन है । परन्तु मेकलियोड का यह विचार भ्रमपूर्ण है । आलोचकों के अनुसार साख के द्वारा केवल साधनों का हस्तान्तरण होता है । साख उत्पत्ति का एक साधन न होकर श्रम विभाजन की तरह एक विधि (Method) मात्र है जिसकी सहायता से साधनों की उपयोगिता में वृद्धि की जाती है । साख न तो पूंजी है और न पूंजी के निर्माण में ही सहायक होती है । इसीलिए रिकार्डो तथा मिल ने मेकलियोड के विचार का खण्डन किया है । रिकार्डो के अनुसार “साख पूंजी का सृजन नहीं करती वरन् यह केवल इतना निश्चित करती है कि पूंजी का उपयोग किसके द्वारा हो ।”² साख तो पूंजी को ऐसे व्यक्तियों को हस्तान्तरित कर देती है जो पूंजी का सबसे लाभकारी प्रयोग करने में समर्थ हैं । साख की सहायता से पूंजी सबसे आवश्यक उत्पादन कार्यों में लग जाती है । साख तो केवल साधन है, साध्य नहीं । साख की सहायता से पूंजी प्राप्त की जा सकती है, साख स्वयं पूंजी नहीं है । इस मत की पुष्टि प्रो० जे० एस० मिल ने भी इन शब्दों में की है “केवल मात्र ऋण देने से ही नयी पूंजी का सृजन नहीं हो जाता, इससे तो केवल ऋणदाता के पास की पूंजी का ऋणी की हस्तान्तरण होता है । साख तो केवल हमारे व्यक्ति की पूंजी का प्रयोग करने का अधिकार है, इससे उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि नहीं की जा सकती बल्कि इनका केवल हस्तान्तरण ही होता है ।”³

¹ “Money and credit are both capital. Mercantile credit is mercantile capital.”—Macleod : *Elements of Banking*, Chap IV

² “Credit does not create capital, it only determines by whom capital should be employed”

—Ricardo : *Principles of Political Economy and Taxation*.

³ “New capital is not credit by the mere fact of lending, only the capital that was in the hands of the lender is now transferred to the hands of the borrower, credit being only the permission to use the capital of another person; the means of production cannot be increased by it but only be transferred.”

—J. S. Mill : *Principles of Political Economy*.

रिकार्डों तथा मिल के विचार अधिक उपयुक्त प्रतीत होते हैं। वास्तव में साख पूँजी नहीं है, केवल पूँजी को गतिशीलता प्रदान करने का साधन मात्र है।

साख की उपयोगिता तथा महत्व (Utility and Importance of Credit)

आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में साख के महत्व के सम्बन्ध में जितना कहा जाय, थोड़ा है। साख के बिना आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आज की व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण कारण साख रही है। इसीलिए साख को औद्योगिक व्यवस्था का हृदय तथा धारिण्य और उद्योग का जीवन-रक्त कहा गया है। आधुनिक समाज की साख ने विभिन्न प्रकार से सेवायें की हैं। साख की उपयोगिता तथा महत्व का अनुमान साख के निम्नलिखित कार्यों से लगाया जा सकता है

(1) सकट के समय सरकार को धन प्राप्त (Enables Government to obtain funds to meet emergencies) : युद्ध तथा अन्य सकट कालों में सरकारें अपनी आवश्यकतायें पूर्ण करने के लिए सार्वजनिक साख तथा ऋण लेती हैं जिससे अल्पकालीन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जा सकती है।

(2) पूँजी की उत्पादन शक्ति में वृद्धि (Increase the productivity of Capital) साख पूँजी को गतिशीलता प्रदान कर उसकी उत्पादन शक्ति में वृद्धि करती है। योग्य व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को उद्योग चलाने के लिए आवश्यक पूँजी साख द्वारा ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार साख आवश्यकता से अधिक धन रखने वाले व्यक्तियों को उसे योग्य व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को उधार देने की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रक्रिया द्वारा पूँजी उसके प्रयोग की इच्छा तथा योग्यता न रखने वाले व्यक्तियों से इच्छुक तथा व्यापारिक जोखिम उठाने की क्षमता वाले व्यक्तियों को हस्तान्तरित हो जाती है। इस प्रकार समाज की निष्क्रिय तथा अनुपयोगी पूँजी उत्पादक कार्यों में लगती है और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इससे सीमित राष्ट्रीय साधनों का अधिक प्रभावकारी उपयोग सम्भव हो जाता है।

(3) बहुमूल्य धातुओं की बचत (Economy in the use of precious metals) : साख पत्रों के प्रचलन से बहुमूल्य धातुओं के प्रयोग में बचत हो जाती है। व्यापारी अधिकतर साख पत्रों द्वारा ही भुगतान करते हैं और इस प्रकार विनिमय-माध्यम के रूप में साख के प्रयोग के कारण धातु-मुद्रा तथा पत्र-मुद्रा के प्रयोग में बचत सम्भव हो जाती है।

(4) देश के आर्थिक विकास में सहायता (Helps economic development) : साख देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है। साख की

सुविधा के ही कारण व्यापारी तथा उद्योगपति नये नये क्षेत्रों में कार्य करने तथा ज़ाखिम उठाने को प्रोत्साहित होते हैं। उधार लेने की सुविधा के कारण प्रबन्धक व्यापार की परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप पूंजी की मात्रा को बन्ध घटा सकता है। जब किसी निर्माता की वस्तुओं की माग बढ जाय तो वह अनिश्चित कार्यशील पूंजी उधार लेकर अपने उत्पादन का विस्तार कर सकता है और यदि किन्हीं समयों में वस्तुओं की माग घट जाय तो वह पूंजी की मात्रा को घटा सकता है। सरकार भी पूंजी उधार लेकर सावजनिक क्षेत्र में उद्योगों का विस्तार करती है। इस प्रकार साख की सुविधा देश के आर्थिक तथा वाणिज्यिक विकास में महत्वपूर्ण सहायता पहुँचाती है।

(5) बचत तथा पूंजी संचय को प्रोत्साहन (Encouragement to savings and capital formation) साख की सुविधा ने लोगों में बचत करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया है जिससे पूंजी निर्माण में सहायता मिलती है। बैंक लोगों की छोटी छोटी बचतों को एकत्र कर व्यापार और उद्योग की वित्त व्यवस्था करती है। इस प्रकार व्यापार, उद्योग और वाणिज्य का विकास होता है।

(6) अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में सुविधा (Facility in International Payments) : अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में राष्ट्रीय मुद्रायें स्वीकार न होने के कारण विदेशी साख पत्रों के माध्यम से ही भुगतान होते हैं। विनिमय बिलों की व्यवस्था के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक भुगतानों में बड़ी सुविधा हो गई है और विदेशी व्यापार के विस्तार में बड़ी सहायता मिली है।

(7) मुद्रा प्रणाली में लोच (Elasticity in the Monetary System) साख का सृजन व्यापारिक बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है। देश के व्यापार, उद्योग तथा वाणिज्य की आवश्यकताओं के अनुसार बैंक साख का विस्तार तथा सकुचन करती रहती है और देश का केन्द्रीय बैंक साख का नियन्त्रण और नियमन करता है। इस प्रकार मुद्रा प्रणाली में पर्याप्त लोच आ जाती है जो आदर्श मुद्रा प्रणाली का महत्वपूर्ण गुण है।

(8) कीमत तल की स्थिरता (Stability of the Price Level) किसी भी देश में साख पत्र, चलन माध्यम का बहुत बड़ा अंग होता है अतः मुद्रा के नियमन के साथ साथ साल का नियन्त्रण भी केन्द्रीय बैंक का बड़ा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। बैंकों द्वारा निर्मित साख की मात्रा का नियमन कर केन्द्रीय बैंक देश के कीमत तल में स्थायित्व लाने का प्रयत्न करता है। केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति का यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है।

(9) दूरस्थ स्थानों पर भुगतानों में सुविधा (Facility of Distant Payments) . चेक, विनिमय बिल इत्यादि साख पत्र भुगतान करने के बड़े सुगम

साधन हैं। इनकी सहायता से दूरस्थ स्थानों पर सुविधापूर्वक भुगतान किया जा सकता है। इनके प्रयोग से एक स्थान से दूसरे स्थान को नकदी लाने ले जाने की जोखिम समाप्त हो जाती है और इसमें मितव्ययिता भी होती है।

(10) सुविधाजनक रूप में ऋण प्राप्त (Enables loans to be taken in a convenient form) : साख पत्रों के रूप में ऋण बड़ी सुविधापूर्वक प्राप्त किये जा सकते हैं। यह ऋण व्यापार, वाणिज्य तथा उत्पादन में सहायक सिद्ध होते हैं। एक साख पत्र "समय तथा स्पेस पर पुल" का काम करता है।¹ साख पत्रों की सहायता से क्रेता कोषों को प्राप्त कर भुगतान कर सकता है तथा उत्पादनकर्ता माँग के अनुमानों के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है।

(11) राष्ट्रीय साधनों का अधिकतम उपयोग (Effective Utilisation of National Resources) साख की सहायता से राष्ट्रीय साधनों का अधिकतम उपयोग सम्भव हो जाता है। जिन क्षेत्रों में विकास की सम्भावनाएँ होती हैं उन क्षेत्रों में साहसी साख की सहायता से उत्पादन कार्यों का विस्तार करते हैं और इस प्रकार देश के उपलब्ध साधनों का अधिकतम लाभकारी उपयोग हो जाता है और देश के विकास को गति मिलती है।

(12) उपभोग में वृद्धि (Increase in Consumption) साख सुविधाओं के कारण उपभोक्तियों के जीवन-स्तर में सुधार हुआ है। उपभोक्ता साख (Consumer Credit) की व्यवस्था से उपभोक्ता दीर्घकालीन उपभोग्य पदार्थ जैसे कार, स्कूटर, रिकॉर्डेजरेटर, रेडियो इत्यादि खरीद सकते हैं और अपने जीवन स्तर को ऊँचा कर सकते हैं। अमेरिका इत्यादि देशों में उपभोक्ता साख के द्वारा उपभोग स्तर में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है।

(13) रोजगार के अवसरों में वृद्धि (Increase in Employment Opportunities) : किसी भी देश में पूर्ण रोजगार (Full Employment) के उद्देश्य की प्राप्ति में साख पर्याप्त सहायता प्रदान करती है। मन्दीकाल में जब बेरोजगारी बढ़ जाती है तो साख-विस्तार द्वारा कीमत तल में वृद्धि कर उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सकता है और रोजगार के अवसर सुलभ किये जा सकते हैं। केन्द्रीय बैंक अपनी साख नियंत्रण नीति का निर्माण करते समय इस दृष्टिकोण से भी विचार करता है।

साख व्यवस्था का विकास तीन बातों के उदय के कारण सम्भव हो सका है।

- (1) व्यापारिक नैतिकता की भावना (A sense of business morality),
- (2) मावी-भुगतान का सापेक्षिक रूप से स्थायी मोद्रिक मान (A relatively stable monetary standard for deferred payments) तथा
- (3) व्यक्तियों

¹ A credit instrument is a "bridge over time and space."

के अधिकारों को सुरक्षित तथा अनुबंधों की शीघ्र पूर्ति को लागू करने वाली विधिव्यवस्था (A legal system designed to safeguard the rights of individuals and to enforce a prompt fulfilment of contracts)। आधुनिक औद्योगिक समाज के विकास में साख व्यवस्था के इन तीनों सहायकों ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। इन सभी का विकास परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित रहा है। इनमें से प्रत्येक ने साख व्यवस्था के विकास में सहायता की है और प्रत्येक साख व्यवस्था के विकसित होने पर स्वयं विकसित हुआ है।

साख का महत्व इतना बढ़ गया है कि कम या अधिक प्रत्येक व्यापार आज उधार लिए गये ऋणों पर निर्भर है। इसीलिए मोल्टन (Moulton) ने कहा है कि "Borrowing has become an indispensable handmaiden of business" साख की महत्ता का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा Credit is in truth a pervasive, fundamental institution—one that is indispensable to the conduct of a capitalistic industrial system'.

साख की हानियाँ (Dangers of Credit)

साख पत्र तथा साख व्यवस्था समाज के लिए बड़े लाभदायक सिद्ध हुए हैं परन्तु कुछ परिस्थितियों में वे समाज के लिए बड़े हानिकारक बन जाते हैं। यही कारण है कि उसे एक अच्छा सेवक किन्तु बुरा स्वामी कहा जाता है। (Credit is a good servant but a bad master) साख की मुख्य हानियाँ निम्नलिखित हैं —

(1) साख के अत्याधिक प्रसार का भय (Danger of Over-issue) देश के व्यापार, उद्योग तथा वाणिज्य की आवश्यकताओं की तुलना में जब साख का अनियन्त्रित विस्तार हो जाता है तो यह स्थिति स्फीति के दुष्परिणामों का जन्म देती है। देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और कृत्रिम सम्पन्नता के बावजूद अर्थ-व्यवस्था क्षणिक हो जाती है। यह स्थिति अर्थ-व्यवस्था के लिए बड़ी भयावह होती है और अन्त में मौद्रिक ढांचा अस्त-व्यस्त हो जाता है।

(2) अपव्यय को प्रवृत्ति को बढ़ावा (Easy credit leads to extravagance) • जब साख मुविधा सरलतापूर्वक उपलब्ध हो जाती है तो उसका अपव्यय होने लगता है। व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान अनावश्यक क्षेत्रों में व्यय करने लगते हैं और उपभोक्ता फिजूलखर्चों का लोभ सवरण नहीं कर पाते। इस प्रकार सीमित राष्ट्रीय साधना का अवाञ्छनीय प्रयोग होने लगता है जो किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता।

(3) अयोग्य तथा अकुशल व्यापारियों का पोषण (Protection to incapable and inefficient businessmen) : साख की सहायता से अकुशल तथा अर्वाङ्मनीय व्यापारियों का पोषण होता है। सुगमतापूर्वक ऋण आदि प्राप्त कर ये व्यापारी अपनी दुर्बलताओं का छिपाने में सफल हो जाते हैं परन्तु सक्रम काल में ये स्वयं ही नष्ट नहीं होने बरन् सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था को हानि पहुँचाते हैं।

(4) आर्थिक असमानता में बढि (Increase in Economic Inequalities) : साख की सहायता से पूँजी का निर्माण होता है और समाज का एक विभिन्न वर्ग धीरे-धीरे पूँजी का केन्द्रीयकरण कर शक्तिशाली बन जाता है। साख की सहायता से ये लोग अपनी आय को बहुत अधिक बढा लेते हैं और समाज में आर्थिक शक्ति कुछ इन्ने गिने व्यक्तियों में केन्द्रित हो जाती है।

(5) एकाधिकारी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन (Encourages monopolistic tendencies) : साख व्यवस्था एकाधिकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करती है। साख का आधार विश्वास तथा चुकान की क्षमता होती है और इस कारण साधन सम्पन्न तथा आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्ति तथा संस्थाएँ साख प्राप्त कर लेती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ अपने साधनों का एकीकरण कर एकाधिकार या ट्रस्ट बना लेती हैं और मितव्ययितापूर्वक उत्पादन तथा वितरण कार्य करती हैं। इनके समक्ष छोटी इकाइयाँ प्रतिस्पर्धा में उठर नहीं पाती। इन एकाधिकारियों द्वारा उपभोक्ता का शोषण होगा है और समाज को और भी हानियाँ होती हैं।

(6) अत्याधिक उत्पादन का भय (Danger of over-production) : सस्ती साख सुविधायें उपलब्ध होने के कारण उत्पादन के आवश्यकता से अधिक बढ जाने की आशंका रहती है। अत्याधिक उत्पादन के फलस्वरूप मिला तथा व्यापारियों के पास माल भरा रहता है और ग्राहकों द्वारा माग नहीं होती। परिणामस्वरूप कीमतें गिरने लगती हैं, बेकारी फैलती है और उत्पादनक्षमताओं को हानि उठानी पडती है।

(7) सट्टे की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन (Encourages speculation) : शेयर तथा वस्तु बाजारों में सट्टे की प्रवृत्ति की साख व्यवस्था ने प्रोत्साहित किया है। सट्टोरिये बैंकों तथा अन्य साख संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सट्टा क्रियाओं को करते हैं। इस दिशा में अवाङ्मनीय क्रियायें अथ व्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न करती हैं।

(8) व्यापार चक्रों को जन्म (Causes of Trade Cycles) हाट्टे (Hawtrey) के अनुसार साख का विस्तार तथा सकुचन व्यापार चक्रों (Trade Cycles) को जन्म देता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अनियोजित तथा अनियन्त्रित साख व्यवस्था देश के विकास के लिए बरदान न हाकर अभिशाप बन जाती है। मुद्रा के सम्बन्ध में राबर्टसन (Robertson) का कथन साख पर भी ठीक उतरता है - "Money, which is a source of so many blessings to mankind, becomes also, unless we control it, a source of peril and confusion." इस कारण मुद्रा तथा साख की मात्रा पर समुचित नियन्त्रण तथा नियमन बहुत आवश्यक है। इसीलिए साख के निर्माण तथा वितरण पर केन्द्रीय बैंक का नियन्त्रण रहता है और अर्थ-व्यवस्था के हित में वह आवश्यक कार्यवाही करता है।

साख-पत्र

(Credit Instruments)

साख-पत्रों के प्रचलन का इतिहास बड़ा पुराना है। इस बात के प्रमाण मिले हैं कि प्राचीन काल में हिन्दू, ग्रीक तथा रोमन लोग साख पत्रों का प्रयोग करते थे। परन्तु वाणिज्य में साख पत्रों की इतना महत्वपूर्ण स्थान आधुनिक समय में ही प्राप्त हुआ है। प्रमुख साख-पत्रों का वर्णन नीचे किया है :

- 1 चेक (Cheque)
- 2 विनिमय बिल (Bill of Exchange)
- 3 प्रतिज्ञा-पत्र या खूका (Promissory Note)
- 4 हुंडी (Hundi)
- 5 साख-प्रमाण-पत्र (Letters of Credit)
- 6 यात्री चेक (Travellers Cheque)
- 7 कोषागार विपत्र (Treasury Bills)
- 8 बुक-क्रेडिट (Book Credit)

ये सभी साख-पत्र किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार की ओर से लिखित वायदे होते हैं कि वह उसमें लिखित राशि को अमुक समय, अमुक व्यक्ति को दे देगा और यह सब विनिमय के माध्यम का कार्य करते हैं।¹ परन्तु साख पत्र तथा मुद्रा में दो अन्तर पाये जाते हैं : (अ) मुद्रा की तरह साख-पत्र कानूनी या विधि-प्राप्त नहीं होती। साख पत्रों को स्वीकार करने को किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता

¹ (a) Credit instruments are written documents containing the various terms and conditions on which debts have been negotiated

(b) "Credit instruments are the written evidences of antecedent credit operations that serve as media of exchange"

—Harold G Moulton *Financial Organisation and the Economic System*, p 106.

जबकि मुद्रा को स्वीकार करने के लिये बाध्य किया जा सकता है। (ब) साख पत्र मुद्रा की तरह सर्वमान्य भी नहीं होते क्योंकि इनका स्वीकार करना विश्वास पर निर्भर करता है। पारस्परिक जानकारी रखने वाले व्यक्तियों में ही साख-पत्रों का प्रचलन होता है।

1 चेक या धनादेश (Cheque)

चेक सबसे अधिक प्रचलित साख पत्र है। चेक को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है, "चेक एक लिखित आज्ञा पत्र है जो बैंक में रुपया जमा करने वाला अपने बैंक के नाम जारी करता है और जिसमें उस बैंक को आज्ञा रहती है कि चेक में लिखित राशि को, उसमें लिखित व्यक्ति को या उसके आदेश प्राप्त व्यक्ति को या धारक को मागने पर प्रदान करें।"² इस परिभाषा के अनुसार चेक के तीन पक्ष होते हैं : प्रथम चेक को लिखने वाला (Drawer), द्वितीय, जिस बैंक पर वह लिखा गया हो (Drawee), तृतीय, रकम को पाने वाला (Payee)। जब चेक लिखने वाला स्वयं रकम पाने वाला होता है तो वही पाने वाला (Payee) हो जाता है।

चेक की निम्नलिखित विशेषतायें होती हैं—(1) चेक एक बिना शर्त का लिखित आदेश होता है। (2) चेक सदा किसी बैंक पर लिखा जाता है। (3) चेक पर लिखने वाले (Drawer) के हस्ताक्षर होते हैं। (4) चेक केवल कुछ रकम का भुगतान करने का आज्ञा पत्र होना है। (5) भुगतान माग पर (On Demand) होना चाहिए तथा (6) इसका भुगतान लिखित व्यक्ति या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति या धारक को होना चाहिए।

चेक दो प्रकार के होते हैं : (1) बियरर या वाहक चेक (Bearer Cheque) जिसका भुगतान वाहक या चेक प्रस्तुत करने वाले को कर दिया जाता है। वाहक चेक पूर्ण रूप से हस्तान्तरणीय होते हैं और कोई भी व्यक्ति उसका भुगतान ले सकता है। इसीलिए वाहक चेक सुरक्षित नहीं होते। (2) आदेश चेक (Order Cheque) जिसमें राशि प्राप्त करने वाले (Payee) के नाम का उल्लेख होता है और उसको या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति के पक्ष में वैधानिक हस्तान्तरण (Endorsement) किया जाना आवश्यक है।

² (a) A cheque is an instrument in writing, containing an unconditional order, signed by the maker, drawn upon a specified banker, directing the bank to pay, on demand, a certain sum of money, only to, or to the order of, a certain person or to the bearer of the instrument

(b) A cheque is a bill of exchange drawn on a banker payable on demand.

चेको का रेखांकन (Crossing) भी किया जा सकता है। जब चेक के बायीं ओर के ऊपरी भाग पर दो तिरछी समानान्तर रेखाएँ खींचकर अंग्रेजी में ' & Co.' शब्द लिख दिए जाते हैं तो इसे रेखांकित चेक कहते हैं। रेखांकित चेक का भुगतान बैंक की खिडकी पर नहीं होता बल्कि रकम पाने वाले के खाते में ही जमा हो सकती है। रेखांकन भी दो प्रकार का होता है : साधारण रेखांकन (General Crossing) तथा विशिष्ट रेखांकन (Special Crossing)। साधारण रेखांकन वह रेखांकन होता है जब चेक के बायीं ओर ऊपरी भाग पर ' & Co.' शब्दों सहित या उनके बिना दो तिरछी समानान्तर रेखाएँ खींची जाती हैं और उनके बीच किसी विशिष्ट बैंक का नाम नहीं होता है। विशिष्ट रेखांकन के अंतर्गत भुगतान किसी विशिष्ट बैंक को ही हो सकता है जिसका नाम उन दो समानान्तर रेखाओं के बीच लिख दिया जाता है।

2. विनिमय बिल (Bill of Exchange)

विनिमय बिल भी एक प्रचलित साक्ष्य पत्र है। भारतीय विनिमय साध्य विपणन अधिनियम (Indian Negotiable Instrument Act) के अनुसार "विनिमय बिल एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं और उसकी ओर से किसी व्यक्ति को शर्त रहित आदेश होता है कि वह एक निश्चित राशि किसी व्यक्ति को या उसके आदेशित व्यक्ति को या धारक को भुगतान कर दे।"¹ बिल के भी तीन पक्ष होते हैं : (1) बिल लिखने वाला या ऋणदाता (Drawer) (2) जिस पर बिल लिखा जाता है या ऋणी (Drawee) तथा (3) राशि पाने वाला (Payee)।

विनिमय बिल की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं : (1) यह लिखित होना चाहिए। (2) भुगतान करने का शर्त रहित आदेश होना चाहिए। (3) लेखक के हस्ताक्षर होने चाहिए। (4) किसी निश्चित व्यक्ति को भुगतान करने का निर्देश होना चाहिए। (5) भुगतान कुछ निश्चित रकम का होना चाहिए।

विनिमय बिल दो प्रकार के होते हैं प्रथम, दर्शनी बिल (Sight or Demand Bill of Exchange) वह होता है जिसका भुगतान भाग पर करना होता है। द्वितीय, मुद्दती बिल (Time or Usance Bill of Exchange) वह होता है जिसका भुगतान लिखित अवधि के पश्चात् करना होता है। विनिमय बिल देशी (Inland) तथा विदेशी (Foreign) भी हो सकते हैं। जब बिल के दोनो

¹ "A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order, signed by the maker, directing a certain person to pay a certain sum of money only to, or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument."

पक्ष एक ही देश के हैं तो उसे देशी बिल (Inland Bill) कहते हैं और जब दो में से एक पक्ष विदेशी हो तो उसे विदेशी बिल (Foreign Bill) कहते हैं ।

3 प्रतिज्ञा-पत्र या रुबका (Promissory Note)

भारतीय विनिमय साध्य विपत्र अधिनियम (Indian Negotiable Instruments Act) के अनुसार “प्रतिज्ञा-पत्र एक लिखित प्रपत्र है जिसमें उसका लेखक उसमें लिखी हुई राशि किमी निश्चित व्यक्ति या उसके आदेशित व्यक्ति या वाहक को देने की शर्त रहित प्रतिज्ञा करता है ।”¹ प्रतिज्ञा-पत्र के केवल दो पक्ष होने हैं :

(1) लिखने वाला या ऋणी (Promisor) तथा (2) रुपया पाने वाला या ऋण-दाता (Payee) ।

प्रतिज्ञा पत्र की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं—(1) यह लिखित होना चाहिए । इसमें बिना शर्त भुगतान करने की प्रतिज्ञा होनी चाहिए । (2) भुगतान की प्रतिज्ञा धन के सम्बन्ध में होनी चाहिए अन्य किसी वस्तु के सम्बन्ध में नहीं । (4) लेखक के हस्ताक्षर होने चाहिए । (5) भुगतान निश्चित व्यक्ति या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति या धारक को होना चाहिए ।

प्रतिज्ञा पत्र में जब प्रतिज्ञा माग पर भुगतान करने की होती है तो उसे माग प्रतिज्ञा-पत्र (Demand Promissory Note) कहते हैं और जब निश्चिन अवधि व्यतीत होने के बाद भुगतान की प्रतिज्ञा होती है तो उसे मुदती प्रतिज्ञा-पत्र (Time Promissory Note) कहते हैं ।

4 हुंडी (Hundi)

भारत में प्राचीन काल में प्रचलित भारतीय विनिमय बिल को हुंडी कहा जाता है । हुंडी क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी जाती है । “हुंडी एक बिना शर्त वाला लिखित आदेश है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर लिखा जाता है जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति को या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को मागने पर या निश्चित अवधि व्यतीत होने पर एक निश्चित रकम का भुगतान करने का आदेश होता है ।”²

¹ “A Promissory note is an instrument in writing (not being bank note or a currency note), containing an unconditional undertaking, signed by the maker, to pay a certain sum of money only to, or to the order of, a certain person or to the bearer of the instrument”

² “A hundi is a written order, usually unconditional, drawn by one person on another for payment, on demand or after a specified time, of a certain sum of money, to a person named therein.”

हुडिया कई प्रकार की होती हैं परन्तु दो प्रकार की—दर्शनी हुडी तथा मुहती हुडी अधिक प्रचलित हैं। दर्शनी हुडी का भुगतान माघ पर किया जाता है और मुहती हुडी का भुगतान निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद।

5 साख प्रमाण-पत्र (Letters of Credit)

साख प्रमाण पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो किसी व्यक्ति, सस्या या बैंक द्वारा लिखा जाता है और उसे किसी व्यक्ति, व्यापारी, सस्या या बैंक से यह प्रार्थना की जाती है कि अमुक व्यक्ति को एक निश्चित अधिकतम सीमा के भीतर साख प्रदान करें। इस पत्र में उस तिथि का भी उल्लेख कर दिया जाता है जिस तक साख प्रदान की जाय। साख-प्रमाण पत्र दो प्रकार के होते हैं—साधारण साख प्रमाण पत्र (Ordinary Letters of Credit) तथा गश्ती साख-प्रमाण पत्र (Circular Letters of Credit)। साधारण साख-प्रमाण पत्र वह है जो व्यक्ति, फर्म या बैंक को लिखा जाता है जबकि गश्ती साख-प्रमाण पत्र बैंक की अनेक शाखाओं तथा सम्बन्धित बैंकों को लिखा जाता है और उसकी सहायता से कहीं से भी साख प्राप्त की जा सकती है।

6 यात्री चेक (Traveller's Cheque)

यह चेक बैंकों द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए जारी किए जाते हैं जिससे उन्हें नकदी ले जाने की जोखिम न उठाना पड़े। बैंक की किसी शाखा को नकद भुगतान के बदले यह चेक प्राप्त किए जा सकते हैं और बैंक की किसी भी शाखा में उन्हें भुनाया जा सकता है।

7 कोषागार विपत्र (Treasury Bills)

सरकार अपनी अल्पकालीन धन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोषागार विपत्र जारी करती है। ये प्रायः 3 या 6 महीने की अवधि के होते हैं। इन विपत्रों को बेचने के लिए सरकार टेन्डर (Tender) आमन्त्रित करती है और जिसमें न्यूनतम ब्याज या बट्टे की दर होती है उसे स्वीकार कर लिया जाता है। स्वीकृत टेन्डर वाला व्यक्ति वट्टा काट कर विपत्रों की राशि का भुगतान कर देता है और निश्चित अवधि के बाद सरकार सम मूल्य (At Par) पर विपत्रों का भुगतान कर देती है। कोषागार विपत्र बड़े तरल विनियोग हैं और बैंक अपने कोषों का अधिकतर भाग इनमें विनियोजित करते हैं।

8. बुक क्रेडिट (Book-Credit)

जब कोई दुकानदार किसी को उधार माल बेचता है और उसे अपने खाते में उधार रूप में दिखलाता है तो इसे बुक-क्रेडिट कहते हैं। व्यापारी के खाते में दिखाया गया ऐसा ऋण अदालतों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है चाहे ऋणों के उस पर हस्ताक्षर न हो।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके सकेत

1 साख शब्द का अर्थ समझाइये और आधुनिक व्यापार में इसके महत्त्व पर प्रकाश डालिए ।

(आगरा बी० काम, 1958)

[सकेत—प्रथम भाग में साख की मुख्य परिभाषायें देते हुए साख का अर्थ स्पष्ट कीजिए । द्वितीय भाग में आधुनिक व्यापार के लिए साख का महत्त्व तथा उपयोगिता बताइये ।]

2 साख पत्रों के विभिन्न भेदों की व्याख्या कीजिए ।

(पटना बी० काम०, 1964)

[सकेत—विभिन्न प्रकार के साख-पत्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए ।]

बैंक-विकास, परिभाषा तथा कार्य (Banks-Evolution, Definition and Functions)

"Banking consists of receiving other people's money and lending it out again to the people who deposited it. The banker really borrows the depositor's money, usually for nothing, and then lends the same money back again on interest."

बैंको का उद्गम (Origin of Banks) बैंको के विकास का इतिहास बहुत पुराना है। इस बात के प्रमाण मिले हैं कि ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया और यूनान के मंदिरों में बैंकिंग के कार्य हुआ करते थे। भारत में वैदिक काल में भी बैंक थे। कुछ समय पश्चात् धार्मिक तथा राजनैतिक व्यवस्था के पतन के साथ बैंक प्रणाली का भी पतन हो गया। पुनः सैन्डो वर्षों के पश्चात् व्यापारिक उन्नति के साथ साथ साख मस्याओं का विकास हुआ।

'बैंक' शब्द की उत्पत्ति के सम्बन्ध में दो विचारधाराएँ हैं। एक विचारधारा के अनुसार 'बैंक' शब्द की उत्पत्ति इटैलियन भाषा के 'बैंको' (Banco) शब्द से हुई जिसका अर्थ होता है बेन्च। उस समय यहूदी अपना लेन देन कार्य बेन्चों पर बैठकर किया करते थे। जिस व्यक्ति का व्यापार समाप्त हो जाता था उसका बेन्च तोड़ दिया जाता था और उसको दीवालिया (Bankrupt) घोषित कर दिया जाता था। यदि यह विचार सही है तो बेन्च पर बैठकर अपना लेनदेन का कार्य करने वाले यहूदियों को इटैलियन भाषा में 'बेन्चेरी' (Bencheri) कहना चाहिए था, परन्तु इन लोगों को बेन्चेरी नहीं कहा गया अतः इस विचारधारा में कहीं गलती है। मैक्सिलियोड ने इस विचारधारा को भ्रान्त बताया है।

'बैंक' की उत्पत्ति के सम्बन्ध में दूसरी विचारधारा के अनुसार 'बैंक' शब्द का आविर्भाव जर्मन शब्द Banck से हुआ। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले इटली में हुआ। 12वीं शताब्दी में इटली में छोटी छोटी रियासतें थीं। वेनिस नामक रियासत में 1171 में युद्ध के कारण वहाँ के राजा को धन की आवश्यकता पड़ी अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति का प्रतिशत ऋण के रूप में देने के लिए बाध्य किया गया। उस समय इटली के अधिनाश भाग पर जर्मनों का शासन था। जर्मनों ने

इस कोष को Banck नाम से पुकारा । इटेलियन भाषा में किसी संयुक्त कोष (Common fund) को 'Monte' या 'Banco' कहते हैं । फ्रेंच भाषा में इसे 'Banke' कहा गया और फिर अंग्रेजों ने इसको Bank कहा ।

बैंक की परिभाषा (Definition of a Bank)

बैंको के कार्य क्षेत्र तथा प्रणाली में उत्तरोत्तर परिवर्तन होते आये हैं और उनके साथ साथ बैंक की परिभाषा बदलती रही है । विभिन्न विद्वानों ने बैंक की भिन्न-भिन्न परिभाषायें दी हैं । बैंक की सर्वमान्य परिभाषा देना बड़ा कठिन है क्योंकि देश और काल के अनुसार बैंक के कार्य बदला करते हैं । एक परिभाषा जो एक देश तथा काल के लिए उपयुक्त हो सकती है दूसरे देश अथवा काल के बैंको के लिए उचित न प्रतीत हो । एक कठिनाई यह भी है कि आजकल बैंको के कार्यों में बड़ा विशिष्टीकरण हो गया है और विभिन्न प्रकार के बैंक अपने अपने क्षेत्र में दक्षता प्राप्त कर कार्य कर रहे हैं । इसलिए किसी एक परिभाषा में सभी प्रकार के बैंको के कार्यों का उल्लेख करना एक दुर्लभ कार्य है । बैंक की सही परिभाषा करने के लिए हम उनके कार्यों में ऐसी समानता खोजनी चाहिये जिनके आधार पर निर्मित परिभाषा इतनी व्यापक हो जो सभी प्रकार के बैंको पर लागू हो, साथ ही वह इतनी परिमित भी हो कि उसके अन्तर्गत केवल ऐसी सस्थाओं का समावेश हो सके जो वास्तव में बैंक कही जा सके । इसी दृष्टिकोण से यहाँ हम कुछ प्रतिनिधि परिभाषाओं का विश्लेषण करेंगे जिससे बैंक का अर्थ तथा कार्य स्पष्ट हो सके ।

द्वि शोर्टर ऑक्सफोर्ड इंगलिश डिक्शनरी (The Shorter Oxford English Dictionary) में बैंक की परिभाषा इस प्रकार है — "बैंक एक ऐसी सस्था है जो अपने ग्राहकों या उनकी ओर से प्राप्त धन को अपने संरक्षण में रखती है । इसका मुख्य कार्य उनके द्वारा बैंक पर जारी किये गये विपत्रों का भुगतान करना होता है । उसके लाभ उस धन के प्रयोग द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसका वे उपयोग नहीं करते हैं ।"¹ इस परिभाषा के अनुसार बैंक वह सस्था है जो जमा पर धन प्राप्त करती है और मांग पर उसका भुगतान करती है । यह परिभाषा अपूर्ण है क्योंकि आधुनिक बैंक के अन्य कार्यों पर इसमें प्रकाश नहीं डाला गया है ।

गिल्बर्ट के शब्दों में "बैंक पूर्ण अथवा अधिक उपयुक्त शब्दा में मुद्रा का व्यवसायी है । वह ऋणी तथा ऋणदाता के बीच का मध्यस्थ है । वह एक पक्ष से उधार लेता है और दूसरे पक्ष को उधार देता है और उधार देने तथा लेने की शर्तों

¹ 'An establishment for the custody of money received from or on behalf of its customers Its essential duty is to pay their drafts on it; its profits arise from the use of the money left unemployed by them.'

में अन्तर ही उसके लाभ का स्रोत है।"¹ यह परिभाषा भी बैंक के दो कार्यों-उधार लेना और उधार देना-पर ही प्रकाश डालती है परन्तु आधुनिक बैंक के कार्य बहुत विस्तृत हैं। आज बैंक केवल मध्यस्थ ही नहीं है बल्कि वह साख का सृजनकर्त्ता भी है। अतः यह परिभाषा भी सकीर्ण है।

डा० एच० एल० हार्ट के अनुसार "बैंकर वह है जो अपने साधारण व्यवसाय में धन प्राप्त करता है और जिससे वह उन व्यक्तियों के चेकों का भुगतान करता है जिनसे या जिनके खाते में वह धन प्राप्त करता है।"² इसी प्रकार वाल्टर लीफ के शब्दों में "बैंक वह सस्था या व्यक्ति है जो हर समय निक्षेप के रूप में द्रव्य प्राप्त करने के लिए तैयार हो और जिसको वह निक्षेप कर्त्ताओं को उनके चेकों के माध्यम से वापिस करे।"³ किन्ले ने भी ऐसे ही बैंक की परिभाषा दी है—'बैंक एक ऐसी सस्था है जो आवश्यकतानुसार तथा सुरक्षा के साथ लोगों को ऋण देती है और जिसके पास व्यक्ति अपना फालतू धन जमा कराते हैं।'⁴ हार्ट, वाल्टरलीफ तथा किन्ले बैंक के दो कार्यों—ऋण देना तथा जमाये प्राप्त करना—पर ही बल देते हैं। इसी-लिए यह सभी परिभाषायें सकीर्ण हैं।

किन्डले शिराज के शब्दों में "बैंकर वह व्यक्ति, फर्म या कम्पनी है जिसके पास व्यावसायिक स्थान है जहां जमा तथा मुद्रा या चलन के सग्रहण के द्वारा साख का कार्य किया जाता है जिसको वह ड्रापट, चेक या आदेश के द्वारा भुगतान करता है या जहां स्टॉक, बॉन्ड्स, घातुओं, विनिमय-पत्रों पर ऋण दिया जाता हो या बिलों

¹ "A banker is a dealer in capital or more properly a dealer in money. He is an intermediary party between the borrower and the lender. He borrows from one party and lends to another and the difference between the terms at which he borrows and those at which he lends forms the source of his profits."—Gilbert.

² 'A banker is one who in the ordinary course of his business, receives money which he pays by honouring cheques of persons from whom or on whose account he receives it.'—Dr. H. L. Hart.

³ "A bank is that institution or individual who is always ready to receive money on deposits to be returned against the cheques of their depositors."—Walter Leaf.

⁴ "Bank is an establishment which makes to individuals such advances of money as may be required and safely made and to which individuals entrust money when not required by them for use."—Kinley.

तथा प्रतिज्ञा पत्रों को बढ़ा करने तथा विक्रय करने के लिए प्राप्त किया जाता हो।¹ यद्यपि शिराज की परिभाषा काफी विस्तृत है क्योंकि इसमें बैंक के उधार लेने तथा उधार देने के कार्य के साथ साख के कार्य भी सम्मिलित किए गये हैं परन्तु फिर भी यह एक पूर्ण तथा सर्व सम्मन परिभाषा नहीं है।

इंग्लैण्ड के बैंकिंग कानून के विद्वान सर जान पेजेट (Sir John Paget) ने बैंक की कार्यानुसार परिभाषा दी है। उनके अनुसार “कोई भी व्यक्ति या संस्था (सम्मिलित या व्यक्तिगत रूप में) बैंकर नहीं कहला सकता जब तक कि वह—

- (i) द्रव्य को जमा के रूप में नहीं लेता है,
- (ii) चालू खाते में रुपया जमा नहीं करता है,
- (iii) चेकों का निर्गमन तथा भुगतान नहीं करता है,
- (iv) चेकों को, चाहे वे अरेखांकित हो या रेखांकित अपने ग्राहकों के लिए एकत्रित नहीं करता है।

यह कहा जा सकता है कि चाहे ये सब उपरोक्त कार्य एक व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप में किये जाते हैं, परन्तु कोई भी बैंकर या बैंक नहीं कहला सकता जब तक कि वह निम्न शर्तें पूरी न करता हो—

- (i) बैंकिंग उसका मान्य या ज्ञात व्यवसाय हो,
- (ii) वह अपने आपको बैंकर या बैंक मानता हो और जनता भी ऐसा ही समझती हो,
- (iii) उसका विचार भी ऐसा कार्य करके लाभ कमाना हो, तथा
- (iv) यह व्यवसाय उसका गौण व्यवसाय न हो।²

¹ “A banker is a person, firm, or company having place of business where credits are opened by the deposit or collection of money or currency, subject to be paid or remitted upon draft, cheques, order or where money is advanced or loaned on stocks bonds, bullion, and B/E and P/N are received for discount or sale.”—Findley Shirras.

² “No one or no body, corporate and otherwise, can be a banker who does not—(i) take deposit accounts, (ii) take current accounts, (iii) issue and pay cheques drawn upon himself, (iv) collect cheques, crossed and uncrossed, for his customers and it might be said that even if all the above functions are performed by a person or body corporate, he or it may not be a banker or bank unless he or it fulfills the following conditions—(i) Banking is his or its known occupation, (ii) he or it must profess to be a banker or bank and the public take him or it as such, (iii) has an intention of earning by doing so, and (iv) this business is not subsidiary.”—John Paget

पैजेंट की परिभाषा व्यापक अवश्य है परन्तु ऋण देने के मुख्य कार्य को भुला दिया गया है।

भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (स) में बैंकिंग कम्पनी उसे कहा गया है जो बैंकिंग का व्यवसाय करे।¹ 'बैंकिंग' शब्द की परिभाषा धारा 5 (ब) में दी गई है— "बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से धन जमा करना है जो माग पर देय होगा तथा चेक, ड्राफ्ट, आज्ञा अथवा अन्य प्रकार से निकाला जा सकेगा।"² यह परिभाषा भी बैंक के सभी कार्यों का समावेश नहीं करती। इसमें भी वही दोष है जो गिलवर्ट तथा पेजेंट की परिभाषाओं में है।

बैंक की उपर्युक्त सभी परिभाषाओं की व्याख्या से स्पष्ट है कि यह परिभाषाये आधुनिक बैंकों के वर्तमान विकसित कार्य क्षेत्र का लाष्टीकरण करने में असमर्थ हैं। वास्तव में बैंक वह सस्था है जो मुद्रा और साख का व्यवसाय करती है तथा उससे सम्बन्धित सेवायें प्रदान करती है। हारेस व्हाइट (Horace White) की परिभाषा कि 'बैंक साख का सृजन कर्ता और विनियम को सुविधापूर्ण बनाने का यन्त्र है'³ अधिक उपयुक्त लगती है।

आधुनिक बैंकों के कार्य तथा सेवायें

(Functions and Services of Modern Banks)

प्रो० सेयर्स के अनुसार 'साधारण बैंकिंग व्यापार में नकदी को बैंक जमाओं तथा बैंक जमाओं को नकदी में बदला जाता है, बैंक जमाओं को एक व्यक्ति या निगम से दूसरे को हस्तान्तरित किया जाता है; विनियम-द्विती, सरकारी बान्डो, व्यापारियों द्वारा अदायगी के रक्षित प्रतिज्ञाओं आदि के बदले बैंक जमाये दी जाती है।'⁴ आधुनिक बैंकों के कार्य बहुत विस्तृत तथा महत्वपूर्ण हैं। आधुनिक बैंकों के कार्यों तथा सेवाओं को निम्न चार्ट से जाना जा सकता है —

¹ "Banking company means any company which transacts the business of banking"

² "The accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from public repayable on demand or otherwise and with drawl by cheque, draft, order or otherwise"

—Indian Banking Regulation Act, 1949.

³ "Bank is 'a manufacturer of credit and a machine for facilitating exchanges.'" — Horace White

⁴ "Ordinary banking business consists of changing cash for bank deposits and bank deposits for cash; transferring bank deposits from one person or corporation to another; giving bank deposits in exchange for bills of exchange, Government bonds, the Secured promises of businessmen to repay etc"

मुख्य कार्य (Primary Functions): बैंको के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं

(1) निक्षेप स्वीकार करना (Accepting of Deposits): आधुनिक बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य जनता से निक्षेप प्राप्त करना होता है। समाज के विभिन्न वर्ग अपनी श्रम के अनुसार कुछ न कुछ बचाते हैं। उन सभी लोगों में व्यापारिक योग्यता तथा साहस नहीं होता। अतः वे सुरक्षा तथा कुछ ब्याज प्राप्त करने के लिए अपनी बचत बैंको के पास जमा कर देते हैं। बैंको के निक्षेप दो प्रकार के होते हैं—(1) नकद निक्षेप या प्रत्यक्ष निक्षेप (Cash deposit or Direct deposit) (2) साख निक्षेप या अप्रत्यक्ष निक्षेप (Credit deposit or Indirect deposits)। नकद निक्षेप व होते हैं जिनमें वास्तव में लोग अपनी बचत नकदी में बैंक के पास जमा करते हैं परन्तु साख निक्षेप वे निक्षेप होते हैं जिनमें ग्राहको द्वारा बिना रुपया जमा कराया बैंक एक निश्चित सीमा तक रुपया निकालने का अधिकार दे देता है। (साख निक्षेपों की विस्तृत व्याख्या बैंको द्वारा साख सृजन नामक अध्याय में पढ़िए।)

व्यापारिक बैंक निम्नलिखित खातों में धन जमा कराने की सुविधा प्रदान करते हैं :—

(1) स्थायी जमा खाता (Fixed Deposit Account) स्थायी जमा खाता में एक निश्चित अवधि के लिए रुपया जमा कराया जाता है। यह अवधि 3 माह से 5 वर्ष या इससे अधिक भी हो सकती है। स्थायी जमा खाता खुलवाने के लिए एक प्रार्थना पत्र देना पड़ता है और बैंक को प्रार्थी अपने नमूने के हस्ताक्षर (Specimen Signature) देता है। रकम जमा करवाते समय बैंक एक स्थायी जमा रसीद (Fixed Deposit Receipt F. D R.) देता है जिसमें रकम जमा कराने की तिथि, रकम निकालने की तिथि (Due Date), रकम जमा कराने वाले का नाम, रकम तथा ब्याज की दर लिखी होती है। यह जमा रसीद अपरिवर्तनीय (Non Transferrable) होती है अर्थात् जमा की गई रकम जमा कराने वाले व्यक्ति को ही मिल सकती है अन्य किसी व्यक्ति को नहीं। जमा खाते में जमा रकम अवधि समाप्त होने पर ही वापिस की जाती है परन्तु ग्राहको की सुविधा के लिए जमा रसीद की धरोहर पर ऋण मिल सकता है जिस पर दिए जाने वाले ब्याज की दर से 1 प्रतिशत अधिक ब्याज देना पड़ता है। यदि जमाकर्ता अवधि से पहले ही रकम निकलवाना चाहे तो उसे ब्याज से हाथ धोना पड़ता है।

स्थायी जमा खाते में जमा रकम पर अन्य खातों की तुलना में ब्याज दर अधिक होती है। अवधि बढ़ने के साथ ब्याज दर ऊंची होती जाती है। कई बैंक 5 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए जमा रकम पर 7 प्रतिशत तक ब्याज देते हैं। अवधि के अनुसार प्रथम श्रेणी के बैंको द्वारा दिये जाने वाले ब्याज दरों की तालिका अप्रलिखित प्रकार है—

अवधि	ब्याज दर
91 दिन से अधिक तथा 6 माह से कम	4%
6 माह से अधिक तथा 9 माह से कम	4½%
9 माह से अधिक तथा 1 वर्ष से कम	5%
1 वर्ष से अधिक तथा 2 वर्ष से कम	5½%
2 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष से कम	5¾%
3 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम	6%
5 वर्ष से अधिक.....	6½%

स्थायी जमा खाते में वे लोग रकम जमा कराते हैं जिनके पास निश्चित रकम है और उस निश्चित रकम से आय तो चाहते हैं परन्तु कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। इंग्लैंड में स्थायी जमा खाते को (Seven Days Notice Deposit) कहते हैं क्योंकि वहाँ एक सप्ताह का नोटिस देकर जमा रकम निकाली जा सकती है यदि रकम जमा कराये हुए एक मास का समय व्यतीत हो गया हो।

(ii) चालू खाता (Current Account) : इस खाते के अन्तर्गत जितनी बार आवश्यकता हो, रकम जमा करायी जा सकती है और निकलवायी जा सकती है। यह खाता व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के लिए बड़ा उपयोगी है जिनके पास 111 में बहुत से चेक आते हैं और भुगतान में अनेको चेक देने पड़ते हैं। इस प्रकार इस खाते के द्वारा बैंक ग्राहकों के सभी लेन देनों का हिसाब रखता है और आवश्यकता पड़ने पर किसी भुगतान का प्रमाण-पत्र दे सकता है। प्रथम श्रेणी के बैंको द्वारा इस खाते में जमा रकम पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता परन्तु कुछ बैंक शेष राशि के न्यूनतम सीमा से कम न होने पर कुछ ब्याज देते हैं। चालू खाते पर बैंको द्वारा कुछ सेवा व्यय लिया जाना है जिसे प्रासंगिक व्यय (Incidental Charges) कहते हैं। खाता खोलने पर बैंक पास बुक (Pass Book), चेक बुक (Cheque Book) तथा पे इन स्लिप बुक (Pay-in-slip book) देती है। अमेरिका में चालू खाते को चेक खाता (Check or Checking Account) कहते हैं।

(iii) बचत खाता (Saving Bank Account) बचत खाता वेतन भोगी कर्मचारियों तथा साधारण आय वाले व्यक्तियों द्वारा खोले जाते हैं और वे इस प्रकार अपनी छोटी छोटी बचतों को संचित करते हैं। यह खाता 5 रुपये की न्यूनतम राशि से खोला जा सकता है। इस खाते में रकमें जितनी बार चाहे जमा कराई जा सकती हैं परन्तु धन सप्ताह में दो बार ही निकाला जा सकता है। कुछ बैंक 111 नर में कुछ निश्चित बार रकम निकालने की सुविधा देती हैं जैसे वर्ष में

अधिक से अधिक 100 बार। कुछ बैंक एक निश्चित राशि से अधिक रकम एक बार में निकालने की अनुमति नहीं देती। खाता खोलने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है और बैंक खाता खोलने वाले के नमूने के हस्ताक्षर (Specimen Signature) अपने पास रख लेता है। बचत खाते पर ब्याज दिया जाता है परन्तु यह स्यासी जमा खाते की तुलना में कम होता है। आजकल बैंक बचत खाते पर $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज देती है। अब अधिकतर बैंकों ने बचत खाता खोलने वाले को चेक द्वारा रकम निकालने की सुविधा दे दी है। पश्चिमो देशों में बचत खाते बचत बैंको (Savings Banks) द्वारा ही खोले जाते हैं परन्तु भारत में व्यापारिक बैंक बचत खाते खोलते हैं।

(iv) घरेलू बचत खाता (Home Safe Account) : परिवारों में बचत की आदत डालने के लिए बैंक अपने ग्राहकों को एक गोलक या निजोरी दे देते हैं जिसमें परिवार के सदस्य अपनी बचतें डालते रहते हैं। कुछ समय पश्चात् गोलक को बैंक में ले जा कर कुल रकम खाते में जमा करवा दी जाती है। खाली गोलक फिर ग्राहक को वापिस कर दी जाती है और यह क्रम जारी रहता है। जमा रकम पर नाम मान को ब्याज दिया जाता है। बच्चों में बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए यह खाता बड़ा उपयोगी है।

(ii) ऋण देना (Lending of Money) : ऋण देना व्यापारिक बैंको का महत्वपूर्ण कार्य है। बैंको के पास जो धन जमाकर्ताओं में प्राप्त होना है उसे वह व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को उत्पादक कार्यों के लिए उधार दे देती हैं। जमाकर्ताओं को दी जाने वाली ब्याज की दर उधार लेने वाली से ली जान वाली ब्याज की दर से कम होती है और इन्हीं ब्याज दरों का अन्तर बैंक का लाभ होता है। इस प्रकार बैंक एक मध्यस्थ (Intermediary) का कार्य करता है। ऋण देते समय बैंको को दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है—(1) तरलता (Liquidity) तथा (2) आय (Income)। बैंक अपनी जमाओं का कुछ प्रतिशत नकदी के रूप में रखती है जिससे ग्राहकों की मांगों पर तुरन्त भुगतान किया जा सके। साथ ही साथ बैंक यह भी देखता है कि दिये गये ऋणों से उसे पर्याप्त मात्रा में आय होती रहे। अतः तरलता तथा आय में सतुलन स्थापित कर ही बैंक सफल हो सकता है। बैंक की सफलता बहुत कुछ उसकी ऋण सम्बन्धी नीति पर निर्भर करती है।

बैंको द्वारा निम्नलिखित प्रकार के ऋण दिये जाते हैं —

(1) नकद साख (Cash Credit) : नकद साख द्वारा ऋण देने की प्रथा का जन्म स्काटलैंड में हुआ था। वहाँ की आर्थिक उन्नति में इस प्रथा का इतना महत्वपूर्ण योगदान रहा कि बैंकलियोड ने कहा कि स्काटलैंड के लिए नकद साख प्रणाली उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मित्र के लिए नील नदी। लेबी के अनुसार इस

प्रणाली ने बहुत से निर्धन व्यक्तियों को उद्योगपति के आसन पर बिठा दिया है।¹ नकद साख प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत बैंक व्यापारियों को वाडम् व्यापारिक माल या अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण देते हैं। जब व्यापारी माल की जमानत पर ऋण लेते हैं तो माल बैंक के गोदामों में रख लिया जाता है। व्यापारी अपनी भावी आवश्यकताओं के अनुमानों के आधार बैंक से एक निश्चित राशि उधार लेने का समझौता कर लेते हैं। उधार ली गई कुल रकम व्यापारियों द्वारा एक बार में ही नहीं निकाली जाती बल्कि जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है रकम निकाल ली जाती है। इस प्रणाली के अन्तर्गत व्याज वास्तव में निकाली गई रकम पर ही लिया जाता है। भारतीय व्यापारियों के लिए नकद साख प्रणाली बड़ी सुविधाजनक सिद्ध हुई है अतः उनमें यह बहुत प्रचलित है।

(ii) अधिविकल्प (Overdraft) जिन व्यापारियों का चालू खाता (Current Account) बैंक में खुला रहता है उन व्यापारियों को खाते में जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा को अधिविकल्प (Overdraft) कहते हैं। अधिविकल्प की सीमा का निर्धारण प्रतिभूतियों या व्यापारी की साख के आधार पर होता है। व्यापारी आवश्यकतानुसार इसी सीमा के अन्दर रकम निकालते रहते हैं। नकद साख की तरह अधिविकल्प में भी वास्तव में निकाली गई रकम पर ही व्याज लिया जाता है।

नकद साख तथा अधिविकल्प में अन्तर (Difference between Cash Credit and Overdraft) नकद साख तथा अधिविकल्प में मुख्य अन्तर यह है कि नकद साख किसी व्यक्ति को भी मिल सकती है जबकि अधिविकल्प की सुविधा केवल चालू खाता रखने वाले ग्राहकों को ही दी जाती है। नकद साख दीर्घ काल के लिए दी जाती है जबकि अधिविकल्प कभी-कभी धन की अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लिया जाता है। अधिविकल्प पर कभी कभी अधिक व्याज लिया जाता है।

(iii) ऋण तथा अग्रिम (Loans and advances) . नकद साख तथा अधिविकल्प के अतिरिक्त बैंक ऋण तथा अग्रिम भी देते हैं। जब बैंक एक भुक्त रकम उधार दे जिसे बाद में निकालने की आज्ञा सहित अंशतः या पूर्णतः अदा नहीं किया जा सकता, ऋण कहलाता है।² यदि ऋणी ऋण के कुछ भाग का

1 "It (cash credit system) has raised many a penniless to the state of industrialists"
— L. Levi

2 When a banker makes an advance in a lump sum which cannot be paid wholly or partially with permission to its subsequent with-drawal, it is called a loan.

भुगतान कर देता है और बाद में अदा की गई रकम को फिर उधार लेना चाहता है तो तब तक वह इस रकम को नहीं ले सकेगा जब तक कि बैंक एक नया ऋण स्वीकृत नहीं करता। इस व्यवस्था में ऋणी बैंक से ऋण की सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर लेना है और ऋण की पूर्ण रकम अदा कराये बिना ऋण का अन्त नहीं होता। ऋण तथा अग्रिम के अन्तर्गत व्याज उधार लेने की तारीख से ही पूरी रकम पर लगता है चाहे ऋणी पूरी रकम एक साथ निकाले या उसका कुछ भाग ही निकाले जबकि नकद साख तथा अधिविकल्प में व्याज वास्तव में निकाली गई रकम पर ही लगाया जाता है।

(iv) बिलों का बट्टा करना (Discounting of Bills of exchange)

बिलों का बट्टा करके रुपया उधार देने की प्रणाली एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। बैंक सावधि बिलों (Usance Bills) की भुगतान-तिथि के पहले ही बट्टा करके बिल की रकम देकर व्यापारियों को साख की सुविधा देते हैं। इस कार्य के लिए बैंक कुछ बट्टा (Discount) लेते हैं जो उस अवधि में व्याज के बराबर होता है। बट्टे की दर बिल की परिपक्वता की अवधि (Time of maturity) तथा बिल की जोखिम पर निर्भर करती है। इस प्रणाली में बैंकों को ऋणों तथा अग्रिमों की भांति कुछ भी प्रवध व्यय नहीं करना पड़ता।

इस प्रणाली में बैंकों को यह भी सुविधा रहती है कि यदि परिपक्वता की तिथि से पहले ही धन की आवश्यकता पड़ जाय तो वे इन बट्टा किए हुए बिलों का देश के कन्द्रीय बैंक से पुनः बट्टा करवा सकती हैं। व्यापारियों में बिलों के प्रचलन के कारण बिलों का बट्टाकर साख देने की यह प्रणाली काफी लोकप्रिय सिद्ध हुई है।

(2) सहायक या अभिकर्ता कार्य (Secondary or Agency functions) :

जमायें स्वीकार करना तथा ऋण देने के अतिरिक्त आधुनिक बैंक अपने ग्राहकों के अभिकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में कई प्रकार की सेवाएँ करता है। यह सेवाएँ निम्नलिखित हैं :—

(1) चेक, बिल आदि का भुगतान सग्रहण (Collection of cheques, bills etc.) आज कल व्यापारियों को भुगतान में विभिन्न बैंकों की चकें तथा बिल आदि प्राप्त होने रहने हैं। यदि व्यापारी स्वयं जाकर सभी बैंकों से भुगतान प्राप्त करे तो इसमें समय का अपव्यय तथा असुविधा होनी है। ग्राहकों की ओर से जमा कराये गये बिलों तथा चेकों का भुगतान बैंक बसूल करना है और अपने ग्राहकों के खातों में जमा कर देता है।

बैंकों का यह कार्य बैंकों को साख के नृजन में बहुत ही सहायक होता है। बैंकों को चेकों का भुगतान नकद मुद्रा में न कर केवल खात की प्रविष्टियाँ द्वारा

करना होता है। इस प्रकार बैंको का काम कम नकद कोष रखकर ही चल जाता है। यदि बैंको को सभी चेको का भुगतान नकदी में करना पड़े तो इससे उनकी साख-निर्माण शक्ति बहुत कम हो जायेगी।

(ii) ग्राहको की ओर से भुगतान करना (Making of Payments on behalf of the customers) ग्राहको की ओर से बैंक उनके आदेशानुसार भुगतान करता है जैसे बीमा पालिसी का प्रीमियम, मकान का किराया, ब्याज या चन्दा इत्यादि। एसी रकमा का भुगतान जो नियमित रूप से देनी होती है तथा जिनकी राशि निश्चित होती है बैंक करता रहता है। ग्राहक को केवल एक स्थायी आदेश (Standing order) इस सम्बन्ध में बैंक को देना होता है जिसमें भुगतान की तिथि तथा राशि के सम्बन्ध में सूचना देनी होती है। बैंक इस कार्य के लिए कुछ शुल्क लेते हैं।

(iii) ग्राहकों की ओर भुगतान प्राप्त करना (Collection of payments on behalf of the customers) जिस प्रकार बैंक ग्राहको की ओर से भुगतान करते हैं उसी प्रकार वे ग्राहको की ओर से लाभांश, ब्याज, किराया कमीशन, ऋण-धन आदि के भुगतान भी प्राप्त करते हैं और उन्हें एकत्रित कर ग्राहक के खाते में जमा कर देते हैं।

(iv) कोष हस्तान्तरण की सुविधा (Remittance facilities) : बैंक अपने ग्राहको को सुविधा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को धन भेजने की सेवा प्रदान करते हैं। यह सुविधा ड्राफ्ट (Draft) डाक तथा तार स्थानान्तरण (Mail and Telegraphic Transfers) द्वारा प्रदान की जाती है। इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान का धन सुरक्षित रूप से पहुँच जाता है। इस सेवा के लिए बैंक कुछ शुल्क भी लेते हैं।

(v) ग्राहको की ओर से प्रतिभूतियों का अध-विक्रय (Purchase and sale of shares and securities on behalf of the customers)- बैंक अपने ग्राहको की ओर से विभिन्न प्रकार के अशा ऋण पत्रों सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी प्रतिभूतियों का नया विक्रय करते हैं। इससे ग्राहको का प्रतिभूतिया खरीदन तथा बचन में दृढ़ी सुविधा हा जाती है और नया विक्रय का शर्तों में लाभदायक होती है।

(vi) प्रत्यासी तथा प्रबन्धक के रूप में कार्य करना (To act as Trustees and Administrators) बैंक अपने ग्राहको की ओर से प्रतिनिधि, मुत्तयार (Attorney), उत्तरसाधक (Executors), प्रत्यासी (Trustee) तथा प्रबन्धक (Administrator) के रूप में कार्य करते हैं।

(vii) ग्राहको की ओर से बिल स्वीकार करना (Acceptance of bills on behalf of the customers) : बैंक ग्राहको की ओर से बिलों को स्वीकृति

(Acceptance) प्रदान करते हैं जिससे व्यापारियों की साख बढती है और लेन-देन में उन्हें बड़ी सुविधा हो जाती है ।

(3) सामान्य उपयोगी सेवायें (General Utility Services).—मुख्य तथा अभिकर्ता कार्यों के अतिरिक्त बैंक व्यापार तथा समाज की कुछ अन्य सेवायें भी करते हैं जिन्हें सामान्य उपयोगी सेवायें कहते हैं । इनमें मुख्य निम्नलिखित हैं:—

(i) व्यापारिक निर्णयकर्ता के रूप में कार्य करना (To act as Trade Referees):—बैंक अपने ग्राहकों की साख तथा वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में व्यापारियों को सही सूचना तथा जानकारी देते हैं । इस सूचना से व्यापारियों को यह पता चल जाता है कि वे ग्राहकों को किस सीमा तक उधार दे और किन्हे उधार न दे । इससे व्यापारी उस हानि से बच जाते हैं जो अयोग्य फर्मों को साख देने से होती है । यह सूचना बड़ी सावधानी तथा जाच पड़ताल करके बैंक द्वारा दी जानी चाहिए और इसे पूर्ण गोपनीय रखना चाहिए ।

(ii) सुरक्षा सम्बन्धी काम (Safe Custody Functions):—ग्राहकों के जेवर, महत्वपूर्ण दस्तावेज, अश तथा प्रतिभूतियाँ और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की आग, चोरी इत्यादि से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बैंक कुछ मुख्य शाखाओं में विशेष प्रकार के लाकर्स (Lockers) या सेफ डिपोजिट वाल्ट्स (Safe deposit vaults) की सुविधा प्रदान करते हैं । विशेष रूप से भजबूत बने इन कमरों में लाकर्स होते हैं जहाँ ग्राहक अपनी मूल्यवान वस्तुएँ रख देता है । इन लाकर्स की दो चाबियाँ होती हैं एक ग्राहक के पास और एक बैंक के पास । जब ग्राहक को कुछ निकालना या रखना होता है तो बैंक के रजिस्टर में प्रविष्टि की जाती है और ग्राहक के हस्ताक्षर कराकर लाकर बैंक तथा ग्राहक दोनों द्वारा अपनी अपनी चाबी लगाकर खोला जाता है और फिर उसी प्रकार बन्द कर दिया जाता है । इस सुविधा के लिए बैंक कुछ शुल्क लेते हैं जो लाकर के आकार पर निर्भर करता है ।

(iii) साख-प्रमाण पत्र तथा यात्री चेक जारी करना (To issue Letters of Credit and Travellers Cheques).—व्यापार सम्बन्धी कार्यों के लिए विदेश जाने वाले ग्राहकों के लिए बैंक साख प्रमाण पत्र जारी करता है जिससे विदेशों में आसानी से माल उधार मिल जाता है । यात्री चेको द्वारा किसी स्थान पर रुपया प्राप्त किया जा सकता है और यानी नकदी ले जाने की जोखिम से बच जाता है । यात्री चेको पर कोई कमीशन नहीं लिया जाता ।

(iv) अशो तथा प्रतिभूतियों का अभिगोपन करना (Underwriting of Shares and Securities) : कम्पनियों, सरकार तथा अन्य व्यापारिक सत्वाओं द्वारा निर्गमित अशो, ऋण-पत्रो तथा प्रतिभूतियों के अभिगोपन का कार्य भी बैंकें करती हैं । इस प्रकार के अनुबधित राशि की प्रतिभूतियों के देचने का दायित्व और

न विक्रेता पर स्वयं खरीदने की प्रतिज्ञा कर लेती हैं। इससे नियंत्रण करने वाली सस्था निश्चित हो जाती है। इस कार्य के लिए बैंक कुछ कमीशन लेते हैं।

(v) व्यापारिक सूचना तथा आंकड़े इकट्ठा करना (Collection of Business Information and Statistics) बैंक व्यापारिक तथा वित्तीय गतिविधियों से सम्बन्धित सूचनाएँ तथा आंकड़े इकट्ठा करती है और उनका प्रकाशन करती है जिससे व्यापार तथा वित्त सम्बन्धी समस्याओं में रुचि रखने वाले लाभान्वित हो सके। बड़े बड़े बैंक अपनी पत्रिकाएँ प्रकाशित करते हैं जिनमें बैंकिंग तथा वित्तीय समस्याओं पर लेख तथा टिप्पणियाँ होती हैं।

(vi) विदेशी विनिमय-व्यवस्था (Foreign Exchange Management) : दश के व्यापारियों का विदेशी व्यापारियों से लेन देन कराने में बैंको का विशेष योगदान होता है। विदेशी विनिमय बिलों का बट्टा कर वे विदेशी विनिमय-व्यवस्था करती हैं। इससे बैंको को भी लाभ होता है। भारत में विदेशी विनिमय बैंक (Foreign Exchange Banks) इस कार्य को करती हैं परन्तु अब भारतीय व्यापारिक बैंको ने इस क्षेत्र में अपने कार्य का विस्तार किया है।

(vii) वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करना (To act as financial adviser) वित्तीय समस्याओं के विशेषज्ञ होने के कारण बैंक अपने व्यापारी ग्राहकों को वित्तीय विषयों पर परामर्श देते हैं और इस प्रकार व्यापार की समूल्य सेवा करते हैं।

उपर्युक्त कार्यों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि बैंको की आधुनिक व्यापारिक जगत में बड़ी उपयोगिता है।

बैंको का महत्व (Importance of Banks)

किसी भी देश की अर्थ व्यवस्था के सफल संचालन तथा आर्थिक विकास के लिए एक सुसंगठित तथा उन्नत बैंकिंग व्यवस्था की अति आवश्यकता है। आज की उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था की सफलता बैंका की कार्यकुशलता पर निर्भर है। योरोप में यदि 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में बैंको का विकास न हुआ होता तो शायद वहाँ औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution) न आयी होती। किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए पूँजी की बड़ी आवश्यकता है परन्तु पूँजी के प्रयोग की सुविधा बैंक ही प्रदान करती है। बचत को प्रोत्साहित कर अप्रयुक्त धन को उद्योगों तथा व्यापार में विनियोजित कर वे देश के आर्थिक विकास में सहायता पहुँचाती हैं। टामस के शब्दों में "बैंक साख पत्रों के चलन तथा निर्माण को संगठित तथा नियंत्रित करती हैं, वे ऋण तथा अग्रिमों के रूप में बैंक साख की स्वीकृति का नियंत्रण करती हैं, वे उधार देय पूँजी के विनियोजन को सुविधाजनक बनाती हैं तथा उसका सबसे लाभदायक प्रयोग तथा वितरण सम्भव बनाती हैं, जब और जहाँ

चलन की आवश्यकता होती है उसको पूर्ण करती हैं तथा कुछ क्षेत्रों के अत्यधिक चलन को कम पूर्ति वाले स्थानों की स्थानान्तरित करती हैं।¹ इसी कारण बैंक के महत्व को स्वीकार कर अर्थशास्त्रियों ने बैंकों को आधुनिक व्यापारिक तथा औद्योगिक व्यवस्था का हृदय, केन्द्र बिन्दु, धमनिया (nerve centre) आदि कहा है। देशों के आर्थिक विकास में व्यापारिक बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका उनकी निम्न-लिखित उपयोगिताओं से स्पष्ट होती है —

(1) व्यापार तथा उद्योगों की उन्नति में सहायक (Helpful in the Development of Trade and Industry) पिछले 200 वर्षों का आर्थिक विकास व्यापार के विस्तार तथा औद्योगीकरण पर आधारित रहा है और व्यापार बिना मुद्रा के प्रयोग के नहीं हो सकता। मुद्रा की तुलना में बैंक निलेपो का अधिक महत्व है। आन्तरिक तथा विदेशी व्यापार बिलों के माध्यम से होता है जिनका बट्टा बैंक ही करती है। अप्रयुक्त धन तथा बचतों को जमाकर व्यापार तथा उद्योग की वित्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर बैंक महत्वपूर्ण सेवा करते हैं। बैंकों की सहायता के बिना आधुनिक व्यापार तथा वाणिज्य की कल्पना नहीं की जा सकती।

(2) पूंजी निर्माण तथा बचत को प्रोत्साहन (Banks promote capital formation and Savings) : विभिन्न वर्गों के लिए सुविधाजनक जमा खाते खोलकर बैंक बचत को प्रोत्साहित करती है। लोगों में बचत की आदत डालने में बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार पूंजी का निर्माण होता है जो देश का आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण शर्त है।

(3) उपयुक्त प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन (Banks encourage the right type of industries) : अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की सुविधा प्रदान कर बैंक उपयुक्त प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन देती हैं। वे केवल औद्योगीकरण में ही सहायक नहीं बल्कि समाज का इच्छानुकूल आर्थिक विकास करती हैं क्योंकि वे ऐसे साहसियों को वित्त सहायता देती हैं जिनके माल की बाजार में मांग हाती है।

(4) क्षेत्रीय आधार पर कोषों के उपयुक्त वितरण में सहायक (Banks help in distribution of funds between regions) . बैंक पूंजी को अत्याधिक

¹ "Banks organise and control the issue and currency of credit instruments, they regulate the granting of banks credit in the form of advances and loans, they facilitate the investment of loanable capital and make possible its distribution and use to the best advantage, they provide currency when and where it is required and transfer surplus currency from some area to places that are short of supplies"

पूति वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को स्थानान्तरित कर देती है जिससे उसका अधिक लाभदायक तथा कार्य क्षम प्रयोग हो सके। पूंजी का इस प्रकार स्थानान्तरण पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है और क्षेत्रीय असन्तुलनों (Regional imbalances) में कमी होती है।

(5) साख का सृजन कर व्यापारिक विकास में सहायक (Bnks create Credit and help in Business Expansion) बैंक साख का सृजन कर समाज तथा व्यापार की बड़ी सहायता करते हैं। साख के विस्तार से साहसियों को अधिक धन प्राप्त होता है जिससे विनियोजन बढ़ता है। एक विकासशील अर्थ व्यवस्था में बैंक साख के विस्तार द्वारा उद्योगों को अधिक धन प्राप्त होता है और आर्थिक विकास की गति तीव्र होती है।

(6) मुद्रा प्रणाली में लोच (Elasticity in the Monetary System) - बैंक मुद्रा प्रणाली में लोच पैदा करते हैं। अर्थ व्यवस्था की आवश्यकतानुसार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि तथा कमी करके मांग और पूति में सन्तुलन स्थापित करते हैं। यह साख के विस्तार या सकुचन द्वारा किया जाता है।

इस प्रकार बैंको का देश के व्यापार, उद्योग तथा वाणिज्य की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान है। देश के औद्योगिक विकास का आधार विकसित बैंकिंग प्रणाली ही हो सकती है।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संकेत

(1) एक आधुनिक बैंक के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि बैंकर अपने कोषों का विनियोजन करते समय किन बातों का ध्यान रखता है ?
(राजपूताना बी० काम०, 1958)

[संकेत—प्रथम भाग में बैंको के मुख्य, अभिकर्ता तथा सामान्य उपयोगी कार्यों का वर्णन संक्षेप में कीजिए। दूसरे भाग में बैंक कोषों का विनियोजन करते समय जो बातें ध्यान रखता है उनका विवेचन कीजिए। दूसरे भाग के लिए 'बैंक की विनियोग नीति' अध्याय देखिए।]

(2) व्यापारिक बैंको के कार्यों की व्याख्या कीजिए। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में उनका क्या महत्व है ?
(आगरा, 1960)

[संकेत—प्रश्न (1) की तरह ही प्रथम भाग में बैंक के मुख्य, अभिकर्ता तथा सामान्य उपयोगी कार्यों का वर्णन कीजिए। दूसरे भाग में बैंको का महत्व बताइये।]

बैंको द्वारा साख-सृजन (Credit Creation by Banks)

"If all the insured people conspire to die on the same day, the insurance companies will fail banking similarly is based on certain assumptions which enable the bankers to create a vast credit structure"

आधुनिक समय में बैंको के कार्यों में उनके द्वारा साख सृजन का महत्वपूर्ण स्थान है। देश के व्यापार तथा वाणिज्य की आवश्यकतानुसार बैंक साख का सृजन कर देश की बहुत बड़ी सेवा करती हैं। उनके द्वारा साख सृजन का कार्य देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है और इस प्रकार वे ग्रथ व्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं।

साख सृजन की विधि (Method of Credit Creation)

व्यापारिक बैंक साख का सृजन निम्नलिखित तरीका से करती हैं—

(1) बैंक द्वारा नोट निगमन करके साख सृजन (Creation of Credit by Issue of Notes) नोट निगमन करते समय शत प्रतिशत धात्विक कोप न रखना साख सृजन का ही रूप है। प्रारम्भ में जनता का विश्वास बनाये रखने तथा नोटों की परिवर्तन शीलता (Convertibility) बनाये रखने के लिए नोट निगमन के पीछे शत प्रतिशत धात्विक कोप रखे जाते थे परन्तु अब किसी देश में भी यह प्रणाली प्रचलन में नहीं है। आजकल कुछ थोड़ा धात्विक कोप रखकर अधिक नोटों का निगमन किया जाता है जो साख सृजन का ही एक रूप है। परन्तु नोट निगमन का अधिकार अब व्यापारिक बैंको से लेकर केन्द्रीय बैंक को दे दिया गया है और इस प्रकार के साख सृजन का एकाधिकार सभी देशों में केन्द्रीय बैंक को ही प्राप्त है।

(2) नकद जमा तथा साख जमा द्वारा साख सृजन (Creation of Credit through Cash Deposits and Credit Deposits) नकद जमा तथा साख जमा द्वारा साख सृजन की रीति अति महत्वपूर्ण है। यह बड़ी आवश्यकता है कि किसी देश में मुद्रा की मात्रा की तुलना में बैंको के निक्षेप कई गुना अधिक होते हैं। एक बैंक अपनी नकद तथा अल्प जमाओं की तुलना में कई गुना

अधिक ऋण देने में कैसे समर्थ हो जाता है ? यही साख-सृजन बैंको की विशेषता है । साख सृजन की इस रीति की विस्तृत व्याख्या इस प्रकार है :—

बैंको को जमायें दो प्रकार की होती हैं

(1) नकद जमा या प्रारम्भिक जमा (Cash Deposit or Primary Deposits)

(2) साख जमा या व्युत्पन्न जमा (Credit Deposit or Derivative Deposits)

नकद जमायें या प्रारम्भिक जमायें वे जमायें हैं जो जमाकर्ता बैंको के पास नकदी में जमा करते हैं । यह नकद जमायें बैंक अपने पास बेकार पड़े रखने के लिए नहीं स्वीकार करती बल्कि व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा अन्य लोगों को ऋण के रूप में देती है । इस प्रकार बैंक लाभ कमाती हैं । यह नकद जमायें ही वास्तव में साख-सृजन का आधार हैं । नकद जमाओं का कुछ भाग बैंक अपने पास रख कर शेष ऋण के रूप में दे देती हैं । बैंक जो धन ऋण के रूप में देते हैं वह नकद न दफ्तर ग्राहको को बैंक से राशि निकालने के अधिकार (Power to withdraw from the bank) के रूप में दिया जाता है । ऋण के रूप में स्वीकृत राशि खाते में जमा कर दी जाती है । इसे ही साख जमा (Credit Deposit) कहते हैं । साख जमाओं का जन्म नकद जमाओं द्वारा होता है अतः साख जमाओं को व्युत्पन्न जमायें (Derivative Deposits) या ऋण जमायें (Loan Deposits) भी कहा जाता है । साख जमाओं या व्युत्पन्न जमाओं का सृजन ही साख निर्माण के तुल्य है ।¹ आधुनिक समय में नकद जमाओं की तुलना में साख जमाओं का अधिक महत्व है । इंग्लैण्ड की चर्चा करते हुए हाटले विद्वान ने कहा है कि 'वहाँ के पाँच सबसे बड़े बैंको की 1666 मिलियन पौड की कुल जमाओं में 1249 मिलियन साख जमायें हैं और केवल 417 मिलियन पौड की नकद जमायें ।' "आधुनिक अंग्रेजी वाणिज्य तथा वित्त की मुद्रा चेक है और लन्दन मुद्रा बाजार में प्रचलित साख चेक लिखने का अधिकार ही है ।"²

¹ "The creation of derivative deposit is identical with what is commonly called the creation of credit"

—G N Halm *Monetary Theory*, p 39

² Referring to Great Britain, Mr Hartley Withers has remarked that "out of the total deposits of the five biggest commercial banks amounting to 1666 million pounds, 1249 million consists of credit deposits and only 417 million of cash deposits"

"The money of modern English commerce and finance is the cheque and the credit dealt in the London Money Market is the right to draw a cheque"

—Hartley Withers

नकद जमाओं के ही कारण बैंक ऋण देने में समर्थ हो पाती हैं और दिया हुआ प्रत्येक ऋण साख जमा (Credit Deposit) का रूप ग्रहण कर लेता है। इसे एक सरल उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। माना कि किसी बैंक के पास नकद जमा या प्रारम्भिक जमा के रूप में 100 रुपये की राशि है। कानूनी मान्यता तथा स्वयं के अनुभव से यदि बैंक 20 प्रतिशत नकद कोप रखने का निर्णय करता है क्योंकि इससे अधिक नकदी जमाकर्ता एक समय में मागने के लिए नहीं आयेंगे तो $100 - 20 = 80$ रुपये बैंक किसी को ऋण के रूप में दे देगा। यह 80 रुपये नकद न देकर बैंक ऋणी को खाते में जमा करके उसे रुपया निकालने के अधिकार के रूप में देगा। इसी प्रकार 80 रुपये का 20 प्रतिशत 16 रुपये बैंक अपने पास नकद रखकर $80 - 16 = 64$ रुपये किसी अन्य व्यक्ति को उधार दे देगा। यह 64 रुपये की राशि भी इस ऋणी के खाते में जमा कर दी जायेगी। यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। इस प्रकार 100 रुपये की नकद जमा पर बैंक $80 + 64 + \dots + \dots$ इत्यादि की व्युत्पन्न जमा का सृजन कर लेता है। 100 रुपये की नकद जमा के आधार पर बैंक 400 रुपये तक के ऋण दे देता है और कुल नकद तथा साख जमायें 500 रुपये की हो जाती हैं। इस प्रकार बैंक अपनी नकद जमा का कई गुना साख सृजन करने हैं।

इसी आधार पर कहा जाता है कि ऋण जमा का निर्माण करते हैं (Loans create deposits) और जमायें ऋणों का सृजन करती हैं (Deposits create loans)। लार्ड कीन्स के शब्दों में “ऋणों का जमाओं से जन्म होता है और जमाओं का ऋणों से।”¹ सेयर्स ने भी कहा है कि “बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली सत्ता ही नहीं है बरन्, एक महत्वपूर्ण अर्थ में मुद्रा के सृजनकर्ता भी हैं।”² अतः बैंकों के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि “बैंक बिना बोये ही फसल काट लेती हैं।” (The Banks reap where they have not sown)

एक अन्य उदाहरण द्वारा भी बैंकों की भाव सृजन प्रक्रिया को स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ हम यह मान लेते हैं :

(अ) A, B, C, D, इत्यादि बहुत से बैंक हैं और उनके अलग अलग जमाकर्ताओं के समूह हैं,

(ब) परम्परा तथा कानून के अनुसार प्रत्येक बैंक 20 प्रतिशत नकद कोप रखता है,

¹ “Loans are the children of deposits and deposits are the children of loans”
—J. M. Keynes.

² “Banks are not merely purveyors of money, but also, in an important sense, manufacturers of money”

(स) बैंक A के पास 1000 रुपये की नयी जमा रकमी गई है।

जब बैंक A के पास 1000 रुपये जमा कराये गये तो इस नये सौदे को ही ध्यान में रखकर बैंक का स्थिति विवरण इस प्रकार होगा:—

TABLE 1

Bank A

1000 रुपये की जमा प्राप्त होने के समय की स्थिति

Liabilities		Assets	
New Deposit	Rs 1000	New Cash	Rs. 1000
Total	Rs 1000	Total	Rs. 1000

दोहरे लेखा प्रणाली के अन्तर्गत 1000 रुपया दोनों ओर दिखाया जायेगा। 1000 रुपया बैंक की देनदारी है क्योंकि बैंक इसे जमाकर्ता को वापिस करेगा, यह 1000 रुपया बैंक का आदेय है जिससे बैंक ब्याज कमा सकता है। यदि बैंक A शत प्रतिशत नकद कोष रखे तो बैंक अधिक जमाग्रो का सृजन नहीं कर सकेगा और बैंक अपनी जमा का चार गुना ऋण नहीं दे सकेगा। एक अकेला बैंक यदि शत प्रतिशत कोष रखे तो Table 2 से दिखाई गई स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता।

TABLE 2

Bank A

अकेले बैंक के लिए असम्भव स्थिति

Liabilities		Assets	
Deposits	Rs. 5000	Cash	Rs 1000
		Loans & Investments	Rs. 4000
Total	Rs 5000	Total	Rs. 5000

परन्तु यदि बैंक A केवल 20 प्रतिशत नकद कोष रखता है तो 200 रुपया नकद रखकर शेष 800 रुपये वह लाभकारी विनियोग में लगा सकता है। माना कि बैंक A 800 रुपये Mr X को ऋण के रूप में देता है जिसे Mr. X अपने ऋणदाताग्रो को भुगतान में दे देते हैं। जब X 800 रुपये बैंक A से निकाल लेता है तो Bank A की स्थिति Table 3 में दिखाई गई है।

TABLE 3
Bank A
ऋण देने के बाद की स्थिति

Liabilities		Assets	
Deposits	Rs 1000	Cash	Rs 200
		Loan to X	Rs 800
Total	Rs 1000	Total	Rs 1000

अब यह माना कि X के लेनदारो ने जो 800 रुपया प्राप्त किया उसे उन्होने अपने बैंक B में जमा कराया। तब Bank B की स्थिति Table 4 में दिखाई गई है।

TABLE 4
Bank B
बैंक A द्वारा दिये गये ऋणों का धन बैंक B में जमा कराने के समय की स्थिति

Liabilities		Assets	
New Deposits	Rs 800	New Cash	Rs 800
Total	Rs 800	Total	Rs 800

Bank B अनुभव करता है कि उसके पास नकदी आवश्यकता से अधिक है। अब वह भी 20 प्रतिशत नकद कोष रखकर अर्थात् 160 रुपये (800 रुपये का 20%) रखकर शेष 640 रुपये किसी को ऋण दे देता है। माना कि 640 रुपये का ऋण वह Y को देता है तो बैंक B की स्थिति Table 5 में दिखाई गई है।

TABLE 5
Bank B
नई जमा का 80 प्रतिशत ऋण देने पर बैंक की स्थिति

Liabilities		Assets	
Deposits	Rs 800	Cash	Rs 160
		Loan to Y	Rs 640
Total	Rs 800	Total	Rs 800

ठीक उसी प्रकार Y भी प्राप्त राशि को अपने लेनदारो को जुगतान स्वरूप देता है जिसे वे अपनी बैंक में जमा करते हैं। माना कि 640 रुपये उन लेनदारो ने अपने बैंक C में जमा कराया तो बैंक C की स्थिति इस प्रकार होगी।

TABLE 6

Bank C

बैंक B द्वारा दिए गये ऋण की राशि बैंक C में
जमा कराने के समय की स्थिति

Liabilities		Assets	
New Deposits	Rs. 640	New Cash	Rs. 640
Total	Rs. 640	Total	Rs. 640

अब बैंक C अपनी 640 की जमा का 20 प्रतिशत अर्थात् 128 रुपये नकद कोष के रूप में रखकर शेष 512 रुपये Z को उधार दे दता है। उधार देने के बाद Bank C की स्थिति Table 7 में दिखाई गई है।

TABLE 7

Bank C

नई जमा का 80 प्रतिशत उधार देने के बाद की स्थिति

Liabilities		Assets	
Deposits	Rs 640	Cash	Rs 128
		Loan to Z	Rs 512
Total	Rs 640	Total	Rs. 640

अब Z, जिसने Bank C से 512 रुपये ऋण के रूप में प्राप्त किए, यह धन अपने लेन दारों को भुगतान में देगा और वे फिर इसे अपने बैंको में जमा करेंगे। वे बैंक फिर 20 प्रतिशत नकद कोष रखकर शेष राशि उधार दे देंगे। इस प्रकार जमाओं का ऋणों के रूप में परिवर्तन और फिर ऋणों का नई जमाओं में परिवर्तन का यह क्रम चलता रहेगा जब तक कि 1000 रुपये की प्रारम्भिक जमा समाप्त न हो जाय। बैंको द्वारा बैंक जमाओं का सृजन सचेप में इस प्रकार होगा :—

TABLE 8

बैंक	जमायें	नकद कोष	ऋण
A	1,000 00	200 00	800 00
B	800 00	160 00	640 00
C	640 00	128 00	512 00
D	512 00	102 40	409 60
E	409 60	81 92	327 68
F	327 68	65 54	262 14
G	262 14	52 42	209 72
H	209 72	41 95	167 77
I	167 77	33 55	134 22
J	134 22	26 85	107 37
प्रथम 10 बैंको का योग	4,463 13	892 63	3,570 50
अन्य बैंको का योग	536 87	107 37	429 50
बैंकिंग व्यवस्था का कुल योग	5,000 00	1,000 00	4,000 00

इस प्रकार स्पष्ट है कि 1000 रुपये की जमा द्वारा बैंकिंग व्यवस्था ने 4000 रुपये की जमाओं का सृजन किया और कुल योग 5000 रुपये हुआ। कुल जमाओं का सृजन नकद कोष के प्रतिशत का ठीक उल्टा होता है। यदि नकद कोष 20 प्रतिशत या $\frac{2}{10}$ रखा जाता है तो साख-सृजन $\frac{5}{2}$ या प्रारम्भिक जमा का 5 गुना होगा। अतः यह सिद्ध है कि तालिका 2 की असम्भव स्थिति पूरी बैंक व्यवस्था को साख सृजन प्रक्रिया ने सम्भव बना दी। यदि सभी बैंको का मिला जुला स्थिति विवरण बनाया जाय तो वह तालिका 9 की तरह होगा।

TABLE 9

सभी बैंको का सम्मिलित स्थिति विवरण

(Consolidated Balance Sheet showing final position of all banks together)

Liabilities		Assets	
Deposits	Rs 5000	Cash	Rs. 1000
		Loans	Rs 4000
Total	Rs 5000	Total	Rs. 5000

यदि तालिका 2 तथा तालिका 9 की तुलना की जाय तो वे एक समान हैं। सभी बैंको ने मिलकर उसे सम्भव बना दिया जो एक बैंक के लिए असम्भव था। (The whole banking system can do what no one bank can do by itself) इसी बात को साधारण एलजेबरा द्वारा इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है —

$$\begin{aligned} \text{Rs } 1,000 + \text{Rs } 800 + \text{Rs } 640 + \dots &= \\ \text{Rs } 1000 \left[1 + \frac{4}{5} + \left(\frac{4}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^3 + \dots \right] &= \\ = \text{Rs } 1000 \left(\frac{1}{1 - \frac{4}{5}} \right) &= \\ = \text{Rs. } 1,000 \times 5 &= \\ = \text{Rs } 5,000 & \end{aligned}$$

साख सृजन की इस प्रक्रिया को 'गुणित-साख-विस्तार' (Multiple Credit Expansion) कहते हैं। इस सम्बन्ध में प्रो० जी० एन० हाम के शब्द उद्धरण योग्य है —

"Multiple credit expansion increases the circulation of common money because the resulting increase in the amount of business turnover involves cash payments and correspondingly decreases the available cash reserves"

'गुणित साख विस्तार' का मंकमिलन समिति (Committee on Finance and Industry U K) ने इन शब्दों में समर्थन किया है —

"All these commercial banks in turn expand their loans again, part of the additional reserve which they have previously gained will pass over to other banks, until in the end, the increased reserves are spread over the system as a whole, supporting a large volume of loans and deposits"¹

क्या बैंक वास्तव में साख-सृजन करते हैं ?

(Do Banks really create Credit ?)

बैंको द्वारा साख सृजन के सम्बन्ध में अर्थ-शास्त्रियों में कुछ मतभेद हैं। सर्वश्री हार्टले विदर्स, आर० एस० सेयर्स, सेलिगमैन तथा जे० एम० कीन्स इत्यादि अर्थ शास्त्री इस बात के समर्थक हैं कि बैंक साख-सृजन करती है परन्तु डा० वाल्टर लोफ तथा एडविन कैनन इसे स्वीकार नहीं करते।

हार्टले विदर्स का विचार है कि "ऋण जमा को जन्म देते हैं और उनके सृजन का श्रेय बैंक को है।" ("Loans make deposits and the initiative of

¹ Report of the Committee on Finance and Industries (U K.) 1931, p 12

creating them goes to the bank ") परन्तु डा० वाल्टर लीफ तथा एडविन कैनन ने इसका विरोध किया है । उनके अनुसार साख-सृजन का श्रेय बैंक को न होकर जमाकर्त्ता को है । यदि जमाकर्त्ता अपनी राशि बैंक के पास न छोड़कर स्वयं उपभोग कर ले और ऋणी ऋण की रकम नकदी में प्राप्त कर ले तो साख-सृजन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । एडविन कैनन (Edwin Cannon) के शब्दों में "बैंकिंग साख का सृजन बैंको द्वारा नहीं बल्कि उन ग्राहकों के द्वारा होता है जो उनके लिए आवेदन देते हैं तथा उन जमानतों द्वारा होता है जो ब लाते हैं" "प्रत्येक व्यावहारिक बैंकर जानता है कि वह साख, मुद्रा या अन्य किसी वस्तु का सृजनकर्त्ता नहीं है बरन् ऐसा व्यक्ति है जो उन लोगों, जिनके पास साधन हैं, से उन व्यक्तियों को जो उनका प्रयोग कर सकते हैं, ऋण दिलाने की सुविधाजनक बनाता है ।" कैनन ने अपने मत के समर्थन में यह कहा है कि यदि जमाकर्त्ता अपनी जमा राशि बैंक से वापस ल ल तो बैंक की इस साख सृजन प्रक्रिया की असत्यता प्रकट हो जायेगी । इस सम्बन्ध में उन्होंने लबादा गृह (Cloak Room) का उदाहरण दिया है । किसी पार्टी में जाने से पूर्व अतिथिगण यदि अपने लबादे लबादा-गृह (Cloak Room) में जमा करा देते हैं तो उन लबादों को ऐसे व्यक्तियों को उधार दिया जा सकता है जो पार्टी समाप्त होने के पहले उन्हें लौटा दें । इस प्रकार लबादा गृह का व्यक्ति खाली समय में लबादे प्रयोग करने की सुविधा अवश्य देता है परन्तु लबादों का निर्माण नहीं करता । इसी प्रकार बैंक जमा राशि के प्रयोग करने की सुविधा अवश्य देता है, साख का सृजन नहीं करता । इसी प्रकार डा० वाल्टर लीफ भी यह मानते हैं कि बैंक जो कुछ जमायें प्राप्त करते हैं उससे अधिक उधार नहीं दे सकत । उनके अनुसार भी जमाकर्त्ता ही साख के सृजनकर्त्ता हैं क्योंकि बैंक उनकी जमाओं के आधार पर ही साख का सृजन करते हैं ।

आज सभी स्वीकार करते हैं कि बैंक साख का सृजन करते हैं । बैंको द्वारा साख सृजन का व्यापार और वाणिज्य के लिये बड़ा महत्व है और इसे स्वीकार न करना उपयुक्त नहीं । अतः वाल्टर लीफ तथा कैनन का विरोध अधिक तर्क सम्मन नहीं कहा जा सकता ।

1 ".....Banking credits are manufactured, not by banks, but by the customers who apply to them and by the security that the customers bring....."

"Every practical banker knows that he is not a creator of credit or money or anything else, but a person who facilitates the lending of resources by the people who have lend them to those who can use them"

—Edwin Cannon : *An Economist's Protest*, p. 382

बैंको की साख-सृजन शक्ति की सीमायें (Limitations of Credit Creation by Banks)

बैंको की साख सृजन की शक्ति असीम नहीं है उसकी अपनी सीमायें हैं। प्रो० वेनहम ने बैंक की साख सृजन की तीन सीमायें बताई हैं—विधि ग्राह्य मुद्रा की मात्रा, तरलता पसन्दगी तथा जमाओं के साथ नकद कापो का अनुपात। इनके अतिरिक्त बैंको की साख सृजन शक्ति की अन्य सीमायें भी हैं

1 देश में विधि ग्राह्य मुद्रा की मात्रा (The quantity of Legal tender money in the country) बैंको की साख सृजन की शक्ति उस देश में प्रचलित विधि ग्राह्य मुद्रा की कुल मात्रा पर निर्भर करती है। जिस देश में विधि ग्राह्य मुद्रा की मात्रा अधिक होगी वहा बैंक अधिक साख का सृजन कर सकेंगे। मुद्रा की मात्रा की वृद्धि से प्रारम्भिक जमायें बढ़ जाती हैं और प्रारम्भिक जमायें बढ़ जाने से बैंको की साख सृजन की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिये काउचर ने कहा है 'The bank's cash is the lever with which the whole gigantic system is manipulated'

2 तरलता पसन्दगी या जनता की बैंकिंग की आदत (Liquidity Preference or Banking Habit of the people) तरलता पसन्दगी अर्थात् नकद मुद्रा की वह मात्रा जो जनता अपने पास रखना चाहती है बैंको की साख सृजन की शक्ति को प्रभावित करती है। यदि जनता नकदी में अधिक व्यवहार करती है और बैंक से अधिक रुपया निकालती है तो बैंको की नकद जमायें कम हो जाती हैं और उनके द्वारा निर्मित साख का सकुचन हो जाता है। यदि जनता में बैंकिंग की आदत विकसित है और लोग चेक आदि साख पत्रों के माध्यम से भुगतान करते हैं तो बैंको की नकद जमायें अधिक होंगी और वे अधिक साख का सृजन कर सकेंगे। इसीलिये विकसित देशों में बैंको द्वारा अधिक साख का सृजन होता है।

3 जमाओं के साथ नकद कोषों का अनुपात (Proportion of Cash Reserves to Total Deposits) देश में विधि ग्राह्य मुद्रा की मात्रा के अतिरिक्त जमाओं के साथ नकद कोषों का अनुपात बैंको की साख सृजन शक्ति को प्रभावित करता है। हम पहले यह चर्चा कर चुके हैं कि साख सृजन सक्रम कोष अनुपात का ठीक उल्टा होता है। यदि परम्परा तथा कानून की मायता के अनुसार बैंक 20 प्रतिशत या $\frac{1}{5}$ नकद कोष रखता है तो बैंक नकद जमाओं का 5 गुना या $\frac{1}{5}$ साख सृजन कर सकेगा और यदि बैंक 10 प्रतिशत या $\frac{1}{10}$ नकद कोष रखता है तो नकद जमाओं का 10 गुना या $\frac{1}{10}$ साख सृजन होगा। (The lower the proportion of cash reserve to total deposits, the higher the capacity of the bank to create credit and vice versa).

4. प्रतिभूतियों का स्वरूप (Nature of Securities) जब तक उपयुक्त प्रकार की जमानतें उपलब्ध न हो तब तक बैंक ऋण तथा भ्रष्टिम देकर जमाओं का विस्तार नहीं कर सकते। ऋण के शब्दों में 'बैंक शून्य से साख का सृजन नहीं करते, वे केवल किसी अन्य प्रकार के धन को मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं।' किसी भी देश में आय प्रदान करने वाली कुल प्रतिभूतियों की मात्रा बैंको द्वारा साख सृजन की अधिकतम सीमा का निर्धारण करती है।

5. व्यापार की स्थिति (Nature of business conditions) बैंको द्वारा साख सृजन व्यापारिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बैंक किसी को ऋण लेने के लिये वाध्य नहीं कर सकती। ऋण तभी लिये जाते हैं जब उपयुक्त विनियोग के अभावसे उपलब्ध हो। मन्दी काल में जमाओं में कमी आ जाती है और साख का सृजन कम होता है। तेजी काल में ऋणों की माग अधिक होती है और बैंको की साख सृजन की शक्ति बढ़ जाती है।

6 साख सृजन के क्रम में क्षरण (Leakages in credit creation) साख सृजन के क्रम में कुछ क्षरण के कारण अधिकतम साख विस्तार तथा वास्तविक साख विस्तार में अन्तर हो सकता है (अ) बैंक के पास जो अधिक कोष है वह पूरा हो उधार दे दिया जाय, यह आवश्यक नहीं। ऋण कोष से जितना कम होगा, साख सृजन भी कम होगा। (ब) सभी ऋणी ऋण की कुल राशि बैंक में न रखकर अपने पास रख सकते हैं और फिर प्रत्येक स्तर पर नये जमायें ऋणों की कुल राशि से कुछ कम होगी। उस सीमा तक साख सृजन भी कम होगा।

7. केन्द्रीय बैंक की नीति (Policy of the Central Bank) केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति बैंको की साख सृजन की शक्ति की नियमन करती है। बैंक दर खुले बाजार की क्रियाओं, नकद कोष के अनुपात में परिवर्तन इत्यादि साख नियन्त्रण के साधनों का प्रयोग कर केन्द्रीय बैंक साख की मात्रा का दश हित में नियन्त्रित करती है।

उपयुक्त सीमाओं के विवेचन से स्पष्ट है कि बैंक एक सीमा के अन्दर ही साख सृजन कर सकती है।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संकेत

1 व्याख्या कीजिये कि बैंक साख-निर्माण कैसे करते हैं। साख निर्माण करने में बैंक की शक्तियों की क्या कोई सीमा भी है? यदि है तो उसकी व्याख्या करें।
(राजस्थान टो० डी० सी० फाइनल, 1967)

2. "Banks do not create money out of thin air, it transmutes other forms of wealth into money"
—Crowther

[सकेत-बैंको द्वारा साख सृजन की विधि का उदाहरणों सहित विस्तृत विवेचन कीजिये तथा बैंको की साख सृजन की शक्ति की सीमाये बताइये ।]

2. बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली सस्था ही नहीं, वे एक महत्वपूर्ण अर्थ म मुद्रा के सृजनकर्ता भी है ।” (सेयर्स) इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये ।

(राजस्थान वी० ए०, 1964)

[सकेत-सक्षेप मे यह बताइय कि बैंक का कार्य केवल जमायें स्वीकार करन तथा ऋण देने तक ही सीमित नहीं है वरन् उनका इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य साख वा सृजन करना है । बैंको द्वारा साख सृजन की विधि का विस्तार से उदाहरण सहित स्पष्टीकरण कीजिये ।]

3 “ऋण का सृजन जमा से होता है और जमा का सृजन ऋण से होता है ।” इस कथन की सूक्ष्म रूप से विवेचना कीजिये ।

(मगध वी० वाम०, 1963)

[सकेत-स्पष्ट कीजिये कि जमायें ऋण और ऋण जमायो को कैसे जन्म दते हैं और विस्तार से बैंको द्वारा साख सृजन की विधि का उदाहरणों सहित वर्णन कीजिये ।]

आधुनिक बैंकों के विभिन्न रूप (Types of Modern Banks)

"There is no line of demarcation with regard to the functions which a bank has to perform. An exchange bank may engage itself in commercial business as well, while indigenous bankers may not only invest their capital in long term industrial loans but also in side business as well"

बैंक ऋण देने तथा निक्षेप प्राप्त करने से सम्बन्धित सभी कार्य करती है परन्तु विशिष्टीकरण के इस युग में बैंक भी कुछ विशिष्ट प्रकार के कार्यों में दक्षता प्राप्त कर लेती हैं। विभिन्न व्यवसायों तथा क्षेत्रों की साख आवश्यकताओं की प्रकृति भिन्न-भिन्न होने के कारण एक ही बैंक के द्वारा सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव नहीं है। इसीलिए बैंकों ने कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही अपने कार्यों को सीमित रखा है और उसी रूप में उनको जाना भी जाता है। बैंकों को उनके कार्यों की विभिन्नता के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बाटा जाता है —

1. व्यापारिक बैंक (Commercial Banks)
2. कृषि बैंक (Agricultural Banks)
3. औद्योगिक बैंक (Industrial Banks)
4. विदेशी विनिमय बैंक (Foreign Exchange Banks)
5. स्वदेशी बैंकर्स (Indigenous Bankers)
6. बचत बैंक (Saving Banks)
7. केन्द्रीय बैंक (Central Bank)
8. अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (International Banks)

1. व्यापारिक बैंक (Commercial Banks) : व्यापारिक बैंक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वे बैंक हैं जो मुख्यतः व्यापारियों को अल्पकालीन ऋण तथा अग्रिम देते हैं। इनके द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की अवधि 3 महीने से 12 महीने तक की होती है। ये बैंक व्यापार की केवल अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति इसलिए करते हैं क्योंकि इन बैंकों को निक्षेप अल्पकाल के लिए ही प्राप्त होते हैं। अल्पकालीन निक्षेपों के रूप में प्राप्त कोषों को ये बैंक उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण के रूप में देने की स्थिति में नहीं होते। भारत के अधिकांश संयुक्त पूंजी बैंक व्यापारिक

बैंक ही हैं। व्यापार की वित्त व्यवस्था के अतिरिक्त ये बैंक बहुत से अन्य कार्य भी करते हैं जिनका विस्तृत विवरण अध्याय 12 में किया गया है। व्यापार के सदर्भ में इनका कार्य क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है और देश के आर्थिक संगठन में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ व्यापारिक बैंक अब विदेशी व्यापार की वित्त व्यवस्था में योगदान करने लगे हैं। जब हम केवल 'बैंक' शब्द का प्रयोग करते हैं और इसके पहले कोई विशेषण नहीं लगाते तो हमारा तात्पर्य व्यापारिक बैंक से ही होता है। हमारे देश में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बड़ोदा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक आदि मुख्य व्यापारिक बैंक हैं।

2. कृषि बैंक (Agricultural Banks) : कृषि की आर्थिक आवश्यकतायें तथा तत्सम्बन्धी समस्यायें व्यापार तथा उद्योग धन्वों की आर्थिक आवश्यकताओं तथा समस्याओं से भिन्न होती हैं। इसलिए जो बैंक व्यापार तथा उद्योग की वित्त-व्यवस्था करते हैं वे कृषि की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सामान्यतः असमर्थ होते हैं। अतः कृषि की पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशिष्ट बैंकों की आवश्यकता है। कृषि के लिए तीन प्रकार की पूंजी की आवश्यकतायें होती हैं। (1) अल्पकालीन पूंजी (Short term capital) कृषकों को बीज, खाद आदि खरीदने के लिए, लगान देने के लिए तथा दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 6 माह से एक साल तक के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। (2) मध्यम कालीन पूंजी (Intermediate term capital) कृषि से सम्बन्धित छोटे-मोटे औजार, बैल आदि खरीदने के लिए कृषकों को 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के लिए ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। (3) दीर्घकालीन पूंजी (Long term capital) भूमि खरीदने, उस पर बड़े पैमाने के स्थायी सुधार करने तथा सिंचाई आदि की व्यवस्था करने के लिए तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए ऋणों की आवश्यकता पड़ती है।

कृषकों की उपर्युक्त पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दो प्रकार के कृषि बैंक हैं। प्रथम, कृषि सहकारी बैंक (Agricultural Co-operative Banks) जो कृषकों की अल्पकालीन तथा मध्यकालीन पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। द्वितीय, भूमि बंधक बैंक (Land Mortgage Banks) जो कृषकों की दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इन दोनों प्रकार के बैंकों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

(अ) कृषि सहकारी बैंक (Agricultural Co-operative Banks) कृषि सहकारी बैंक कृषकों की अल्प तथा मध्यम कालीन पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हमारे देश में सहकारी बैंकों का संगठन स्तूपीकार (Pyramidal) है जिसमें ग्राम स्तर पर प्राथमिक साख समितियाँ (Primary Credit Societies) जिला

स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक (Central Co-operative Banks) तथा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक या शीर्ष बैंक (State Co-operative Bank or Apex Bank) कार्य करते हैं। ग्राम के दस या दस में अधिक व्यक्ति प्राथमिक साख समिति का गठन कर सकते हैं। ये साख समितियाँ अपने सदस्यों को श्रल्प तथा मध्यम वालीन ऋण देती हैं। जिल भर की प्राथमिक साख समितियाँ जिला सहकारी बैंक की सदस्य होती हैं और वही से उन्हें ऋण के रूप में काप प्राप्त होने हैं। जिला सहकारी बैंक राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक से सम्बद्ध होते हैं जो उनकी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इन राज्य सहकारी बैंको को रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त होते हैं।

(ब) भूमि-बन्धक बैंक (Land Mortgage Banks) कृषकों को भूमि क्रय करने तथा भूमि पर सुधार करने इत्यादि क लिए ऋण भूमि बधक बैंको द्वारा दिये जाते हैं। यह ऋण 5 वर्ष से 25 वर्ष तक के लिए दिये जाते हैं और इनका भुगतान आसान किस्तों में किया जाता है। ऋण देते समय भूमि को बधक (Mortgage) रखा जाता है। भूमि बधक बैंको का संगठन सहकारी तथा मिश्रित पूँजी आधार पर किया जाता है। भारत में ये बैंक मद्रास, महाराष्ट्र आदि राज्यों में अधिक सफल रहे हैं।

(3) औद्योगिक बैंक (Industrial Banks) : ऐसे बैंक जो उद्योगों की वित्त व्यवस्था करते हैं औद्योगिक बैंक कहलाते हैं। उद्योगों को 5 वर्ष से 20 वर्ष तक के लिए दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता होती है जिमकी पूर्ति व्यापारिक बैंक नहीं कर सकते। ये ऋण औद्योगिक बैंको द्वारा ही दिये जाते हैं। दीर्घकालीन ऋण देने के अतिरिक्त ये बैंक कम्पानियों के अण-पत्रों तथा ऋण-पत्रों का अभिगोपन (Underwriting of Shares and Debentures) करती हैं और औद्योगिक सम्स्याओं के सम्बन्ध में सलाह भी देते हैं। जर्मनी और जापान में इस प्रकार के बैंक बहुत सफल हुए हैं। भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले इस प्रकार के बैंक नहीं थे। बहुत पहले टाटा इन्डस्ट्रियल बैंक की स्थापना हुई थी जो असफल हो गया था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उद्योगों की वित्त-व्यवस्था के लिए बहूत से वित्त-निगमों की स्थापना की गई है जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation of India) राज्यों के औद्योगिक वित्त निगम (State Finance Corporations) औद्योगिक साख तथा बिनियोग निगम (Industrial Credit and Investment Corporation) इत्यादि। इन निगमों में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक कम्पनियों का पर्याप्त वित्तीय सहायता दी है और देश के बढत औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(4) विदेशी विनिमय बैंक (Foreign Exchange Banks): इन बैंको को

विनिमय बैंक भी कहते हैं। ये बैंक विदेशी व्यापार की वित्त व्यवस्था (Financing of Foreign Trade) करते हैं और विदेशी व्यापार में अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक लेन-दान की जटिलताओं को सरल बनाते हैं। ये बैंक विदेशी वित्त का प्रयत्न करके विदेशी भुगतान में सहायता पहुँचाते हैं। ब्रिटिश शासन काल में जिन देशों से भारत का अधिक व्यापार होता था उन देशों की बैंकों ने भारत में शाखाएँ खोलकर विदेशी व्यापार की वित्त व्यवस्था की। इसलिए इन विनिमय बैंकों को भारत में विदेशी विनिमय बैंकों के नाम से जाना जाने लगा। विदेशी व्यापार तथा विनिमय सम्बन्धी विशेष ज्ञान तथा विशाल पूँजी साधनों के कारण इन बैंकों का विदेशी व्यापार की वित्त व्यवस्था करने में पूरा एकाधिकार था और ये बैंक भारतीय व्यापारियों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाते थे। अब भारतीय व्यापारिक बैंक भी विदेशी व्यापार की वित्त व्यवस्था करने लगे हैं और इस ओर अधिक प्रयत्न हो रहे हैं।

(5) स्वदेशी बैंक (Indigenous Bankers) आधुनिक बैंकों के साथ प्राचीन बैंकिंग प्रणाली पर आधारित बैंक भी भारत में कार्य कर रहे हैं। इन्हें स्वदेशी बैंक के नाम से जाना जाता है। भारत की ग्राम्य व्यवस्था में इनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। स्वदेशी बैंक बैंकिंग व्यवसाय के साथ-साथ शर्फी, थोक व फुटकर व्यापार, आड़त इत्यादि ग्राम्य कार्य भी करते हैं। स्वदेशी बैंकों का मुख्य कार्य निक्षेप प्राप्त करना, ऋण देना तथा हुडियों में व्यवहार करना है। ये बैंक निक्षेपों का चेक द्वारा निकालने की सुविधा नहीं देते। ऋणों पर इनके द्वारा ली जाने वाली व्याज दर ग्राम्य बैंकों की तुलना में ऊँची होती है। इनकी कार्य प्रणाली बड़ी सरल तथा लचीली है परन्तु इसमें कुछ दोष भी पाये जाते हैं। स्वदेशी बैंक रिजर्व बैंक के नियन्त्रण से मुक्त हैं और उन्हें भारतीय मुद्रा बाजार के समन्वित भाग के अंग बनाने के रिजर्व बैंक के सभी प्रयत्न असफल रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वे अपने व्यावसायिक कार्य बन्द नहीं करना चाहते।

(6) बचत बैंक (Savings Banks) इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य जनता में मितव्ययिता की आदत डालना है। अमेरिका में इस प्रकार के बैंक अलग हैं परन्तु हमारे देश में बचत बैंकों का कार्य व्यापारिक बैंकों तथा डाकघरों द्वारा किया जाता है। इन बचत खानों में लोग अपनी छोटी-छोटी बचतों को जमा कर देते हैं और इन पर व्याज भी मिलता है। बैंकों में तो बचत खाते में चेक द्वारा राशि निकालने की सुविधा भी प्रदान की है। इन खातों में रुपया कितनी भी बार जमा कराया जा सकता है। कुछ बैंकों वष में अधिक से अधिक 100 बार रुपया निकालने की आज्ञा देती है।

(7) केन्द्रीय बैंक (Central Bank) केन्द्रीय बैंक, जैसा कि नाम से ही विदित है, देश की बैंकिंग व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था होती है। इसकी स्थापना साम

के उद्देश्य के लिए न होकर देश की बैंकिंग व्यवस्था का देश हित में संचालन करने के उद्देश्य से की जाती है। केन्द्रीय बैंक का प्रमुख कार्य बैंकिंग व्यवस्था का नियन्त्रण तथा नियमन करना होता है। देश की मौद्रिक नीति का निर्धारण तथा क्रियान्वयन का गुरुत्तर उत्तरदायित्व केन्द्रीय बैंक का ही है। सभी देशों में नोटों के निर्गमन का एकाधिकार केन्द्रीय बैंक को ही प्राप्त है। यह बैंको के बैंक (Banker's Bank) तथा सरकारी बैंक (Banker to the Government) का भी कार्य करता है। केन्द्रीय बैंक को देश की बैंक व्यवस्था का नेता, सलाहकार तथा शुभचिन्तक कहा जाता है। लगभग सभी देशों में केन्द्रीय बैंक है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक (Federal Reserve Banks) है परन्तु वे अलग-अलग न होकर एक केन्द्रीय बैंक व्यवस्था (Central Banking System) के ही अंग हैं। भारत का केन्द्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया है जिसकी स्थापना 1934 में की गई थी।

(8) अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank) : अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवहारों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बैंको की स्थापना की गई है—(1) अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों का बैंक (The Bank of International Settlement) की स्थापना 1930 में जर्मनी से क्षतिपूर्ति तथा प्रथम महायुद्ध के शरणों की समस्या का समाधान करने के लिए हुई थी। अब यह बैंक पश्चिमी योरोप के देशों के अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में व्यवहार करता है। (2) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) का गठन सयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्य देशों में अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग बढ़ाने के लिए हुआ था। इसका कार्य विदेशी भुगतानों को सुविधाजनक बनाना है और देशों की मुद्रा के विनिमय मूल्य में स्थिरता लाना है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अबाध गति से होता रहे। (3) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (International Bank for Reconstruction and Development), जिसे संक्षेप में विश्व बैंक कहा जाता है, विभिन्न देशों के पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए ऋण देता है। कोष तथा बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी।

बैंको के विभिन्न प्रकारों का उपर्युक्त विवेचन बैंकिंग व्यवस्था पर प्रकाश डालने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि अध्याय के प्रारम्भ में दिए उद्धरण से स्पष्ट है कि इन विभिन्न बैंको में भेद की रेखा बड़ी सूक्ष्म है और एक प्रकार की बैंक दूसरे प्रकार की बैंको के कुछ कार्य भी करती है। सभी बैंक अपनी विशेषता रखते हैं और एक सुदृढ़ तथा संगठित बैंकिंग व्यवस्था के अंग के रूप में सभी का महत्व है।

बैंकिंग संगठन

(Organisation of Banking)

व्यापारिक बैंक के संगठन की दो मुख्य रीतियाँ हैं :

- (अ) शाखा बैंकिंग (Branch Banking)
- (ब) इकाई बैंकिंग (Unit Banking)

कुछ समय पहले अर्थशास्त्रियों तथा बैंकरो में बड़ा वाद विवाद था कि इन दो बैंकिंग संगठनों—शाखा तथा इकाई बैंकिंग में कौन अधिक उपयुक्त तथा लाभदायक है। परन्तु अब इसका महत्व अध्ययन मात्र की दृष्टि से है; इस विवाद का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है।

(अ) शाखा बैंकिंग (Branch Banking)

इस प्रणाली के अन्तर्गत बैंकों की संख्या तो कम होती है परन्तु किसी बड़े नगर में स्थित अपने प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त बैंको की अनेक शाखाएँ देश के विभिन्न भागों में फैली रहती हैं। इस प्रणाली का सबसे सुन्दर रूप हमें इंग्लैंड में देखने को मिलता है। यह प्रणाली कनाडा, फ्रांस, जर्मनी तथा आस्ट्रेलिया आदि देशों में प्रचलित है। इंग्लैंड में तो 11 समाशोधन बैंको (Clearing Banks) में से पाच बड़ी बैंको (The Big Five)—मिड लैंड, लायड्स, बकलेज, नेशनल प्राविन्सियल तथा वेस्ट मिनिस्टर—अपनी 8,000 शाखाओं द्वारा देश के अधिकतर बैंकिंग व्यवसाय का सम्पादन करते हैं। भारत में भी शाखा बैंकिंग प्रणाली का प्रचलन है। यहाँ भी कुछ बड़े बड़े बैंक अनेक राज्यों में फैली अपनी अनेक शाखाओं द्वारा बैंकिंग कार्य करते हैं।

शाखा बैंकिंग के गुण

(Merits of Branch Banking)

शाखा बैंकिंग प्रणाली के निम्नलिखित गुण उल्लेखनीय हैं :-

(1) पूँजी का उपयुक्त वितरण (Proper Distribution of Capital) : शाखा बैंकिंग प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि देश भर में फैली शाखाओं के जाल के कारण पूँजी ऐसे क्षेत्रों से जहाँ वह अधिक होती है, ऐसे क्षेत्रों में स्थानान्तरित हो जाती है जहाँ उसकी आवश्यकता होती है। उसका लाभ यह होता है कि पूँजी अपने अधिकतम लाभपूर्ण उपयोग में आ जाती है और देश के उत्पादन का राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में योगदान करती है। इसके साथ साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों की व्याज दरों में एक रूपता आ जाती है।

(2) बड़े पैमाने की उत्पत्ति तथा श्रम-विभाजन के लाभ (Advantages of Large Scale Production and Division of Labour) : शाखा बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत बड़े बड़े बैंक होते हैं और उन बैंको की पूँजी जुटाने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है। सभी कार्य बड़े पैमाने पर होते हैं अतः बड़े पैमाने की सभी मितव्ययितायें प्राप्त हो जाती हैं और प्रबन्ध तथा प्रशासन की लागत कम हो जाती है। बैंक अपने मुख्य कार्यालयों में अनुसन्धान विभागों की स्थापना कर नये-नये परीक्षण कर अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सकती है। बैंक योग्य तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवायें तथा विशेषज्ञों की सलाह भी प्राप्त कर सकती है।

(3) नकद कोषों की बचत (Economy in Cash Reserves) शाखा बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत शाखाओं का कम नकद कोष रख कर भी कार्य चल जाता है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर अन्य शाखाओं तथा मुख्य कार्यालय से कोषों को प्राप्त करके अपनी आवश्यकता पूर्ति की जा सकती है। कम नकद रखने के कारण बैंको की साख सृजन की शक्ति भी अधिक होती है।

(4) धन हस्तान्तरण में सुविधा : (Remittance facilities) बैंको की शाखाएँ देश के विभिन्न भागों में फैली होने के कारण धन का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरण सुविधापूर्वक तथा सस्ती दर पर हो जाता है।

(5) जोखिम का वटवारा (Diversification of Risks) शाखा बैंकिंग प्रणाली में देश के विभिन्न भागों में शाखाएँ फैली होने के कारण निक्षेपों तथा आदेशों की दृष्टि से फैलाव (Diversification) की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं। बैंको द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों तथा उद्योगों में विनियोग किये जाते हैं इसलिए जोखिम क्षेत्रीय तथा उद्योगों के आधार पर वितरित हो जाती है। (Risks are scattered over a number of industries and over a wide area) इकाई बैंकिंग की तरह बैंको का किसी क्षेत्र या उद्योग विशेष से ही बंधे नहीं रहना पड़ता। इस प्रकार यदि किसी क्षेत्र या उद्योग पर कोई आर्थिक संकट आता है तो बैंक उसका सामना दृढ़ता से कर सकता है और वह फेल नहीं होगा। बैंक की छोटी से छोटी शाखा के पीछे पूरे बैंक के साधनों का सहारा होता है। एव शाखा की हानि दूसरी शाखा के लाभ से पूरी की जा सकती है। इस प्रणाली का एक लाभ यह भी है कि इतने शक्तिशाली, साधन सम्पन्न तथा कुशल प्रबन्ध वाले बैंको की सेवाओं का लाभ छोटे छोटे व्यापारियों भी उठा सकते हैं। शाखा बैंकिंग से व्यापार को बढ़ी सुविधा हो जाती है क्योंकि एक क्षेत्र के व्यापारियों दूसरे क्षेत्र के व्यापारियों के सम्पर्क में आ जाते हैं।

(6) बैंकिंग सुविधाओं में वृद्धि (Expansion of banking services) शाखा बैंकिंग प्रणाली द्वारा उच्च स्तरीय बैंकिंग सेवाओं का छोटे छोटे कस्बों तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों में विस्तार किया जा सकता है। इकाई बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत छोटे स्थानों पर बैंको का खोलना आर्थिक दृष्टि से असम्भव होता है।

(7) ऋण तथा अग्रिम गुणों के आधार पर (Loans and advances made on merits) शाखा बैंकिंग प्रणाली में ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम मिद्दानों के आधार पर ही स्वीकृत किए जाते हैं, अन्य कारणों से प्रभावित होकर नहीं। शाखा मैनेजर ऋण स्वीकृत करते समय किसी व्यक्तिगत या स्थानीय तत्वों से प्रभावित नहीं होता क्योंकि ऋणों को स्वीकृत करने के नियम इत्यादि मुख्य कार्यालय द्वारा निर्मित होते हैं। यदि ग्राहक ऋण देने योग्य नहीं है और उसे ऋण

नहीं दिया गया तो मैनेजर इसकी जिम्मेदारी मुख्य कार्यालय पर डालकर ग्राहक से मधुर व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाये रख सकता है।

(8) केन्द्रीय बैंक द्वारा नियन्त्रण प्रभावपूर्ण (Central Banking Control Effective) शाखा बैंकिंग प्रणाली में केन्द्रीय बैंक का बैंको पर नियन्त्रण अधिक प्रभावपूर्ण हो सकता है क्योंकि बैंको की सख्या कम होती है। केन्द्रीय बैंक विभिन्न बैंको के प्रतिनिधियों से शीघ्र सम्पर्क स्थापित कर सकता है और अपनी मौद्रिक नीतियां उन्हें स्पष्ट कर उनका सहयोग प्राप्त कर सकता है। इंग्लैंड में बैंक आफ इंग्लैंड तथा भारत में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने कई बार बैंको के सहयोग से अपनी नीतियों को सफलतापूर्वक निरान्वित किया है।

(9) प्रशिक्षण सुविधायें (Training facilities) : शाखा प्रणाली में शक्तिशाली बैंको द्वारा अपने कर्मचारियों को उच्चस्तरीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण सुविधायें मिल जाती हैं। उनके बैंकिंग शिक्षा तथा व्यवहार सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिक उपयुक्त तथा व्यापक होने हैं। इस प्रकार बैंकिंग सेवा अधिक कार्यकुशल होती है और जनता का बैंको में विश्वास बढ़ता है।

शाखा प्रणाली के दोष (Defects of Branch Banking)

शाखा बैंकिंग प्रणाली के दोष निम्नलिखित हैं —

(1) प्रबन्ध तथा निरीक्षण में कठिनाई (Difficulties in Organisation and Supervision) शाखा बैंकिंग प्रणाली में दूर दूर अनेक शाखायें होती हैं और बैंक का आकार इतना बड़ा होता है कि उसका प्रबन्ध तथा निरीक्षण मुख्य कार्यालय से करना बड़ा कठिन होता है। ब्रांच मैनेजर को अधिकारों का पर्याप्त हस्तान्तरण न होने के कारण वह सदा मुख्य कार्यालय के आदेशों की बाट जाहता है और इस प्रकार ऋण स्वीकृत होने में अनावश्यक देरी हो जाती है।

(2) स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति सद्भावना का अभाव (Lack of sympathy for local needs) : शाखा बैंकिंग प्रणाली के अलोचकों का कथन है कि शाखाओं के मैनेजर स्थानीय परिस्थितियों तथा ऋणियों की विशेष कठिनाइयों तथा समस्याओं से परिचित नहीं होते क्योंकि उनका थोड़े समय बाद स्थानान्तरण होता रहता है। मुख्य कार्यालय भी स्थानीय परिस्थितियों से परिचित नहीं होता। अतः शाखा बैंकिंग प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति सद्भावना नहीं रखती।

(3) प्रारम्भ प्रेरणा का अभाव (Lack of Initiative and Enterprise) . शाखा प्रणाली में नीति निर्धारण तथा नियम इत्यादि का निर्माण मुख्य कार्यालय द्वारा ही होता है अतः शाखा स्तर पर आवश्यक उरसाह, प्रारम्भ प्रेरणा

(initiative) तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार शीघ्र निर्णय क्षमता का अभाव रहता है। परिस्थिति के अनुसार तथा ग्राहक विशेष की रुचियों के अनुसार निर्णयों में लोच की भी कमी रहती है।

(4) एकाधिकार तथा शक्ति के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति (Creates Monopolies and Concentration of Power) : शाखा बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत एकाधिकार तथा साधनों के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। कुछ मुट्टी भर लोगों के हाथों में असामान्य वित्तीय साधन केन्द्रित हो जाते हैं जो समाज के लिए हानिकारक है। इसी डर के कारण अमेरिका में इकाई बैंकिंग प्रणाली अपनायी गई है।

(5) स्थानीय कोषों का अन्य बड़े स्थानों पर प्रयोग (Funds of locality used elsewhere) . इस प्रणाली के अन्तर्गत यह भय है कि स्थानीय कोषों का प्रयोग उसी क्षेत्र के विकास के लिए न होकर अन्य बड़े शहरों तथा क्षेत्रों के विकास के लिए होता है। बैंकें बड़े-बड़े व्यापारिक तथा औद्योगिक केन्द्रों में पूंजी का विनियोग करना अधिक लाभदायक समझते हैं। परन्तु इस तर्क को उल्टा भी जा सकता है। जैसा कि एल० डी० चैंडलर ने कहा है :

• The channels or pipeline which are constructed between small and big places serve to pump rather than drain funds from small places "

(6) खर्चीली प्रणाली (Expensive System) : बड़े सगठनों की प्रबन्ध व्यवस्था तथा प्रशासन पर बहुत अधिक व्यय होता है। कमी कमी प्रबन्ध Top heavy हो जाता है और खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ जाते हैं।

(7) अनार्थिक प्रतियोगिता (Uneconomic and Wasteful Competition) : शाखा बैंकिंग प्रणाली का यह दोष है कि इसमें बैंकों के बीच अनावश्यक तथा अपव्ययी प्रतिस्पर्धा होती है। एक ही स्थान पर कई बैंकों की शाखाएँ खोली जाती हैं और उनमें निचेप आकर्षित करने तथा ग्राहकों को अपनी ओर लाने के लिए अनार्थिक प्रतियोगिता होनी है जो बैंकिंग व्यवस्था तथा देश हित में नहीं है। एक ओर बैंकों की शाखाएँ परस्पर प्रतियोगिता में लगी रहती हैं और दूसरी ओर कुछ क्षेत्र बैंकिंग सेवाओं से वंचित रह जाते हैं।

(ब) इकाई बैंकिंग (Unit Banking)

इकाई बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत बैंक का एक ही कार्यालय होता है या एक सीमित क्षेत्र में कुछ शाखाएँ खोलकर भी बैंक कार्य करता है। केन्ट के अनुसार "इकाई बैंकिंग प्रणाली में प्रत्येक स्थानीय बैंक एक पृथक निगम होती है जिसकी पृथक रचना होती है और जिसकी अपनी पूंजी, संचालक मंडल तथा प्रशासकीय होते

है।" देश में इस प्रकार के स्वतन्त्र बैंक बहुत अधिक सरया में होते हैं। अमेरिका में यह प्रणाली बड़ी लोकप्रिय सिद्ध हुई है। यद्यपि वहाँ प्रत्येक बैंक की स्वतन्त्र सत्ता है परन्तु फिर भी वे एक दूसरे से व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं। वस्वे के बैंक निकटवर्ती नगर के बैंक के पास अपने नकद कोष जमा करा देते हैं और उन्हें करंस्पोंडेन्ट बैंक (Correspondent Bank) बना लेते हैं।

इकाई बैंकिंग के गुण (Merit of Unit Banking)

इकाई बैंकिंग प्रणाली के निम्नलिखित गुण हैं —

- (1) प्रबंध तथा निरीक्षण में सुविधा (Facility in Management and Supervision) इकाई बैंकिंग प्रणाली में बैंको का कार्य क्षेत्र बहुत सीमित होता है इसलिए बड़े पैमाने की उत्पत्ति की अमितव्ययिताओं (Diseconomies of Large Scale Production) से बचत हो जाती है। बैंक का प्रबन्ध तथा कार्य का निरीक्षण अधिक सरल तथा सुविधाजनक हो जाता है।
- (2) स्थानीय हितों की सुरक्षा (Protection of local interests) : इकाई बैंकिंग प्रणाली में स्थानीय हितों की अधिक सुरक्षा होती है। उसी क्षेत्र के कोषों का प्रयोग उसी क्षेत्र के आर्थिक विकास में होता है। स्थानीय तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं तथा समस्याओं से बैंक अधिक परिचित रहता है और उनके समाधान का प्रयत्न करता है।
- (3) प्रारम्भन प्रेरणा की उपस्थिति (Individual initiative and enterprise) : विभिन्न बैंकों की स्वतन्त्र सत्ता तथा प्रबंध होने के कारण व्यक्तिगत प्रारम्भन प्रेरणा तथा साहस के लिए पर्याप्त क्षेत्र रहता है। कर्मचारियों में भी कार्य के प्रति उत्साह तथा उत्तरदायित्व की भावना रहती है।
- (4) आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण (Decentralisation of Economic Power) इकाई बैंकिंग प्रणाली में छोटे छोटे बैंक होते हैं इसलिए वित्तीय साधनों पर कुछ इने गिने लोगों का एकाधिकार नहीं होता।
- (5) स्वतन्त्र उपक्रम सिद्धांत के अनुकूल (In Conformity with the principle of free enterprise) यह प्रणाली स्वतन्त्र उपक्रम सिद्धान्त के अधिक अनुकूल है क्योंकि प्रत्येक इकाई को पर्याप्त स्वतन्त्रता तथा प्रारम्भन प्रेरणा रहती है।

इकाई बैंकिंग के दोष

(Defects of Unit Banking)

इकाई बैंकिंग के दोष निम्नलिखित हैं —

- (1) जोखिम का बटवारा नहीं (Diversification of risk not possible) : इकाई बैंकिंग के अंतर्गत बैंको का कार्य क्षेत्र भौगोलिक तथा औद्योगिक

दृष्टि से सीमित होने के कारण जोखिम का बटवारा सम्भव नहीं है। सकटकाल में बैंको के फेल होने का डर अधिक रहता है। अमेरिका में 1931-33 के मंदीकाल में 5 100 बैंक फेल हो गई थी और इससे यह स्पष्ट हो गया कि इकाई बैंकिंग कठिनाईयों को झलने के अयोग्य है। (Unit banks are ill equipped to stand adversity)

(2) बैंकिंग सेवाओं के प्रसार में बाधक (Obstruction in the expansion of banking services) इकाई बैंको के वित्तीय साधन तथा कार्य धन सीमित होने के कारण वे सभी को पर्याप्त बैंकिंग सेवायें उपलब्ध नहीं कर सकते। साधनों के अभाव में इन बैंकों की प्रबंध व्यवस्था भी अधिक कायकुशल नहीं होती।

(3) पूंजी के हस्तान्तरण में कठिनाई (Difficulties in the transfer of funds) इकाई बैंको की शाखाएँ देश के विभिन्न क्षेत्रों में न होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को कोषों के हस्तांतरण में कठिनाई पैदा होती है। परन्तु करेस्पोंडेन्ट बैंक (Correspondent Banks) बनाकर यह कठिनाई दूर की जा सकती है जैसा कि अमेरिका में किया जाता है।

(4) श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण का अभाव (Lack of Division of Labour and Specialisation) इकाई बैंकिंग में छोटे छोटे बैंक अधिक संख्या में होने के कारण बड़े पैमाने की उत्पात्ति की मितव्ययितायें नहीं प्राप्त की जा सकती और श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण को नहीं अपनाया जा सकता। परिणाम स्वरूप बैंको की लागत बढ़ जाती है।

शाखा बैंकिंग श्रेष्ठ है या इकाई बैंकिंग ?

(Which is better Branch Banking or Unit Banking ?)

शाखा तथा इकाई बैंकिंग प्रणालियों के गुण दोषों का सापेक्षिक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि शाखा बैंकिंग प्रणाली अधिक लाभप्रद है और सवकालीन कठिनाईयाँ सहन करने की उसकी शक्ति अधिक है। टामस (Thomas) के शब्दों में 'यद्यपि दोनों ही प्रणालियाँ अपूर्ण हैं परन्तु दोनों की कार्य पद्धति देखने से पता चलता है कि शाखा बैंकिंग प्रणाली अधिक उत्तम है।' यहाँ तक कि अमेरिका में भी जहाँ इकाई बैंकिंग प्रणाली अति लोकप्रिय हुई है, इकाई बैंकिंग प्रणाली के दोषों को दूर कर उसमें सुधार करके शाखा बैंकिंग प्रणाली के लाभों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। भारत में भी शाखा बैंकिंग प्रणाली को अपनाया गया है और इसके अंतर्गत भारतीय बैंकिंग व्यवस्था ने पर्याप्त प्रगति भी की है।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संकेत

(1) शाखा बैंकिंग तथा इवाई बैंकिंग प्रणालियाँ के सापेक्षिक गुण तथा दोषों की व्याख्या कीजिए। भारत के लिए उनमें से कौन सी प्रणाली अधिक उपयुक्त है।

(राजस्थान बी काम, 1948, 1950, 1952; बिहार बी. ए., 1960)

[संकेत-प्रथम भाग में शाखा तथा इवाई बैंकिंग प्रणालियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके गुण तथा दोष बताइये। दूसरे भाग में भारत की परिस्थितियों के संदर्भ में शाखा बैंकिंग प्रणाली की उपयुक्तता सिद्ध कीजिए।]

(2) बैंकों के विभिन्न प्रकारों तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए।

(विक्रम बी० ए०, 1959)

[संकेत-इसी अध्याय में वर्णित विभिन्न प्रकार के बैंकों तथा उनके कार्यों का विस्तारपूर्वक विवेचन कीजिए।]

बैंकों की कार्य-प्रणाली (The Banking Operations)

"As long as financial skies are sunny, the same profit maximizing logic that compels the abandonment of a system of 100 per cent reserves argues in favour of negligible reserves"

Samuelson

बैंको को मुद्रा का व्यापारी (Dealers in Money) एवं मुद्रा का निर्माता (Manufactures of Money) कहा गया है। इन दोनों रूपों में बैंक किस प्रकार अपने कार्यों का सम्पादन करता है, यह जानना आवश्यक है। पिछले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि बैंक किस प्रकार मुद्रा अथवा साख का निर्माण करते हैं। यहाँ हम यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि बैंक किस प्रकार मुद्रा प्राप्त करता है और किस प्रकार उसके प्रयोग द्वारा अधिकतम लाभ पान का प्रयत्न करता है।

बैंक के साधन (Resources Available to a Bank)

बैंक जिन साधनों से मुद्रा या पूँजी प्राप्त करके उनका प्रयोग लाभ प्राप्ति के लिए करता है वे निम्नलिखित हैं—

1. **अंश पूँजी (Share Capital)** : बैंक भी अपनी पूँजी अन्य सम्युक्त पूँजी कम्पनियों की भाँति अंश निर्गमित करके प्राप्त करते हैं। प्रत्येक बैंक की एक अधिकृत पूँजी होती है जिसका एक भाग विक्रयार्थ जारी किया जाता है। जितने अंशों को खरीदने के लिए प्रार्थना पत्र आते हैं उसे प्रायित पूँजी कहते हैं और उसका जो भाग चुकता कर दिया जाता है वह बैंक की चुकता पूँजी होती है। विभिन्न कोटि की पूँजी के सम्बन्ध में प्रायः नियम बना दिए जाते हैं। भारत में प्रायित पूँजी, अधिकृत पूँजी के आधे से कम नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार चुकता पूँजी कम से कम प्रायित पूँजी की आधी होनी चाहिए। बैंको के साधन के रूप में अंश पूँजी का कोई विशेष महत्व नहीं होता।

2. **संचित कोष (Reserve fund)** . प्रत्येक बैंक अपने वार्षिक लाभ का वितरण करने के पूर्व उसका एक भाग संचित कोष में रख लेता है। यह कोष बैंक की आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनने के लिए आवश्यक होता है। अनेक देश कानून

द्वारा कोप रखना अनिवार्य कर देते हैं और निश्चित कर देते हैं कि लाभ का कितना हिस्सा सचिव कोप में रखा जाना चाहिए। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 17 में यह प्रावधान दिया गया है कि सचिव कोप के चुकता पूँजी के बराबर होने तक प्रत्येक बैंक अपने शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत सचिव कोप में रखेगा। बैंक की सक्रिय पूँजी में यह स्रोत भी महत्वहीन है।

3. निक्षेप (Deposit) बैंको का अपने साधन प्राप्त करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निक्षेप हैं। बैंक अपने ग्राहकों से विभिन्न प्रकार के खातों में निक्षेप प्राप्त करता है। यही उसकी सक्रिय पूँजी का अधिकांश भाग उपलब्ध करता है। बैंक प्रायः निम्नलिखित खातों में निक्षेप प्राप्त करता है :—

- 1 चालू खाता (Current Account)
- 2 स्थायी जमा खाता (Fixed Account)
- 3 बचत खाता (Saving Account)

बैंको की सक्रिय पूँजी का अधिकांश भाग इन खातों में प्राप्त निक्षेपों पर निर्भर करता है। व्यापारियों और उद्योगपतियों के दृष्टिकोण से चालू खाता सुविधाजनक है क्योंकि इसमें किसी भी समय रुपया जमा करने या निकालने की सुविधा होती है। वेतन प्राप्त करने वालों और सामान्य आय वाले व्यक्तियों के लिए बचत खाता सुविधाजनक है क्योंकि रुपया निकालने की भी सुविधा होती है और साथ में कुछ ब्याज भी प्राप्त हो जाता है। स्थायी जमा खाता उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास कुछ सचिव रकम है और वे उससे निश्चित आय पाना चाहते हैं। इस खाते पर ब्याज अधिक मिलता है परन्तु रुपया निश्चित समय के बाद ही निकाला जा सकता है।

बैंको के दृष्टिकोण से चालू खाता विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर ब्याज नहीं देना पड़ता। यहाँ यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि निक्षेपों का अधिकांश भाग स्वयं बैंको द्वारा निर्माण किया जाता है। बैंको द्वारा जमा निर्माण की विधि पहले बतलाई जा चुकी है। स्पष्ट है कि बैंक अपनी सक्रिय पूँजी अपनी आवश्यकता के अनुसार स्वयं भी एक सीमा तक बढ़ा सकता है। इन निक्षेपों से जनता की बचत सुरक्षित रहती है, व्यापारियों को इनमें ऋण प्राप्त होता है और देश में पूँजी का निर्माण होता है।

4 ऋण (Borrowings) प्रत्येक बैंक आवश्यकता पड़ने पर अपनी सक्रिय पूँजी ऋणों से भी प्राप्त करता है। एक बैंक अन्य बैंकों से अल्पकालीन आवश्यकता को पूरा करने में 'काल मनी' (Call Money) के रूप में उधार लेता है। प्रतियोगी बैंको से उधार लेने से थथासम्भव बचना चाहता है क्योंकि इससे बैंको को साख पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए बैंक केन्द्रीय बैंक से ही ऋण प्राप्त

करने का प्रयत्न करते हैं। केन्द्रीय बैंक पुनः कटौती (Re-discount) की सुविधा देने या अनुमोदित प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण देने के लिए सदैव तत्पर रहता है।

बैंक के साधनों का प्रयोग (Use of the Resources of a Bank)

क-लाभहीन प्रयोग (Profitless Uses) :

1. मृत स्तक (Dead Stock) . बैंक भी एक व्यावसायिक संस्था है इसलिए अपने साधनों को बेकार (Idle) नहीं रहने देता। बैंक के साधनों में से एक भाग आवश्यक रूप से उसे इमारत, फर्नीचर, भूमि तथा अन्य स्थिर सम्पत्तियों पर लगाना पड़ता है। यद्यपि इस प्रकार के साधन का प्रयोग करना प्रत्यक्ष रूप से बैंक के लाभ में वृद्धि नहीं करता परन्तु फिर भी यह बैंक के कार्यों को सुचारु रूप से करने के लिए परम आवश्यक है। ग्राहकों को आकर्षित करने एवं कोषों की सुरक्षा के लिए भी इसी प्रकार कुछ साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। लाभ की दृष्टि से यह सम्पत्तियाँ मृत प्रायः हैं।

2. नकद कोष (Cash Reserve) . बैंक का सम्पूर्ण व्यवसाय जनता के विश्वास पर निर्भर करता है। यदि बैंक ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने में सफल है तो बैंक भी सफलता पूर्वक चलता रहेगा, यदि बैंक पर से ग्राहकों का विश्वास उठ जाता है तो बैंक भी फेल हो जाता है। बैंक अपने अनुभव से यह जानता है कि उसके सभी जमाकर्ता एक साथ बैंक से रुपया वापस लेने नहीं आ सकते। प्रायः प्रतिदिन कुछ लोग रुपया वापस भी लेते हैं और कुछ लोग जमा भी करते हैं और बैंक की नकद की स्थिति एक सी रहती है। एक विकासशील समाज में प्रायः रुपया निकालने (Withdraw) की अपेक्षा जमा (Deposit) अधिक होता है। परन्तु कभी ऐसा भी हो सकता है कि रुपया निकालने वाले अधिक हों और जमा करने वाले कम। इसलिए बैंक को सदैव कुछ नकद रखना आवश्यक होता है।

बैंक के नकद कोष को निर्धारित करने वाली बातें

कोई बैंक कितना नकद अपने पास रखे, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसी पर उसकी सफलता या असफलता निर्भर कर सकती है। यदि आवश्यकता से कम है तो ग्राहकों की मांग पूरी नहीं कर सकेगा और जनता का विश्वास खो बैठेगा। यदि आवश्यकता से अधिक है तो उपयुक्त मात्रा में लाभ नहीं कमा सकेगा क्योंकि इस प्रकार की नकद पर कोई लाभ नहीं होता। इसलिए नकद की मात्रा न अधिक होनी चाहिए न कम। बैंक अपनी रक्षा की इस प्रथम पंक्ति को निश्चित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखता है —

1. ग्राहकों की संख्या और निक्षेपों का आकार (Number of Customers and Size of Deposits) : नकद की मात्रा निर्धारित करते समय बैंक अपने ग्राहकों की संख्या तथा निक्षेपों के आकार का विशेष ध्यान रखता है। ग्राहकों की संख्या

और निक्षेपों के आकार जितने ही अधिक बड़े होंगे बैंक को कुल जमा का उतना ही कम अश नकद के रूप में रखना होगा क्योंकि उस परिस्थिति में निकाली जानी वाली और जमा की जाने वाली राशि में अन्तर को कम सम्भावना रहती है।

2. वैधानिक आवश्यकता (Legal Requirements) : अनेक देशों में प्रायः कानून द्वारा वह निश्चित कर दिया जाता है कि बैंकों को नकद के रूप में कितनी राशि रखना आवश्यक है। कुछ देश कुल नकद को कुल जमा के एक निश्चित अनुपात में रखने का नियम बनाते हैं, कुछ देश व्यापारिक बैंकों द्वारा केन्द्रीय बैंक के पास जमा की गई रकम और कुल जमा का अनुपात निश्चित करते हैं, कुछ देश अलग-अलग प्रकार की जमा के लिए अलग अलग अनुपात निश्चित करते हैं और कुछ सभी प्रकार की जमा के लिए एक ही अनुपात। भारत में वर्तमान नियमों के अनुसार कुल जमा का 3 प्रतिशत नकद के रूप में रिजर्व बैंक के पास जमा करना अनिवार्य है।

3 अन्य बैंकों की नकद कोष नीति (Cash Reserve Policy of other Banks) . कोई बैंक जिस क्षेत्र में कार्य करता है उस क्षेत्र के बैंकों से ही उसे अपना सामंजस्य करना पड़ता है। इसलिए बैंक अपने क्षेत्र के अन्य बैंकों के समान ही नकद अनुपात अपनाता है। यदि वह उससे कम नकद की नीति अपनाए तो सम्भव है उसकी साख में जनता का कम विश्वास हो। उस क्षेत्र के ग्राहकों के स्तर और प्रकृति का भी नकद अनुपात पर प्रभाव पड़ता है।

4 ग्राहकों के व्यवसाय का स्वभाव (Nature of customer's Business) कोई भी बैंक अपना नकद कोष निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखे बिना नहीं रह सकता कि उसके अधिकांश ग्राहक किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं। यदि जमाकर्ता अधिकांशतया कृषक वर्ग तथा निश्चित आय वर्ग और स्थायी जमा रखने वाले हैं तो कम नकद की आवश्यकता होगी। यदि उत्पादक और दलाल वर्ग के लोग अधिक हैं तो अधिक नकद की आवश्यकता पड़ेगी।

5 बैंकिंग की आदत (Banking habit of the people) : यदि ग्राहकों में बैंकिंग की आदत है तो नकद कोष कम रखने की आवश्यकता होगी क्योंकि अधिकतर भुगतान चेकों के माध्यम से किया जायगा और बैंक को केवल अपनी पुस्तकों में लेखा करना होगा। यदि जनता में बैंकिंग की आदत नहीं है तो नकद रुपये की मांग अधिक होगी, इसलिए नकद कोष अधिक रखना होगा।

6. समाशोधन गृहों की उन्नति . (Development of Discount Houses) : समाशोधन गृहों के विकसित होने पर जनता में भी बैंकिंग की आदत बढ़ती है और चेक अथवा बिलों का प्रयोग अधिक होता है। इसलिए कम नकद कोष से ही बैंकों का काम अच्छी तरह चलता रहता है।

7 अर्थव्यवस्था की सामान्य दशा (General Condition of the Economy) : अर्थव्यवस्था की सामान्य अवस्था किस प्रकार की है इसका भी नकद कोष पर प्रभाव पड़ता है। यदि तेजी का समय है तो मुद्रा की आवश्यकता अधिक हो जाती है, इसलिए ऐसी अवस्था में अधिक नकद कोष की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत मन्दीकाल में कम नकद से ही काम चल जाता है।

8 बैंक के अन्य विनियोगों की प्रकृति (Nature of Bank's other Investments) : यदि बैंक के अन्य विनियोग अवकाशना तरल हैं तो बैंक किसी भी संकट कालीन स्थिति का सामना कर सकता है इसलिए वह कम नकद कोष से भी अपना काम चला सकता है। यदि बैंक के विनियोगों के तरल विनियोगों की कमी है तो अपेक्षाकृत अधिक नकद कोष रखने की आवश्यकता होती है।

(ख) लाभदायक प्रयोग (Profitable uses) ;

बैंक लाभ अर्जित करना चाहता है इसलिए अपने साधनों का प्रयोग इस प्रकार से करता है कि उसे अधिक से अधिक लाभ हो सके। परन्तु ऐसा करने में वह यह भी ध्यान रखता है कि उसे संकट का सामना न करना पड़े। बैंक के लाभदायक विनियोगों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं -

1 याचना राशि (Call Money) : लाभ की दृष्टि से यह मद बहुत ही महत्वहीन है क्योंकि इस पर बहुत कम व्याज मिलना है। एक बैंक दूसरे बैंकों को इस प्रकार का उधार देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त वापस माग लेते हैं। तुरन्त रुग्ण वापस न मिलने पर अमानत में रखी प्रतिभूतियां बेचकर रुपया वमूल करते हैं।

2 विनिमय-पत्रों को भुनाना या क्रय (Discounting of Purchasing of Bills) - बैंको द्वारा बिलों को भुनाना और उनको क्रय करना भी लाभदायक प्रयोग की एक मद है। इस मद में साधन लगाना एक ही साथ लाभदायक और तरल दोनों ही है क्योंकि बिलों को पुनः भुनाया जा सकता है। विनिमय पत्र स्वतः निस्फीर्ण (Self liquidating) होते हैं इसलिए भुगतान तिथि पर उनकी रकम भी अदृश्य प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार के विनियोग में किसी प्रकार की जोखिम नहीं है।

3 विनियोग (Investments) : लाभदायक विनियोग के अन्तर्गत प्रतिभूतियों, अश ऋण पत्र, बांड, आदि के क्रय विक्रय एवं अन्य विनियोग सम्मिलित हैं। प्रतिभूतियों के अन्तर्गत कई प्रकार की प्रतिभूतियां शामिल हैं। प्रतिभूतियों को निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं -

(i) सरकारी प्रतिभूतियां (Govt. Securities) : कोषागार विपन्न, अल्प-कालीन तथा दीर्घकालीन बचत प्रमाण पत्र आदि सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं

क्योंकि ये प्रतिभूतियाँ केन्द्रीय बैंक की अनुमोदित प्रतिभूतियाँ होती हैं और आवश्यकता के समय शीघ्र बिना हानि के मुद्रा में बदली जा सकती हैं। इनमें तरलता एवं सुरक्षा के साथ-साथ पर्याप्त लाभदायकता भी है। परन्तु लाभ की दृष्टि से वे निजी प्रतिभूतियों की अपेक्षा कम लाभप्रद हैं।

(ii) अर्द्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ (Semi-Government Securities) : इस श्रेणी में नगर निगमों, जिला परिषदों, इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट, जन हितकारी संस्थाएँ, विद्युत-मण्डलों, नगरपालिकाओं आदि की प्रतिभूतियाँ शामिल हैं। इन प्रतिभूतियों पर अपेक्षावृत्त अधिक ब्याज प्राप्त होता है। इन संस्थाओं की प्रतिभूतियों में रुपया लगाने में जोखिम भी नहीं होती क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा भुगतान की गारन्टी दी जाती है।

(iii) निजी प्रतिभूतियाँ (Commercial Securities) इस श्रेणी में व्यापारिक संस्थाओं के अक्ष ऋणपत्र आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इन पर ब्याज की दर सबसे अधिक होती है परन्तु सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन्हें सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी प्रतिभूतियों के समान नहीं समझा जाता है। इन प्रतिभूतियों की कीमत भी बढ़ती घटती रहती है इसलिए इनमें विनियोग करते समय बैंक को बड़ी सतर्कता से काम लेना पड़ता है।

4. ऋण तथा अग्रिम (Loans and Advances) : बैंक का सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे लाभदायक विनियोग ऋणों और अग्रिम के रूप में किया जाता है। ऋणों के द्वारा ही बैंक साख का निर्माण भी करते हैं। प्रायः बैंक निम्नलिखित रूपों में ऋण देते हैं :

(i) अधिविकर्ष (Overdrafts) बैंक अपने चालू जमा वर्तियों को प्रायः अधिविकर्ष की सुविधा देता है। इसके अनुसार चालू जमा वर्तियों को जमा रकम से एक सीमा तक अधिक रकम निकालने की सुविधा प्राप्त हो जाती है परन्तु ब्याज केवल उभी रकम पर लिया जाता है जितना वास्तव में निकाला जाता है। उदाहरणार्थ यदि किसी ग्राहक को 1 लाख के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा 1 माह के लिए दी जाय परन्तु ग्राहक केवल 50 हजार ही निकाले तो ब्याज केवल 50 हजार पर ही लिया जायगा। अधिविकर्ष की सुविधा अल्पकालीन होती है। सामान्यतया जमानत रखने की आवश्यकता होती है परन्तु कभी-कभी व्यक्तिगत जमानत पर भी यह सुविधा प्राप्त हो जाती है।

(ii) नकद साख (Cash Credit) : नकद साख की सुविधा भी बैंक अपने ग्राहकों को उपलब्ध करता है। ग्राहक अपनी आवश्यकतानुसार निश्चित रकम की नकद साख का समझौता बैंक से कर लेता है और जमानत रख कर सुविधानुसार रुपया निगलता रहता है। नकद साख की व्यवस्था में भी ब्याज केवल

वास्तव में निकाली गई रकम पर ही तिमा जाना है। नकद साख और अधिविक्रय का प्रमुख अन्तर यह है कि नकद साख अपेक्षाकृत लम्बे समय (प्रायः 1 वर्ष) के लिए एवं अधिविक्रय अल्प समय (प्रायः 3 माह) के लिए दिए जाते हैं। नकद साख किसी को भी दी जा सकती है परन्तु अधिविक्रय केवल चालू खाता रखने वाले ग्राहकों को ही दी जाती है। अधिविक्रय पर कभी कभी अधिक व्याज लिया जाता है।

(iii) ऋण एवं अग्रिम (Loans and Advances) इस प्रकार के ऋणों की प्रमुख विशेषता यह है कि ऋण देने की तिथि से ही इस पर ऋणी को व्याज देना पड़ता है चाहे वह इसका प्रयोग कर रहा है या नहीं। इस मद से बैंको को सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है। बैंक ऋण लेने वाले का खाता खोल लेता है और ऋण की रकम जमा कर देता है। ऋणी अपनी आवश्यकतानुसार रकम निकालता रहता है।

इस प्रकार का ऋण देने में बैंक ऋणी की माख आदि की पूर्ण जाच करा लेना है और समुचित जमानत की व्यवस्था का अनुरोध करता है।

जब कोई व्यक्ति या संस्था बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहती है तो उसे एक प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। इस कथ के लिए बैंको के पास उनके छपे हुए फार्म होते हैं जिसमें ग्राहक से सम्बन्धित एवं प्रतिभूतियों से सम्बन्धित सभी सूचनाएँ देनी होती हैं। बैंक ऋण सम्बन्धी नियमों का भी उसमें उल्लेख कर देता है और ग्राहक को उन नियमों के मानने की घोषणा करनी पड़ती है। आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद बैंक ग्राहक की उपयुक्तता के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और ऋण देने के सम्बन्ध में निराय लेता है। ऋण की स्वीकृति होने पर उसे ग्राहक के खाते में जमा कर दिया जाता है जिसका प्रयोग वह अपनी इच्छानुसार करता है।

ऋण देने के उपरान्त भी बैंक को सावधानी रखनी पड़ती है। यह देखना बैंक का काय है कि ऋणी ऋण का प्रयोग उही कार्यों के लिए कर रहा है जिनके लिए उसने ऋण लिया था। यदि ऋण का प्रयोग अनुत्पादक कार्यों के लिए किया जा रहा हो तो और भी अधिक सतकना की आवश्यकता होती है। यदि जमानत में रखी गई प्रतिभूतियों का मूल्य कम हो गया हो तो और प्रतिभूतियाँ मागनी चाहिए। विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियाँ का ध्यान में रखकर उचित सावधानी रखना बैंक के लिए बहुत आवश्यक है।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संकेत

(1) व्यापारिक बैंको द्वारा अपनी पूँजी प्राप्त करने के विभिन्न तरीके क्या हैं ? विवेचना कीजिए।

(भाग 1 वी० काम 1960)

[संकेत—बैंकों को जिन साधनों से पूंजी प्राप्त होती है—ग्रंथ पूंजी, संचित कोष, निक्षेप तथा ऋण—उनका विस्तार से विवेचन कीजिए ।]

(2) “साहस व्यापार का जीवन है, परन्तु सावधानी न कि भीरुता प्राधुनिक बैंकिंग का सार है ।” इस कथन की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए ।

(आगरा बी० काम, 1961)

[संकेत—पहले समझाइये कि व्यापार में जोखिम उठाना पड़ता है; बिना जोखिम उठाये लाभ नहीं कमाया जा सकता । बैंकिंग के क्षेत्र में भीरुता न अपना कर सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि बैंक दूसरों के कोषों से व्यापार करता है । फिर बताइये कि ऋण देते समय बैंक को कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए ।]

(3) किसी बैंक के नकद कोषों को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या कीजिए ।

(आगरा बी० काम, 1959)

[संकेत—बैंकों के नकद कोषों के निर्धारित करने वाले तत्वों की विस्तार-पूर्वक व्याख्या कीजिए ।]

अमेरिकी राष्ट्रपति श्री आइजनहोवर ने स्वीकृति प्रदान करदी । अगस्त 1959 मे राष्ट्रपति आइजनहोवर ने सार्वजनिक रूप से इसे अपना समर्थन प्रदान किया । अक्टूबर 1959 मे वाशिंगटन मे होने वाली अपनी वार्षिक बैठक मे विश्व बैंक के गवर्नर मण्डल ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया और कार्यकारी सचानको से विकास सघ का समझौता-पत्र (Articles of Agreement) तैयार करने को कहा । 26 जनवरी 1960 को समझौता-पत्र तैयार हो गया और उसे विश्व बैंक के सभी सदस्य देशो मे प्रसारित किया गया । निर्धारित सदस्यो की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर 24 सितम्बर 1960 को अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ का जन्म हुआ और उसने 8 नवम्बर 1960 को विधिवत कार्य करना आरम्भ किया ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ विश्व बैंक की एक पूरक सस्था है और इसका उद्देश्य विकासशील देशो को सरल शर्तों पर ऋणो की व्यवस्था करना है । (The purpose of IDA is to provide development finance to less developed member countries on easy terms that will bear less heavily on the balance of payments position of recipient countries than do Banks loans granted on conventional terms) विकास सघ विकासशील देशो को कम व्याज पर दीर्घकालीन ऋण देने की व्यवस्था करता है और उनका भुगतान उन्ही की राष्ट्रीय मुद्राओ मे स्वीकार करता है । तक्षेप मे, विकास सघ विकासशील देशो को 'सुलभ ऋण' (Soft Loans) प्रदान करता है ।

विकास सघ की सदस्यता

(Membership of the Association)

विकास सघ विश्व बैंक की सहयोगी (Affiliate) सस्था है और विश्व बैंक का कोई भी सदस्य विकास सघ का सदस्य हो सकता है प्रारम्भ मे विकास सघ के केवल 51 सदस्य थे । 31 दिसम्बर 1968 को विकास सघ की कुल सदस्य सख्या बढकर 102 हो गई है । मारीशस, बोत्सवाना, लेसोथो तथा इन्डोनेशिया ने 1968 मे ही विकास सघ की सदस्यता ग्रहण की है ।

विकास सघ के पूँजी साधन

(Capital Resources of the Association)

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ के प्रारम्भिक पूँजी 1 बिलियन (1000 मि० डालर) निर्धारित की गई थी । सदस्य देशो को भाग 1 तथा 2 भाग मे विभाजित किया गया है । भाग 1 मे 18 विकसित देश हैं । पहले भाग 1 के सदस्य देशो की सख्या 17 थी और कुर्वत के भाग 1 के सदस्य बन जाने से यह 18 हो गई है । भाग 2 मे शेष 84 अर्विकसित तथा अर्धविकसित देशो को सम्मिलित किया गया है ।

भाग 1 के विकसित देशों को उनके पूँजी अंशों का शत प्रतिशत भाग स्वर्ण या परिवर्तनशील मुद्रा में विकास सघ को अदा करना पड़ता है। भाग 1 के विकसित देशों को अपने प्रारम्भिक पूँजी अंशों का 10 प्रतिशत निम्न प्रकार चुकाना था :

(1) आधा भाग विकास सघ का कार्य प्रारम्भ होने या देश के सदस्य बनने के 30 दिन के भीतर।

(ii) 12.5 प्रतिशत विकास सघ का कार्य प्रारम्भ होने के 1 वर्ष के भीतर और फिर 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष जब तक कुल पूँजी अंश का 10 प्रतिशत अदा न हो जाय।

भाग 2 के देशों को शेष 90 प्रतिशत भाग स्वर्ण या परिवर्तनशील मुद्रा में पाच किस्तों में अदा करना होता है।

भाग 2 के देशों को उनके पूँजी अंशों का 10 प्रतिशत स्वर्ण या परिवर्तनशील मुद्रा में चुकाना होता है। उनको अपनी पूँजी अंशों का शेष 90 प्रतिशत भाग अपने दश की मुद्रा में ही पाच किस्तों में चुकाना होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ

मुरम देशों के पूँजी अंश (30 जून 1968)

(मिलियन डालरों में)

भाग 1			भाग 2		
देश	पूँजी अंश	कुल का प्रतिशत	देश	पूँजी अंश	कुल का प्रतिशत
1. अमेरिका	320 29	32 02	1. भारत	40 35	4 03
2. ब्रिटेन	131 14	13 11	2. चीन	30 26	3 03
3. फ्रांस	52 96	5 26	3. ब्राजील	18 83	1 08
4. प. जर्मनी	52 96	5 29	4. अर्जेंटाइना	18 83	1 08
5. कनाडा	37 83	3 78	5. पाकिस्तान	10 09	1 01
6. जापान	33 09	3 35	6. स्पेन	10 09	1 01
7. नीदरलैंड्स	27 74	2 77	7. मेक्सिको	8 74	0 87
8. आस्ट्रेलिया	20 18	2 02	8. टर्की	5 80	0 58
9. इटली	18 16	1 82	9. यू. ए. आर.	5 08	0 51
10. स्वीडन	10 09	1 01	10. फिनीषाईस	5 04	0 50

विकास सघ का प्रबन्ध (Management of IDA)

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ विश्व बैंक की सहयोगी संस्था है और उसका प्रबन्ध तथा प्रशासन विश्व बैंक ही करता है। विश्व बैंक का गवर्नर मंडल (Board of Governors) कार्यकारी संचालक मंडल (Board of Executive Directors) तथा अन्य कार्यकारी विकास सघ की भी व्यवस्था करते हैं।

विकास संध की ऋण व्यवस्था
(Lending Operations of IDA)

अन्तर्राष्ट्रीय सघ ने सदस्य देशों को पर्याप्त ऋण सहायता दी है।

विकास सघ ने अपने जीवन काल के 9 वर्षों में विकास शील देशों को पर्याप्त सहायता दी है। प्रारम्भ से 30 जून 1968 तक विकास सघ ने 40 देशों को 1968 मि० डालर के ऋण प्रदान किए हैं। जनवरी 1969 तक विकास सघ 43 देशों को 2,000 मिलियन डालर के 141 ऋण प्रदान कर चुका था। प्रथम दस देशों को मिले ऋणों का विवरण निम्न तालिका में दिखाया गया है।

विकास सघ द्वारा दिए गये ऋणों का विवरण
(30 जून 1968 तक) (मिलियन डालरों में)

देश	ऋणों की संख्या	ऋण राशि (\$)
1 भारत	21	887
2 पाकिस्तान	24	331
3. टर्की	7	80
4 कीनिया	8	39
5 नाइजीरिया	2	36
6. इथोपिया	3	28
7. मलावी	5	28
8. तन्जानिया	4	27
9 कोरिया	2	25
10 ट्यूनीशिया	3	24

विकास सघ द्वारा दिए गये ऋणों का कार्यानुसार वितरण निम्न तालिका में दिखाया गया है

विकास सघ द्वारा दिये गये ऋणों का कार्यानुसार वितरण
(30 जून 1968 तक) (मिलियन डालरों में)

मद	ऋण राशि
1 विद्युत शक्ति	112.2
2 यातायात	617.0
3 सड़क याहन	74.8
4 कृषि वन तथा मत्स्य पालन	310.6
5 उद्योग	501.1
6 शिक्षा	127.1
7 जल प्रदान	34.0
8 प्रायोजना निर्माण	1.6
योग	1788.4

विकास सघ द्वारा दिए गये ऋणों का क्षेत्रानुसार वितरण निम्न तालिका में दिखाया गया है :

विकास सघ द्वारा दिये गये ऋणों का क्षेत्रानुसार वितरण

(IDA Credits by Area)

(30 जून 1968 तक)

(मिलियन डालरों में)

क्षेत्र	ऋण राशि
1. एशिया तथा मध्य पूर्व	1280.6
2. अफ्रीका	309.8
3. पश्चिमी गोलार्ध	117.5
4. योरोप	80.5
योग	1788.4

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विकास सघ ने कुल ऋणों का 88 प्रतिशत एशिया, मध्यपूर्व तथा अफ्रीका के देशों को दिया है।

ऋणों की अवधि 50 वर्ष की है। प्रथम 10 वर्षों तक कोई अदायगी नहीं करनी होगी। अगले 10 वर्षों में ऋण राशि का 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा बाकी अगले 30 वर्षों में 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से अदा करना पड़ता है। ऋणों पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता। केवल $\frac{3}{4}$ प्रतिशत में 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से सेवा व्यय (Service charge) लिया जाता है।

विकास सघ तथा भारत (IDA and India)

भारत अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ का प्रारम्भिक सदस्य है। उसका पूँजी अंश पाचवें नम्बर का है परन्तु विकासशील देश होने के कारण उसे भाग 2 के देशों की श्रेणी में रखा गया है जिससे उसे विकास सघ से पर्याप्त मात्रा में ऋण सुविधायें प्राप्त हो सकें।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ से सहायता प्राप्त करने वाले विकासशील देशों में भारत से गत 9 वर्षों में सबसे अधिक ऋण प्राप्त किए हैं। प्रारम्भ से लेकर 30 जून 1968 तक भारत ने विकास सघ के 887 मि० डालर के ऋण प्राप्त किए हैं। उन ऋणों का कार्यानुसार वितरण निम्न तालिका से स्पष्ट है :

विकास संघ द्वारा भारत को स्वीकृत ऋण

(31 जून 1968 तक)

(मिलियन डालरों में)

काय	राशि
1. धिद्युत शक्ति	79 0
2. यातायात .	
रेलें	197 5
बन्दरगाह	18.0
सडकें	59.5
हवाई जहाज	—
3. सदेश वाहन	75 0
4. कृषि, वन तथा मत्स्य	56 5
5. उद्योग	340 0
योग	825 5

विकास संघ ने दिसम्बर 1966 के बाद जनवरी 1969 में भारत को उसके विकास कार्यक्रम में सहायता देने के लिए 125 मिलियन डालर का ऋण स्वीकृत किया। इस राशि का प्रयोग भारत सरकार उत्पादन माल के आयात के लिए विदेशी विनिमय की व्यवस्था के लिए करेगी।

विकास संघ तथा विश्व बैंक ने जून 1969 में भारत को सदेश वाहन के विकास के लिए 55 मिलियन डालर का ऋण स्वीकृत किया है जिसमें से 35.4 मि० डालर का उपयोग सांख्यिक क्षेत्र की तीन समस्याओं आवश्यक आयात के लिए करेगी। शेष 19.6 मि० डालर आवश्यक साज सामान के आयात के लिए प्रयुक्त होंगे।

विश्व बैंक तथा संघ के एशिया विभाग के निदेशक श्री पीटर कारगिल (Peter Cargill) की भारत सरकार से जून 1969 की बातचीत से छाशा है कि शीघ्र ही विकास संघ उर्वरक उत्पादन के लिए नागल तथा कोचीन के प्रस्तावित कारखानों को सहायता देगा। इन परियोजनाओं की जाच के लिए एक दल जुलाई 1969 में भारत आयेगा।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संकेत

1. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना किन कारणों से हुई ? भारत को इसकी सदस्यता से क्या लाभ प्राप्त हुआ है ?

[संकेत—प्रथम भाग में विकास संघ की स्थापना के कारण बताइये। विश्व बैंक द्वारा दिए गये ऋणों की कमिश्नों की चर्चा करते हुए बताइये कि अधिकतम तथा अर्द्ध विकसित देशों को सस्ती तथा मुलम शर्तों पर दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराने के लिए विकास संघ की स्थापना हुई। द्वितीय भाग विकास संघ से भारत को प्राप्त सहायता का व्योरा दीजिए।]

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation)

"The International Finance Corporation was established by member governments in 1956 as an affiliate of the International Bank for Reconstruction and Development (World Bank), to assist less developed member countries by helping to promote the growth of the private sector of their economies.

IFC's principal objectives are to provide risk capital for productive private enterprises, in association with private investors and management, to encourage the development of local capital markets, and to stimulate the international flow of private capital."

विश्व बैंक ने ससारा के देशों के पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। परन्तु बैंक द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता में दो मुख्य कमियाँ रही हैं। प्रथम, बैंक ऋण देता है, यह औद्योगिक तथा अन्य संस्थानों की पूँजी के अभाव नहीं खरीदता। इससे बैंक ऋणदाता के रूप में संस्थानों में उतनी रुचि नहीं रखता जितनी अभावकारी रखते हैं। और फिर ऋणी संस्थान व्याज के बोझ से सदैव दबे रहते हैं। द्वितीय, विश्व बैंक द्वारा ऋण या तो सरकार या सरकार की गारन्टी पर दिए जाते हैं। एक ओर तो सरकारें निजी क्षेत्र के संस्थानों की गारन्टी करना नहीं चाहती और दूसरी ओर सरकार की गारन्टी लेना निजी संस्थान भी नहीं पसन्द करते क्योंकि इससे उनके कार्यों में मरकरारी हस्तक्षेप के बढ़ने का भय रहता है। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना की गई।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना का विचार सर्वप्रथम 1952 में विश्व बैंक द्वारा संयुक्त राष्ट्र सभ की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद (Economic and Social Council) के लिए तैयार की गई एक रिपोर्ट में उठाया गया। बाद में आर्थिक तथा सामाजिक परिषद तथा साधारण सभा (General Assembly) ने वित्त निगम की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार हुआ। दिसम्बर 1954 में एक प्रस्ताव पारित कर साधारण सभा ने विश्व बैंक से वित्त निगम का घोषणा पत्र (Charter)

बनाने तथा उस पर सहमति प्राप्त करने की प्रार्थना की। 11 अप्रैल 1955 को कार्यकारी सचालको ने समझौता पत्र का प्रारूप तैयार कर लिया और उसे सदस्य देशों को प्रसारित कर दिया गया और 21 जुलाई 1955 को अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की विधिवत स्थापना हो गई। स्थापना के समय निगम क 31 सदस्य थे और उनकी कुल स्वीकृत पूंजी 78 मि० डालर थी।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के उद्देश्य (Purposes of International Finance Corporation)

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के समझौता पत्र (Articles of Agreement) के अनुसार "निगम का उद्देश्य सदस्य देशों विशेषकर विकासशील देशों में उत्पादक निजी उपक्रम को प्रोत्साहन देकर उनके आर्थिक विकास को बढ़ाना है और इस प्रकार विश्व बैंक की क्रियाओं का पूरक हाना है....."¹ निगम इस मूलभूत उद्देश्य की पूर्त के लिए निम्नलिखित कार्य करता है —

¹ "The purpose of the Corporation is to further economic development by encouraging the growth of productive private enterprise in member countries particularly in the less developed areas, thus supplementing the activities of the International Bank for Reconstruction and DevelopmentIn carrying out this purpose, the Corporation shall :

- (i) in association with private investors, assist in financing the establishment, improvement and expansion of productive private enterprises which would contribute to the development of its member countries by making investments, without guarantee of repayment by the member government concerned, in cases where sufficient private capital is not available on reasonable terms,
- (ii) seek to bring together investment opportunities domestic and foreign private capital, and experienced management, and,
- (iii) seek to stimulate and to help create conditions conducive to, the flow of private capital, domestic and foreign, into productive investment in member countries.

"The Corporation shall be guided in all its decisions by the provisions of this Article:"

—Article One, Articles of Agreement

(1) उत्पादक निजी साहस संस्थाओं की स्थापना, सुधार तथा विस्तार की वित्त व्यवस्था में सहायता :

वित्त निगम निजी विनियोगकर्त्ताओं के साथ मिलकर निजी क्षेत्र के उद्योगों तथा अन्य व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना, सुधार तथा विस्तार के लिए पूँजी सहायता देता है जिससे सदस्य देशों का आर्थिक विकास हो सके। निगम द्वारा बिना सरकारी गारन्टी के ऋण दिये जाते हैं। ऋण विशेषकर ऐसे क्षेत्रों के लिए दिए जाते हैं जहाँ सुगम शर्तों पर पर्याप्त निजी पूँजी उपलब्ध न हो।

(2) विनियोग अवसर, पूँजी तथा प्रबन्ध में सहयोग स्थापित करना :

निगम देशी तथा विदेशी निजी पूँजी को विनियोग के क्षेत्र ढूँढने में सहायता करता है। जहाँ योग्य प्रबन्ध उपलब्ध है परन्तु पूँजी नहीं है वहाँ पूँजी की व्यवस्था करता है और जहाँ पूँजी है परन्तु कुशल प्रबन्ध नहीं है वहाँ कुशल प्रबन्धकों की व्यवस्था करता है। इस प्रकार विनियोग अवसर, पूँजी तथा प्रबन्ध (Investment Opportunities, Capital and Experienced Management) में सहयोग तथा समायोजन स्थापित करता है।

(3) देशी तथा विदेशी निजी पूँजी के प्रवाह तथा उसके उत्पादक विनियोजन को प्रोत्साहन तथा उसके लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना :

सदस्य देशों के आर्थिक विकास के लिए देशी तथा विदेशी निजी पूँजी के विनियोजन को प्रोत्साहित करना तथा उसमें उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करना निगम का मुख्य कार्य है।

निगम की सदस्यता

(Membership of the Corporation)

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक के साथ काम करने वाली संस्था होती हुई भी स्वतन्त्र संस्था है। वित्त निगम का सदस्य बनने के लिए विश्व बैंक का सदस्य होना आवश्यक है। स्थापना के समय जुलाई 1955 में निगम के 31 सदस्य थे जो 30 जून 1968 को बढ़कर 86 हो गये थे। 31 दिसम्बर को निगम की सदस्य संख्या 90 थी। 1967-68 में कियतनाम, मीरीटाना तथा इन्डोनेशिया ने निगम की सदस्यता ग्रहण की। जुलाई 1968 से दिसम्बर 1968 तक बनने वाले नये सदस्य थे—मारीशस, यूगोस्लाविया, यूरानुमे तथा सिंगापुर। जनवरी 1969 में चीन (तैवान) भी निगम का सदस्य बना और इस प्रकार निगम की सदस्य संख्या बढ़कर 91 हो गई।

अतः ग्राहक उन व्यक्ति, फर्म या संस्था का कहते हैं जिसका किसी बैंक में खाता—सर्वाधिक या चालू खाता या इसी प्रकार का सम्बन्ध होता है और जिसे रुपया चेक या किसी दूसरी प्रकार से, बिना किसी पूर्व सूचना के, निकालने का अधिकार होना है। अन्य शब्दों में, ग्राहक वह है जो बैंक का खाताधारक है चाहे खाता खोलना उसका प्रथम लेन देन ही क्यों न हो।

बैंक और ग्राहक का पारस्परिक सम्बन्ध

(The relation between a Banker and his Customer)

बैंक और ग्राहक का पारस्परिक सम्बन्ध तीन प्रकार का होता है —

- (1) ऋणी तथा ऋण दाता का सम्बन्ध (Relation of Debtor and Creditor)
- (2) प्रतिनिधि और प्रधान का सम्बन्ध (Relation of Agent and Principal)
- (3) प्रत्यासी तथा प्रत्यासी का सम्बन्ध (Relation of Trustee and Beneficiary)

नीचे तीनों प्रकार के सम्बन्धों की विस्तृत व्याख्या की गई है

(1) ऋणी तथा ऋणदाता का सम्बन्ध (Relation of Debtor and Creditor) — सर जान पैजेट के अनुसार “बैंकर तथा ग्राहक का सम्बन्ध मुख्यतः ऋणी तथा ऋणदाता का है।”¹ जब ग्राहक बैंक में खाता खोलकर रुपया जमा करता है तो बैंक ऋणी तथा ग्राहक ऋणदाता होता है और जब ग्राहक बैंक से ऋण लेता है तो ग्राहक ऋणी तथा बैंक ऋणदाता होता है।

ऋणी और ऋणदाता के रूप में बैंक और ग्राहक के पारस्परिक सम्बन्ध की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं —

(अ) बैंक केवल मात्र प्रत्यासी नहीं (A banker is not mere Trustee) बैंक और ग्राहक का सम्बन्ध मुख्यतः ऋणी और ऋणदाता का है। जब ग्राहक बैंक में रुपया जमा करता है तो रुपया प्रधान अर्थात् ग्राहक की सम्पत्ति नहीं रहता बरन् वह पूर्णरूपेण बैंक की सम्पत्ति हो जाता है और बैंक को रुपय का इच्छानुसार प्रयोग करने का अधिकार मिल जाता है; बैंक का केवल यह दायित्व होना है कि यदि उसके खाते में जमा धोप है तो मांग पर ग्राहक को मुगतान कर देगा। इस प्रकार बैंक प्रत्यासी (Trustee) या प्रतिनिधि (Agent) नहीं है बरन् केवल मात्र ऋणी (Debtor) है।

¹“The relation of banker and customer is primarily that of debtor and creditor.”

(ब) भुगतान की मांग आवश्यक (Demand for repayment necessary):— ग्राहक द्वारा बैंक को जमा के रूप में दिया गया ऋण साधारण वाणिज्यिक ऋण से एक दृष्टि से भिन्न होता है। साधारणतया ऋण का भुगतान करने का दायित्व ऋणी का होता है और ऋणी अपने आप निश्चित समय पर भुगतान करता है, ऋणदाता द्वारा उमका भुगतान मांगना आवश्यक नहीं होता। परन्तु बैंक जमा के रूप में प्राप्त ऋण का भुगतान तभी करने को बाध्य है जब ऋणदाता उस रकम के भुगतान की मांग करे।¹ सामान्य ऋण तथा बैंक को जमा के रूप में दिये गये ऋण में शायद यह अन्तर ग्राहक को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से रखा गया जिसे कि बैंक किसी भी स्थान तथा किसी भी समय जमा की राशि ग्राहक को वापिस कर बिना पर्याप्त सूचना दिए उसका खाता न बन्द कर दे तथा उसके द्वारा जारी की गई चेको को अस्वीकृत कर उसकी साख को घबका न पहुँचा सके। लाई चोलों का यह कथन ठीक ही है कि बिना मांगे ग्राहक की रकम का भुगतान करने का तात्पर्य है कि बैंक ग्राहक का खाना बन्द कर रहा है। ऐसा बिना किसी गम्भीर कारण के करना उपयुक्त नहीं है।

(स) समय-सीमा नियम (Law of Limitation):—सामान्यतः समय सीमा नियम (Law of Limitation) के अनुसार ऋणों की अदायगी की तिथि के 3 वर्ष के भीतर ही उनकी वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ हो जानी चाहिए। ऋण अदायगी तिथि के 3 वर्ष व्यतीत हो जाने तक यदि वसूली की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जाती तो समय-सीमा नियम (Law of Limitation) के अनुसार ऋणदाता ऋणी से ऋण की रकम वसूल नहीं कर सकता। परन्तु बैंको द्वारा लिए गये ऋणों पर यह नियम लागू नहीं होता। बैंको द्वारा लिए गये ऋणों पर इस नियम का लागू होना तब तक प्रारम्भ नहीं होता जब तक कि ग्राहक अपनी रकम के भुगतान के लिए मांग न करे। सावधि जमाघो (Fixed Deposits) की भुगतान तिथि बैंक के पास सावधि जमा रसीद (Fixed Deposit Receipt) भेजने की तिथि मानी जाती है। इस तिथि के 3 वर्ष के भीतर रकम वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ हो जानी चाहिए। चालू खाते की रकम के सम्बन्ध में 3 वर्ष की अवधि उस दिन के बाद से गिनी जाती है जब ग्राहक उस रकम के लिए बैंक से मांग करता है। इस प्रकार चालू खाते में रकम जमा कराने के तीन वर्ष तक यदि बैंक तथा ग्राहक में किसी

¹. 'Whereas in the case of ordinary debts, a request for payment is not necessary before a creditor can take steps to enforce payment, a demand on the bank for repayment is necessary before the debt owing to a customer becomes what is known 'as actually and accruing due, and so recoverable in law'.

प्रकार का लेन देन न भी हुआ हो ग्राहक में किसी प्रकार का लेन देन न भी हुआ तो ग्राहक बैंक से अपनी जमा रकम न्यायालय के माध्यम से वसूल कर सकता है।

बैंको द्वारा लिए गये ऋणों पर समय-सीमा नियम का यह सिद्धान्त ग्राहको द्वारा बैंक से लिए ऋणों पर लागू नहीं होता। ग्राहको द्वारा बैंक से लिए गये ऋण साधारण ऋण माने जाते हैं।

(2) प्रतिनिधि और प्रधान का सम्बन्ध (Relation of Agent and Principal):—बैंक और ग्राहक के बीच दूसरा महत्वपूर्ण सम्बन्ध प्रतिनिधि और प्रधान (Agent and Principal) का है। बैंको के कार्यों की व्याख्या करते समय हमने उन सेवाओं का उल्लेख किया था जो बैंक ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में करता है। जब बैंक इन कार्यों को करता है—जैसे ग्राहको की ओर से अग्रे तथा प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय, बैंको का भुगतान प्राप्त करना, अग्रे का लाभांश तथा प्रतिभूतियों का ब्याज वसूल करना, बीमा पर प्रीमियम की किस्तें अदा करना, ग्राहक की ओर से प्रत्यासी (Trustee) सर्वराकार (Executor) या मुहत्तार (Attorney) का कार्य करना इत्यादि—तो वह ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इन कार्यों के सम्बन्ध में बैंक और ग्राहक पर एजेन्सी कानून की सभी धारयें लागू होती हैं। प्रतिनिधि के रूप में बैंक को पूर्ण सद्विश्वास तथा पर्याप्त सावधानी और मेहनत से कार्य करना चाहिए। इन कार्यों को करते समय बैंक अपने ग्राहक के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करे अथवा असावधानी तथा अधिकारों के दुरुपयोग के फलस्वरूप ग्राहक को होने वाली हानि के लिए बैंक उत्तरदायी होगा। एजेन्सी के नियमों के अनुसार बैंक को अपने कमीशन आदि के लिए ग्राहक की प्रतिभूतियों इत्यादि पर गृहणाधिकार (lien) प्राप्त होता है।

(3) प्रत्यासी तथा प्रत्यासी का सम्बन्ध (Relation of Trustee and Beneficiary) : बैंक तथा उसके ग्राहक के बीच तीसरा महत्वपूर्ण सम्बन्ध प्रत्यासी या धरोहरधारी (Trustee or Bailee) तथा प्रत्यासी या धरोहरधर्ता (Beneficiary or Bailor) का होता है। जिस समय कोई ग्राहक बैंक के पास सोना, चांदी, आभूषण तथा अन्य बहुमूल्य पदार्थ तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज इत्यादि सुरक्षा के लिए रखता है तो बैंक धरोहरधारी या प्रत्यासी बन जाता है। इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने के लिए बैंक कुछ कमीशन या शुल्क लेता है। सुरक्षा के लिए बैंक को सौंपी गई वस्तुओं को उसी रूप में ग्राहक को लौटाने के लिए बैंक उत्तरदायी है। बैंक को इन वस्तुओं की सुरक्षा के लिए यथोचित प्रयत्न करना चाहिए। यदि बैंक यह प्रयत्न न करे और उसकी असावधानी के कारण धरोहर की वस्तु लो जाय या नष्ट हो जाये तो बैंक को ग्राहक की क्षतिपूर्ति करनी होगी। यदि बैंक उन वस्तुओं को किसी अन्य व्यक्ति के पास रख देता है और वस्तुओं को कोई हानि

पहुँचती है तो बैंक ग्राहक के प्रति उत्तरदायी होगा चाहे उसन पर्याप्त सावधानी ने ही काम बयो न किया हो ।

धरोहरधारी के रूप में बैंक का उत्तरदायित्व इस बात पर भी निर्भर करना है कि इस कार्य के लिए बैंक कुछ शुल्क लेता है या नहीं । बहुमूल्य वस्तुप्राप्त का सुरक्षा प्रदान करने के लिए जब बैंक कुछ शुल्क लेता है तो बैंक का उत्तरदायित्व अधिक होता है । परन्तु इस सम्बन्ध में मतभेद है कि जब बैंक इस कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लेता तो वह पारिश्रमिक प्राप्त धरोहरधर्ता माना जाय या नहीं । कुछ विद्वानों का मत है तो उस समय भी उसे पारिश्रमिक प्राप्त धरोहरधर्ता माना जाना चाहिए क्योंकि बैंक ग्राहकों को यह सुविधा उनका अपनी ओर आकर्षित करत क लिए देता है जिसमें बैंक उनके खातों का लाभ उठा सके । यदि बैंक ऐसी सुविधायें अपने ग्राहकों को न दे तो वे दूसरे बैंकों में चले जाय । कुछ दशा में इस प्रकार का नियम है कि यदि बैंक धरोहर को सुरक्षित रखन की मवा के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लेते है और इस सम्बन्ध में उनको घोर प्रसावधानी सिद्ध न हो तो बैंक क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होते परन्तु भारत के कानून के अनुसार बैंक की प्रसावधानी के कारण धरोहर की वस्तु की हानि के लिए बैंक उत्तरदायी है चाहे बैंक पारिश्रमिक लेता हा या न लेता हो ।

ग्राहकों के प्रति बैंक के विशेष उत्तरदायित्व

(Special Obligations of Banks towards Customers)

अभी तक वर्णित तीनों प्रकार के बैंक और ग्राहक के पारस्परिक सम्बन्ध 'साधारण सम्बन्ध' (General Relations) के रूप में जान जाते हैं परन्तु ऋणी और ऋणदाता के प्रमुख सम्बन्ध के अन्तर्गत बैंक की कुछ विशेष जिम्मेदारियाँ (Special Obligations) तथा अधिकार होते हैं जिन्हें बैंक और ग्राहक के विभिन्न सम्बन्ध (Special Relations) की श्रेणी में रखा जाता है । यहाँ हम बैंक और ग्राहक के इन्हीं विशिष्ट सम्बन्धों की व्याख्या करेंगे —

(1) चेकों के भुगतान का दायित्व (Bankers obligation to pay Customers cheques) : बैंक का यह प्रमुख दायित्व है कि वह अपने ग्राहकों द्वारा लिखे गये चेकों का भुगतान करे जिनकी रकम जमा की रकम की सीमा तक हा या उस सीमा तक हो जिस तक बैंक न ग्राहक को अतिविकर्ष (Overdraft) की स्वीकृति दी हो, जो उपयुक्त रूप में लिया गया हो तथा लेखन की तिथि के उचित समय के भीतर (within reasonable time after their dates of issue) बैंक के समक्ष उपस्थित किया गया हो । भारत में लखन तिथि के 6 माह व्यतीत हा जान पर चेक पुराना (Stale) हा जाता है और बैंक उसका भुगतान नहीं करते । बैंकर को ग्राहकों द्वारा खातों से रकमें निकालने से पहले रकमों को जमा करने का पर्याप्त

समय दिया जाना चाहिए। अतः बैंक ग्राहको की चेको तथा डपटो को रकम वसूल होने से पहले उनके खाते में जमा करने तथा ऐसे चेको, जो जमा किए गये चेको तथा ड्राफ्ट के दिवस में लिखे गये हैं, का भुगतान करने को बाध्य नहीं है। यदि बैंक अकारण या बिना औचित्य के ग्राहको के चेको का भुगतान करने से इन्कार कर देता है तो ग्राहको की साख की हानि की क्षति पूर्ण करने के लिए वह उत्तरदायी है। ग्राहक बैंक से असाधारण (Substantial) क्षति की पूर्ति करवा सकता है यदि वह यह सिद्ध कर सके कि उसकी साख की हानि हुई है चाहे उसे कोई मौद्रिक हानि न भी हुई हो। क्षति पूर्ति की रकम तभी अधिक नहीं होगी जब चेक का रकम अधिक होता है वरन् छोटी रकम के चेक के प्रस्वीकृत होने पर ग्राहक का साख को हानि बड़ी ही घातक होती है और वह अधिक क्षति पूर्ति का दावा कर सकता है। साख को हुई हानि का अनुमान लगाने समय न्यायालय ग्राहक की वित्तीय स्थिति उसकी वादसायिक प्रसिद्धि, उसके व्यापार की रातिया इत्यादि तत्वों का विचार करते हैं।

कुछ परिस्थितियों में बैंक को चाहिए कि वह ग्राहक के चेका का भुगतान न करे जैसे यह सूचना मिलने पर कि ग्राहक पागल या दिवानिया हो गया है, ग्राहक न किसी चक का भुगतान न करने का लिखित आदेश दिया है या ग्राहक से चेक खा गया है।

(2) बैंक का सामान्य ग्रहणाधिकार (Banker's General Lien)
ग्रहणाधिकार का अर्थ होता है वस्तुओं को रोक रखने या ग्रहण कर लेने का अधिकार। (The right to retain goods is known as lien) यदि बैंक का कुछ रुपया ग्राहक पर बाका है तो बैंक रुपया वसूल करने के लिए ग्राहक की उस रकम प्रतिभूति या सम्पत्ति को, जो उस बैंकर के हाथ प्राप्त हुई है, रोक लेने का अधिकार है। यह सामान्य ग्रहणाधिकार उन सभी रकमों तथा प्रतिभूतियों पर लागू होता है जो बैंक के पास आती हैं और जो विशिष्ट कार्यों के लिए निश्चिन्त नहीं की गई हैं। (It extends to all funds and securities coming into the hands of the banker which are not specifically appropriated)

निम्नलिखित वस्तुओं पर बैंक को ग्रहणाधिकार नहीं मिल सकता —

(अ) सुरक्षा जमा तथा T/T (Telegraphic Transfers) इत्यादि न्य करने के लिए जमा (Valuables for safe custody and money deposited for purchase of Telegraphic Transfers etc) ग्राहक द्वारा सुरक्षा के लिए बैंक के पास जो मूल्यवान वस्तुएँ जमा साना, चादी, आभूषण अथवा प्रतिभूतिया इत्यादि जमा करवाया गइ हैं या कुछ रकम T/T इत्यादि क्रय करने के लिए जमा करवाया गइ है ता किमी नियमित भुगतान की वसूली के लिए बैंक इन्हें नहीं रोक

सकता। किन्तु यदि बैंक के पास प्रतिभूतियाँ जमा करायी जाती हैं और बैंक को उन प्रतिभूतियों के कूपन निकालकर ब्याज वसूल करने के लिए अधिकृत किया जाता है तो बैंक को कूपन तथा प्रतिभूतियों दोनों पर ग्रहणाधिकार प्राप्त हो जाता है क्योंकि यहाँ बैंक ये प्रतिभूतियाँ एक सग्रहण-प्रतिनिधि के रूप में प्राप्त करता है। लेकिन यदि ग्राहक स्वयं कूपन निकालकर उनका ब्याज वसूल करने के लिए बैंक को देता है और प्रतिभूतियाँ सुरक्षा हेतु जमा करवाता है तो ग्रहणाधिकार केवल कूपनो पर लागू होगा, प्रतिभूतियों पर नहीं।

(ब) भूल से चक के पास छूटी हुई प्रतिभूतियाँ (Securities left with banker through mistake or inadvertence) यदि ग्राहक भूल से बैंक के पास कुछ प्रतिभूतियाँ पड़ी रखे तो उन पर बैंक ग्रहणाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेगा क्योंकि उन्हें वह बैंक की हैसियत से प्राप्त नहीं करता। यदि कोई ग्राहक बैंक को ऋण की जमानत के तौर पर कुछ प्रतिभूतियाँ देता है और किसी कारणवश ऋण स्वीकृत न होना पर भी वे बैंक के पास पड़ी रहनी हैं तो उन पर बैंक को ग्रहणाधिकार नहीं होगा परन्तु ऋण स्वीकृत हो और उसका भुगतान निश्चित तिथि पर कर दिया जाय और फिर भी प्रतिभूतियाँ बैंक के पास पड़ी रहे तो उन पर बैंक का सामान्य ग्रहणाधिकार होगा।

(स) विशिष्ट कार्यों के लिए जमाये (Deposits with specific purposes) : यदि ग्राहक कुछ रकम, चेके बिल इत्यादि विशिष्ट कार्यों में प्रयुक्त करने के आदेश सहित जमा कराये तो उन्हें बैंक उन्हीं विशिष्ट कार्यों में प्रयुक्त करने के लिए बाध्य है और उन्हें अपने सामान्य भुगतान की वसूली के लिए नहीं रोक सकेगा।

(द) विक्रय हेतु जमा सम्पत्ति (Property assigned for sale) . यदि कोई ग्राहक अपनी सम्पत्ति बेचने के लिए बैंक के पास जमा करवाता है तो ऐसी सम्पत्ति पर बैंक का सामान्य ग्रहणाधिकार नहीं होगा क्योंकि ग्राहक की सम्पत्ति बेचना बैंक का नियमित बैंकिंग व्यवसाय नहीं है।

(घ) अपरिपक्व ऋण (Loans not matured) यदि ग्राहक द्वारा लिए गये किसी ऋण की भुगतान तिथि नविष्य में आने वाली है तो भुगतान तिथि के आने तक बैंक जमा सम्पत्ति पर ग्रहणाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता।

अतः बैंक को ग्रहणाधिकार तभी मिल सकता है जब निम्नलिखित आवश्यक शर्तें पूर्ण होती हों

(1) वह वस्तु या रकम बैंक को बैंक की हैसियत से या बैंकिंग के नियमित व्यवसाय के अंतर्गत तथा बैंक रूप में प्राप्त हुई हो,

(ii) वह वस्तु किसी विशिष्ट कार्य में प्रयुक्त होने के लिए बैंक के पाम न जमा करायी गई हो,

(iii) ग्राहक तथा बैंक के बीच कोई ऐसा समझौता न हो जिससे ग्रहणाधिकार लागू न हो सके। (There should be no express contract, or circumstances that show an implied contract, inconsistent with lien (Brandao vs Barnett))

(3) खाते की गोपनीयता (Secrecy of the Customers Account) - बैंकर का यह महत्वपूर्ण दायित्व है कि वह अपने ग्राहक के खाते के शेष या वास्तविक स्थिति को पूरातया गुप्त रखे और उसे किसी बाहरी व्यक्ति को न बताय जिससे कि ग्राहक की साख पर आच आये। यदि बैंक इस सम्बन्ध में अपने दायित्व को सावधानी पूर्वक न निभाये और ग्राहक को कोई हानि हो जाय तो बैंक क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है। बैंक का यह दायित्व रीति पर आधारित था परन्तु बाद में Tournier Case में इसे न्यायिक मान्यता प्रदान की गई। इस निर्णय में यह व्यवस्था दी गई थी कि बैंकर उचित तथा उपयुक्त परिस्थितियों को छोड़कर अपने ग्राहक के खाते की स्थिति की सूचना किसी को नहीं देगा और बैंक के इस दायित्व का खाता बंद हो जाने पर भी अंत नहीं होगा।

परन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में बैंकर ग्राहक के खाते के तथ्यों को प्रकट कर सकता है —

(i) न्यायालय के आदेश पर (By an order of a Court) यदि किसी न्यायालय के आदेश पर खाते के सम्बन्ध में सूचना देना आवश्यक हो जाय तो बैंक का कोई दायित्व नहीं होगा।

(ii) बैंक का रेफरी के रूप में नाम देने पर (Where customer has given his banker's name as a referee) जब ग्राहक स्वयं बैंक का नाम रेफरी के रूप में देता है तो ध्यावसायिक पूछताछ के उत्तर में बैंक सूचनाएँ दे सकता है।

(iii) राष्ट्रीय दायित्व के रूप में सूचना (When under a public duty to disclose) देशद्रोह तथा राष्ट्र की सुरक्षा को मज की स्थितियों में बैंक ग्राहक के खाते के सम्बन्ध में सूचनाएँ दे सकता है।

(iv) अपने हित की रक्षा में (When the protection of bankers own interests legally requires it) कमी कमी बैंक स्वयं अपने हित में जैसे ऋण की रकम बसूल करने के लिए दावा करने पर खाते की सूचना दे सकता है।

(4) प्रासंगिक व्यय लेने का अधिकार (Right to realise Incidental Charges) — बैंक को ग्राहक का खाता रखन में कुछ व्यय करना होता है। इसलिए ग्राहक के हौदों की मात्रा के आधार पर बैंक वापिक या अग्र वापिक खाते में एक पूर्व निश्चिन राशि से कम जमा रहन पर प्रासंगिक व्यय लेते हैं।

(5) चक्र वृद्धि व्याज लगाने का अधिकार (Right to charge Compound interest) — बैंक को अपने ग्राहक से, यदि कोई विपरीत समझौता न हो, अभीष्ट चक्र वृद्धि व्याज प्राप्त करने का अधिकार है।

बैंक और ग्राहक के पारस्परिक सम्बन्ध को उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि बैंक और ग्राहक के सम्बन्धों का दो दृष्टिकोणों से विचार दिया जाना चाहिए— वैधानिक (Legal) तथा व्यवहारिक (Practical)। बैंक का वैधानिक आवश्यकताओं तथा नियमों का पालन तो करना ही पड़ता है परन्तु व्यवहारिक बैंकर के नाते नियमों के सम्बन्ध में वह बिल्कुल जड़ भी नहीं हो सकता। अतः इस दिशा में बैंक को एक सम्यक् तथा नतिशील नीति बनानी चाहिए जिसमें वह अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर अपने व्यापार का विस्तार कर सके और देश के व्यापार तथा वाणिज्य के विकास में अधिक से अधिक योगदान कर सके।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संकेत

(1) बैंकर किसे कहते हैं? बैंकर का ग्राहक किसे कहा जाता है? उनके मध्य सम्बन्धों का वर्णन कीजिए।

(आगरा बी० काम०, 1957)

[संकेत—प्रश्न भाग में बैंकर तथा ग्राहक की परिभाषायें दीजिए। दूसरे भाग में बैंकर और ग्राहक के ऋणी तथा ऋणदाता, प्रतिनिधि तथा प्रधान और प्रत्यासी के रूप में पारस्परिक सम्बन्धों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए।]

(2) बैंक और ग्राहक के पारस्परिक सम्बन्धों की परीक्षा कीजिए।

(राजस्थान बी० काम०, 1960)

[संकेत—भूमिका स्वरूप बैंकर और ग्राहक की सक्षिप्त परिभाषायें देते हुए उनके बीच ऋणी तथा ऋणदाता, प्रतिनिधि तथा प्रधान और प्रत्यासी तथा प्रत्यासी के रूप में उनके पारस्परिक सम्बन्धों की विवेचना कीजिए।]

केन्द्रीय बैंकिंग (Central Banking)

"There have been three great inventions since the beginning of time - Fire, the Wheel, and Central Banking"

Will Rogers

आधुनिक समय में ससार के सभी देशों में एक ऐसा विशिष्ट बैंक होता है जो देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग व्यवस्था पर नियन्त्रण तथा नियमन रखता है। देश की बैंको तथा व्यापार-उद्योग के निकट सम्पर्क में रहकर वह देश हित में साख का विस्तार तथा सकुचन करता है। ऐसे बैंक का केन्द्रीय बैंक (Central Bank) कहा जाता है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में उसका केन्द्रीय स्थान होता है। ससार के लगभग सभी देशों में ऐसे बैंक स्थापित हैं और उनके द्वारा समाज की अभूतपूर्व सेवा हुई है। इसीलिए रोजर्स (Rogers) ने केन्द्रीय बैंकिंग को ससार के तीन आविष्कारों में से एक माना है।

केन्द्रीय बैंकिंग का विकास (Evolution of Central Banking)

केन्द्रीय बैंकिंग का आरम्भ कब हुआ बताना बड़ा कठिन है। इस शताब्दी के पूर्व तक "केन्द्रीय बैंकिंग के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट धारणा नहीं थी।"¹ अधिकतर प्राचीन देशों में कोई एक बैंक नोट निर्गमन का एकाधिकार तथा सरकारी बैंक के रूप में कार्य करने के कारण धीरे धीरे केन्द्रीय बैंक का स्थान ग्रहण करता गया। आरम्भ में उन्हें केन्द्रीय बैंक न कहकर निर्गम बैंक (Bank of Issue) अथवा राष्ट्रीय बैंक (National Banks) कहा जाता था परन्तु शनैः शनैः ये बैंक केन्द्रीय बैंक के अन्य कार्य भी करने लगे और इसी नाम से पुकारे जाने लगे। वर्तमान केन्द्रीय बैंको में स्वीडन का रिक्स बैंक (Riksbank of Sweden) सबसे अधिक प्राचीन है क्योंकि इसकी स्थापना 1656 ई० में हुई परन्तु 1694 ई० में स्थापित बैंक ऑफ इंग्लैंड

¹. "Prior to the beginning of the twentieth century there had been no clearly defined concept of central Banking"

—M. H. De Kock : *Central Banking* (Third Edition), p.1

(Bank of England) प्रथम निर्गम बैंक था जिनने केन्द्रीय बैंक के कार्य करने प्रारम्भ किए। इसीलिए बैंक आफ इंग्लैण्ड को 'केन्द्रीय बैंको की जननी' (Mother of Central Banks) तथा 'थ्रेडनीडल गली की वृद्ध महिला' (Old Lady of the Threadneedle Street) कहा जाता है तथा बैंक आफ इंग्लैण्ड का इतिहास केन्द्रीय बैंक के सिद्धान्तों तथा कार्य शैली के विकास का इतिहास माना जाता है। बैंक आफ इंग्लैण्ड की स्थापना 1694 ई० में सरकार को ऋण देने के लिए अधिधारियों व बैंक के रूप में संसदीय विधान (under a special charter of Parliament) के अन्तर्गत हुई थी और इसके बदले उसे नोट निगमन करने का अधिकार दिया गया। उस समय बैंक आफ इंग्लैण्ड को नोट निर्गमन का एकाधिकार नहीं था और अन्य व्यापारिक बैंक भी नाट निर्गमन करते थे। 1844 के बैंक एक्ट (Bank Act of 1844) के अन्तर्गत अन्य बैंको के नोटों की यात्रा उस समय की प्रचलित माना पर सीमित कर दी गई और कुछ परिस्थितियों में उनके नोटों की समाप्ति की व्यवस्था कर दी गई। इस प्रकार बैंक आफ इंग्लैण्ड को नाट निर्गमन का आंशिक एकाधिकार (Partial Monopoly) हो रहा। बैंक आफ इंग्लैण्ड के नोट निर्गमन के आंशिक एकाधिकार तथा सरकारी बैंक के कार्यों के फलस्वरूप उसकी विशिष्ट स्थिति के कारण अन्य बैंको ने इस बैंक में कोष रखने प्रारम्भ किए जिससे यह बैंक बैंको के नकद कोषों तथा इस प्रकार देश के स्वर्ण कोषों का संरक्षक (Custodian of the Cash Reserves of Private Banks, and thus of the Country's gold reserves) बन गया। इस दिशा में सन् 1854 के बाद विशेष उन्नति हुई जब समाशोधन-गृह (Clearing House) प्रणाली का जन्म हुआ।

बाद में बैंक आफ इंग्लैण्ड पर अन्य बैंको की सहायता का दायित्व भी आ पड़ा और यह बैंक बेजहाट (Bagehot) की शताब्दी में 'आपत्ति काल का अन्तिम ऋणदाता (Lender of last resort) समझा जान लगा। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक साख नियन्त्रण के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में 'बैंक दर' की महत्ता स्थापित हो चुकी थी। प्रथम महायुद्ध के बाद की सत्तार की आर्थिक परिस्थितियों में बैंक दर के अतिरिक्त साख नियन्त्रण के अन्य साधनों का भी उदय हुआ। केन्द्रीय बैंक के रूप में बैंक आफ इंग्लैण्ड की सफलता ने सत्तार के अन्य देशों में केन्द्रीय बैंको के विकास को प्रोत्साहित किया।

फ्रांस में बैंक आफ फ्रांस (Bank of France) की सन् 1800 में तथा जर्मनी में रीच बैंक (Reichs Bank) की सन् 1875 में स्थापना हुई थी। बैंक आफ नीदरलैंड्स (The Bank of Netherlands) सन् 1814 में स्थापित हुई थी। दि नेशनल बैंक आफ आस्ट्रिया तथा बैंक आफ नार्वे सन् 1817, नेशनल बैंक आफ डेनमार्क सन् 1818, नेशनल बैंक आफ बेल्जियम सन् 1850 तथा बैंक आफ स्पेन सन् 1856 में

स्थापित हुई थी। बैंक ऑफ रशिया (Bank of Russia) की स्थापना सन् 1860 में हुई। जापान की मौद्रिक अव्यवस्था दूर करने के लिए सन् 1882 में बैंक ऑफ जापान स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त 19वीं शताब्दी में पुर्तगाल, रमानिया, बल्गारिया, टर्की, जावा, मिस्र तथा अल्जीरिया में भी केन्द्रीय बैंको की स्थापना हुई। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के अन्त तक योरोप के लगभग सभी देशों में पूर्व में जापान, जावा तथा परसिया में तथा अफ्रीका में मिस्र तथा अल्जीरिया में विशिष्ट अधिकार प्राप्त निर्गमन बैंक के रूप में केन्द्रीय बैंको की स्थापना हो चुकी थी। 20वीं शताब्दी में भी केन्द्रीय बैंको के विकास का क्रम जारी रहा। 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक भारत तथा चीन जैसे देशों में केन्द्रीय बैंक नहीं थे। अमेरिका में सन् 1907 के वित्तीय संकट में वहाँ की विकेंद्रित बैंकिंग व्यवस्था के दोषों को प्रकट किया और उनकी जाच के लिए विशेष आयोग की नियुक्ति हुई। परिणामस्वरूप सन् 1914 में 12 फेडरल रिजर्व बैंको तथा धाशिंगटन में फेडरल रिजर्व बोर्ड की स्थापना द्वारा वहाँ भी एक केन्द्रीय बैंकिंग व्यवस्था को जन्म दिया गया।

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् राष्ट्रवाद के उदय तथा आर्थिक जीवन में राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता ने केन्द्रीय बैंकिंग के विकास को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। सन् 1920 में ब्रुसेल्स (Brussels) में हुए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त सम्मेलन (International Financial Conference) में एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया, जिसमें कहा गया कि जिन देशों में केन्द्रीय बैंक स्थापित नहीं हुए हैं उन देशों में शीघ्रातिशीघ्र केन्द्रीय बैंक स्थापित करके न केवल देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग व्यवस्था में स्थिरता लानी चाहिए बल्कि विश्व मौद्रिक सहयोग भी बढ़ाना चाहिए।

सन् 1920 से अगले 30 वर्षों में सप्तर के विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्रीय बैंको की स्थापना को प्रोत्साहन मिला जैसा कि डी कोक (M. H. De Kock) द्वारा दी गई निम्न सूची से प्रकट होता है —

स्थापना का वर्ष	केन्द्रीय बैंक का नाम
1921	1 South African Reserve Bank
1922	1 Reserve Bank of Peru (reconstituted as Central Reserve Bank of Peru in 1931) 2 Bank of Latvia 3. Bank of Lithuania
1923	1. Bank of the Republic of Colombia

स्थापना का वर्ष	केन्द्रीय बैंक का नाम
1924	1 National Bank of Hungary. 2 Bank of Poland. 3 Bank of Danzig 4. Commonwealth Bank of Australia and Bank of the Republic of Uruguay converted into central Banks
1925	1 National Bank of Albania
1926	1 National Bank of Czechoslovakia. 2. Central Bank of Chile 3. Central Bank of Guatemala (replaced by Bank of Guatemala in 1946.)
1927	1 Central Bank of Ecuador 2. Bank of Estonia Converted into a central bank.
1928	1 Central Bank of China 2 National Bank of Persia (Iran) 3. Central Bank of Bolivia 4. Bank of Greece (In place of National Bank of Greece) 5. National Bank of Iceland converted into a central bank
1931	1 Central Bank of Turkish Republic.
1932	1 Bank of Mexico converted into a central bank.
1934	1 Reserve Bank of New Zealand 2. Central Reserve Bank of Salvador.
1935	1. Bank of Canada 2. Reserve Bank of India. 3. Central Bank of Argentine Republic
1936	1. Bank of Republic of Paraguay (reconstituted as Bank of Paraguay in 1944)
1937	1 National Bank of Costa Rica (replaced by Central Bank of Costa Rica in 1950.)
1940	1. Central Bank of Venezuela
1941	1. National Bank of Afghanistan 2. National Bank of Nicaragua converted into a central Bank.
1942	1. Central Bank of Ireland 2. Bank of Thailand. 3. State Bank of Ethiopia.

स्थापना का वर्ष	केन्द्रीय बैंक का नाम
1945	1. National Bank of Poland.
1947	1. Central Bank of Dominican Republic.
1948	1. State Bank of Pakistan 2. Union Bank of Burma 3. Central Bank of Philippines. 4. National Bank of Cuba.
1949	1. National Bank of Iraq.
1950	1. Central Bank of Ceylon 2. Central Bank of Honduras.
1952	1. Central Bank of Belgian Congo. 2. Bank of Issue of Associated States of Indo China
1954	1. Bank of Israel.
1957	1. Bank of Ghana.
1958	1. Central Bank of Tunisia, 2. Central Bank of Malaya (renamed as the Central Bank of Malaysia in 1963)
1959	1. Central Bank of the States of West Africa 2. Central Bank of the States of Equatorial Africa and of Cameroon. 3. Bank of Morocco 4. Central Bank of Nigeria.
1960	1. Bank of Sudan 2. Bank of the Republic of Guinea 3. Somali National Bank.
1962	1. Bank of Jamaica 2. Malagasy Bank of Issue. 3. Bank of Republic of Mali.
1963	1. Central Bank of Algeria. 2. Central Bank of Cyprus.
1964	1. Bank of Lebanon. 2. National Bank of Rwanda. 3. Bank of Kingdom of Burundi 4. National Bank of the Congo (Leopoldville).

कुछ अपवादों को छोड़कर अब सशर में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ केन्द्रीय बैंक न हो। अनुमानतः सशर में इस समय सी से कुछ अधिक केन्द्रीय बैंक हैं और उनमें से प्रायः से अधिक सन् 1940 के बाद स्थापित हुए हैं। केन्द्रीय बैंकिंग के विकास के कई कारण रहे हैं।

केन्द्रीय बैंकों की स्थापना के कारण (Causes of establishment of Central Banks) : केन्द्रीय बैंकों के तीव्रगति से विस्तार के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

1. मुद्रा व्यवस्था का नियमन (Regulation of Monetary System) : सप्ताह में सन् 1931 के बाद स्वयंमान के समाप्त हो जाने से मुद्रा मान की स्वयं-मचालिता का गुण नष्ट हो गया । पर मुद्रामानों के प्रवन्ध तथा मुद्रा के नियंत्रण और नियमन के उत्तरदायित्व का वहन करने के लिए एक केन्द्रीय सस्था की आवश्यकता अनुभव की गई ।

2. बैंकिंग व्यवस्था का नियंत्रण (Control of the Banking System) : बैंकिंग व्यवस्था के विकास के कारण उसमें काफी जटिलता आ गई और बैंकों के नियंत्रण तथा भागद्वान के लिए सरकार द्वारा सरक्षण प्राप्त किसी केन्द्रीय सस्था की स्थापना को प्रोत्साहन मिला ।

3. देशों की बैंक व्यवस्थाओं के बीच कड़ी (Means of communication between the banking system of one country and another) : देशों को युद्धोत्तरकाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नयी वित्तीय समस्याओं का सामना करना पडा । अंतर्राष्ट्रीय लेन देन तथा देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय बैंकों की स्थापना आवश्यक हो गई । केन्द्रीय बैंकिंग के विद्वान् डा० डी काक के शब्दों में, "केन्द्रीय बैंकों के विकास का एक कारण यह अनुभव रहा है कि एक देश तथा दूसरे देश की बैंकिंग व्यवस्थाओं के बीच सहयोग तथा आदान-प्रदान का सर्वोत्तम साधन केन्द्रीय बैंक ही है ।"¹

उपरोक्त कारणों ने सप्ताह के विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्रीय बैंकों की स्थापना को प्रोत्साहित किया ।

केन्द्रीय बैंक की परिभाषा (Definition of a Central Bank)

केन्द्रीय बैंक देश की बैंकिंग व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु होता है और उसके कार्य तथा उत्तरदायित्व बड़े विस्तृत तथा प्रभावकारी होते हैं । केन्द्रीय बैंक की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों तथा वित्त विशेषज्ञों ने निम्न निम्न प्रकार से की है । विद्वानों ने केन्द्रीय बैंक के कार्यों के आधार पर अपनी अपनी परिभाषायें दी हैं । प्रो० आर०पी० केन्ट (Prof. R P. Kent) के शब्दों में "केन्द्रीय बैंक एक ऐसी सस्था है जिसे

1. "Another factor is the realisation that a central bank offers the best means of communication and cooperation between the banking system of one country and that of another."

सामान्य जन्-हित में मुद्रा की मात्रा के विस्तार तथा सकुचन का उत्तरदायित्व सौंपा गया हो।¹ केन्ट के अनुसार मुद्रा तथा साख का नियंत्रण करने वाली संस्था केन्द्र बैंक कहलाती है। बैंक ऑफ कनाडा अधिनियम 1934 में केन्द्रीय बैंक को इस प्रकार परिभाषित किया गया है - "केन्द्रीय बैंक वह है जो देश के आर्थिक जीवन के सर्वोत्तम हित में साख तथा मुद्रा का नियमन करे, राष्ट्रीय मौद्रिक इकाई के बाह्य मूल्य का नियंत्रण तथा संरक्षण करे तथा यथा सम्भव अपने मौद्रिक कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत प्रभाव डालकर उत्पादन व्यापार, मूल्य तथा रोजगार के उच्चावचनों को रोके।"² बैंक ऑफ कनाडा अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय बैंक वह संस्था है जो साख तथा मुद्रा का नियमन करे, मुद्रा के आंतरिक तथा बाह्य मूल्य में स्थिरता तथा अर्थ-व्यवस्था में उच्चावचनों को रोके।

बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटिलमेंट्स (Bank of International Settlements) के अनुसार, "केन्द्रीय बैंक किसी देश का वह बैंक है जिसे वहाँ के चलन तथा साख की मात्रा के नियमन का कर्तव्य सौंपा गया हो।"³ इस परिभाषा में भी केन्द्रीय बैंक के मुद्रा तथा साख के नियमन के कार्य का उल्लेख किया गया है। किश तथा एल्किन (Messrs Kisch and Elkin) के शब्दों में, "केन्द्रीय बैंक वह बैंक है जिसका प्रमुख कार्य मुद्रा मान की स्थिरता को बनाये रखना होता है।"⁴ इस परिभाषा के अन्तर्गत मुद्रा तथा साख पर पूर्ण नियंत्रण आ जाना है।

केन्द्रीय बैंक की कुछ अन्य परिभाषायें इस प्रकार हैं -

ओ० एम० स्प्रेग (O M Sprague) "केन्द्रीय बैंक के विशेष कार्यों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है वे सरकारी के प्रशुल्क अधिकर्ता के

1. ".....it may be defined as an institution charged with the responsibility of managing the expansion and contraction of the volume of money in the interest of general public welfare"

—R P Kent *Money and Banking* p 351

2. ".....the Bank is to regulate credit and currency in the best interests of economic life of the nation, to control and to protect the external value of the national monetary unit and to mitigate by its influence fluctuations in the general level of production, trade, prices and employment so far as may be possible within the scope of monetary action"

—*Bank of Canada*

3. "the bank in any country to which has been entrusted the duty of regulating the volume of currency and credit in that country"

—*Statutes of the Bank for International Settlements*

4. "The essential function of a central bank is the maintenance of the stability of the monetary standard which involves the control of the monetary circulation"

—Kisch and Elkin. *Central Banks* (Fourth Edition), p. 74.

रूप में कार्य करते हैं; नोट-निर्गमन के लगभग पूर्ण एकाधिकार द्वारा चलन पर नियंत्रण के बहुत अधिकार रखते हैं तथा, अंतिम रूप से, चूँकि उनके पास अन्य बैंकों के कोषों का अधिकतर भाग जमा रहता है अतः साख पर नियंत्रण करने का कार्य भी करते हैं। यह अंतिम कार्य केन्द्रीय बैंक का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य है।”¹

भारतीय मुद्रा तथा वित्त आयोग के समक्ष बैंक आफ इंग्लैंड के गवर्नर : “केन्द्रीय बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार होना चाहिए; इसको विधि-ग्राह्य मुद्रा निकालने तथा वापिस लेने का माध्यम—एक मात्र माध्यम होना चाहिए। इसे सभी सरकारी कोषों का धारक तथा देश की सभी बैंकों तथा उनकी शाखाओं के सभी कोषों का धारक होना चाहिए। इसे एक ऐसे अभिजाति का कार्य करना चाहिए जिसके द्वारा देश की सरकार के आंतरिक तथा बाह्य वित्तीय कार्य सम्पन्न हो सके। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक का यह भी दायित्व होगा कि वह सामान्य स्थायित्व के उद्देश्य के अतिरिक्त (साख का) उपयुक्त विस्तार तथा संकुचन करे और आंतरिक तथा बाह्य स्थायित्व बनाये रखे। उसे आवश्यकता के समय ऋण प्राप्त करने का ऐसा अन्तिम स्रोत होना चाहिए जहाँ से स्वीकृत विलों का बढ़ा करार या स्वीकृत अल्पकालीन प्रतिभूतियों या सरकारी पत्रों की आड़ पर आवश्यक राशि प्राप्त हो सके।”²

1. “The special functions of the central banks may be grouped under three heads : they serve as fiscal agents of governments; they have large powers of control over currency through more or less complete monopoly of note issue; and finally, since they hold a large part of the reserves of other banks, they are directly responsible for the foundation of the central bank.” — O M Sprague.

2. It should have the sole right of note-issue, it should be the channel and the only channel for the output and intake of legal tender currency. It should be the holder of all the government balances, the holder of all the reserves of other banks and the branches of all banks in the country. It should be agent, so to speak, through which the financial operations at home and abroad, of the government would be performed. It would further be the duty of the central bank to effect, as far as it could, suitable contraction and suitable expansion, in addition to aiming at general stability, and to maintain that stability within as well as without. When necessary it would be the ultimate source from which necessary funds might be obtained in the form of rediscounting of approved bills or advances on approved short securities or government paper.” — Governor, Bank of England ; *Report of the Royal Commission on Indian Currency and Finance, 1926—Evidences.*

वेरास्मिथ (Vera Smith) : “केन्द्रीय बैंकिंग का मुख्य अन्विष्ट उक्त बैंकिंग व्यवस्था से है जिसमें किसी एक बैंक को नोट निर्गमन का पूर्ण या शेष एकाधिकार प्राप्त हो। इसी नोट निर्गमन के एकाधिकार से हमारी आधुनिक केन्द्रीय बैंको के सहायक कार्य तथा लक्षण निकले हैं।”¹

हाट्टे (R.G. Hawtrey) : “केन्द्रीय बैंक बैंको का बैंक है। समाज के अन्य बैंको—प्रतिस्पर्धी बैंको—को बही सुविधायें देता है जो वे अपने ग्राहको को देते हैं। केन्द्रीय बैंक के पास जमा कोषों को निकालकर प्रतिस्पर्धी बैंक एक दूसरे को भुगतान करती है, अपने व्यापार की आवश्यकतानुसार वे जमा कोषों के आधार पर चलन निकालते हैं या जमा करती हैं और जमा कोषों के कम हो जाने पर केन्द्रीय बैंक से ऋण लेकर उन्हें पूरा करती हैं।”²

शा (Shaw) : “एक स्वचालित तथा स्वनियमित चलन के लिए राज्य को नोट निर्गमन करना चाहिए और यदि चाहे तो उनके वितरण के लिए केन्द्रीय बैंक का प्रयोग करे।...केन्द्रीय बैंक का एक मान सत्य तथा साथ में अपने में पूर्ण कार्य माख का नियंत्रण करना है।”³

जॉन्से (Jauncey) . “समाशोधन (Clearing) ही केन्द्रीय बैंक का मुख्य कार्य है।”⁴

1. “The primary definition of central banking is a banking system in which a single bank has either a complete or residuary monopoly in the note issue”, and that, “it is out of monopolies in the note issue that were derived the secondary functions and characteristics of our modern central banks.”

—Vera Smith : *Rationale of Central Banking*

2. “A central bank is a banker's bank. It affords to the other banks of the community, the competitive banks, the same facilities as they afford to their customers. The competitive banks make payments to one another by drawing on balances at the central bank, they draw out currency against those balances or pay currency in, as their business may require, and they replenish their balances, when low by borrowing from the central bank.”

—R.G. Hawtrey *The Art of Central Banking*, 1962, p 116

3. “In order to have an automatic, self-regulatory currency the state should issue notes and use the central bank only for the distribution of notes, if at all....the one true, but at the same time all-sufficient function of a central bank is control of credit.”

—Shaw : *Theory and Principles of Central Banking*, pp V and 78-80.

4. “Clearing is the main operation of central banking.”

—Jauncey : *Australia's Government Bank*, p 166

केन्द्रीय बैंक की विभिन्न परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट है कि केन्द्रीय बैंक का कार्य क्षेत्र कितना विस्तृत तथा महत्वपूर्ण है और केन्द्रीय बैंक के सभी कार्यों का विवेचन किसी एक परिभाषा में नहीं है। अतः ये सभी परिभाषायें केन्द्रीय बैंक के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट तो करती हैं परन्तु पूर्ण नहीं कही जा सकती। अन्त में हम केन्द्रीय बैंक की विस्तृत तथा सर्वोत्तम परिभाषा देते हैं जो केन्द्रीय बैंकिंग के प्रवाह पंडित डा० एम०एच०डी० काक ने अपनी पुस्तक 'Central Banking' में दी है—

“केन्द्रीय बैंक उस बैंक को कहते हैं जो देश के राष्ट्रीय आर्थिक हित में निम्नलिखित कार्यों को करती है

- (1) व्यापार तथा सामान्य जनता की आवश्यकतानुसार चलन का नियमन करना जिसके लिए उसको नोट निर्गमन का पूर्ण या आंशिक एकाधिकार प्राप्त होता है।
- (2) राज्य के लिए सामान्य बैंकिंग तथा अभिकर्ता सेवार्थें प्रदान करना।
- (3) व्यापारिक बैंकों के नकद कार्यों का संरक्षण।
- (4) राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के कार्यों का संरक्षण तथा प्रबन्ध।
- (5) व्यापारिक बैंकों, बिल दलालों तथा व्यापारियों अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं को बिलों तथा ढुंडियों का बट्टा करके या अग्रिम द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा अग्रिम ऋणदाता के उत्तरदायित्व की सामान्य स्वीकृति।
- (6) बैंकों के पारस्परिक लेन देन समाशोधन द्वारा निपटाना।
- (7) राज्य द्वारा निर्धारित मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन के उद्देश्य से तथा व्यापार की आवश्यकताओं के अनुसार साख का नियंत्रण करना।¹

1. “A central bank is a bank which constitutes the apex of the monetary and banking structure of its country and which performs as best as it can in the national economic interest the following functions

- 1 The regulation of currency in accordance with the requirements of business and the general public, for which purpose it is granted either the sole right of note issue or at least a partial monopoly thereof
- 2 The performance of general banking and agency services for the state
3. The custody of the cash reserves of the commercial banks.
4. The custody and management of the nations reserves of international currency.
5. The granting of accommodation, in the form of rediscounts

केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता (Necessity of Central Bank)

आधुनिक अर्थ-व्यवस्थाओं के संचालन में केन्द्रीय बैंको का इतना महत्वपूर्ण योगदान है कि आज वे सभी देशों के आर्थिक संगठनों का आवश्यक अंग बन गया है। वैसे तो उनकी आवश्यकता के अनेक कारण हैं परन्तु उनमें से कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :—

1. नोटों का निर्गमन (Issue of Notes) : केन्द्रीय बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार देने के सम्बन्ध में अब कोई मतभेद नहीं है। सभी लोग यह स्वीकार करते हैं कि नोट निर्गमन को लोचपूर्ण बनाने तथा उसे राजनीतिक प्रभावों से मुक्त कर विशुद्ध आर्थिक भिद्धान्तों पर आधारित रखने के लिए एक स्वतंत्र केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता होती है।

2. साख का नियमन (Regulation of Credit) : आधुनिक आर्थिक जीवन में मुद्रा की तुलना में साख का अत्याधिक महत्व है। आज व्यापारिक बैंको का एक महत्वपूर्ण तथा प्रमुख कार्य साख का सृजन करना है। बैंको की साख-सृजन प्रक्रिया से देश की अर्थ-व्यवस्था को अनेक लाभ हैं परन्तु व्यापार-वाणिज्य की आवश्यकता से अधिक साख का विस्तार तथा सकुचन देश के लिए भयावह सिद्ध हो सकता है। अतः बैंकों के द्वारा साख-सृजन की मात्रा का देश तथा अर्थ-व्यवस्था के हित में कृपि स्वतन्त्र सस्था द्वारा नियमन होना आवश्यक है और यह सस्था केन्द्रीय बैंक ही हो सकती है।

3. बैंको को आवश्यकता के समय वित्तीय सहायता (Financial accommodation to banks in times of need) : सङ्कट काल तथा वित्तीय कठिनाइयों के समय देश के बैंको को आर्थिक सहायता की आवश्यकता पडती है। यदि ऐसे समय उन्हें बाह्य सहायता न मिले तो वे फेल हो जायें और इससे बैंको में जन विश्वास समाप्त हो जाय। अतः कठिनाइयों के समय बैंको को 'अन्तिम श्रृणदाता' के रूप में केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता पडती है।

or collateral advances, to commercial banks, bill brokers and dealers, or other financial institutions, and the general acceptance of the responsibility of lender of last resort.

6. The settlement of clearance balances between the banks; and
7. The control of credit in accordance with the needs of business and with a view to carrying out the broad monetary policy adopted by the state."

—M. H. De Kock : Central Banking, (Third Ed.) 1954, p 22

4. बैंकिंग विकास (Banking Development) : किसी देश में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार तथा बैंक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए किसी मार्गदर्शक तथा सहायक की आवश्यकता होती है और यह कार्य केन्द्रीय बैंक ही करता है।

5. मौद्रिक नीति का निर्धारण तथा क्रियान्वयन (Formulation and Implementation of Monetary Policy) : देश के आर्थिक विकास में मौद्रिक नीति का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश के विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप मौद्रिक नीति का निर्माण तथा उसका सफल क्रियान्वयन सरकार तथा केन्द्रीय बैंक के द्वारा ही हो सकता है।

6. सरकारी बैंक के रूप में कार्य (Functions as a Government Banker) : सरकार के कार्यों के विस्तार के फलस्वरूप सरकार की वित्तीय प्रणियाँ का जो सख्यावर्धन हुआ है उसके उत्तरदायित्व को सभालने के लिए केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता होती है।

केन्द्रीय बैंकिंग के सामान्य सिद्धांत

(General Principles of Central Banking)

केन्द्रीय बैंकिंग अथवा बैंकिंग की पूर्णतः अलग शाखा स्वीकार की जाने लगी है। केन्द्रीय बैंक के अपने अलग नियम तथा रीतियाँ होनी हैं जिन्हें 'केन्द्रीय बैंकिंग की कला' (The Art of Central Banking) कहा जाता है। डा० डी० काक के अनुसार, "अथ 'केन्द्रीय बैंकिंग का विज्ञान' कहना भी अधिक उपयुक्त होगा।"¹ केन्द्रीय बैंकिंग के मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :

1. केन्द्रीय बैंक सदा जनहित में कार्य करता है (Central Bank always acts in public interest) : केन्द्रीय बैंक कोई लाभ कमाने वाली सस्था नहीं है बल्कि राष्ट्रहित या जनहित के उद्देश्य को समक्ष रखकर कार्य करती है। डा० डी० काक के शब्दों में, "केन्द्रीय बैंक का मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि लाभ को प्राथमिक निर्धारक न स्वीकार करते हुए उसे सदा केवल जनहित में कार्य करना चाहिए चाहे किसी विशिष्ट समय पर वह चाहे जो कार्य या कार्यों का समूह करे।"² केन्द्रीय बैंक

¹. "It is now also legitimate to speak of the science of central banking."
— M.H. De Kock : *Central Banking*, p 22

² "The guiding principle for a central bank, whatever function or group of functions it performs at any particular moment, is that it should act only in the public interest and without regard to profit as a primary consideration"

निर्देशों पर ब्याज नहीं देता और जोखिम वाले उद्योगों में विनियोजन करने की उस मनाही है।

2 देश के विभिन्न हितों के बीच निष्पक्षता (Should be impartial as between different sectional interests in the country) केन्द्रीय बैंक को सदा त्रिगुण्ड आर्थिक सिद्धान्तों के आधार पर ही नियंत्रण लाना चाहिए। देश के विभिन्न वर्गों के आर्थिक हितों के बीच उसे निष्पक्ष होना चाहिए। केन्द्रीय बैंक की नीतियाँ तथा उनका क्रियान्वयन राजनीतिक प्रभावों से मुक्त होना चाहिए। केन्द्रीय बैंक का एक मात्र लक्ष्य जनहित तथा पूरे देश का कल्याण होना चाहिए।

3 देश में मुद्रा की पूर्ति का अन्तिम स्रोत (Ultimate source of money supply in the country) केन्द्रीय बैंक के पास नोट निर्गमन का एकाधिकार होता है। केन्द्रीय बैंक विभिन्न रीतियों के द्वारा बैंक मुद्रा का नियंत्रण करता है। मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण के अधिकार का प्रयोग केन्द्रीय बैंक द्वारा इस प्रकार होना चाहिए कि राज्य की आर्थिक नीतियों के अनुरूप बैंकिंग तथा मौद्रिक व्यवस्था संचालित हो।

केन्द्रीय बैंकिंग तथा व्यापारिक बैंकिंग की तुलना

(Comparison between Central and Commercial Banking)

केन्द्रीय बैंकिंग के सामान्य सिद्धान्तों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय बैंकिंग तथा व्यापारिक बैंकिंग भिन्न भिन्न हैं। केन्द्रीय बैंकिंग तथा व्यापारिक बैंकिंग में कुछ असमानताएँ हैं तो कुछ समानताएँ भी हैं।

समानताएँ (Similarities)

केन्द्रीय तथा व्यापारिक बैंकिंग के सिद्धान्तों तथा कार्य प्रणालियों में निम्न लिखित समानताएँ हैं —

1 दोनों ही प्रकार के बैंक मुद्रा तथा साख के निर्माता हैं (Both types of banks are creators of money and credit) केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक दोनों ही मुद्रा और साख का निर्माण करते हैं। केन्द्रीय बैंक नोट निर्गमन करते समय शन प्रतिशत धानु कोष नहीं रखते और व्यापारिक बैंक नकद जमाओं के आधार पर साख जमाओं का निर्माण करते हैं।

2 दोनों प्रकार के बैंकों को स्थिर पूँजी की आवश्यकता पूर्ति नहीं करनी चाहिए (Both should not finance fixed capital requirements) केन्द्रीय बैंक 'अन्तिम ऋणदाता' के रूप में बैंकों को तथा व्यापारिक बैंक व्यापार तथा उद्योगों की वित्त व्यवस्था के लिए ऋण देते हैं। परन्तु ये ऋण अल्पकालीन होते हैं और कायशील पूँजी की आवश्यकता पूर्ति के लिए दिए जाते हैं। दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति दोनों ही बैंक नहीं करते हैं।

3. अल्पकालीन ऋण तथा आदेशों की तरलता (Short term loans and liquidity of assets) : दोनों ही प्रकार की बैंको द्वारा कोपो की तरलता को बहुत महत्व दिया जाता है। व्यापारिक बैंको की विनियोग नीति वा यह एक प्रमुख सिद्धांत है। व्यापारिक बैंक अपने दायित्वों का कुछ प्रतिशत ही नकद कोप रखते हैं अतः बैंको को ऐसे चेन्नो में अपने कोपो का विनियोग करना चाहिए जिसे आवश्यकता के समय शीघ्र ही नकदी में परिवर्तित किया जा सके। अल्पकाल के लिए प्राप्त जमाओं के आधार पर व्यापारिक बैंक दीर्घकालीन ऋण कैसे दे सकते हैं ? आदेशों की तरलता की दृष्टि से दोनों ही प्रकार की बैंक अचल सम्पत्ति जैसे भूमि तथा भवन की प्रतिभूति पर ऋण नहीं देते।

असमानतायें (Dissimilarities) :—

केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंको के सिद्धान्तों तथा कार्य पद्धति में निम्नलिखित भिन्नतायें उल्लेखनीय हैं :—

1. दोनों बैंको के उद्देश्यों में अन्तर (Difference in objects of establishing them) जैसा कि बताया जा चुका है कि केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंको की स्थापना का ध्येय भिन्न भिन्न होता है। केन्द्रीय बैंक की स्थापना का उद्देश्य देश के बैंकिंग तथा साख-संगठन का देश तथा लोक-हित में नियंत्रण करना होना है। केन्द्रीय बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है जबकि व्यापारिक बैंक लाभ कमाने के उद्देश्य में ही खोली जाती हैं।¹

2 व्यापारिक बैंको की तरह केन्द्रीय बैंक जनता से प्रत्यक्ष व्यवहार नहीं करता, केवल बैंको से व्यवहार करता है (Like commercial banks, the Central Bank does not directly deal with public; it only deals with banks) केन्द्रीय बैंक सामान्य बैंकिंग सेवामें नहीं करता जो व्यापारिक बैंको द्वारा की जाती हैं। इस कारण केन्द्रीय बैंक जनता से प्रत्यक्ष लेन देन नहीं करते, वह बैंकिंग तथा साख व्यवस्था को अपनी सेवामें बैंको के माध्यम से ही प्रदान करता है। केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंको की सहायता करते हैं और व्यापारिक बैंक जनता की सेवा करता है।

3. केन्द्रीय बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार, परन्तु व्यापारिक बैंको को नहीं (Central Bank has the Monopoly of Note Issue but not Commercial Banks) : केन्द्रीय बैंकिंग के विकास की प्रारम्भिक अवस्था में

¹ "The commercial bank thinks primarily of profit making; whereas the Central Bank thinks of the effects of its operations on the working of the economic system."

इस सम्बन्ध में वाद-विवाद या कि नोट कौन निर्गमित करे—केन्द्रीय बैंक या सरकार (Central Bank vs. State Issue), एक बैंक या बहुत से बैंक (Single vs Multiple Note Issue) । सरकार तथा बहु-नोट निर्गमन के दोषों का अनुभव कर अब यह सर्व स्वीकार्य है कि नोट निर्गमन का एकाधिकार केन्द्रीय बैंक को होना चाहिए, निजी बैंकों को यह अधिकार प्राप्त नहीं होना ।

4 केन्द्रीय बैंक 'अन्तिम ऋणदाता' का कार्य करता है व्यापारिक बैंक नहीं (Central Bank acts as the Lender of Last Resort but not Commercial Banks) केन्द्रीय बैंक बैंकों का बैंक (Banker's Bank) होता है और आवश्यकता पड़ने पर व्यापारिक बैंकों को ऋण सुविधा प्रदान करता है और उनके लिए साख के कोष (Reservoir of Credit) के रूप में कार्य करता है । इसीलिए बेजहाट की शब्दावली में उसे 'अन्तिम ऋणदाता' (Lender of Last Resort) कहा जाता है । केन्द्रीय बैंक पर व्यापारिक बैंकों की इस निर्भरता के कारण केन्द्रीय बैंक उन पर सफनतापूर्वक नियंत्रण रख पाता है । व्यापारिक बैंक यह कार्य नहीं करती ।

5 केन्द्रीय बैंक सरकारी बैंकर का कार्य करता है व्यापारिक बैंक का नहीं (Central Bank acts as a Government Banker but not Commercial Banks) —जिस प्रकार सामान्य ग्राहकों को बैंक की सहायता की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार सरकार को भी एक बैंक की सेवा चाहिए । सरकार के लेन-देन, सार्वजनिक-ऋण की व्यवस्था तथा अन्य वित्तीय कार्यों को केन्द्रीय बैंक ही सम्पन्न करता है । केन्द्रीय बैंक का यह विशेषाधिकार उसकी स्थिति को और भी अधिक सुदृढ़ तथा शक्तिशाली बनाता है । अन्य व्यापारिक बैंकों को यह कार्य नहीं सौंपा जाता ।

6. केन्द्रीय बैंक को साख नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है, व्यापारिक बैंकों को नहीं (Central Bank has the right to Control credit but not Commercial Banks):—यद्यपि केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक दोनों ही मुद्रा तथा साख के सृजनकर्त्ता हैं परन्तु बैंकों द्वारा सृजित साख पर देश तथा जनहित में नियंत्रण का अधिकार केन्द्रीय बैंक को ही प्राप्त है । व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग की आवश्यकतानुसार बैंकों द्वारा सृजित साख का केन्द्रीय बैंक विस्तार तथा संकुचन (Expansion and Contraction of Credit) करता है, यह कार्य व्यापारिक बैंकिंग के कार्य क्षेत्र के बाहर है ।

7 केन्द्रीय बैंक पर देश की मौद्रिक नीति के निर्धारण तथा क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व होता है, व्यापारिक बैंकों पर नहीं (Central Banks are charged with the responsibility of formulation and implementation of Monetary Policy but not Commercial Banks) —केन्द्रीय बैंक सर-

कार के सहयोग से देश की मौद्रिक नीति का निर्धारण तथा क्रियान्वयन करता है जिससे देश की अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ आधार पर विकसित होती रहे। मौद्रिक व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालन का यह भार बड़ा गुरुतर है और इसे केन्द्रीय बैंक जैसा वित्त विशेषज्ञ तथा शीर्षस्व बैंक ही उठा सकता है। व्यापारिक बैंको का मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन में सहयोग तो अपेक्षित है परन्तु प्रत्यक्ष रूप से नीति-निर्धारण तथा क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं होता।

अतः केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंको की नीति-नीति में मूलभूत अन्तर है और इसीलिए केन्द्रीय बैंकिंग अथवा बैंकिंग को एक विशिष्ट तथा पृथक् शाखा मानी जाने लगी है।

केन्द्रीय बैंक का संगठन

(Organisation of the Central Bank)

केन्द्रीय बैंक के संगठन की रूपरेखा का निर्धारण करने के लिए तीन पक्षों पर विचार करना आवश्यक है —

(1) केन्द्रीय बैंक का संचालन तथा नियन्त्रण (Direction and Control of the Central Bank)

(2) केन्द्रीय बैंक का स्वामित्व (Ownership of the Central Bank)

(3) केन्द्रीय बैंक का प्रबन्ध (Management of the Central Bank)

(1) केन्द्रीय बैंक का संचालन तथा नियन्त्रण

(Direction and Control of the Central Bank)

केन्द्रीय बैंक के संचालन तथा नियन्त्रण के अन्तर्गत एक ही प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए कि केन्द्रीय बैंक की स्वतन्त्रता पर किस सीमा तक वैधानिक प्रतिबन्ध होने चाहिए और, दूसरे इस बात पर कि सरकार और केन्द्रीय बैंक का पारस्परिक सम्बन्ध क्या होना चाहिए? लगभग सप्ताह के सभी देशों में केन्द्रीय बैंक को नोट निगमन का एकाधिकार है परन्तु नोट निगमन की व्यवस्था कानून द्वारा निश्चित होनी चाहिए जिससे इस सम्बन्ध में केन्द्रीय बैंक के अधिकारी तथा दायित्वों के विषय में कोई अनिश्चितता न रहे। केन्द्रीय बैंक नोट निगमन के अपने अधिकार का दुरुपयोग न कर सके, इस विषय में पर्याप्त व्यवस्थायें होनी चाहिए। केन्द्रीय बैंक का कार्यक्षेत्र भी कानून के द्वारा निर्धारित होना चाहिए। उसके लिए ऐसे कार्य निषिद्ध होने चाहिए जिनसे उसकी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता हो अथवा जिनसे उसकी देश के अन्य बैंको से प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बनती हो। केन्द्रीय बैंक 'बैंको के बैंक' या 'अन्तिम ऋणदाता' के रूप में सफलतापूर्वक तभी कार्य कर सकता है और अन्य बैंको का सहयोग तभी प्राप्त कर सकता है जब केन्द्रीय बैंक अन्य बैंको के प्रतिस्पर्धी कार्य न करे। यहाँ यहाँ भी स्मरणीय है कि

केन्द्रीय बैंक एक लाभ कमाने वाली व्यावसायिक संस्था नहीं है और उसके सभी कार्य तथा निर्णय राष्ट्र तथा जनहित में होने चाहिए ।

सरकार तथा केन्द्रीय बैंक के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में बड़ा मतभेद रहा है । 19वीं शताब्दी में यह विचारधारा प्रचलित थी कि केन्द्रीय बैंकों को कानून के अन्तर्गत कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता (Complete Independence) होनी चाहिए और सरकार का उस पर किसी प्रकार का नियन्त्रण या हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए । प्रथम महायुद्ध काल में सरकार तथा केन्द्रीय बैंक के सहयोग की आवश्यकता अनुभव की गई थी परन्तु युद्ध समाप्ति के बाद फिर वही 'केन्द्रीय बैंक के वाय स्वातन्त्र्य' के पक्ष में विचारधारा रही । प्रथम महायुद्ध के बाद के काल (Post war Period) में विभिन्न देशों की सरकारों ने मुद्रा स्फीति को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जिसका उनकी अर्थ-व्यवस्थाओं पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा और जनमत केन्द्रीय बैंक के कार्यों में सरकार के हस्तक्षेप के विरुद्ध हो गया । सन् 1929 की महान् मन्दी तथा स्वर्णमान के पतन के परिणामस्वरूप आर्थिक तथा मौद्रिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप तीव्र गति से बढ़ने लगा । द्वितीय महायुद्ध-काल में युद्धकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा युद्धोत्तर-काल में आर्थिक पुनर्निर्माण की योजनाओं को कार्यान्वित करने में सरकार के प्रभाव का पर्याप्त विस्तार हुआ । इसी प्रकार यह माना जाना लगा कि केन्द्रीय बैंक पर सरकार का पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिए । इसी कारण सत्तार के अधिकतर केन्द्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और उनका स्वामित्व तथा प्रबन्ध पूर्ण रूप से सरकार के हाथ में आ गया । विवेकपूर्ण दृष्टिकोण यही है कि केन्द्रीय बैंक पर सरकार का सामान्य नियन्त्रण रहे किन्तु उसकी व्यवस्था स्वतन्त्र रूप से होती रहे । आजकल सभी राज्य-नियन्त्रित केन्द्रीय बैंकों के सामने इस कोष की व्यवस्था कर शेष राज्य को ही दे दिया जाता है । सरकार तथा केन्द्रीय बैंक के पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में **मॉन्टेग्यू नॉर्मन (Montague Norman)** का कथन है —

'केन्द्रीय बैंक तथा सरकार की नीति में सदा सामंजस्य होना चाहिए । मैं सदा बैंक को सलाह देने का अनोखा अधिकार रखने वाली संस्था मानता हूँ और उस सलाह पर अधिकतम सीमा तक जोर देना चाहिए । परन्तु यह सत्र सरकार की सर्वोच्च शक्ति की सीमा में ही होना चाहिए ।'¹ केन्द्रीय बैंक तथा सरकार के

¹.the policy of the Bank and the policy of the Government should at all times be in harmony—in as complete harmony as possible I look upon the Bank as having the unique right to offer advice and to press such advice even to the point of nagging, but always, of course subject to the supreme authority of the Government." —Montague Norman, Governor of the Bank of England.

पारस्परिक सम्बन्धों पर इंग्लैंड को रेडक्लिफ समिति (The Radcliffe Committee) क विचार उद्घरण योग्य हैं.—

“The Central Bank is one of the principal authorities concerned with the framing and operation of monetary policy. It follows that this policy whatever form it may take from time to time must include the general planning of monetary policy and monetary operations and that the policies pursued by the Central Bank must be from first to last in harmony with those avowed and defended by Ministers of the Crown responsible to parliament. The problem resolves itself into one of making sure that the exchanges between the two bodies (Government and Bank of England) are organised in such a way that the bank contributes to the Government's discussions on policy, the advice and suggestions which its unique operational experience and contacts qualify it to offer, while the government on its side is careful to associate the Bank with the formation of those decisions on economic policy in which monetary operations are capable of taking a part. The true position, as we see it, is that the Bank carries an equal measure of responsibility, to advise to the best of its ability, and having advised, to execute within limits of the determined policy.”

2 केन्द्रीय बैंक का स्वामित्व (Ownership of the Central Bank)

केन्द्रीय बैंक की पूंजी जनता, सरकार या देश के बैंकों द्वारा जुटायी जा सकती है। डा० डी० कोक (Dr. De Kock) ने पूंजी लगाने वाला के अनुसार केन्द्रीय बैंक के स्वामित्व को सात श्रेणियों में बाटा है :—

(1) ऐसे बैंक जिनकी कुल पूंजी सामान्य जनता द्वारा जुटायी जाय जैसे नोदरलैंड बैंक, रीश बैंक आदि,

(2) ऐसे बैंक जिनकी कुल पूंजी सरकार द्वारा जुटायी जाय जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड, रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया, बैंक ऑफ रश्या, बैंक ऑफ फ्रान्स, बैंक ऑफ मनाडा, बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया आदि,

(3) ऐसे बैंक जिनकी कुल पूंजी देश के बैंकों द्वारा ली जाय जैसे अमेरिका की फेडरल रिजर्व व्यवस्था,

(4) ऐसे बैंक जिनकी पूंजी सामान्य जनता तथा सरकार दोनों द्वारा जुटायी जाय जैसे सेन्ट्रल बैंक ऑफ वेनेजुला, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ मेक्सिको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आदि,

(5) ऐसे बैंक जिनकी पूंजी सामान्य जनता तथा बैंकों दोनों द्वारा जुटायी जाय जैसे सेन्ट्रल रिजर्व बैंक ऑफ सेल्वाडोर,

(6) ऐसे बैंक जिनकी पूंजी सरकार तथा बैंको ने जुटायी हो; तथा

(7) ऐसे बैंक जिनकी पूंजी जनता, सरकार तथा बैंको ने जुटायी हो जैसे

सेन्ट्रल बैंक आफ़ चिली ।

उपर्युक्त श्रेणियों में से सप्तर के मुख्य देशों के केन्द्रीय बैंक प्रथम तीन श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं । तीसरी श्रेणी में केवल अमेरिका की फेडरल रिजर्व व्यवस्था ही आती है ।

केन्द्रीय बैंको के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न

(The Question of Nationalisation of Central Banks)

प्रारम्भ में तो अधिकतर केन्द्रीय निजी अशधारियों के बैंक के रूप में स्थापित किए गये थे परन्तु पिछले 30-35 वर्षों में अनेक देशों में केन्द्रीय बैंको का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है और पूर्णरूपेण सरकारी स्वामित्व में आ गये हैं । अधिकतर नये स्थापित केन्द्रीय बैंक राष्ट्रीयकृत सन्ध्या के रूप में ही हैं । केन्द्रीय बैंक के स्वामित्व के प्रश्न पर विचारधारा आर्थिक क्षेत्र में सरकार के स्थान (Role of Government in Economic field) के प्रश्न के साथ जुड़ी हुई है । केन्द्रीय बैंक के सरकारी स्वामित्व के पक्ष-विपक्ष में तर्कों की भीमसा नीचे की जा रही है ।

राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क (Arguments in Favour of Nationalisation) केन्द्रीय बैंको के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं—

(1) देश तथा जनहित सरकारी स्वामित्व में अधिक सुरक्षित (National or Public Interest more safe in State Ownership) : केन्द्रीय बैंक देश तथा जनहित में कार्य करता है और वह लाभ कमाने वाली व्यावसायिक संस्था नहीं है जैसे कि व्यापारिक बैंक होते हैं । निजी अशधारियों की तुलना में राष्ट्रहित सरकार के हाथों में अधिक सुरक्षित होता है । निजी अशधारी अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए देश तथा जनहित का बलिदान कर सकते हैं ।¹

(2) लाभ का राष्ट्रहित में उपयोग (Use of profits for national purposes) केन्द्रीय बैंक के नोट निर्गमन के एकाधिकार, सरकारी तथा बैंको के बैंक के कार्य करने से जो लाभ प्राप्त होता है उस पर राष्ट्र की प्रतिनिधि सरकार का अधिकार होना चाहिए जिमसे उसका राष्ट्र हित में उपयोग हा सके । उस लाभ पर निजी अशधारियों का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये ।

1. 'People being narrow minded and selfish, a private Central Bank may adopt a monetary policy not in the interests of the whole country but to enrich themselves'

(3) आर्थिक विकास के लिए सरकार की अर्थनीति तथा मौद्रिक नीति में सामन्जस्य आवश्यक (Necessity of adjustment between economic and monetary policy of the Government for economic development) : व्यापार चक्रों तथा आर्थिक विकास की समस्याओं का समाधान के लिए सरकार की अर्थ नीति तथा मौद्रिक नीति में पूर्ण सामन्जस्य की अति आवश्यकता है। समस्या का उचित समाधान केन्द्रीय बैंक तथा सरकार के मिलकर योजनात्मक ढंग से कार्य करने से ही निकल सकता है। केन्द्रीय बैंक तथा सरकार के कार्यों में प्रभावी सहयोग तथा सामन्जस्य तभी स्थापित हो सकता है जब केन्द्रीय बैंक एक राष्ट्रीयकृत संस्था हो।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक तथा अन्य आर्थिक संस्थाओं से सम्पर्क तथा विचार विमर्श अधिक सुविधाजनक (Contact and exchange of views with International Monetary and other Economic Institutions facilitated) द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक तथा आर्थिक सहयोग के उद्देश्य से स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सत्कार के विभिन्न केन्द्रीय बैंकों का विचार विमर्श होता रहता है। उनके इस पारस्परिक सम्पर्क तथा आदान प्रदान में निजी अर्थधारियों के बैंक के स्थान पर राज्य नियंत्रित केन्द्रीय बैंक अधिक सुविधा प्रदान करेगा क्योंकि उसकी अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीति तथा देश की विदेश नीति में अधिक सामन्जस्य होगा।

(5) समाजवादी विचारधारा के पक्ष में जनमत (Public Opinion in favour of Socialist Ideology) सत्कार में समाजवादी विचारधारा की ओर जनमत का अधिक झुकाव है और इन विचारों पर आधारित अर्थ व्यवस्था में राज्य स्वामित्व तथा नियन्त्रण का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कारण केन्द्रीय बैंक जैसी शीर्ष संस्था के राष्ट्रीयकरण का सुभाव दिया जाता है।

(6) केन्द्रीय बैंक के कार्यों का स्वभाव (Nature of functions of the Central Bank) 'केन्द्रीय बैंकिंग का विज्ञान तथा कला' (Science and Art of Central Banking) इतना विशिष्ट तथा जटिल कार्य है कि उसे निजी अर्थधारियों द्वारा संचालित बैंक के हाथों में नहीं सौंपा जा सकता। केन्द्रीय बैंकिंग कार्यों का इतना विशिष्ट स्वभाव स्वयं राष्ट्रीयकरण का पक्ष सबल करता है।

राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तर्क (Arguments against Nationalisation) केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं—

(1) बैंक की नीति राजनीति से प्रभावित (Not free from Partisan Political Intervention) : जब केन्द्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व तथा

नियन्त्रण रहता है तो इस बात का भय रहता है कि बैंक की नीतियां राजनीति से प्रभावित हो जाय। इसका प्रभाव अर्थ-व्यवस्था पर बड़ा बुरा होगा।¹

(2) कार्यों तथा निर्णयों में देरी तथा लालफीताशाही (Delay and Red-tapism in functioning and decisions) केन्द्रीय बैंक पूर्ण सरकारी नियन्त्रण में आने पर सरकारी कामकाज की तरह वहा भी कार्यों तथा निर्णयों में देरी तथा लालफीताशाही का बोलबाला हो जाता है। केन्द्रीय बैंक को अर्थव्यवस्था की गति-विधियों का अध्ययन कर शीघ्र निर्णय लेने तथा उनको क्रियान्वित करना होता है। यदि इस दिशा में कोई भी ढीलढाल हो तो उसके परिणाम बड़े भयावह हो सकते हैं। अतः कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने तथा शीघ्र निर्णय आदि के लिए निजी स्वामित्व ही उचित है।

(3) सरकार आर्थिक तथा मौद्रिक गतिविधियों के निकट सम्पर्क में नहीं (Government not in intimate touch with economic and monetary developments) : देश की आर्थिक तथा मौद्रिक गतिविधियों से जितना निकट सम्पर्क व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा वित्त विशेषज्ञों का रहता है उतना सरकार का नहीं। अतः सरकार द्वारा नियन्त्रित बैंक उतनी कार्यकुशलता से कार्य नहीं कर सकता जितना निजी अर्थधारियों का बैंक।

(4) मुद्रा स्फीति का भय (Danger of Inflation) : सरकार द्वारा नियन्त्रित केन्द्रीय बैंक सरकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हीनार्थ प्रबन्धन (Deficit Financing) तथा मुद्रा स्फीति (Inflation) बिना किसी कठिनाई के कर लेगी जिसकी सीमा अतिक्रमण होने पर अर्थव्यवस्था को हानि होगी। परिणामस्वरूप जनता को स्फीति जन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

राष्ट्रीयकरण के विरोध में प्रस्तुत किए जाने वाले तर्कों के बावजूद आज सामान्य प्रवृत्ति राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है। आवश्यकता पडने पर मुद्रा स्फीति की नीति जब सरकार अपनाती है तो अर्थधारियों का बैंक भी इस दिशा में कुछ नहीं कर सकेगा। इस सम्बन्ध में डा० डी० फाक का विचार है—

¹ " Governments change very often, with them the policies; and if the Central Bank comes under the control of such ever-changing governments, there can be no economic stability in the country, and in the place of such an instability, chaos will reign supreme—the august financial custodian will be ridden by political party chieftains, and the road will be open for political intrigue, there can be no safeguard for the bank to carry on its economic policy in national interests."

“...it is increasingly felt in the realms of both official and public opinion that a semi-independent central bank, free from direct partisan political intervention, can atleast be relied upon to offer resistance against undue abuse of monetary management and to serve as a bulwark or safeguard against a catastrophic decline in the value of money”.

जब केन्द्रीय बैंक निजी स्वामित्व में रहता है तो भी उस पर सरकार का कुछ न कुछ नियंत्रण तो रहता ही है और फिर केन्द्रीय बैंक तथा सरकार में मतभेद होने पर केन्द्रीय बैंक को सरकार की इच्छानुसार चलना ही पड़ता है।

3. केन्द्रीय बैंक का प्रबंध (Management of the Central Bank)

केन्द्रीय बैंक का प्रबंध एक प्रबंध समिति या संचालक मंडल द्वारा किया जाता है जिसका अध्यक्ष गवर्नर या प्रेसिडेंट कहलाता है। केन्द्रीय बैंक के नीति निर्धारण तथा प्रबंध की यह सर्वोच्च सस्या होती है। विभिन्न देशों में प्रबंध समिति के सदस्यों की संख्या में बड़ा अन्तर है। सरकारी स्वामित्व के केन्द्रीय बैंक की प्रबंध समिति के सभी सदस्य सरकार द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं परन्तु निजी अशुधारियों के केन्द्रीय बैंक की प्रबंध समिति में भी अशुधारियों के प्रतिनिधियों के साथ साथ कुछ सदस्य सरकार द्वारा भी नियुक्त किए जाते हैं। गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर तो सरकार द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं।

प्रबंध समिति के सदस्यों की नियुक्ति सदा योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए। विशेष हितों के प्रतिनिधियों को समिति में नियुक्त करने के बजाय यदि वित्तीय तथा मौद्रिक विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाय तो यह अधिक उपयुक्त होगा।

इस प्रकार प्रबंध समिति के निर्माण तथा कार्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निष्कर्ष दिए जा सकते हैं—

(1) प्रबंध समिति या संचालक मंडल में विशेष हितों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति के स्थान पर विशेषज्ञों (Experts) की नियुक्ति होनी चाहिए।

(2) सरकार द्वारा निर्धारित नीति की सीमा (Within the broad policy frame work as formulated by the Government) के भीतर दिन-प्रतिदिन के कार्यों में समिति को पूरी स्वतंत्रता हो और उसमें सरकार हस्तक्षेप न करे।

(3) सरकार का कार्य केवल नीति निर्धारण तक ही सीमित रह और सरकारी नीतियों पर ससद का नियंत्रण हो।

उपर्युक्त विवेचन में निर्धारित मान्यताओं के आधार पर यदि केन्द्रीय बैंक का संचालन तथा संगठन किया जाय तो केन्द्रीय बैंक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक सफल हो सकेगा और देश की मुद्रा तथा साख व्यवस्था की अधिक सेवा कर सकेगी ।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके सकेत

(1) एक केन्द्रीय बैंक की क्या आवश्यकता है ? केन्द्रीय बैंकिंग के सिद्धान्तों का विवेचन कीजिए ।

(आगरा बी० काम, 1966)

[सकेत—प्रथम भाग में आधुनिक अर्थ-व्यवस्थाओं के संचालन के लिए केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता के विभिन्न कारण बताइये । दूसरे भाग में केन्द्रीय बैंक के सिद्धान्तों, जैसे जन-हित में कार्य, मुद्रा की पूर्ति का अंतिम स्रोत आदि की विवेचना कीजिए ।]

(2) क्या आप केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं ? अपने मत के कारण बताइये ।

(विक्रम, 1962)

[सकेत—केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण के पक्ष तथा विपक्ष में दिए जाने वाले तर्कों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए । फिर यह बताइये कि ससार में केन्द्रीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है ।]

(3) केन्द्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर स्पष्ट कीजिए ।

(सागर बी० ए०, 1957)

[सकेत—केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक की संज्ञेय में समानताएँ बताते हुए उनकी असमानताओं का विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए ।]

केन्द्रीय बैंक के कार्य

(Functions of the Central Bank)

"The cardinal virtue of the central banker is not conservatism in techniques, but rather a disposition to discover novelties and to be versatile in techniques"

पिछले अध्याय में केन्द्रीय बैंक की परिभाषाओं का अध्ययन करते समय हमने यह देखा था कि केन्द्रीय बैंक के कार्यों के सम्बन्ध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं। कोई किसी कार्य पर बल देता है और कोई किसी दूसरे कार्य पर। डा० डी० स्काक के अनुसार केन्द्रीय बैंक के निम्नलिखित सात कार्य हैं —

- (1) नोट निर्गमन का एकाधिकार (Monopoly of note Issue)
- (2) सरकारी बैंकर, अभिकर्ता तथा परामर्शदाता (Government Banker, Agent and Adviser)
- (3) व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का संरक्षक (The Custodian of the Cash Reserves of the Commercial Banks)
- (4) राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषों का संरक्षक (The Custodian of the Nation's Reserves of International Currency)
- (5) पुनः बट्टा का बैंक तथा अंतिम ऋणदाता (The Bank of Rediscount and the Lender of Last Resort)
- (6) केन्द्रीय समाशोधन, भुगतान तथा हस्तान्तरण का बैंक (Bank of Central Clearance, Settlement and Transfer)
- (7) साख का नियंत्रणकर्ता (Controller of Credit)

1. नोट निर्गमन का एकाधिकार (Monopoly of Note Issue)

संसार के सभी देशों में केन्द्रीय बैंक को नोट निर्गमन का पूर्ण या आंशिक एकाधिकार प्राप्त है। केन्द्रीय बैंक का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है यह विशया-

धिकार केवल केन्द्रीय बैंक को ही प्राप्त होता है। डा० डी० काक के अनुसार “नोट निर्गमन का कार्य लगभग सभी स्थानों पर केन्द्रीय बैंको के प्रारम्भ तथा विकास के साथ सम्बन्धित रहा है। वास्तव में 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ होने तक उनको निर्गम बैंको (Banks of Issue) के नाम से जाना जाता था।”¹ प्रारम्भ में कुछ देशों में नोट सरकारों द्वारा निर्गमित किए जाते थे। परन्तु मुद्रा के मूल्य में गिरावट के कारण लोगों का विश्वास सरकारों में न रहा। बाद में यह अधिकार या तो वर्तमान बैंको या विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए स्थापित बैंक को सौंप दिया गया। कालान्तर में बैंको की सस्या में वृद्धि तथा व्यापार के विस्तार के कारण नोटों के अधिक प्रचलन के कारण नोटों की एकरूपता तथा नोट निर्गम के उपयुक्त नियमन की आवश्यकता अनुभव की गई और इस उद्देश्य से विभिन्न देशों में नोट निर्गमन के पूर्ण या आंशिक एकाधिकार किसी एक बैंक को देने के लिए कानून पारित किए गये। हालैंड ने सन् 1814, इंग्लैंड ने सन् 1844, फ्रांस ने 1848, जर्मनी ने 1875, स्वीडन ने 1897, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1914, आस्ट्रेलिया ने 1924, कनाडा ने 1935 में कानून पास किए। इंग्लैंड में सन् 1844 के अधिनियम के अंतर्गत बैंक ऑफ इंग्लैंड के अतिरिक्त अन्य बैंको को भी नोट नियमन का अधिकार दिया गया था परन्तु कुछ परिस्थितियों में उसकी समाप्ति की व्यवस्था थी। सन् 1920 में अन्य बैंको का यह अधिकार समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार जर्मनी में भी सन् 1875 में जब रीश बैंक स्थापित किया गया तो 33 बैंक नोट निर्गमित करती थी। परन्तु सन् 1935 तक उनका यह अधिकार समाप्त हो गया और रीश बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त हो गया।

लगभग सभी देशों में केन्द्रीय बैंको को अब नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। नोट निर्गमन का यह विशेषाधिकार केन्द्रीय बैंको के विकास में प्रमुख तत्व रहा है। सैद्धान्तिक रूप से यद्यपि हाट्टे (R. G. Hawtrey) नोट निर्गमन के कार्य को केन्द्रीय बैंकिंग का आवश्यक कार्य नहीं मानते परन्तु व्यवहार में सत्तार मर में यह केन्द्रीय बैंकिंग संगठन का इतना महत्वपूर्ण अंग माना जाता है कि सभी देशों में केन्द्रीय बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार दिया गया है। नोट निर्गमन यदि सरकार द्वारा किया जाता है तो यह भय है कि मुद्रा मीट्रिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों तथा सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं

¹. “The privilege of note issue was almost everywhere associated with the origin and development of Central Banks. In fact, until the beginning of the twentieth century they were generally known as banks of issue”.

के कारण इन अधिकार का दुरुपयोग हो और चलनाधिक्य (Over Issue) तथा मुद्रा मूल्य ह्रास हो जाय। आयरिश फ्रीस्टेट के बैंकिंग आयोग (Irish Free State Banking Commission) का विचार इन सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य है—

“Mindful as it is of the distress of past years in all countries where currency was issued by Government, and recognising the hazards which come from changes of Government from the development of budget deficits and other evils from which no country has found itself immune, the commission is definitely of the opinion that the management of the legal tender note issue should be placed in the hands of a non-political and independent body, which shall control the conditions of issue and shall have full control and custody of the securities it holds”

अतः नोट निर्गमन का अधिकार सरकार के हाथ में रहने पर चलनाधिक्य का भय बना ही रहता है। यदि सरकार ‘अन्य मन्तव्यों’ (Ulterior Motives) से स्वतंत्र नौ हा ना नौ वह पत्र मुद्रा की माग के अनुसार उनकी पूर्ति का समायोजन करने में अनमर्त्य रहेगी। अतः वह सर्वमान्य है कि नोट-निर्गमन का एकाधिकार सरकार के हाथों में न दकर केन्द्रीय बैंक को ही देना चाहिए। अन्य बैंकों द्वारा नौ नोट निर्गमन स्वतंत्र से नाली नहीं है क्योंकि लान बसाने वाली मस्याएँ होने के कारण वे नाट-निर्गमन के अधिकार का दुरुपयोग कर सकते हैं। यद्यपि उनकी क्रियाएँ कानून द्वारा नियंत्रित की जा सकती हैं फिर भी उनके द्वारा नोट निर्गमन में चलनाधिक्य का भय तथा नोटों में एकरूपता का अभाव (Danger of Over Issue and Lack of Uniformity) तो रहेगा। अतः केन्द्रीय बैंक ही वह मस्या है जो नोट निर्गमन के लिए उपयुक्त है। भारतीय चलन तथा वित्त आयोग के समक्ष अपनी गवाही में बैंक आफ इंग्लैंड के गवर्नर ने ठीक ही कहा था—

“A central bank should have the sole right of note-issue, it should be the channel and the only channel, for the output and intake of legal tender currency”¹

डा० डी० काक ने सभी देशों में केन्द्रीय बैंकों द्वारा नोट निर्गमन के निम्नलिखित चार कारण बताये हैं—

(अ) नोटों में एक रूपता तथा प्रभावी सरकारी नियंत्रण (Uniformity in Note Issue and Effective State Supervision).—सभी देशों में नोटों की एकरूपता तथा प्रभावी सरकारी नियंत्रण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए

¹. Report of the Royal Commission on Indian Currency and Finance (1926)—Evidences.

नोट निर्गमन का एकाधिकार केन्द्रीय बैंक को सौंपा गया। वैसे तो इन उद्देश्यों को सरकार द्वारा नोट निर्गमन करके भी प्राप्त किया जा सकता था परन्तु सरकार द्वारा मुद्रा-मूल्य-ह्रास तथा उससे उत्पन्न जनता के अविश्वास के कारण सरकार ने नोट निर्गमन केन्द्रीय बैंक को सौंपा। सरकार ने केवल नोट-निर्गमन पर केन्द्रीय सरकार के माध्यम से अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखना ही उपयुक्त समझा।

(ब) केन्द्रीय बैंक द्वारा अत्यधिक साख-विस्तार पर नियंत्रण (Gives Central bank some measure of control over Undue Credit Expansion) केन्द्रीय बैंक द्वारा नोट निर्गमन व्यापारिक बैंकों द्वारा अत्यधिक साख-विस्तार पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है। साख का अत्यधिक विस्तार नोटों की माग में वृद्धि करता है और नोटों की पूर्ति केन्द्रीय बैंक के हाथ में रहने के कारण वह साख नियंत्रण अच्छी प्रकार कर सकता है।

(स) नोटों को विशिष्ट आदर (Gives Notes a Distinctive Prestige): केन्द्रीय बैंक में नोट निर्गमन का अधिकार केन्द्रित होने के कारण और उसको सरकार द्वारा समर्थन दिए जाने के कारण नोटों को विशिष्ट आदर प्राप्त हो जाता है। जिससे नोटों में जनता का विश्वास सुदृढ़ हो जाता है।¹

(द) नोट निर्गमन से प्राप्त लाभ का बटवारा सुविधाजनक (Participation in profits more advantageous):—नोट-निर्गमन कार्य करना सरकारें उपयुक्त नहीं समझती और केन्द्रीय बैंक को नोट निर्गमन से जो लाभ होता है उसका कुछ भाग प्राप्त कर लेती हैं।

(2) सरकार का बैंक, अभिकर्ता तथा सलाहकार (Banker, Agent and Adviser to Government)

जिस प्रकार व्यापारियों तथा सामान्य जनता को बैंक की सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार सरकार को भी एक बैंकर चाहिए। केन्द्रीय बैंक सरकार के बैंक, अभिकर्ता तथा सलाहकार का कार्य करता है। सरकार के बैंक के रूप में केन्द्रीय बैंक सरकारी विभागों, बोर्डों तथा संस्थानों के बैंकिंग खाते रखता है, सरकार को जनता से कर्ज की वसूली तथा ऋणों का धन मिलने तक अल्पकालीन

¹. "Concentration of the note issue in one bank which, moreover, enjoys the support of the State, gives such notes a distinctive prestige not attaching to notes issued by several banks a prestige which has proved to be of great value in a crisis or other emergency"

अग्रिम देता है तथा मन्दी, युद्ध या अन्य सकटकाल में सरकार को असाधारण ऋण देता है; और विदेशी मुद्रा के उभय-विक्रय से सम्बन्धित सरकारी सौदे करता है।

सरकार के विभागों तथा सस्थाओं के खाते रखकर केन्द्रीय बैंक के सभी कार्य करता है जो व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए करता है। यह उनके चेक, ड्राफ्ट तथा नकदी जमा करता है, उनके चेकों तथा ड्राफ्टों का एकत्रीकरण करता है, वेतन आदि के भुगतान के लिए नकद की पूर्ति करता है तथा सरकारी कोषों का एक खाते से दूसरे खाते तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तान्तरण करता है। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक सरकार की समस्त प्राप्तियाँ जैसे कर, निक्षेप इत्यादि सरकार के खाते में जमा करता है और सरकार की ओर से समस्त भुगतान करता है। सरकार की वित्तीय प्रक्रियाओं में वृद्धि हो जाने के कारण यह सब कार्य बड़ा कठिन है। कुछ देशों में इन कार्यों के बदले सरकार केन्द्रीय बैंक को कुछ भुगतान करती है तथा कुछ अन्य देशों में कानून के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक को यह सेवाएँ नोट-निर्गमन के विशेषाधिकार के बदले निशुल्क करनी होती हैं।

डा० डी० काक के शब्दों में "केन्द्रीय बैंक सरकार के बैंक के रूप में केवल इसलिए कार्य नहीं करता है क्योंकि सरकार के लिए यह अधिक सुविधाजनक तथा मितव्ययी है वरन् इसलिए भी करता है क्योंकि वित्तीय तथा मौद्रिक मामलों में घनिष्ठ सम्बन्ध है।"¹ सभी देशों में सरकारें सबसे अधिक आय प्राप्तकर्ता (Largest Receiver of Revenue) तथा सबसे बड़े ऋणी (Biggest Borrower) हैं और उनके द्वारा किए गये व्यय का देश के आर्थिक जीवन पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बैंको पर देश के आर्थिक हित में साख का नियंत्रण तथा समायोजन करने का उत्तरदायित्व होता है तथा सरकार द्वारा निर्धारित मौद्रिक नीति को क्रियान्वित करना होता है। डा० डी० काक का कथन है कि—

"As the manifold financial activities of the State can in certain circumstances exercise a disturbing influence on money market conditions and exchange rates and counteract the credit policy of the central bank, the centralisation of Government banking operations in the central bank atleast gives the latter a better opportunity of judging the general financial situation at any time,

¹. "The central bank operates as the Government's banker, not only because it is more convenient and economical to the Government but also because of the intimate connection between public finance and monetary affairs"

giving the appropriate advice to the Government and taking the necessary remedial measures"¹

सरकार के खाते रखने के अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक सरकार के अभिकर्ता के रूप में राष्ट्रीय ऋणों का प्रबंध तथा ब्याज आदि के भुगतान की व्यवस्था करता है। इस कार्य के लिए केन्द्रीय बैंक कुछ शुल्क लेता है। अभिकर्ता के रूप में केन्द्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों तथा विपनों का लेन देन, विनिमय-नियंत्रण का प्रबंध, विदेशी लेन-देन तथा भुगतान सतुलन का प्रबंध करता है। केन्द्रीय बैंक वित्तीय मामलों का विशेषज्ञ होने के कारण वित्तीय तथा मौद्रिक विषयों में सरकार को परामर्श भी देते हैं और वित्तीय और आर्थिक समस्याओं पर विचार-विनिमय तथा सरकारी नीतियों की जांच तथा तत्सम्बन्धी सुझाव भी देते हैं।

इस प्रकार केन्द्रीय बैंक तथा सरकार का हित पारस्परिक है तथा उनके कर्तव्य तथा दायित्व भी एक दूसरे के पूरक हैं। राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में सरकार को केन्द्रीय बैंक का समर्थन, आदर, सद्भावना तथा परामर्श (Support, respect sympathy and advice of the central bank) तथा देश की बैंकिंग तथा मौद्रिक व्यवस्था के केन्द्र के रूप में केन्द्रीय बैंक को भी इन सब चीजों की सरकार से आशा रखनी चाहिए। दोनों ही सस्थाओं की स्थापना सार्वजनिक हितों की पूर्ति के उद्देश्य से की जाती है और एक दूसरे के अधिकारों तथा दायित्वों के प्रति पारस्परिक सद्भाव तथा उनमें पूर्ण सहयोग से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

(३) व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का सरक्षक

(Custodian of the Cash Reserves of the Commercial Banks)

देश के व्यापारिक बैंक अपने निक्षेपों का कुछ प्रतिशत केन्द्रीय बैंक में पास जमा कर देते हैं। केन्द्रीय बैंक का व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों के सरक्षक के रूप में कार्य का विकास नोट निर्गमन तथा सरकारी बैंक के कार्यों के साथ ही हुआ। 18 वीं शताब्दी में इंग्लैंड के निजी बैंकों ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास अपने अधिक कोष रखने आरम्भ किए थे जो बाद में एक परम्परा बन गई। अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक की स्थापना होने पर व्यापारिक बैंकों द्वारा नकद कोष रखने की अनिवार्यता को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण तथा मध्य अमेरिका, न्यूजीलैंड तथा भारत में स्थापित केन्द्रीय बैंकों के अधिनियमों में नकद कोष रखने की अनिवार्य व्यवस्था की गई। यह सब मुख्यतः सामान्य रूप

¹. M.H. De Kock, *Central Banking*, p. 43-44

स केन्द्रीय बैंक की वित्तीय स्थिति तथा सामूहिक हित में साख-नियंत्रण की शक्ति को सुदृढ करने के लिए किया गया।¹

केन्द्रित नकद कोषों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डा० डी० फाकन कहा है—

“The centralisation of cash reserves in the central bank is a source of great strength to the banking system of any country. Centralised cash reserves can at least serve as the basis of a larger and more elastic credit structure than if the same amount were scattered among the individual banks. It is obvious that, when bank reserves are pooled in one institution which is, moreover, charged with the responsibility of safeguarding the national economic interest, such reserves can be employed to the fullest extent possible and in the most effective manner during periods of seasonal strain and in financial crises or general emergencies.”²

कन्द्रीय बैंक में नकद कोषों के केन्द्रीयकरण से बैंकिंग व्यवस्था को बड़ी शक्ति मिलती है। इस प्रणाली के कई लाभ हैं—

(अ) बैंकिंग तथा साख-व्यवस्था में लोच तथा तरलता (Elasticity and Liquidity in the Banking and Credit System)—जब व्यापारिक बैंकों द्वारा अपने दायित्वा का कुछ प्रतिशत कन्द्रीय बैंक के पास जमा कराया जाता है तो बैंकों की साख सृजन शक्ति अधिक लोचपूर्ण हो जाती है। बैंक अधिक से अधिक मात्रा में साख का सृजन कर सकते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास रहता है कि आवश्यकता पड़ने पर कन्द्रीय बैंक से ऋण प्राप्त कर अपनी मांगों की पूर्ति सरलतापूर्वक कर सकेंगे। इस प्रकार बैंकिंग व्यवस्था में लोच तथा साख सृजन में तरलता का गुण आ जाता है। यह लोच तथा तरलता केन्द्रीय बैंक के पुनः बट्टा के काय (Function of Rediscount) के द्वारा प्राप्त होती है।

(ब) नकद कोषों का अधिकतम उपयोग (Maximum Utilisation of Cash Reserves)—जब व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का अथ व्यवस्था तथा लोकरहित की रक्षा के उद्देश्य में स्थापित केन्द्रीय बैंक जैसी शीघ्रस्थ संस्था में केन्द्रीयकरण होता है तो केन्द्रित नकद कोषों का मौसमी कठिनाइयों तथा सकट कालों में अधिकतम तथा प्रभावी प्रयोग हो सकता है। इस प्रकार व्यापारिक बैंक सकट तथा आकस्मिक कठिनाइयों का दृढतापूर्वक सामना कर सकते हैं।

¹ It was chiefly done 'to strengthen the financial position of the central bank in general and its capacity to control credit in the common interest'

² M H De Kock *Central Banking* (Third Edition) 1954, p 63

(स) नकद कोषों में मितव्ययिता (Economy in Cash Reserves) —

सभी व्यापारिक बैंकों के खाते केन्द्रीय बैंक में होने के कारण उनके आपसी लेन-देन समाशोधन प्रक्रिया के माध्यम से बिना नकदी के प्रयोग के ही सुविधापूर्वक निपट जाते हैं और बैंक कम नकद कोष रखकर भी काम चला लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय बैंक द्वारा वित्तीय सहायता के विश्वास के कारण बैंक कम नकद-कोष रख कर अपने दायित्वों की पूर्ति कर लेती हैं और नकद-कोषों में बचत हो जाती है।

इस प्रकार नकद कोषों का केन्द्रीयकरण बैंकिंग तथा साल-व्यवस्था के लिए बड़ा लाभदायक है। अमेरिका में सदस्य बैंकों द्वारा फेडरल रिजर्व बैंक में नकद कोषों के केन्द्रीयकरण के सम्बन्ध में बर्गस (Burgess) ने ठीक ही कहा है कि “सदस्य बैंकों के पास से फेडरल रिजर्व बैंक के पास कोषों का हस्तान्तरण केवल उसकी (नकद कोषों) स्थिति में परिवर्तन नहीं है बल्कि यह सुरक्षित कोषों की प्रकृति तथा प्रभावोत्पादकता में परिवर्तन है जिससे वे अपने मौलिक कार्य अधिक सुचारु रूप से करते हैं।”¹

(4) राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषों का संरक्षण

(Custodian of the Nation's Reserves of International Currency)

केन्द्रीय बैंक का एक प्रमुख कार्य देश के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषों का संरक्षण करना है। केन्द्रीय बैंक का यह कार्य नोट-निर्गमन के एकाधिकार तथा व्यापारिक बैंकों के कोषों के संरक्षण के कार्यों से जुड़ा हुआ है। (The function is the necessary corollary of the previous functions) आजकल केन्द्रीय बैंक दो प्रकार के कोष रखता है—आंतरिक (Internal) तथा बाह्य (External)। आंतरिक कोष वह कोष होता है जो देश की मौद्रिक व्यवस्था के आधार का कार्य करता है। किसी देश के मौद्रिक मान की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कोषों का रखना आवश्यक है। आंतरिक कोषों के रखने की प्रथा का आरम्भ पत्र मुद्रा के प्रचलन से हुआ क्योंकि पत्र मुद्रा निर्गमित करने पर पर्याप्त मान में स्वर्ण कोष रखने पड़ते थे जिससे उनकी परिवर्तनशीलता बनाये रखी जा सके। 1931 में स्वर्णमान के पतन के बाद आंतरिक कोष में स्वर्ण का प्रतिशत बहुत कम हो गया और द्वितीय

¹. “The shift of reserves from the vaults of the member banks to the vaults of the Federal Reserve Banks was not simply a change in its physical location, but that it made change in the character and effectiveness of the reserves and enabled them to serve more adequately their original purposes”

—Burgess : *Reserve Banks and the Money Market*, Revised Edition (Harper), pp. 26-27. Quoted by De Kock.

महायुद्ध के बाद तो यह और भी घटा दिया गया। अतः आजकल आंतरिक कोष का महत्व बहुत कम हो गया है।

वाह्य कोष मुद्रा के वाह्य मूल्य में स्थिरता बनाये रखने तथा किसी देश के साथ विपरीत भुगतान संतुलन निपटाने के लिए होता है। अतः देश के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण केन्द्रीय बैंक करता है और विनिमय-दरों में स्थिरता बनाये रखना तथा विनिमय-नियंत्रण के प्रबंध इत्यादि के कार्य करता है।

(5) पुनः बट्टा-कार्य या अंतिम ऋणदाता

(Re-discounting Function and Lender of last Resort)

केन्द्रीय बैंक देश के बैंकों के 'अंतिम ऋणदाता' के रूप में कार्य करता है। अंतिम ऋणदाता के रूप में केन्द्रीय बैंक अपनी बट्टा-नीति की शर्तों के अनुसार देश के व्यापारिक बैंकों, बट्टा-गृहों तथा अन्य साख-संस्थाओं की वित्तीय सहायता की जायज मांगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ति करता है। यह कार्य 18 वीं शताब्दी के अन्त में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने आरम्भ किया परन्तु सन् 1866 के सकटकाल में उसने इस कार्य को अपने उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार किया। आजकल तो यह कार्य केन्द्रीय बैंक का इतना महत्वपूर्ण कार्य हो गया है कि केन्द्रीय बैंकिंग की एक आवश्यक विशेषता बन गयी है। (It has come to be regarded as *sine qua non* of central banking)

अंतिम ऋणदाता के रूप में केन्द्रीय बैंक के कार्य को विशेष महत्व सन् 1873 में वाल्टर बेजहाट (Walter Bagehot) की पुस्तक 'Lombard Street' के प्रकाशन पर प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने कहा —

“Whatever bank or banks keep, the ultimate banking reserve of the country must lend that most freely in time of apprehension for that is one of the characteristic uses of the bank reserves, and the mode in which it attains one of the main ends for which it is kept”¹

अंतिम ऋणदाता के कार्य का जन्म पुनः बट्टा के कार्य से ही हुआ है। पुनः बट्टा करने का अर्थ होता है कि व्यापारिक बैंक या अन्य साख संस्थाएँ आवश्यकता पड़ने पर व्यापारिक बिलों को केन्द्रीय बैंक के हाथ बेचकर धन प्राप्त करती हैं।

(6) केन्द्रीय समाशोधन, भुगतान तथा हस्तान्तरण

(Central Clearance, Settlement and Transfer)

केन्द्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य समाशोधन गृह की सुविधायें प्रदान करना है। शां, बिलिस तथा जान्से जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने बैंकों के पारस्परिक

1. Walter Bagehot : *Lombard Street*, p. 66

लेन-देनों को समाशोधन द्वारा निबटाने को केन्द्रीय बैंक का एक प्रमुख कार्य माना है। श्री एच० पी० विलिस (H. P. Willis) के मतानुसार, “समाशोधन गृह का कार्य केन्द्रीय बैंकिंग के कार्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और यह एक ऐसा कार्य है जिसे अन्य कोई सस्था इतनी अच्छी तरह नहीं कर सकती है।”¹ जान्से (Jauncey) के शब्दों में “समाशोधन केन्द्रीय बैंकिंग की मुख्य प्रक्रिया है।”²

समाशोधन गृह की सुविधा द्वारा बैंक बिना नकद कोषों का हस्तान्तरण किए पारस्परिक दायित्वों का निबटा लेते हैं। व्यापारिक बैंकों के लिए यह सुविधा बड़ी महत्वपूर्ण है। इससे बैंकों का आरसी भुगतान सुविधा पूर्वक हो जाता है और तकरी के उपयोग में मितव्ययिता होती है। विलिस (H. P. Willis) के शब्दों में “केन्द्रीय बैंक द्वारा संगठित समाशोधन व्यवस्था केवल नकद तथा पूँजी की मितव्ययिता का साधन ही नहीं है बल्कि किसी भी समय समाज द्वारा बनाये रखी जाने वाली तरलता का परीक्षण का भी एक साधन है जिसके सम्बन्ध में केन्द्रीय बैंक को दिन प्रतिदिन जानकारी रखना आवश्यक है।”³

(7) साख का नियमन तथा नियन्त्रण (Regulation and Control of Credit)

साख का नियन्त्रण तथा नियमन केन्द्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। केन्द्रीय बैंक के अन्य सभी कार्य इसी को सफलतापूर्वक करने के लिए किए जाते हैं। व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख का सृजन किया जाता है और वे लाभ कमाने वाली व्यावसायिक संस्थायें होने के कारण कभी कभी अत्यधिक साख का सृजन कर देती हैं। साख मुद्रा व्यापार तथा वाणिज्य के लिए बड़ी लाभदायक है परन्तु जब देश की व्यापारिक आवश्यकताओं से अधिक साख का विस्तार हो जाता है तो

¹ “The clearing function, with its ancillary elements, is among the most significant of central banking function and is one for which only a very incomplete substitute may be found through resort to other expedients”

—H. P. Willis : *Theory and Practice of Central Banking*, p 359.

² “Clearing is the main operation of central banking”

—Jauncey *Australia's Government Bank*, pp 166 + 168.

³ “A system of clearing, organised and solidified by the central banks is not only a means of economising cash or capital but is also a means of testing at any time the degree of liquidity which the community is maintaining, a matter which is essential for the central bank to know from day-to-day.”

—H. P. Willis : *Theory and Practice of Central Banking*.

यह अर्थव्यवस्था के लिए मकट का कारण बन जाता है। अतः बैंकी द्वारा मृजित साख की मात्रा पर देश तथा जन हित में केन्द्रीय बैंक का नियन्त्रण होना अति आवश्यक है। केन्द्रीय बैंक साख का नियमन तथा नियन्त्रण कर देश के सामान्य कीमत स्तर (General price level) में स्थिरता रख सकता है, विदेशी विनिमय दर की स्थिरता (Stability in the Foreign Exchange Rates) बनाये रख सकता है, उत्पत्ति तथा रोजगार का विस्तार कर सकता है, व्यापार चक्रों से अर्थ-व्यवस्था को बचा सकता है तथा देश की आर्थिक प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त कर सकता है। इसी कारण साख के नियमन तथा नियन्त्रण की आवश्यकता आज ससार के सभी देशों में समझी जाती है।

केन्द्रीय बैंक द्वारा साख के नियमन तथा नियन्त्रण के उद्देश्य तथा उसकी प्राप्ति के लिए अपनाय जान वाले विभिन्न तरीकों का वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया है।

डा० डी० काव द्वारा बताये गये इन सात कार्यों के अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक कुछ अन्य कार्य भी करता है।

(8) सूचनायें तथा आंकड़े एकत्रित करना और प्रकाशित करना (Collection and Publication of Statistics and other Economic Information)

केन्द्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य आर्थिक सूचनायें तथा आंकड़े एकत्रित करना तथा उन्हें प्रकाशित करना है। इन आंकड़ों की सहायता से देश की आर्थिक नीतियों के निर्धारण तथा क्रियान्वयन में बड़ी सहायता मिलती है। आर्थिक नियोजन (Economic Planning) को सफल बनाने में इन सूचनाओं तथा आंकड़ों का उपयोग किया जा सकता है। इन आंकड़ों की सहायता से देश की आर्थिक प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है और उसकी अन्य देशों से तुलना की जा सकती है। आजकल सभी देशों के केन्द्रीय बैंकों में इस कार्य को सफलता पूर्वक करने के लिए पृथक् 'अनुसंधान तथा सांख्यिकी' विभाग होते हैं जिनमें अनेक कुशल तथा प्रशिक्षित व्यक्ति कार्य करते हैं। इन योग्य तथा कुशल विशेषज्ञों की सहायता से सूचनाओं तथा आंकड़ों का सफलतापूर्वक प्रकाशन अधिक विश्वसनीय तथा निपुणतापूर्वक किया जा सकता है। ससार के सभी केन्द्रीय बैंक विभिन्न प्रकार के कुलेटिन, रिब्यूज तथा प्रकाशन निकालते हैं जिनसे सूचनाओं का प्रसारण केन्द्रीय बैंक की नीतियों को समझने में बड़ी सहायता मिलती है।

केन्द्रीय बैंक द्वारा साख का नियमन तथा नियन्त्रण (Regulation and Control of Credit by the Central Bank)

केन्द्रीय बैंक द्वारा साख-मुद्रा का नियमन तथा नियन्त्रण केन्द्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। केन्द्रीय बैंक का यह ऐसा कार्य है जिसमें केन्द्रीय बैंकिंग

नीति के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न निहित हैं तथा जिसके माध्यम से केन्द्रीय बैंक के सभी कार्य एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और सम्मिलित उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। नोट नियन्त्रण के एकाधिकार द्वारा चलन का नियमन साख के नियन्त्रण से जुड़ा हुआ है और विभिन्न केन्द्रीय बैंकिंग अधिनियमों में इसका उल्लेख है। उदाहरणार्थ बैंक आफ कनाडा के अधिनियम में बैंक का प्रमुख कार्य "साख तथा चलन का नियन्त्रण, राष्ट्रीय मौद्रिक इकाई के बाह्य मूल्य की सुरक्षा तथा नियन्त्रण और मौद्रिक कार्य के अन्तर्गत जहाँ तक सम्भव हो, उत्पादन, व्यापार, कीमतों तथा रोजगार के सामान्य स्तर के उच्चावचनों को अपने प्रभाव द्वारा कम करना" (To regulate credit and currency, to control and protect the external value of the monetary unit, and to mitigate by its influence fluctuations in the general level of production, trade, prices and employment so far as may be possible within the scope of monetary action) तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के अधिनियम में 'चलन तथा साख प्रणाली का देश के लाभ के लिए संचालन' (Generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage) आदि की व्यवस्था की गई है।

केन्द्रीय बैंक द्वारा साख नियन्त्रण का कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि इसी कार्य के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के बैंक के अधिनियम में केन्द्रीय बैंक की परिभाषा इस प्रकार दी गई है. 'केन्द्रीय बैंक वह बैंक है जिसको देश के चलन तथा साख को मात्रा के नियमन का उत्तरदायित्व सौंपा गया हो'¹ सभी जानते हैं कि आज प्रत्येक देश की मौद्रिक व्यवस्था में साख मुद्रा का महत्व बढ़ गया है और व्यापारिक बैंकों द्वारा सृजित साख की मात्रा देश की अर्थ-व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालती है। अतः मौद्रिक नीति के सफल संचालन के लिए साख का नियन्त्रण आवश्यक हो जाता है। केन्द्रीय बैंक द्वारा साख के नियमन तथा नियन्त्रण के कार्य का अर्थ है कि देश के व्यापार, उद्योग तथा वाणिज्य की आवश्यकताओं के अनुसार साख की पूर्ति का समायोजन करना है।

साख नियन्त्रण की आवश्यकता (Need for Control of Credit)

बहुत वर्षों में आधुनिक जटिल आर्थिक संगठन में साख क सृजन तथा वितरण के नियन्त्रण की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि सभी प्रकार के मौद्रिक एवं व्यावसायिक भुगतानों में साख का बड़ा महत्व-

¹. "Central Bank is a bank in any country to which has been entrusted the duty of regulating the volume of currency and credit in that country"

पूर्ण योगदान है और देश की अर्थ व्यवस्था पर उसका बुरा और अच्छा दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। (Credit represents a powerful force for good or evil) अतएव आधुनिक अर्थ-व्यवस्था मुद्रा अर्थ-व्यवस्था (Money Economy) न होकर साख-अर्थ-व्यवस्था (Credit Economy) है।

यद्यपि विद्वानों ने इस बात पर मतभेद है कि साख की मात्रा में परिवर्तन किस सीमा तक तथा किन परिस्थितियों में मुद्रा की क्रय-शक्ति तथा व्यापारिक क्रियाओं और रोजगार पर प्रभाव डालता है परन्तु सभी सामान्यतया यह स्वीकार करते हैं कि इन तत्वों में पारस्परिक सम्बन्ध है तथा कीमती और व्यापारिक क्रियाओं में परिवर्तन आर्थिक सगठन के विभिन्न अंगों में विघ्न (Disturbances) तथा कुसमा-योजन (Mal adjustment) उत्पन्न करता है। वास्तव में गत 50-60 वर्षों में मुद्रा की क्रय शक्ति तथा व्यापारिक क्रियाओं में परिवर्तनों के फल स्वरूप उत्पन्न सामाजिक तथा आर्थिक दुष्परिणामों ने साख के नियमन तथा नियंत्रण के महत्व को और भी बढ़ा दिया है।

साख-नियन्त्रण के उद्देश्य (Objectives of Credit Control)

साख नियन्त्रण की आवश्यकता तथा विशेषाधिकार युक्त केन्द्रीय बैंक को साख नियन्त्रण का कार्य सौंपने के सम्बन्ध में आज सभी एकमत हैं किन्तु साख के नियन्त्रण के मुख्य उद्देश्यों के सम्बन्ध में आज भी मतभेद है। साख-नियन्त्रण के साधारणतया निम्न तीन उद्देश्य बताये जाते हैं :-

- (1) आन्तरिक कीमत-स्तर की स्थिरता (Stability of Internal Price Level)
- (2) विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता (Stability of the Rate of Foreign Exchange)
- (3) आय तथा रोजगार के उच्च स्तर पर आर्थिक स्थायित्व (Economic Stabilisation at High Levels of Income and Employment)

साख नियन्त्रण के विभिन्न उद्देश्यों का विवेचन इस प्रकार है।

(1) आन्तरिक कीमत स्तर की स्थिरता (Stability of Internal Price Level) :- बहुत अधिक समय तक केन्द्रीय बैंक की साख नियन्त्रण नीति का एक-मात्र उद्देश्य विदेशी विनिमय दर में स्थिरता रखना था परन्तु प्रथम युद्धोत्तर काल में विशेषकर स्वर्णमान के पतन के पश्चात् आन्तरिक कीमत-स्तर की स्थिरता के उद्देश्य को अधिक महत्व दिया जाने लगा। लांड जे० एम० कीन्स तथा प्रो० गुस्त्व फंसल जैसे अनेक विद्वानों का मत है कि आन्तरिक साम्यावस्था (Internal

Equilibrium) के लिए कीमत स्तर को स्थिर रखने की नीति अपनानी चाहिए। डा० रेगनर नर्से (Dr. Ragnar Nurkse) के शब्दों में आन्तरिक साम्यावस्था “राष्ट्रीय आय का वह स्तर है जबकि न तो सामान्य बेरोज़गारी हो और न कीमतों में स्फीतिक वृद्धि।”¹ इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अर्थ-व्यवस्था की सामान्य क्रियाशीलता को अस्त व्यस्त करने वाले कीमतों के उच्चावचनों से बचना चाहिये। हम पहले यह अध्ययन कर चुके हैं कि कीमतों में स्फीतिक वृद्धि से समाज के विभिन्न वर्गों को कितना कष्ट होता है और यदि मुद्रा स्फीति बढ़ता जाय तो यह सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक तन्त्र को ही उखाड़ फेंकता है। मुद्रा सकुचन से लोग क्रय शक्ति की कमी तथा बेकारी का शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार कीमतों में अत्यधिक उच्चावचन घन और आय के वितरण को असमान कर देते हैं तथा उत्पादन कार्यों में अस-तुलन स्थापित हो जाता है। यदि कीमत स्तर की स्थिरता बनाये रखी जाय तो समाज के विभिन्न वर्गों के पारस्परिक आर्थिक सम्बन्धों को स्थिर रखा जा सकता है और साथ ही अर्थव्यवस्था को बाह्य कीमत परिवर्तनों के कुप्रभावों से बचाया जा सकता है।

(2) विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता (Stability of the Rates of Foreign Exchange):—पहले केन्द्रीय बैंकों की साख नियन्त्रण नीति का उद्देश्य विदेशी विनिमय दर को ही स्थिर रखना होता था। प्रथम महायुद्ध के पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान का मुख्य उद्देश्य विदेशी विनिमय-दर को स्थायी बनाना ही था क्योंकि विभिन्न देशों की मुद्राय या तो स्वर्ण की थी या स्वर्ण पर आधारित थी और उनकी विनिमय दरों में स्वयं ही स्थिरता बनी रहती थी। द्विघातुमान काल में भी द्विघातुमान पर आधारित सभी विनिमय दरें स्वतः स्थिर रहती थीं। विनिमय दरों की स्थिरता के लिए आन्तरिक कीमत स्तर में परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ती थी। इसके लिए कभी मुद्रा स्फीति और कभी मुद्रा सकुचन किया जाता था। उस समय लोग ऐसा मानते थे कि अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास (International Confidence) को टूट कराने तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के लिए, जिनमें विश्व का अधिकतम आर्थिक कल्याण निहित है, विनिमय दरों की स्थिरता आवश्यक है। प्रथम युद्धोत्तर काल विशेषकर स्वर्णमान के पतन के पश्चात् आन्तरिक कीमत स्तर की

¹. “Internal equilibrium is a level of national income such that there is neither general unemployment nor an inflationary tendency for prices to rise”

—Dr Ragner Nurkse ; Article on Domestic and International Equilibrium in *New Economics* (Edited by S E Harris), p. 272.

स्थिरता पर अधिक जोर दिया जान लगा और विनिमय दरों की स्थिरता गौण समझी गई। विदेशी विनिमय दरों की स्थिरता तथा आन्तरिक कीमत स्तर स्थिरता परस्पर विरोधी नहीं है (Exchange Stability is not inconsistent with Internal Price Stability) आजकल विदेशी विनिमय दरों की स्थिरता विनिमय नियन्त्रण (Exchange Control) के द्वारा प्राप्त की जाती है। अब केन्द्रीय बैंक मुद्रा के आन्तरिक और बाह्य दोनों मूल्यों में स्थिरता स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं।

(3) आय और रोजगार के उच्च स्तर पर स्थायित्व (Economic Stabilisation at High Levels of Income and Employment) —साख नियन्त्रण का उद्देश्य आय और रोजगार के उच्चस्तर पर स्थायित्व प्राप्त करना है। सभी देश इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि आय स्तर उच्चतम हो, वृत्ति में वृद्धि हो, रहन-सहन के दर्जे में सुधार हो और अर्थ-व्यवस्था को पूर्ण वृत्ति (Full Employment) के स्तर तक पहुँचाया जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति व्यापार चक्रों को नियन्त्रित करके ही की जा सकती है। साइं कोस के विचारानुसार "The object of a monetary policy should be to reduce the ebb and flow of trade cycles and bring about equilibrium between savings and investment at the point of full employment."¹ अतः साख तथा मौद्रिक नीति का उद्देश्य पूर्ण वृत्ति विन्दु पर सचय और विनियोग के बीच साम्यावस्था स्थापित करना तथा व्यापार चक्रों का नियन्त्रण तथा निराकरण करना होना चाहिए। इसीलिए इंग्लैंड, अमेरिका, स्वीडन आदि देशों ने साख तथा मौद्रिक नीति में आय और वृत्ति के उच्चतम स्तर पर स्थायित्व की प्राप्ति को अपना उद्देश्य माना है।

इस सम्बन्ध में "आधुनिक प्रवृत्ति एक ऐसी मौद्रिक तथा साख नीति अपनाती है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय स्थायित्व (कुछ परिस्थितियों में विनिमय दरों के व्यवस्थित समायोजन को ध्यान में रखते हुए) तथा वास्तविक आय तथा वृत्ति के उच्चतम स्तरों को बनाये रखने के दोनों उद्देश्यों में समन्वय स्थापित किया जा सके।"² अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ने उक्त व्यवस्था को जन्म दिया है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय स्थायित्व तथा उच्चतम स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक

¹. J. M. Keynes : *A Treatise on Monetary Reform*, 1923

². "The most recent tendency in official monetary circles is to combine the objective of international exchange stability (subject to provisions for orderly adjustment of exchange rates in certain circumstances) with that of promoting and maintaining high levels of employment and real income"

स्थापित्व के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके और उनमें सामान्त्रस्य स्थापित किया जा सके।

साख-नियन्त्रण की रीतियाँ (Methods of Credit Control)

केन्द्रीय बैंक द्वारा साख-नियन्त्रण के मुख्य उद्देश्यों का अध्ययन करने के बाद उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बैंक जिन रीतियों का प्रयोग करता है उनका विवेचन भी आवश्यक है। साख-नियन्त्रण की रीतियों को दो मुख्य श्रेणियों में बाटा जाता है (1) परिमाणात्मक विधिया (Quantitative Methods) (2) गुणात्मक विधिया (Qualitative Methods)। परिमाणात्मक विधियाँ वे विधिया हैं जो साख के परिमाण तथा उसकी लागत का नियन्त्रण करती हैं जब कि गुणात्मक विधिया साख के प्रयोग तथा व्यवहार को नियन्त्रित करती है। पहले यह मान्यता थी कि साख का परिमाणात्मक नियन्त्रण ही पर्याप्त है क्योंकि साख के परिमाण के नियन्त्रण से ही साख के प्रयोग तथा व्यवहार पर भी नियन्त्रण हो जाता है। परन्तु अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि साख का परिमाणात्मक नियन्त्रण ही पर्याप्त नहीं है वरन् उसका गुणात्मक नियन्त्रण भी आवश्यक है। गुणात्मक नियन्त्रण का अर्थ होता है कि साख का प्रयोग उन्हीं कार्यों के लिए हो जिन्हे केन्द्रीय बैंक वांछनीय समझता है, अवाछनीय तथा अनुपयुक्त क्षेत्रों में साख के प्रयोग पर रोक लगा दी जाती है।

केन्द्रीय बैंक साख के नियन्त्रण की निम्नलिखित रीतियों का प्रयोग करता है :—

(अ) परिमाणात्मक विधिया (Quantitative Methods of Credit Control)

- (1) बैंक दर नीति (Bank-Rate Policy)
- (2) खुले बाजार की क्रियायें (Open Market Operations),
- (3) व्यापारिक बैंकों के नकद कोष अनुपात में परिवर्तन (Variation in the Cash Reserve Ratios of Commercial Bank)
- (4) तरल कोषानुपात (Liquidity Ratios)

(ब) गुणात्मक विधिया (Methods of Qualitative Credit Control)

- (5) साख की राशनिग (Rationing of Credit)
- (6) प्रतिभूति ऋणों की सीमा आवश्यकताओं में परिवर्तन (Changes in Margin Requirements of Security Loans)

- (7) उपभोक्ता-साख का नियम (Regulation of Consumers Credit)
- (8) प्रत्यक्ष कार्यवाही (Direct Action)
- (9) नैतिक दबाव (Moral suasion)
- (10) प्रचार (Publicity)

अब हम साख नियन्त्रण की इन उपर्युक्त विधियों का विस्तारपूर्वक विवेचन करेंगे ।

(1) बैंक-दर नीति

(Bank-Rate Policy)

साख नियन्त्रण की विधियों में बैंक-दर का महत्वपूर्ण स्थान और अन्य विधियों की तुलना में यह सबसे प्राचीन है ।

बैंक-दर का अर्थ (Meaning of Bank Rate):—बैंक-दर से अग्रिम प्राप्त उस दर से होता है जिस पर देश का केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों का पुनः बट्टा (Rediscount) करता है या स्वीकृत प्रतिभूतियों पर ऋण या अग्रिम देता है । प्रतिभूतियाँ की जमानत पर दिए गये ऋणों या अग्रिमों की ब्याज-दर को अग्रिम दर (Advances Rate) कहा जाता है ।

ग्रा० एस० सेयर्स (R. S. Sayers) के अनुसार "बैंक-दर वह ब्याज की दर है जो केन्द्रीय बैंक द्वारा बिलों का पुनः बट्टा करने तथा अग्रिमों को देने पर ली जाती है, यह सदस्य बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास नकद कोष ला देती है ।"¹ स्पाल्डिंग (Spalding) के शब्दों में बैंक दर वह "न्यूनतम ब्याज दर है जो बैंक (केन्द्रीय बैंक) द्वारा स्वीकृत प्रतिभूतियों का पुनः बट्टा करने पर ली जाती है ।"²

लार्ड जे० एम० कीन्स (Lord J. M. Keynes) के अनुसार "यह ब्याज की वह प्रभावी दर है जो बाजार में ऋण लेने तथा ऋण देने के लिए प्रचलित है ।"³

¹. "Bank rate is the rate of interest charged by the central bank when, by rediscounting bills or by making advances, it puts reserve cash at the disposal of approved banks or other financial institutions" — R S Sayers . *Central Banking After Bagehot* (Oxford 1957) p 123

² Bank rate is "the minimum rate charged by the Bank (Central Bank) for discounting approved bills of exchange"

—W F. Spalding Quoted by Hartley Withers *Meaning of Money*, p. 182.

³ Bank rate is "the effective rate for lending and borrowing which prevails in the market."

—J. M. Keynes : *A Treatise on Money*, Vol I, p. 200.

कुछ देशों जैसे इंग्लैण्ड तथा अमेरिका में इसे कटौती दर (Discount Rate) भी कहते हैं। इसीलिए पीटर फोसेक (Peter G. Fousek) के कथनानुसार "कटौती-दर नीति वह है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक उन शर्तों में परिवर्तन करता है जिन पर स्वीकृत अल्पकालीन सम्पत्तियों की कटौती अथवा सुरक्षित ऋणों के माध्यम से वह बाजार को वित्तीय सहायता देता है।"¹

यहाँ पर हमें बैंक-दर (Bank Rate) तथा बाजार दर का अन्तर समझ लेना चाहिए। जैसा कि विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट है कि बैंक दर वह दर है जिस पर केन्द्रीय बैंक देश के व्यापारिक बैंकों के बिलों का पुनः बट्टा करता है। इसके विपरीत बाजार दर (Market Rate) वह दर है जिस पर व्यापारिक बैंक तथा अन्य ऋणदाता सत्यायें मुद्रा बाजार में स्वीकृत बिलों या ड्रिडियो का बट्टा करती हैं या स्वीकृत प्रतिभूतियों के आधार पर उन्हें ऋण या अग्रिम देती हैं।² बैंक-दर तथा बाजार-दर में आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। जब बैंक दर बढ़ा दी जाती है तो सभी बाजार दरें बढ़ जाती हैं और साख की लागत बढ़ने के कारण ऋण लेना हतोत्साहित होता है और साख का संकुचन हो जाता है। इसके विपरीत जब बैंक-दर घटा दी जाती है तो सभी व्याज दरें घट जाती हैं और साख की लागत घटने के कारण ऋण लेना प्रोत्साहित होता है और साख का विस्तार हो जाता है। संक्षेप में, यही बैंक-दर द्वारा साख नियन्त्रण की प्रक्रिया है।

बैंक-दर नीति का विकास (Evolution of Bank Rate Policy)

बैंक आफ इंग्लैण्ड पहला केन्द्रीय बैंक था जिम्ने साल-नियन्त्रण के साधन के

1. "Discount policy may conveniently be defined as the varying of the terms, and of the conditions in the broadest sense, under which the market may have temporary access to central bank credit through discount of selected short term assets or through secured advances."

—Peter G. Fousek : *Foreign Central Banking : The Instruments of Monetary Policy*, 1957, p. 13.

2. Bank Rate (Discount Rate) is the rate at which the Central Bank discounts the approved bills of exchange of the commercial banks Market Rate is the rate at which the commercial banks and other lending institutions discount the bills or hundies of their customers or grant loans to them. Deposit Rate is the rate which is paid by the commercial and other banks on the deposits of their depositors. Call Rate is the rate at which the money is advanced to brokers for very short periods and on the condition that money will be returned either on demand or within the stipulated period usually one or two days.

रूप में बैंक-दर का प्रयोग पहली बार सन् 1839 में किया। बाद में सन् 1847, 1857 तथा 1866 के सकटकालों में फिर इसका प्रयोग किया गया। इस काल में बैंक आफ इंग्लैंड धीरे-धीरे 'अन्तिम ऋणदाता' (Lender of Last Resort) की स्थिति ग्रहण करता जा रहा था और साख की राशिनिय (Rationing of Credit) इत्यादि साख नियन्त्रण के साधनों का प्रयोग करने में इसलिए कठिनाई अनुभव कर रहा था क्योंकि इस साधन का 'अन्तिम ऋणदाता' के कार्य से सामान्यतया नहीं बैठता था। 'अन्तिम ऋणदाता' के दायित्व के अनुरूप उसे सकटकाल में धन की सभी उचित मागों की पूर्ति करनी थी और इसलिए उसने अपनी सुरक्षा तथा धन की मागों को केवल 'आवश्यक' तक ही सीमित रखने के लिए कटौती दरों को बढ़ाया। सकट कालों में अपने अनुभव से बैंक आफ इंग्लैंड ने दो मुख्य बातें सीखीं जो बाद में अन्य केन्द्रीय बैंकों की कटौती नीति का आवश्यक अंग बन गईं। ये दो निष्कर्ष थे—

(1) साख सकुचन लागू करने के लिए केन्द्रीय बैंक को बहुत अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि साख विस्तार तथा मद्धे की प्रवृत्तियों को उलटना तब बड़ा कठिन है जब वे बहुत दूर तक मागे बढ़ चुकी हों। (2) बैंकों को आश्वस्त करना चाहिए कि सकटकाल में उनकी धन की मागों की किसी भी कीमत पर पूर्ति की जायेगी। इस आश्वासन से ही सकट टल जायेगा। उस समय यह माना जाता था कि बैंक-दर का सामान्यतया व जार-दर से ऊंचा रखना चाहिए जिससे केन्द्रीय बैंक की सहायता केवल सकटकाल में ही अन्य बैंकों को उपलब्ध हो सके।

प्रथम महायुद्ध के पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय स्तरोंमान के युग में 'बैंक दर का प्रयोग' बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता था परन्तु प्रथम महायुद्ध के पश्चात् साख नियन्त्रण के अन्य साधनों की तुलना में इसका प्रयोग काफी कम हो गया। अक्टूबर 1929 के बाल स्ट्रीट सकट तथा 1931 में स्वयंमान के पतन के परिणामस्वरूप केन्द्रीय बैंकों ने सस्ती मुद्रा नीति (Cheap Money Policy) अपनायी और इस प्रकार बैंक दर का प्रयोग तथा महत्व बहुत कम हो गया। सन् 1951 से फिर बैंक आफ इंग्लैंड ने साख-नियन्त्रण के लिए बैंक दर का प्रयोग आरम्भ किया है। भारत में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने भी सन् 1951 में बैंक दर के अस्वकी साख नियन्त्रण के लिए प्रयोग किया है। अब इधर कुछ वर्षों में बैंक दर का महत्व फिर बढ़ रहा है।

बैंक-दर नीति का सिद्धान्त (Theory of Bank Rate Policy)

अन्तर्राष्ट्रीय स्तरोंमान के अन्तर्गत साख नियन्त्रण के साधनों के रूप में प्रयुक्त बैंक दर नीति के पीछे यह मान्यता थी कि बैंक दर में परिवर्तन के फलस्वरूप सभी व्याज दरों में समान परिवर्तन होते हैं, व्याज दरों में परिवर्तन मुद्रा तथा साख

की मांग पूर्ति तथा पूंजी के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह (International flow of capital) में परिवर्तन लाता है और फिर कीमत-तल, उत्पादन-व्यय, उत्पादन तथा व्यापार में अपेक्षित परिवर्तन होगा और भुगतान का सतुलन ठीक हो जायेगा। यदि किसी देश का व्यापार शेष उसके विरुद्ध हो जाता है और भुगतान में स्वर्ण विदेशों को जाने लगता है तो केन्द्रीय बैंक बैंक-दर बढ़ा देती है जिससे आंतरिक कीमत तल, व्याज दरें प्रभावित होती हैं और बिना स्वर्ण निर्यात के भुगतान सतुलन ठीक हो जाता है। बैंक दर ऊँची होने से विदेशी अपने कोष तथा पूंजी उसी देश में लगाते हैं और उसी देश की मुद्रा की मांग विदेशी बाजारों में बढ़ जाती है फलतः विदेशी मुद्रा की इकाइयों में उस देश की मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और विनिमय दर उस देश के पक्ष में हो जाती है। बैंक दर बढ़ जाने से ऋण लेना हतोत्साहित होता है क्योंकि ऋणियों के लिए वह देश महंगा हो जाता है, व्यापारिक क्रियाएँ कम हो जाती हैं बाजार में मदी की प्रवृत्ति के कारण मौद्रिक आथ तथा कीमत तल घट जात है, कीमतेँ घटने पर निर्यात प्रोत्साहित तथा आयात हतोत्साहित होते हैं। फलतः व्यापार शेष देश के पक्ष में आ जाता है। इस प्रकार बैंक दर में परिवर्तन अल्पकालीन मुद्रा बाजार तथा दीर्घकालीन पूंजी बाजार के माध्यम से विदेशी विनिमय बाजार को प्रभावित करता है और अतः म व्यापार-शेष प्रभावित होता है।

बैंक-दर में परिवर्तन देश की आन्तरिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। जब बैंक दर में वृद्धि होती है तो बाजार की व्याज दरें बढ़ जाती हैं। ऋण लेना महंगा तथा कम लाभदायक हो जाता है और पूंजी की मांग कम हो जाती है। विनियोग वस्तुओं के उत्पादन में कमी के कारण निर्माण उद्योग में मदी आ जाती है। त्रय शक्ति में कमी के कारण कीमत गिरने लगती हैं। व्यापारी तथा दुकानदार ऋण लेकर स्टॉक रखत थे कीमतों में कमी के अनुमान के कारण ऋणों तथा स्टॉक दोनों को घटाते हैं। व्यापारी उत्पादन को दिशे गये आडर रद्द कर देते हैं और उत्पादनकर्ता उनको कम कीमत पर माल बेचने को तैयार हो जाता है फलतः थोक कीमतें भी गिर जाती हैं। लेकिन उत्पादनकर्ताओं की लागतें तथा मजदूरों व्यय नहीं घटता और अतः उन्हें उत्पादन घटाना पड़ना है और बेरोजगारी फैलती है और फिर उत्पादन तथा मजदूरी आथ में कम हो जाती है। बैंक दर घटने पर विपरीत प्रभाव होता है।

इस प्रकार बैंक दर में परिवर्तन देश की आंतरिक तथा बाह्य दोनों स्थितियों को ठीक करता है। (The delicate and beautiful instrument of Bank rate is used by the Central Bank for operating on the internal situation as well as on the external situation) बैंक दर में परिवर्तन के अन्य पक्षों को प्रभावित करने की प्रक्रिया का ही हम बैंक-दर नीति का सिद्धान्त (Theory of Bank Rate Policy) कहते हैं।

बैंक दर में परिवर्तनों का प्रभाव (Effect of Changes in Bank Rate)—

बैंक-दर नीति साख को किस प्रकार प्रभावित करती है, इस सम्बन्ध में अर्थ शास्त्रियों में ये मतभेद हैं ।

परम्परागत विचारधारा (The Traditional View)—

इस दिशा में हॉट्टे तथा लाई कीन्स के वाद-विवाद (Hawtrey-Keynes Controversy) का विस्तृत विश्लेषण करने से पहले लाई-कीन्स द्वारा अपनी पुस्तक *Treatise on Money* में उल्लिखित बैंक-दर के तीन परम्परागत सिद्धान्तों की ओर दिशा संकेत करना अनुपयुक्त न होगा—

(1) प्रथम : विचारधारा के अनुसार बैंक-दर को “बैंक मुद्रा या साख मुद्रा की मात्रा का नियमन करने का साधन” माना गया । लाई और स्टोन ने बैंक-दर को चलन की मात्रा का सकुचन करने का सबसे प्रभावी तरीका माना । प्रो० ए० सी० पीगू (Prof A. C. Pigou) के अनुसार बैंक-दर प्रत्यक्ष रूप से बैंक-साख की मात्रा और फिर कीमत-तल पर प्रभाव डालती है ।

(2) दूसरी : विचार धारा के अनुसार बैंक-दर विदेशी-उधार (Foreign Lending) की दर का नियमन कर देश के स्वर्ण कोषों की रक्षा करती है ।

(3) तीसरी : विचार धारा के अनुसार बैंक-दर विनियोग की दर (Rate of Investment) को प्रभावित करती है । बैंक-दर में वृद्धि सचय की तुलना में विनियोग को हतोत्साहित करती है । प्रो० नुट विकसेल (Prof Knut Wicksell) के विचारानुसार बैंक-दर सचय तथा विनियोग के पारस्परिक सम्बन्ध को प्रभावित करती है ।

हॉट्टे-कीन्स विवाद (Hawtrey-Keynes Controversy)

बैंक-दर परिवर्तन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में दो मत प्रतिपादित किए गये हैं । एक मत हॉट्टे (Hawtrey) का है और दूसरा लाई कीन्स (Keynes) का । यहाँ हम इन दोनों विचारों की विस्तृत व्याख्या करेंगे ।

हॉट्टे की विचारधारा (The Hawtrey Line of Thought)—

श्री आर० जी० हॉट्टे (R G Hawtrey) ने अपने विचारों का प्रतिपादन अपनी 'Art of Central Banking' तथा 'A Century of Bank Rate' नामक पुस्तकों में किया है । हॉट्टे के अनुसार बैंक दर में परिवर्तन, अल्पकालीन व्याज दरों को प्रभावित करता है और फिर इसका व्यापारी द्वारा रखे माल के स्टॉक पर प्रभाव पड़ता है । हॉट्टे के मतानुसार व्यापारी ही अर्थ-व्यवस्था का केन्द्र है और उसका कार्य उपभोक्ताओं की मांग के अनुमान लगा कर मांग और पूर्ति में समायोजन

स्थापित करना होता है। यहाँ यह स्मरणीय है कि प्रत्येक व्यापारी जो स्टॉक रखता है उसकी मात्रा उसके स्टॉक रखने के व्यय (जिसमें ब्याज मुख्य होता है) पर निर्भर रहती है। अतः प्रत्येक व्यापारी की स्टॉक रखने की माग लोचदार होती है। हाट्टे के विचारानुसार यदि बैंक दर में वृद्धि की जाती है तो अल्पकालीन ब्याज-दरें बढ़ जाती हैं, पक्के तथा अर्घ्य-पक्के माल का स्टॉक रखने की लागत बढ़ जाती है। परिणामस्वरूप व्यापारी स्टॉक कम कर देते हैं, उत्पादकों को कम माल के आदेश देते हैं, विक्रय राशि वे स्वयं एकत्रित करने के लिए या ऋणों का भुगतान करने के लिए अपने पास रख लेते हैं। फलस्वरूप उत्पादन घट जाता है और बेरोजगारी फैलती है, मजदूरी तथा आय घट जाती है और मदी की सृष्टि होती है। सेयर्स (Sayers) के शब्दों में "The contraction of money incomes leads to a decline in retail sales, leading to reduced purchases from dealers, who again reduce their purchases and so on. The whole movement, sometimes called the vicious circle of deflation, is intensified by a general tendency to hold off the market. Once it is realised that the prices are falling — people postpone purchases in the expectation of securing more favourable terms later,"¹

इसके विपरीत जब बैंक-दर घटा दी जाती है तो अल्प-कालीन ब्याज दरें घट जाती हैं, वस्तुओं के स्टॉक की लागत कम हो जाती है, व्यापारी स्टॉक की मात्रा बढ़ा देते हैं क्योंकि ब्याज के रूप में अब उन्हें कम देना पड़ता है, वे उत्पादन-कर्त्ताओं को अधिक माल के आदेश देते हैं फलतः उत्पादन, रोजगार तथा मौद्रिक आय बढ़ती है। क्रय-शक्ति में वृद्धि के कारण वस्तुओं की बिक्री भी बढ़ती है और यह सब 'मुद्रा-स्फीति के दुष्चक्र' (Vicious circle of Inflation) के कायशील होने के कारण होता है।

हाट्टे के तर्कों का मुख्य आधार माल का स्टॉक रखने की लागत है जिसमें ब्याज की दर सम्मिलित है। इस सम्बन्ध में उनका निष्कर्ष दो बातों पर निर्भर करता है—

- (1) स्टॉक रखने की कुल लागत में ब्याज के व्यय का अनुपात (The proportion of interest charges to the total cost of holding stocks) तथा,
- (2) वस्तुओं की माग की लोच (The Elasticity of demand for those Commodities)

जहाँ तक पहले तत्व का सम्बन्ध है, ब्याज माल का स्टॉक रखने की लागत में बहुत से व्ययों में से एक है (अन्य हैं बीमा, मडार कम इत्यादि) अतः ब्याज व्यापारी

1. R. S. Sayers : *Modern Banking* (Second Ed., 1957) p. 142.

के खर्च का प्रमुख भाग नहीं है, जैसा कि हाट्टे ने माना है। वस्तुओं की मांग भी पर्याप्त रूप से लोचदार नहीं होती। अतः हाट्टे के सिद्धान्त की आलोचना की गई है।

कीन्स की विचार धारा (The Keynesian Line of Thought) :

लार्ड जे० एम० कीन्स ने अपनी विचारधारा का प्रतिपादन अपनी पुस्तक 'A Treatise on Money' में किया है। कीन्स न बैंक दर परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या करते समय 'दीर्घकालीन व्याज दरों तथा उसका पूंजीगत वस्तुओं के स्टाक पर प्रभाव' को ध्यान में रखा है। कीन्स के अनुसार बैंक-दर देश की आंतरिक स्थिति का अल्पकालीन वंशज दरों के माध्यम से नहीं बरन् दीर्घकालीन व्याज दरों के द्वारा प्रभावित करती है। जब बैंक दर बढ़ा दी जाती है तो दीर्घकालीन व्याज दरें बढ़ जाती हैं और साहसियों को कारखानों, यन्त्रों इत्यादि पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कम आकर्षक लगन लगता है। व्याज दर जितनी ऊँची होगी, किसी भी प्रकार का पूंजी-विस्तार उतना ही कम आकर्षक होगा और व्याज-दर जितनी कम होगी, साहसी उतनी ही अधिक पूंजी विस्तार करेंगे। (The higher the rate of interest, the less attractive is any form of capital extension and the lower the rate, the more it is likely that the entrepreneurs will be undertaking capital extension) इस प्रकार दीर्घकालीन व्याज-दरें बढ़ने से पूंजी की मांग कम हो जाती है, पूंजीगत उद्योगों में उत्पादन घटता है, बेकारी फैलती है और आम, कीमन व्यापार तथा वृत्ति तल गिर जाता है और अर्थ-व्यवस्था में मंदी फैलती है। परन्तु व्यावहारिक जीवन में व्यापार तथा कीमतों व्याज-दर नीतियों से इतनी संवेदनशील नहीं होती "Bitter experience has shown that the state of trade, although it does appear to respond eventually to dear or cheap money, responds painfully slowly" अतः दीर्घकालीन व्याज-दर नीति की सफलता पूंजी की मांग की लोच पर निर्भर करती है। पूंजी की मांग लोच जितनी अधिक होगी, यह नीति उतनी ही प्रभावी होगी। परन्तु मंदी-काल में व्याज दर की कितनी भी कमी उत्पादन को नहीं बढ़ा सकती और तेजीकाल में व्याज दर की वृद्धि उसे विनियोग करने से नहीं रोक सकती। फलतः व्यापारियों की पूंजी की मांग कुछ बेलाच होती है।

यदि हम उपर्युक्त दोनों विचारधाराओं की तुलना करें तो यह विदित होगा कि हाट्टे तथा कीन्स दोनों यह आधार लेकर चले हैं कि बैंकिंग नीति वस्तुओं के स्टाक रखन की लागत का प्रभावित करती है अतः केवल वस्तुओं के प्रकार का है जो बैंक दर से प्रभावित होते हैं और यह अतः केवल महत्व की सीमा (Degree of Emphasis) का है।

आज हॉटे तथा कॉन्स के इस विवाद का कोई महत्व नहीं रह गया है क्योंकि आजकल सभी स्वीकार करते हैं कि बैंक दर दीर्घकालीन व्याज दरों के माध्यम से अर्थ व्यवस्था को प्रभावित करती है।

बैंक दर का महत्व (Significance of Bank Rate)

डा० डी० काक न बैंक दर का तीन प्रकारों का महत्व बताया है। प्रथम बैंक दर उन दरों की ओर संकेत करती है जिन पर जनता व्यापारिक बैंको तथा केन्द्रीय बैंक से स्वीकृत पत्रों के आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करती है। द्वितीय जहाँ व्यापारिक बैंको के लिए अलग दरों का प्रकाशन नहीं होता, बैंक दर उन दरों का आधार होती है जिन पर व्यापारिक बैंक केन्द्रीय बैंक से साख प्राप्त करती है। तृतीय केन्द्रीय बैंक के साख-नियंत्रण के साधन के रूप में बैंक दर का मनोवैज्ञानिक महत्व बहुत अधिक है। जैमाकि गिबसन (Gibson) ने कहा है कि "बैंक दर की वृद्धि को एक स्वचालित वित्त तथा अर्थ तन्त्र को चेतावनी की लाल रोशनी मानना चाहिए जबकि बैंक दर में कमी हरी रोशनी की भाँति है जिसका अर्थ है कि रास्ता साफ है और व्यापार का जहाज आगे परन्तु सावधानी से, बढ़ सकता है।"¹

बैंक-दर नीति की सीमायें (Limitations of Bank Rate Policy)

साख नियंत्रण के साधन के रूप में बैंक दर की निम्नलिखित सीमायें —

(1) देश की अर्थ व्यवस्था में लोच (Elasticity in the Economy) - बैंक दर नीति तभी सफल है जबकि देश की अर्थव्यवस्था लोचपूर्ण हो। लोचदार अर्थव्यवस्था में बैंक-दर परिवर्तनों का प्रभाव व्याज दर, विनियोग उत्पादन, मजदूरी, कीमतों, आय तल आदि पर शीघ्रतापूर्वक पड़ता है। यदि अर्थ-व्यवस्था लोचदार नहीं है तो बैंक दर में परिवर्तन का प्रभाव सभी क्षेत्रों पर नहीं पड़ेगा और बैंक दर नीति सफल नहीं होगी।

(2) बैंक दर में परिवर्तन के अनुरूप अन्य व्याज दरों में परिवर्तन (Change in all money rates in line with the Bank Rate) - बैंक दर नीति की सफलता की दूसरी आवश्यक शर्त है कि बैंक दर में परिवर्तन के अनुसार देश की सभी धन की दरें परिवर्तित होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो बैंक दर नीति की सफलता संदिग्ध ही रहेगी। इस शर्त की पूर्ति के लिए देश का मुद्रा बाजार

¹ "A rise in the discount rate may be regarded as the amber coloured light of warning of a robot system of finance and economics, while a fall in discount rate may be looked upon as the green light indicating that the coast is clear and the ship of commerce may proceed on her way with caution."

² —Gibson, Quoted by M H De Kock, *Central Banking*, p, 168.

विकसित तथा सवेदनशील होना चाहिए। भारत जैसे अर्थ-विकसित देश में, जहाँ मुद्रा बाजार विकसित तथा सुसंगठित नहीं है, बैंक-दर-नीति में परिवर्तन सभी व्याज दरों को शीघ्र प्रभावित नहीं करता।

उपर्युक्त दोनों सीमाओं के कारण बैंक दर नीति की सफलता साख-नियंत्रण के साधन के रूप में सीमित रहती है।

(2) खुले-बाजार की क्रियायें (Open Market Operations)

केन्द्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण की दूसरी परम्परागत तथा परिमाणात्मक रीति खुले बाजार की क्रियायें हैं। इस रीति के अंतर्गत केन्द्रीय बैंक खुले बाजार में स्वयं तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर साख की मात्रा का नियमन करता है। विस्तृत अर्थों में "खुले बाजार की नीति का अर्थ केन्द्रीय बैंक द्वारा मुद्रा बाजार में किसी भी प्रकार के विलो अथवा प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय है, किन्तु सकीर्ण अर्थों में खुले बाजार की क्रियाओं का अर्थ केन्द्रीय बैंक द्वारा केवल सरकारी प्रतिभूतियों में खुले बाजार की क्रियाओं का अर्थ केन्द्रीय बैंक द्वारा केवल सरकारी प्रतिभूतियों में दीर्घकालीन अथवा मध्यकालीन का क्रय-विक्रय है।"¹ साख नियंत्रण की इस रीति का प्रयोग सर्वप्रथम स्वयं मान के पतन के पश्चात् विभिन्न देशों में किया गया।

खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय कर साख की मात्रा को प्रभावित किया जाता है। साख का विस्तार करने के लिए प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है और साख का संकुचन करने के लिए प्रतिभूतियों को बेचा जाता है। डॉ० डी० फ्रांक के शब्दों में "केन्द्रीय बैंक के द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय प्रत्यक्ष रूप से तथा शीघ्र ही चलन में मुद्रा की मात्रा और व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों को बढ़ाता और घटाता है, बैंक नकदी की पूर्ति में वृद्धि या कमी और इस प्रकार व्यापारिक बैंकों की साख-सृजन की शक्ति में वृद्धि या कमी मुद्रा की मात्रा को और भी बढ़ाती या घटाती है। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन व्याज दरों तथा साख में सापेक्षिक परिवर्तन लाता है जो फिर कीमत-तल, लागतों, उत्पादन तथा व्यापार में आवश्यक समायोजन लाता है।"²

¹ "In the wider sense, open market operations may be held to cover the purchase and sale by the Central Bank in the market of any kind of paper in which it deals, whether Government security or other securities. But in the narrower sense, open market operation has come to be applied only to the purchases or sale of Government securities, both long term and short-term.

² "That purchases or sales of securities by the central bank tend directly and immediately to increase or decrease in the quantity of money in circulation and the cash reserves of commercial banks;

खुले बाजार की क्रियाओं के इस साधन का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। बैंक-दर नीति को सफल बनाने, आंतरिक कीमत-तल में स्थिरता लाने, भुगतान-मतुलन ठीक करने इत्यादि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस नीति का प्रयोग किया जाता है।

खुले बाजार की क्रियाओं की सीमाएँ (Limitations of Open Market Operations) खुले बाजार की क्रियाओं की सफलता की शर्तें निम्नलिखित हैं—

(1) प्रतिभूतियों की मांग तथा पूर्ति (Demand and Supply of Securities)—केन्द्रीय बैंक की खुले बाजार की क्रियाओं की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि अर्थ-व्यवस्था में प्रतिभूतियों की पर्याप्त मांग तथा पूर्ति हो।

(2) बैंकों के नकद कोषों का प्रभावित होना (Bank's Cash Reserves should be effected)—व्यापारिक बैंकों की साल-सृजन की शक्ति उनके द्वारा रखे गये नकद कोषों की मात्रा पर निर्भर करती है। खुले बाजार की क्रियाएँ तभी सफल हो सकती हैं जब केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय उनके नकद कोषों को प्रभावित करे। यदि प्रतिभूतियों का विक्रय हो और लोग बैंकों से धन न निकाल कर अपनी संचित राशि से ही भुगतान कर दें और बैंकों के नकद कोष न प्रभावित हो तो खुले बाजार की क्रियाएँ सफल नहीं होंगी।

(3) संगठित मुद्रा तथा प्रतिभूति बाजार (Organised Money and Security Markets)—खुले बाजार की क्रियाएँ तभी सफल हो सकती हैं जब देश में एक पूर्ण विकसित तथा सुसंगठित मुद्रा बाजार तथा प्रतिभूति बाजार हो। केन्द्रीय बैंक तथा मुद्रा बाजार के अन्य अंगों में घनिष्ट पारस्परिक सम्बन्ध हो।

(4) केन्द्रीय बैंक की प्रतिभूतिया क्रय-विक्रय की शक्ति (Adequate Capacity of Central Bank to deal in Securities).—खुले बाजार की क्रियाएँ तभी सफल हो सकती हैं जब केन्द्रीय बैंक के पास पर्याप्त वित्तीय साधन तथा प्रतिभूतियों की मात्रा हो। जिससे वह आवश्यकता पड़ने पर प्रतिभूतियों में लेन देन कर सके। लार्ड कीन्स के शब्दों में "केन्द्रीय बैंक आने वाली तेजी को

that an increase or decrease in the supply of bank cash and, therefore, in the credit creating capacity of the commercial banks, tends still further to increase or decrease the quantity of money, and that changes in the quantity of money tend to bring about relative changes in money rates and credit conditions, which in turn tend to bring about the desired adjustments in the domestic levels of prices, costs, production and trade."

—M. H. De Kock : *Central Banking*, p. 183-4.

रोकने के लिए केवल नतनी ही बारुद का प्रयोग कर सकती है जितनी उन्होंने मदी से लडने के समय प्राप्त कर पायी है ।¹

(3) बैंको के नकद कोष अनुपात में परिवर्तन (Variation in Cash Reserve Ratios of Banks)

आजकल ससार के सभी देशो मे व्यापारिक बैंको को अपने दायित्वो का कुछ प्रतिशत केन्द्रीय बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा कराना पडता है । हम अध्ययन कर चुके हैं कि बैंको द्वारा साख निर्माण का आधार उनके नकद कोष हैं । साख नियत्रण की इस रीति द्वारा केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंको द्वारा रखे जाने वाले कोष की मात्रा को घटा-बढाकर उनके द्वारा सृजित साख की मात्रा को प्रभावित करते हैं । यदि व्यापारिक बैंक आवश्यकता से अधिक साख का सृजन कर रहे हैं तो केन्द्रीय बैंक उनके द्वारा रखे जाने वाले कोषो का प्रतिशत बढा देता है फलतः उनके नकद कोष घट जाते हैं और उनके द्वारा साख-निर्माण उसी अनुपात मे कम हो जायेगा । इसके विपरीत जब देश मे आवश्यकता से कम साख का निर्माण हो रहा है तो बैंको द्वारा रखे जाने वाले नकद कोषो का अनुपात घटा दिया जाता है और बैंको द्वारा साख का निर्माण उसी अनुपात मे बढ जाता है । इस प्रकार केन्द्रीय बैंक इस रीति द्वारा साख का सकुचन तथा विस्तार करता है ।

साख-नियत्रण की इस रीति का उपयोग सर्वप्रथम सन् 1933 मे अमेरिका में किया गया । बाद मे न्यूजीलैंड, कनाडा, नार्वे आदि देशो मे इसका प्रयोग हुआ । भारत मे भी रिजर्व बैंक को यह अधिकार प्राप्त है । महा अनुसूचित बैंको को अपने कुल निलेपो का तीन प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पडता है ।

साख नियत्रण की यह पद्धति केन्द्रीय बैंको के हाथो में एक बडा ही महत्वपूर्ण तथा प्रभावो अस्त्र है । यह रीति बडी सरल तथा सुविधाजनक है और बैंको के नकद कोषो पर सीधेतापूर्वक प्रभाव डालकर साख के निर्माण को नियमित करती है । बर्गस (Burgess) के शब्दो मे

“Despite these limitations the power (to raise or lower the bank's cash reserve requirements) is the most useful addition to the system's mechanism for credit control, especially as a means for dealing fundamentally with the large excess of reserves created by the extraordinary events of depression emergency.”

1. “The Reserve Banks can fire off against an incipient boom only such ammunition as they have been able to pick up while resisting a slump.”
—J. M. Keynes

सेयर्स (R. S. Sayers) ने भी इस पद्धति का समर्थन इन शब्दों में किया है :

“It is a weapon which should always be placed in the hands of a central bank whose technique is circumscribed by the conditions hindering the effective utilisation of open market operations. Given such power, the central bank can perform useful functions that commercial banks cannot be expected to perform”

खुले बाजार की क्रियाओं के सम्बन्ध में वर्णित सीमायें इस नीति पर भी लागू होती हैं फिर भी ऐसे देशों के लिए विशेषकर विकासशील देशों के लिए यह रीति बड़ी उपयुक्त है क्योंकि बड़ा सुसंगठित तथा विकसित मुद्रा तथा प्रतिभूति बाजारों का अभाव है ।

(4) तरल कोषानुपात (Liquidity Ratios)

साख नियंत्रण की इस रीति का प्रयोग सर्वप्रथम सन् 1945 में अमेरिका में हुआ जब Federal Reserve System की रिपोर्ट में इसको उठाया गया । इस रीति के अन्तर्गत बैंकिंग कानून के अनुसार व्यापारिक बैंकों को केन्द्रीय बैंक में जमा किए गये नकद कोषों के अतिरिक्त कुछ गौण-कोषों (Secondary Reserves) का रखना भी अनिवार्य होता है । इस प्रकार बैंकों को अपनी कुल सम्पत्ति का कुछ भाग तरल रूप (Liquid Form) में रखना अनिवार्य कर दिया जाता है जिससे उनकी साख-सृजन की शक्ति सीमित हो जाती है । तरल कोषों में नकद राशि तथा स्वीकृत प्रतिभूतियाँ (Approved Securities) रखी जाती हैं ।

इस पद्धति का प्रयोग विभिन्न देशों में स्फीति जनित साख विस्तार को नियंत्रित करने के लिए किया गया था । कुछ देशों में इसे स्फीति-नियंत्रक उपाय (Anti-inflationary Measure) के रूप में प्रयुक्त किया गया और केन्द्रीय बैंक की बैंक-दर नीति को प्रभावी बनाने में इसने पर्याप्त सहायता की । डा० डी० काक ने इस रीति के सम्बन्ध में लिखा है—

“There is no doubt, however, that this new method can be made to play a valuable part in any positive deflationary policy under conditions of exceptional inflationary pressures caused by war, rearmament or other abnormal circumstances,”¹

¹. M. H. De Kock : *Central Banking* p 241.

(5) साख की राशनिंग (Rationing of Credit)

साख की राशनिंग साख नियन्त्रण की गुणात्मक रीतियों में महत्वपूर्ण है। केन्द्रीय बैंक अन्तिम ऋणदाता का कार्य करता है और आवश्यकता पड़ने पर सभी सदस्य बैंकों को धन की सहायता देता है। इस रीति के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक सदस्य बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर कुछ प्रतिबन्ध लगा देता है जिससे उनकी साख सृजन की शक्ति कुछ कम हो जाती है। अधिकतर मुद्रा स्फूर्ति के समय सदस्य बैंकों द्वारा अत्यधिक साख-सृजन की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक या तो किसी बैंक की विलो के पुनः बट्टा कराने की सुविधा समाप्त कर देता है या किसी बैंक की पुनः बट्टा कराने की सीमा को नियन्त्रित कर देता है या विभिन्न बैंकों के लिए साव का कोटा निश्चित कर देता है।

साख नियन्त्रण की इस पद्धति का प्रयोग बैंक आफ इंग्लैंड ने 18वीं शताब्दी के अन्त में किया। इसके अन्तर्गत बैंक आफ इंग्लैंड "placed a limit upon its discounts for any one house or rejected a proportion of each discount application whenever total demands exceeded the sum which it was prepared to discount on any one day"

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् किसी न किसी रूप में इस पद्धति का प्रयोग किया गया। जर्मनी, फ्रांस तथा मैक्सिको में इस पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। रूस की साख नीति का यह पद्धति आवश्यक अंग है। साख-नियन्त्रण के साधन के रूप में साख के राशनिंग की रीति ऐसे देशों के लिये अधिक उपयुक्त है जहाँ राज्य के नियन्त्रण के अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजन (Centralised Planning) होता है। इसीलिए डा० डी० काक ने कहा कि "Rationing of credit and capital is a logical concomitant of the intensive and extensive planning adopted by authoritarian states"

(6) प्रतिभूति ऋणों की सीमा आवश्यकताओं में परिवर्तन (Changes in Margin Requirements on Security Loans)

साख नियन्त्रण की इस पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका में (Securities Exchange Act of 1934) के अन्तर्गत फेडरल रिजर्व सिस्टम द्वारा किया गया। इस रीति का मुख्य उद्देश्य प्रतिभूतियों में सट्टे की प्रवृत्ति को नियन्त्रित करना होता है। इस रीति के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋणों की सीमा (Margin Requirements) के सम्बन्ध में परिवर्तन करने के आदेश देता है जिससे

दिये गये ऋणों में बैंकों को अधिक जोखिम न रहे। ऋणों की सीमा परिवर्तन के फेडरल रिजर्व बोर्ड के अधिकार के सम्बन्ध में बर्गस (Burgess) का कथन है :

“It is a form of control which is in some degree paternalistic and restrictive, but speculation in securities has proved itself so destructive of economic stability in this country that some vigorous form of control of this sort appeared to be necessary.”

श्री गोल्डेन वीजर (Golden Weiser) के शब्दों में :

“Margin requirements have served a useful public purpose and some light has been thrown upon their possibilities and their limitations as an instrument of policy,”

(7) उपभोक्ता साख का नियमन (Regulation of Consumers Credit)

द्वितीय महायुद्ध काल में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली साख का नियन्त्रण हेतु इस साधन का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका में किया गया। युद्ध काल में उपभोक्ताओं द्वारा प्रयुक्त टिकाऊ वस्तुएँ जैसे मोटर कार, मोटर साइकिल, रेफ्रिजरेटर, सिलाई मशीन, रेडियो इत्यादि की माग बढ़ जाती है और कृषिों द्वारा भुगतान अदायगी की सुविधा के कारण उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। अमेरिका में 9 अगस्त 1942 के एक आदेश द्वारा बोर्ड आफ गवर्नर्स को यह अधिकार दिया गया कि वे उपयोग्य वस्तुओं के क्रय के लिए दिए जाने वाले ऋणों की शर्तों का नियमन करे। अमेरिका में यद्यपि प्रारम्भ में इसे एक 'सुरक्षा उपाय' (Defence Measure) के रूप में प्रयुक्त किया गया परन्तु इसे युद्ध के पश्चात् भी जारी रखा गया और गुणात्मक साख नियन्त्रण का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया। इस साधन का प्रयोग कनाडा, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा बेल्जियम इत्यादि देशों में भी किया गया।

(8) प्रत्यक्ष कार्यवाही (Direct Action)

प्रत्यक्ष कार्यवाही के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्धारित नीतियों तथा निर्देशों का पालन न करने वाले व्यापारिक बैंकों के विरुद्ध केन्द्रीय बैंक कार्यवाही कर सकता है। केन्द्रीय बैंक ऐसे व्यापारिक बैंकों को पुनः बट्टा की सुविधायें प्रदान करने से मना कर सकता है और यदि कोई बैंक अपने कोषों से अधिक अनुपात में पुनः बट्टा सुविधा प्राप्त कर चुका हो तो उसे पुनः बट्टा की और सुविधा देने से मना कर सकता है और यदि दे भी तो निर्धारित दर से ऊँची दर (Penalty Rate) ले सकता है। डा० डी० कोक (Dr. De Kock) के शब्दों में :

“Direct action embraces only those cases where the central bank decides to take such coercive measures against an offending commercial or other financial institution as it can within the limits of its power and functions, or to issue directives to banks generally concerning their lending and investment operations under special statutory authority

साख नियंत्रण तथा अन्य प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था के नियमन के इतने विस्तृत अधिकार विभिन्न केन्द्रीय बैंको को अब प्राप्त हैं कि इस साधन के प्रयोग का प्रवर्ण ही नहीं आता। बैसे इस रीति का बैंको पर बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता और भविष्य में उनका सहयोग प्राप्त करन में कठिनाई आ सकती है। अतः इस रीति की उपयुक्तता तथा सफलता में सदेह व्यक्त किया जाता है।

(9) नैतिक दबाव (Moral Suasion)

आज के प्रजातन्त्रीय युग में नैतिक दबाव भी गुणात्मक साख नियंत्रण की एक मुख्य रीति है। इस रीति के अन्तर्गत देश के बैंको पर केन्द्रीय बैंक अपनी शीर्षस्थ तथा नेता की स्थिति का प्रयोग कर उनको समझा बुझा कर ठीक मार्ग पर लाता है। सीधी कार्यवाही तथा नैतिक दबाव में अन्तर केवल इतना है कि नैतिक दबाव में किसी प्रकार का वैधानिक जोर (Legal Compulsion) या दण्डनीय कार्यवाही (Punitive Action) की धमकी नहीं होती। यदि कोई जोर या दबाव डाला भी जाता है तो वह मित्रतापूर्ण चेतावनी या परामर्श होता है। नैतिक दबाव का यह लाभ है कि इसका कोई बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव बैंको पर नहीं पड़ता। बर्गस (Burgess) के अनुसार .

“The informal influence which they (central banks) exercise in this way, may at times prove more important than their formal action under law. It is an influence to be exercised with the utmost discretion, and would vanish with excessive use”

नैतिक दबाव की इस रीति का प्रयोग इंग्लैंड, फ्रान्स, स्वीडन तथा हॉलैंड इत्यादि देशों में बड़ी सफलता पूर्वक किया गया है परन्तु अमेरिका जैसे देशों में जहाँ इकाई बैंकिंग प्रणाली प्रचलन में है, यह पद्धति सफल नहीं रही है। साख नियंत्रण की इस रीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि देश में केन्द्रीय बैंक की क्या स्थिति तथा शक्ति है तथा केन्द्रीय बैंक तथा अन्य बैंको में सहयोग की क्या सीमा है।

(10) प्रचार

(Publicity)

केन्द्रीय बैंक द्वारा साख नियन्त्रण के साधन के रूप में प्रचार (Publicity) का प्रयोग किया जाता है। इस रीति के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक प्रचार तथा विज्ञापन द्वारा जनमत (Public Opinion) अपनी नीतियों के पक्ष में करता है और ऐसा वातावरण पैदा करता है जिससे बैंक वही नीति अपनायें जो केन्द्रीय बैंक चाहता हो। इसके साथ साथ केन्द्रीय बैंक अपनी आर्थिक स्थिति, क्रिया कलापों तथा देश तथा अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न पक्षों जैसे मुद्रा बाजार, उद्योग, व्यापार, आयात निर्यात, विदेशी विनिमय, सार्वजनिक ऋण इत्यादि के सम्बन्ध में आकड़े तथा सूचनायें प्रकाशित करता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक के अधिकारी पत्रकार-सम्मेलनों, गोष्ठियों तथा अन्य सार्वजनिक अवसरों पर बैंक की नीति का स्पष्टीकरण तथा मावी नीति की दिशा के बारे में ज्ञान कराते रहते हैं।

यद्यपि साख नियन्त्रण के इस साधन का प्रयोग बहुत से देशों में हुआ है परन्तु इसका सर्वाधिक प्रयोग अमेरिका में हुआ है जहाँ प्रत्येक रिजर्व बैंक अपनी स्थिति के विवरण के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण (Reviews) तथा प्रकाशन निकालता है। जर्मनी के रीश बैंक ने भी इस साधन का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया है तथा स्वीडन के रिक्स बैंक ने भी इस रीति को उपयोग में लिया है। भारत में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया भी मासिक बुलेटिन के अतिरिक्त विभिन्न प्रकाशन निकालता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

ऊपर हमने केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रयुक्त साख नियन्त्रण की विभिन्न रीतियों, उनकी सप्रभाविकता तथा उनकी परिसीमाओं का विस्तार से विवेचन किया है। यह कहना बड़ा कठिन है कि उनमें से कौन सी रीति अधिक उपयुक्त है। परिस्थितियों के अनुसार केन्द्रीय बैंक किसी एक या कई का साथ साथ प्रयोग करता है। यह सत्य है कि केन्द्रीय बैंक की सक्रियता की तुलना में स्फीति नियंत्रित करने की शक्ति अधिक है और इन प्रवृत्तियों को उनकी प्रारम्भिक अवस्था में ही नियंत्रित किया जा सकता है। साख नियन्त्रण की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उनके पास पर्याप्त अधिकार हों और वे उनका उपयुक्त समय पर तीव्रता से प्रयोग करें।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके सकेत

(1) बैंक दर के महत्व की व्याख्या कीजिए। यह उत्पादन तथा मूल्यों के सामान्य स्तर को, व्यावसायिक क्रिया-कलाप और नियोजन को किस प्रकार प्रभावित करती है ?

[संकेत—प्रथम भाग में साख-नियन्त्रण के साधन के रूप में बैंक-दर नीति की परिभाषा बताते हुए उसके महत्व की व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में बैंक दर परिवर्तन के प्रभावों का विस्तारपूर्वक विश्लेषण कीजिए। सक्षेप में हार्डि-कीन्स विवाद का भी उल्लेख कीजिए।]

(2) उन मुख्य उपायों का विवेचन कीजिए जिनके द्वारा आधुनिक केन्द्रीय बैंक किसी समाज में साख के परिमाण को नियमित करता है।

(राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल, 1966)

अथवा

साख-नियन्त्रण के विभिन्न उपायों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

(राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल, 1968)

अथवा

राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंक किस प्रकार साख का नियन्त्रण करता है? साख नियन्त्रण की उसकी शक्ति की सीमाएँ बताइये।

(आगरा 1968)

[संकेत—केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रयुक्त साख नियन्त्रण की विभिन्न परिमाणपरक तथा गुणात्मक विधियों का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। तृतीय प्रश्न के उत्तर में साख-नियन्त्रण की विधियों के अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक की साख-नियन्त्रण की शक्ति की सीमाएँ भी बताइये।]

(3) केन्द्रीय बैंक के क्या कार्य हैं? केन्द्रीय बैंक दूसरे व्यापारिक बैंकों को फेल होने से किस प्रकार बचाता है?

(सागर बी० ए०, 1959)

[संकेत—प्रथम भाग में केन्द्रीय बैंक के विभिन्न कार्यों का (साख-नियन्त्रण तथा नियमन के सहित) वर्णन कीजिए। दूसरे भाग में यह बतलाइये कि बैंक व्यवस्था का शीर्ष होने के नाते उसकी सुदृढता तथा विकास का उत्तरदायित्व केन्द्रीय बैंक पर रहता है अतः वह सकट काल के अतिम ऋणदाता का कार्य करता है जिससे बैंक फेल न हों।]

(4) केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए और बतलाइये कि यह साख का नियन्त्रण—(क) खुले बाजार की क्रियाओं तथा (ख) बैंक दर के द्वारा किस प्रकार करता है?

(आगरा बी० ए०, 1959)

(जबलपुर बी० ए० 1958)

[संकेत—प्रथम भाग में साख-नियन्त्रण के कार्य सहित केन्द्रीय बैंक के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। द्वितीय भाग में साख नियन्त्रण की दो परिमाणपरक रीतियों—बैंक दर तथा खुले बाजार की क्रियाओं—की विस्तार से व्याख्या कीजिए। उत्तर का प्रथम भाग बहुत संक्षिप्त हो नहीं तो उत्तर बहुत लम्बा हो जायेगा।]

भाग ३

Part Three

“A doctor may be a better gardener whom he employs, but he may be a still better doctor and he would lose, if he did not restrict himself to the highest type of work which he could do. His advantage over the gardener is the greatest not when he is acting as a gardener, but when he exercises his function as a doctor. So a country may be able to produce every thing better than every other country, but it will pay it best to concentrate on those articles at which its comparative advantage is greatest whilst the inferior country must restrict itself to those products at which its comparative disadvantage is least.”

Bastable

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा
विदेशी विनिमय
(International Trade and
Foreign Exchange)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade)

"The benefit of international trade—a more efficient employment of the productive forces of the world"

J. S. Mill

विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के क्रय-विक्रय को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सजा दी जाती है। वास्तव में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में मौलिक रूप से कोई विशेष अन्तर नहीं है। ओह्लिन के विचार इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं। उनके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अन्तर्देशीय व्यापार की एक विशेष अवस्था है। (International trade is only a special case of inter regional trade between different parts of one country.) दोनों प्रकार के व्यापारों का आधार विनिमय द्वारा आवश्यक एक अतिरिक्त वस्तु के बदले आवश्यक एवं अपेक्षाकृत दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त करना है जिससे अधिकतम सतुष्टि प्राप्त की जा सकें। जिस प्रकार विनिमय द्वारा दो व्यक्तियों को लाभ होता है वैसे ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा दो राष्ट्रों को लाभ होता है। परन्तु इन समानताओं के होते हुए भी आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ ऐसे अन्तर पाए जाते हैं जिनके कारण अर्थशास्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में अलग-अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है।

आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अन्तर (Difference between Internal and International Trade)

आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में निम्नलिखित प्रमुख अन्तर हैं—

1. उत्पादन के साधनों की गतिशीलता (Factors mobility) उत्पादन के साधनों की गतिशीलता आन्तरिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसके फलस्वरूप उत्पादन के साधनों के पारिश्रमिक में एक देश में सभी क्षेत्रों में काफी हद तक समानता होती है। एक देश से पूँजी तथा श्रम का दूसरे देश में जाना-भ्राना कम होने के कई कारण हैं जो सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा भाषा सम्बन्धी कठिनाइयों से उत्पन्न होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गतिशीलता कम होने के कारण विभिन्न

देशों में उत्पादन के साधनों के पारिश्रमिक में बहुत अन्तर पाया जाता है। उत्पादन के विभिन्न साधनों में भी श्रम सर्वाधिक गतिहीन है। एडमस्मिथ के शब्दों में "Man is, of all forms of luggage, the most difficult to transport." इसलिए मजदूरी में ब्याज-दर एवं लगान की अपेक्षा अधिक अन्तर पाया जाता है।

2. सरकारी प्रतिबन्ध (Govt. Restrictions) : एक देश से दूसरे देश में माल भेजने अथवा मगाने की प्रायः पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं होती है। कभी-कभी तो सरकारें विदेशी आयात तथा निर्यात पूर्णरूप से बन्द कर देती हैं। प्रत्येक देश अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी आर्थिक नीति निर्धारित करता है; इसलिए उनमें अन्तर पाया जाना स्वाभाविक है। परन्तु आंतरिक क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल भेजने व मगाने की प्रायः स्वतन्त्रता होती है। इस प्रकार आंतरिक क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान में स्वतन्त्रता रहती है; परन्तु लाइसेन्स, क्वांटा, टैरिफ आदि के कारण अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन में स्वतन्त्रता नहीं होती।

3. परिवहन की समस्या (Transportation Problem) : आंतरिक व्यापार में परिवहन की समस्या सरलता से हल हो जाती है, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवहन की समस्या शीघ्रता से हल नहीं हो पाती। उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त जोखिम भी अधिक होता है। कई देशों के बीच परिवहन के साधनों का समुचित विकास भी नहीं हुआ है। जहा विचार हुआ भी है वहा राजनैतिक तनाव की स्थिति में मार्ग कभी-कभी अवरोध हो जाते हैं। स्वेज नहर की बन्दी इसका उबलत प्रमाण है।

4. मौद्रिक भिन्नता (Monetary Differences) : आंतरिक व्यापार में क्रेता एवं विक्रेता एक ही मुद्रा का भुगतान के माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं इसलिए सौदों में कोई कठिनाई नहीं होती। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में दोनों देशों में अलग-अलग प्रामाणिक मुद्राओं का प्रयोग होता है जिसके फलस्वरूप विनिमय-दर की समस्या पैदा होती है। यही नहीं, विभिन्न देशों की मौद्रिक सत्थाओं, बैंक व्यवस्था तथा मौद्रिक अधिकारियों एवं उनके द्वारा प्रयुक्त साख, रोजगार एवं कीमत सम्बन्धी नीतियों में भिन्नता पाई जाती है। मुद्राओं के नाम में समानता होने पर भी उसका अलग-अलग देश में अलग-अलग मूल्य होता है। इस प्रकार विनिमय दर ज्ञात करने की कठिनाई एवं विनिमय-नियंत्रण की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की एक विशेष समस्या के रूप में सामने आती है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा काष के प्रयत्न भी इस समस्या को पूर्ण रूप से हल करने में अभी तक असमर्थ रहे हैं।

5. अन्य भिन्नताएँ (Other Differences) : उपरोक्त भिन्नताओं के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आंतरिक व्यापार से इसलिए भी भिन्न है क्योंकि

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को अनेक भाषाओं, अनेक सरकारों तथा उनके नियमों एवं कानूनों तथा विभिन्न व्यापारिक रीति रिवाजों तथा परम्पराओं का सामना करना पड़ता है। आंतरिक व्यापार में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होती।

ऊपर लिखे गए विवरण से यह स्पष्ट है कि उत्पादन के साधनों की गतिशीलता में अन्तर होने के कारण किसी भी वस्तु विशेष की उत्पादन-लागत प्रत्येक देश में समान नहीं होती है। प्रत्येक देश तुलनात्मक रूप से अन्य देशों की अपेक्षा कुछ वस्तुओं अपेक्षाकृत कम लागत में उत्पन्न करता है और कुछ वस्तुओं अपेक्षाकृत अधिक लागत में। इसलिए उत्पादन में विशिष्टीकरण प्रधान हो जाना है। दीर्घकाल में उत्पादन-व्यय में समानता की प्रवृत्ति होने के बावजूद भी कई वस्तुओं के मूल्यों में अन्तर पाया जाता है। उत्पादन व्यय एवं मूल्यों में अन्तर बनाए रखने में सरकारी नियमों, मुद्रा प्रणाली तथा भौगोलिक दशाओं में विद्यमान अन्तर भी महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याएँ आंतरिक व्यापार की समस्याओं से पूर्णरूपेण भिन्न होती हैं जिनका विश्लेषण पृथक सिद्धांतों द्वारा ही सम्भव है। परन्तु इस विचारधारा से सभी आधुनिक अर्थशास्त्री सहमत नहीं हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में प्रो ओहलिन का नाम सर्वविदित है और उनकी यह मान्यता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अपनी विशिष्ट समस्याओं के कारण 'पृथक अध्ययन' के द्वारा आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। ऐसा करना लाभप्रद एवं सुविधाजनक है परन्तु इसके अध्ययन के लिए 'पृथक सिद्धान्त' की कोई आवश्यकता नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता

(Need for International Trade)

1 दोनों पक्षों को लाभ (Profitable to both the Parties) विभिन्न देशों की उत्पादन दशाओं (Conditions of Production) में अन्तर (Diversity) होने के कारण एक वस्तु का उत्पादन-व्यय अथवा मूल्य विभिन्न देशों में असमान होता है। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों को लाभ होता है। प्रत्येक देश का प्रकृतिप्रदत्त प्रसाधन, मानवीय श्रम तथा तकनीकी ज्ञान अपनी अलग विशेषताएँ रखते हैं। इसलिए प्रत्येक देश की उत्पादन-सम्भावनाएँ (Production possibilities) भी भिन्न होती हैं। यदि कोई देश सभी वस्तुओं का उत्पादन करने का प्रयत्न करे तो उस या तो असफलता प्राप्त होगी या सफलता बड़ी महंगी पड़ेगी। यदि दो देशों में एवही वस्तुएँ बनाया सम्भव भी हो तो भी उनके लिए कितनी एक वस्तु या कुछ वस्तुओं में विशिष्टीकरण करना तथा विनिमय द्वारा दूसरी वस्तुएँ प्राप्त करना अधिक लाभप्रद होता है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व में विशिष्टीकरण एवं व्यापार के आधार पर कुल उत्पादन में वृद्धि करता है। उत्पादन में वृद्धि होने से सभी देशों का उपभोग स्तर भी ऊँचा उठता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उम्र अवस्था में भी दोनों पक्षों के लिए लाभदायक है जब एक देश प्रायः सभी वस्तुओं दूसरे देश की अपेक्षा कम लागत पर उत्पादित करने की स्थिति में होता है। जबतक दो देशों में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन की तुलनात्मक क्षमता (Relative efficiency of producing different goods) भिन्न होगी तब तक दोनों देशों की तुलनात्मक रूप से अधिक क्षमता वाले क्षेत्र में उत्पादन करना तुलनात्मक रूप से लाभप्रद होगा। इसलिए प्रत्येक देश तुलनात्मक रूप से अधिक लाभप्रद क्षेत्र में उत्पादन करने में विशिष्टीकरण करता है।

उपरोक्त विवरण इस बात को स्पष्ट करता है कि उत्पादन व्यय का अंतर-चाहे वह निरपेक्ष अंतर हो अथवा तुलनात्मक अंतर हो, (Absolute Differences or Relative Differences) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को आवश्यक बना देता है। इससे दोनों ही पक्ष लाभान्वित होते हैं।

2 अन्य कारण (Other Causes)

(i) लागत ह्रास (Decreasing Cost) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विशिष्टीकरण अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है और बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण पैमाने की मितव्ययिता (Economies of Scale) प्राप्त होती हैं। इसलिए उत्पादन लागत कम हो जाती है तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है।

(ii) माग या पसंदगी का अंतर (Differences in Tastes or Demand) दो देशों में उत्पादन लागत में अंतर न होने पर भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सम्भावना समाप्त नहीं होती क्योंकि सम्बन्धित देशों की माग या पसंदगी में अंतर होता है। जैसे यदि 'क' तथा 'ख' देशों में गेहूँ और चावल समान लागत और माग में उत्पादित किए जाते हों परन्तु 'क' देश में गेहूँ की अधिक माग हो और 'ख' देश में चावल की अधिक माग हो तो दोनों के बीच व्यापार करना लाभदायक होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत (Theories of International Trade)

तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त (Theory of Comparative Cost)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत के सिद्धांत की सम्यक व्याख्या में डेविड रिकार्डो (David Ricardo) ने बड़े ही सुंदर ढंग से यह स्पष्ट किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण (International Specialisation) किसी भी देश के लिए लाभप्रद होता है। बाद में इस सिद्धांत की नवीन व्याख्या फ्रांक डब्लू टासिग (F W Taussig) द्वारा प्रस्तुत की गई है।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई तुलनात्मक-लागत-सिद्धांत की व्याख्या के अन्तर्गत निम्नलिखित दो प्रमुख प्रश्नों पर विचार किया गया है—

1. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या कारण हैं ?
2. आयात-निर्यात की शर्तों (Terms of trade) को कौन-सी शक्तियाँ निर्धारित करती हैं ?

प्रथम प्रश्न के सम्बन्ध में इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होने का प्रमुख कारण यह है कि प्रत्येक देश उन वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनका उत्पादन अन्य देश की तुलना में अधिक सुविधाजनक है तथा जिनके लिए उसके पास प्रचुर मात्रा में प्रसाधन और तकनीकी जाकारी उपलब्ध है, एवं इन वस्तुओं का निर्यात करके उन वस्तुओं को प्राप्त करता है जिनके उत्पादन के लिए प्रसाधन अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपलब्ध है। इस प्रकार विशिष्टीकरण एवं व्यापार का लाभ प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता पड़ती है।

इस सिद्धांत के अनुसार सभी देश यदि उस वस्तु का उत्पादन करें जिसके लिए वे सर्वथा उपयुक्त परिस्थिति में हैं तो सभी व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से अपनी वास्तविक आय में वृद्धि कर सकते हैं। वास्तव में प्रत्येक देश बचा पैदा करेगा यह उस वस्तु की वास्तविक उत्पादन लागत पर निर्भर करता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लागता में निरपेक्ष अंतर रहने पर तथा लागतों में सापेक्ष अंतर रहने पर—दोनों ही दशाओं में लाभप्रद है

1. लागत में निरपेक्ष अंतर (Absolute Differences in Costs)

जब किसी देश की जलवायु एवं प्रकृतिप्रदत्त साधन किसी वस्तु विशेष के उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं तो अन्य देशों की अपेक्षा उत्पादन-लागत कम होती है और वह इस निरपेक्ष अंतर का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से विशिष्टीकरण करता है एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा अन्य आवश्यक वस्तुएँ आयात करता है। निम्नलिखित उदाहरण द्वारा यह बात अधिक स्पष्ट होती है

उत्पादित वस्तुएँ		देश	धर्म की इकाई के रूप में लागत
चावल	कपड़ा		
2 इकाई	या 3 इकाई	भारत	धर्म की 1 इकाई
3 इकाई	या 2 इकाई	नेपाल	धर्म की 1 इकाई

इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि भारत को कपड़े के उत्पादन में तथा नेपाल को चावल के उत्पादन में विशिष्टीकरण करने से लाभ होगा। यदि दोनों

वस्तुओं का उत्पादन करें तो दो इकाई धम लगाने से दोनों देशों का कुल उत्पादन इस प्रकार होगा -

भारत—	2 इकाई चावल + 3 इकाई कपडा
नेपाल—	3 इकाई चावल + 2 इकाई कपडा
योग	5 इकाई चावल + 5 इकाई कपडा

परन्तु यदि भारत कपडे के उत्पादन में तथा नेपाल चावल के उत्पादन में अपने धम की दोनों इकाइयों का प्रयोग करे तो स्थिति इस प्रकार होगी .

भारत—	6 इकाई कपडा	सामूहिक उत्पादन	
नेपाल—	6 इकाई चावल		6 इकाई कपडा

अब यदि भारत तथा नेपाल अपने अतिरिक्त कपडे तथा चावल का विनिमय करें तो भारत 3 इकाई कपडे के बदले नेपाल से कम से कम 3 इकाई चावल प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से वह 1 इकाई चावल का लाभ प्राप्त करेगा, क्योंकि यदि स्वयं पैदा करता तो उसे केवल 2 इकाई चावल प्राप्त होता। ठीक इसी प्रकार नेपाल को अपनी 3 इकाई चावल के बदले कम से कम 3 इकाई कपडा प्राप्त हो सकता है और उसे 1 इकाई कपडे का लाभ होगा। दोनों देशों को सामूहिक रूप से देखा जाय तो कुल उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। इस प्रकार लागतों में निरपेक्ष अंतर होने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक हो जाता है और यही सबके लिए श्रेयस्कर है।

2 लागत में सापेक्ष अंतर (Comparative Differences in Costs)

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल लागतों में निरपेक्ष अंतर होने की स्थिति में ही नहीं होता बल्कि उस समय भी होता है जब लागतों में सापेक्ष अंतर होता है। उदाहरणार्थ यदि अमेरिका भारत की तुलना में 'क' तथा 'ख' दोनों ही वस्तुएँ सस्ती पैदा करता हो परन्तु 'क' के उत्पादन में अमेरिका की दक्षता भारत से केवल 20% अधिक हो तथा 'ख' के उत्पादन में अमेरिका की दक्षता भारत से 30% अधिक हो तो ऐसी स्थिति में अमेरिका 'ख' के उत्पादन में विशिष्टीकरण करके लाभ प्राप्त कर सकता है और भारत 'क' के उत्पादन में विशिष्टीकरण करके अपने हानि (Disadvantage) को कम कर सकता है। इस प्रकार तुलनात्मक लाभ (Comparative Advantage) दो देशों के उत्पादकता-अनुपात (Productivity Ratio) पर निर्भर करता है। निम्नलिखित उदाहरण द्वारा यह बात और स्पष्ट हो जाती है

उत्पादित वस्तु	अमेरिका	ब्रिटेन
1 इकाई खाद्य पदार्थ	1 इकाई धम	3 इकाई धम
1 इकाई कपडा	2 इकाई धम	4 इकाई धम

उपरोक्त उदाहरण के अनुसार अमेरिका खाद्य पदार्थ तथा कपड़ा दोनों ही ब्रिटेन की अपेक्षा अधिक दक्षता से उत्पादित करता है, परन्तु अमेरिका को खाद्य पदार्थ के उत्पादन से तुलनात्मक लाभ अधिक है तथा ब्रिटेन को कपड़े के उत्पादन से तुलनात्मक हानि कम है, क्योंकि अमेरिका में खाद्य पदार्थ तथा कपड़े का लागत अनुपात 1 : 2 (कपड़े की एक इकाई की लागत बराबर है खाद्य पदार्थ की 2 इकाई की लागत के) तथा ब्रिटेन में खाद्य पदार्थ तथा कपड़े का लागत अनुपात 3 : 4 है। अमेरिका दोनों वस्तुओं के उत्पादन में अधिक दक्षता रखता है परन्तु उसकी दक्षता खाद्य पदार्थों के उत्पादन में अपेक्षाकृत अधिक है इसलिए वह खाद्य पदार्थों में विनिष्ठीकरण करके लाभान्वित होगा। दूसरी तरफ ब्रिटेन दोनों में कम दक्ष है परन्तु दक्षता की कमी कपड़े के उत्पादन में अपेक्षाकृत कम है और खाद्य पदार्थों के उत्पादन में दक्षता की कमी अपेक्षाकृत अधिक है। इसलिए इसे कपड़ों का उत्पादन करना लाभप्रद है। यद्यपि यह कुछ विचित्र सा प्रतीत होता है कि एक देश जिस वस्तु को दूसरे की अपेक्षा सस्ता बना सकता है उसे भी वह दूसरे देश से मगाता है, परन्तु यह इसलिए सम्भव होता है क्योंकि उसे ऐसा करने में तुलनात्मक लाभ अधिक है। एक लेक्चरर अपने नौकर की अपेक्षा शीतल से एब अच्छी पालिश कर सकता है और भाषण तो अच्छा देगा ही फिर भी वह नौकर से पालिश करा कर तुलनात्मक लाभ अधिक प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अजनबी देर वह पालिश करने में लगाएगा उतना ही समय भाषण में लगाकर अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। क्योंकि नौकर उससे दोनों में कम कुशल है पर वह पालिश करने में कम कमकुशल (Less lessefficient) है। केपरनेस के शब्दों में 'The difference in the comparative cost of producing the commodities exchanged is essential to, and sufficient for, the existence of international trade'

3. लागत में समान अन्तर (Equal Differences in Costs) .

तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त यह स्पष्ट कर देता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तभी सम्भव होता है जब लागतों में निरपेक्ष या सापेक्ष अन्तर पाया जाता है। यदि लागतों में समान अन्तर हो तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से किसी भी पक्ष को लाभ नहीं होता है। इसलिए समान अन्तर होने की दशा में या तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारम्भ ही नहीं होता या प्रारम्भ होकर शीघ्र समाप्त हो जाता है। निम्नलिखित उदाहरण द्वारा यह बात स्पष्ट हो जाती है।

	चावल	कपड़ा	श्रम की इकाइया (लागत)
भारत	4 इकाई	या 2 इकाई	1 इकाई
नेपाल	2 इकाई	या 1 इकाई	1 इकाई

इस उदाहरण के अनुसार भारत में 1 इकाई कपड़ा = 2 इकाई चावल है तथा नेपाल में भी लागत अनुपात वही है। 1 इकाई कपड़ा = 2 इकाई चावल

ऐसी परिस्थिति में यदि भारत चावल के उत्पादन में ही अपने धर्म की दोनों इकाइयाँ लगा दे तो 8 इकाई चावल पैदा करेगा परन्तु नेपाल से 2 इकाई कपडा प्राप्त करने के लिए उसे अपनी 4 इकाई चावल का निर्यात करना पड़ेगा और वस्तु स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए दोनों में व्यापार का प्रश्न नहीं पैदा होता है।

आयात-निर्यात शर्तों का निर्धारण (Determination of Terms of Trade):

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत इस बात की भी व्याख्या करता है कि निरपेक्ष या सापेक्ष लागत-अन्तर होने पर दो देशों के बीच व्यापार की शर्तें किस प्रकार निर्धारित होती हैं। इस प्रश्न पर विचार करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जिन वस्तुओं को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से कोई देश प्राप्त करता है वह उन्हें स्वयं भी पैदा कर सकता है, इसलिए उन वस्तुओं का आंतरिक विनिमय अनुपात विद्यमान होता है। इन आंतरिक विनिमय अनुपातों के अनुसार ही अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय अनुपात की अधिकतम तथा न्यूनतम दरें निर्धारित होती हैं तथा वास्तविक विनिमय अनुपात सम्बन्धित देशों की एक दूसरे देश की वस्तु की माग की तीव्रता एवं मूल्य सापेक्षता द्वारा निर्धारित होता है। निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा इसे आसानी से समझा जा सकता है।

निरपेक्ष अन्तर होने पर (Absolute Differences) : यदि भारत में 2 इकाई चावल का मूल्य 3 इकाई कपडा के बराबर हो तथा नेपाल में 2 इकाई चावल का मूल्य 1 33 इकाई कपडा के बराबर हो तो भारत और नेपाल में आंतरिक विनिमय अनुपात क्रमशः 1 इकाई चावल = 1 5 इकाई कपडा तथा 1 इकाई चावल = 0 67 इकाई कपडा होगा। भारत एक इकाई चावल प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक 1 5 इकाई कपडा नेपाल को दे सकता है और नेपाल 1 इकाई चावल के बदले कम से कम 0 67 इकाई कपडा लेना चाहेगा। वास्तविक विनिमय अनुपात 67 और 1 5 इकाई कपडा के बीच निर्धारित होगी। यदि 1 इकाई चावल के बदले 1 5 के निकट किसी मात्रा में कपडा मिलता है तो नेपाल को अधिक लाभ होगा और यदि 67 के निकट किसी मात्रा में मिलता है तो भारत को अधिक फायदा होगा। यदि भारत की चावल की माग की तीव्रता नेपाल की कपडे की माग की तीव्रता से अधिक है तो भारत 1 इकाई के बदले अधिक कपडा देने को तैयार हो जायेगा और विनिमय दर 1 5 इकाई कपडा के निकट होगी। इसके विपरीत यदि नेपाल की कपडे की माग भारत की चावल की माग से अधिक तीव्र है तो विनिमय दर 0 67 इकाई कपडे के निकट होगी।

सापेक्ष अन्तर होने पर (Comparative Differences) : ऊपर सापेक्ष

लागत अन्तर के सम्बन्ध में दिये गये उदाहरण के अनुसार अमेरिका 1 इकाई खाद्य पदार्थ के बदले कम से कम 5 इकाई कपड़ा चाहेगा क्योंकि उसका स्वयं का उत्पादकता अनुपात (Productivity Ratio) खाद्य और कपड़े के बीच 2 : 1 है। इसी प्रकार ब्रिटेन 1 इकाई खाद्य के बदले अधिक से अधिक 75 कपड़ा दे सकता है क्योंकि ब्रिटेन का दोनों वस्तुओं का उत्पादकता अनुपात 4 : 3 है। इसलिए वास्तविक विनिमय दर जिस पर दोनों देश खाद्य एवं कपड़े का लेन देन करेंगे वह 1 इकाई खाद्य = 5 से 75 इकाई कपड़े के बीच उनकी मांगों की पारस्परिक तीव्रता के अनुसार निश्चित होगी। यदि अमेरिका की कपड़े की मांग ब्रिटेन की खाद्य की मांग से अधिक तीव्र है तो विनिमय दर 5 के निकट होगी और इसके विपरीत यदि ब्रिटेन की मांग अधिक तीव्र है तो विनिमय दर 75 के निकट होगी।

तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यताएँ (Assumptions of Theory of Comparative Cost)

1 यह सिद्धांत श्रम लागत मूल्य सिद्धांत (Labour cost of value) पर आधारित है। प्रत्येक वस्तु की उत्पादन लागत श्रम की इकाइयों द्वारा व्यक्त की जाती है तथा श्रम की इकाइयों को समान समझा जाता है।

2 इस सिद्धांत की दूसरी मान्यता यह है कि एक देश के अन्दर उत्पादन के साधन पूर्ण गतिशील होते हैं परन्तु दो देशों के बीच पूर्ण गतिहीन होते हैं।

3 यह सिद्धांत उत्पादन के क्षेत्र में समान लागत सिद्धांत (law of constant costs) के लागू होने की मान्यता पर आधारित है।

4 इस सिद्धांत को व्यापार में परिवहन व्यय को ध्यान में नहीं रखा गया है।

5 यह सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर निर्भर है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

6 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल वस्तुएँ समान आर्थिक महत्त्व रखती हैं।

7 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाले देश स्थायी सतुलन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं तथा साम्बावस्था में होते हैं।

तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचना (Criticism of the theory of comparative cost)

1 प्रायः तुलनात्मक लागत सिद्धांत की यह आलोचना की जाती है कि इसमें अधिक वस्तुओं अथवा दो से अधिक देशों के बीच आयात निर्यात की व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर सरलता से नहीं की जा सकती। साथ ही यह भी आरोप लगाया जाता है कि श्रम मूल्य का सिद्धांत कई कारणों से आर्थिक विचित्रताओं के लिए अनुपयुक्त है एवं उत्पादन में समान लागत सिद्धांत नहीं बल्कि वृद्धिमान लागत

नियम लागू होता है। परन्तु जिन अर्थशास्त्रियों ने इन सिद्धांत की गहन व्याख्या की है उनका मत है कि यह सिद्धांत मौलिक रूप से सभी परिस्थितियों में लागू होता है। हा, यह आवश्यक है कि तुलना करने के लिए द्रव्य लागन को आधार मानना अधिन उपयुक्त है। इसी प्रकार व्यवहार में वृद्धिमान लागन नियम एवं ह्रासमान लागत नियम अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण को सीमित करने की प्रवृत्ति रखते हैं।

2 तुलनात्मक लागत सिद्धांत का दूसरा दोष इसकी इस मान्यता में निहित है कि उत्पादन के साधन आंतरिक दृष्टि से पूर्ण गतिशील एवं अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से पूर्ण गतिहीन है। वास्तव में स्थिति यह है कि उत्पादन साधन आंतरिक दृष्टि से न तो पूर्ण गतिशील है, न तो अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से पूर्ण गतिहीन। हाँ, यह आवश्यक कहा जा सकता है कि साधनों की गतिशीलता आंतरिक क्षेत्र में अपेक्षावृत्त अधिक है।

3 इस सिद्धांत का सबसे गम्भीर दोष यह है कि इसमें आर्थिक सतुलन एवं साम्यावस्था का स्थिर (Static) माना गया है। कीमन एवं मजदूरी, मुद्रा प्रसार एवं भुगतान सतुलन की समस्याओं को इसमें ध्यान में नहीं रखा गया है। इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि जब धमिक एक उद्योग को छोड़ता है तो वह दूसरे अधिक दक्ष (Efficient) उद्योग में काम करता है। उसे कभी बेकारी का सामना नहीं करना पड़ता है। परन्तु व्यवहार में यह सभी बातें खरी नहीं उतरती। वास्तव में यह सिद्धांत परिस्थितियों को बहुत ही आसान मानकर चलता है परन्तु व्यवहार में परिस्थितियाँ बहुत जटिल होती हैं, फिर भी प्रो० सैमुएलसन के शब्दों में :

“Yet, for all its over simplification, the theory of comparative advantage provides a most important glimpse of truth.”

4 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक सिद्धांत में परिवहन व्यय पर ध्यान न देना भी इसका दोष कहा जाता है क्योंकि कभी-कभी परिवहन व्यय उत्पादन लागत से भी अधिक होता है जिसके कारण उसकी स्थानापन्न वस्तु का प्रयोग प्रारम्भ हो जाता है। परन्तु यदि परिवहन व्यय को लागत का एक अंग मान लिया जाय तो यह कठिनाई दूर हो सकती है। परिवहन व्यय का महत्व इस बात से भी स्पष्ट होता है कि एक ही देश में एक भाग में एक वस्तु उत्पादित करके निर्यात की जाती है और दूसरे भाग में उसी वस्तु का विदेश में आयात किया जाता है।

5 प्रो० प्रोह्लिन ने इस सिद्धान्त को अनावश्यक एवं जटिल कह कर आलोचना की है। उनके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मौलिक रूप से आंतरिक व्यापार से भिन्न नहीं है, इसलिए इसकी व्याख्या भी मूल्य के सामान्य सिद्धांत के आधार पर सरलता से की जा सकती है। इसके लिए पृथक सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं है।

तुलनात्मक लागत सिद्धांत का वर्तमान रूप
(Theory of Comparative Costs-Modern View)

आधुनिक अर्थशास्त्री भी इस सिद्धांत को कुछ सुधारों के साथ स्वीकार करते हैं। प्रथम मुझाव यह रचा गया है कि लागत में केवल श्रम की ही नहीं अपितु पूँजी आदि की भी सम्मिलित किया जाना चाहिए एवं लागत को श्रम के द्वारा नहीं बरत मुद्रा द्वारा व्यक्त किया जाना चाहिए। दूसरा सुधार इस सम्बन्ध में यह मुझाया गया है कि तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त को सक्षम लागत नियम पर आधारित करना अन्वयावहारिक है क्योंकि व्यवहार में वृद्धिमान लागत नियम एवं ह्रासमान नियम लागू होते हैं। वास्तव में यह सिद्धांत सभी परिस्थितियों में सत्य है। तीसरा सुधार यह प्रस्तुत किया गया है कि द्विनिमय दर निर्धारण में वस्तुओं की मांग की लोच को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इस प्रकार तुलनात्मक लागत सिद्धांत आधुनिक युग में अधिक व्यापक हो गया है परन्तु इस सिद्धांत की आधारभूत मान्यता—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लागतों में अन्तर पाये जाने की स्थिति में ही लागू होता है, आज भी पूर्ण रूप से सत्य मानी जाती है। लागतों का अन्तर श्रम के माध्यम से व्यक्त किया जाय अथवा मुद्रा के माध्यम से वस्तु स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। निम्नलिखित उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है :

लागतों में निरपेक्ष अन्तर (Absolute Differences in Costs) :

लागतों का अन्तर मुद्रा के माध्यम से व्यक्त किया गया है।

	प्रति इकाई लागत (सीमात)	
	चावल	गेहूँ
भारत	50 रु०	30 रु०
नेपाल	30 रु०	50 रु०

लागत के दृष्टिकोण से भारत गेहूँ में तथा नेपाल चावल में विशिष्टीकरण कर सकते हैं तथा बदले में चावल तथा गेहूँ एक दूसरे से प्राप्त कर लाभ उठा सकते हैं। भारत गेहूँ भेजकर नेपाल से 30 रु० से 50 रु० प्रति इकाई के बीच अपनी मांग के लोच के अनुसार किसी भी दर पर चावल प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार नेपाल गेहूँ प्राप्त कर सकता है। लाभ जिसे अधिक होगा वह उनकी मांग की तीव्रता एवं लोच पर निर्भर करेगा।

सापेक्ष अन्तर (Comparative Differences in Costs) :

सापेक्ष अन्तर मुद्रा के माध्यम से व्यक्त किया गया है।

	प्रति इकाई लागत (सीमात)	
	जूट	कपास
भारत	30 रु०	30 रु०
पाकिस्तान	20 रु०	25 रु०

यहां भारत जूट तथा कपास दोनों का उत्पादन पाकिस्तान की अपेक्षा अधिक लागत पर करता है परन्तु पाकिस्तान वो जूट के उत्पादन में अधिक तुलनात्मक लाभ है क्योंकि इसमें उसकी तुलनात्मक दक्षता (relative efficiency) अधिक है। इसी प्रकार भारत कपास का उत्पादन करके अपनी सापेक्ष हानि (Comparative disadvantage) को कम कर सकता है। भारत में जूट और कपास का विनिमय अनुपात 1 : 1 है तथा पाकिस्तान में जूट और कपास का विनिमय अनुपात 1 : 1.25 (अर्थात् 1.25 इकाई जूट = 1 इकाई कपास) अब भारत यदि कपास के बदले पाकिस्तान से जूट प्राप्त करे तो उसे 1 से 1.25 इकाई तक जूट प्राप्त होगा जिससे उसे लाभ होगा। दूसरी ओर पाकिस्तान जूट पैदा करके भारत से 20/25 अर्थात् 4/5 इकाई से 1 इकाई तक कपास प्राप्त कर सकता है और उस लाभ हो सकता है।

ओहलिन का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत (Ohlin's Theory of International Trade)

बर्स्टिल ओहलिन ने अपनी पुस्तक 'Interregional and International Trade' में सामान्य सन्तुलन सिद्धांत (General Equilibrium Theory) को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में लागू किया है, क्योंकि वे अन्तर्राष्ट्रीय एवं आंतरिक या अन्तर्देशीय व्यापार में कोई मौलिक अन्तर नहीं मानते। ओहलिन ने इस बात की ओर संकेत किया है कि केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ही सापेक्ष लाभ (Comparative advantage) पर आधारित नहीं है बल्कि यह (सापेक्ष लाभ) सभी प्रकार के व्यापार अथवा विनिमय का आधार है चाहे वह आंतरिक हो, अन्तर्देशीय हो या अन्तर्राष्ट्रीय हो। ओहलिन के विचारानुसार विभिन्न क्षेत्र अथवा देश उन्ही कारणों से विशिष्टीकरण एवं विनिमय तथा व्यापार करते हैं जिन कारणों से व्यक्ति करते हैं। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अन्तर्देशीय व्यापार की एक विशिष्ट प्रवस्था है तथा इसके अध्ययन के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार ओहलिन अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साधनों की गतिहीनता को भी महत्व नहीं देते क्योंकि साधनों की गतिहीनता एक ही देश के दो क्षेत्रों में पाई जा सकती है। दो देशों में दो भिन्न मुद्राओं का चलन भी पृथक सिद्धांत के लिए पर्याप्त कारण नहीं है, क्योंकि विनिमय दर मुद्रा की बाह्य क्रयशक्ति को प्रकट करता है तथा बाह्य क्रयशक्ति एवं आंतरिक क्रयशक्ति का घनिष्ठ सम्बन्ध होना है।

ग्रोहलिन के अनुसार विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में प्रकृति ने अलग-अलग प्रकार से उत्पादन के साधन उपलब्ध किए हैं। यदि प्रत्येक क्षेत्र (उसी देश में या अलग-अलग देशों में) अपने यहाँ अधिकमात्रा में उपलब्ध साधनों का प्रयोग करने वाली वस्तुओं के उत्पादन में अपनी शक्ति केन्द्रित करें तो व्यापार के द्वारा सभी क्षेत्रों को पारस्परिक लाभ प्राप्त हो सकता है। ऐसा करने से प्रति इकाई उत्पादन लागत न्यूनतम रखा जा सकता है तथा कीमत अंतर (*Price Differences*) के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार किया जा सकता है। इस प्रकार विशिष्टीकरण तथा विनिमय द्वारा विश्व के उत्पादन साधनों का उपयुक्त एवं मितव्ययितापूर्ण (*economical*) प्रयोग किया जा सकता है तथा विश्व की वास्तविक आय में वृद्धि की जा सकती है।

ग्रोहलिन की व्याख्या से यह निष्कर्ष निकलता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सापेक्ष कीमतों (*comparative costs*) के अन्तर पर आश्रित है तथा सापेक्ष कीमतों में अन्तर इसलिए होता है क्योंकि उत्पादन के साधनों की पूर्ति सभी देशों में समान नहीं होती। सामान्यतया किसी भी क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले साधन सस्ते, और कम मात्रा में पाए जाने वाले साधन महंगे होते हैं। जिस वस्तु के उत्पादन में अधिक सस्ते साधनों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है उसी में विशिष्टीकरण किया जाता है तथा उसका निर्यात किया जाता है। दूसरे शब्दों में सस्ते साधनों का निर्यात एवं महंगे साधनों का आयात किया जाता है। विनिमय दर का निर्धारण तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आकार सम्बन्धित देशों की पारस्परिक मांगों द्वारा निर्धारित होता है।

ग्रोहलिन के सिद्धांत की अन्य विशेषता यह है कि उनके अनुसार उत्पादन साधनों की दृष्टि से समान देशों के लिए भी व्यापार लाभदायक हो सकता है क्योंकि इससे बड़े पैमाने के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। समान तुलनात्मक लागत वाले क्षेत्र जिन वस्तुओं की घरेलू मांग कम है उनके उत्पादन में विशिष्टीकरण करके दूसरे देश से विनिमय कर सकते हैं।

अधिकांश अर्थशास्त्री ग्रोहलिन के विचारों की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं परन्तु हैबरलर जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री यह विचार व्यक्त करते हैं कि ग्रोहलिन का सिद्धांत तुलनात्मक लागत के सिद्धांत के साथ रखा जा सकता है यदि उसे हैबरलर द्वारा पुनर्कथित रूप में देखा जाय। इस बारे में प्रो० सैमुएलसन का निम्न उद्धरण बड़ा सुन्दर प्रतीत होता है :

“With proper public policies, modern nations can achieve a neoclassical synthesis which need not sacrifice the great benefits from trade, but rather can recreate the environment in which the principle of comparative advantage will apply”.

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ (Advantages of International Trade)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों का आधार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन एवं विशिष्टीकरण है, जिसके फलस्वरूप विश्व के कुल उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है और सभी देशों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से अनेक लाभ होते हैं :

1. विश्व में उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग (Utilisation of the productive resources of the world to the best advantage) प्रत्येक देश उसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण कर लेता है जिसके लिए वह सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक देश कम से कम लागत से अधिक से अधिक एवं अष्टी वस्तुओं का उत्पादन करने में समर्थ होता है और अपने साधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करता है।

2. दुर्लभ वस्तुओं का उपभोग सम्भव (Consumption of goods which cannot be produced at home, becomes possible) : जिन वस्तुओं का उत्पादन देश में सम्भव नहीं है उन्हें विदेशों से प्राप्त किया जा सकता है तथा उन-मोक्त विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपभोग कर सकता है। इससे आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि होती है एवं रहन सहन का स्तर उचा उठता है।

3. कीमतों में अधिक उतार-चढ़ाव पर प्रतिबन्ध (Violent fluctuations in prices are restricted) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण वस्तुओं का बाजार बहुत विस्तृत हो जाता है इसलिए कीमत में उतार-चढ़ाव लाने वाले कारणों का विकेंद्रित प्रभाव पड़ता है। यदि किसी स्थान पर किसी चीज की कीमत अभावपूर्ण रूप से बढ़ जाती है तो दूसरे देशों से उस वस्तु का आयात करके उसकी पूर्ति बढ़ा दी जाती है और कीमत को कम कर दिया जाता है। इस प्रकार कीमतों में अपेक्षाकृत स्थायित्व रखा जा सकता है।

4. संकटकाल में सहायक (Helpful in difficult periods) : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के परिणामस्वरूप आवश्यकता के समय कोई भी देश दूसरे देशों से सहायता प्राप्त कर सकता है। धनी देश निर्धन देशों की आर्थिक संकट की स्थिति में सहायता करते हैं और विश्व एक आर्थिक इकाई के रूप में संगठित होने की दिशा में बढ़ने लगता है।

5. उत्पादन विधि में सुधार (Improvement in production techniques) विशिष्टीकरण होने के कारण प्रत्येक देश नये तरीकों का आविष्कार करना चाहता है जिससे वह वस्तुओं को और अच्छा एवं सस्ता बना सके तथा तुलनात्मक

लाभ की मात्रा को बढ़ा सके। इस होड़ में विज्ञान एवं तकनीक का विकास होता रहता है।

6. वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में कमी तथा समानता की प्रवृत्ति (*Tendency of prices to be less and equal*) : विशिष्टीकरण के कारण वस्तुएँ सस्ती बनाने का प्रयत्न किया जाता है और बाजार विस्तृत करने के लिए कीमतों को कम रखने की प्रवृत्ति होती है। देशों में पारस्परिक स्पर्धा होने के कारण सभी स्थानों पर कीमतों में समानता होने की भी प्रवृत्ति रहती है।

7. सांस्कृतिक सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (*Cultural gains and international co operation*) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से एक देश की संस्कृति दूसरे देश के सम्पर्क में आती है और विकसित होती है। इससे विश्व शांति एवं सहयोग की भावना में वृद्धि होती है। युद्ध से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भग्न होने का डर रहता है इसलिए सभी युद्ध से बचना चाहते हैं। कोई भी देश पूर्णरूप से आत्म निर्भर नहीं हो सकता इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा वे आपसी सहायता बढ़ाकर अपना आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण अधिकतम करने की दिशा में प्रयत्नशील रहते हैं।

8. उत्पादन के साधनों की कीमतों में समानता की प्रवृत्ति (*The prices of factors of production tend to be equal*) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण अपेक्षाकृत महंगी वस्तुएँ जब आयात की जाने लगती हैं तो उनसे सम्बन्धित उत्पादन के साधनों की मांग कम होने लगती है और निर्यातक देश में अधिक उत्पादन के लिए उनकी मांग बढ़ती है इसलिए कीमतें बढ़ने लगती हैं। इस प्रक्रिया के कारण उनकी कीमतों में समानता होने की प्रवृत्ति रहती है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियाँ

(Disadvantages of International Trade)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ मुक्त व्यापार की नीति एवं सद्भावना के वातावरण में ही प्राप्त हो सकते हैं। व्यवहार में मुक्त व्यापार की नीति पर कायम रहना एक सद्भावना का वातावरण बनाए रखना प्रायः कठिन होता है जिसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ हानियों का जन्म होता है। प्रमुख हानियाँ निम्नलिखित हैं।

1. पिछड़े देशों में हस्तकला एवं कुटीर उद्योगों का विघटन (*Destruction of handicrafts and cottage industries in backward countries*) : औद्योगिक विकास में पिछड़े हुए देश कुटीर उद्योगों से उत्पादन करते हैं। हाथ से बने एक छोटे पैमाने पर उत्पादित पदार्थों विशिष्टीकरण करने वाले देशों द्वारा उत्पादित माल से प्रतिযোগिता नहीं कर पाते और धीरे-धीरे बर्बाद हो जाते हैं। भारत इस बात का प्रमाण है।

2 अन्तराष्ट्रीय व्यापार एक देश को दूसरे देश की राजनीति में हस्तक्षेप का अवसर देता है (International Trade provides opportunity for political interference) : अन्तराष्ट्रीय व्यापार के कारण कभी-कभी किसी देश का आयात इतना बढ़ जाता है कि निर्यातक आयातक के देश की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर देता है और यह स्थिति आयातक देश को निर्यातक देश के विलकुल आधीन बना सकती है। कहा जाता है कि साम्राज्यवादी, व्यापारी का अनुगमन करता है (The empire-builder follows the trader)। भारत में ब्रिटिश लोग व्यापार करने आए थे परन्तु बाद में शासक बन बैठे।

3. विदेशों पर निर्भरता (Dependence on foreign nations) : विदेशी व्यापार के कारण एक देश दूसरे देश पर निर्भर रहने लगता है। इसका परिणाम यह होता है कि राजनैतिक तनाव की स्थिति में व्यापार स्थगित हो जाता है और सम्बन्धित देशों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एक देश की दूसरे देश पर निर्भरता के कारण एक देश में आर्थिक संकट आने पर उसका प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ता है।

4 कृषिप्रधान देशों को हानि (Disadvantage to agricultural countries) : कृषि प्रधान देशों को इसलिए हानि उठानी पड़ती है क्योंकि कृषि उत्पादन में वृद्धिमान लागत नियम शीघ्र लागू हो जाता है तथा औद्योगिक क्षेत्रों में प्रायः ह्रासमान लागत नियम लागू होता है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पाद अधिक टिकाऊ न होने के कारण कृषि प्रधान देशों की मोल-भाव करने की शक्ति को सीमित कर देते हैं। इसके विपरीत निर्मित माल अधिक टिकाऊ होता है इसलिए औद्योगिक देशों की मोल-भाव शक्ति अधिक होती है।

5. देश का एकांगी विकास (Imbalanced development) : अन्तराष्ट्रीय व्यापार के कारण प्रत्येक देश केवल कुछ चुने हुए क्षेत्रों का विकास करने लगता है और उसी में विशिष्टीकरण करके लाभ प्राप्त करता है। इसलिए अन्य क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाता। संकटबालीन परिस्थिति में इस प्रकार के विकास का परिणाम अत्यन्त कष्ट प्रद होता है। दो महासुद्धों का अनुभव इस चरम की पुष्टि करता है। इसीलिए प्रायः प्रत्येक देश आत्म निर्भर होने की दिशा में प्रयत्नशील है। एकांगी विकास के कारण बड़े साधनों का पूर्ण उपयोग भी नहीं हो पाता और कई बार देश में कई क्षेत्रों में अनुसंधान तथा आविष्कार को भी प्रोत्साहन मिलना बन्द हो जाता है, जो उचित नहीं है।

6. राशिपातन का भय (Dumping) : कभी-कभी विदेशी व्यापार पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के प्रलोभन में कई देश दूसरे देशों में बहुत सस्ते मूल्य पर

वस्तुये वेचना प्रारम्भ कर देते हैं। जिससे देशी व्यापार उनकी प्रतियोगिता में नहीं टिक पाता और प्रायः बन्द सा हो जाता है। बाद में विदेशी व्यापारी मनमाना मूल्य बढ़ा कर इस स्थिति का फायदा उठाते हैं। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शोषण का साधन बन जाता है।

7. कच्चे माल की समाप्ति (Country's natural resources are exhausted) : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप कई देशों के ऐसे प्राकृतिक साधन, जिनका प्रतिस्थापन असम्भव होता है, समाप्त हो जाते हैं—जैसे कोयला तेल और अन्य खनिज पदार्थ। इन वस्तुओं का लाभ प्राप्त करने के दृष्टिकोण से निर्यात कर दिया जाता है परन्तु वास्तव में यह लाभ अल्पकालिक होता है। दीर्घकालीन दृष्टिकोण से उनका स्वयं प्रयोग करना और औद्योगिक विकास करना अधिक लाभप्रद है।

8. व्यापारिक द्वेष युद्ध तथा तनाव पैदा करता है (Trade rivalry leads to war and friction) : व्यापारिक प्रतियोगिता अन्तर्-आपसी सम्बन्धों में तनाव पैदा कर देती है। दो महायुद्धों के कारणों में जर्मनी की अपनी वस्तुओं के लिए विस्तृत बाजार स्थापित करने की भावना भी उल्लेखनीय है।

9. हानिकारक एवं विलासिता की वस्तुओं का प्रयोग (Use of harmful goods and Luxuries) : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उपभोक्ताओं की आदतों में कभी-कभी हानिकारक परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण वे विलासिता के आदी हो जाते हैं और उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है।

10. उपभोग में कमी (Less Consumption) : निर्यात के लोभ में आकर कई देश उन वस्तुओं का भी निर्यात करने लगते हैं जो आवश्यकता से अधिक उत्पादित नहीं होनी हैं। इसलिए उस देश के उपभोक्ता चाहते हुए भी उनके उपभोग से वंचित रह जाते हैं। चीनी की कमी होने पर भी उसका निर्यात करने से भारत-वासी इसके उपभोग से वंचित रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में रुकावटें

(Obstructions in the way of International Trade)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनेक लाभों के बावजूद, इसकी हानियों को ध्यान में रखकर, अनेक राष्ट्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर अकुल लगाने की नीति समय-समय पर अपनाई है। सदियों से पिछड़े हुए देशों में राजनैतिक जागृति के साथ आर्थिक विकास की भावना ने भी वहाँ की जनता एवं नेताओं को व्याकुल कर दिया है और वे अपने प्राकृतिक साधनों का निर्यात बन्द कर स्वयं उनका प्रयोग करने लगे हैं। सभी देशों ने युद्धकालीन अनुभव के आधार पर आत्मनिर्भरता का लक्ष्य स्वीकार कर लिया है। इन कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में निम्नलिखित रुकावटें आती हैं—

1 भुगतान समझौते (Clearing Agreements)—दो देश वस्तु विनिमय कर लिया करते हैं और किसी प्रकार का मौद्रिक लेनदेन नहीं होता ।

2 आयात कोटा (Import Quotas)—कोई वस्तु कितनी मात्रा में विदेशों से मगाई जा सकती है इसका कोटा निर्धारित कर दिया जाता है ।

3 आयात निर्यात कर (Import Export duties)—इन उपायों द्वारा भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मुक्त प्रवाह को रोका जाता है ।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संकेत

(1) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या आधार है ? विवेचन कीजिए । विदेशी व्यापार के लाभों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए ।

(राजस्थान टी०डी०सी० फाइनल, 1965, 1966)

[संकेत—प्रथम भाग में बताइय कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तभी होता है जब दो देशों की उत्पादन लागतों में निरपेक्ष तथा सापेक्ष अन्तर होता है । दूसरे भाग में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों का वर्णन कीजिए ।]

(2) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लागत सिद्धान्त कैसे लागू होता है? इसकी स्पष्ट व्याख्या इस सिद्धान्त के आधुनिक रूप में करिए ।

(राजस्थान बी० ए०, 1964)

अथवा

तुलनात्मक परिद्वय के सिद्धान्त की तर्कपूर्ण व्याख्या कीजिए और इस सिद्धान्त के अपवादों का वर्णन कीजिए ।

अथवा

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या के रूप में परीक्षा कीजिए ।

(आगरा, 1967)

[संकेत—तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की दो देशों के उदाहरण लेकर विस्तृत व्याख्या कीजिए । रिकार्डों द्वारा प्रनिपादित प्रतिष्ठित दृष्टिकोण से लेकर सिद्धान्त के आधुनिक रूप तक की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए । केवल दूसरे प्रश्न में सिद्धान्त के अपवादों का भी वर्णन कीजिए ।]

(3) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आन्तरिक व्यापार से किस प्रकार भिन्न होता है? इसके विशेष लक्षण कौन से हैं ?

(नागपुर बी० काम, 1961)

[संकेत—प्रथम भाग में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आन्तरिक के अन्तर की मुख्य बातों की व्याख्या कीजिए और बताइये कि उनमें कोई आधारभूत अन्तर नहीं है। जो अन्तर है वह केवल सीमा (Degree) मात्र का है। द्वितीय भाग में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य लक्षणों की व्याख्या कीजिए।]

(4) 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एक प्रकार का वस्तु-विनिमय ही है।' व्याख्या करें।

(राजस्थान टी०डी०सी० फाइनल, 1967)

[संकेत—जिस प्रकार वस्तु-विनिमय ऐसे दो पक्षों के बीच होता है जिनको एक दूसरे की वस्तुओं की आवश्यकता होती है उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ऐसे दो देशों के बीच होता है जिनको एक दूसरे की वस्तुओं की आवश्यकता है। इसी को समझते हुए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न आधारों तथा उसके महत्व को चर्चा कीजिए।]

विदेशी विनिमय (Foreign Exchange)

"...exchange rate policy is only one aspect of the much broader problem of equilibrating balances of payments, of determining the response of a nation's economy to developments in the rest of the world, and of making international adjustments to developments within the country itself."

Lester V. Chandler

विदेशी विनिमय का सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों से है। प्रत्येक देश की अपनी प्रामाणिक मुद्रा होती है एवं आंतरिक भुगतानों के लिए स्वतन्त्रता पूर्वक स्वीकार की जाती है; परन्तु कोई भी राष्ट्रीय सीमा के बाहर स्वतन्त्रता पूर्वक स्वीकार नहीं की जाती। हम सब यह जानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र का अन्य राष्ट्रों से व्यापारिक सम्बन्ध होता है। एक देश के नागरिकों द्वारा दूसरे देश के नागरिकों को भुगतान किया जाता है तथा सरकारों को पारस्परिक भुगतान की आवश्यकता पड़ती रहती है। इस प्रकार के भुगतानों में एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की प्रक्रिया निहित है, क्योंकि सभी देशों द्वारा मान्य कोई मौद्रिक इकाई चलन में नहीं होती है। यदि भारत के किसी व्यापारी को अमेरिका में भुगतान करना है तो या तो भारतीय व्यापारी को रुपए के बदले डालर प्राप्त करके उसे अमेरिकन व्यापारी के पास भेजना होगा या अमेरिकन व्यापारी को प्राप्त रुपए के बदले डालर प्राप्त करना होगा क्योंकि डालर ही उसके काम आ सकता है। दोनों ही परिस्थितियों में दो मुद्राओं में विनिमय होता है। यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि प्रत्येक विनिमय (मुद्राओं का) में दो पक्ष होना आवश्यक है अर्थात् रुपया डालर में तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक उसी समय डालर को रुपए में न बदला जाय। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एक देश द्वारा अन्य देशों को किया जाने वाला भुगतान ठीक उस भुगतान के बराबर होना चाहिए जो उस देश

को अन्य देशों से प्राप्त होना है। इस आधारभूत सिद्धान्त को काउथर ने विदेशी विनिमय का सुनहरा सिद्धान्त कहा है।¹

एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने का कार्य विशेष प्रकार के बैंको या व्यापारिक बैंको के विशेष विभागों, केन्द्रीय बैंको एवं सरकारों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार विदेशी भुगतान से सम्बन्ध सौदों को करने वाली सस्थाएँ तथा व्यक्ति विदेशी विनिमय बाजार के नाम से संबोधित किए जाने हैं। विदेशी विनिमय का कार्य करने वाली सस्थाओं की कार्यप्रणाली तथा विनिमय दर सम्बन्धी समस्याओं का सम्यक अध्ययन ही विदेशी विनिमय के अध्ययन की विषय सामग्री है। इस प्रकार विदेशी विनिमय एक प्रणाली है, एक व्यवस्था है जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान किया जाता है। हार्टले विदर्स के अनुसार विदेशी विनिमय अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक विनिमय की कला एवं विज्ञान है—(Foreign exchange is the art and science of international money changing)

‘विदेशी विनिमय’ शब्द का प्रयोग विदेशी मुद्रा के प्रथम में भी किया जाता है। यहाँ इसका तात्पर्य एक देश द्वारा दूसरे देशों की मुद्रा की प्राप्ति या विदेशों में जमा रकम (Balance held abroad) से होता है। परन्तु यह विदेशी विनिमय का सङ्कुचित अर्थ ही कहा जा सकता है।

विनिमय दर

(The Rate of Exchange)

अभी हमने देखा कि अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन में विभिन्न प्रकार की मुद्राओं को चलन में रखने वाले देश एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं और प्रत्येक देश अपनी मुद्रा में भुगतान प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलना आवश्यक होता है। जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा से परिवर्तित की जाती है उसे ही विनिमय दर कहा जाता है। स्पष्ट है कि एक देश की मुद्रा की विनिमय दर अलग-अलग मुद्राओं के सदृश भिन्न-भिन्न होगी। इस प्रकार विनिमय दर एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में व्यक्त की गई कीमत है (The rate of exchange is the price of one currency in terms of another)

¹ “It necessarily follows that every flow of payments from one country to the rest of the world must be exactly balanced by an equal flow of payments into that country from the rest of the world, for every pound given in exchange by one set of persons is also a pound taken in exchange by another set of persons. This is the first and virtually the only, Golden Rule of the foreign exchange”
—Crowther : *An Outline of Money* p 207

विनिमय दर उद्धृत करने के तरीके (Methods of quoting the rate of exchange) : जिस प्रकार कीमत उद्धृत करने के दो तरीके होते हैं वैसे ही विनिमय दर भी दो प्रकार से उद्धृत की जा सकती है—(1) एक इकाई विदेशी मुद्रा की कीमत स्वदेशी मुद्रा की इकाइयों में, तथा (2) एक इकाई स्वदेशी मुद्रा की कीमत विदेशी मुद्रा की इकाइयों में। प्रथम प्रकार से उद्धृत विनिमय दर प्रत्यक्ष विनिमय या निश्चित विनिमय (Fixed or direct exchange) कहा जाता है तथा दूसरे प्रकार से उद्धृत विनिमय दर को अप्रत्यक्ष विनिमय (indirect exchange) कहा जाता है।

विनिमय दर उद्धृत करने के तरीकों को ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि विनिमय दर के बढ़ने या घटने का अर्थ दोनों ही तरीकों में समान नहीं है। यदि विनिमय दर प्रत्यक्ष तरीके से उद्धृत की गई है तो विनिमय दर बढ़ने का तात्पर्य है एक इकाई विदेशी मुद्रा की कीमत पूर्वपिशा स्वदेशी मुद्रा की अधिक इकाइयाँ। इसके विपरीत यदि विनिमय दर अप्रत्यक्ष ढंग से व्यक्त की गई है तो विनिमय दर बढ़ने का अर्थ है एक इकाई स्वदेशी मुद्रा की कीमत पूर्वपिशा विदेशी मुद्रा की अधिक इकाइयाँ। दूसरे शब्दों में प्रत्यक्ष ढंग से विनिमय दर उद्धृत करने पर विनिमय दर का बढ़ना स्वदेश के लिए महंगा एवं हानिप्रद और विदेश के लिए सस्ता एवं लाभप्रद होता है तथा अप्रत्यक्ष ढंग से विनिमय दर उद्धृत करने पर विनिमय दर का बढ़ना स्वदेश के लिए सस्ता एवं लाभप्रद एवं विदेश के लिए महंगा एवं हानिप्रद होता है। दोनों ही तरीकों में प्रत्यक्ष ढंग से विनिमय दर उद्धृत करना अधिक वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें यह ज्ञात हो जाता है कि एक इकाई विदेशी मुद्रा के लिए अपनी मुद्रा में कितनी कीमत देना है।

विनिमय दर का निर्धारण

(Determination of the Rate of Exchange)

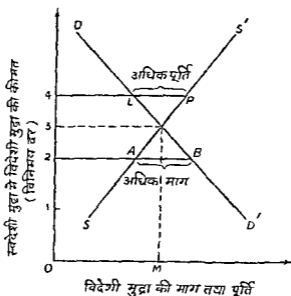
माग पूति का सिद्धांत (Demand and Supply Theory) :

ऊपर लिखा जा चुका है कि विदेशी विनिमय दर एक प्रकार की कीमत है और विदेशी विनिमय बाजार इस कीमत निर्धारण का स्थान है। इस बाजार की अपनी निजी विशेषता यह है कि इसमें मुद्रा बेची जाती है, इसलिए मुद्रा ही माग और पूति दोनों पक्षों में विद्यमान है। विनिमय दर एक कीमत होने के कारण कीमत निर्धारण के सामान्य नियम द्वारा निर्धारित होती है। जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु की माग और पूति के सतुलन बिन्दु पर निर्धारित होता है वैसे ही किसी भी निश्चित समय पर विनिमय दर वह होगी जिस दर पर सम्बन्धित देश की विदेशी मुद्रा की माग तथा पूति बराबर हो।

विदेशी विनिमय (विदेशी मुद्रा) को विदेशी बाजार में प्रवेश पाने का टिकट कहा जाता है। सामान्य परिस्थितियों में विदेशी मुद्रा की स्वदेशी मुद्रा के सदृश में कीमत कम होने पर विदेशी मुद्रा की अधिक मांग की जाती है। विदेशी मुद्रा की कीमत में कमी होने का अर्थ विदेशी वस्तुओं का सस्ता होना है जिसके फलस्वरूप आयातों को प्रोत्साहन मिलता है। आयातों के बढ़ने से उनके भुगतान के निमित्त अधिक विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ती है और उनकी मांग बढ़ जाती है। उसी प्रकार विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ जाने पर विदेशी वस्तुएँ महंगी पड़ने लगती हैं और आयात कम हो जाता है। कम आयातों के भुगतान के लिए कम विदेशी विनिमय की मांग की जाती है। अक्षेप में विदेशी विनिमय का मांगवक्र नीचे से नीचे दाहिनी ओर का झुकाव है। यहाँ पर विनिमय दर के अतिरिक्त विदेशी विनिमय की मांग को प्रभावित करने वाले प्रभावकों (Determinants) को स्थिर मान लिया गया है, क्योंकि उनमें परिवर्तन होने पर मांग वक्र भी परिवर्तित हो सकता है।

विदेशी विनिमय का पूतिवक्र नीचे से ऊपर दाहिनी ओर का उठना है, क्योंकि विनिमय दर कम होने पर विदेशी द्वारा किया जाने वाला आयात (अपना निर्यात) कम होगा और विनिमय दर अधिक होने पर विदेशी द्वारा किया जाने वाला आयात अधिक होगा। इस प्रकार विनिमय दर कम होने पर विदेशी विनिमय की पूति कम और अधिक होने पर पूति अधिक होती है। पूति के सम्बन्ध में भी विनिमय दर के अतिरिक्त अन्य प्रभावकों को स्थिर मान लिया जाता है।

विनिमय दर साम्यावस्था में उस समय होगा जब विदेशी विनिमय की मांग ठीक विदेशी विनिमय की पूति के बराबर होगी। विनिमय दर साम्यदर से अधिक होने पर विदेशी विनिमय की पूति विदेशी विनिमय की मांग से अधिक होगी तथा विनिमय दर साम्य दर से कम होने पर विदेशी विनिमय की मांग विदेशी विनिमय की पूति से अधिक होगी। दोनों ही अवस्थाओं में मांग और पूति की शक्तियाँ इस प्रकार से कार्य करती हैं कि विनिमय दर साम्यदर पर पहुँचने की प्रवृत्ति रखती है। इस प्रकार बाजार विनिमय दर साम्यदर से भिन्न हो सकती है परन्तु उसकी प्रवृत्ति साम्यदर की ओर आने की होती है। साम्यदर उस समय तक स्थायी रहती है जब तक विदेशी विनिमय की मांग एवं पूति के प्रभावकों में स्थिरता रहती है। इन प्रभावकों में परिवर्तन होने पर विनिमय की साम्यदर भी परिवर्तित हो जाती है। अगले पृष्ठ पर दिए चित्र द्वारा मुक्त विनिमय बाजार में विनिमय दर के निर्धारण की विधि को समझाने का प्रयत्न किया गया है :



उपरोक्त चित्र से यह स्पष्ट है कि जब विदेशी मुद्रा की माग एवं पूर्ति दोनों OM के बराबर है तो विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत 3 इकाई स्वदेशी मुद्रा है। यही विनिमय की साम्यदर है। यदि विनिमय दर कम होकर 2 इकाई स्वदेशी मुद्रा के बराबर हो जाय तो विदेशी विनिमय की पूर्ति की अपेक्षा माग AB मात्रा से अधिक होगी, फलस्वरूप विनिमय दर के बढ़ने की प्रवृत्ति होगी। इसके विपरीत यदि विनिमय दर बढ़कर 4 इकाई स्वदेशी मुद्रा के बराबर हो जाय तो विदेशी विनिमय की पूर्ति माग की अपेक्षा LP मात्रा से अधिक होगी और विनिमय दर कम होने की प्रवृत्ति होगी। इस प्रकार बाजार विनिमय दर साम्यदर के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। यदि अन्य प्रभावों (विनिमय दर के अतिरिक्त) के कारण माग-वक्र या कीमत वक्र में परिवर्तन हो जाय तो साम्यदर भी परिवर्तित हो जायेगी।

वास्तव में विनिमय दर का माग और पूर्ति सिद्धान्त विनिमय दर के भुगतान सतुलन सिद्धान्त का ही सुघरा हुआ रूप है। इस सुघरे हुए रूप में यह भुगतान सतुलन सिद्धान्त से श्रेष्ठ है। भुगतान सतुलन सिद्धान्त का बखाना आगे किया जायेगा।

यद्यपि विनिमय दर निर्धारित करने का माँग पूर्ति का सिद्धान्त सभी प्रकार के मौद्रिक मानों में लागू होता है, फिर भी यह ध्यान देना आवश्यक है कि विदेशी विनिमय की माग एवं पूर्ति को निर्धारित करने वाले तब मौद्रिक व्यवस्था के अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए विभिन्न मौद्रिक व्यवस्थाओं और विनिमय प्रणालियों में विनिमय दर की कुछ अपनी अलग विशेषताएँ होती हैं। अतः विभिन्न मौद्रिक व्यवस्थाओं में विनिमय-दर के निर्धारण की समस्या पर विचार करना आवश्यक है।

स्वर्णमान के अन्तर्गत विनिमय दर (Exchange Rate under Gold Standard)

स्वर्णमान व्यवस्था के अन्तर्गत चलन में स्वर्ण मुद्राएँ होती हैं अथवा मुद्रा स्वर्ण में निश्चित दर पर परिवर्तनीय होती है। जिस दर पर देश की प्रामाणिक मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनीय होती है उसे स्वर्ण का टकसाल मूल्य (Mint Price of Gold) कहा जाता है। स्वर्णमान व्यवस्था की दो प्रमुख आवश्यकताएँ (requirements) हैं—(1) चलन मुद्रा और स्वर्ण की पारस्परिक परिवर्तनशीलता (Inter convertibility between domestic currency and gold) तथा (2) स्वर्ण का स्वतंत्र आयात एवं निर्यात (Free export and import of gold)। इन दोनों आवश्यकताओं में किसी भी एक की पूर्ति न होने पर विश्व बाजार (World Market) में निश्चित मात्रा-स्वर्ण एवं मुद्रा विभेद (स्वर्णमान व्यवस्था में) के बीच की समानता (parity) निश्चित नहीं रह सकती है।

टकसाली विनिमय दर (Mint Par of Exchange)

स्वर्णमान पर आधारित देशों के बीच विनिमय दर सामान्यतया उनके टकसाली स्वर्ण मूल्य पर निर्भर करती है। यदि स्वर्णमान पर आधारित एक देश की एक इकाई मुद्रा स्वर्ण की 'क' मात्रा के बराबर है दूसरे देश में वही स्वर्ण-मात्रा 'क' वहाँ की चार इकाई मुद्रा के बराबर है तो इस देश की 4 इकाई मुद्रा के बदले पहले देश की 1 इकाई मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। इस विनिमय दर को टकसाली विनिमय दर (Mint Par of Exchange) कहा जाता है क्योंकि यह दर स्वर्ण के टकसाल मूल्य के आधार पर निकाली जाती है।

स्वर्ण बिन्दु (Specie Points)

टकसाली विनिमय दर ही स्वर्णमान व्यवस्था के अन्तर्गत आधारभूत विनिमय दर होती है। परन्तु व्यवहार में वास्तविक विनिमय दर, भुगतान मतुलन की स्थिति के अनुसार, आधारभूत विनिमय दर से कम या अधिक हो सकती है। वास्तविक विनिमय दर आधारभूत विनिमय दर से कितनी अधिक या कम हो सकती है इसका निर्णय एक देश से दूसरे देश में सोना भेजने के खर्चों के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार सोना भेजने का खर्च वास्तविक विनिमय दर की उतार-चढ़ाव की सीमा निर्धारित करता है। इन सीमाओं को 'स्वर्ण बिन्दु' (Specie Points or Gold Points) कहा जाता है। इन बिन्दुओं को प्राप्त करने के लिए टकसाली विनिमय दर में से एक देश से दूसरे देश में सोना भेजने का खर्च जाड़ा या घटाया जाता है। यदि विनिमय दर को प्रत्यक्ष ढंग से व्यक्त किया जाय तो टकसाली विनिमय दर

मे स्वर्ण निर्यात व्यय जोडन से स्वर्ण निर्यात बिन्दु (Gold Export Point) ज्ञात होता है और घटाने से स्वर्ण आयात बिन्दु (Gold Import Point) ज्ञात होता है। वास्तविक विनिमय दर स्वर्ण आयात एवं निर्यात बिन्दुओं के बीच सम्बन्धित देशों की माग एवं पूर्ति के सन्तुलन बिन्दु पर निर्धारित होती है। स्वर्णमान मे विनिमय दर की विशेषता यह है, कि उसमे इन स्वर्ण बिन्दुओं की सीमाओं के अन्दर ही परिवर्तन होना है। इसके पने परिवर्तन की कोई सम्भावना नहीं होती क्योंकि स्वर्ण बिन्दुओं पर विदेशी विनिमय की माग एवं पूर्ति की लोच पूर्ण लोचदार होती है। दूसरे शब्दा मे उससे अधिक परिवर्तन होने पर विदेशो मे भुगतान करने के लिए स्वर्ण धातु का प्रयोग होने लगता है विदेशी विनिमय की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। निम्नलिखित उदाहरण से स्वर्ण बिन्दुओं को अच्छी तरह समझा जा सकता है :

मान लीजिए अमेरिका और ब्रिटेन स्वर्ण मान पर आधारित हैं। यह भी मान लीजिए कि ब्रिटेन की 1 इकाई मुद्रा (पौण्ड) टकसाल मे 20 ग्रन सोने के बराबर है और अमेरिका की 1 इकाई मुद्रा (डालर) टकसाल मे 5 ग्रन सोने के बराबर है। इसलिए टकसाली विनिमय दर 1 पौण्ड=4 डालर होगा।

मान लीजिए कि किसी दिए हुए समय म अमेरिका के निर्यात आयात की अपेक्षा कम है। आयात के इस प्राधिक्य का भुगतान करने के लिए अमेरिका के व्यापारियों के सामने दो विकल्प होंगे (1) पौण्ड खरीदकर भुगतान करने का विकल्प तथा (2) स्वर्ण भेजकर भुगतान करने का विकल्प। अमेरिका मे पौण्ड की पूर्ति पौण्ड की माग से कम है (क्योंकि आयात अधिक एवं निर्यात कम है) इसलिए विनिमय दर अधिक होगी अर्थात् 1 पौण्ड के लिए 4 डालर से अधिक देना होगा (पौण्ड के खरीददारों के बीच प्रतियोगिता के कारण)। यदि व्यापारी सोना भेजना चाहें तो उसे ब्रिटेन भेजने मे बाधा, धीमा आदि के रूप मे कुछ खर्च भी उठाना पड़ेगा। मान लीजिए 1 पौण्ड व मूल्य का सोना भेजने मे उसे 1 डालर का खर्च उठाना पड़ता है। इसलिए अमेरिकी व्यापारी को ब्रिटेन मे एक पौण्ड का भुगतान करने म 4 डालर (1 पौण्ड के बराबर 20 ग्रन सोना खरीदने मे) + 1 डालर (भेजने का खर्च) अर्थात् 5 डालर लगाना पड़ता है। यदि अमेरिकी व्यापारी का बाजार मे 5 डालर से कम मे 1 पौण्ड मिल जाता है तो वह पौण्ड खरीदकर भुगतान करना चाहेगा क्योंकि इसमे उसे सोना भेजकर भुगतान करने की अपेक्षा लाभ है। यदि बाजार मे 5 डालर मे भी 1 पौण्ड नहीं प्राप्त हो रहा है अर्थात् 1 पौण्ड का 5 डालर से अधिक मूल्य हो जाता है तो व्यापारी सोना भेजकर भुगतान करेगा और पौण्ड की माग बिलकुल समाप्त हो जायेगी। इसलिए अमेरिका मे 1 पौण्ड की कीमत कभी भी 5 डालर से अधिक नहीं हो सकती। विनिमय दर 4=1 तथा 5=1

के बीच कही भी हो सकती है। $5=1$ स्वर्ण निर्यात बिन्दु है। यदि परिस्थिति इसके विपरीत हो और अमेरिका का निर्यात अधिक हो तथा आयात कम तो ब्रिटिश व्यापारी जो अमेरिका में 4 डालर के बराबर भुगतान करने के लिए 1 डालर का खर्च भी उठाना पड़ेगा। अर्थात् 1 पाउंड खर्च करके वह केवल $4-1=3$ डालर का भुगतान कर सकता है। विनिमय दर $4=1$ से कम होकर $3=1$ होने की प्रवृत्ति दिखाएगी परन्तु विनिमय दर इमसे नीचे नहीं जा सकती क्योंकि उस परिस्थिति में सोना भेजकर ही भुगतान होने लगेगा। अर्थात् विनिमय दर $3=1$ होत ही अमेरिका में स्वर्ण आयात प्रारम्भ हो जायगा। इसलिए यह स्वर्ण आयात बिन्दु कहा जाता है। अमेरिका का स्वर्ण निर्यात बिन्दु ब्रिटेन का स्वर्ण आयात बिन्दु होगा तथा अमेरिका का स्वर्ण आयात बिन्दु ब्रिटेन का निर्यात बिन्दु होगा।

इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण में अमेरिका और ब्रिटेन में उनकी मुद्राओं का टक्काली मूल्य अनुपात (4:1) ही उनका बीच की टक्काली विनिमय दर होगी। यदि अमेरिका का भुगतान सन्तुलन उत्तक विपक्ष में है तो विनिमय दर बढ़कर (5:1) होने की प्रवृत्ति रहेगी। जब विनिमय दर अधिकतम 5:1 हो जायेगी तो अमेरिका से सोना बाहर भेजा जाने लगेगा। यदि अमेरिका का भुगतान सन्तुलन पक्ष में है तो विनिमय दर घटकर 3:1 होने की प्रवृत्ति रखेगी। जब विनिमय दर न्यूनतम बिन्दु 3:1 हो जायगी तो ब्रिटेन से सोना आने लगगा। इस प्रकार विनिमय दर स्वर्ण निर्यात एवं स्वर्ण आयात बिन्दुओं के बीच ही परिवर्तित हो सकती है, इससे अधिक नहीं। वास्तविक विनिमय दर दोनों देशों की मुद्राओं की पारस्परिक मांग और पूर्ति की दशाओं द्वारा निर्धारित होगी। वास्तविक विनिमय दर मांग और पूर्ति के सन्तुलन बिन्दु द्वारा ही निर्धारित होगी। यहाँ यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि स्वयं स्वर्ण आयात एवं निर्यात बिन्दु भी परिवर्तित हो सकते हैं, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में सोना भेजने का खर्च कई कारणों से परिवर्तित हो सकता है।

पत्र मान के अन्तर्गत विनिमय दर (Rate of Exchange under Paper Standard)

पत्र मान व्यवस्था के अन्तर्गत मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनीय नहीं होती इसलिए किसी टक्काली विनिमय दर का प्रश्न नहीं उठता। यदि विदेशी विनिमय बाजार पर कोई नियन्त्रण न हो तो विनिमय दर में असीमित परिवर्तन होता है। नियन्त्रण रहित विनिमय बाजार से एवं अपरिवर्तनशील मुद्रा व्यवस्था में दो सिद्धान्तों का उल्लेख किया जाता है—(1) क्रय शक्ति समता सिद्धान्त (Purchasing Power Parity Theory) तथा (2) भुगतान सन्तुलन सिद्धान्त (The Balance of Payments Theory)

त्रय शक्ति समता सिद्धान्त (The Purchasing Power Parity Theory)

इस सिद्धान्त का प्रमुख आधार यह है कि मुद्रा की वाह्य त्रय शक्ति या वाह्य मूल्य उसकी आन्तरिक त्रय शक्ति पर निर्भर करता है। अतः जब दो देश अन्वितर्जनशील पत्र मुद्रा पर आधारित होते हैं तो उनके बीच विनिमय दर उनकी मुद्राओं की त्रय शक्ति द्वारा निर्धारित होती है। गुस्टव कसेल (Gustav Cassel) इस सिद्धान्त के प्रणेता माने जाते हैं। इनके अनुसार एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा से उनकी आन्तरिक त्रयशक्ति के अनुपात में बदली जायेगी। दूसरे शब्दों में विनिमय दर आवश्यक रूप से उनकी आन्तरिक त्रय शक्तियों के अनुपात को प्रकट करती है। (The rate of exchange between two currencies "must stand essentially as the quotient of the internal purchasing powers of these currencies" —Gustav Cassel) त्रय शक्ति समता सिद्धान्त को 'बाजार समता विनिमय दर' (Market par of exchange) भी कहा जाता है।

यदि रुपए की 1 इकाई भारत में दी हुई किस्म और गुण की वस्तुओं की 'क' मात्रा खरीद सकती है और वही मात्रा यदि अमेरिका में (गुण और किस्म के समान रहने पर) $\frac{1}{4}$ डालर से खरीदी जा सकती है तो 1 रुपया $\frac{1}{4}$ डालर के बराबर या 7 रुपया = 1 डालर होगा। यही भारत और अमेरिका के बीच विनिमय दर होगी। यदि किसी समय अमेरिका में डालर की त्रय शक्ति बढ़ जाय और रुपये की त्रय शक्ति भारत में पूर्ववत् रहे तो विनिमय दर उसी अनुपात में बढ़ जायेगी जिस अनुपात में डालर की त्रय शक्ति बढ़ी है। यदि मुद्राओं की त्रय शक्ति में परिवर्तन न हो तो विनिमय दर भी अपरिवर्तित रहेगी। यदि किसी कारणवश विनिमय दर बढ़ जाय अर्थात् 1 डालर का मूल्य 7 रुपए से अधिक हो जाय तो विनिमय बाजार में रुपए की कीमत कम हो जाने के फलस्वरूप भारत का निर्यात बढेगा और आयात कम होगा। अमेरिका में भुगतान अधिक प्राप्त होगा और दूसरी तरफ भारत को कम भुगतान करना होगा। विनिमय बाजार में भारत की मुद्रा (रुपया) की माग बढेगी और डालर की माग कम होगी तथा रुपए की पूर्ति कम होगी एवं डालर की पूर्ति बढेगी। परिणाम स्वरूप रुपये का मूल्य मुद्रा बाजार में पुनः बढ़ने लगेगा और विनिमय दर पुनः 7 रुपया = 1 डालर होने की प्रवृत्ति दिखाएगी। यदि रुपये का मूल्य विनिमय बाजार में किसी कारणवश बढ़ जाय तो विनिमय बाजार में माग और पूर्ति में इस प्रकार परिवर्तन होये कि विनिमय दर पुनः त्रय शक्ति समता सिद्धान्त पर पट्ट चलेगी।

इस सिद्धान्त से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यदि परिवहन व्यय तथा अन्य शर्तों पर ध्यान न दिया जाय तो किसी भी वस्तु की कीमत, त्रय शक्ति समता प्रकट करने वाली दर पर, सम्बन्धित देशों में समान होगी। परन्तु यह कथन

केवल उन्ही वस्तुओं के सदमं मे सत्य प्रतीत होता है जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय माग और पूर्ति है। ऐसी वस्तुएं जिनकी माग और पूर्ति देश की सीमा तक ही सीमित होनी - उनकी कीमतों मे विभिन्न देशों मे पर्याप्त अन्तर होता है। परन्तु मुद्रा की क्रय शक्ति की माप सभी वस्तुओं के आधार पर की जानी चाहिए। मुद्रा की सामान्य क्रय शक्ति निर्देशांक के महारे जानने की विधि अपनाई जानी है, परन्तु निर्देशांक केवल क्रय शक्ति के परिवर्तनों को ही प्रकट कर पाते हैं। मुद्रा की निरपेक्ष क्रय शक्ति जानने मे निर्देशांक असफल होत है। गुस्टव कंसल ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया और क्रय शक्ति के परिवर्तनों के आधार पर किसी निश्चित समय पर दो देशों की आधार भूत विनिमय दर ज्ञात किए जाने का सुझाव रखा। इसके लिए सामान्य आधार वर्ष मे दोनों देशों के बीच प्रचलित विनिमय दर को उस समय की आधार भूत विनिमय दर मान लिया जाता है। फिर जिस वर्ष की आधार भूत विनिमय दर को ज्ञात करना होना है उस समय के दोनों देशों के निर्देशांक निकाल लिए जाते हैं। जिस अनुपात मे निर्देशांक मे परिवर्तन हुआ होता है उमी अनुपात मे आधार वर्ष की आधार भूत विनिमय दर मे परिवर्तन करके वर्तमान आधार भूत विनिमय दर ज्ञात कर ली जाती है।

उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 1952 आधार वर्ष मे भारत और अमेरिका के निर्देशांक 100 थे और उस समय दोनों देशों के बीच विनिमय दर 5 रुपये = 1 डालर थी। यदि हमे 1961 मे विनिमय दर ज्ञात करना हो ना 1961 के निर्देशांक ज्ञान करन होंगे। मान लीजिए कि 1961 मे भारत का निर्देशांक 400 तथा अमेरिका का 200 है तो 1961 की आधार भूत विनिमय दर इस प्रकार ज्ञात की जायेगी

आधार वर्ष की विनिमय दर 5 = 1

परिवर्तित वर्तमान क्रय शक्ति 400 तथा 200

भारत मे $400 \times 5 = 2000$ की जा क्रय शक्ति होगी अमेरिका मे

वह 1×200 डालर की क्रय शक्ति होगी। इसलिए 2000 =

200 डालर के बराबर होगा और विनिमय दर 10 = 1 डालर होगी।

इस उदाहरण से स्पष्ट है कि किसी साम्य विनिमय दर के ज्ञात होने पर ही मौद्रिक इकाइयों की परिवर्तित क्रय शक्ति के आधार पर नई साम्य विनिमय दर ज्ञात हो सकती है। स्वयं श्री कंसल के शब्दों मे :

"It is only when we know the exchange rate which represents a certain equilibrium that we can calculate the rate which represents the same equilibrium at an altered value of the monetary units of the two countries"¹

1. "Money and Foreign Exchange after 1914", p. 142

प्रो० हैबरत्तर ने भी इस पर अपना विचार व्यक्त करते हुए निम्ना है कि ऋय शक्ति समता सिद्धान्त निरपेक्ष कीमत स्तरों पर (Absolute Levels of Prices) नहीं लागू किया जा सकता, केवल कीमत स्तर के परिवर्तनों पर लागू किया जा सकता है। हैबरत्तर के अनुसार "Cannot...be applied to absolute levels of prices but only to changes in the price levels"¹

ऋय शक्ति समता सिद्धान्त की आलोचनायें (Criticism of the Purchasing Power Parity Theory)

1 कौनसा कीमत स्तर (What price levels) : किसी देश की सामान्य कीमत स्तर सभी प्रकार की वस्तुओं की कीमतों के आधार पर ज्ञान किया जाता है परन्तु विदेशी मुद्रा की आवश्यकता केवल उन्हीं वस्तुओं के लेन देन के लिए होती है जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होती हैं। इसलिए विनिमय दर केवल इन्हीं वस्तुओं की कीमत से प्रभावित हो सकती है। कौनसी वस्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होगी यह स्वयं बहुत कुछ विनिमय दर पर निर्भर करता है। यदि इस सिद्धान्त में ऋय शक्ति माप का आधार अन्तर्राष्ट्रीय वस्तुओं को माना जाय तो पूरा सिद्धान्त एक रिक्त सत्यवाद (an empty truism) रह जाता है क्योंकि ऐसी वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय माग और पूर्ति होने के कारण उनकी कीमत स्वयं ही समान होने की प्रवृत्ति रखती है। यदि ऋय शक्ति माप का आधार घरेलू वस्तुओं या सभी वस्तुओं को बनाया जाय तो परिणाम और भी अविश्वसनीय होगा क्योंकि आंतरिक ऋय शक्ति और विनिमय दर में एक अनुपात में परिवर्तन नहीं होता। आंतरिक ऋय शक्ति एवं विनिमय दर के सम्बन्धों में जो परिवर्तन होता है वह आंशिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय वस्तुओं के घरेलू वस्तुओं की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण होने पर निर्भर करता है।

2 विनिमय दर पर माग का प्रभाव (Exchange Rate is affected by the change in one country's demand for the other country's products) : कीमत स्तर के परिवर्तन को ही ऋय शक्ति समता सिद्धान्त का केन्द्र बिन्दु माना गया है परन्तु कीमत स्तर के अपरिवर्तित रहने पर भी विनिमय दर, किसी एक देश में दूसरे देश की वस्तुओं की माग में वृद्धि या कमी होने से, परिवर्तित हो सकती है। प्रो० नर्वर्स ने इसी प्रकार का विचार व्यक्त करते हुए अपनी पुस्तक 'International Currency Experience' में लिखा है :

"The purchasing power parity approach, which uses price movements as the main criterion, tends to neglect the important conditions affecting the volume of demand, it treats demand simply

¹ "The theory of International Trade" p 35

as a function of price, leaving out of account the wide shifts in aggregate income and expenditure which occur in the business cycle and which lead to wide fluctuations in the volume and hence the value of foreign trade even if prices or price relationships remain the same "

3. एक पक्षीय अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों का प्रभाव (Effects of one sided International payments) : ऋण शक्ति समता सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी के लेन देन तथा ऋण सम्बन्धी सौदों के फलस्वरूप होने वाले विनिमय दर के परिवर्तनों को ध्यान में नहीं रखता। जब एक देश से पूंजी दूसरे देश में जाती है तो इसकी अन्तर्राष्ट्रीय मांग में वृद्धि होती है तथा उसकी कीमत दूसरी मुद्राओं में बढ़ जाती है, लेकिन इसका प्रभाव कीमन स्तर पर उसी समय नहीं पड़ता।

4 कीमन स्तर के अनुपात में विदेशी व्यापार में परिवर्तन का प्रभाव (Effect of a proportionate change in the terms of the change in price level) : यदि किसी देश के कीमन स्तर में तकनीकी विकास के कारण 10% कमी हो जाय और उसी समय विदेशी व्यापार उस देश के पक्ष में 10% और बढ़ जाय (जिससे उस देश के कुल विदेशी व्यापार के मूल्य में परिवर्तन न हो) तो विदेशी विनिमय बाजार प्रभावित नहीं होगा यद्यपि कीमन स्तर में परिवर्तन हो गया है।

5 केवल विनिमय दर के परिवर्तनों को ज्ञात करने के लिए उपयोगी (Useful only to know the changed exchange rate on the basis of changed price levels) : इस सिद्धान्त में निरपेक्ष विनिमय दर (Absolute exchange rate) को निर्धारित नहीं किया जाता। उसे मान लिया जाता है। केवल परिवर्तित कीमन स्तरों के आधार पर परिवर्तित विनिमय दर को ज्ञात किया जाता है।

6. विनिमय दर का कीमन स्तर पर प्रभाव (Price level is affected by exchange rate) : इस सिद्धान्त के अनुसार कीमन स्तर का प्रभाव विनिमय दर पर पड़ता है परन्तु विनिमय दर कीमन स्तर को प्रभावित नहीं करती। परन्तु कई कारणों से (सट्टा, पूंजी का स्थानान्तरण, व्यापार का विस्तार आदि) स्वयं विनिमय दर कीमन स्तर को प्रभावित करती है।

7 केवल दीर्घकालीन व्याख्या (A long term explanation) : श्रय-शक्ति समता सिद्धान्त विनिमय दर को दीर्घकालिक प्रवृत्ति की व्याख्या करता है परन्तु व्यवहार में अल्पकालीन विनिमय दर अधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उसके विस्तृत एवं गम्भीर परिणाम होते हैं।

उपरोक्त भालीचनाओ एव व्यावहारिक अनुभव के आधार पर क्रयशक्ति समता सिद्धान्त खरा नही उतरता । परन्तु इसका तात्पर्य यह नही है कि यह सिद्धान्त विस्तृत निरर्थक है । यह सिद्धान्त कुछ विशेष परिस्थितियों मे जहा पूँजी के लेन-देन न होते हो, जहा तकनीकी स्थिति तथा व्यापार-दशा (Terms of Trade) अपरिवर्तित रहे, सत्य प्रतीत होना है । इतना तो निश्चित रूप मे कहा जा सकता है कि विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारणों मे क्रयशक्ति या कीमत स्तर एक प्रमुख कारण है ।

भुगतान सतुलन सिद्धान्त (The Balance of Payments Theory)

इस सिद्धान्त के अनुसार विनिमय दर भुगतान सतुलन (Balance of Payments) द्वारा निर्धारित होती है । इस सिद्धान्त की यह मान्यता है कि हम विदेशों को उतना ही भुगतान कर सकते हैं जितना विदेशो से हमे प्राप्त होता है । दूसरे शब्दो मे इस सिद्धान्त का मौलिक आधार यह है कि निर्यातो से ही आयातो का भुगतान किया जाता है । दीर्घकालीन साम्य विनिमय दर उस बिन्दु पर होगी जहा भुगतान सतुलन साम्यावस्था मे होगा । यदि किसी समय किसी देश का भुगतान शेष सतुलन की स्थिति मे नहीं है तो विनिमय दर मे भी परिवर्तन होंगे । यदि भुगतान शेष पक्ष मे होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि उस देश को भुगतान करने की अपेक्षा पाना अधिक है । इसलिए उस देश की मुद्रा की माग, पूर्ति की अपेक्षा, अधिक है एव उसकी कीमत दूसरी मुद्रा के सन्दर्भ मे बढ रही है । भुगतान शेष विपक्ष मे होने पर उस देश की मुद्रा की कीमत दूसरे देश की मुद्रा के सन्दर्भ मे कम होगी । इस प्रकार इस सिद्धान्त के अनुसार आयात की अधिक आवश्यकता का परिणाम मुद्रा या चलन ह्रास (Currency Depreciation) के रूप मे सामने आता है और उसके कारण विनिमय दर मे वृद्धि हो जाती है (प्रत्यक्ष ढग) अर्थात् दूसरे देश की एक मुद्रा का मूल्य अपनी मुद्रा मे बढ जाता है । इस विनिमय ह्रास (Exchange Depreciation) के कारण सामान्य कीमत स्तर भी बढने लगता है ।

परन्तु जब तक विनिमय दर का पता न हो तब तक यह नही कहा जा सकता कि अमुक देश की लेनदारिया (receipts) तथा देनदारिया (payments) बराबर हैं क्योंकि दो देशो मे दो अलग-अलग मुद्राओ का प्रयोग होता है । विनिमय दर के माजूम होने पर एक देश अपने आयातो और निर्यातो की कीमत की तुलना कर सकता है । जिस दर पर आयातो और निर्यातो की कीमत बराबर होगी वही प्रचलित विनिमय दर होगी । लेकिन इस आयात और निर्यात मे स्वर्ण का लेन देन अथवा दीर्घकालीन ऋण का लेन-देन शामिल नही होता है । परन्तु दीर्घकालीन

अवस्था में आयात और निर्यात को संतुलित करने के लिए स्वर्ण या अल्पकालीन ऋण का लेन-देन सम्भव नहीं है इसलिए दीर्घकाल में विनिमय दर को साम्यावस्था बह होगी जहाँ आयातों और निर्यातों का संतुलन होगा।

भूतान संतुलन सिद्धांत की आलोचना (Criticism of the Balance of Payment Theory) :

इस सिद्धांत के अनुसार विनिमय दर में आयातों एवं निर्यातों में परिवर्तन होने पर ही विनिमय दर परिवर्तित होती है परन्तु वास्तव में विनिमय दर का परिवर्तन स्वयं आयातों और निर्यातों को परिवर्तित कर देता है और एक देश की मुद्रा की माँग और पूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय बाजार में बदल जाती है। इस प्रकार विनिमय दर स्वयं अपना सुधारक है।¹ इस सिद्धांत के अनुसार आयातों की अधिक आवश्यकता विनिमय ह्रास (Exchange Depreciation) को जन्म देती है परन्तु यह सिद्धांत इस तथ्य को भुला देता है कि किननी ही आवश्यकता क्यों न हो भुगतान करने के साधनों के अभाव में अधिक आयात नहीं किया जा सकता।

इन आलोचनाओं के बावजूद भी भुगतान संतुलन सिद्धांत में कुछ ऐसे तथ्यों की ओर संकेत किया गया है जिसके आधार पर विनिमय दर निर्धारण के माँग और पूर्ति सिद्धांत का विवेचन किया गया है। इन सिद्धांत ने भुगतान शेष आयात तथा निर्यात की ओर ध्यान आकृष्ट किया जो वास्तव में विदेशी विनिमय की माँग और पूर्ति का आधार है। इस सिद्धांत ने इस बात की ओर भी संकेत दिया है कि विनिमय दर निर्धारण भी सामान्य साम्य विश्लेषण (General Equilibrium Analysis) में शामिल है।

स्थायी, परिवर्तनशील, साम्य तथा पेंड विनिमय दरें

(Stable, Fluctuating, Equilibrium and Pegged Exchange Rates)

स्थायी विनिमय दर (Stable Exchange Rate) :

विनिमय दर के स्थायित्व को बनाये रखना प्रायः सभी देशों की मौद्रिक नीति का काफ़ी समय तक प्रमुख लक्ष्य रहा है। विनिमय दर के स्थायित्व के निम्न-लिखित लाभों के कारण इसे मौद्रिक नीति का अंग माना गया है —

1. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन (Encouragement to Foreign Trade) : विनिमय दर में उतार-चढ़ाव न होने के कारण विदेशी व्यापारियों को हानि की आशंका नहीं रहती है। उन्हें आयात और निर्यात करने से पूर्व ही यह पता हो

¹. ".....the rate of exchange provides its own corrective by re-adjusting the demand for and the supply of a currency in the exchange market."
—Prof S. M. Tiwary : *Money*, p. 202

जाता है कि जितना भुगतान देना और पाना होगा। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास इस बात को प्रमाणित करता है कि जब भी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव की स्थिति आई, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को घटका लगा। स्यायी विनिमय दर से सम्बद्ध देशों की मुद्रा की विस्तृत सर्वे स्वीकार्यता विदेशी व्यापार को बटा देनी है।

2. अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी का मुक्त प्रवाह (Free flow of international capital) : विनिमय दर में स्थायित्व होने के कारण एक देश से दूसरे देश में विनियोग पूँजी का स्वतन्त्रता पूर्वक लेन-देन किया जाता है क्योंकि ऋणदाता को यह विश्वास रहता है कि भविष्य में बिना हानि के वह अपनी पूँजी प्राप्त कर सकता है। ऋणी देश इनसे अपने विनियोगों में वृद्धि करता है और विनिमय दर बढ़ने (दूसरे देश की मुद्रा का मूल्य अपनी मुद्रा के सदमं में बढ़ने) की हानि की ओर से आश्वस्त रहता है।

3 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (International Co operation) : विनिमय दर के स्थिर रहने के कारण समान द्रव्य क्षेत्र व लोगों में सहयोग की भावना का विकास होता है। स्यायी विनिमय दर के प्रभाव में ऐसे क्षेत्रों में तनाव की स्थिति पैदा होना का भय ही सकता है। सभी देशों के विकास के लिए शांतिपूर्ण वातावरण लाभदायक होता है।

कठिनाइया (Difficulties) :

1 स्यायी विनिमय दर की नीति अपनाने का तात्पर्य, आन्तरिक कीमत, रोजगार तथा उत्पादन की नीति राष्ट्रीय हितों के अनुरूप रखने की स्वतन्त्रता का त्याग करना है। इसके अनुसार आंतरिक नीति में इन प्रकार परिवर्तन करना पड़ता है कि आंतरिक अर्थव्यवस्था पर बाह्य आर्थिक प्रभावों का पूर्ण प्रभाव पड सके। आधुनिक युग में प्रत्येक राष्ट्र अपने देश का अधिकतम आर्थिक बल्याण चाहता है और उसी के अनुसार अपनी मौद्रिक नीति निर्धारित करता है। इसलिए स्यायी विनिमय दर की नीति समय के अनुकूल नहीं है।

2. यह भी तर्क दिया जाता है कि विनिमय दर की स्थिरता की नीति न अपनाने पर भी भुगतान समुलन में क्षम्य की स्थिति लार्ई जा सकती है। वास्तव में विनिमय दर के परिवर्तन द्वारा भुगतान शप की कठिनाइयों से छुटकारा पाया जा सकता है।

3 आधुनिक युग में सभी अविक्तित देश विकास की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। प्रारम्भ में उन्हें विकास के लिए आयात भी अधिक करने होते हैं तथा मुद्रा-प्रसार की नीति अपनानी पड़ती है। इनके कारण जो विनिमय दर पर प्रभाव पड़ता है उसके फलस्वरूप विनिमय दर को स्थिर रखना व्यवहार में कठिन हो जाता है।

परिवर्तनशील विनिमय दर (Fluctuating Exchange Rate) :

यदि विनिमय बाजार में विदेशी विनिमय का अन्त-विनय स्वतन्त्रतापूर्वक किया जाता हो और मौद्रिक अविनारी विनिमय दर को प्रभावित करने का कार्य नहीं कर रहे हो तो विनिमय दर परिवर्तित होने के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता होनी है। इस प्रकार की व्यवस्था में न तो कोई निश्चित विनिमय दर (Fixed Exchange rate) होती है और न ही उसे स्थिर रखने की इच्छा। देश की मौद्रिक नीति भुगतान शेष की स्थिति से प्रभावित नहीं होती और उस पर बाह्य आर्थिक प्रभाव असर नहीं डालते। स्थिर विनिमय दर की कठिनाइयाँ ही परिवर्तनशील विनिमय दर की इच्छाइयाँ हैं। परिवर्तनशील विनिमय दर में पूर्ण को सन्तुलित होने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया जाना है। देश की मौद्रिक नीति को विदेशी प्रभावों से मुक्त रख कर देश के हितों को अनुकूल रखा जाता है।

परन्तु विनिमय दर के परिवर्तित होते रहने पर वे लाभ प्राप्त नहीं हो सकते जो विनिमय दर के स्थायी रहने पर प्राप्त होते हैं। विदेशी व्यापार, पूँजी का अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहाय्य का प्रभाव हो जाता है। प्रो० हेन्डरसन ने अपनी पुस्तक 'The Problem of Monetary Stabilisation' में लिखा है, "That fluctuating parities, by creating additional hazard and uncertainty, will be prejudicial to international trade"। जिस आंतरिक स्थिरता का दावा परिवर्तनशील विनिमय दर के अन्तर्गत किया जाता है वह भी सम्भव नहीं प्राप्त की जा सकती। यदि विनिमय दर में गम्भीर परिवर्तन हो जाय तो आंतरिक स्थिरता बनाए रखना असम्भव है। इसके अतिरिक्त विनिमय दर का परिवर्तन विदेशी विनिमय से सम्बन्धित किसी एक पक्ष के लिए अवश्य हानिकर होता है। जब तक विनिमय दर एक सीमा के अन्दर परिवर्तित होती है तब तक हानिकर नहीं कही जा सकती क्योंकि विदेशी व्यापारी हेजिंग के द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। एक देश से, जिसमें मुद्रा के ह्रास (Currency Depreciation) की आशंका हो, पूँजी दूसरे देश में प्रवाहित होने लगती है, और इनके बुरे परिणाम हो सकते हैं। दीर्घकालीन विदेशी विनिमयों को परिवर्तनशील विनिमय दर से विशेष हानि होनी है। इन कठिनाइयों के कारण स्वतन्त्रता पूर्वक परिवर्तित होने वाली विनिमय दर की तीव्र आलोचना की जाती है और इसे अविवेकपूर्ण कहा जा सकता है।

साम्य विनिमय दर (Equilibrium Exchange Rate) :

पूर्ण रूप से स्थिर और स्वतन्त्र रूप से परिवर्तनशील विनिमय दरों की जा कमियाँ हैं उनके कारण जिस ऐसी विनिमय दर की आवश्यकता महसूस की जाती है जिसे बिना विशेष कठिनाई के एक सीमा तक स्थायी भी रखा जा सके और भुगतान

शेष में मौलिक असंतुलन (Fundamental disequilibrium) की स्थिति में परिवर्तित करके भुगतान शेष के असंतुलन को ठीक भी किया जा सके। ऐसी विनिमय दर की ही साम्य विनिमय दर की सजा दी जाती है। प्रो० नवर्स ने साम्य विनिमय दर को परिभाषित करते हुए लिखा है, "The rate which, over a certain period, maintains the balance of payments in equilibrium without any net change in the international currency reserve" साम्य विनिमय दर में इच्छित स्थायित्व (desired stability) बनाये रखने का कार्य मौद्रिक अधिकारी विनिमय बाजार में नियंत्रण करके करते हैं और असंतुलन पैदा करने वाले कारणों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। मौद्रिक अधिकारी विनिमय बाजार को प्रभावित करने की नीति अपनाते हैं। साम्य विनिमय दर एक प्रकार से 'तटस्थ' होती है क्योंकि इस पर सम्यन्वित मुद्रा न तो अधमूल्यन होती है, न ही अधिमूल्यन (neither under valued nor over valued)। साम्य विनिमय दर में निम्न विशेषताएँ होनी चाहिए :—

1. विनिमय दर एक अतिसत आंतरिक स्थिरता के अनुकूल होनी चाहिए।
2. दीर्घकालिक दृष्टिकोण से स्थायित्व प्राप्त करने के प्रयत्न में देश के विदेशी विनिमय कोष और स्वर्ण कोष को समाप्त नहीं कर देना चाहिए। साथ ही मुद्रा सङ्कुचन की नीति अपना कर आंतरिक स्थिरता को खतरे में नहीं डालना चाहिए।
3. साम्य विनिमय दर का तात्पर्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बनावटी ढंग से लाभ या हानि पहुँचाना नहीं होना चाहिए अर्थात् मुद्राओं में अधमूल्यन की प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए।

यदि कोई विनिमय दर इन तीन शर्तों को पूरा नहीं करती तो नई विनिमय दर ज्ञात करनी होगी जो साम्य दर के रूप में स्थान ग्रहण करेगी। साम्य विनिमय दर का विचार विभिन्न देशों के जागरूक सहयोग (conscious cooperation) की नींव पर ही सफलतापूर्वक व्यवहार में लाया जा सकता है। इस प्रकार की विनिमय दर को लोचपूरण विनिमय दर (Flexible exchange rate) भी कहा जाता है।

पेगड विनिमय दर (Pegged Exchange Rate)

कभी कभी दो या अधिक देशों की आपसी विनिमय दर समझौते के आधार पर निश्चित कर दी जाती है और समझौते से सम्बन्धित पक्ष उस विनिमय दर को बनावटी तरीकों (artificial devices) से बनाए रखने को सहमत हो जाते हैं। इस प्रकार से निश्चित की गई विनिमय दर को पेगड विनिमय दर कहा जाता है। पेगड विनिमय दर को बहुत लम्बे समय तक बनाए रखना बहुत कठिन होने के कारण

'ऐडजस्टेबल पेग्ड रेट' (Adjustable Pegged Rate) अपनाता अधिक अछड़ा समझा जाता है। इस प्रकार की विनिमय दर में लम्बे समय तक पेग्ड विनिमय दर को बनाए रखने पर सहमति नहीं होती। जब कभी मौलिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है तो पेग्ड दर उसके अनुसार समायोजित (adjust) कर दी जाती है। परन्तु जब तक बिना विशेष हानि के कोई देश निश्चित दर को बनाए रखने में समर्थ है तब तक उसी दर को बनाए रखना है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समझौते के अनुसार इसी प्रकार की विनिमय दर सदस्य देशों द्वारा अपनाई गई है। परन्तु इस सबब में यह कठिनाई आती है कि सभी देश पेग्ड विनिमय दर को बनाए रखने का समान प्रयत्न नहीं करते। कोई देश अधिक त्याग करके भी इसे बनाए रखने का प्रयत्न करता है तो दूसरा थोड़ी सी कठिनाई होने पर ही नई पेग्ड दर अपनाता चाहता है। इस कठिनाई के कारण इस प्रकार की विनिमय दर कुछ देशों के लिए लाभदायक और कुछ के लिए हानिकर सिद्ध होने लगती है।

विनिमय दर में परिवर्तन

(Fluctuations in the Rate of Exchange)

विनिमय दर में होने वाले दुष्परिणामों से बचने के लिए प्रत्येक देश विनिमय दर के परिवर्तनों को सीमित रखना चाहता है। व्यवहार में नीचे दिये गये कारणों से विनिमय दर समय-समय पर परिवर्तित होती ही रहती है।

1. मांग और पूर्ति में परिवर्तन (Change in demand and supply of currency) यह स्पष्ट किया जा चुका है कि विनिमय दर विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। इसलिए इनमें से किसी एक में या दोनों में परिवर्तन होने से विनिमय दर का परिवर्तित होना स्वाभाविक है। किसी मुद्रा की मांग और पूर्ति निम्न कारणों से प्रभावित होती है :

मुद्रा-मांग के प्रभावक—

1. अन्य देशों की वास्तविक आय।
2. अन्य देशों की तुलना में उस देश की कीमत और लागत स्तर।
3. अन्य देशों की तुलना में उस देश की ब्याज दर।
4. विनिमय दर सम्बन्धी भविष्य का अनुमान।
5. उस देश की वस्तुओं के सम्बन्ध में रचि (Taste)।
6. उस देश तथा अन्य देशों की उत्पादकता तथा तुलनात्मक लागत का प्रभावित करने वाले अन्य तत्व।

किसी देश की मुद्रा की मांग को प्रभावित करने वाले उपरोक्त प्रभावकों में किसी एक में परिवर्तन होने पर विनिमय दर प्रभावित हो सकती है।

पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व—

उस देश की वास्तविक आय तथा ग्रन्थ नम्बर 2 से 6 तक, सभी प्रभावक जो माँग को प्रभावित करते हैं। इनमें से किसी में परिवर्तन होने पर विनिमय दर परिवर्तित होती है।

2. मौद्रिक नीति (Monetary policy) : यदि किसी देश की मौद्रिक नीति में परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसका प्रभाव उस देश के सम्पूर्ण आर्थिक ढाँचे पर पड़ता है। मुद्रा की शक्ति भी आधारभूत रूप से प्रभावित होती है। इन सबका प्रभाव मुद्रा की माँग और पूर्ति पर पड़ता है और विनिमय दर परिवर्तित हो जाती है।

3. पूँजी के लेन-देन में परिवर्तन (Changes in the flow of capital) . व्याज दर और राजनैतिक परिस्थितियाँ पूँजी के आदान-प्रदान को पर्याप्त अंश में प्रभावित करती हैं, जिनके फलस्वरूप विनिमय दर परिवर्तित हो जाती है।

4. सट्टे का प्रभाव (Speculative influences) : सट्टेवाजार में विदेशी विलो का प्रयत्न किया जाता है। किता मुद्रा के मूल्य में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के अनुमान पर सटोरिये उसकी माँग और पूर्ति को प्रभावित करते हैं जिसके कारण विनिमय दर परिवर्तित हो जाती है। अतःपणन के सौदे भी विनिमय दर को प्रभावित करते हैं।

5. प्राकृतिक कारण (Natural reasons) : कभी-कभी प्राकृतिक कारणों से देश के उत्पादन में कमी हो जान से उसका प्रभाव विनिमय दर पर पड़ सकता है।

6. सामयिक परिवर्तन (Seasonal fluctuations) . कुछ देश ऐसे होते हैं जिनका कुछ महीनों में निर्यात अधिक होता है और कुछ महीनों में आयात। इसलिए विनिमय दर में भी सामयिक परिवर्तन होता रहता है।

कुछ अन्य शब्द (Few Other Terms)

अन्तर्पण (Arbitrage)

जब कभी विभिन्न देशों के बीच की विनिमय दरों में अन्तर (Discrepancy) पैदा हो जाता है तो अन्तर्पण की प्रक्रिया उसे ठीक करने में सहायक होती है। सभी देशों की विनिमय दरें परस्पर सम्बन्धित होती हैं। किसी कारण से यदि किसी देश की विनिमय दर परिवर्तित हो जाती है तथा अन्य देशों से उसका सम्बन्ध वैसा ही रहता है तो अन्तर्पण प्रारम्भ हो जाता है और विनिमय दर पुनः पूर्व स्तर पर आ जाती है। लंदन के लिए भारत, ब्रिटेन तथा अमेरिका की विनिमय दरों का

एक निश्चित सम्बन्ध मान लीजिए । यदि पौंड भारत में महंगा पड़ने लगे और भारत तथा ब्रिटेन के बीच की विनिमय दर ब्रिटेन के पक्ष में बदल जाय परन्तु भारत तथा अमेरिका एवं ब्रिटेन तथा अमेरिका के बीच की विनिमय दरें पूर्ववत् रहे, तो ऐसी अवस्था में डालर द्वारा पौंड, पौंड द्वारा रुपया और रुपए द्वारा डालर खरीदने में विदेशी विनिमय का लेन-देन करने वालों को लाभ होगा । परन्तु इस प्रक्रिया में रुपए की मांग बढ़ने लगेगी और पौंड तथा डालर, एवं रुपए और डालर के सम्बन्धों में भी परिवर्तन प्रारम्भ हो जायगा । पुनः इन मुद्राओं की विनिमय दरें समायोजित हो जायेंगी ।

अग्रिम विनिमय (Forward Exchange) :

विनिमय दर में समाहित परिवर्तनों की हानि से बचने के लिए वे व्यापारी जिन्हें भविष्य में भुगतान करना होता है, अग्रिम विनिमय खरीदते हैं तथा वे व्यापारी जिन्हें भविष्य में भुगतान प्राप्त होता है, अग्रिम विनिमय बेचते हैं । भुगतान कर्ता विनिमय महंगा होने की हानि से तथा भुगतान पाने वाला विदेशी विनिमय सस्ता होने की हानि से बचना चाहता है । अग्रिम विनिमय के सौदे पहले ही तय कर लिए जाते हैं कि अमुक तिथि पर अमुक मात्रा में विदेशी विनिमय अमुक दर पर बेचा या खरीदा जायगा । अग्रिम विनिमय का सौदा करने में जो खर्च है वह एक प्रकार से भविष्य की जोखिम से बचने की कीमत है ।

ऐसी परिस्थितियों में जहाँ विनिमय दर में अधिक परिवर्तन होते हैं, अग्रिम विनिमय के सौदे लाभप्रद होते हैं । यह स्वर्ण-मान की अपेक्षा पत्र-मान में अधिक लाभप्रद है । प्रथम महायुद्ध के बाद इन प्रकार के सौदे बहुत किए जाते थे परन्तु द्वितीय महायुद्ध के बाद जब से विनिमय नियंत्रण की नीति अपनाई जाने लगी है, इस प्रकार के सौदों का महत्व कम हो गया है ।

अग्रिम विनिमय दर अग्रिम विनिमय की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है । अग्रिम विनिमय दर टी० टी० दर पर बट्टा (Discount) या नजराना (Premium) के रूप में सकेत की जाती है । बट्टा अथवा प्रीमियम व्याज की दरों पर आधारित होता है । अग्रिम विनिमय की मांग बढ़ने से प्रीमियम बढ़ता है या बट्टा कम होता है । इसके विपरीत अग्रिम विनिमय की पूर्ति अधिक होने की स्थिति में प्रीमियम कम होता है अथवा बट्टा बड़ जाता है ।

विदेशों में भुगतान का तरीका (The Procedure of Foreign Payments)

विदेशों में किए जाने वाले भुगतानों को निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जा सकता है । यहाँ पर हम इन श्रेणियों में विदेशी भुगतान सम्बन्धी तरीकों का उल्लेख करेंगे ।

व्यक्तिगत भुगतान तथा यात्री व्ययों का भुगतान (Personal Remittances and Tourist Expenditures)

1. मनीऑर्डर (Money Order) :

जब किसी व्यक्ति को विदेशों में किसी अल्प राशि का भुगतान करना होता है तो मनीऑर्डर भेज कर भुगतान कर सकता है। प्रत्येक देश द्वारा मनीऑर्डर द्वारा भुगतान करने की कोई सीमा भी निश्चित कर दी जाती है। यदि विनिमय नियंत्रण की नीति अपनाई जाती हो तो नियंत्रण अधिकारी की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। इस तरीके द्वारा भुगतान प्रायः विदेशों से पुस्तकें मगाने या मंगजीन आदि का वार्षिक चन्दा देने में हाता है।

2. यात्री-चेक (Traveller's Cheque) :

यात्री-चेको द्वारा विदेशी यात्रियों को बड़ी सुविधा रहती है। विदेश जान वाला व्यक्ति अपने बैंक से निश्चित रकम का यात्री-चेक खरीद लेता है। यह यात्री-चेक बैंक अपनी विदेश स्थित शाखा या प्रतिनिधि बैंक के नाम लिखता है। यात्री अपने गन्तव्य स्थान पर इस चेक को भुना कर अपना कार्य कर सकता है। यात्री-चेको का प्रयोग सुविधाजनक और सुरक्षित होता है। बड़े बैंकों के यात्री-चेक तो नोट की तरह ही प्रयोग किए जा सकते हैं क्योंकि इसे दूसरे देश के व्यापारी-होटल आदि नि सफाच स्वीकार कर लेते हैं। व्यापारी, होटल या यात्री-कार्यालय उस समय प्रचलित विनिमय दर पर उसे भुनाते हैं। यात्री-चेक बेचने वाला बैंक इस कार्य के लिए कुछ शुल्क लेता है।

3. यात्री साख पत्र (Traveller's Letter of Credit) :

जब किसी व्यक्ति को कई देशों की ओर अधिक समय तक यात्रा करनी होती है तो उसे यात्री चेक की अपेक्षा यात्री साख पत्र ले जाने में अधिक सुविधा और सुरक्षा रहती है। यात्री साख पत्र भी अपने बैंक से खरीदा जाता है। इसे बेचने वाला बैंक अपनी शाखाओं या प्रतिनिधि बैंकों के नाम लिखता है। साख पत्र की सूचना बेचने वाला बैंक अपनी शाखाओं और प्रतिनिधि बैंकों को भी भेज देता है। साख पत्र बेचने वाले बैंक के देश में प्रचलित मुद्रा में लिखा जाता है। जब यात्री विदेश में स्थित शाखा या प्रतिनिधि बैंक के पास उस देश की मुद्रा प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करता है तो वह उसे इच्छित माना में मुद्रा देकर साख पत्र पर लिख देता है। उसी साख पत्र को दूसरे देश में सम्बन्धित शाखा या प्रतिनिधि बैंक के पास प्रस्तुत करने पर फिर यात्री को मुद्रा प्राप्त हो जाती है और यह कम साख पत्र की कुल रकम प्राप्त हो जाने तक चलता रहना है। भुगतान करने वाली शाखाएँ या बैंक बेचने वाले को भी सूचित करते हैं। साख पत्र प्रयोग करने वाले यात्रियों को अपने साथ अपने हस्ताक्षर तथा फोटो युक्त परिचय पत्र भी रखना पड़ता है।

व्यापारिक भुगतान (Commercial Payments)

1. विनिमय पत्र द्वारा भुगतान (Payments through Bill of Exchange) : इस पद्धति का प्रयोग प्रथम महायुद्ध के पूर्व प्रायः सामान्य था। इस पद्धति में भुगतान पाने वाले व्यापारी को भुगुमा बनना पड़ता है। भुगतान पाने वाला भुगतान करने वाले को निश्चित समय बाद निश्चित रकम भुगतान करने का आदेश देता है। इस प्रकार का विनिमय पत्र लिख कर भुगतान पाने वाला माल से सम्बन्धित अधिकार पत्र बिल से सलग्न कर देता है एवं अपने बैंक से भुना (Discount) लेता है और उसे अपनी मुद्रा में भुगतान प्राप्त हो जाता है। बिल डिस्टाउन्ट करने वाला बैंक उस बिल को विदेश स्थित अपनी शाखा या प्रतिनिधि बैंक के पास भेज देता है। शाखा या प्रतिनिधि बैंक उस बिल को भुगतान करने वाले के पास प्रस्तुत करता है और वह अपनी स्वीकृत बिल पर अंकित कर देता है। यदि विनिमय पत्र की शर्तों के मुताबिक अधिकार पत्र स्वीकृति पर मिलने होते हैं तो अधिकार पत्र उसी समय दे दिया जाता है। यदि शर्तों के अनुसार अधिकार पत्र भुगतान पर मिलने होते हैं तो अधिकार पत्र भुगतान प्राप्त होने के बाद दिए जाते हैं। भुगतान तिथि पर भुगतान करने वाला अपनी मुद्रा में भुगतान कर देता है। इस प्रक्रिया में भुगतान पाने वाले देश के बैंक के "विदेशी पावने" में वृद्धि हो जाती है। भविष्य में जब इसी बैंक को दूसरे देश में भुगतान करना होता है तो इसका प्रयोग किया जाता है।

2. बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान (Payment through Bank draft) : इस प्रणाली के अनुसार भुगतान करने वाले को भुगुमा बनना होता है। भुगतान करने वाला अपने बैंक से ड्राफ्ट खरीद लेता है। ड्राफ्ट बेचने वाला बैंक अपनी विदेश स्थित शाखा या प्रतिनिधि बैंक को आदेश देता है कि वह उसमें लिखित रकम, लिखित व्यक्ति या उसके आदेशानुसार अन्य व्यक्ति को दे देवे। यह ड्राफ्ट भुगतान करने वाला भुगतान पाने वाले के पास भेज देता है और पाने वाला उसका भुगतान सम्बन्धित शाखा या बैंक से प्राप्त कर लेता है।

3. साख पत्र (Letter of Credit) : साख पत्र का प्रयोग व्यापारियों द्वारा उस समय किया जाता है जब तत्काल भुगतान की आवश्यकता होती है। आयात कर्ता अपने बैंक से निश्चित रकम का साख पत्र प्राप्त करता है और निर्यात कर्ता के पास भेज देता है। साख पत्र बेचने वाला बैंक भी अपनी विदेश स्थित शाखा या प्रतिनिधि बैंक को इस बात की सूचना भेज देता है। निर्यात कर्ता माल निर्यात करते ही सम्बन्धित अधिकार पत्र शाखा या प्रतिनिधि बैंक को भौतिक भुगतान प्राप्त कर लेता है।

4. मेल ट्रान्सफर (Mail Transfer) : यह तरीका काफी सरल है। भुगतान करने वाला अपने बैंक के पास भुगतान की रकम जमा कर देना है और उसे यह आदेश देता है कि अमुक देश के अमुक बैंक में अमुक व्यक्ति के खाते में वह रकम जमा करनी है। भुगतान कर्ता का बैंक विदेश स्थित अपनी शाखा या प्रतिनिधि बैंक को उस व्यक्ति के खाते में रकम जमा कराने का आदेश देता है। शाखा या प्रतिनिधि बैंक रकम जमा करा कर भुगतान पाने वाले को सूचित कर देते हैं। भुगतान कर्ता का बैंक यह आदेश डाक द्वारा भेजता है जिसमें अनिश्चित समय लग सकता है। यदि समय की अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए भुगतान कर्ता निश्चित समय में भुगतान हो जाने की गारण्टी चाहता है तो गारण्टी सहित मेल ट्रान्सफर (Guaranteed Mail Transfer) की व्यवस्था की जाती है और इसके लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है।

भुगतान कर्ता बैंक यदि उपरोक्त सूचना तार द्वारा भेजता है (ग्राहक के आदेश पर) तो इसे T. T. या टेलीग्राफिक ट्रान्सफर कहते हैं और इसका और भी अधिक शुल्क देना पड़ता है।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संकेत

1. स्वर्ण बिन्दु क्या है? क्या विनिमय दर इन बिन्दुओं से आगे जा सकता है? यदि हाँ तो कब और कैसे? विवेचना कीजिए।

(राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल, 1964; 1967)

[संकेत—स्वर्ण मान पर आधारित दो देशों की विनिमय दर टुकसाली समानता दर सिद्धान्त द्वारा निश्चित होती है और स्वर्ण बिन्दुओं के बीच ही रहती है, इसे उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। बताइये कि विनिमय दर साधारणतया इन बिन्दुओं से आगे नहीं जा सकता।]

2. ऋय-शक्ति समता सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

(राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल, 1966)

(आगरा, 1968)

अथवा

विदेशी विनिमय से सम्बन्धित ऋय-शक्ति-समता सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं? इस समता से यह दर कब भिन्न होती है?

(राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल, 1962)

[संकेत—प्रथम भाग में ऋय शक्ति समता सिद्धान्त की उदाहरण देकर विस्तृत व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में इस सिद्धान्त की मुख्य आलोचनाओं का विवेचन कीजिए।]

3. विदेशी विनिमय दरों के भुगतान सतुलन सिद्धान्त का वर्णन कीजिए ।

(राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल, 1968)

[सकेत—प्रथम भाग में विनिमय दरों के भुगतान सतुलन सिद्धान्त का विस्तृत विवेचन कीजिए । दूसरे भाग में संक्षेप में उसकी आलोचना कीजिए ।]

4. विभिन्न देशों में जहाँ पत्र-मुद्रा-मान का चलन हो, विनिमय दरों के निर्धारण की सम्पूर्ण विवेचना कीजिए ।

(राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल, 1969)

[सकेत—प्रपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा-मानों के अन्तर्गत दो देशों के बीच विनिमय दर का निर्धारण दो सिद्धान्तों—क्रय-शक्ति-समता सिद्धान्त तथा भुगतान सतुलन सिद्धान्त-द्वारा होता है । दोनों सिद्धान्तों की उदाहरणों सहित संक्षिप्त व्याख्या कीजिए और उनकी आलोचना कीजिए ।]

5. "निर्यात, आयातों का भुगतान करते हैं ।" स्पष्ट कीजिए कि यह कैसे होता है । अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में मुद्रा क्या पाठं अदा करती है ?

(राजस्थान बी० काम०, 1962) (आगरा, 1962)

[सकेत—प्रथम भाग में विदेशी विनिमय के भुगतान सतुलन सिद्धान्त की सविस्तार व्याख्या कीजिए । दूसरे भाग में बताइये कि अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में मुद्रा का क्या योगदान है ।]

भुगतान संतुलन (Balance of Payments)

Miss Prism Cecily, you read your Political Economy in my absence The chapter on the fall of the rupee you may omit It is somewhat too sensational Even these metallic problems have their melodramatic side.

Oscar Wilde

भुगतान-संतुलन एक ऐसा विवरण (Statement) है जिसमें किसी देश के विभिन्न मदों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों का ब्यौरेवार चिट्ठा तैयार किया जाता है। यह विवरण एक निश्चित अवधि (प्रायः एक वर्ष) के लिए होता है।¹ इस विवरण के अन्तर्गत वे सभी मदें (items) सम्मिलित होती हैं जो किसी एक देश तथा अन्य देशों के बीच भौतिक भुगतानों को जन्म देती हैं। इस प्रकार भुगतान संतुलन किसी देश द्वारा समस्त पाए जाने वाले और दिए जाने वाले भुगतानों की एक सूची है।

इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना आवश्यक है कि भुगतान संतुलन देशों के बीच होने वाले वर्तमान भुगतानों (Current Flows) को ही सम्मिलित करता है। एक प्रकार से भुगतान संतुलन विवरण (Balance of Payments Statement) को आय-विवरण तो कहा जा सकता है परन्तु आवधिक चिट्ठा (Balance Sheet) नहीं कहा जा सकता है।

भुगतान संतुलन किन्हीं दो देशों के बीच के भुगतान सम्बन्धों (Payments relationship) को ही नहीं बल्कि एक देश तथा 'अन्य सभी देशों के बीच के भुगतान सम्बन्धों को भी दर्शाता है। भुगतान संतुलन विवरण में सम्मिलित सभी मदें, किसी मुद्रा की विनिमय बाजार में की जाने वाली मांग और पूर्ति की, स्रोत होती

¹ "The balance of international payments is a comprehensive summary of the international transactions of a country in a given period (usually a year)".

हैं, इसलिए वे अन्तर्राष्ट्रीय ऋण (international indebtedness) को आघार होती हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों को जन्म देने वाली जिन मदों को भुगतान सतुलन में सम्मिलित किया जाता है, उन्हें मुख्य रूप से दो भागों में रखा जाता है :

1. चालू आदान-प्रदान (Current Account) *
2. पूंजीगत आदान प्रदान (Capital movements)

चालू आदान प्रदान (Current Account)

1. माल का आयात एव निर्यात (Import Export of merchandise) :

जब कोई देश किसी अन्य देश से कोई वस्तु मंगाता है तो उसे विदेशों में भुगतान करना होता है और उसकी विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाती है। दूसरी ओर जब वह देश निर्यात करता है तो उसे विदेशों से भुगतान प्राप्त होता है और उसकी विदेशी विनिमय की पूर्ति बढ़ जाती है। भुगतान सतुलन में निर्यातों को f. o b तथा आयातों को c. i. f कीमत पर सम्मिलित किया जाता है। सरकारी और व्यापारी आयातों और निर्यातों को अलग-अलग दिखाया जाता है।

2. विनियोगों पर आय, ब्याज, लाभांश आदि (Income on Investments—Interests, dividends, etc)

भुगतान सतुलन विवरण में सरकारी ऋणों के ब्याजों और लाभांशों की व्यापारिक ऋणों के ब्याजों एव लाभांशों से पृथक दिखाया जाता है। सरकारी और व्यापारिक विभाजन के साथ अल्पकालीन और दीर्घकालीन के रूप में भी ब्याजों और लाभांशों को विभाजित किया जा सकता है। जो ब्याज और लाभांश हमारी विदेशी विनिमय की पूर्ति बढ़ाते हैं उन्हें 'पावना' (credit item) के अन्तर्गत रखा जाता है। इसके विपरीत जिस ब्याज और लाभांश से हमारी विदेशी विनिमय की मांग बढ़ती है उसे 'देना' (Debit item) के अन्तर्गत रखा जाना है।

3. यात्री व्यय (Travellers' Expenditure) :

आधुनिक युग में विदेशों में भ्रमण करना निरंतर बढ़ता जा रहा है। विदेश से यात्रियों को आकर्षित करने के अनेक प्रयत्न किये जा रहे हैं। विदेश भ्रमण में सांस्कृतिक सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में तो लाभ होता ही है, इसमें विदेशी विनिमय की प्राप्ति भी होती है। विदेशों से आने वाले व्यक्ति अपने देश की वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं। यह एक प्रकार से विदेशों द्वारा किए जाने वाले आयात के समान है और अपने लिए निर्यात के समान। इसी प्रकार अपने देश से विदेशों में जाने वाले यात्री वहाँ उनकी सेवाओं और वस्तुओं का उपयोग करते हैं।

पह अपने देश के लिए आयात के समान है। स्पष्ट है कि विदेश से आने वाले अपने देश की मुद्राओं द्वारा हमारी मुद्रा खरीदेंगे। हमारे विदेशी 'पावने' में वृद्धि होगी, एव विदेश जाने वाले अपने देश के निवासी दूसरे देश की मुद्रा ले जावेंगे। हमारा विदेशी 'देना' बढ़ेगा। इन भुगतानों का परिणाम आने-जाने वालों की सव्या, आय, कीमत स्तर आदि पर निर्भर करेगा।

4. परिवहन तथा अन्य व्यय (Transportation and other charges) :

जब कोई देश दूसरे देशों को माल भेजता है या दूसरे देश से माल मंगाता है तो उसे परिवहन सम्बन्धी खर्च करने पड़ते हैं। माल के लान और ले जाने के कार्य में सभी देशों की जहाजरानी लगी हुई है। जब विदेश के व्यापारी हमारे देश की जहाजों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें हमारे देश की मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है। उसी प्रकार यदि माल का बीमा हमारे देश की कम्पनियों से कराते हैं तो प्रीमियम भी हमारे देश की मुद्रा में चुकाना पड़ता है। इस प्रकार वे अपनी मुद्रा के बदले हमारी मुद्रा खरीदते हैं और हमारा 'पावना' बढ़ता है। इसके विपरीत जब हम उनकी जहाजों और बीमा कम्पनियों का प्रयोग करते हैं तो हमें उनकी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है और हमारा 'देना' बढ़ता है। इसी प्रकार जब विदेशी हमारे देश की वित्तीय संस्थाओं का प्रयोग करते हैं तो हमारी विदेशी वित्तिय की प्राप्ति बढ़ती है और जब हम विदेशी बैंकों आदि की सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमारा 'देना' बढ़ जाता है।

5. प्रतिफल रहित भुगतान (Unrequitted Payments) :

अभी तक हमने जिन मदों का वर्णन किया है उनके दो पक्ष होते हैं। जब हम भुगतान करते हैं तो बदले में वस्तुएँ या सेवाएँ प्राप्त करते हैं। परन्तु कुछ प्रतिफल रहित (बदले में कुछ प्राप्त किए बिना) भुगतान भी किए जाते हैं। किसी देश में जो दूसरे देश के नागरिक होते हैं वे अपने सम्बन्धियों को जो रकम भेजते हैं वह इसी प्रकार का भुगतान है। इसी प्रकार किसी देश के नागरिकों या सरकार द्वारा दूसरे देश को जो दान और सहायता दी जाती है, एक प्रतिफल रहित भुगतान है। युद्ध आदि के हर्जाने के रूप में किए जाने वाले भुगतान भी इसी श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं।

पूँजीगत आदान-प्रदान (Capital Movements)

1. दीर्घावधि पूँजी का लेन-देन (Long-term Capital movements)

पूँजी का लेन देन सरकारों तथा व्यापारियों के बीच होता है। दीर्घावधि पूँजी का लेन-देन ऋणों और विदेशी व्यापारिक संस्थानों के अगुओं या ऋण पत्रों के

माध्यम से होता है। जब कोई देश किसी अन्य देश की व्यापारिक संस्थाओं के अथवा ऋणपत्र खरीदते हैं तो उस देश की मुद्रा की माँग बढ़ जाती है और खरीदने वाले देश का विदेशी 'देना' बढ़ जाता है। जब दूसरे देश से पूँजी आती है तो विदेशी 'पावना' बढ़ जाता है और दूसरे देश की मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है।

2. अल्पावधि पूँजी का लेन देन (Short-term capital movements) :

अल्पावधि पूँजी दो प्रकार से लेन देन की जाती है। प्रथम जब किसी देश की सरकार या व्यापारी वर्ग खाड़े समय के लिए दूसरे देश में पूँजी लगाते हैं या ऋण देते हैं। ऐसी अवस्था में उस देश के विदेशी विनिमय की माँग और पूर्ति पर उसी प्रकार प्रभाव पड़ता है जैसा दीर्घावधि लेन-देन की स्थिति में पड़ता है। दूसरे रूप में अल्पावधि पूँजी का लेन-देन उस समय पैदा होता है जब चालू आदान प्रदान तथा दीर्घावधि पूँजी के लेन-देन के दोनो पक्ष (Debit and Credit) एक निश्चित समय में बराबर नहीं होते। यही अंतर एक प्रकार से अल्पावधि पूँजी का आदान-प्रदान या आयात निर्यात कहा जाता है। यदि 'पावना' अधिक है और 'देना' कम है तो हम एक प्रकार से विदेशों से अल्पावधि पूँजी प्राप्त करते हैं और इसके विपरीत जब 'देना' अधिक और 'पावना' कम है तो एक प्रकार से अल्पावधि पूँजी देते हैं।

3. स्वर्ण का आदान-प्रदान (Gold movement) :

चालू आदान-प्रदान तथा दीर्घावधि पूँजी के लेन-देन के दोनो पक्षों के अंतर को निपटाने के लिए स्वर्ण का आयात-निर्यात भी किया जाता है; परन्तु आजकल स्वर्ण का लेन-देन न करके अल्पावधि पूँजी के लेन-देन द्वारा इस अंतर का निपटारा करने का प्रयास किया जाता है।

भुगतान संतुलन विवरण तैयार करने के लिए कई स्रोतों से आकड़े एकत्र किए जाते हैं इसलिए आकड़ों में कभी-कभी अंतर पाया जाता है। इस अंतर के कारण भुगतान संतुलन के 'पावनों' एवं 'देनों' का योग असमान हो जाता है। इस असमानता को 'भूल-चूक' (Errors and omissions) की मद के अन्तर्गत दिखाते हैं। कभी-कभी किसी वस्तु या सेवा का भूल से भुगतान संतुलन में उल्लेख नहीं हो पाता; इस कारण भी दोनो पक्ष बराबर नहीं हो पाते। इन्हें भी 'भूल-चूक' के अन्तर्गत दिखाया जाता है। भुगतान संतुलन विवरण की मदों का एक नमूना अगले पृष्ठ पर दिया जा रहा है।

भुगतान सतुलन विवरण
वर्ष (.....)

करोड रुपयों में

क—चालू खाता (Current Account)		पावना +	देना —	शेष
1. वस्तुएँ				
	(i) निजी क्षेत्र			
	(ii) राजकीय क्षेत्र			
2. भ्रमण				
3. परिवहन				
4. बीमा				
5. ब्याज तथा लाभांश				
6. अन्य				
7. दान आदि				
	(i) निजी क्षेत्र			
	(ii) राजकीय क्षेत्र			
	भूल-चूक			
	योग			
ख—पूँजी खाता (Capital Account)				
1. दीर्घावधि				
	(i) निजी क्षेत्र			
	(ii) राजकीय क्षेत्र			
2. अल्पावधि				
	(i) निजी क्षेत्र			
	(ii) राजकीय क्षेत्र			
	भूल-चूक			
	योग			

भुगतान सतुलन की माल के अतिरिक्त सभी मदें 'अदृश्य मदें' (invisible items) कही जाती हैं। माल के आयात-निर्यात को दृश्य मदें (visible items) कहते हैं।

भुगतान सतुलन तथा व्यापार सतुलन (Balance of Payment and Balance of Trade)

व्यापार सतुलन का सम्बन्ध केवल माल के आयातों तथा निर्यातों से होता है। इन आयातों और निर्यातों को 'दृश्य मदें' (Visible items) की संज्ञा दी जाती है एवं ये ही भुगतान सतुलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। भुगतान सतुलन जैसा पहले बताया जा चुका है, किसी देश की सम्पूर्ण देनदारियों और लेनदारियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है। इसमें विदेशी विनिमय से सम्बन्धित 'दृश्य मदें' (Visible items) तथा 'अदृश्य मदें' (Invisible items) सभी शामिल होती हैं।

भुगतान सतुलन तो सदैव सतुलित होता है परन्तु व्यापार सतुलन के दोनों पक्ष किसी निश्चित अर्थात् मे एक समान नहीं भी हो सकते हैं। निर्यात अधिक होने अर्थात् लेनदारिया (Credit) अधिक होने पर इसे कई लोग 'पक्ष मे' (Favourable) और आयात अर्थात् देनदारिया (Debit) अधिक होने पर विपक्ष मे (unfavourable) कहते हैं। परन्तु वास्तव म यह विचार भ्रामक है क्योंकि प्रत्येक सौदे के दो पक्ष होते हैं - प्रत्येक आयात एक प्रकार का निर्यात भी है (Every import is at the same time an export)। जैसे भारत का आयात किसी न किसी देश का निर्यात व निर्यात किसी न किसी देश का आयात है। यदि सम्पूर्ण सत्सार को एक मानकर देखें तो सम्पूर्ण आयात सम्पूर्ण निर्यात के बराबर होगा। इसके अनिश्चित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतो मे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सौदे दोनो पक्षो (आयातकर्ता एव निर्यातकर्ता) को लाभदायक होते हैं। किन्ही परिस्थितियो मे आयात निर्यात की अपेक्षा राष्ट्रीय हितो की अधिक वृद्धि करता है।

व्यापार सतुलन पर सर्वाधिक प्रभाव किसी देश के आयातो के कीमत-तल एव निर्यातो के कीमत-तल के सम्बन्धो का पडता है। इन्हे ही व्यापार की दशा (Terms of Trade) कहते हैं। यदि निर्यातो का कीमत-तल, आयातो के कीमत-तल की तुलना मे ऊचा है तो व्यापार दशा (Terms of Trade) पक्ष मे तथा इनके विपरीत यदि आयातो का कीमत-तल निर्यातो के कीमत-तल की तुलना मे ऊचा ह तो व्यापार दशा (Terms of Trade) विपक्ष मे कही जाती है। यदि व्यापार दशा किसी देश के विपक्ष मे जा रही है तो इसका तात्पर्य है कि उसे लगा-तार एक दिए हुए आयात के लिए अधिक निर्यात करना होगा। किसी देश के आयातो मे यदि खाद्य एव कच्ची सामग्रिया अधिक हैं तो आयातो मे कमी करना अत्यन्त कठिन हो जाता है और व्यापार दशा प्राय उसके विपक्ष मे होती है।

भुगतान सतुलन सदैव सतुलित होता है
(Balance of Payments always balances)

पूर्ण रूप से तैयार किया गया भुगतान सतुलन, जिसमे चालू और पूजो खातों की सभी लेनदारिया और देनदारिया ध्यान मे रखी गई हो, अवश्य सतुलित होगा। दूसरे शब्दो मे हम कह सकते हैं कि स्वभाव से ही भुगतान शेष सतुलित होता है। यदि चालू खाते मे पूरा समानता न हो तो उसे किसी अन्य प्रकार से पूरा (cover) किया जाता है। जब भी लेनदारिया देनदारियो से कम होगी, उन्हे पूरा करने के लिए विदेशो से ऋण प्राप्त किया जायगा या स्वर्ण भेजा जायगा। ऋण प्राप्त करने से एव स्वर्ण भेजने से लेनदारिया बढकर देनदारियो के बराबर हो जायगी। पिछडे हुए देशो के लिए ऋण प्राप्त करके भुगतान सतुलन को सतुलित करना अधिक

उपयुक्त समझा जाता है क्योंकि इन ऋणों का प्रयोग वे अपने विकास के लिए करते हैं। अन्ततोगत्वा इन ऋणों का भुगतान वे वस्तुएं भेजकर ही करते हैं क्योंकि कोई भी देश सदैव ऋणों पर नहीं जीवित रहता। इसीलिए कहा जाता है कि निर्यातों से ही आयातों का भुगतान होता है।

प्रश्न यह पैदा होता है कि जब भुगतान सतुलन सदैव सतुलित होता है तो यह कहने का क्या महत्व है कि भुगतान सतुलन पक्ष में है या विपक्ष में? इस बात को समझने के लिए हमें भुगतान सतुलन में सम्मिलित मदों पर ध्यान देना होगा। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक दिए हुए समय में आयात और निर्यात बराबर ही हों या सेवाओं का आदान प्रदान बराबर हो अथवा व्याज और लाभांश का लेन देन समान हो या अन्य मदें (मौद्रिक स्वर्णों को ध्यान में न रखने पर) बराबर हों। इस प्रकार सम्भव है कि किसी अवधि में भुगतान करना अधिक और पाना कम हो, या भुगतान करना कम और पाना अधिक हो। इस प्रकार जब 'पावना' और 'देना' को बराबर करने के लिए मौद्रिक स्वर्णों या अल्पकालीन ऋणों के लेन-देन का सहारा लेना पड़े तो भुगतान सतुलन मौलिक रूप से असतुलित ही कहा जायगा। यदि पावना और देना को बराबर करने के लिए मौद्रिक स्वर्णों की प्राप्ति या अल्पकालीन ऋण देना पड़ता है तो भुगतान सतुलन पक्ष में और जब मौद्रिक स्वर्णों भेजना या अल्पकालीन ऋण लेना पड़े तो भुगतान सतुलन विपक्ष में कहा जायगा। इसीलिए मौद्रिक स्वर्णों के लेन देन एवं अल्पकालीन पूँजी के लेन देन को सतुलक मदें (Balancing items) कहा जाता है।

भुगतान सतुलन की साम्यावस्था (Equilibrium in the Balance of Payments)

यद्यपि भुगतान सतुलन की सभी मदों को ध्यान में रखने पर भुगतान सतुलन सदैव सतुलित होता है, परन्तु भुगतान सतुलन का सतुलित होना भुगतान सतुलन की साम्यावस्था का द्योतक नहीं कहा जा सकता। इस कथन की सत्यता को पूर्ण रूप से समझने के लिए भुगतान सतुलन में शामिल मदों को दो भागों में बाटा जा सकता है— (1) स्वायत्त भुगतान की मदें (Items of Autonomous Payments) तथा (2) अनुग्रही भुगतान की मदें (Items of Accommodating Payments)। स्वायत्त भुगतान की मदें वे हैं जिनका आदान-प्रदान राष्ट्रों के बीच स्वतः ही होता रहता है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इनका लेन-देन करता रहते हैं, बाध्य होकर नहीं। इनकी अपनी सत्ता होती है। अपना अस्तित्व होता है। इसके विपरीत अनुग्रही भुगतान की मदें वे हैं जिन्हें स्वायत्त भुगतानों को पूरा (Cover) करने के लिए आदान-प्रदान किया जाता है। ये

भुगतान स्वायत्त भुगतान के अन्तर को पूरा करने के लिए किए जाते हैं; इनका अपना अस्तित्व नहीं होता है। इस अंतर को पूरा करने के लिए या तो विदेशों से ऋण का लेन-देन करना पड़ता है या विदेशों को अन्तर के बराबर के मूल्य का माल आयात करने का आग्रह करना पड़ता है या यदि स्वर्ण भोप है तो उसमें से भुगतान करना पड़ता है। इस प्रकार स्वायत्त और अनुग्रही भुगतानों को मिलाकर भुगतान संतुलन संतुलित हो जाता है परन्तु वास्तव में वह भुगतान संतुलन की साम्यावस्था नहीं होती।

भुगतान संतुलन की साम्यावस्था का अर्थ यह है कि देश की अर्थ-व्यवस्था विश्व के अन्य देशों से इस प्रकार समन्वित (integrated) है कि इसके वर्तमान आर्थिक सम्बन्धों में ऐसी कोई चीज अंतर्निहित (inherent) नहीं है जिसके कारण इसे विश्व के अन्य देशों से सम्बन्धित विनिमय के ढर्रे (Patterns of exchange) में कोई परिवर्तन करना पड़े।¹ अर्थात् एक देश वस्तुओं, सेवाओं और दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के विनियम से ठीक उतना विदेशी विनिमय प्राप्त कर रहा है जितना उसे वस्तुओं, सेवाओं और दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए पर्याप्त है। स्पष्ट है कि भुगतान संतुलन साम्यावस्था में तमी कहा जा सकता है जब 'पावना' और 'देना' बिना मौद्रिक स्वर्ण के आवागमन एवं अल्पकालीन ऋणों के लेन-देन को शामिल किए ही संतुलित हो सके। व्यवहार में इस प्रकार की साम्यावस्था सदैव प्राप्त नहीं की जा सकती। अनेक कारणों से भुगतान संतुलन के स्वायत्त भुगतानों में असमानता आ जाती है। इसलिए भुगतान संतुलन की साम्यावस्था एक ऐसी अवधि के सदर्भ में अध्ययन की जानी चाहिए जिसमें असंतुलन लाने वाले अस्थायी कारणों को खंडित किया जा सके। अर्थशास्त्रियों ने इसके लिए व्यापार चक्र की अवधि चुनी है। यदि सम्पूर्ण व्यापार चक्र की अवधि में कुल 'पावना' कुल 'देना' के बराबर है तो भुगतान संतुलन साम्यावस्था में समझा जायगा। ध्यान रहे कि यहाँ कुल 'पावना' और कुल 'देना' में मौद्रिक स्वर्ण के आवागमन एवं अल्पकालीन ऋणों को शामिल करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।² विनिमय नियंत्रण

¹ "It signifies that a nation's economy is so integrated with the rest of the world that there is nothing inherent in its current economic relations which requires a change in patterns of exchange with other countries".

—Whittlesey, Freedman and Herman : *Money and Banking* p 565.

² "Thus movements of gold and short-term debt are to be taken as symptoms of disequilibrium in the balance of international payments."

—Whittlesey, Freedman and Herman : *Money and Banking*, p. 565.

भादि का भी सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। स्वतः ही भुगतान सतुलन सतुलित हो जाना चाहिए।

भुगतान सतुलन को साम्यावस्था में लाने के उपाय

(Measures to Bring Balance of Payments in Equilibrium)

किसी भी देश का भुगतान सतुलन कुछ समय तक विदेशी अल्पकालीन ऋणों और स्वर्ण निर्यात की सहायता से सतुलित रखा जा सकता है। परन्तु ये दोनों श्रोत निरन्तर बने नहीं रह सकते। अल्पकालीन ऋण किसी सीमा तक ही लिया जा सकता है। उसी प्रकार प्रत्येक देश का स्वर्ण कोष सीमित होता है और उसका प्रयोग इस कार्य के लिए एक सीमा तक ही किया जा सकता है।

किसी भी देश का भुगतान सतुलन असाम्यावस्था (disequilibrium) में उन कारणों के प्रभाव के फलस्वरूप ही आ सकता है जो वस्तुओं और सेवाओं के आयात या निर्यात को प्रभावित करते हैं, या स्वदेश और विदेश में विनिमयों की सामंजस्य-कता का प्रभावित करते हैं, या एक पक्षीय भुगतान को प्रभावित करते हैं। ध्यान से विचार करने पर ज्ञात होता है कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले सभी तत्व-देश और विदेशों की आय में तुलनात्मक अंतर, मुद्रा सकुचन या मुद्रा प्रसार की मात्रा में अंतर, कच्चे माल के श्रोतों की खोज या समाप्ति, तकनीकी परिवर्तन भादि, भुगतान सतुलन को प्रभावित करते हैं।

जब भुगतान सतुलन असाम्यावस्था में होता है तो उसमें सुधार लाने के लिए निम्नलिखित तरीकों का प्रयोग किया जाता है—

1. आय में परिवर्तन (Changes in income)
2. कीमत-तल में परिवर्तन (Changes in internal price level)
3. विनिमय दर में परिवर्तन (Changes in exchange rate)
4. प्रत्यक्ष नियंत्रण (Direct Controls)

1 आय में परिवर्तन (Changes in Income) :

आय की वृद्धि अथवा कमी उपभोगों में भी वृद्धि अथवा कमी कर देती है। आय का कुछ हिस्सा विदेशों से उपभोग वस्तुओं के आयात करने पर एवं कुछ उत्पादक वस्तुओं के आयात पर भी लगाया जाता है। इसलिए आय बढ़ने से स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था में आयात भी अवश्य बढ़ेगा और आय कम होने से आयात भी कम होगा। आय के कम होने से आंतरिक क्षेत्र में भी वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम होगी और वस्तुओं की कीमत गिरेगी। कीमत कम होने से वस्तुओं का निर्यात अधिक हो सकता है। इसलिए आय कम करके आयातों को निर्यातों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। परन्तु आधुनिक युग में प्रत्येक देश आय बढ़ाने और पूर्ण

रोजगार बिन्दु पर पहुचने का लक्ष्य निर्धारित किए हुए है इसलिए यह तरीका अपनाना आधुनिक समय मे सम्भव नही है क्योकि इससे बेरोजगारी बढती है ।

2. कीमत तल मे परिवर्तन (Changes in Price Level) :

अभी ऊपर यह उल्लेख किया गया है कि कीमत-तल के गिरने का निर्यात पर क्या प्रभाव पडता है । कीमत तल गिराने से भुगतान सतुलन तभी सुधारा जा सकता है जब विभिन्न वस्तुओ की माग की लोच इकाई से अधिक हो । यदि कीमत तल के गिरने पर भी कुल विदेशी विनिमय की प्राप्ति ज्यो की र्यो बनी रहे तो भुगतान सतुलन विपक्ष मे ही रहेगा । परन्तु बार-बार इस तरीके का प्रयोग हानि-कारक हो सकता है ।

3 विनिमय दर मे परिवर्तन (Changes in Exchange Rate) :

मुद्रा ना बाह्य मूल्य गिराकर-अवमूल्यन (Devaluation) द्वारा भी भुगतान सतुलन को ठीक किया जा सकता है । अवमूल्यन का प्रभाव भी निर्यात को बढावा देना और आयात को कम करना ही होना है । परन्तु अवमूल्यन बडा ही कोमल अस्त्र है और इसका प्रयोग सामान्यतया नही किया जाना चाहिए, क्योकि इसका प्रभाव उन्टा भी पड सकता है । जब भुगतान सतुलन सुधारने के अन्य उपाय कारगर न हो तभी इसका प्रयोग किया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध मे यह भी याद रखना होगा कि इसका प्रभाव उसी समय ठीक पड सकता है जब अन्य देश अवमूल्यन न करें, यदि सभी देश अवमूल्यन करने लगें तो यह प्रभावहीन होगा । दूसरी स्मरणीय बात इस सम्बन्ध मे यह है कि यह तरीका उसी हालत मे सफल हो सकता है जब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे कीमत-स्तर मे असाम्य की स्थिति आ गई हो । भुगतान सतुलन की असाम्यावस्था यदि किसी देश के आर्थिक ढाचे के अस्त-व्यस्त होने के कारण पैदा हुई है तो यह तरीका असफल ही रहेगा ।

4. प्रत्यक्ष नियन्त्रण (Direct Controls) :

प्रत्यक्ष नियन्त्रणो के अन्तर्गत कई उपाय काम मे लाये जा सकते हैं जिनमे निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं

- 1 आयात पर रोक (Import Restrictions) ।
- 2 निर्यात को प्रोत्साहन (Export Promotion)
- 3 विनिमय नियन्त्रण (Exchange Control)

1. आयातों पर रोक • आयातों पर रोक लगा कर विदेशी विनिमय की माग को प्रभावित किया जाता है । आयातों मे कमी होने से भुगतान सतुलन सुधरने लगता है बशर्ते निर्यात बने रहें या बढें । आयात स्थानापन्न व्यवस्था (Import substitution) को बायें रूप दिया जाता है और आयात की जाने वाली वस्तुओ

की स्थानापन्न वस्तुएं स्वदेश में ही बनाई जाने लगती हैं। आयात कर और आयात कौटा (quota) के द्वारा आयातों को सीमित कर दिया जाता है।

2. निर्यातों को प्रोत्साहन . निर्यातों को प्रोत्साहित करके विदेशी विनिमय की पूर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे भुगतान संतुलन को सुधारा जा सके। निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात वृत्ति और सहायता (Export Bounty and Subsidy) आदि दी जाती है। दूसरे देशों से दीर्घकालीन ऋण लेकर उत्पादन बढ़ाना, वस्तु विनिमय के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार करना एवं उचित मौद्रिक नीति अपना कर निर्यातों को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है।

3. विनिमय नियन्त्रण (Exchange Control) . इसके द्वारा विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से नियन्त्रण में रखा जाता है। इसका विस्तृत अध्ययन अगले अध्याय में किया गया है।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संकेत

1. भुगतान संतुलन के क्या क्या अंग हैं? विपरीत भुगतान संतुलन के सुधारने के क्या उपाय हैं?

(आगरा बी० ए०, 1964)

[संकेत-प्रथम भाग में भुगतान संतुलन की मद्दों को तालिका रूप में दिखाइये और विभिन्न मद्दों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दूसरे भाग में भुगतान संतुलन की असाम्यता को दूर करने के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए।]

2. व्यापार-संतुलन तथा भुगतान-संतुलन में क्या अन्तर है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन को किस प्रकार सुधारा जा सकता है?

(आगरा, 1960)

[संकेत प्रथम भाग में बताइये कि व्यापार संतुलन किसी देश की निश्चित अवधि में होने वाले आयात तथा निर्यात के अन्तर को बताता है जबकि भुगतान-संतुलन अधिक व्यापक शब्द है जिसमें समस्त अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक लेन-देनों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की व्यापारिक मद्दों का समावेश होता है। दूसरे भाग में, प्रतिकूल भुगतान संतुलन को सुधारने के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए।]

विनिमय नियंत्रण (Exchange Control)

"The system of exchange control is at once very similar to and very different from that of the traditional exchange market"

—Bertrand Nogaro

यो तो प्राचीन काल से ही न्यूनाधिक अंशो मे विनिमय नियंत्रण की नीति अपनाई जाती रही है परन्तु जिन अर्थो मे विनिमय नियंत्रण की नीति का प्रयोग आधुनिक युग मे किया जाता है उसका प्रारम्भ, व्यापक रूप मे, 1931 के बाद हुआ। जब 1931 के बाद एक-एक करके अनेक देशो ने स्वर्णमान का परित्याग कर दिया तो उनके सामने यह प्रश्न पैदा हुआ कि विदेशी विनिमय की कौन सी पद्धति अपनाई जाय। लोगो को ऐसी विदेशी विनिमय प्रणाली की तलाश थी जिसमे स्वर्णमान की हठधर्मी (Rigidity) तो न हो परन्तु विनिमय दर मे स्थायित्व हो। यह सोचा गया कि मौद्रिक अधिकारी ऐस उपाय ढूँढ निकालने मे सफल हो सकेंगे जिससे आंतरिक नीति को बाह्य प्रभावो से मुक्त रखा जा सके और साथ ही विनिमय दर के नित्य प्रति होने वाले उच्चावनो से बचा जा सके। मौद्रिक अधिकारियो द्वारा तय की गई ऐसी स्थायी विनिमय दर की आवश्यकता थी जिसे बदली हुई परिस्थितियो के अनुसार बदला भी जा सके। इन्ही उद्देश्यो से प्रेरित होकर किसी न किसी रूप मे विनिमय नियंत्रण की नीति अपनाई जाने लगी।

विनिमय नियंत्रण उन सरकारी हस्तक्षेपो की ओर सकेत करता है जिनके द्वारा विनिमय दर की स्वाभाविक प्रवृत्ति एवं पूँजी के आवागमन पर, पूर्व निर्धारित उद्देश्यो की पूर्ति के निमित्त, रोक लगाई जाती है। दूसरे शब्दो मे विनिमय नियंत्रण के अन्तर्गत, विदेशी विनिमय से सम्बद्ध सौदो पर, मुद्रा विशेष के विनिमय मूल्य पर पडने वाले दबाव को कम करने के उद्देश्य से, लगाये गए प्रतिबन्ध सम्मिलित हैं।

¹ "The term 'exchange control' refers to the regulation of transactions involving foreign exchange with a view to relieving pressure on the exchange value of a particular currency."

इसी प्रकार विनिमय नियंत्रण के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए हैबरलर ने लिखा है कि 'विनिमय नियंत्रण, विदेशी विनिमय बाजार में आर्थिक शक्तियों की स्वतंत्र प्रियाशीलता पर राजकीय नियमन का ही नाम है।'¹ इस प्रकार विनिमय नियंत्रण मूलतः विदेशी विनिमय के माग और पूर्ति के स्रोतों (Sources) को नियमित करना है। संक्षेप में विनिमय नियंत्रण की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं—

1. विदेशी विनिमय सम्बन्धी सौदों का संचालन सरकार या अधिकृत सस्था द्वारा ही किया जाता है।

2. जो भी विदेशी विनिमय प्राप्त होता है उसे सरकार या अधिकृत सस्था को सौंपना पड़ता है।

3. विदेशी विनिमय का वितरण तथा व्यय सरकार या अधिकृत सस्था द्वारा निश्चित कार्य विधि के अनुसार किया जाता है।

4. विदेशी विनिमय पर पूर्ण नियंत्रण होने के कारण देश के आयात एवं निर्यात पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है।

विनिमय नियंत्रण के उद्देश्य

(The Purpose of control in The Exchange Market)

प्रो० आर० जी० थॉमस के शब्दों में—“विनिमय नियंत्रण का उद्देश्य विनिमय दर को मुक्त विनिमय बाजार में स्थापित होने वाली विनिमय दर से, भिन्न स्तर पर बनाए रखना है।”² यदि माग एवं पूर्ति की स्वतंत्र शक्तियों द्वारा निर्धारित विनिमय दर से सरकार सतुष्ट है तो विनिमय नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है, परन्तु जब नियंत्रित दर को स्वतंत्र दर से भिन्न रखना हो तो इसके तीन उद्देश्य हो सकते हैं—

1. अधिमूल्यन (Over-valuation)
2. अधोमूल्यन (Under-valuation)
3. विनिमय-दर के उच्चावचनों से बचना (Avoidance of Fluctuations in the Rate of Exchange)

अब हम इन उद्देश्यों की व्याख्या करेंगे।

¹“...The state regulation excluding the free play of economic forces from the foreign exchange market”

—Haberler : *The Theory of International Trade*, p. 83

²“The purpose of such intervention or control was to hold foreign exchange rates at some point different from the rates that would have existed in a completely free exchange market”

—R. G. Thomas *Our Modern Banking and Monetary System* p. 543

1 अधिमूल्यन (Over-valuation)

अधिमूल्यन ही विनिमय नियंत्रण का सामान्य उद्देश्य रहा है। कोई देश क्यों अधिमूल्यन करना चाहता है, इसके कई कारण हो सकते हैं परन्तु इन सबका खोन एक ही है और वह यह कि सम्बन्धित देश का व्यापार सन्तुलन गम्भीर रूप से विपक्ष में है। स्वतंत्र विनिमय दर उस देश की मुद्रा की पूर्ति का भाग की अपेक्षा अत्यधिक बढ़ा देगी और उसकी मुद्रा का अन्य मुद्राओं के सदृश में मूल्य गिर जायेगा। इन सबके फलस्वरूप विदेशों में भुगतान करने के लिए उस देश को अपनी अधिक मुद्रा देनी होगी। युद्ध की परिस्थितियों में या युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के समय या पिछड़ी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अधिक आयातों की आवश्यकता तथा निर्यातों की कम सम्भावना इस कठिनाई को और अधिक बढ़ा देती है। ऐसी परिस्थिति में माग और पूर्ति की सामान्य शक्तियाँ साम्यावस्था में आने की प्रवृत्ति नहीं रखती। इसलिए मुद्रा के अधिमूल्यन की आवश्यकता होती है।¹

अधिमूल्यन का दूसरा कारण बड़ी मात्रा के विदेशी ऋणों के भुगतान के भार को कम करना है। जिन देशों को विदेशी ऋणों का भुगतान करना होता है उन्हें विदेशी मुद्रा अधिक मात्रा में प्राप्त करनी होती है। यदि ऋणी देश अपनी मुद्रा का नियंत्रण द्वारा अधिमूल्यन कर सके तो विदेशी भुगतान की लागत (cost) कुछ कम हो सकती है।

अधिमूल्यन की आवश्यकता का तीसरा कारण किसी देश विशेष की आंतरिक स्थिति भी हो सकती है। यदि किसी देश में मुद्रा स्फीति का भय हो और विदेशी व्यापार उसकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग हो तो दूसरी मुद्राओं के सदृश में उसकी मुद्रा का मूल्य गिरने से आयात बहुत महंगे हो जायेंगे और निर्यातों को आकस्मिक लाभ होने लगेगा। दोनों ही परिस्थितियाँ मुद्रा स्फीति को उग्र बना देंगी। इसका प्रभाव सामान्य कीमत-स्तर पर पड़ेगा और मुद्रा का आंतरिक और बाह्य मूल्य गिरता चला जायगा। इस खतरनाक स्थिति से बचने के लिए अधिमूल्यन की नीति अपनाई जाती है।

अधिमूल्यन के दोष :

उपरोक्त कारणों से अधिमूल्यन की नीति अपनाई जाती है, परन्तु अधिमूल्यन के कुछ दोष भी हैं जिनसे अर्थव्यवस्था पंगु हो सकती है। अधिमूल्यन के

¹ "Over valuation is usually a desirable policy for any country that is under the sudden necessity of making very large purchases from abroad".

कारण उस देश का कीमत स्तर अन्य देशों के कीमत स्तर से अधिक होता है। यदि टैरिफ और कोटा (quota) का सहारा न लिया जाय तो निर्यात का घक्का लगता है। इस प्रकार अधिमूल्यन कमी लाभदायक और कमी हानिकारक होता है। सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि ऋणों का भुगतान करने के लिए या अधिक आयातों का भुगतान करने के लिए अधिमूल्यन लाभदायक है। परन्तु विश्वव्यापी मंदी के समय अधिमूल्यन के स्थान पर अधोमूल्यन (Under valuation) को अपनाना लाभदायक है।¹

2 अधोमूल्यन (Under-valuation)

अधोमूल्यन का प्रभाव सामान्यतया अधिमूल्यन के विपरीत होता है। निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है, आयात कम हो जाते हैं। अधोमूल्यन द्वारा देश अपने निर्यात व्यापार की प्रतियोगिता की शक्ति को बढ़ाता है। प्रारम्भ में इस प्रकार की नीति जापान द्वारा अपनाई गई और बाद में अमेरिका सहित अन्य अनेक देशों ने भी यह नीति अपनाई। अधोमूल्यन के लाभ दो परिस्थितियों में प्राप्त होते हैं—(1) पहले से वर्तमान अधिमूल्यन को ठीक करने के लिए किया गया अधोमूल्यन स्पष्टतः लाभप्रद होता है (2) अधोमूल्यन का लाभ तभी प्राप्त होता है जब अन्य देश इस प्रकार की नीति अपनाने में असफल होते हैं। आंतरिक रोजगार तथा निर्यात के क्षेत्र में अधोमूल्यन इसीलिए लाभप्रद होता है क्योंकि उत्पादन लागत अधोमूल्यन के साथ कदम नहीं मिला पाती एवं धीरे धीरे समायोजित होती है।²

अधोमूल्यन की नीति सामान्य कीमत स्तर को आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों के माध्यम से प्रभावित करती है। इसलिए जिस देश में विदेशी व्यापार बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ इसका विस्तृत एवं गहन प्रभाव शीघ्र पड़ता है। इसके साथ ही यदि अधोमूल्यन की नीति अपनाने वाला देश छोटा है और विश्व व्यापार में उसका भाग विशेष महत्वपूर्ण नहीं है तो उसे अधिक लाभप्रद होगा क्योंकि उसकी प्रति क्रिया अन्य देशों में होने की आशंका कम होती है। इसका

¹ "...in times of war and scarcity, over value your currency, in times of slump and surfeit, under value your currency".

—Crowther : *An Outline of Money*, p. 240

² "The gains in exports and in domestic employment resulting from under-valuation arise from the tendency for costs of production to lag and adjust slowly to the depreciation in the exchange value of the currency".

—R. G. Thomas : *Our Modern Banking and Monetary System* p 545

अभिप्राय यह है कि अधोमूल्यन की नीति न्यूजीलैण्ड तथा डेनमार्क जैसे देशों के लिए, जिनका विदेशी व्यापार स्वयं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हुए भी विश्व व्यापार का बहुत छोटा भाग है, लाभदायक है।

अधोमूल्यन के दोष—

अधोमूल्यन की नीति को स्वार्थपूर्ण कहा जा सकता है क्योंकि इससे किसी देश को जो भी लाभ प्राप्त होता है वह किसी अन्य देश की कीमत पर ही प्राप्त होता है। यदि सभी देश इस प्रकार की नीति अपनाना प्रारम्भ कर दे तो सभी देशों की मुद्राएं बेकार हो जायगी। इस सम्बन्ध में फ्राउडर को उद्धृत करना असंगत नहीं होगा

“Under valuation is a game that any one can play, but it every one plays at it and currencies enter upon a competition to see which can be pushed furthest below its real value, it quickly develops into a race to render all currencies worthless”

3 विनिमय दर के उच्चावचनो से बचना

(Avoidance of Fluctuations in the Rate of Exchange)

इस बात से सभी सहमत हैं कि विदेशी व्यापार में लगे हुए देशों के बीच की विनिमय दर स्थिर होनी चाहिए। विनिमय दर के अस्थायी रहने से विदेशी व्यापार की जोखिम बढ जाती है। परन्तु व्यवहार में इस नीति को अपनाना बड़ा कठिन है। इस नीति का उद्देश्य, स्वतंत्र विनिमय दर के अस्थायी उतार चढ़ाव को रोकना एवं विभिन्न मुद्राओं के वास्तविक मूल्यों में परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाले विनिमय दर के परिवर्तनों में दखल न देना, होता है। परन्तु कौन अस्थायी परिवर्तन हैं और कौन नहीं इसका तत्काल निर्णय करना कठिन होता है, इसलिए इस नीति के पालन में अवसरवादिता का प्रवेश हो जाता है।

विनिमय दर के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए नियन्त्रणों की आवश्यकता अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा प्रणाली में स्वयंमान की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। विशेष रूप से इस प्रकार की मुद्राओं में सामयिक परिवर्तन होते ही रहते हैं। इसलिए विनिमय नियंत्रण विनिमय दर के स्थायित्व के लिए आवश्यक है।

विनिमय नियंत्रण की रीतियाँ

(Methods of Exchange Control)

विनिमय नियंत्रण के विभिन्न तरीकों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। प्रथम वर्ग में उन उपायों को शामिल किया जा सकता है जिनको अपनाने का प्राथमिक (Primary) उद्देश्य विनिमय दर नियंत्रण करना नहीं होता, परन्तु

इनका प्रभाव परोक्ष रूप से विदेशी विनिमय की माग और पूर्ति पर पड़ता है। दूसरे वर्ग में उन उपायों को सम्मिलित किया जा सकता है 'जिनको अपनाते वा प्राथमिक (Primary) उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से विदेशी विनिमय की माग और पूर्ति को प्रभावित करना होता है। इस प्रकार इनको (1) अप्रत्यक्ष उपाय (Indirect Methods) तथा (2) प्रत्यक्ष उपाय (Direct Methods) की सजा दी जा सकती है।

अप्रत्यक्ष उपाय (Indirect Methods)

इस वर्ग में उन उपायों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से बिन्ही और कारणों से अपनाए जाते हैं परन्तु फिर भी उनका विनिमय दर पर प्रभाव पड़ता है।¹ इस प्रकार के उपायों में आयात नियंत्रण के तरीकों का उल्लेख किया जा सकता है जिनके परिणाम स्वरूप विदेशी विनिमय बाजार में उस देश की मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है और उसका मूल्य अन्य मुद्राओं के सदृश म बढ़ने की प्रवृत्ति दिखलाता है। परन्तु यदि अन्य देश भी आयात नियंत्रण की नीति अपनावें तो किसी भी देश की मुद्रा का तुलनात्मक मूल्य (Relative values) नहीं बदलेगा। इसी प्रकार यदि निर्यातों को प्रोत्साहित करने के उपाय अपनाए जाय तो उनका भी विनिमय दर पर प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि निर्यात वृत्ति (Export Bounties) का तरीका अपनाया जाय तो दूसरे देशों की मुद्रा के सदृश में उस देश की मुद्रा का मूल्य बढ़ने की प्रवृत्ति रहेगा। यदि निर्यातों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय तो मुद्रा का मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में गिरेगा।

किसी देश में आन्तरिक कारणों से ब्याज दर में किए गए परिवर्तन भी पराक्ष रूप से विनिमय दर को प्रभावित करते हैं। विनिमय बाजार के बहुत से सौदे वस्तुओं के नये विषय से सम्बन्ध नहीं रखते। उनका सम्बन्ध पूँजी और विनियोगों के आवागमन से होता है। किसी देश में यदि ब्याज दर बढ़ जाती है तो अन्य देशों की पूँजी और विनियोग आकृष्ट होते हैं और उस देश की मुद्रा की माग बढ़ जाती है तथा उसका तुलनात्मक मूल्य बढ़ने लगता है। 1924 से 1930 का जर्मनी का अनुभव इसका स्पष्ट उदाहरण है। इस प्रकार ब्याज दर अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी विनिमय की माग एवं पूर्ति को प्रभावित करती है।

उपरोक्त सभी परोक्ष उपाय विनिमय नियंत्रण के उद्देश्य से नहीं अपनाये जाते। कस्टमस् ड्यूटी (Customs duties) का उद्देश्य कुछ उद्योगों को संरक्षण

¹ "devices that may be applied for entirely different reasons but that nevertheless have an effect on the rates of exchange"

विनिमय नियंत्रण

देना या सरकार की आय बढ़ाना हो सकता है, नियंत्रित वृत्ति का विदेशी वस्तु निर्यातों को बढ़ाना होता है तथा आयात प्रतिबन्धों का लक्ष्य आयातों की कम क़ौर्ता होता है। व्याज दर आंतरिक माध्व नियंत्रण के उद्देश्य से परिवर्तित क्रिया आर्ता है। परन्तु इन सबका प्रभाव विनिमय दर पर भी पडता है। हाँ, उसका प्रभाव परोक्ष रूप में पडता है। इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि इनके क्रियाशील होने की सीमाएँ होती हैं। अन्य देशों के सहयोग के अभाव में विनिमय नियंत्रण की अप्रत्यक्ष रीतियाँ सफलता नहीं पा सकती। क्राउयर ने अप्रत्यक्ष नियंत्रणों के सम्बन्ध में निष्कर्ष देते हुए लिखा है

“These methods of indirect control, therefore, though they are by no means negligible, are not nearly strong or precise enough instruments for a government that aspires to bring the exchange rates under close control.”

प्रत्यक्ष उपाय

(Direct Methods)

विनिमय नियंत्रण का वही तरीका प्रभावशाली हो सकता है जो विदेशी विनिमय बाजार में मुद्राओं की माग और पूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सके। इस वर्ग में विनिमय नियंत्रण के दो प्रमुख ढंग सम्मिलित किए जाते हैं—

(अ) हस्तक्षेप (Intervention)

(ब) विनिमय प्रतिबन्ध (Exchange Restriction)

(अ) हस्तक्षेप (Intervention) :

यदि मुक्त विनिमय दर किसी देश की सरकार अथवा अधिकारी सस्था की पसन्द के अनुकूल न हो तो वह स्वयं विनिमय बाजार में प्रवेश करती है तथा मुद्रा की माग अथवा पूर्ति को आवश्यकतानुसार बढ़ाकर विनिमय दर को इच्छित स्तर पर रखने का प्रयत्न करती है। उदाहरण के लिए यदि भारत सरकार रुपए का मूल्य ऊँचा रखना चाहती है तो स्वयं बाजार में प्रवेश कर रुपए की माग को बढ़ा सकती है और उसका विनिमय मूल्य ऊँचा रख सकती है। यही हस्तक्षेप की नीति कही जाती है। इस नीति की प्रथम विशेषता यह है कि इससे विनिमय बाजार में सीदो की संख्या बढ जाती है। दूसरी विशेषता यह है कि विनिमय बाजार स्वतन्त्र रहना है विदेशी विनिमय के ऋय विक्रय पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता, परन्तु विनिमय बाजार स्वाभाविक न होकर कृत्रिम हो जाता है। तीसरी विशेषता यह है कि हस्तक्षेप की नीति का पालन करने के लिए देश की मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा अथवा स्वर्ण वा पर्याप्त भंडार होना चाहिए। इसकी चौथी विशेषता यह है कि इसका प्रयोग विनिमय दर में अस्थायी एवं असामान्य कारणों से उत्पन्न परिवर्तनों को कने के लिए ही किया जाता है।

हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करने के लिए सरकार प्रायः दो तरीके अपनाती है .

(1) विनिमय उदबन्धन (Exchange Pegging)

(2) विनिमय स्थिरीकरण कोष (Exchange Stabilisation Fund)

1. विनिमय उदबन्धन (Exchange Pegging) :

जब वास्तविक विनिमय दर को मुक्त विनिमय दर की अपेक्षा नीची दर पर स्थिर करने का प्रयत्न किया जाता है तो इसे नीचे अटकाना (pegging down) कहा जाता है। इस काम के लिए सरकार को पूर्ति पत्र को समर्थन देना पड़ता है। इसे अपनी मुद्रा की पूर्ति को बाजार में बढ़ानी हाती है और विदेशी विनिमय खरीदना पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि भारत का एक रुपया 15 सेण्ट के बराबर हो परन्तु भारत सरकार इसे नीचे अटका कर (Pegged down) 14 सेंट कर दे तथा बाजार शक्तियाँ इसे 14.5 की ओर ले जाय तो सरकार स्वयं 14 सेंट की दर से डालर खरीदने लगेगी और डालर की अपेक्षा रुपए की पूर्ति को बढ़ाकर विनिमय दर को 14 सेण्ट पर स्थिर करने का प्रयास करेगी।

इसके विपरीत यदि सरकार वास्तविक विनिमय दर को स्वाभाविक विनिमय दर से ऊपर टांकना (Pegging up) चाहती हो तो सरकार को विनिमय बाजार में प्रवेश करके विदेशी मुद्रा को सीमित मात्रा में बेचने तथा अपनी मुद्रा खरीदने का कार्य करना पड़ता है जिससे विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की पूर्ति का बढ़ाकर विनिमय दर को ऊपर टकी दर (Pegged up rate) पर स्थिर किया जा सके। उदाहरण के लिए यदि वास्तविक विनिमय दर को (ऊपर के उदाहरण में) 16 सेंट पर टांकने का प्रयत्न किया जाय और बाजार शक्तियाँ उसे 15.5 सेण्ट पर ल जाने लग तो सरकार को 16 सेण्ट की दर पर डालर बेचने का कार्य करना होगा जिससे डालर की पूर्ति बढ़ और रुपये की मात्रा में कमी हो और विनिमय दर 16 सेण्ट पर स्थिर हो सके।

वास्तव में नीचे टांकना (Pegging Down) तथा ऊपर टांकना (Pegging up) इन दोनों में नीचे टांकना अधिक सरल है क्योंकि उसमें अपनी मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना हाता है तथा ऊपर टांकने में विदेशी मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना होता है जिसके लिए विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार होना आवश्यक है। अतः ऊपर टांकने की शक्ति सीमित होती है।

2 विनिमय स्थिरीकरण कोष (Exchange Stabilisation Fund)

विनिमय स्थिरीकरण कोष की स्थापना विनिमय दर को स्थिर रखने के उद्देश्य से की जाती है। अस्थायी कारणों से विनिमय दर में होने वाले उन्वावचनों को रोकना तथा सट्टे के प्रभाववश पूँजी के अल्पकालीन आवागमनों के प्रभावों से

विनिमय दर को सुरक्षित रखना ही इन स्थिरीकरण कोषों का लक्ष्य है ।¹ यद्यपि इन कोषों का कार्य स्थायी एवं आधारभूत कारणों से होने वाले विनिमय दर के परिवर्तनों को रोकना नहीं है फिर भी व्यवहार में अस्थायी एवं स्थायी परिवर्तनों में अन्तर करना कठिन होने के कारण इनका प्रयोग आधारभूत कारणों से होने वाले परिवर्तनों को रोकने के लिए भी किया गया है । इस तरह की नीति का सबसे अच्छा नमूना 'ब्रिटिश समानीकरण खाता' प्रस्तुत करता है । इसके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए ब्राउडर ने लिखा है—

"The aim of the Accounts operations was neither to over-value nor to undervalue the pound, but merely to 'iron-out' temporary ups and downs. In practice, there are reasons for believing that there were times both of under-valuation and of over-valuation of the pound in these years."

कुछ अन्य देशों के स्थिरीकरण कोषों के कार्यों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि उक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य बातों को भी स्थिरीकरण कोषों ने अपना लक्ष्य बनाया । 1931 के पश्चात् जब अमेरिका को विदेशी व्यापार में इंग्लैंड की प्रतिबाधिता करने में कठिनाई का अनुभव हुआ तो अमेरिका के स्थिरीकरण कोष ने स्टर्लिंग के बाह्य मूल्य के गिरने का प्रतिरोध (offsetting) करना अपना प्रमुख उद्देश्य बना लिया । इसी प्रकार फ्रांस के स्थिरीकरण कोष की स्थापना 1936 में इसलिए की गई कि इसकी सहायता में फ्रैंक को पुनः योरोप की मुद्राओं में उच्च स्थान पर प्रतिस्थापित करके उसके महत्त्व को कायम किया जा सके ।

इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के पूर्व सामान्यतया हस्तक्षेप की नीति द्वारा ही विनिमय नियन्त्रण किया जाता था । विनिमय स्थिरीकरण कोष भी इसी नीति पर आधारित था और इसका उद्देश्य विनिमय दर को स्वाभाविक दर स्थिर करना था तथा मुद्रा के बाह्य मूल्य को नीचे गिरने या ऊपर बढ़ने से रोकना अर्थात् मुद्रा का अधिमूल्यन या अधोमूल्यन न होने देना था । इनका कार्य अस्थायी कारणों से उत्पन्न विनिमय दर के परिवर्तनों को रोकना तथा ऐसा करने में अधिक जोखिम से बचना एवं बाह्य परिस्थितियों के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को बचाना था ।

ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका में विनिमय समानीकरण कोषों की स्थापना हो जाने के बाद आपस में एक विपक्षीय समझौता भी (Tripartite Agreement)

1. "Such a fund is for the purpose of defending the exchange market from the effects of speculative inflows and out-flows of short term capital"

किया जिसके अनुसार वे किसी भी मुद्रा को (तीन में से) दूसरे दो देशों द्वारा बेची जाने पर, स्वर्ण में पूर्ण निश्चित दर पर खरीद देने को वचनबद्ध थे। उदाहरण के लिए फ्रांस डालर तथा पौण्ड के बदले, अमेरिका फ्रैंक तथा पौण्ड के बदले तथा इंग्लैंड फ्रैंक तथा डालर के बदले स्वर्ण देने को तैयार था। इनकी विनिमय दर में मौलिक असंतुलन (Fundamental disequilibrium) की स्थिति में सभी सदस्यों की सहमति से परिवर्तन हो सकता था। बाद में इस समझौते में स्विटजरलैंड, बेल्जियम तथा हालैंड भी शामिल हुए। द्वितीय महायुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के कारण इन कोषों का महत्व सहायक के रूप में ही महत्वपूर्ण है।

(घ) विनिमय प्रतिबन्ध (Exchange Restriction) :

विनिमय प्रतिबन्ध सर्वाधिक प्रत्यक्ष, कठोर परन्तु प्रभावशाली ढंग है। वास्तव में आधुनिक युग में विनिमय नियंत्रण, विनिमय प्रतिबन्ध का ही पर्यायवाची समझा जाता है। इस रीति से विनिमय नियंत्रण करने में विनिमय बाजार की स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है। इसके प्रभाववश विनिमय बाजार में सौदों की सरया कम हो जाती है। जनता द्वारा विदेशी विनिमय का रखना प्रतिबन्धित होता है और इसका प्रयोग सरकार की इच्छा और आदेशों के अनुसार ही किया जा सकता है। विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय निश्चित नियमों के अनुसार सरकार या किसी अधिकृत सस्था द्वारा ही किया जाता है।

द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने के बाद हस्तक्षेप की नीति अपनाकर विनिमय दर को नियंत्रित करना कई देशों के लिए प्रभावहीन सिद्ध हुआ और उन्हें बाध्य होकर विनिमय प्रतिबन्ध (Exchange Restriction) के अधिक सशक्त तरीकों का प्रयोग करना पड़ा। हस्तक्षेप और विनिमय प्रतिबन्ध की रीतियों का मौलिक अंतर यह है कि हस्तक्षेप की रीति अपनाने वाली सरकारों को विनिमय बाजार में सौदों की सरया बढ़ानी पड़ती और इसके लिए उनके पास अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा या स्वर्ण की आवश्यकता होती, दूसरी ओर प्रतिबन्ध की नीति द्वारा देश की मुद्रा की माग को कृत्रिम ढंग से बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि इसके स्थान पर बाजार में मुद्रा की पूर्ति को अनिवाद्य रूप से कम कर दिया जाता है। हस्तक्षेप में माग को बढ़ाकर तुलनात्मक माग बढ़ाई जाती है और प्रतिबन्ध में पूर्ति को कम करके तुलनात्मक माग को बढ़ाया जाता है। विनिमय प्रतिबन्ध की परिभाषा देते हुए फ्राउडर ने लिखा है "We must say that any thing that diminishes the turnover of the foreign exchange market constitutes restriction."।

इस प्रकार विनिमय प्रतिबन्ध की निम्नलिखित विशेषताएँ हो सकती हैं—

1. विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय सरकार या उसकी अधिकृत सस्था के हाथ में केन्द्रित रहता है।

2. विदेशी मुद्रा क्रय करने के पूर्व सरकार से आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होता है। बिना आज्ञा के किसी प्रकार का विदेशी भुगतान वर्जित है।
3. बिना आज्ञा के विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय दंडनीय अपराध होता है।
4. भुगतान स्वरूप प्राप्त विदेशी विनिमय को निश्चित विनिमय दर पर सरकार या अधिकृत सस्था को बेचना आवश्यक होता है।
5. पूंजी के निर्यात तथा दूसरे देश की पूंजी की वापसी पर भी सरकार का प्रतिबन्ध होता है।

इस प्रकार के विनिमय प्रतिबन्ध का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मनी और आस्ट्रिया द्वारा 1931 के आर्थिक संकट के समय किया गया। जर्मनी में इस रीति का बड़ी कठोरता से पालन किया गया। इन नियमों का उल्लंघन करने का दंड जर्मनी में मृत्युदंड था। द्वितीय महायुद्ध छिड़ने के समय तक विनिमय प्रतिबन्ध की रीति मध्य योरोप तथा दक्षिण अमेरिका के देशों तक सीमित थी परन्तु युद्ध छिड़ने के बाद और युद्ध समाप्त होने तक ससार की लगभग सभी मुद्राएँ विनिमय प्रतिबन्ध की परिधि में समाविष्ट हो गईं।

विनिमय प्रतिबन्ध के कई रूप हो सकते हैं, जिनमें कुछ रूपों का वर्णन नीचे दिया जा रहा है—

(1) अवरुद्ध खाते (Blocked Accounts)

1931 की महान आर्थिक संकट की स्थिति में अनेक न्हण्टी देशों द्वारा, जिनमें जर्मनी का नाम प्रमुख है, 'अवरुद्ध खातों' का प्रयोग किया गया। इन खातों का उद्देश्य विदेशी ऋणों और ब्याज का भुगतान रोकना था। न्हण्टी देशों ने विदेशी ऋणों और ब्याज का भुगतान करना बन्द कर दिया और ऋण की रकम के बराबर मूल्य की अपनी देश की मुद्रा अपने केंद्रीय बैंक के पास न्हण्टादाता के नाम जमा करा दी। न्हण्टादाना इस जमा को निकाल नहीं सकता था। इस प्रकार के जमा खातों को ही "अवरुद्ध खाता" कहा जाता है।

अवरुद्ध खातों के कारण विदेशी न्हण्टादाताओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था क्योंकि वे इसका इच्छित प्रयोग नहीं कर सकते थे। इन खातों के प्रयोग के कारण उन देशों को विशेष हानि हुई जो अवरुद्ध खातों की रीति अपनाते वाले देशों को माल निर्यात करते थे। अवरुद्ध खातों में जमा रकम का प्रयोग उन्ही देशों में कुछ विशेष भुगतानों के लिए किया जा सकता था। जो लोग (न्हण्टादाता) इस प्रकार स्वयं इन खातों का प्रयोग नहीं कर सके उन्होंने इस जमा को हानि उठाकर दूसरों को बेचना ही ठीक समझा। खरीदने वालों को अवरुद्ध खाता

रखने वाले देशों की मुद्रा सस्ती प्राप्त होती थी इसलिए वे वहाँ से अधिक माल मगाते थे। फलस्वरूप इस प्रकार के खातों का प्रयोग करने वाले देशों का नियति बढ़ता था। जर्मनी को इस ढंग से काफी लाभ हुआ।

(2) बहुमुखी विनियम दरें (Multiple Exchange Rates) :

यदि विनियम बाजार पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न हो तो दो देशों के बीच की विनियम दर केवल एक ही होती है परन्तु विनियम बाजार पर प्रतिबन्ध लगाकर अनेक विनियम दरें रखी जा सकती हैं। य दरें विभिन्न वस्तुओं के आयात अथवा निर्यात के लिए अलग-अलग हो सकती हैं। पूँजी के लेन-देन के लिए अलग विनियम दर का प्रयोग किया जा सकता है। तात्पर्य यह कि एक ही साथ विभिन्न सौदों के लिए विभिन्न दरें हो सकती हैं परन्तु एक बात का ध्यान अवश्य रखा जाता है कि विभिन्न दरों का सम्मिलित प्रभाव आयातों को सस्ता और निर्यातों को अधिक लाभप्रद बनाना हो।

बहुमुखी विनियम दर की रीति का प्रयोग भी सबसे पहले जर्मनी में ही किया गया। जर्मनी में 1933 से 1945 तक इस रीति का काफी प्रयोग किया गया। जर्मनी के बाद अर्जेंटिना, पेरू, चिली तथा ब्राजील आदि ने इस रीति को अपनाया। सभी देशों का बहुमुखी विनियम दर कर रीति अपनायें वे दो उद्देश्य थे। प्रथम निर्यातों के लिए नीची विनियम दर अपना कर अधिक विदेशी विनियम प्राप्त करना तथा द्वितीय, आयातों के लिए ऊँची विनियम दर अपना कर अनावश्यक आयातों को कम करना तथा विदेशी विनियम का मितव्ययिता पूर्ण रख करना।

बहुमुखी विनियम दरों के अपनाने से देश के सन्तुलित विकास में तभी सहायता हो सकती है जब इसका संचालन व्यवस्थित ढंग से एवं कुशलतापूर्वक किया जाय। परन्तु इस व्यवस्था के संचालन में इतनी जटिलता है कि इसका कुशल संचालन प्रायः बहुत ही कठिन है। इस कठिनाई के कारण कई देशों ने इस रीति का परित्याग भी कर दिया।

(3) समाशोधन समझौते (Clearing Agreements)

अवहृद्ध खातों के प्रयोग का फलस्वरूप वे देश, जो खाता प्रयोग करने वाले देशों को निर्यात अधिक करते थे, असह्य स्थिति में थे परन्तु जो देश ऐसे देशों से आयात अधिक करते थे उनमें इनकी पर्याप्त प्रतिक्रिया हुई। इन देशों से अधिक आयात करने वाले देशों ने भी यह धमकी दी कि वे भी अवहृद्ध खातों का प्रयोग करेंगे और अधिक आयात (Surplus Imports) का भुगतान नहीं करेंगे। कुछ देशों ने तो वास्तव में प्रतिक्रिया स्वरूप अवहृद्ध खातों का प्रयोग प्रारम्भ भी कर दिया। ऐसी स्थिति में जर्मनी आदि देशों को, जो पहले से अवहृद्ध खातों का प्रयोग कर रहे

थे अपने निर्यातों में कमी की आशंका स्पष्ट दिखाई देने लगी इसलिए उन्होंने समाशोधन समझौते करना स्वीकार कर लिया।

समाशोधन समझौते के अनुसार सम्बन्धित देशों के केन्द्रीय बैंकों को महत्वपूर्ण भूमिका निम्नानी पड़ती है। दोनों देश के आयातकर्त्ता आयातित माल का भुगतान अपने अपने केन्द्रीय बैंक को करते हैं। इसी प्रकार दोनों देशों के निर्यातकर्त्ताओं को उनके देश का केन्द्रीय बैंक भुगतान करता है। एक निर्धारित समय के बाद दोनों देशों के केन्द्रीय बैंक यह देखते हैं कि उनकी आयातों से प्राप्त तथा निर्यातों के भुगतान की स्थिति क्या है। उसके आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि उन्हें एक दूसरे से कितना पाना अथवा देना है और समझौते की शर्तों के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि अबरुद्ध खातों का प्रयोग करने वाले देशों से अधिक आयात करने वाले देशों की धमकी के फलस्वरूप ही ऐसे समझौते किये गए थे इसलिए शेष रकम का प्रयोग अबरुद्ध पूँजी और व्याज के भुगतान के लिए प्रयोग की जाने की शर्तें भी समझौते की प्रमुख अङ्ग थी। उदाहरण के लिए यदि 'अ' देश अबरुद्ध खातों के प्रयोग द्वारा 'ब' देश की पूँजी और व्याज का भुगतान बन्द करद तथा 'ब' देश 'अ' देश से एक निश्चित अवधि में 10 करोड़ का माल मगता हो तथा 6 करोड़ का माल भेजता हो। (अ देश की मुद्रा में मूल्य व्यक्त किया गया है) तो दोनों देशों के केन्द्रीय बैंक अपने आयातकों से भुगतान प्राप्त करेंगे और निर्यातकों को भुगतान करेंगे। अवधि के अन्त में 'अ' देश को 4 करोड़ पाना है तथा 'ब' देश को भुगतान देना है। चूँकि 'अ' देश ने 'ब' देश की पूँजी तथा व्याज अबरुद्ध खातों में डाल रखा है इसलिए समझौते के अनुसार इस 4 करोड़ में से एक भाग 'ब' देश अपने ऋण और व्याज की वसूली के रूप में रख लेगा। शेष भाग का प्रयोग समझौते की शर्तों के अनुसार होगा।

विनिमय समाशोधन समझौतों के फलस्वरूप विदेशी विनिमय के बिना ही निर्यातों और आयातों का भुगतान होता रहता है और विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है। दोनों देश इस बात का प्रयत्न करते हैं कि उनके आयात और निर्यात बराबर हो जिससे भुगतान की समस्या पैदा ही न हो। इस प्रकार के समझौतों का प्रयोग विदेशी व्यापार की दिशा को परिवर्तित करने के लिए भी किया गया।

(4) भुगतान समझौते (Payments Agreement) :

समाशोधन समझौतों के दोषों को समाप्त करने के लिए भुगतान समझौतों का आश्रय लिया गया। समाशोधन समझौतों में निर्यातकर्त्ता प्रोत्साहन नहीं पाता था क्योंकि कभी-कभी उसे भुगतान मिलने में विलम्ब हो जाता था। इसी प्रकार भुगतानों का केन्द्रीयकरण हो जाने से भी आयातकों तथा निर्यातकों को कठिनाई होती थी। भुगतान समझौते एक प्रकार से विदेशी विनिमय की राशनिंग की व्यवस्था है। इसके

अनुसार भी निर्यातकों का मुग्तान निर्यातकर्ता देश का केन्द्रीय बैंक ही करता था। निर्यात के फलस्वरूप दूसरे देश से जा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी उसके एक निश्चित भाग के बराबर ही उस देश से आयात किया जा सकता था तथा शेष भाग का प्रयोग समझौते की शर्तों के अनुसार किया जाता था। इस प्रकार के समझौते का उदाहरण ब्रिटेन और जर्मनी के बीच 1934 में किया गया समझौता है। इसके अनुसार जर्मनी ब्रिटेन से प्रतिमास उस रकम के 55 प्रतिशत के मूल्य के बराबर आयात कर सकता था, जितनी रकम का जर्मनी ने पिछले माह के पूर्व के माह में ब्रिटेन से निर्यात किया हो। शेष रकम ब्रिटेन के ऋण और व्याज आदि के भुगतान में प्रयुक्त होती थी।

(5) यथास्थिर समझौते (Standstill Agreements) :

इस प्रकार के समझौतों का प्रारम्भ भी जर्मनी में 1931 की मन्त्री के वाद किया गया। स्थिति यह थी कि अनेक देश जर्मनी से अपनी पूंजी निकालने लगे थे और जर्मनी को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। जर्मनी ने अपने मार को स्थगित करने के उद्देश्य से कई ऋणदाता देशों से तत्काल भुगतान न लेकर उनकी पूंजी को पुनः उधार के रूप में लेने का समझौता किया। इसमें जर्मनी का तत्काल भुगतान करने की कठिनाई टल गई। पूंजी और व्याज का भुगतान करने के लिए किशतों के प्रयोग का समझौता किया गया। इन समझौतों के फलस्वरूप विनिमय दर को नियन्त्रण में रखने के लिए काफी समय उपलब्ध हो गया।

(6) विलम्बकाल हस्तान्तरण (Transfer Moratoria) .

इस रीति के अनुसार विदेशी पूंजी अथवा सम्पत्ति का भुगतान स्थगित कर दिया जाता है। स्थगन काल के समाप्त होने पर ही इनका भुगतान किया जाता है। इस प्रकार स्थगन काल में सरकार को विदेशी विनिमय को समायोजित करने का समय मिल जाता है। वास्तव में भुगतान स्थगन की रीति में सरकार आयातकर्ताओं को आयातों तथा ऋणों का भुगतान अधिवृत्त बैंक को अपनी मुद्रा में करने का आदेश देता है परन्तु विदेशी इनकी अपनी मुद्रा में केवल स्थगन काल के समाप्त होने पर ही परिवर्तित करा सकते हैं।

(7) प्रति पूंति समझौते (Compensation Agreement) :

ये समझौते वस्तु विनिमय दर पर आधारित हैं। आयातों की अनुमति उसी समय दी जाती है जब ठीक उतनी ही मात्रा में निर्यात भी किया जाय जिससे भुगतान के लिए विदेशी विनिमय की आवश्यकता न पैदा हो।

भारत में विनिमय-नियन्त्रण

(Exchange Control in India)

द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होने पर भारत में लागू किए गए "भारत रक्षा नियम" (Defence of India Rules) के अन्तर्गत विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी

नियमों का भी उल्लेख किया गया। विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी इन नियमों के अनुसार विदेशी विनिमय के ऋय-विनय, वस्तुओं के आयात-निर्गत, पूंजी के लेन-देन आदि पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया एवं विनिमय नियन्त्रण का कार्य-भार रिजर्व बैंक को सौंप दिया गया। परन्तु विनिमय नियन्त्रण को स्थायी रूप से 1947 में विदेशी विनिमय अधिनियम (*Foreign Exchange Regulation Act 1947*) पारित होने पर लागू किया गया। इस कानून के अनुसार विदेशी विनिमय सम्बन्धी समस्त कार्य भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक को दिया गया।

युद्ध काल में विनिमय नियन्त्रण स्टर्लिंग क्षेत्र के बाहर के देशों तक सीमित था। इन देशों की मुद्राओं की पूर्ति सीमित होने के कारण उनके प्रयोग पर नियन्त्रण रखना आवश्यक समझा गया। इसलिए अमेरिका तथा अन्य सीमित मुद्रा वाले देशों से होने वाले आयातों को कम करने के उद्देश्य से विनिमय नियन्त्रण की नीति अपनाई गई। यद्यपि युद्ध-काल में भारत ने पर्याप्त 'स्टर्लिंग शेप' (Sterling Balance) संचित कर लिया था फिर भी युद्ध के बाद विनिमय नियन्त्रण का क्षेत्र बढ़ा दिया गया और उसकी परिधि में स्टर्लिंग क्षेत्र के देश भी आ गए। भारत में पंचवर्षीय योजना काल के प्रारम्भ होने से विनिमय नियन्त्रण को आर्थिक विकास के सहायक यंत्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। औद्योगीकरण एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए विनिमय नियन्त्रण मौद्रिक नीति का प्रमुख अङ्ग बन गया है। भारत में विनिमय नियन्त्रण की व्यवस्थाये निम्न प्रकार है—

अधिकृत व्यापारी (Authorised Dealers)

विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम के अनुसार विदेशी मुद्राओं तथा नहरा पत्रों का लेन-देन करने का अधिकार भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक को प्राप्त है। परन्तु सुविधा के दृष्टिकोण से रिजर्व बैंक ने अधिनियम में प्राप्त शक्तियों के आधार पर विदेशी विनिमय का लेन देन करने के लिए 37 सस्थाओं को अधिकृत किया है जिनमें अधिकांश भारतीय अनुमूचित बैंक शामिल हैं।

विनिमय दरें (Exchange Rates) :

विदेशी विनिमय दरें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित की जाती हैं जो वास्तविक विनिमय बाजार में प्रतिगण तक अट-बढ़ सकती हैं। स्टर्लिंग और रुपये की विनिमय दर के निश्चित करने में विनिमय व्यापारी सघ का महत्वपूर्ण हाथ रहता है। जनता की विदेशी विनिमय की आवश्यकता अधिकृत व्यापारियों द्वारा पूरी होती है। कुछ स्वीकृत छूटों के अतिरिक्त सभी भुगतानों के लिए रिजर्व बैंक की आज्ञा (Permit) प्राप्त करना आवश्यक होता है।

विदेशी भुगतान (Foreign Payments) .

विदेशी भुगतानों की आवश्यकता मुख्य रूप से आयातों के कारण होती है।

भारत में बिना लाइसेन्स के आयात नहीं किया जा सकता है। आयात लाइसेन्स प्राप्त करने का तात्पर्य होता है कि सरकार उस सीमा तक भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध करेगी। लाइसेन्स प्राप्त आयात का भुगतान हो जाने पर सम्बन्धित लाइसेन्स रद्द कर दिया जाता है। नियमित रूप से किए जाने वाले आयातों का भुगतान करने की विशेष अनुमति भी रिजर्व बैंक द्वारा दी जाती है परन्तु इन आयातकर्त्ताओं को मासिक विवरण भेजना आवश्यक होता है। आयातों के अतिरिक्त यात्रा, प्रशिक्षण परिवहन व्यय, बीमा शुल्क आदि का भुगतान भी करना पड़ता है। इन सब भुगतानों के लिए रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी पड़ती है। अनुमति देने के पूर्व ऐसे भुगतानों की आवश्यकता एवं उपादेयता पर समुचित विचार किया जाता है। विशेष रूप से डालर का भुगतान करने में बहुत सतर्कता रखी जाती है और आवश्यक होने पर ही अनुमति दी जाती है।

भारत में निवास करने वाले विदेशी नागरिक एक सीमा तक ही रकम भेज सकते हैं इसीलिए जब कोई सस्या विदेशियों की सेवाओं का लाभ उठाना चाहती है तो उसे रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी पड़ती है। लाभार्थ तथा व्याज की राशि भेजने पर सीमा प्रतिबन्ध नहीं है। पेशन की पूरी रकम भी अधिकृत व्यापारियों द्वारा भेजी जा सकती है। स्टर्लिंग क्षेत्र में रकम भेजने के 150 पौण्ड तक कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है परन्तु डालर भेजने के लिए एवं पाकिस्तान में रुपया भेजने के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति आवश्यक है। पाकिस्तान के लिए 50 रु० तक प्रति माह भेजने की आज्ञा जिलाधीश दे सकता है।

विदेशों से प्राप्ति (Receipt From Foreign Countries)

जिस प्रकार आयात करने के लिए लाइसेन्स की आवश्यकता होती है वैसे ही निर्यात के लिए भी लाइसेन्स आवश्यक है। भुगतान में प्राप्त विदेशी मुद्रा को अधिकृत व्यापारी के पास जमा करा कर रिजर्व बैंक की सूचना देनी पड़ती है। इसका उद्देश्य यह है कि विदेशी मुद्रा सरकार को प्राप्त हो और उसका उचित ढंग से प्रयोग किया जा सके तथा अनाधिकृत व्यापारी उसका लेन-देन न कर सकें। विदेशों में निवास करने वाले भारतीय भारत में किसी भी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेज सकते हैं। भारत में विदेशी पूंजी लगाने के लिए सरकार और पूंजी निर्गम के नियन्त्रक (Controller of Capital Issue) से अनुमति लेनी पड़ती है। विदेशी पूंजी वापस लेने के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति आवश्यक है।

स्वर्ण के आयात-निर्यात पर भी प्रतिबन्ध है। बिना लाइसेन्स स्वर्ण आदि का आयात-निर्यात नहीं किया जा सकता।

विनिमय नियन्त्रण का प्रशासन रिजर्व बैंक के विनिमय नियन्त्रण विभाग द्वारा किया जाता है जिसका नियन्त्रक रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। विभाग का

उपनियन्त्रक विभाग के कार्यों की देख-रेख करता है। बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली, मद्रास तथा कानपुर में विनिमय नियन्त्रण विभाग के उप-कार्यालय स्थित हैं जिनका नियन्त्रण सहायक नियन्त्रको द्वारा किया जाता है। उप-कार्यालयों के क्षेत्र निश्चित हैं और उन क्षेत्रों से सम्बन्धित विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी सामान्य मामलों का निपटारा वहीं किया जाता है।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संकेत

(1) भारत में प्रयुक्त रीतियों के विशेष सन्दर्भ में विनिमय-नियन्त्रण के उद्देश्यों तथा रीतियों का विवेचन कीजिए। (राजस्थान बी० काम, 1962)

[संकेत—प्रथम भाग में विनिमय-नियन्त्रण के तीन उद्देश्यों—अधिमूल्यन, अधोमूल्यन तथा विनिमय-दर के उच्चावचनों से बचना—की सक्षिप्त व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में विनिमय-नियन्त्रण की इन रीतियों का वर्णन कीजिए जिनका प्रयोग भारत में हुआ है। उत्तर भारतीय उदाहरणों सहित दीजिए।]

(2) किसी एक परिचित देश के विनिमय-नियन्त्रण के उद्देश्य तथा कार्य-कारिता पर एक सक्षिप्त व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखें।

(राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल, 1967)

[संकेत—प्रथम भाग में विनिमय नियन्त्रण के तीन उद्देश्यों—अधिमूल्यन, अधोमूल्यन तथा विनिमय-दर के उच्चावचनों से बचना—की व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में भारत में विनिमय नियन्त्रण की क्रियाशीलता का विवेचन कीजिए।]

(3) विनिमय नियन्त्रण का अर्थ समझाइये। विनिमय-नियन्त्रण की महत्वपूर्ण विधियों का स्पष्टीकरण कीजिए। (नागपुर बी० काम०, 1961)

[संकेत—प्रथम भाग में विनिमय नियन्त्रण की विभिन्न परिभाषायें देते हुए उनका अर्थ स्पष्ट कीजिए। द्वितीय भाग में विनिमय-नियन्त्रण की मुख्य विधियों की व्याख्या कीजिए।]

भाग ४

Part Four

“The economic problems of the world—inhabited by less-developed nations with their appallingly low living standards, on the one hand and affluent nations worried about the Damocle’s sword hanging perilously on their economic prosperity, on the other, have never been so challenging as they appear today. The international monetary system ought, therefore, to be so strengthened that pressures on key currencies are eased, world trade is allowed to grow and the precious foreign aid smoothly flows in a high tide to the receptive shores of less developed countries.”

अन्तराष्ट्रीय मौद्रिक संस्थायें
(International Monetary Institutions)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund)

“The International Monetary Fund is an ingenious attempt to enable the member countries to practice stabilising intervention without committing them to absolute rigidity of the exchange value of their currencies at all times.”

प्रथम महायुद्ध के बाद सत्तार के सभी देशों में आर्थिक अस्थिरता आ गई थी। प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ होते ही स्वर्णमान का त्याग कर दिया गया परन्तु युद्ध की समाप्ति के बाद फिर स्वर्णमान अपनाने के प्रयत्न हुए। सन् 1922 में जेनेवा में एक आर्थिक सम्मेलन (Economic Conference) बुलाया गया जिसने स्वर्णमान अपनाने का सुझाव दिया। स्वर्णमान के अपनाने के बाद फ्रैंक का अवमूल्यन हुआ जिसके फलस्वरूप फ्रान्स ने बहुत सा स्वर्णकोष तथा विदेशी विनिमय जमा कर लिया। जर्मनी और इटली जैसे ऋणी देशों के विपरीत व्यापार सतुलन के कारण उनके यहाँ से स्वर्ण कोषों का निर्यात हो गया और सत्तार के अधिकांश स्वर्णकोष अमरीका तथा फ्रांस के पास केन्द्रित हो गये। अमरीका ने अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के नियमों की अवहेलना कर स्वर्ण कोषों को दबा लिया और सरक्षणारमक नीतियाँ अपनाकर उनका प्रभाव कीतल-तल पर नहीं पड़ने दिया। इस प्रकार देशों की सकुचित स्वार्थ-पूर्ण नीतियों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान का पतन हो गया। स्वर्णमान के पतन के पश्चात् विनिमय दरों की स्थिरता के उद्देश्य से अमेरिका, इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच विनिमय स्थिरीकरण कोषों (Exchange Stabilisation Funds) की व्यवस्था द्वारा कुछ सहयोग चलता रहा परन्तु इस व्यवस्था का क्षेत्र बहुत सीमित था और कुछ देशों के स्वार्थों के कारण चला।

स्वर्णमान की समाप्ति के बाद भुगतान असतुलन को दूर करने की स्वयं-संचालक प्रक्रिया नष्ट हो गई और कोई उपयुक्त प्रणाली उसका स्थान न ले सकी। स्वर्णमान के पतन तथा सन् 1929 की महाद मदी के फलस्वरूप सत्तार में आर्थिक राष्ट्रवाद (Economic Nationalism) का युग आ गया और देश स्वार्थी आर्थिक नीतियों को अपनाने लगे। आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया।

भुगतान-संतुलन (Balance of Payments) की समस्या का समाधान करने के लिए विनिमय नियंत्रण तथा प्रतियोगी अवमूल्यन की नीतियाँ अपनायी गईं और देशों ने व्यापार तथा भुगतान पर नियंत्रण की विभिन्न विधियाँ अपनायी जैसे समाशोधन समझौते (Clearing Agreements), अवरोध खाते (Blocked Accounts), बहुमुखी विनिमय दरें (Multiple Exchange Rates) इत्यादि। इसका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार घटने लगा। सप्तर के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्थाएँ अस्तव्यस्त हो गईं और आर्थिक अस्थिरता का शिकार हो गईं। द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ हो जाने से इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया जा सका।

द्वितीय महायुद्ध काल में यह अनुभव किया जाने लगा कि अर्थव्यवस्थाओं में पूर्ण-वृत्ति (Full Employment) की प्राप्ति के लिये युद्धोत्तर-काल में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार आवश्यक है और विनिमय-स्थायित्व (Exchange Stabilisation) की प्राप्ति के उपायों पर विचार विमर्श प्रारम्भ हो गया। सभी लोग यह मानने लगे थे कि विनिमय अवमूल्यन (Exchange Depreciation) तथा विनिमय नियंत्रण से बचकर ही विनिमय स्थायित्व, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों के समुचित प्रवाह के उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग तथा सहकार (International Monetary Cooperation and collaboration) के प्रश्न को पर्याप्त महत्व प्राप्त हो गया। परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की विभिन्न योजनाओं के निर्माण का काम प्रारम्भ हुआ।

कीन्स-योजना (The Keynes' Plan) : ब्रिटेन की ओर से विख्यात अर्थशास्त्री लार्ड जे० एम० कीन्स ने 8 अप्रैल, 1943 को 'अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान संधि के प्रस्ताव' (Proposals for an International Clearing Union) के नाम से अपनी योजना प्रकाशित की जो कीन्स-योजना (Keynes' Plan) के नाम से जानी जाती है। इस योजना के अंतर्गत एक केन्द्रीय भुगतान संधि नामक एक केन्द्रीय सन्स्था के निर्माण का आयोजन था। इस योजना में 'बैंकोर' (Bancor) नाम की एक पृथक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की व्यवस्था थी जिसका प्रबंध भुगतान संधि करेगा और बैंकोर का मूल्य स्वर्ण में निश्चित किया जायगा। भुगतान संधि में सदस्य देशों के खाते होने और वे एक दूसरे से बैंकोर के द्वारा खातों में जमा के रूप में भुगतान प्राप्त करेंगे। नदस्य देश एक निश्चित सीमा तक भुगतान संधि से 'बैंकोर' की अधिविक्रय सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। योजना के अंतर्गत सदस्य देशों की 'अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लागत-तल तथा भुगतान संतुलन की स्थिति के अनुरूप विनिमय-दरों में समायोजन की स्वतंत्रता थी। कीन्स के प्रस्तावों में दीर्घकालीन पूँजी-विनियोजन (Long-term Invest-

ments) के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय वैकिंग प्रणाली की भी व्यवस्था थी। कीन्स योजना को अमेरिका में स्वर्णमान पुनर्स्थापन योजना कहा गया था।

व्हाइट योजना (White Plan) : अमेरिका की ओर से हारवर्ड अर्थशास्त्री तथा अमरीका कोषागार के मौद्रिक अनुसंधान विभाग के निदेशक (Director, Monetary Research in U. S. Treasury) डा० हैरी डेक्सटर व्हाइट (Dr Harry Dexter White) ने 10 जुलाई 1943 को "अन्तर्राष्ट्रीय स्थायित्व कोष का अमरीकी प्रस्ताव" (A United States Proposal for a United and Associated Nations' Stabilisation Fund) के नाम एक योजना प्रकाशित की। इस योजना के अंतर्गत एक 'अन्तर्राष्ट्रीय स्थायित्व कोष' की स्थापना का सुझाव था जो 'समायोजन प्रणाली' (Adjustment Mechanism) का कार्य करेगा। कोष को विनिमय दरों को अपनी मुद्रा में निश्चित करने का अधिकार होगा और उसमें परिवर्तन 'मूलभूत असंतुलन' (Fundamental Disequilibrium) को ठीक करने के लिए आवश्यक होने पर ही किया जाएगा और उसके लिए सदस्य देशों के कुल मूल्यों के 1/3 की स्वीकृति आवश्यक होगी। इस योजना में 'यूनिटास' (Unitas) नामक अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक इकाई की व्यवस्था थी जो 10 डालर के बराबर थी और जिसमें सदस्य देशों के स्वर्ण को मापा जाता था।

उपर्युक्त दो योजनाओं में अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग बढ़ाने, अन्तर्राष्ट्रीय देखरेख द्वारा विनिमय-दरों का नियंत्रण तथा अन्तर्राष्ट्रीय तन्त्रता के राष्ट्रीय कोषों में वृद्धि करने की व्यवस्था थी। स्कैमेल (W M. Scammell) के अनुसार "The Keynes Plan was more daring in conception and the White Plan was sober and prosaic"¹

केनेडियन योजना (Canadian Plan) . 19 देशों की वाणिज्यदल में हुई वार्ताओं में कनाडा ने 9 जून 1943 को एक "Tentative Draft Proposal of Canadian Experts for an International Exchange Union" नामक योजना रखी। यह योजना कीन्स तथा व्हाइट योजनाओं का एक समझौता मात्र थी क्योंकि कनाडा के विशेषज्ञों ने अपनी योजना बनाने के पहले दोनों योजनाओं का अध्ययन कर लिया था। इस योजना पर विचार विमर्श हुआ परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया।

ब्रेटनवुड्स सम्मेलन (Bretton Woods Conference) : इन योजनाओं पर विधिवत् विचारविमर्श के पहले लंदन में लार्ड कीन्स तथा डा० व्हाइट में अनौपचारिक बातचीत हुई। अमरीकी कीन्स योजना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे अतः

¹. W M. Scammell ; *International Monetary Policy*, p 134-5.

ग्रन्त मे ब्रह्माइट योजना मे सशोधन तथा परिवर्तन कर एक परिवर्तित योजना "The Joint Statement by Experts on the Establishment of an International Monetary Fund" के नाम से अप्रैल 1944 मे प्रकाशित की गई ।

इस परिवेश मे अमरीका के ब्रेटन वुड्स (न्यू हैम्पशायर) नामक स्थान पर 'मौद्रिक कोष' की योजना पर विचार करने के लिए जुलाई 1944 मे 44 देशो का एक सम्मेलन हुआ जिसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन (Bretten Woods Conference) के नाम से जाना जाता है । सम्मेलन का समारम्भ 1 जुलाई 1944 को अमरीकी बोपागार के तत्कालीन सचिव श्री हेनरी मारगेन्थो (Mr. Henry Morgenthau) के भाषण से हुआ । इस सम्मेलन मे हुए समझौते के अनुसार निम्नलिखित दो अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सस्थाओ की स्थापना हुई :

(1) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund).

(2) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (International Bank for Reconstruction and Development).

पहली सस्था अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सतुलित विकास, सदस्य देशो के भुगतानाशेषो मे अस्थायी असतुलन को दूर करने; विनिमय स्थायित्व तथा देशो के बीच अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित की गई । दूसरी सस्था, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, विकसित देशो के पुनर्निर्माण तथा अविकसित देशो के आर्थिक विकास मे योगदान करन के उद्देश्य से दीर्घकालीन पूंजी के विनियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित हुई । अब हम इस अध्याय मे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विस्तार से विवेचन करेगे ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

(International Monetary Fund)

ब्रेटन वुड्स समझौते के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसम्बर 1945 को हुई जब वाजिंगटन मे 30 देशो के प्रतिनिधियो ने हस्ताक्षर समारोह मे भाग लिया । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वास्तव मे 1 मार्च 1947 से कार्य करना प्रारम्भ किया । प्रारम्भ मे कोष के 40 सदस्य थे परन्तु अब सदस्यो की सख्या बढकर 111 हो गई है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग के क्षेत्र मे एक अति महत्वपूर्ण घटना है (The establishment of the Fund was indeed a great landmark in the sphere of international monetary co-operation)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य

(Purposes of the International Monetary Fund)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के समझौता-पत्र (Articles of the Charter) के अनुसार उसकी स्थापना के उद्देश्य अग्रलिखित है :

1. अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग (International Monetary Co operation) : मुद्रा कोष की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य संसार के विभिन्न देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना है। कोष सदस्य देशों में अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक क्षेत्र में विचार विमर्श तथा मिल जुल कर कार्य करने की व्यवस्था करता है।

2. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार तथा संतुलित विकास (To facilitate the expansion and balanced growth of International Trade) : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सभी बाधाओं को दूर कर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार तथा संतुलित विकास को सुविधाजनक बनाना है और इस प्रकार देशों में वास्तविक आय तथा वृत्ति के उच्चस्तर बनाये रखने तथा उन्हें विकसित करने और उनके उत्पादक-साधनों का विकास करने में योगदान करना है।

3. विनिमय स्थायित्व (To Promote Exchange Stability) : मुद्रा कोष का महत्वपूर्ण उद्देश्य विनिमय दरों में स्थिरता लाना है। विनिमय दरों में उच्चावचन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को हानि पहुँचाते हैं। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् देशों की विनिमय दरों में अस्थिरता तथा व्यापारिक लाम प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक मुद्रा अवमूल्यन के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत घट गया। स्वर्णमान के पतन से उसकी स्वयंचालित प्रणाली द्वारा विनिमय स्थायित्व प्राप्ति की व्यवस्था समाप्त हो गई थी और पत्र मुद्रामान के अतर्गत विनिमय-दरों में उच्चावचन बहुत अधिक होने लगे थे। अतः सदस्य देशों के बीच विनिमय व्यवस्था (Orderly Exchange Arrangements) बनाये रखने के लिए विनिमय स्थायित्व (Exchange Stability) का प्रोत्साहन तथा प्रतिस्पर्धात्मक मुद्रा-अवमूल्यन (Competitive Exchange Depreciation) से बचना मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य रखा गया। मुद्राकोष द्वारा निश्चिन्त दरें कुछ परिस्थितियों में परिवर्तित भी की जा सकती हैं। मुद्रा कोष स्वर्णमान की (Rigid Exchange Stability) तथा पत्र-मुद्रामान की अधिक परिवर्तनशील विनिमय-दरों (Widely fluctuating Exchange Rates) के बीच की स्थिति लोचदार विनिमय स्थायित्व (Flexible Exchange Stability) की प्राप्ति का प्रयत्न करता है।

4. बहुमुखी भुगतान प्रणाली की स्थापना में सहायता (To assist in the establishment of a Multilateral System of Payments) : मुद्रा कोष का चौथा महत्वपूर्ण उद्देश्य विभिन्न देशों द्वारा लगाये गये विनिमय-नियंत्रणों को समाप्त कर अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की ऐसी बहुमुखी प्रणाली की स्थापना में सहायता देना है

जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अवरोध समाप्त हो और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार हो।

5. भुगतानाशेषों के असंतुलन को दूर करने के लिए सदस्य देशों को आर्थिक सहायता (Making funds available to member countries to correct Balance of Payments Disequilibria) : मुद्रा कोष का पाचवा उद्देश्य सदस्य देशों के बीच भुगतानाशेषों के असंतुलन को दूर करने के लिए विदेशी मुद्रा उधार देना है जिससे वे अपनी अल्पकालीन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकें। ऐसा करते समय सदस्य देश ऐसा कोई भी कार्य न करने के लिए बाध्य है जो राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय समृद्धि के हित में न हो।

6. भुगतानाशेषों के असंतुलन की अवधि तथा मात्रा में कमी (To shorten the duration and lessen the degree of disequilibrium in International Balance of Payments of members) उपर्युक्त प्रबन्धों के अनुरूप मुद्रा कोष सदस्य राष्ट्रों की कठिनाइयों के समय सहायता कर उनके भुगतानाशेषों के अल्पकालीन असंतुलन की अवधि तथा मात्रा (Duration and Degree of Temporary Balance of Payments Disequilibria) में कमी लाता है। इस प्रकार सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता।

कोष की सदस्यता

(Membership of the Fund)

कोष की सदस्यता सभी देशों के लिए सुलभ है परन्तु सदस्य देशों के लिए कोष के उद्देश्यों तथा शर्तों का पालन करना आवश्यक है। उद्देश्यों तथा शर्तों की अवहेलना करने वाले राष्ट्रों को सदस्यता से पृथक् किया जा सकता है परन्तु इससे पहले उसे उचित चेतावनी देनी पड़ती है। सदस्य राष्ट्र अपनी इच्छानुसार सदस्यता का त्याग भी कर सकते हैं। कोष की स्थापना के समय इसके 40 सदस्य थे परन्तु अब उनकी संख्या बढ़कर 111 हो गई है। चार नवोदित राष्ट्रों—बोट्सवाना (Botswana) लेसेथो (Lesotho), माल्टा (Malta) तथा मारीशस (Mauritius) न पिछले वर्ष (1968) में ही कोष की सदस्यता ग्रहण की।

कोष की पूंजी तथा अग्रगण्यता

(Capital and Quotas)

मुद्राकोष के सदस्यों का अग्रगण्यता (Quota) निर्दिष्ट कर दिया जाता है और इन अग्रगण्यता का योग ही मुद्रा कोष की पूंजी है। यदि कोई सदस्य देश अपने अग्रगण्यता की मात्रा में परिवर्तन कराना चाहे तो कोष उस पर विचार कर सकता है परन्तु कुल मूल शक्ति का 80 प्रतिशत उस परिवर्तन के पक्ष में होना आवश्यक है। प्रत्येक

देश को कम से कम अपने अभ्यश वा 25 प्रतिशत अथवा अपने स्वर्ण तथा डालर कोषों का 10 प्रतिशत (इन दोनों में जो भी कम हो) स्वर्ण में तथा शेष अपने देश की मुद्रा में मुद्रा कोष को देना आवश्यक होता है। मुद्राकोष के स्वर्ण कोष का 50 प्रतिशत भाग सबसे अधिक अभ्यश वाले देश में तथा कम से कम 40 प्रतिशत अन्य चार अधिकतम अभ्यश वाले देशों में रखा जाता है। देशों की राष्ट्रीय मुद्रा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के खाते में देशों की केन्द्रीय बैंकों के पास ही रखा रहती है।

सदस्य राष्ट्रों के अभ्यश निर्धारित करते समय (1) उनका राजनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व (2) उनकी राष्ट्रीय आय (3) उनके स्वर्ण तथा विदेशी विनिमय कोष, तथा (4) उनके भुगतानांशों की स्थिति इत्यादि पर ध्यान दिया गया है।

ब्रिटन बुडस सम्मेलन के निर्णयानुसार मुद्रा कोष की पूंजी 10,000 मिलियन डालर निश्चित की गई थी परन्तु 1200 मि० डालर के अभ्यश वाले रूस द्वारा सदस्यता स्वीकार न करने के कारण प्रारम्भ में कोष के कुल साधन 8,800 मि० डालर ही थे जिसे सदस्य राष्ट्रों के अभ्यशों के रूप में बाटा गया था तथा शेष बाद में बनने वाले सन्स्यों में निर्धारित होना था। उस समय कुछ प्रमुख देशों के अभ्यश थे—अमेरिका 2750 मि० डालर, इंग्लैंड 1300 मि० डालर, चीन 550 मि० डालर, फ्रान्स 525 मि० डालर, भारत 400 मि० डालर तथा कनाडा 300 मि० डालर इत्यादि।

अभ्यश वृद्धि (Increase in Quotas) अक्टूबर 1958 में नयी दिल्ली में हुई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 13 वीं वार्षिक बैठक में कोष की पूंजी बढ़ाने का निर्णय लिया गया और कार्यकारी सचालको (Executive Directors) को अधिकार दिया गया कि इस प्रश्न पर विचार कर अपना प्रतिवेदन दे। कार्यकारी सचालकों ने 22 दिसम्बर 1958 को अपनी रिपोर्ट पेश की और सदस्य देशों के अभ्यशों में 50 प्रतिशत वृद्धि का सुझाव दिया। इस प्रतिवेदन के स्वीकृत होने पर 15 दिसम्बर 1959 से अधिकांश देशों के अभ्यशों में 50 प्रतिशत वृद्धि कर दी गई। कनाडा, पश्चिमी जर्मनी तथा जापान के तीव्र आर्थिक विकास के कारण उनके अभ्यशों में अतिरिक्त वृद्धि का सुझाव भी स्वीकृत हो गया।

अभ्यशों में फिर वृद्धि (Increase in Quotas again) मुद्रा कोष की सितम्बर 1963 में टोकियो में हुई अपनी वार्षिक बैठक में अभ्यशों की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव का गई और कार्यकारी सचालको को निश्चित प्रस्ताव पेश करने को कहा गया। 26 फरवरी 1965 के अपने प्रतिवेदन में कार्यकारी सचालको ने सदस्य देशों के अभ्यशों में 25 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त 16 देशों के अभ्यशों में विशेष वृद्धि (Special Increase) करने का

सुभाव दिया गया था। वे 16 देश थे—ब्रासिलिया, कनाडा, फिनलैंड, पश्चिमी जर्मनी, ग्रीस, ईरान, इज्राइल, जापान, मेक्सिको, नाबो, फिलीपीन्स, दक्षिणी अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, थायरलैंड तथा वेनजुला। कार्यकारी सचिवों का यह सुभाव बोर्ड आफ गवर्नर्स ने अपन 31 मार्च 1965 के प्रस्ताव द्वारा स्वीकार कर लिया।

दिसम्बर 1959 तथा मार्च 1965 की अग्र्यश वृद्धि को निम्न तालिका में दिखाया गया है :

मुद्रा कोष में मुख्य देशों के अग्र्यश

(मिलियन डालरों में)

देश	अग्र्यश (प्रारम्भिक)	अग्र्यश दिस 1959	अग्र्यश मार्च 1965	नई अग्र्यश वृद्धि की स्वीकृति तिथि
U S A.	2750	4125	5160	Feb. 23, 1966
U K.	1300	1950	2440	March 23, 1966
China	550	550	690	— —
France	525	787.5	985	Aug. 17, 1966
India	400	600 0	750	March 12, 1966
West Ger- many	300	787.5	1200	May 27, 1966
Canada	300	550	740	May 31, 1966
Japan	250	500	725	March 25, 1966
Italy		500	625	March 24, 1966
Netherlands		412.5	520	May 25, 1966
Australia		400	500	Feb 23, 1966

मार्च 1965 में सभी सदस्य देशों के अग्र्यश में 25 प्रतिशत तथा 16 देशों के अग्र्यश में विशेष वृद्धि हो जाने के बाद इस विषय पर सदस्य देश अपनी स्वीकृति देते रहे हैं। 27 मई 1968 तक 95 सदस्य देशों ने इस सम्बन्ध में अपनी सहमति कोष को दे दी है। अग्र्यश वृद्धि की स्वीकृति भेजने वाले इन 95 सदस्य देशों की मत शक्ति कुल सदस्यों की मत शक्ति (26 फरवरी 1965 को) का 95.83 है। 26 फरवरी 1965 को जो कोष के सदस्य थे उनमें से 6 सदस्य देशों ने अग्र्यश वृद्धि के प्रस्तावों पर अपनी औपचारिक स्वीकृति 30 अप्रैल 1968 तक कोष को नहीं दी है।

दिसम्बर 1968 को मुद्रा कोष के 111 सदस्य देशों के अग्र्यशों का योग 21198 मि० डालर था।

मुद्रा कोष एवं विनिमय स्थायित्व

(Monetary Fund and Exchange Stability)

जैसा कि हम अध्ययन कर चुके हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख उद्देश्य विनिमय-दरों में स्थायित्व की स्थापना करना है तथा सदस्य राष्ट्रों के बीच

नियमित विनिमय व्यवस्था (Orderly Exchange Arrangements) बनाये रखना है जिससे अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का विस्तार तथा सन्तुलित विकास बिना किसी अवरोध के हो सके। किन्तु विनिमय-स्थायित्व के लिए विभिन्न देशों की मुद्राओं के बीच एक सामान्य आधार (Common Basis of Currencies) की आवश्यकता है। इसीलिए कोष में सदस्य देशों के बीच समता दरों के निर्धारण की व्यवस्था है।

समता-दरों का निर्धारण (Determination of Par Values) :

विनिमय-स्थायित्व तथा विभिन्न देशों की मुद्राओं के लिए एक सामान्य आधार प्राप्त करने के लिए सभी सदस्य देशों को अपनी मुद्रा की कीमत स्वर्ण या अमरीकी डालर (जिसका वजन तथा शुद्धता वह होगी जो 1 जुलाई 1944 को थी) में यक्त करनी पड़ती है और इस प्रकार प्रत्येक सदस्य देश की समता-दरों (Par Values) का पता लग जाता है। सदस्य देशों की मुद्राओं की समता दर को स्वर्ण अथवा डालर में ज्ञात करने के बाद विनिमय-दरों के निर्धारण में कोई कठिनाई नहीं रह जाती।

समता-दरों में परिवर्तन (Changes in Par Values) .

अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान की तरह विनिमय-दरों को बिल्कुल स्थायी (Rigid Exchange Stability) नहीं बनाता बल्कि एक सीमा में विनिमय-दरों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। कोष के Articles of Agreement के Articles IV की विभिन्न धाराओं के अनुसार समता-दरों में परिवर्तन के नियम इस प्रकार हैं—

(1) कोई भी सदस्य देश 'आधारभूत असंतुलन' (Fundamental Disequilibrium) को दूर करने के उद्देश्य के अतिरिक्त समता-दरों में परिवर्तन नहीं करेगा।

(2) समता-दरों में परिवर्तन केवल सदस्य देश के प्रस्ताव पर तथा कोष से परामर्श करके ही किया जा सकता है।

(3) यदि समता-दर में परिवर्तन 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं है तो कोष को कोई एतराज नहीं होगा। इसके अतिरिक्त सदस्य देश समता-दर में 10 प्रतिशत तक और (अर्थात् कुल 20 प्रतिशत) परिवर्तन कर सकते हैं और इसके लिए कोष स्वीकृति दे सकता है मना भी कर सकता है परन्तु इस सम्बन्ध में अपना निर्णय 72 घंटे के अन्दर ही देना पड़ता है। उपर्युक्त दो सीमाओं से भी अधिक (अर्थात् प्रारम्भिक समता-दर में 20 प्रतिशत से अधिक) परिवर्तन के लिए सदस्य देश कोष से प्रार्थना कर सकते हैं और कोष इसे स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है

परन्तु निर्णय देने में अधिक समय लग सकता है। 20 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन के लिए कोप के सदस्य देशों के दो-तिहाई बहुमत की सहमति आवश्यक है।

(4) कोई भी सदस्य देश कोप की बिना सहमति के समता दर में परिवर्तन कर सकता है यदि यह परिवर्तन सदस्य राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय सौदों पर बुरा प्रभाव न डालता हो।

मुद्रा कोप समता दरों में परिवर्तन की अनुमति तभी देता है जब उसे विश्वास हो जाता है कि परिवर्तन 'आधारभूत असाम्यता' (Fundamental Disequilibrium) के सुधार के लिए आवश्यक है। इसके पीछे कोप का मन्तव्य यह है कि समता दरों में परिवर्तन सदस्य देशों के आन्तरिक कीमन तथा आय तलों में परिवर्तन के अनुसार ही हो। कोप प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय अवमूल्यन (Competitive Exchange Depreciation) की स्वीकृति कभी नहीं देता क्योंकि यह कोप के मूलभूत उद्देश्यों के विरुद्ध है।

इस प्रकार कोई भी सदस्य देश बिना कोप की अनुमति के विनिमय-दर में 10 प्रतिशत तक परिवर्तन कर सकता है। 'आधारभूत असाम्यता' क्या है, इस सम्बन्ध में निर्णय लेते समय कोप सदस्य देश की राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों से प्रभावित नहीं होना। इस प्रकार सदस्य देशों की आन्तरिक नीति में कोप किमी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता और उन्हें स्वतन्त्र मौद्रिक तथा आर्थिक नीतियाँ अपनाने की स्वतन्त्रता रहनी है। इस प्रकार "कोप ने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों में निःशस्त्रीकरण के उपाय को प्रवेश दे दिया है।" (The Fund has introduced a measure of disarmament into the field of international economic relations) इस प्रकार की स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान की स्वचालिता व्यवस्था में नहीं थी। इस प्रकार मुद्रा कोप अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान की स्थायी विनिमय दर के स्थान पर सदस्य देशों को विनिमय दर में व्यवस्थित-परिवर्तन की सुविधा प्रदान करता है। (The Fund substitutes for the Gold Standard's exchange rigidity, the principle of managed flexibility in the adjustment of exchange values of member currencies.)

सदस्य देशों द्वारा 20 प्रतिशत तक समता दरों में परिवर्तन की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रो० के० के० कुरिहरा (Prof K K Kurshara) का कथन है—

"It is one important concession to exchange flexibility which is impossible under either the gold standard or the paper standard. For under the Gold Standard, the exchange flexibility of any kind is out of the question while under the paper standard, exchange flexibility is in the habit of degenerating into disorderly, discriminatory competitive exchange depreciation"¹

¹ K K. Kurshara : *Monetary Theory and Public Policy*, p p 343-4

मुद्रा कोष से ऋण व्यवस्था (Credit Arrangements under the Fund)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक महत्वपूर्ण कार्य सदस्य देशों को मुग्नान्त-शेष के अस्थायी घाटे (Temporary Deficits) की पूर्ति के लिए विदेशी मुद्रा के ऋण देना है। मुद्रा कोष के पास सभी देशों की मुद्रायें होती हैं और आवश्यकता पड़ने पर सदस्य देश किसी देश की मुद्रा उधार ले सकते हैं। कोष किसी देश के लिए आवश्यक सारी विदेशी मुद्रा की पूर्ति का दायित्व नहीं लेना। कोष के द्वारा दी जाने वाली ऋण सुविधा सकट काल की द्वितीय रक्षा पक्ति का कार्य करती है।

ऋण देने की शर्तें (Conditions for Loans) :

सदस्य अपनी मुद्रा देकर विदेशी मुद्रा निम्नलिखित शर्तों पर त्रय कर सकते हैं—

(1) विदेशी मुद्रा का त्रय कोष के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए अर्थात् ऋण देश के अति आवश्यक ऋण चालू सौदों की वित्त व्यवस्था करने के लिए होने चाहिए न कि पूंजी सौदों की पूर्ति के लिए।

(2) किसी भी समय कोष के पास किसी सदस्य देश की मुद्रा की मात्रा उसके अर्थशास्त्र के 200 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् सदस्य देश अधिक से अधिक अपने अर्थशास्त्र के 125 प्रतिशत तक विदेशी मुद्रा खरीद सकते हैं।

(3) कोई भी सदस्य देश एक वर्ष की अवधि में अपने अर्थशास्त्र के 25 प्रतिशत से अधिक विदेशी मुद्रा नहीं खरीद सकता। (परन्तु पिछले वर्षों में इस धारा का पालन नहीं हो रहा है और प्रायः 50 प्रतिशत तक ऋण दे दिए जाते हैं)

उपर्युक्त शर्तों को एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। माना कि किसी सदस्य देश का अर्थशास्त्र 200 मिलियन डालर है जिसका 25 प्रतिशत अर्थात् 50 मि० डालर स्वयं में तथा 75 प्रतिशत अर्थात् 150 मि० डालर की शेष राशि सदस्य देश की राष्ट्रीय मुद्रा में कोष के पास जमा कराई गई है। शर्तों के अनुसार कोष के पास सदस्य देश की मुद्रा उसके अर्थशास्त्र के 200 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये अर्थात् 400 मि० डालर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें 150 मि० डालर अर्थशास्त्र के रूप में उसने पहले ही जमा करा दी है इसलिए ऋण के रूप में अब उसे $(400-150)=250$ मि० डालर (अर्थात् अर्थशास्त्र का 125 प्रतिशत) ही प्राप्त हो सकता है। अन्तिम शर्त के अनुसार किसी एक वर्ष में सदस्य देश अपने अर्थशास्त्र का 25 प्रतिशत से अधिक ऋण नहीं प्राप्त कर सकता अतः 250 मि० डालर उसे पांच

वर्ष की अवधि में प्राप्त करने चाहिए परन्तु इस शर्त का अर्थ कोष द्वारा ढील बरतने के कारण महत्व नहीं रह गया है।

ऋणों के प्रकार (Kinds of Loans) •

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिए जाने वाले ऋण चार प्रकार के होते हैं—

(1) सकटकालीन ऋण (Emergency Loans) यदि किसी देश या क्षेत्र में आकस्मिक आर्थिक संकट की परिस्थिति पैदा हो जाय या कोई राजनैतिक संकट खड़ा हो जाय जिससे देशों के आर्थिक स्थायित्व को खतरा पैदा होने की आशंका हो तो ऐसे समय कोष सकटकालीन ऋण देता है। दिसम्बर 1956 में ब्रिटेन को स्वेडन-नहर संकट के समय दिया गया ऋण इसका उदाहरण है।

(2) स्थायित्व ऋण (Stability Loans) मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य विनिमय दरों में स्थायित्व की स्थापना करना है। आर्थिक कठिनाइयों के समय देश बहुमुखी विनिमय दर (Multiple Exchange Rates) अपना लेते हैं और विभिन्न देशों या विभिन्न वस्तुओं के भुगतान के लिए अलग अलग विनिमय दरें प्रयुक्त होती हैं। बहुमुखी विनिमय दर समाप्त कर विनिमय दर समता स्थापित करने के लिए देशों को स्थायित्व ऋण दिए जाते हैं। इज्याइल, कोस्टारिका, ब्राजील आदि देशों का ये ऋण दिए गये हैं।

(3) सामयिक विनिमय कठिनाई दूर करने के लिए ऋण (Loans to tide over Seasonal Exchange Difficulties) जिन देशों को मौसमी या सामयिक निर्यातों के कारण भुगतान शेष की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनको अल्पकाल के लिए (६ माह से 1 वर्ष तक) ऋण दिए जाते हैं। उदाहरणार्थ एलसेल्वाडर, क्यूबा, निकारागुआ को दिए गये ऋण।

(4) धातू भुगतान शेष की असाम्यता दूर करने के ऋण (Loans to tide over current Balance of payments disequilibria) — सदस्य देशों की विकास योजनाओं को क्रियान्वित करते समय उनको भुगतानाशेष की असाम्यता की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इन अल्पकालीन कठिनाई को दूर करने के लिए मुद्राकोष ऋण सहायता देता है। इस प्रकार के ऋण भारत, जापान, कनाडा फ्रांस आदि देशों को दिए गये हैं।

ऋण शुल्क (Charges)

मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों को दिए गये विदेशी मुद्रा के ऋणों पर शुल्क लिया जाता है। शुल्क की दर ऋण की मात्रा तथा अवधि पर निर्भर करती है। जैसे जैसे ऋण की मात्रा तथा अवधि बढ़ती जाती है वैसे वैसे शुल्क की दर भी बढ़ती जाती है। शुल्क की दरें 0.5 प्रतिशत से 5.0 प्रतिशत होती हैं। तीन माह

तक के लिए गये ऋणों पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता। शुल्क का भुगतान स्वयं में किया जाना चाहिए।

दुर्लभ मुद्रायें (Scarce Currencies) :

किसी देश की मुद्रा 'दुर्लभ मुद्रा' (Scarce Currency) होने का तात्पर्य यह है कि सदस्य देश उस मुद्रा को लगातार खरीदते रहे हैं और कोष के पास उसका भंडार न्यूनतम रह गया है। ऐसी स्थिति में कोष सदस्य देशों की सापेक्षिक आवश्यकताओं तथा सामान्य अन्तर राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति इत्यादि बातों को ध्यान में रख कर उस मुद्रा की राशनिंग कर देता है जिससे उसकी मांग तथा पूर्ति में समायोजन स्थापित हो सके।

किसी देश की मुद्रा 'दुर्लभ' क्यों हो जाती है? या तो (1) उस देश की मुद्रा अधोमूल्यित (Undervalued) है या (2) उस देश ने आयातों पर ऊँचे कर लगा रखे हैं या (3) उस देश ने विदेशों में अपनी पूँजी का पर्याप्त विनियोजन नहीं किया है या (4) वह देश विदेशों में वस्तुओं का राशि पातन (Dumping) करता रहा है। वास्तव में किसी देश की मुद्रा के दुर्लभ होने का तात्पर्य यही है कि उस देश का भुगतान शेष लगातार उसके अनुकूल रहा है। इसका कारण आर्थिक विकास की उच्चावस्था तथा नियति की अनुकूल स्थिति होती है। वास्तव में विनिमय स्थायित्व को धक्का पहुँचाने में अनुकूल भुगतान शेष वाले देश उतने ही दोषी हैं जितने प्रतिकूल भुगतान शेष वाले देश और दोनों ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास को हानि पहुँचाते हैं। कोष ऐसे देशों को अपनी मुद्रा का पुन-मूल्यन (Revaluation) करने का परामर्श देता है जिससे उसके आन्तरिक मूल्य तथा लागत तल में वृद्धि हो, उसके आयात बढें और निर्यात घटें और इस प्रकार स्थिति में सुधार हो। कोष सदस्य देशों को दुर्लभ मुद्रा वाले देश के प्रति विनिमय नियन्त्रण लगाने का अधिकार दे सकता है।

कोष के साधनों की तरलता (Liquidity of the Fund's Resources) —

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सस्यार में एक रक्षित कोष के रूप में सदा सहायक होने के उद्देश्य से अपने साधनों को सदा तरल बनाये रखने का प्रयत्न करता है। यदि सदस्य देश अपनी मुद्रा के बदले दुर्लभ मुद्रा खरीदते चले जाय तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि कोष के पास अधिक मांगी जाने वाली मुद्रा के कोष समाप्त हो जाय और उसके पास ऐसी मुद्रा के भंडार अत्यधिक हो जाय जिनकी मांग न हो। ऐसा होने पर कोष रक्षित कोष के अपने दायित्व पूर्ण नहीं कर सकेगा। इसीलिए सदस्य देशों द्वारा विदेशी मुद्रा खरीदते समय जो अपनी मुद्रा दी जाती है उसके पुन-प्राप (Re purchase) की व्यवस्था है। कोष के साधनों की तरलता के लिए यह भी

व्यवस्था है कि (i) सदस्य देश स्वर्ण देकर किसी देश की भी मुद्रा क्रय कर सकते हैं, (ii) यदि कोष के पास किसी देश की मुद्रा उसके अन्त्यक्ष से अधिक मात्रा में है तो वह अतिरिक्त मुद्रा स्वर्ण देकर क्रय कर सकता है तथा (iii) सदस्य देश कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में कोष के पास अपनी मुद्रा का कुछ भाग स्वर्ण या परिवर्तनीय मुद्रा देकर क्रय कर सकता है।

पिछले दस-बारह वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व विस्तार तथा विश्व के आर्थिक विकास के उद्देश्य में अन्तर्राष्ट्रीय तरलता (International Liquidity) बढ़ाने के लिए चर्चाएँ हुईं और बहुत से सुझाव दिए गए। ट्रिफिन योजना (Triffin Plan), स्टाम्प योजना (Stamp Plan) बर्नस्टीन योजना (Bernstein Plan) इत्यादि अनेक योजनाएँ रक्खी गईं।

स्पेशल ड्राइंग राइट्स (Special Drawing Rights):

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सितम्बर 1967 में रियोडेजेनरो (Rio de Janeiro) में हुई वार्षिक बैठक में स्पेशल ड्राइंग राइट्स (Special Drawing Rights) (S. D. R.) की व्यवस्था स्वीकार की गई जिसका अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक जगत में हार्दिक स्वागत हुआ। रियोडेजेनरो बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार 19 अप्रैल 1968 को कोष के कार्यकारी सचालकों ने Articles of Agreement में संशोधन सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट बोर्ड आफ गवर्नर्स को भेज दी जब यह संशोधन विधिवत स्वीकार किए जाने हैं। समझौते की धाराओं में आवश्यक संशोधन स्वीकृत होते ही यह वित्तीय सहायता सदस्य राष्ट्रों को प्राप्त होने लगेगी। सितम्बर 1969 में होने वाली कोष की वार्षिक बैठक में S. D. R. के Ratification के सम्बन्ध में निम्न पर पूर्व बातचीत के लिए Group of Ten की बैठक जून 1969 में पेरिस में हुई जिसमें S. D. R. के समय तथा मात्रा दोनों पर मतभेद थे। शायद अगस्त तक इन देशों की फिर कोई बैठक हो।

मुद्रा कोष व्यवस्था में स्वर्ण का स्थान (Position of Gold under the Fund's Scheme)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की व्यवस्था में स्वर्ण को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कोष को कई प्रकार से स्वर्ण के साथ सम्बन्धित किया गया जैसा कि निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट है—

(1) सदस्य देशों को अपनी मुद्रा की प्रारम्भिक विलिपय दर (Initial par value) स्वर्ण में ही निश्चित करनी होती है। इस प्रकार स्वर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य-मापक (International measure of value) तथा सामान्य इकाई (Common Denominator) का कार्य करता है।

(2) सदस्य देशों को अपने अम्यश (Quota) का एक निश्चिन्न भाग स्वर्ण में ही जमा कराना पड़ता है। प्रत्येक सदस्य देश को अपने अम्यश का 25 प्रतिशत भाग अथवा अपने स्वर्ण तथा डालर कोपो का 10 प्रतिशत (इन दोनों में जो भी कम हो) स्वर्ण में जमा कराना पड़ता है।

(3) सदस्य देश स्वर्ण का क्रय विनय कोप द्वारा निर्धारित दर पर ही कर सकते हैं।

(4) कोप व्यवस्था के अनुसार प्रतिकूल भुगतान शेष वाल देश (Deficit Countries) स्वर्ण देकर विदेशी मुद्रा क्रय कर सकते हैं। अनुकूल भुगतानशेष वाले देशों (Surplus Countries) से स्वयं मुद्रा कोप स्वर्ण देकर उनकी मुद्रा खरीद सकता है।

मुद्रा कोप की व्यवस्था में स्वर्ण को इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप को स्वर्ण मान का पुनर्स्थापन माना है। प्रो० जान० एच० विलियम्स (Prof. John H. Williams) के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान में कोई अन्तर नहीं है। उनके अनुसार मुद्रा कोप से लेन देन का प्रभाव सदस्य देशों पर उभी प्रकार पड़ता है जिस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान में स्वर्ण के आयात-निर्वात (Gold Import and Export) का पड़ता था।

मुद्रा कोप तथा स्वर्ण मान में समानताएँ (Similarities between the fund and gold standard) :

मुद्रा कोप की व्यवस्था को स्वर्णमान का पुनर्स्थापन मानने वाले अपने मत के पक्ष में मुद्रा कोप तथा स्वर्ण मान की निम्नलिखित समानताओं को तर्क के रूप में प्रस्तुत करते हैं :

(1) दोनों में विनिमय दरों का स्वर्ण में निर्धारण (Exchange Rates determined in terms of Gold) — अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप की व्यवस्था में स्वर्ण को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य मापक के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रत्येक देश को अपनी मुद्रा को स्वर्ण के मूल्य में ही व्यक्त करना पड़ता है और इस प्रकार विनिमय समता दरों का निर्धारण होता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान में भी देश अपनी मुद्राओं की विनिमय दर मुद्रा के स्वर्ण मूल्य के अनुपात में ही निश्चिन्न करते थे।

(2) दोनों में बहु पक्षीय भुगतान प्रणाली (Multilateral Payment System exists under both):—जिस प्रकार स्वर्णमान में मुद्राओं के स्वर्ण मूल्य के अनुपात में विनिमय दरों का निर्धारण कर एक बहु पक्षीय भुगतान प्रणाली चलन में थी उसी प्रकार मुद्रा कोप भी निश्चित समता दरों के द्वारा विभिन्न देशों की

मुद्राओं की बहुपक्षीय परिवर्तनशीलता को प्रोत्साहन देता है। (Fund also encourages multilateral Convertibility of currencies at fixed parities).

(3) स्वर्ण या अन्यथा द्वारा प्रतिकूल भुगतान शेष में सुधार (Improvement in adverse balance of Payments Position through gold or Quota) — अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान में प्रतिकूल भुगतान शेष वाले देश को स्वर्ण का निर्यात कर असंतुलन दूर करना पड़ता था। अब मुद्रा कोप व्यवस्था में स्वर्ण का स्वयं अन्यथा (Quota) ले ले लिया है जिसके आधारे पर ही विदेशी मुद्रा के ऋण प्राप्त होते हैं। उना कि प्रो० जान० एच० विलियम्स ने कहा है :—

“Transactions made through the Fund affect bank reserves in precisely the same manner as the movements of gold under the gold standard”¹

(4) दोनों में स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को भायता तथा विनियमनियन्त्रण दूर करने का सुझाव (Both accept the Principle of Free International Trade and Removal of Exchange Controls) — स्वर्णमान की तरह मुद्रा कोप भी अवरोध रहित स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार तथा सतुलित विकास के सिद्धान्त को मानता है और विनियम निपन्त्रणों को दूर करने का प्रयत्न करता है।²

उपर्युक्त तर्कों के आधारे पर यह कहा जाता है कि मुद्रा कोप अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान का ही एक परिवर्तित रूप है। प्रो० जी० एन० हॉलम (Prof. George N. Halm) व अनुमार—‘कोप के अन्तर्गत स्वर्ण की स्थिति केवल दिखावा मात्र नहीं है। सदस्य देशों की मुद्राओं की स्थिरता प्रदान करने तथा कोप के सबसे तरल आदय के रूप में स्वर्ण का महत्वपूर्ण योगदान है।’³

इस विवेचन से हम यह नहीं मान लना चाहिए कि मुद्रा कोप व्यवस्था स्वर्णमान का ही प्रतिरूप है। वास्तव में दोनों व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण अन्तर है। इसी कारण

¹ John H. Williams : *Post War Monetary Plans*, pp 8-9

² “Under gold standard there are no restrictions on international movement of goods in the form of quotas or other exchange restrictions. The Fund also frowns upon such restrictions and is committed to their removal as early as possible and the establishment of multilateral trade on the basis of freely convertible currencies”.

³ “The Fund’s gold provisions are not just window dressing. Gold plays a really important role as the Fund’s most liquid asset and as a common anchorage for the member currencies”

—George N. Halm : *Monetary Theory*, p 285.

लाई जे० एम० कीन्स ने कोष व्यवस्था को स्वर्णमान का ठीक उल्टा माना है। (The new arrangement [I. M. F.] is just the opposite of gold Standard.) इस मत के पक्ष में स्वर्णमान तथा मुद्रा कोष की अद्यमानता को तर्क के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

मुद्रा कोष तथा स्वर्णमान में अद्यमानताएँ (Dissimilarities between the Fund and Gold Standard):—

मुद्रा कोष व्यवस्था तथा स्वर्णमान में निम्नलिखित महत्वपूर्ण अन्तर हैं —

(1) विनिमय-दर तथा अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की स्थिति (Rate of Exchange and International Payments position) — अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के अन्तर्गत विनिमय-दरों में जड़ स्थायित्व (Rigid Exchange Stability) होता है क्योंकि स्वर्णमान का उद्देश्य दरों में पूर्ण स्थिरता की स्थापना है परन्तु मुद्रा कोष में समता दरों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन की व्यवस्था है। मुद्रा कोष विनिमय दरों में लोचदार विनिमय स्थायित्व (Flexible Exchange Stability) की स्थापना करता है।

(2) देश की आर्थिक नीतियाँ (Economic Policies of the Country):— स्वर्णमान के अन्तर्गत स्वचालिता के कारण स्वर्ण के गमनागमन का प्रभाव उत्पादन तथा वृत्ति तल पर पड़ना था। प्रतिकूल भुगतानशेष के फलस्वरूप स्वर्ण का निर्यात हो जाता था और मुद्रा तथा साख का सङ्कुचन हो जाता था जिससे मन्दी तथा बेकारी फैलती थी। अर्थव्यवस्था पर इन कुप्रभावों में मुद्रा कोष व्यवस्था में बचा जा सकता है क्योंकि भुगतान शेष के अस्थायी असाध्य में सुधार के लिए मुद्रा कोष सदस्य देशों को विदेशी मुद्रा के ऋण देता है। इस प्रकार स्वर्णमान के अन्तर्गत देश की आर्थिक नीतियों पर अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय सम्बन्धों का प्रभाव पड़ता है जबकि मुद्रा कोष की व्यवस्था में सभी देश स्वतन्त्र आर्थिक नीतियाँ अपनाते हैं।

(3) विनिमय दरों का निर्धारण तथा व्यवस्था की प्रकृति (Determination of Rates of Exchange and Nature of the System) : स्वर्णमान एक स्वचालित मान (Automatic Standard) है और उसमें विनिमय दरों का निर्धारण स्वामाविक रूप से हो जाता है। मुद्रा कोष द्वारा स्थापित स्वर्ण-समता मान एक प्रबन्धित मान (Managed Standard) है और इस व्यवस्था में विनिमय-दरों का निर्धारण कृत्रिम रूप से होता है।

(4) मौद्रिक नीति के उद्देश्य (Objectives of Monetary Policy) : स्वर्णमान के अन्तर्गत मौद्रिक नीति का पहला उद्देश्य विनिमय-दरों की स्थिरता स्थापित करना था जिसे स्वर्ण के आयात तथा निर्यात (Inflow and Outflow

of Gold) द्वारा प्राप्त किया जाता था परन्तु आजकल मौद्रिक नीति के उद्देश्यों में 'कीमत स्थिरता' (Price Stability) को अधिक महत्व दिया जाता है। मुद्रा कोष व्यवस्था जड़ताओं से दूर होकर आधारभूत असाम्य की स्थिति में विनिमय दरों में परिवर्तन की आज्ञा देता है।

स्वर्णमान तथा मुद्रा कोष के अन्तर के बारे में 23 मई 1944 को House of Lords में अपने भाषण में लार्ड जे० एम० कीन्स (Lord J. M. Keynes) ने कहा था कि—“स्वर्णमान व्यवस्था में देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य पूर्णतया स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा से बंधा होता है। इस मूल्य में केवल प्रधान शक्ति की अनुमति से ही परिवर्तन किया जा सकता है। स्वर्णमान में देश को एक ऐसी वित्तीय नीति का पालन करना पड़ता है जिसके अन्तर्गत मुद्रा के आन्तरिक मूल्य को उसके बाह्य मूल्य के समान रखना पड़ता है। इसके विपरीत स्वर्ण को एक ऐसे सामान्य मापक के रूप में उपयोग करना, जिसके द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय मुद्राओं का सापेक्ष मूल्य जिसमें बिना किसी प्रकार की कठिनाई के समझ-समय पर परिवर्तन किए जा सकते हैं, स्वर्णमान से बिल्कुल भिन्न है। कोष की योजना में देश की मुद्रा के आन्तरिक मूल्य में उसके बाह्य मूल्य के अनुसार परिवर्तन होने के बजाय उसके बाह्य मूल्य में उसके आन्तरिक मूल्य के अनुसार परिवर्तन किए जाते हैं। वास्तव में कोष का यह कर्तव्य है कि सदस्य देशों की मुद्राओं के बाह्य मूल्यों में किए जाने वाले इस प्रकार के परिवर्तनों को स्वीकार करे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह प्रस्ताव स्वर्णमान के ठीक उल्टे हैं। कोष की योजना में अन्तर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा एक नये सिद्धान्त का सार प्रस्तुत किया गया है जो स्वर्णमान की पुरानी जड़ता से कोसों दूर है।”²

² “The gold standard, as I understand it, means a system under which the external value of a national currency is rigidly tied to a fixed quantity of gold which can only honourably be broken under *force majeure*, and it involves a financial policy which compels the internal value of the domestic currency to conform to this external value as fixed in terms of gold. On the other hand, the use of gold merely as a convenient common denominator by means of which the relative values of national currencies—these being free to change—are expressed from time to time is obviously quite another matter..... instead of maintaining the principle that the internal value of a national currency should conform to a prescribed *de jure* external value, it provides that the external value should be altered if necessary so as to conform to whatever *de facto* internal value results from domestic policies, which themselves shall be immune from the criticism by the Fund. Indeed, it is

मुद्रा कोष का संगठन तथा प्रबन्ध
(Organisation and Management of the Fund)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबन्ध दो संस्थाओं द्वारा होता है —

- (1) बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (Board of Governors)
- (2) कार्यकारी सचालक मण्डल (Board of Executive Directors)

गवर्नर मंडल (Board of Governors) : कोष की सर्वोच्च संस्था है जिसका कार्य कोष की नीति का निर्धारण करना है। गवर्नर मंडल साधारण सभा (General House) का कार्य करता है। प्रत्येक सदस्य देश को एक गवर्नर तथा एक विकल्प गवर्नर (Alternate Governor) नियुक्त करने का अधिकार है। गवर्नर की अनुपस्थिति में विकल्प-गवर्नर गवर्नर का कार्य करता है। गवर्नर मंडल के अधिकार बड़े व्यापक हैं और उसे सदस्य देशों के अभ्युक्तों में परिवर्तन, समता दरो, सदस्यों के प्रवेश इत्यादि विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत अधिकार हैं।

सचालक मंडल (Board of Executive Directors) कार्यकारिणी समिति है जिसका उत्तरदायित्व सामान्य प्रशासन तथा दैनिक कार्य संचालन करना है। सचालक मंडल में कम से कम 12 सदस्य होने चाहिए जिनमें पांच सचालक स्थायी होते हैं जो पांच सबसे अधिक अभ्युक्त वाले देशों द्वारा मनोनीत किये जाते हैं तथा शेष का निर्वाचन होता है। आजकल सचालक मंडल की कुल सदस्य संख्या (प्रबन्ध सचालक तथा सहायक प्रबन्ध सचालक को छोड़कर) 20 है जिनमें पांच सदस्य स्थायी सदस्य हैं (आजकल अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी तथा भारत स्थायी सदस्य हैं) तथा शेष 15 सदस्य देशों द्वारा निर्वाचित होते हैं। कार्यकारी सचालक के अतिरिक्त एक प्रबन्ध सचालक (Managing Director) तथा एक उप-प्रबन्ध सचालक (Deputy Managing Director) होता है। प्रबन्ध सचालक, सचालक मंडल का अध्यक्ष होता है तथा कार्यालय के कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। आजकल श्री Pierre-Paul Schweitzer प्रबन्ध संचालक तथा श्री Frank A. Southard Jr. उपप्रबन्ध सचालक का कार्य कर रहे हैं।

made the duty of the Fund to approve change which will have this effect. That is why I say that these proposals are the exact opposite of the gold standard. They lay down by "international agreement the essence of the new doctrine, far removed from the old orthodoxy"

—Text of Lord J. M. Keynes' speech delivered before the House of Lords on May 23, 1944 reproduced from *The New Economics* edited by S. E. Harris p. 376.

मुद्रा तथा बैंकिंग

मुद्रा कोष का प्रधान कार्यालय वाशिंगटन (अमेरिका) में है। कोष के विधान के अनुसार कोष का प्रधान कार्यालय सबसे बड़े अर्थशासकी देश में होगा।

मुद्रा कोष के कार्य तथा सेवाएँ (Functions and Services of the Fund)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विश्व प्रगति को बढ़ा देने के लिए महत्वपूर्ण रही हैं। उनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :

(1) ऋण तथा ऋण-वचन (Loans and stand by Agreements) :

मुद्रा कोष सदस्य देशों को आवश्यकता पड़ने पर विदेशी मुद्रा बेचता है या बेचने का वचन देता है। पिछले 21 वर्षों के मुद्रा कोष के लेन-देन इस प्रकार हैं :—

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के लेन-देन

(मिलियन डालरों में)

वर्ष	सदस्यों द्वारा कुल व्यय	मुद्रा विनय के वचन	सदस्यों द्वारा कुल पुनर्ग्रहण
1948	606 04	—	—
1949	119 44	—	—
1950	51 80	—	—
1951	28 00	—	24 21
1952	46·25	—	19 09
1953	66 12	—	36 58
1954	231 29	53 00	184·96
1955	48 75	90 00	145 11
1956	38·75	90 00	276 28
1957	1,114 05	97 50	271 66
1958	665 73	968·90	75 04
1959	263 52	884 28	86 81
1960	165 53	1,132 84	537 32
1961	577 00	291 88	522 41
1962	2,243 20	338 62	658 60
1963	579 97	1,942 88	1,260 00
1964	625 90	1,287 25	807 25
1965	1,897 44	1,970 15	380 41
1966	2,817 29	516·15	516 97
1967	1,061 28	421 04	406 00
1968	1,348 25	401·55	340·12
Total	14,595 ६०	2,017 81	1,115 51
			7,664·31

मुद्रा कोष के प्रारम्भ से 30 अप्रैल 1968 तक 65 सदस्य देशों ने 14 6 अरब डालर की मुद्राये क्रय की। इसके अतिरिक्त 5 सदस्य देशों को 9 मुद्रा विक्रय वचन स्वीकृत हुए किन्तु कोष से नय नहीं किया।

31 दिसम्बर 1968 को समाप्त हुए वर्ष में 37 सदस्य देशों ने 3552 मि० डालर कोष से निकाले। इस वर्ष के सौदों में फरवरी 1968 में कनाडा को 391 मि० डालर, मार्च में अमरिका को 200 मि० डालर, जून 1968 में फ्रांस को 885 मि० डालर और इंग्लैंड को 14 मि० डालर (नवम्बर 1967 के अवमूल्यन के समय स्वीकृत) के ऋण दिये गये। इसके अतिरिक्त भारत (90 मि०), न्यूजीलैंड (99 20 मि०), संयुक्त अरब गणराज्य (63 मि०), फिलीपीन्स (55 मि०) यूगो-स्वालिया (45 मि०) तथा पीह (42.50 मि० डालर) इत्यादि देशों को महायत्ता प्राप्त हुई।

(2) कोष द्वारा तकनीकी सहायता (Technical Assistance by the Fund) :

कोष सदस्य देशों को बड़े पैमाने पर वित्तीय मौद्रिक मामलों में तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इस कार्य के लिए वह विभिन्न देशों में विशेषज्ञ दल भेजता है। तकनीकी सहायता देशों की मौद्रिक विनिमय तथा प्रशुल्क नीतियों के निर्धारण तथा क्रियान्वयन, प्रशुल्क व्यवस्था के सुधार, केन्द्रीय बैंकिंग विधान के निर्माण, केन्द्रीय बैंकों के संगठन तथा उनकी कार्य प्रणाली के विकास, साख तथा बैंकिंग व्यवस्था में सुधार, वित्तीय तथा भुगतान सतुलन सांख्यिकी के विकास इत्यादि विषयों से सम्बन्धित होता है।

अधिकतर तकनीकी सहायता 1964 में स्थापित कोष की केन्द्रीय बैंकिंग सेवा (Central Banking Service) तथा प्रशुल्क मामलों के विभाग (Fiscal Affairs Department) के माध्यम से दी जाती है। 1967-68 में प्रशुल्क मामलों के विभागों ने 17 देशों की 30 प्रार्थनाओं पर तकनीकी सहायता दी। अधिकतर मामलों में यह सहायता विशेषज्ञों के दल भेज कर दी गई। यह सहायता कर नीति, कर-प्रशासन तथा बजट सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में दी गई। 1967-68 में केन्द्रीय बैंकिंग सेवा कर्मचारियों द्वारा 14 देशों को केन्द्रीय बैंकों के सर्वेक्षणों, बैंकिंग व्यवस्थाओं तथा साख समस्याओं को लेकर वित्तीय विधान के निर्माण तक के विषयों में दी गई। इसी वर्ष 26 देशों को 60 विशेषज्ञ भेजे गये।

(3) कोष-प्रशिक्षणालय (The IMF Institute) :

मई 1964 में स्थापित कोष प्रशिक्षणालय वित्तीय मामलों में सदस्य देशों के विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देता है। प्रशिक्षणालय अफ्रीकी, फ्रेंच तथा स्पेनिश भाषाओं में 'वित्तीय विश्लेषण तथा नीति' (Financial Analysis and Policy) पर

साडे चार महीने का कार्यक्रम चलाता है। इस विषय में पहला कार्यक्रम 9 अक्टूबर 1967 को फ्रैंच भाषा में प्रारम्भ किया गया जिसमें 18 देशों के 24 अधिकारी सम्मिलित हुए। इसके अनिर्दिष्ट प्रशिक्षणालय राजस्व (Public Finance) तथा भुगतान सतुलन रीतियों (Balance of Payments Methodology) विषयों पर कार्यक्रम चलाता है। प्रशिक्षणालय द्वारा सितम्बर 1968 से जून 1969 तक 'वित्तीय विश्लेषण तथा नीति' पर 3, भुगतान सतुलन रीतियों पर 1 तथा राजस्व पर एक कार्यक्रम चलाया गया।

(4) अन्य अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संस्थाओं से सहयोग (Relations with other International and Regional Organisations) .

मुद्रा कोष समान रुचि के विषयों पर अन्य अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों से सहाय्य करता है तथा कोष के अधिकारी उनकी सभाओं में भाग लेते हैं। विश्व बैंक (जिसके साथ कोष का विशेष सम्बन्ध है) के अतिरिक्त सयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों से कोष का घनिष्ठ सम्बन्ध है। सयुक्त राष्ट्र परिवार से बाहर अन्य संगठनों जैसे General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Bank for International Settlements (BIS), Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) इत्यादि से भी सम्पर्क रखता है।

मुद्रा कोष की आलोचना

(A Critical Appraisal of the Fund)

अपने 22 वर्ष के कार्यकाल में मुद्रा कोष ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं फिर भी उसकी कुछ अपनी सीमाएँ हैं। विभिन्न आधारों पर मुद्रा कोष की आलोचना की जाती है :

(1) कोष का कार्यक्षेत्र सीमित (Scope of the Functions of the Fund is limited)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक दीर्घकालीन मौद्रिक नियमन संस्था है और उसका कार्य केवल बालू भुगतान तक सीमित है। दीर्घकालीन ऋण तथा पूंजी के आयात-निर्यात के प्रश्न कोष के कार्य क्षेत्र से बाहर हैं। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं का समाधान कोष की वर्तमान व्यवस्था द्वारा सम्भव नहीं दीखता। फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक क्षेत्र में कोष ने सराहनीय कार्य किया है।

(2) डालर का लगातार अभाव (Continuous shortage of Dollars) :

कोष में प्रारम्भ से लेकर आज तक सदा डालर का अभाव बना रहा है और कोष इस समस्या का समाधान नहीं खोज पाया है। प्रो० विलियम्स के कथनानुसार :—

“The main trouble in the scheme of the Fund lies in the disparity between the possible demand for and the available supply of dollars in the Fund.”

मुद्रा कोष भुगतान सन्तुलन की आधारभूत समस्या विशेषकर अविश्रुत राष्ट्रों के भुगतान असन्तुलन को सुधारने में असफल रहा है। डालर तथा अन्य शक्तिशाली मुद्राओं पर पिछल सकट इस बात के प्रमाण है कि इस विषय में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है।

(3) भेदभाव पूर्ण नीति का अद्वलम्बन (Policy of discrimination followed) : मुद्रा कोष न अपनी नीतियों के कार्यान्वयन में भेदभाव पूर्ण नीति अपनायी है। आलोचकों का आरोप है कि कोष अमेरिका तथा अन्य बड़े पश्चिमी राष्ट्रों की इच्छानुसार कार्य करता है और उनके समर्थकों को श्रद्धा देता है। शक्तिशाली राष्ट्रों पर अनुशासन रखने में कोष असफल रहा है। 1948 में फ्रांस न कोष की आज्ञा के विरुद्ध फ्रैंक का 44 प्रतिशत अमूल्यन कर लिया और कोष न उसके विरुद्ध कोई कठोर कदम नहीं उठाया। 1949 में डालर का अभाव होते हुए भी कोष न डालर को ‘दुर्लभ मुद्रा’ घोषित नहीं किया।

इसी प्रकार अनुकूल भुगतानशेष वाले देशों (Surplus Countries) पर कोई अनुशासन न रखकर केवल प्रतिकूल भुगतानशेष वाले देशों (Deficit Countries) पर ही नियन्त्रण लगाये हैं।

“It is disheartening to note that the IMF has forgotten to look to the other side of the equation, namely, to surpluses in the balance of payments of a country accumulating reserves ... The automatic adjustment mechanism devised at Bretton Woods was undermined by increased restrictions being imposed on deficit countries alone”

इसीलिए मुद्राकोष के लिए कहा गया है कि :

“The IMF has degenerated into a traditional bank rather than being elevated to an international institution with an in built device for correcting imbalances in world trade”

उपर्युक्त दोषों तथा सीमाओं के बावजूद कोष ने अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक जगत की अभूतपूर्व सेवा की है। बहुमुखी विश्व व्यापार बढ़ाने तथा विनिमय दरों में स्थिरता स्थापित करने में उसका प्रयत्न सराहनीय है। मुद्रा कोष के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए मुद्रा कोष के भूतपूर्व प्रबन्ध सचालक स्वर्गीय श्री पेर जेकोब्सन (Per Jacobsson) ने कहा था :

“If we then examine how the Fund has actually operated, I think it is fair to say that the Fund has increasingly been a factor not for weakening, but rather for strengthening monetary discipline, been able to grant assistance only when countries make reasonable efforts to solve their problems and present programmes, holding out the hope of enduring stability at realistic rates of exchange. Indeed the mere possibility of having access to the Fund's resources even if no drawing is actually made may make countries more confident in their attempts to restore balance, and may indeed induce them to take stricter measures than if they had to rely on their own resources alone.”

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा भारत (International Monetary Fund and India)

भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य है और पांच सबसे बड़े अर्थशास्त्रीय देशों में से एक होने के कारण संचालक मण्डल (Board of Directors) पर उसे एक कार्यकारी संचालक नियुक्त करने का अधिकार है। भारत की ओर से संचालक मण्डल में श्री बी० के० मदान (Shri B. K. Madan) कार्यकारी संचालक का कार्य कर रहे हैं।

कोष की स्थापना के समय भारतीय रुपये की प्रारम्भिक समता दर (Initial Par Value) 0 268601 ग्राम शुद्ध स्वर्ण या 30 225 अमेरिकन सेन्ट्स के बराबर (या 1\$=Rs. 3 309) निश्चित की गई थी। दिसम्बर 1949 में रुपये के अवमूल्यन के कारण उसका मूल्य घटाकर 0 186621 ग्राम स्वर्ण या 21 अमेरिकी सेन्ट्स (या 1\$=Rs. 4 7619) के बराबर निर्धारित किया गया। जून 1966 में जब फिर रुपये का 36.5 प्रतिशत अवमूल्यन हुआ तो समता दर का पुनर्निर्धारण किया गया और रुपये का मूल्य घटाकर 0.118489 ग्राम स्वर्ण या 13 3 सेन्ट्स (या 1\$=Rs. 7 50) कर दिया गया।

मुद्रा कोष की स्थापना के समय भारत का अर्थशा 400 मि० डालर था जिसे दिसम्बर 1959 में बढ़ाकर 600 मि० डालर कर दिया गया था। मार्च 1965 में जब फिर अर्थशा वृद्धि की गई तो भारत का अर्थशा बढ़ाकर 750 मि० डालर कर दिया गया। अर्थशा की मात्रा की दृष्टि से भारत का पांचवा स्थान है और उसे कुल मत-शक्ति का 3 29 प्रतिशत मताधिकार प्राप्त है।

भारत ने समय-समय पर कोष से विदेशी मुद्रा का क्रय किया है। मुद्रा कोष से भारत के लेन-देन अग्रलिखित तालिका में दिखाये गये हैं।—

भारत द्वारा विदेशी मुद्रा का ऋय तथा पुनर्ऋय

(मिलियन डालरों में)

वर्ष	ऋण	पुनर्ऋय
1947-55	100 00	87 40
1957	200 00	—
1958	—	—
1959	—	—
1960	—	72 50
1961	250 00	127 50
1962	25 00	—
1963	—	25 00
1964	—	50 00
1965	125 00	100 00
1966	262 50	75 00
1967	—	57 50
1968	90 00	57 50
योग		

भारत को मुद्रा कोष से लाभ मुद्रा कोष का सदस्य बनने से भारत को कई महत्वपूर्ण लाभ हुए हैं

(1) सकटकाल में सहायता (Help in times of emergencies) समय-समय पर भारत ने सकट पर विजय पाने तथा भुगतानक्षेप की असाम्यता को दूर करने के लिए मुद्रा कोष से विदेशी मुद्रा उधार ली है। आवश्यक पूंजीगत माल तथा कच्चे माल मगाकर भारत ने अपने उत्पादन में वृद्धि का प्रयास किया है।

(2) विश्व बैंक की सदस्यता (Membership of the World Bank) . मुद्राकोष के सदस्य होने के कारण ही भारत को विश्व बैंक की सदस्यता प्राप्त हो सकी है। अब तक विश्व बैंक से 1000 मि० डालर से अधिक के ऋण भारत प्राप्त कर चुका है।

(3) कोष के प्रबन्ध तथा नीति निर्धारण में योगदान (Contribution in the management and policies of the Fund) कोष के पांच बड़े अन्वय-धारियों में से एक होने के कारण भारत कोष का सस्थापक स्थायी सदस्य है और कार्यकारी संचालक मंडल पर उसे अपना प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार है। इस प्रकार भारत अर्विकसित तथा अर्द्ध विकसित देशों के हितों को ध्यान में रखकर कोष की नीति को प्रभावित करता है। कोष द्वारा नये Special Drawing Rights की स्वीकृति में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

(4) विशेषज्ञों के परामर्श से लाभ (Advantage of Expert Advice) : मौद्रिक तथा वित्तीय मामलों पर भारत की कोप तथा बैंक के विशेषज्ञों के परामर्श का लाभ मिलता रहा है जिनमें भारतीय योजनाओं के निर्माण तथा क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण सहायता मिली है।

इस प्रकार मुद्राकोप की सदस्यता भारत के लिए बड़ी लाभदायक रही है।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संकेत

1. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप की कार्य विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए तथा विनिमय दरों के स्थायित्व में इसके कार्य की समीक्षा कीजिए।

(राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल, 1969)

[संकेत—पहले संक्षेप में मुद्रा कोप के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए और फिर विनिमय-दरों के निर्धारण तथा परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्थाओं का विस्तार से विवेचन कीजिए।]

2. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप के उद्देश्य क्या हैं? अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूपमान से यह किस प्रकार भिन्न है?

(बिहार बी० ए०, 1958)

[संकेत—प्रथम भाग में मुद्रा कोप के उद्देश्य बताइए। दूसरे भाग में मुद्रा कोप तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूपमान की समानताएँ तथा असमानताएँ बताइए। इस सम्बन्ध में प्रो० विलियम्स तथा लाड की-स के कथनों को उद्धृत कीजिए।]

3. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप की स्थापना किन मुख्य उद्देश्यों में की गई थी? कोप से भारत को क्या लाभ प्राप्त हुए हैं?

(आगरा बी० ए०, 1964)

[संकेत—प्रथम भाग में मुद्रा कोप की स्थापना के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। दूसरे भाग में मुद्रा कोप तथा भारत के सम्बन्धों की चर्चा करते हुए भारत को उमस प्राप्त लाभों का उल्लेख कीजिए।]

(4) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप ने कार्यों को समझाएँ। इस कोप ने कार्यों को पूर्ण करने में कहा तक सफलता प्राप्त की है?

(विक्रम, 1961, आगरा, 1968)

[संकेत—प्रथम भाग में मुद्रा कोप के कार्यों तथा भवाओं का वर्णन कीजिए दूसरे भाग में मुद्रा कोप का आलाचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। निष्कर्ष में बताइए कि कुछ सीमाओं के बावजूद कोप ने अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है।]

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक

(International Bank for Reconstruction
and Development)

"A just tribute to the Bank would be that the 'world would be poorer without it, for the underdeveloped countries owe to it the many smiling fields and green pastures which relieve the vast arid deserts of their economy."

ब्रेटेन बुडस (न्यूहैम्पशायर) में जुलाई 1944 में जो संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक तथा वित्तीय सम्मेलन (United Nations Monetary and Financial Conference) हुआ था और जिसमें भारत सहित 44 देशों ने भाग लिया था, उसी में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक की स्थापना का निर्णय हुआ था। सम्मेलन में स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक की समझौते की शर्तों (Articles of Agreement) को 25 दिसम्बर 1945 से लागू किया गया। भारत ने 24 दिसम्बर 1945 को समझौते को स्वीकृति दी थी। बैंक ने वास्तव में 25 जून 1946 से कार्य करना प्रारम्भ किया।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (जिसे साधारणतया विश्व बैंक (World Bank) के नाम से पुकारा जाता है) की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक पूरक सत्त्या के रूप में की गई थी। द्वितीय महायुद्ध काल में ही देशों ने अनुभव कर लिया था कि युद्ध से विध्वंसित राष्ट्रों तथा उनकी जंजर और अस्त-व्यस्त अर्थ-व्यवस्थाओं के पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण के लिए असीम पूँजी तथा अथक परिश्रम की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ स्थायी विश्व शांति की स्थापना के लिए भी यह आवश्यक समझा गया कि अद्विकसित तथा अर्ध-विकसित देशों के आर्थिक साधनों में वृद्धि तथा उनके रहन-सहन के स्तर को उन्नत किया जाय। इसी सन्दर्भ में विश्व बैंक की स्थापना ठीक दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

विश्व बैंक के उद्देश्य (Objectives of the World Bank)

२।

विश्व बैंक एक अन्तर सरकारी कानून जनित सस्था है जिसकी पूंजी सभी सदस्य-सरकारों ने जुटायी है। (The Bank is an inter-governmental institution, corporate in form, the capital stock of which is entirely owned by its member governments) समझौता पत्र की धारा I (Article I of the Agreement) के अनुसार बैंक के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

(1) पूंजी के विनियोग को सुविधाजनक बनाकर पुनर्निर्माण तथा विकास में सहायता (To assist in the reconstruction and development by facilitating investment of Capital) — विश्व बैंक का प्रथम मुख्य उद्देश्य युद्ध विध्वंसित अर्थ व्यवस्थाओं के पुनर्वास तथा देशों के पुनर्निर्माण तथा विकास में सहायता करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैंक उत्पादक कार्यों में पूंजी के विनियोग को सुगम बनाने के लिए प्रयत्नशील रहता है।

(2) विदेशी निजी पूंजी विनियोग को प्रोत्साहन (To promote foreign private investment) — विश्व बैंक अधिकसित तथा पिछड़े राष्ट्रों में विदेशी विनियोगकर्ताओं को पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके लिए विश्व बैंक उनके द्वारा दिए गये ऋणों की गारंटी करता है तथा उनके साम्ने मद्दत देता है। इसके साथ साथ उपयुक्त शर्तों पर निजी पूंजी उपलब्ध न होने पर स्वयं अपने साधनों से पूंजी विनियोग की कमी की पूर्ति करता है।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दीर्घकालीन सतुलित विकास तथा भुगतान शेष में साम्यता बनाये रखने में योगदान (To promote long range balanced growth of international trade and the maintenance of equilibrium in balance of payments) — विश्व बैंक का तीसरा उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय विनियोग को प्रोत्साहन देकर व्यापार के दीर्घकालीन सतुलित विकास तथा देशों के भुगतान शेष में साम्यता (Equilibrium) बनाये रखने में सहायता करना है और इस प्रकार बैंक सदस्य देशों में उत्पादन, रहन-सहन तथा श्रमिकों की दशाओं की उन्नति में योगदान करता है।

(4) शान्तिकालीन अर्थ व्यवस्था की स्थापना (Establishment of Peacetime Economy) विश्व बैंक अपने सभी कार्य इस उद्देश्य से करता है कि सप्ताह की युद्ध विनिष्ट अर्थ व्यवस्थाओं वा शान्तिकालीन अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन सहज हो जाय।

। इस प्रकार विश्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष के उद्देश्यों के पूरक हैं। विश्व बैंक की स्थापना एक विनियोग बैंक (Investment

Bank) की तरह हुई है। "विश्व बैंक मुद्रा कोष की पूरक संस्था के रूप में कार्य करेगा तथा इसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सतुलित विकास तथा आय और वृत्ति के उच्च स्तर को कायम रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विनियोग को प्रोत्साहित करना है।" (The World Bank is intended to serve as an essential adjunct to the Monetary Fund and in particular to ensure a high and stable level of international investment with a view to promoting balanced growth of international trade and maintenance of higher levels of income and employment)

बैंक की सदस्यता (Membership of the Bank)

कोई भी देश विश्व बैंक का सदस्य बन सकता है यदि वह बैंक के उद्देश्य-पत्र (Charter) को स्वीकार करता है परन्तु बैंक का सदस्य होने के लिए मुद्रा कोष का सदस्य होना अनिवार्य है। (Membership of the Fund is a prerequisite for admission to the membership in the Bank) इस प्रकार मुद्रा कोष के सभी सदस्य स्वतः विश्व बैंक के सदस्य बन जाते हैं। कोई भी सदस्य अपनी इच्छानुसार किसी भी समय बैंक की सदस्यता त्याग सकता है और बैंक को इसकी लिखित सूचना मिलने पर त्याग पत्र कार्यशील हो जाता है। यदि कोई सदस्य बैंक के अतर्गत अपने दायित्वों को पूर्ण करने में अग्रफल रहता है तो उसे सदस्यता से निलंबित किया जा सकता है। सदस्यता का त्याग करने के बाद भी उस तिथि को बैंक को हुई हानियों के अपने भाग का भाग पर भुगतान करने को सदस्य देश उत्तरदायी है।

जिन देशों ने 31 दिसम्बर 1945 तक मुद्रा कोष की सदस्यता ग्रहण करली थी वे विश्व बैंक के संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। प्रारम्भ में बैंक की सदस्य संख्या केवल 44 थी परन्तु अब (दिसम्बर 1968 तक) यह बढ़कर 110 तक पहुँच गई है। 1968 के वर्ष में मारीशस, (Mauritius) बोत्सवाना (Botswana) तथा लेसेथो (Lesotho) ने बैंक की सदस्यता ग्रहण की।

बैंक के पूँजी-साधन (Capital Resources of the Bank)

बैंक की स्थापना के समय बैंक की अधिकृत पूँजी 10 मिलियन डालर (10,000 मि० डालर) निश्चित की गई थी जो 1-1 लाख डालर के 1 लाख अंशों में विभाजित थी। 30 जून 1959 तक बैंक की स्वीकृत पूँजी 9.4 बिलियन डालर (9,400 मि० डालर) थी।

प्रत्येक सदस्य की पूंजी तीन भागों में विभाजित है -

(1) प्रत्येक देश को अपने हिस्से की पूंजी का 2 प्रतिशत भाग स्वयं या अमेरिकी डालर में बैंक के पास जमा करना पड़ता है और इस राशि को स्वतन्त्रता-पूर्वक ऋणों के रूप में दिया जा सकता है,

(2) सदस्य देश को अपने हिस्से की पूंजी का 18 प्रतिशत भाग अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में बैंक को देना पड़ता है और इस राशि को सदस्य देश की स्वीकृति लेकर ही ऋणों के रूप में दिया जा सकता है, तथा

(3) हिस्से की पूंजी का शेष 80 प्रतिशत भाग बैंक को नहीं दिया जाता परन्तु आवश्यकता पड़ने पर बैंक के दायित्वा का भुगतान करने के लिए मददसे से मागा जा सकता है।

इस प्रकार बैंक की अधिकृत पूंजी का 20 प्रतिशत भाग स्वयं या अमेरिकी डालरों तथा सदस्य की राष्ट्रीय मुद्राओं के रूप में उसके पास ऋण देने के लिए मदा उपलब्ध रहता है और इससे भी अधिक गारन्टी साधन (Guarantee Resources) बैंक के पास होते हैं जिनसे वह निजा पूंजी के अन्तरराष्ट्रीय विनियोजन को प्रोत्साहित करता है।

बैंक की पूंजी में वृद्धि (Increase in Bank's Capital Resources) —

बैंक के कार्यों के विस्तार तथा सदस्य देशों की ऋणों की बढ़ती हुई मांग का देखते हुए बैंक के पूंजी साधनों में वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गई। अतः अक्टूबर 1958 में बैंक की नई दिल्ली में हुई वार्षिक बैठक में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने बैंक की पूंजी की वृद्धि के प्रश्न पर विचार किया और संचालक मंडल को पूंजी वृद्धि के प्रश्न पर विचार करने तथा तत्सम्बन्धी सुझाव पेश करने को कहा। संचालक मंडल ने सदस्य देशों की पूंजी के हिस्सों को दुगना करने का निश्चय किया। इस प्रकार 15 सितम्बर 1959 तक सदस्य देशों की पूंजी के अंशों को दुगना कर दिया गया तथा कुछ देशों, प० जर्मनी बनाडा, जापान इत्यादि देशों के पूंजी अंशों में दुगने से भी अधिक वृद्धि की गई। फलतः बैंक की अधिकृत पूंजी 10,000 मि० डालर से बढ़कर 21,000 मि० डालर हो गई। इस वृद्धि के बाद फिर 31 दिसम्बर 1963 को बैंक की अधिकृत पूंजी 21,000 मि० डालर से बढ़ाकर 22,000 मिलियन डालर कर दी गई। बाद में इसे 21,000 मि० डालर से बढ़ाकर 24,000 मिलियन डालर कर दिया गया। 30 जून 1968 को बैंक की अधिकृत पूंजी 24,000 मि० डालर थी जो 100,000 डालर के 2,40,000 अंशों में विभाजित थी।

30 जून 1968 को बैंक की प्रारंभिक पूंजी 22,941 मि० डालर थी जो 31 दिसम्बर 1968 को बढ़कर 22,991 मि० डालर हो गई थी।

कुछ मुख्य देशों के पूंजी अंशों को निम्न तालिका में दिखाया गया है।

विश्व बैंक
मुख्य देशों के पूंजी अंश

(मिलियन डालरों में)

सदस्य देश	प्रारम्भिक पूंजी अंश वृद्धि के बाद पूंजीअंश				वर्तमान पूंजीअंश (30 जून 1968)	
	मात्रा	कुल का प्रतिशत	मात्रा	कुल का प्रतिशत	मात्रा	कुल का प्रतिशत
1 U S A	3175	29.72	6350	27.79	6350	27.68
2 U K	1300	12.31	2600	11.38	2600	11.33
3 W Germany	525		1050	5.60	1280	5.58
4 France	525	5.11	1050	4.60	1050	4.58
5 India	400	3.95	800	3.50	800	3.49
6 Canada	325		750	3.47	792	3.45
7 China	600	5.31	750	3.38	750	3.27
8 Japan	250	2.55	660	3.28	772	3.37
9 Netherlands			550	3.41	550	2.40
10 Australia			533	2.33	533	2.32

विश्व बैंक का संगठन तथा प्रबंध

(Organisation and Management of the Bank)

मुद्रा कोष की तरह विश्व बैंक का भी प्रबंध एक गवर्नर मंडल (Board of Governors) कार्यकारी संचालक मंडल (Board of Executive Directors), एक अध्यक्ष (President) तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। प्रबंध के इन अवयवों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है —

गवर्नर मंडल (Board of Governors)

विश्व बैंक के प्रबंध तथा नीति निर्धारण के लिए उत्तरदायी गवर्नर मंडल संगठन की सर्वोच्च संस्था है। यह संस्थाओं की साधारण सभा (General House) की तरह होता है। प्रत्येक सदस्य देश को गवर्नर मंडल पर एक गवर्नर तथा एक विकल्प गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार है जिनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। विकल्प गवर्नर सभाओं में भाग ले सकता है परन्तु गवर्नर की अनुपस्थिति में ही मत दे सकता है। गवर्नर अधिकतर सदस्य देशों के वित्त मंत्री होते हैं। गवर्नर मंडल की वष में एक बैठक होना आवश्यक है। गवर्नर मंडल की वार्षिक बैठक मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल की बैठक के साथ ही होती है। गवर्नर मंडल के सदस्य अपने-अपने एक अध्यक्ष (Chairman) चुन लेते हैं जो वार्षिक बैठकों की अध्यक्षता करता है।

कार्यकारी सचालक मंडल (Board of Executive Directors)

बैंक के दिन प्रति दिन के कार्य के लिए कार्यकारी सचालक मंडल उत्तरदायी है। कुछ कार्यों को छोड़कर¹ गवर्नर मंडल ने अपने अधिकार कार्यकारी सचालकों को सौंप रखे हैं। कार्यकारी सचालक मंडल एक कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) की तरह है और वह अपने समस्त कार्यों के लिए गवर्नर मंडल के प्रति उत्तरदायी है। कार्यकारी सचालक मंडल की बैठक महीने में एक बार होती है। कार्यकारी सचालकों की बैठक में उनकी कुल मत शक्ति का 50 प्रतिशत या उससे अधिक बहुमत कोरम माना जाता है।

कार्यकारी सचालक मंडल के कुल सदस्यों की संख्या 20 होती है जिसमें से पांच सचालक बैंक की पूंजी के पांच सबसे बड़े अंशधारियों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अमेरिका इंग्लैंड, 10 जर्मनी फ्रांस तथा भारत पांच सबसे बड़े अंशधारी हैं और उनके द्वारा मनोनीत कार्यकारी सचालक इसके स्थायी सदस्य होते हैं। शेष 15 कार्यकारी सचालकों का अन्य देशों द्वारा निर्वाचन होता है। कार्यकारी सचालकों को अपने देश के पूंजी अंश के अनुपात में मताधिकार प्राप्त होते हैं।

अध्यक्ष (President)

बैंक का एक अध्यक्ष (President) होता है जो कार्यकारी सचालकों द्वारा चुना जाता है। वह कार्यकारी सचालक मंडल का समापति होता है। उसे मताधिकार नहीं होता परन्तु समान मत पडन पर अपना निर्णय मत (Deciding Vote) देने का अधिकार होता है। बैंक का वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है और नातिगत प्रश्नों पर कार्यकारी सचालकों के निर्देशन में बैंक के संगठन तथा सामान्य कार्य चराने के लिए उत्तरदायी होता है। 1 अप्रैल 1968 से बैंक के अध्यक्ष अमेरिका के श्री राबर्ट एस० मैकनमारा (Robert S McNamara) हैं।

सलाहकार परिषद् (Advisory Council)

बैंक को सामान्य नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर सलाह देने के लिए कम से कम सात सदस्यों की एक सलाहकार परिषद् है जिसमें बैंकिंग वाणिज्य श्रम तथा कृषि

¹ "The exceptions include the admission of new members, the increase or decrease of the capital stock the suspension of a member, decision of appeals from interpretations of the Articles of Agreement made by the Executive Directors, approval of formal agreements with other international organisations, decision on distribution of the net income of the Bank and its liquidation

क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है। इस परिपद की बैठक साधारणतया वर्ष में एक बार होती है परन्तु आवश्यकता पड़ने और बैठकें भी बुलाई जा सकती हैं।

ऋण समितियाँ (Loan Committees)

बैंक को प्राप्त ऋण के प्रायोजनापत्रों की जाच के लिए बैंक समय-समय पर ऋण समितियाँ नियुक्त करता है। इस समितियों की रिपोर्ट के आधार पर ही बैंक ऋण स्वीकृत करता है।

विश्व बैंक के कार्य तथा सेवाएँ (Functions and Services of the Bank)

विश्व के पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में विश्व बैंक ने अविस्मरणीय सेवाएँ की हैं। अविकसित तथा अर्धविकसित राष्ट्रों के लिए विश्व बैंक एक बड़ी उपयोगी सस्था है। विश्व बैंक की क्रियाएँ तथा सेवाएँ निम्नलिखित हैं

1. ऋण देना (Granting of Loans)
2. ऋणों की गारन्टी देना (Guaranteeing of Loans)
3. तकनीकी सहायता (Technical Assistance)
4. प्रशिक्षण सुविधाएँ (Training Facilities)
5. मध्यस्थ के रूप में सेवाएँ (Conciliatory Services)

(1) ऋण देना (Granting of Loans)

विश्व बैंक अपने साधन दो स्रोतों से प्राप्त करता है। एक तो, सदस्य देशों से पूंजी अंश के रूप में प्राप्त तथा दूसरे, उधार लेकर प्राप्त। विश्व बैंक इस प्रकार प्राप्त साधनों का उपयोग सदस्य देशों को ऋण देने में करता है। ऋण सदस्य देश की सरकार या उस देश के किसी राजनीतिक प्रदेश (Political Sub division) जैसे प्रान्त या राज्य या किसी अर्धसरकारी सस्था जैसे, नगरनिगम या उस देश में स्थित किसी निजी व्यापारिक, औद्योगिक या कृषि सस्थान को दिए जा सकते हैं। निजी सस्थानों को दिए गये ऋणों की सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक द्वारा गारन्टी देना आवश्यक है।

बैंक पुनर्निर्माण तथा विकास दोनों कार्यों के लिए ऋण देता है। पुनर्निर्माण के लिए तो युद्धोत्तर काल में कुछ ऋण दिए गये थे। अधिकतर विकास कार्यों के लिए ऋण दिये गये हैं। बैंक सामान्यतया मध्यम तथा दीर्घकालीन ऋण देता है। वास्तव में ऋण की अवधि कारखाने या साज सामान के उपयोगी जीवन काल (useful life of the equipment or Plant) पर निर्भर रहती है। बैंक द्वारा दिए

गये ऋणों पर ब्याज की दर बैंक को उन्ही शर्तों पर बाजार से ऋण लेने की लागत के बराबर होती है और बिना भेदभाव के सभी ऋणी देशों से समान ब्याज दर ली जाती है। अधिकतर दिए गये ऋणों पर 4.5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक ब्याज दर ली गई थी। ऋण लेने की लागत में वृद्धि के कारण बैंक को अपनी ब्याज दर जनवरी 1968 में 6 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत करनी पड़ी। अगस्त 1968 में यह बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत कर दी गई है। सदस्य देशों द्वारा लिए गये ऋणों पर बैंक द्वारा ब्याज दर के अतिरिक्त 1 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत तक कमीशन लेने की सम्भौता पत्र में व्यवस्था थी परन्तु बैंक ने 1 प्रतिशत ही कमीशन लिया है। इस कमीशन द्वारा प्राप्त आय से एक विशेष कोष बनाया गया है जिसका उपयोग ऋणों की वसूली न होने से होने वाली हानि को पूरा करने के लिए किया जाता है।

ऋण स्वीकृति की चार अवस्थायें (Four Stages of Granting Loans) :

सदस्य देशों को दिए जाने वाले ऋणों की स्वीकृति की निम्नलिखित चार क्रमावस्थायें हैं

(1) प्रारम्भिक बातचीत तथा जाच (Exploratory discussions and Preliminary Investigation) जब किसी सदस्य देश की सरकार या सस्था ऋण लेने का प्रार्थनापत्र बैंक के पास भेजती है तो बैंक तथा ऋणी के प्रतिनिधियों में प्रारम्भिक बातचीत होती है और ऋणी की भुगतान योग्यता के बारे में पता लगाया जाता है। यदि किसी देश से पहले ही ऋण की मांग हो रही है तो बैंक वहाँ एक अध्ययन दल भेजता है जो उस देश के कृषि, खनिज तथा औद्योगिक साधनों, निर्यात तथा भुगतान सतुलन, मुद्रा-प्रणाली इत्यादि का अध्ययन करता है जिससे देश की ऋण क उपयोग की क्षमता का ज्ञान हो सके। यदि ऋणी देश द्वारा पहले ऋण लिए जा चुके हैं तो देश की वर्तमान आर्थिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की जाती है।

2 विशिष्ट योजना की जाच (Investigation of the Specific Project) प्रारम्भिक जाच के बाद योजना विशेष (जिसके लिए ऋण मांगा गया है) के तकनीकी, वित्तीय तथा प्रशासनिक पक्षों की जाच की जाती है। उसमें निम्न मुख्य बातों पर विचार होता है

(i) योजना ठीक से बनायी गयी है या नहीं।

(ii) योजना के लिए आवश्यक स्थानीय पूँजी प्राप्त है या नहीं।

(iii) योजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त तकनीकी जानकारी उपलब्ध है या नहीं।

(iv) योजना का प्रबन्ध सुयोग्य हाथों में है या नहीं इत्यादि।

उपर्युक्त तथ्यों की जाच के बाद बैंक यह निर्णय करता है कि इस योजना के लिए ऋण देना उचित है या नहीं।

(3) ऋण की शर्तों के सम्बन्ध में बातचीत (Negotiation of the terms of the Loan) तीसरी अवस्था में ऋण की शर्तों के सम्बन्ध में बातचीत होती है। इसमें बैंक द्वारा कुल विनियोग की मात्रा, व्याज दर, ऋण अवधि, बैंक के हितों की सुरक्षा के लिए आश्वासन तथा गारन्टियों इत्यादि के सम्बन्ध में निरायण होता है। इसमें अधिक समय नहीं लगता क्योंकि बैंक इस सम्बन्ध में प्रमाणित विधि का प्रयोग करता है। सामान्यतः बैंक योजना की विदेशी विनिमय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण देता है।

(4) ऋण-प्रशासन (Administration of the Loan) अंतिम अवस्था में ऋण-प्रशासन आता है जो बैंक ऋणों की विशेषता है। बैंक योजना के निर्माण काय की देख रेख रखता है। बैंक के प्रतिनिधि योजना स्थल पर जाकर यह देखते हैं कि ऋण का प्रयोग ठीक ढंग से हो रहा है और यह ऋण समझौते के अनुरूप है। ऋणों द्वारा बैंक को योजना का प्रगति-विवरण लगातार भेजना आवश्यक है जिससे ऋण के प्रारम्भ से अंत तक बैंक पूरी देख-रेख रख सके।

बैंक द्वारा दिए गये ऋण

(Loan Operations of the Bank)

गत 22 वर्षों में विश्व बैंक ने सदस्य देशों के पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त सहायता दी है। बैंक ने प्रारम्भ में 1947 में फ्रांस, नीदरलैंड्स, डेन मार्क तथा लक्जमबर्ग को पुनर्निर्माण के लिए ऋण दिए थे। बाद में सभी ऋण आर्थिक विकास के लिए दिए गये। स्थापना के समय से 30 जून 1968 तक 85 देशों को 11,247 मिलियन डॉलर के ऋण दिए गये। पिछले कुछ वर्षों का ऋणों का व्यापार निम्न तालिका में दिया गया है।

बैंक द्वारा दिए गये ऋणों का व्योरा

(मिलियन डॉलर में)

प्रशुल्क वर्ष (Fiscal Year)	ऋणों की मात्रा (Loans)
1959 तक	4,251
1960	659
1961	610
1962	882
1963	449
1964	810
1965	1,023
1966	839
1967	877
1968	847
Total	11,247

विश्व बैंक द्वारा प्रारम्भ से 30 जून 1968 तक सदस्य देशों को दिए गये ऋणों का उद्देश्यानुसार (Purpose wise) विवरण निम्न तालिका में दिखाया गया है।

विश्व बैंक द्वारा दिए गये ऋणों का उद्देश्यानुसार वितरण
(प्रारम्भ से 30 जून 1968 तक)

(मिलियन डालरों में)

उद्देश्य	राशि (\$)	राशि (\$)
1. विद्युत शक्ति		3,826
2. यातायात		3,639
(i) रेलें	1,513	
(ii) जहाजरानी	12	
(iii) बन्दरगाह तथा जल मार्ग	399	
(iv) सड़कें	1,579	
(v) हवाई मार्ग तथा हवाई अड्डे	57	
(vi) पाइप लाइनें	79	
3. सदेश वाहन		144
4. कृषि, वन तथा मत्स्य-पालन		942
(i) फार्म यंत्रीकरण	136	
(ii) सिंचाई तथा बाढ नियंत्रण	527	
(iii) भूमि सुधार आदि	91	
(iv) मछार आदि	14	
(v) पशु विकास	141	
(vi) वन तथा मत्स्य पालन	33	
5. उद्योग :		1,782
(i) लौह स्पात	414	
(ii) कागज तथा लुग्दी	135	
(iii) उर्वरक तथा अन्य रसायन	112	
(iv) अन्य उद्योग	260	
(v) खनन	197	
(vi) विकास वित्त कम्पनियां	665	
6. सामान्य विकास		205
7. शिक्षा		35
8. जल व्यवस्थाएँ		74
9. युद्धोत्तर पुनर्निर्माण		497
10. योजना निर्माण		5
11. ऋण वित्त व्यवस्था (IFC)		100
योग		11,247

उपर्युक्त आकृषा से स्पष्ट है कि विश्व बैंक ने अधिकतर ऋण विद्युत-शक्ति, यातायात के साधनों तथा उद्योगों के विकास के लिए दिए हैं।

1967-68 में विश्व बैंक ने 31 सदस्य देशों को 847 मि० डालर के ऋण दिए। इन ऋणों का कार्यानुसार वितरण निम्न तालिका में दिखाया गया है :

विश्व बैंक द्वारा दिए गये ऋणों का कार्यानुसार वितरण
(1967-68)
(मिलियन डालरों में)

मदें	राशि (\$)
1. कृषि	145 30
2. शिक्षा	10 60
3. विद्युत शक्ति	254 45
4. सड़क वाहन	27 00
5. उद्योग	191 50
6. यातायात	196 10
7. जल पूर्ति	22 00
योग	846 95

बैंक के द्वारा दिए गये ऋणों से यह स्पष्ट है कि पिछले 5-6 वर्षों से बैंक कृषि तथा शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए अधिक ध्यान दे रहा है। कृषि-विकास के क्षेत्र में बैंक ने मलेशिया, थाईलैंड, पाकिस्तान तथा फिलिपीन्स को सिचाई के लिए ऋण दिए। 1967-68 में बैंक ने ब्राजील को मास तथा ऊन उत्पादन वृद्धि के लिए 40 मि० डालर का ऋण दिया। इसी प्रकार बैंक ने फसल सुधार के लिए मलावी को, भूमि-साधनों के शोषण के लिए, मलेशिया को, तथा जल साधनों तथा कृषि के विकास के लिए ईरान को ऋण दिए।

प्रारम्भ से 30 जून 1968 तक विश्व बैंक ने जो 11,247 मि० डालर के ऋण दिए उनका क्षेत्रानुसार वर्गीकरण निम्न तालिका में दिखाया गया है।

विश्व बैंक द्वारा दिए गये ऋणों का क्षेत्रानुसार विवरण
(प्रारम्भ से 30 जून 1968 तक)
(मिलियन डालरों में)

क्षेत्र	राशि (\$)
1 एशिया तथा मध्य-पूर्व	3,777
2 पश्चिमी गोलार्ध	3,200
3 योरोप	2,238
4 अफ्रीका	1,412
5 आस्ट्रेलिया	520
6 अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम	100
योग	11,247

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि विश्व बैंक द्वारा दिए गये अधिकांश ऋण एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व तथा लैटिन अमेरिका के अर्थिकसत तथा पिछड़े हुए देशों को दिए गये हैं।

भावी नीति (Future Policy) :

बैंक ग्रुप के अध्यक्ष श्री राबर्ट मैकनामारा (Robert S. McNamara) ने बैंक की सितम्बर-अक्टूबर 1968 की वार्षिक बैठक तथा अन्य भाषणों में बैंक की भावी पांच वर्षीय ऋण योजना का संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में बैंक कृषि तथा शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सहायता देगा।

(2) ऋणों की गारन्टी देना (Guaranteeing of Loans)

बैंक अपने पूंजी साधनों तथा उधार लेकर ऋण देने के अतिरिक्त निजी व्यक्तियों तथा संस्थाओं से ऋण दिलाता है और स्वयं उसकी गारन्टी करता है। इस प्रकार बैंक निजी पूंजी विनियोजन को प्रोत्साहित करता है। बैंक द्वारा की जाने वाली यह सुविधा सदस्य देशों के लिए बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई है। बैंक गारन्टी के इस कार्य के लिए सदस्य देशों से कुछ कमीशन लेता है। बैंक के समझौता पत्र में यह व्यवस्था थी कि बैंक गारन्टी के लिए ऋणी देशों से प्रतिशत से लेकर 1.5 प्रतिशत तक कमीशन लेगा परन्तु बैंक ने प्रतिशत कमीशन ही लिया है।

(3) तकनीकी सहायता (Technical Assistance)

विश्व बैंक ने सदस्य देशों को ऋण-व्यवस्था के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान की है। यह सहायता विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित रही है

- (अ) विभिन्न योजनाओं में प्राथमिकतायें निश्चित करना,
- (ब) योजना की तकनीकी व्यवस्था में संशोधन करना जिससे उसकी लागत में कमी तथा कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके;

(स) योजना की प्रशासकीय या संगठनात्मक व्यवस्था या योजना की वित्त व्यवस्था (स्थानीय पूंजी की व्यवस्था सहित)।

विकास कार्यक्रमों के निर्माण में बैंक ने बड़े पैमाने पर विकासशील देशों को तकनीकी सहायता दी है। बैंक उन देशों में सर्वेक्षण दल (Survey Missions) भेजकर उनके राष्ट्रीय साधनों का अध्ययन करता है। यह अध्ययन उनके दीर्घकालीन आर्थिक विकास का आधार बनता है। विकासशील देशों की प्रार्थना पर वित्तीय तथा आर्थिक विशेषज्ञों को वहाँ भेजा गया है।

तकनीकी सहायता के क्षेत्र में बैंक ने योजनाओं की जानकारी तथा उनके निर्माण में सदस्य देशों की सहायता को ही सदा से महत्व दिया है (The main emphasis of the Bank's technical assistance activities remains on assisting governments in the identification and preparation of projects.) । पूर्वी तथा पश्चिमी अफ्रीका में स्थित बैंक के दो Permanent Missions का यही मुख्य कार्य है । इसी उद्देश्य से बैंक FAO तथा UNESCO से सहयोग करता है ।

पिछले वर्ष बैंक ने पश्चिमी पाकिस्तान के जल तथा शक्ति साधनों का अध्ययन पूर्ण किया है । बैंक ने 1968 में इन्डोनेशिया के आर्थिक विकास में सहायता देने के लिए जकार्ता में Resident staff की नियुक्ति की है ।

विकास नियोजन के क्षेत्र में बैंक परामर्श भी देता है ।

(4) प्रशिक्षण सुविधायें (Training Facilities)

सदस्य देशों की योजनाओं के सफल संचालन के लिए प्रशिक्षित अधिकारियों की व्यवस्था करने के लिए बैंक प्रशिक्षण-सुविधायें भी देता है । 1956 में बैंक ने राकफेलर तथा फोर्ड फाउन्डेशन की वित्तीय सहायता से वाशिंगटन में एक 'आर्थिक विकास संस्थान' (The Economic Development Institute [EDI]) की स्थापना की जिसमें विकासशील सदस्य देशों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है । (EDI is striving forward the long term goal of helping less developed countries to have enough expertise to meet the demands of economic development)

आर्थिक विकास संस्थान ने 1956 में अपने प्रारम्भ से 30 जून 1968 तक 103 देशों के 885 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया । 1967-68 में 69 देशों तथा 4 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के 140 अधिकारियों को प्रशिक्षण मिला । इसके अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग कर वहाँ प्रशिक्षण में संस्थान ने हाथ बँटाया है ।

आजकल इस संस्थान के निदेशक एक भारतीय अर्थ विशेषज्ञ श्री के० एस्० कृष्णास्वामी हैं ।

(5) मध्यस्थ रूप में सेवार्थ (Conciliatory Services)

विश्व बैंक उपयुक्त सेवाओं के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक विवादों में मध्यस्थता (mediation) का कार्य भी करता है । भारत और पाकिस्तान के बीच

वर्षों से चले आ रहे नहरी पानी विवाद में मध्यस्थ के रूप में कार्य करके उसे निपटाया है।

विश्व बैंक और भारत (World Bank and India)

भारत विश्व बैंक का संस्थापक सदस्य है। भारत ने 24 दिसम्बर 1945 को ही बैंक समझौता पत्र को स्वीकृति दे दी थी। बैंक की कुल प्राथित पूंजी में 400 मि० डालर का अंश भारत के पास था। इस प्रकार वह पांच बड़े अंशधारियों में से एक था और उन्हीं बैंक के कार्यकारी सचालक मंडल में स्थायी स्थान प्राप्त है। अब भारत का पूंजी अंश बढ़कर 800 मि० डालर हो गया है जो कुल पूंजी का 3.49 प्रतिशत है। भारत के पास बैंक के 8000 अंश हैं और उसे 8,250 मतों का अधिकार प्राप्त है जो कुल मत शक्ति का 3.22 प्रतिशत है।

विश्व बैंक ने भारत के आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त सहायता दी है। विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले देशों में भारत का प्रथम स्थान है, उसने बैंक से सबसे अधिक ऋण लिए हैं। 30 सितम्बर 1968 तक भारत ने 1007.2 मिलियन डालर राशि के 35 ऋण प्राप्त किए। ऋणों का अधिकतर भाग सड़की, रेलों, जल-परिवहन तथा बंदरगाहों के विकास के लिए दिया गया।

भारत को दिए गये ऋणों का विस्तृत विवरण

समझौते की तिथि	प्रायोजना	राशि (मि डालर)	अन्य विवरण
18-8-49	रेल्वे	34.0	घटाकर 32.80 मि०
29-9-49	भूमि तोड़ना	10.0	घटाकर 7.20 मि०
18-4-50	शक्ति (दामोदर)	18.5	घटाकर 16.72 मि०
18-12-52	उद्योग	31.5	घटाकर 30.02 मि०
23-1-53	शक्ति (दामोदर)	19.5	घटाकर 10.50 मि०
19-11-54	शक्ति	16.2	घटाकर 13.95 मि०
14-3-55	उद्योग	10.0	ICICI को
26-6-56	उद्योग	75.0	टाटा आइरन एण्ड स्टील क० को
19-12-56	उद्योग	20.0	इन्डियन आइरन को
5-3-57	एविएशन	5.6	एयर इन्डिया को
29-5-57	शक्ति	9.8	टाटा ग्रुप को
12-7-56	रेल्वे	90.0	रेल व्यवस्था सुधार के लिए
20-11-57	उद्योग	32.5	टाटा आइरन को
23-7-58	शक्ति (दामोदर)	25.0	तृतीय दामोदर परियोजना
25-7-58	बंदरगाह विकास	29.0	कलकत्ता पोर्ट कमिशनर्स को
25-7-58	बंदरगाह विकास	14.0	मद्रास पोर्ट

—Contd on next page

समझौते की तिथि	प्रायोजना	राशि (मि डालर)	अन्य विवरण
16-9-58	रेल्वे	85 0	रेलो क विकास के लिए
8-4-59	शक्ति	25 0	—
15-7-59	उद्योग	10 0	ICICI को
15-7-59	रेल्वे	50 0	रेलो के विकास के लिए
29-7-60	रेल्वे	70 0	इन्जन इत्यादि आयात करने के लिए
28-10-60	उद्योग	20 0	ICICI को
17-8-61	बंदरगाह विकास	21 0	—
9-8-61	उद्योग	35-0	कोयला उद्योग को
13-10-61	रेल्वे	50 0	रेलो के विकास के लिए
22-12-61	उद्योग	19 5	इन्डियन ग्राइडरन को
28-2-62	उद्योग	20 0	ICICI को
10-8-62	व्यास नदी घाटी	3 0	पोग बांध
28-4-63	"	6 0	—
5-6-63	उद्योग "	30 0	ICICI को
21-5-65	उद्योग	50 0	ICICI को
11-6-65	विद्युत-शक्ति	70 0	साइनों के विस्तार आदि के लिए
11-6-65	विद्युत शक्ति	14 0	कोठागुडेम विद्युत गृह (आंध्र)
8-7-66	उद्योग	30 0	इन्डियन आयरन को
19-9-67	उद्योग	25 0	ICICI को
11-6-69	कृषि	13 0	कृषि (बीज उत्पादन)

शृणो के अतिरिक्त विश्व बैंक ने समय समय पर विशेषज्ञों के दल भेजकर भारत के विकास सम्बन्धी योजनाओं के निर्माण क्रियान्वयन तथा उनके मूल्यांकन में बड़ी सहायता की है। मई 1963 से बैंक ने नई दिल्ली में एक प्रतिनिधि (Resident Mission) नियुक्त कर रखा है। जुलाई 1964 में बैंक ने 0.86 मि० डालर का व्यय कर कोयला-यातायात की समस्या का अध्ययन किया है। एक विशेष अध्ययन दल ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अध्ययन के लिए भारत की आर्थिक स्थिति का गहन अध्ययन किया। इसके बाद भारत की विकास नीति की सफलता का मूल्यांकन करने श्री ड्रू पियरसन (Drew Pearson) के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ दल आया। जून 1969 में बैंक के एशिया विभाग के निर्देशक श्री पीटर कारगिल (Peter Cargill) भारत आये।

इसके अतिरिक्त बैंक भारत को आर्थिक सहायता देने के लिए Aid India Club की बैठको में भाग लेकर भारत की सहायता करता है।

आधारभूत वस्तुओं के मूल्य-स्थायित्व के प्रश्न का अध्ययन (Study of the problem of the stabilisation of prices of primary products) :

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सहयोग से विश्व बैंक आधारभूत वस्तुओं की

कीमतों के स्थायित्व की समस्या का आजकल अध्ययन कर रहा है। इस अध्ययन के लिए बोर्ड आफ गवर्नर्स ने अपनी रियोडेजेनरो बैंक में एक प्रस्ताव पारित कर आदेश दिया था।

पियरसन आयोग (Pearson Commission) •

विकास के लिये देशों को आर्थिक सहायता देने के प्रश्न की सभी पहलुओं से जांच करने, पिछली दशाब्द में दी गई सहायता के प्रभाव तथा भावी नीति के सम्बन्ध में विस्तृत जांच के लिए कनाडा के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लेस्टर पियरसन की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया है। बैंक अध्यक्ष श्री मैकनामारा के शब्दों में "Its function is to examine the past aid efforts, and to see what lessons they teach for the future on both the political and economic level."

कमीशन के अध्यक्ष श्री पियरसन ने इसी जांच के सम्बन्ध में भारत सहित विभिन्न देशों की यात्रायें की हैं। इस कमीशन की रिपोर्टें प्रकाशित होने पर विश्व के आर्थिक विकास तथा विकास के लिए सहायता के प्रश्नों पर विस्तृत प्रकाश पढ़ने की सम्भावना है। कमीशन के निष्कर्षों के आधार पर विश्व बैंक अपनी भविष्य की नीति निर्धारित करेगा।

निष्कर्ष •

विश्व बैंक ने वास्तव में विश्व के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण सेवायें की हैं। विश्व बैंक के महत्व के बारे में बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री ब्लेक का निम्न कथन स्मरणीय है:—

"The Bank's work is not to be assessed in terms of the building of cold monuments of stone, and steel and concrete; it has had a deeper purpose—to enlarge the riches of the earth, to give men light and warmth, to lift them out of drudgery and despair, to interest them in the stirring of ideas and in the grasp of organisation and techniques toward the realisation of a day in which plenty will be a real possibility and not a distant dream "

डब्ल्यू०एम० स्केमेल (W M Scammel) के शब्दों में—

"It has shown that international functional co-operation has meaning and reality."

इसी प्रकार डा० डी. कोक (Dr Kock) के कथनानुसार —

"It has become an essential cog in the machinery of international investment "

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संकेत

(1) अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के मुख्य कार्य क्या हैं ? भारत को इस बैंक से क्या लाभ प्राप्त हुआ है ? वर्णन कीजिये ।

(आगरा, 1959, 1968)

[संकेत—प्रथम भाग में विश्व बैंक के उद्देश्यों का संक्षेप में वर्णन करते हुए बैंक के मुख्य कार्य—ऋण देना, गारन्टी करना, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण सुविधायें इत्यादि की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिये । दूसरे भाग में भारत को विश्व बैंक से प्राप्त ऋणों तथा अन्य प्रकार की सहायता का विवरण दीजिये ।]

(2) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के विधान तथा मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिये । भारत को इससे कहा तक लाभ हुआ है ?

(विक्रम वी०ए०, 1964)

[संकेत—प्रथम भाग में अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के उद्देश्य, सदस्यता, पूंजी-साधन, प्रबन्ध तथा मुख्य कार्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये । दूसरे भाग में बैंक द्वारा भारत को प्राप्त सहायता का विवरण दीजिये ।]

(3) “भारत से विश्व बैंक का सम्बन्ध शायद उसके अन्य 68 (अथ 110) सन्स्थ देशों की तुलना में सबसे अधिक विस्तृत है ।” भारत को दिये गये ऋणों के सन्दर्भ में व्याख्या कीजिये :

(राजस्थान वी०काम०, 1959)

[संकेत—भारत को विश्व बैंक से जो ऋण तथा अन्य सहायता प्राप्त हुई है उसका विस्तृत वर्णन कीजिये । यह बताते हुए कि भारत का ऋण प्राप्त करने वाले देशों में प्रथम स्थान है, भारत तथा विश्व बैंक के घनिष्ठ सम्बन्धों का विवेचन कीजिये ।]

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (International Development Association)

Much of mankind I am convinced yearns for a new philosophy in the conduct of human affairs for a re ordering of our time, our skills and our material resources to build a more creative world order

A danger of our present economic trends is that they will add both to internal and global tensions. If the development of the poor countries lags, their sense of frustration will be an element threatening the stability of society, exacerbating conflict and hobbling progress. The growing contrast between the rich and poor countries in material achievements and ways of life will make dialogue between the two more and more difficult.

Robert S McNamara

विकासशील देशों को ब्रिज शक्तों पर विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से ऋण प्राप्त होना है वे उन्हें उनका अधिक अनुकूल नहीं है। एक बार तो उन्हें दीर्घ कालीन पूंजी की आवश्यकता होना है क्योंकि अधिकतर उन्हें महंगे धन इत्यादि के लिए धन चाहिए और दूसरी ओर उनके सामान ब्याज चुकाने की समस्या रहती है। यदि दशककालीन ऋणों पर 5-6 प्रतिशत की सामान्य दर से ब्याज चुकाया जाय तो 20 वर्षों में मूलधन (Principal) के बराबर ब्याज चुकाना पड़ता है। इस प्रकार विकासशील देशों के लिए यह भार असह्य हो जाता है। विकासशील देशों की इन कठिन समस्याओं के सदृश में एक ऐसी समस्या की स्थापना का विचार हुआ जो सन्वी तथा सुनभ शतों पर विकासशील देशों की दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ इसी दिशा में किए गये प्रयत्न का परिणाम है।

विकास संघ की स्थापना तथा उद्देश्य

(Establishment of Development Association and its Objectives)

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना का विचार सबसे पहले 1958 में अमेरिका के सिनेटर मोनरोनी (Senator Monroney) ने दिया जिसे तत्कालीन

अमेरिकी राष्ट्रपति श्री आइजनहोवर ने स्वीकृति प्रदान करदी । अगस्त 1959 मे राष्ट्रपति आइजनहोवर ने सार्वजनिक रूप से इसे अपना समर्थन प्रदान किया । अक्टूबर 1959 मे वाशिंगटन मे होने वाली अपनी वार्षिक बैठक मे विश्व बैंक के गवर्नर मण्डल ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया और कार्यकारी सचानको से विकास सघ का समझौता-पत्र (Articles of Agreement) तैयार करने को कहा । 26 जनवरी 1960 को समझौता-पत्र तैयार हो गया और उसे विश्व बैंक के सभी सदस्य देशो मे प्रसारित किया गया । निर्धारित सदस्यो की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर 24 सितम्बर 1960 को अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ का जन्म हुआ और उसने 8 नवम्बर 1960 को विधिवत कार्य करना प्रारम्भ किया ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ विश्व बैंक की एक पूरक सस्या है और इसका उद्देश्य विकासशील देशो को सरल शर्तों पर ऋणो की व्यवस्था करना है । (The purpose of IDA is to provide development finance to less developed member countries on easy terms that will bear less heavily on the balance of payments position of recipient countries than do Banks loans granted on conventional terms) विकास सघ विकासशील देशो को कम ब्याज पर दीर्घकालीन ऋण देने की व्यवस्था करता है और उनका भुगतान उन्ही की राष्ट्रीय मुद्राओ मे स्वीकार करता है । संक्षेप म, विकास सघ विकासशील देशो को 'सुलभ ऋण' (Soft Loans) प्रदान करता है ।

विकास सघ की सदस्यता

(Membership of the Association)

विकास सघ विश्व बैंक की सहयोगी (Affiliate) सस्या है और विश्व बैंक का कोई भी सदस्य विकास सघ का सदस्य हो सकता है प्रारम्भ म विकास सघ के केवल 51 सदस्य थे । 31 दिसम्बर 1968 को विकास सघ की कुल सदस्य सस्या बढकर 102 हो गई है । मारीशस, बोत्सवाना, लेसोथो तथा इन्डोनेशिया ने 1968 मे ही विकास सघ की सदस्यता ग्रहण की है ।

विकास सघ के पूँजी साधन

(Capital Resources of the Association)

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ के प्रारम्भिक पूँजी 1 बिलियन (1000 मि० डालर) निर्धारित की गई थी । सदस्य देशो को भाग 1 तथा 2 भाग मे विभाजित किया गया है । भाग 1 मे 18 विकसित देश हैं । पहले भाग 1 के सदस्य देशो की सस्या 17 थी और कुर्वंत के भाग 1 के सदस्य बन जाने से यह 18 हो गई है । भाग 2 म शेष 84 अर्धविकसित तथा अर्धविकसित दसो को सम्मिलित किया गया है ।

भाग 1 के विकसित देशों को उनके पूंजी अंशों का शत प्रतिशत भाग स्वर्ण या परिवर्तनशील मुद्रा में विकास सभ का अदा करना पड़ता है। भाग 1 के विकसित देशों को अपने प्रारम्भिक पूंजी अंशों का 10 प्रतिशत निम्न प्रकार चुकाना था।

(1) आधा भाग विकास सभ का कार्य प्रारम्भ होने या देश के सदस्य बनने के 30 दिन के भीतर।

(ii) 12.5 प्रतिशत विकास सभ का कार्य प्रारम्भ होने के 1 वर्ष के भीतर और फिर 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष जब तक कुल पूंजी अंश का 10 प्रतिशत अदा न हो जाय।

भाग 2 के देशों का शेष 90 प्रतिशत भाग स्वर्ण या परिवर्तनशील मुद्रा में पांच किस्तों में अदा करना होता है।

भाग 2 के देशों को उनके पूंजी अंशों का 10 प्रतिशत स्वर्ण या परिवर्तनशील मुद्रा में चुकाना होता है। उनको अपनी पूंजी अंशों का शेष 90 प्रतिशत भाग अपने दश की मुद्रा में ही पांच किस्तों में चुकाना होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सभ

मुरय देशों के पूंजी अंश (30 जून 1968)

(मिलियन डालर में)

भाग 1			भाग 2		
देश	पूंजी अंश	कुल का प्रतिशत	देश	पूंजी अंश	कुल का प्रतिशत
1 अमरीका	320.29	32.02	1 भारत	40.35	4.03
2 ब्रिटेन	131.14	13.11	2 चीन	30.26	3.03
3 फ्रान्स	52.96	5.26	3 ब्राजील	18.83	1.88
4 जर्मनी	52.96	5.29	4 अर्जेंटीना	18.83	1.88
5 कनाडा	37.83	3.78	5 पाकिस्तान	10.09	1.01
6 जापान	33.59	3.35	6 स्पेन	10.09	1.01
7 नीदरलैंड्स	27.74	2.77	7 मेक्सिको	8.74	0.87
8 आस्ट्रेलिया	20.18	2.02	8 टर्की	5.80	0.58
9 इटली	18.16	1.82	9 यू.ए.आर.	5.08	0.51
10 स्वीडन	10.09	1.01	10 फिन्लैंड	5.04	0.50

विकास सभ का प्रबन्ध

(Management of IDA)

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सभ विश्व बैंक की सहयोगी संस्था है और उसका प्रबन्ध तथा प्रशासन विश्व बैंक ही करता है। विश्व बैंक का गवर्नर मंडल (Board of Governors) वायकारी संचालक मंडल (Board of Executive Directors) तथा अन्य अधिकारी विकास सभ की भी व्यवस्था करते हैं।

विकास संघ की ऋण व्यवस्था
(Lending Operations of IDA)

अन्तर्राष्ट्रीय संघ ने सदस्य देशों को पर्याप्त ऋण सहायता दी है।

विकास संघ ने अपने जीवन काल के 9 वर्षों में विकास शील देशों को पर्याप्त सहायता दी है। प्रारम्भ से 30 जून 1968 तक विकास संघ ने 40 देशों को 1968 मि० डालर के ऋण प्रदान किए हैं। जनवरी 1969 तक विकास संघ 43 देशों को 2,000 मिलियन डालर के 141 ऋण प्रदान कर चुका था। प्रथम दस देशों को मिले ऋणों का विवरण निम्न तालिका में दिखाया गया है।

विकास संघ द्वारा दिए गये ऋणों का विवरण

(30 जून 1968 तक)

(मिलियन डालरों में)

देश	ऋणों की संख्या	ऋण-राशि (\$)
1 भारत	21	887
2. पाकिस्तान	24	331
3. टर्की	7	80
4 कीनिया	8	39
5. नाइजीरिया	2	36
6. इथोपिया	3	28
7. मलावी	5	28
8. तंजानिया	4	27
9 कोरिया	2	25
10. थ्यूनीशिया	3	24

विकास संघ द्वारा दिए गये ऋणों का कार्यानुसार वितरण निम्न तालिका में दिखाया गया है :

विकास संघ द्वारा दिये गये ऋणों का कार्यानुसार वितरण

(30 जून 1968 तक)

(मिलियन डालरों में)

वर्ग	ऋण राशि
1 विद्युत शक्ति	112.2
2 यातायात	617.0
3. सदेश याहन	74.8
4 कृषि, वन तथा मत्स्य पालन	310.6
5. उद्योग	501.1
6 शिक्षा	127.1
7 जल प्रदाय	34.0
8 प्रायोजन निर्माण	1.6
योग	1788.4

विकास सघ द्वारा दिए गये ऋणों का क्षेत्रानुसार वितरण निम्न तालिका में दिखाया गया है :

विकास सघ द्वारा दिये गये ऋणों का क्षेत्रानुसार वितरण
(IDA Credits by Area)

(30 जून 1968 तक)

(मिलियन डालरों में)

क्षेत्र	ऋण राशि
1. एशिया तथा मध्य पूर्व	1280.6
2. अफ्रीका	309.8
3. पश्चिमी गोलार्ध	117.5
4. योरोप	80.5
योग	1788.4

उपर्युक्त वितरण से स्पष्ट है कि विकास सघ ने कुल ऋणों का 88 प्रतिशत एशिया, मध्यपूर्व तथा अफ्रीका के देशों को दिया है।

ऋणों की अवधि 50 वर्ष की है। प्रथम 10 वर्षों तक कोई अदायगी नहीं करनी होगी। अगले 10 वर्षों में ऋण राशि का 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा बाकी अगले 30 वर्षों में 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से अदा करना पड़ता है। ऋणों पर कोई व्याज नहीं लिया जाता। केवल $\frac{3}{4}$ प्रतिशत से 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से सेवा व्यय (Service charge) लिया जाता है।

विकास सघ तथा भारत
(IDA and India)

भारत अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ का प्रारम्भिक सदस्य है। उसका पूँजी अंश पाचवे नम्बर का है परन्तु विकासशील देश होने के कारण उसे भाग 2 के देशों की श्रेणी में रखा गया है जिससे उसे विकास सघ से पर्याप्त मात्रा में ऋण सुविधाएँ प्राप्त हो सकें।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ से सहायता प्राप्त करने वाले विकासशील देशों में भारत से गत 9 वर्षों में सबसे अधिक ऋण प्राप्त किए हैं। प्रारम्भ से लेकर 30 जून 1968 तक भारत ने विकास सघ के 887 मि० डालर के ऋण प्राप्त किए हैं। उन ऋणों का कार्यानुसार वितरण निम्न तालिका से स्पष्ट है :

विकास संघ द्वारा भारत को स्वीकृत ऋण

(31 जून 1968 तक)

(मिलियन डालरो मे)

कार्य	राशि
1. विद्युत शक्ति	79 0
2. यातायात :	
रेलें	197 5
बन्दरगाह	18.0
सडकें	59.5
हवाई जहाज	—
3. सदेश वाहन	75 0
4. कृषि, वन तथा मत्स्य	56.5
5. उद्योग	340 0
योग	825 5

विकास संघ ने दिसम्बर 1966 के बाद जनवरी 1969 में भारत को उसके विकास कार्यक्रम में सहायता देने के लिए 125 मिलियन डालर का ऋण स्वीकृत किया। इस राशि का प्रयोग भारत सरकार उत्पादन माल के आयात के लिए विदेशी विनिमय की व्यवस्था के लिए करेगी।

विकास संघ तथा विश्व बैंक ने जून 1969 में भारत को सदेश वाहन के विकास के लिए 55 मिलियन डालर का ऋण स्वीकृत किया है जिसमें से 35.4 मि० डालर का उपयोग सांख्यिक क्षेत्र को तीन सस्थायें आवश्यक आयात के लिए करेगी। शेष 19.6 मि० डालर आवश्यक साज सामान के आयात के लिए प्रयुक्त होंगे।

विश्व बैंक तथा संघ के एशिया विभाग के निदेशक श्री पीटर कारगिल (Peter Cargill) को भारत सरकार से जून 1969 की बातचीत से आशा है कि शीघ्र ही विकास संघ उर्वरक उत्पादन के लिए नागल तथा कोचीन के प्रस्तावित कारखानों को सहायता देगा। इन परियोजनाओं की जांच के लिए एक दल जुलाई 1969 में भारत आयेगा।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संकेत

1. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना किन कारणों से हुई ? भारत को इसकी सदस्यता से क्या लाभ प्राप्त हुआ है ?

[संकेत—प्रथम भाग में विकास संघ की स्थापना के कारण बताइये। विश्व बैंक द्वारा दिए गये ऋणों की कमियों की चर्चा करते हुए बताइये कि अ विकसित तथा अर्द्ध विकसित देशों को सस्ती तथा सुलभ शर्तों पर दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराने के लिए विकास संघ की स्थापना हुई। द्वितीय भाग विकास संघ से भारत को प्राप्त सहायता का व्योरा दीजिए।]

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation)

"The International Finance Corporation was established by member governments in 1956 as an affiliate of the International Bank for Reconstruction and Development (World Bank), to assist less developed member countries by helping to promote the growth of the private sector of their economies

IFC's principal objectives are to provide risk capital for productive private enterprises, in association with private investors and management, to encourage the development of local capital markets, and to stimulate the international flow of private capital"

विश्व बैंक ने ससार के देशों के पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। परन्तु बैंक द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता में दो मुख्य कमियाँ रही हैं। प्रथम, बैंक ऋण देता है, यह औद्योगिक तथा अन्य संस्थानों की पूंजी के अंश नहीं खरीदता। इससे बैंक ऋणदाता के रूप में संस्थानों में उतनी रुचि नहीं रखता जितनी अंशधारी रखते हैं। और फिर ऋणी संस्थान ब्याज के बोझ से सदैव दबे रहते हैं। द्वितीय, विश्व बैंक द्वारा ऋण या तो सरकार या सरकार की गारन्टी पर दिए जाते हैं। एक ओर तो सरकारें निजी क्षेत्र के संस्थानों की गारन्टी करना नहीं चाहती और दूसरी ओर सरकार की गारन्टी लेना निजी संस्थान भी नहीं पसन्द करते क्योंकि इससे उनके कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप के बढ़ने का भय रहता है। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना की गई।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना का विचार सर्वप्रथम 1952 में विश्व बैंक द्वारा संयुक्त राष्ट्र सभ की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद (Economic and Social Council) के लिए तैयार की गई एक रिपोर्ट में उठाया गया। बाद में आर्थिक तथा सामाजिक परिषद तथा साधारण सभा (General Assembly) ने वित्त निगम की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार हुआ। दिसम्बर 1954 में एक प्रस्ताव पारित कर साधारण सभा ने विश्व बैंक से वित्त निगम का घोषणा पत्र (Charter)

बनाने तथा उस पर सहमति प्राप्त करने की प्रार्थना की। 11 अप्रैल 1955 को कार्यकारी सञ्चालकों ने समझौता-पत्र का प्राहय तैयार कर लिया और उसे सदस्य देशों को प्रसारित कर दिया गया और 21 जुलाई 1955 को अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की विधिवत स्थापना हो गई। स्थापना के समय निगम के 31 सदस्य थे और उसकी कुल स्वीकृत पूंजी 78 मि० डालर थी।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के उद्देश्य (Purposes of International Finance Corporation)

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के समझौता-पत्र (Articles of Agreement) के अनुसार "निगम का उद्देश्य सदस्य देशों विशेषकर विकासशील देशों में उत्पादक निजी उपक्रम को प्रोत्साहन देकर उनके आर्थिक विकास को बढ़ाना है और इस प्रकार विश्व बैंक की क्रियाओं का पूरक होना है....."¹ निगम इस मूलभूत उद्देश्य को प्राप्त के लिए निम्नलिखित कार्य करता है.—

¹ "The purpose of the Corporation is to further economic development by encouraging the growth of productive private enterprise in member countries particularly in the less developed areas, thus supplementing the activities of the International Bank for Reconstruction and DevelopmentIn carrying out this purpose, The Corporation shall :

- (i) in association with private investors, assist in financing the establishment, improvement and expansion of productive private enterprises which would contribute to the development of its member countries by making investments, without guarantee of repayment by the member government concerned, in cases where sufficient private capital is not available on reasonable terms;
- (ii) seek to bring together investment opportunities domestic and foreign private capital, and experienced management, and.
- (iii) seek to stimulate and to help create conditions conducive to, the flow of private capital, domestic and foreign, into productive investment in member countries

"The Corporation shall be guided in all its decisions by the provisions of this Article:"

—Article One, Articles of Agreement.

(1) उत्पादक निजी साहस संस्थाओं की स्थापना, सुधार तथा विस्तार की वित्त व्यवस्था में सहायता :

वित्त निगम निजी विनियोगकर्त्ताओं के साथ मिलकर निजी क्षेत्र के उद्योगों तथा अन्य व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना, सुधार तथा विस्तार के लिए पूँजी सहायता देता है जिससे सदस्य देशों का आर्थिक विकास हो सके। निगम द्वारा बिना सरकारी गारन्टी के ऋण दिये जाते हैं। ऋण विशेषकर ऐसे क्षेत्रों के लिए दिए जाते हैं जहाँ सुगम शर्तों पर पर्याप्त निजी पूँजी उपलब्ध न हो।

(2) विनियोग अवसर, पूँजी तथा प्रबन्ध में सहयोग स्थापित करना :

निगम देशी तथा विदेशी निजी पूँजी को विनियोग के क्षेत्र बढ़ने में सहायता करता है। जहाँ योग्य प्रबन्ध उपलब्ध है परन्तु पूँजी नहीं है वहाँ पूँजी की व्यवस्था करता है और जहाँ पूँजी है परन्तु कुशल प्रबन्ध नहीं है वहाँ कुशल प्रबन्धकों की व्यवस्था करता है। इस प्रकार विनियोग अवसर, पूँजी तथा प्रबन्ध (Investment Opportunities, Capital and Experienced Management) में सहयोग तथा समायोजन स्थापित करता है।

(3) देशी तथा विदेशी निजी पूँजी के प्रवाह तथा उसके उत्पादक विनियोजन को प्रोत्साहन तथा उसके लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना :

सदस्य देशों के आर्थिक विकास के लिए देशी तथा विदेशी निजी पूँजी के विनियोजन को प्रोत्साहित करना तथा उसमें उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करना निगम का मुख्य कार्य है।

निगम की सदस्यता

(Membership of the Corporation)

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक के साथ काम करने वाली संस्था होनी हुई भी स्वतन्त्र संस्था है। वित्त निगम का सदस्य बनने के लिए विश्व बैंक का सदस्य होना आवश्यक है। स्थापना के समय जुलाई 1955 में निगम के 31 सदस्य थे जो 30 जून 1968 को बढ़कर 86 हो गये थे। 31 दिसम्बर को निगम की सदस्य संख्या 90 थी। 1967-68 में बियतनाम, मौरिटानिया तथा इन्डोनेशिया ने निगम की सदस्यता ग्रहण की। जुलाई 1968 से दिसम्बर 1968 तक बनने वाले नये सदस्य थे—मारीशस, यूगोस्लाविया, यूरागुये तथा सिंगापुर। जनवरी 1969 में चीन (तैवान) भी निगम का सदस्य बना और इस प्रकार निगम की सदस्य संख्या बढ़कर 91 हो गई।

निगम के पूँजी साधन
(Capital Resources of the Corporation)

वित्त निगम की अधिकृत पूँजी 110 मिलियन डालर है जो 1000 डालरों के 110,000 अंशों में विभाजित है। दिसम्बर 1968 में निगम की कुल प्राथित पूँजी 102 386 मि० डालर थी। जनवरी 1969 में चीन (तैवान) के निगम के सदस्य बन जाने से निगम की प्राथित पूँजी बढ़कर 106.540 मि० डालर हो गई है।

91 सदस्यीय वित्त निगम के प्रथम दस बड़े अंशधारी सदस्य देशों के पूँजी अंश निम्न तालिका में दिखाये गये हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम

मुख्य देशों के पूँजी अंश
(30 जून 1968)

(मिलियन डालरों में)

सदस्य देश	पूँजी अंश	कुल का प्रतिशत
1 अमेरिका	35 168	34 69
2 ब्रिटेन	14 400	14 21
3 फ्रान्स	5 815	5 74
4 भारत	4 431	4 37
5 जर्मनी	3 655	3 61
6 कनाडा	3 600	3 55
7 नीदरलैंड्स	3 046	3 01
8 जापान	2 769	2 73
9 बेल्जियम	2 492	2 46
10 आस्ट्रेलिया	2 215	2 19

वित्त निगम का प्रबन्ध

(Management of IFC)

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का प्रबन्ध विश्व बैंक की तरह ही एक गवर्नर मण्डल (Board of Governors), कार्यकारी सचालक मंडल (Board of Executive Directors) द्वारा होता है। गवर्नर मंडल में प्रत्येक सदस्य देश का गवर्नर मंडल में एक गवर्नर मनोनीत करने का अधिकार होता है। दिन प्रतिदिन के कार्यों के संचालन का उत्तरदायित्व कार्यकारी सचालक मंडल पर होता है। विश्व बैंक का अध्यक्ष निगम का अध्यक्ष होता है। विश्व बैंक के अध्यक्ष की सलाह से सचालक मंडल एक कार्यकारी उप समिति का निर्वाचन करता है।

निगम के कार्यकारी सचालक मंडल में 20 सदस्य होते हैं। पाँच मनोनीत सदस्य होते हैं जो निगम के पाँच सबसे बड़े अंशधारी देशों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। निगम के चौथे सबसे बड़े अंशधारी होने के कारण भारत को एक कार्यकारी सचालक मनोनीत करने का अधिकार है। शेष 15 सदस्य सदस्य देशों द्वारा निर्वाचित होते हैं।

वित्त निगम की प्रक्रियाये
(Operations of the IFC)

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम केवल निजी क्षेत्र के उद्योगों में पूँजी लगाता है या निजी विनियोग कर्ताओं को पूँजी लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्थापना के समय से लेकर 30 जून 1968 तक निगम ने 39 देशों को 272 मिलियन डालर के विनियोग (Operational Investments) तथा अभिगोपन इत्यादि किए हैं। 31 दिसम्बर, 1968 को यह राशि बढ़कर 289 मि० डालर हो गई। पहले दस देशों को प्राप्त विनियोग सहायता का विवरण निम्न तालिका में दिखाया गया है।

वित्त निगम के विनियोग
(30 जून 1968) (मिलियन डालरों में)

देश	विनियोग राशि
1. ब्राजील	33.50
2. भारत	23.40
3. मयूरिटाना	20.05
4. पाकिस्तान	17.82
5. कोलम्बिया	15.18
6. अर्जेंटाइना	13.71
7. वेनेजुएला	12.48
8. चिली	10.29
9. इथोपिया	6.74
10. पीरू	8.98

वित्त निगम ने अपनी स्थापना से 30 जून 1968 तक 34.08 मि० डालर के अभिगोपन तथा वचन रकम के वायदे किए हैं जिसका विवरण इस प्रकार है :

वित्त निगम द्वारा अभिगोपन तथा वचन दी गई रकम के वायदे
(Stand by and Underwriting Commitments)
(30 जून 1968) (मिलियन डालरों में)

देश	राशि
1. मैक्सिको	22.54
2. फिलीपीन्स	4.36
3. इथोपिया	3.71
4. नाइजीरिया	1.40
5. वेनेजुएला	.52
6. मलेशिया	.49
7. कोलम्बिया	.35
8. कोस्टारिका	.31
9. लाइबेरिया	.24
10. फिनलैंड	.16
योग	34.08

इस देशो से सम्बन्धित इस 34.8 मि० डालर के अभिगोपन दायित्व का सबसे अधिक भाग (22 54 मि० डालर) मेक्सिको के सस्थानो से सम्बन्धित है ।

31 दिसम्बर 1968 को समाप्त हुए वर्ष मे निगम ने 10 देशो में 47 9 मि० डालर के 17 विनियोग किए । इस वर्ष निगम ने ब्राजील, कोलम्बिया, जैमेका, कीनिया, कोरिया, मोरीटानिया, निकारागुआ, पाकिस्तान तथा वेनेज्यूला मे विनियोग किए । इस वर्ष निगम ने आठ बड़े नये उद्योगो को सहायता दी जिनमे 5 लेटिन अमेरिका, दो एशिया तथा एक अफ्रीका मे था ।

अप्रैल 1969 मे निगम ने थाईलैंड के सबसे बड़े Building Material Producer Siam Cement group of Companies को 22.1 मि० डालर के ऋण का दायित्व स्वीकार किया है । 22 1 मि० डालर का 61 प्रतिशत या 14.1 मि० डालर निजी वित्तीय सस्थायें विनियोजित करेगी । निगम द्वारा अभी तक किए गये विनियोगो मे यह सबसे बड़ा विनियोग है ।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम और भारत (IFC and India)

भारत अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का प्रारम्भ से ही सदस्य रहा है । भारत ने 19 अक्टूबर 1955 को वित्त निगम के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे । पूँजी अंश की दृष्टि से भारत का चौथा स्थान है और उसका पूँजी अंश 4 431 मि० डालर है । वित्त निगम के पांच सबसे बड़े पूँजी अंशधारी होने के कारण भारत का एक कार्यकारी सचालक मनोनीत करने का अधिकार है ।

अन्तर्राष्ट्रीय निगम से पूँजी सहायता प्राप्त करने वाले देशो मे भारत का दूसरा स्थान है । 30 जून 1968 तक भारत ने 23.40 मिलियन डालर की विनियोग सहायता प्राप्त की है जिसका विस्तृत विवरण निम्न तालिका मे प्रस्तुत है :

वित्त निगम के भारत मे विनियोग (30 जून 1968)

उद्योग	राशि
1. Republic Forge Company, Ltd.	1 50
2. Kirlosker Oil Engine, Ltd.	0 85
3 Assam Sillimanite Ltd	1.37
4. K. S B Pumps, Ltd.	0 21
5. Precision Bearings India, Ltd.	1 03
6. Fort Gloster Industries, Ltd	1 21
7 Mahindra Ugone Steel Co, Ltd	3 30
8 Lakshmi Machine Works, Ltd	1 31
9 Jayshree Chemicals, Ltd	1 15
10 Indian Explosives, Ltd	11 47
योग	23 40

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि निगम के कार्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों में भारत को कोई विशेष सहायता नहीं मिली। इसका कारण यह रहा है कि विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ से भारत ने पर्याप्त सहायता ली है। निगम की ऊंची ब्याज दरों तथा ऋण स्वीकार करने की कठोर शर्तों के कारण भी निजी क्षेत्र के संस्थान निगम से ऋण लेने के लिए अधिक उत्साहित नहीं रहते।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संकेत

1. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। निगम की प्रगति का विवरण देते हुए बताइये कि यह कहा तक अपने उद्देश्यों में सफल हुआ है।

[संकेत—प्रथम भाग में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना के उद्देश्यों जैसे सदस्य देशों में उत्पादक निजी पूंजी विनियोग को प्रोत्साहन आदि—का वर्णन कीजिए। दूसरे भाग में निगम की प्रगति का उल्लेख करते हुए इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।]

भाग ५

Part Five

"The flavour of Indian tea remains the same after devaluation, so does the quality of jute as cheap packing material. Devaluation does not alter the incomes of people abroad who consume Indian tea, nor is the quantum of world trade affected by devaluation to cause any reduced demand for packing materials. This logic broadly applies to export goods generally."

Prof B R Shenoy

भारतीय मुद्रा का इतिहास
(History of Indian Currency)

भारतीय चलन का इतिहास (The History of Indian Currency)

"On the whole it seems that while in all other branches and departments of administration, we endeavour to give to India the best of every thing so far as we can, yet in respect to metallic currency, we deliberately withhold from her the first rate article and afford her a second rate one"

Sir Richard Temple

यद्यपि सिक्को का प्रयोग भारत में प्राचीन काल में भी होता था परन्तु भारतीय चलन का इतिहास अपनी प्राचीनता से अधिक अपनी जटिलता के लिए प्रसिद्ध है। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के पूर्व उत्तर भारत में सोने की मुहरों और चांदी के सिक्को, दोनों का प्रयोग चलन के रूप में होता था। दक्षिण भारत में स्वर्ण मुद्राएँ ही प्रधान थीं। मुगलों के पतन के बाद अनेक छोटी रियासतों का उदय हुआ जिन्होंने अपनी स्वतन्त्रता के प्रतीक के रूप में अपनी निजी मुद्राएँ जारी कीं। भारत में अन्तर्गत होते हुए भी सम्पूर्ण भारत में दोनों धातुओं के सोना और चांदी, के प्रामाणिक सिक्के चलन में थे परन्तु इनमें कोई वैधानिक अनुपात निश्चित नहीं किया गया था। इस प्रकार उन्नीसवीं सदी के प्रथम चरण में भारतीय मुद्रा व्यवस्था एक प्रकार से बड़ी अस्त-व्यस्त अवस्था में थी जिसमें अनेक प्रकार के स्वर्ण एवं चांदी के सिक्के चलन में थे। इस अस्त-व्यस्त परिस्थिति को श्री एच० डी० मैकलॉयड (H D Mcleod) ने निम्नलिखित शब्दों में चित्रित किया है—

"994 different kinds of gold and silver coins current, of different weights and fineness, and whose value was constantly varying from day to day No one could tell the value of the coins he might hold. In making even moderate payments the parties were obliged to call in a shroff—a professional money changer to declare the value of each coin."

रजत मान की स्थापना (Silver Standard Introduced)

ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सर्वप्रथम उस समय की जटिल एवं उलझी हुई मौद्रिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयत्न किया। इसके लिए साथ-साथ सोने एवं चादी के सिक्के उनकी भार एवं शुद्धता के प्रमाण के साथ जारी किए जाने लगे एवं उनका कानूनी विनियम अनुपात निश्चित कर दिया गया। इस प्रकार द्विधातुमान की स्थापना की गई। दोनो धातुओं के सिक्को का कानूनी अनुपात बनाए रखना कठिन था क्योंकि उनके बाजार मूल्य में बहुत परिवर्तन होता रहता था। उन्ही समय ब्रिटेन के विचारकों ने एक धातुमान की अच्छाईयो का गुणगान भी प्रारम्भ किया। लार्ड लिबर पूल की प्रसिद्ध पुस्तक "ट्रीटाइज ऑन दि क्वाइस आफ दि रीम" (Treatise on the Coins of the Realm) प्रकाशित हुई जिनमें एक धातुमान की विशद् व्याख्या की गई। इन बातों से प्रभावित होकर 1835 में एक कानून द्वारा रजत मान की स्थापना की गई। इसके अनुसार चादी का सिक्का 180 (11/12 शुद्ध) का रखा गया और वही देश का प्रामाणिक एवं विधि ग्राह्य सिक्का था। स्वर्ण की मुहरें विधि ग्राह्य न हाते हुए भी विनियम के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती रही। 1841 में एक घोषणा द्वारा जनता को यह सुविधा प्रदान की गई। वह वर, लगान आदि का भुगतान सरकारी खजानों में सोने के सिक्को के माध्यम से कर सकती थी। इसक अनुसार सोने और चादी के सिक्को के बीच 1:15 का अनुपात निश्चित हुआ। 1853 में इस घोषणा को रद्द कर दिया गया क्योंकि आस्ट्रेलिया तथा कैलिफोर्निया में सोने की नई खोजों के फलस्वरूप सोने का मूल्य कम होने लगा और ग्रेशम का नियम लागू होने लगा तथा चादी के सिक्के चलन से गायब होने लगे। स्वर्ण के सिक्के पूर्ण रूप से चलन से बाहर कर दिए गए।

परन्तु जनता ने स्वर्णमान की मांग जारी रखी। उधर भारत का विदेशी व्यापार भी बढ़ता गया और चादी के सिक्के बढ़ती हुई व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो गए। इसलिए स्वर्ण के सिक्को को विधिग्राह्य बनाने की मांग और अधिक प्रबल होती गई। अन्ततः 1866 में सरकार ने स्वर्णमान के सम्बन्ध में विचार करने के लिए 'मॅन्सफील्ड कमिशन' की स्थापना की। इस कमिशन ने स्वर्णमान के पक्ष में राय दी। परन्तु सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया और 1874 में स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर दी गई कि स्वर्णमान भारत के लिए उपयुक्त नहीं है।

1874 से 1893 की अवधि में चादी के स्वर्ण मूल्य में भारी कमी हुई, क्योंकि अनेक द्विधातुमान देशों ने स्वर्णमान अपना लिया और उनकी चादी की मांग

प्रायः समाप्त हो गई । उनकी चादी की मुद्राओं का घातु के रूप में प्रयोग किया गया जिससे विश्व में चादी की पूर्ति बढ़ी । यही नहीं इस अवधि में अनेक चादी की नई खाने भी प्राप्त हुईं जिससे चादी की पूर्ति बढ़ी । उधर द्विधातुमान छोड़कर अनेक देशों (जर्मनी, फ्रांस, नार्वे, स्वीडन आदि) द्वारा स्वर्णमान अपनाने के कारण सान की माग बढ़ी । इस प्रकार चादी की पूर्ति बढ़ने तथा माग कम होने तथा स्वर्ण की माग बढ़ने के परिणामस्वरूप चादी के स्वर्ण-मूल्य में कमी होती गई । चादी के स्वर्ण-मूल्य को गिरने से रोकने के कई प्रयत्न किए गए जिनमें अमरिका का 'शर्मन एक्ट' महत्वपूर्ण है । परन्तु इन सबका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और 1892 तक चादी का मूल्य बहुत अधिक गिर गया था ।

चादी के मूल्य में जो ह्रास हुआ उसका प्रभाव उन सभी देशों पर पड़ा जो रजतमान अपनाए हुए थे । भारत भी रजतमान पर आधारित था इसलिए इसके प्रभाव से बच नहीं सका । इसके निम्नलिखित प्रभाव पड़े—

(1) भारतीय मुद्रा की विनिमय-दर क्रमशः गिरने लगी ।

(2) विदेशों द्वारा भारत में चादी के माध्यम से भुगतान करने के कारण चादी का आयात बढ़ने लगा और मुद्रा प्रसार की स्थिति पैदा हो गई और कीमत स्तर बढ़ने लगा ।

(3) ब्रिटिश कर्मचारियों को हानि होने लगी क्योंकि रजत सिक्के का पीण्ड-मूल्य कम होता गया ।

(4) भारत सरकार को आर्थिक कठिनाई होने लगी क्योंकि प्रति वर्ष पीण्ड के रूप में निर्धारित रकम भेजने के लिए अधिक रजत-सिक्कों की आवश्यकता होती थी ।

(5) विदेशी पूंजी की सहायता प्राप्त करना तथा देश का आर्थिक विकास करना कठिन हो गया क्योंकि विनिमय दर की अनिश्चितता के कारण ऋणी एवं ऋणदाता की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती थी । इसके कारण देश के औद्योगिक विकास में रुकावटें पैदा होने लगी ।

इस अवधि में चादी के मूल्य में कमी आने के प्रश्न पर विचार करने के लिए दो ममिंतिया नियुक्त की गईं । 1892 में भारत सरकार ने चादी के स्वतंत्र टकन का अन्त करने का प्रस्ताव रखा जिससे स्वर्णमान को अपनाया जा सके । 1893 में भारत सरकार ने एक दूसरा प्रस्ताव भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के समक्ष रखा जिसके अनुसार ब्रिटिश सिक्के को भारत में भी विधिग्राह्य बनाना था । 1892 में ही इस प्रश्न पर विचार करने के लिए 'हर्शल कमेटी' नियुक्त की गई ।

हर्शेल समिति (Herschell Committee)

इस कमेटी की निम्नलिखित बातों पर विचार करने का आदेश दिया गया था :

(1) क्या चादी का स्वतंत्र टकन बन्द कर दिया जाय ?

(2) क्या स्वर्ण के सिक्के अपनाए जाय और स्वर्णमान की स्थापना के लिए - आवश्यक कदम उठाए जाय ?

इस कमेटी ने 1893 में अपनी रिपोर्ट दी जिसमें भारत सरकार के प्रस्तावों का समर्थन किया गया। कमेटी के मुख्य सुझाव निम्नलिखित थे—

1. स्वर्ण अथवा चादी के स्वतंत्र टकन के लिए टकसाल बन्द कर देना चाहिए परन्तु सरकार को यह अधिकार होना चाहिए कि जनता की मांग पर 1 शि. 4 पे. की दर पर स्वर्ण के बदले चादी सिक्के ढाल सके।

2. रुपया पूर्ण विधि ग्राह्य मुद्रा बना रहना चाहिए।

3. सोने के सिक्कों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि स्वर्णमान अपनाने के लिए सोने के सिक्कों का प्रयोग आवश्यक नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से ही स्वर्णमान अपनाना चाहिए।

4. सरकारी खजानों में कर, लगान आदि 1 शि. 4 पे. प्रति रुपए की दर से स्वर्ण के सिक्कों में भी स्वीकार की जानी चाहिए।

भारत सरकार द्वारा इस कमेटी के सुझावों को स्वीकार कर लिया गया। इन्हें लागू करने के उद्देश्य से 1893 में ही क्वॉइनेज ऐक्ट (Coinage Act 1893) पास किया गया। स्वतंत्र टकन बन्द कर दिया गया परन्तु सरकार को आवश्यकता के समय मुद्रण का अधिकार था। टकसालों से 1 शि 4 पे की दर से सोने के बदले सिक्के प्राप्त करने की सुविधा दी गई। जनता को सरकारी भुगतानों में सावरेन अथवा ग्रैंड सावरेन का प्रयोग करने की छूट दी गई। 15 रुपए 1 सावरेन के बराबर निश्चित किया गया। सरकार को इसी दर पर कोप रखकर नोट जारी करने का भी अधिकार दिया गया।

स्वर्ण विनिमय मान (Gold Exchange Standard)

1893 से 1898 की अवधि को संक्रमण काल कहा जा सकता है जिसमें रुपए का विनिमय मूल्य लगभग 1 शि 4 पे. तक पहुँच गया। व्यापारिक वर्गों ने मौद्रिक अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए सरकार से जोरदार आग्रह किया। फलतः भारत सरकार ने स्वर्णमान की स्थापना और स्थायी विनिमय दर के लिए

प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर पूर्ण रूप से विचार करने के लिए 1898 में 'फाउलर कमेटी' (Fowler Committee) की नियुक्ति की गई।

फाउलर कमेटी (Fowler Committee):

इस कमेटी से यह अपेक्षा की गई थी कि भारतीय मुद्रा प्रणाली में क्या स्थाई सुधार किए जाने चाहिए तथा विनिमय दर को स्थायित्व प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की जानी चाहिए। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद इस कमेटी ने निम्नलिखित सिफारिशें की—

1. भारतीय टकसालों में सावरेन तथा अर्द्ध सावरेन का स्वतंत्र टकन प्रारम्भ कर देना चाहिए परन्तु रुपए का स्वतंत्र टकन उस समय तक नहीं होना चाहिए जब तक कि चलन में स्वर्ण का अनुपात जनता की आवश्यकताओं से अधिक न हो जाय :

2. रुपए की विनिमयदर 1 शि 4 पे. बनी रहनी चाहिए।

3. रुपया प्रधान एव विधिग्राह्य मुद्रा बना रहे।

4. स्वर्ण के बदले रुपए दिये जाने चाहिए परन्तु सरकार रुपए के बदले स्वर्ण देने को बाध्य नहीं होनी चाहिए।

5. अलग से एक स्वर्ण कोष (Gold Standard Reserve) की स्थापना की जानी चाहिए और भविष्य में रुपए की डलाई से होने वाला लाभ इसी कोष में रखा जाना चाहिए। इस कोष से रुपए की सावरेन में परिवर्तनीयता निश्चित हो सकेगी।

6. सरकार को विदेशी भुगतानों के लिए स्वर्ण उपलब्ध करना चाहिए।

भारत सरकार ने कमेटी के सुझावों को स्वीकार कर लिया। सावरेन एव अर्द्ध सावरेन को भारतवर्ष में असीमित विधिग्राह्य मुद्रा घोषित किया गया और इसके निमित्त 1899 में एक एक्ट पास किया गया। परन्तु इनके टकन के लिए भारत में टकसाल नहीं खोनी जा सकी। रुपए के टकन पर भी नियंत्रण नहीं रखा जा सका। स्वर्ण कोष भी उस प्रकार नहीं रखा गया जैसे इस कमेटी ने सिफारिश की थी और रुपए की डलाई से होने वाले लाभ को इस कोष में न रखकर अन्यत्र उपयोग किया गया। इन कारणों से सोना भारत से बाहर इंग्लैंड में केन्द्रित होने लगा और स्वर्णमान व्यवहार में स्थापित नहीं हो सका। स्वर्ण के सिक्कों के स्थान पर कागजी मुद्रा और प्रतीक सिक्के चलन में रखे गए। ऐसे नियम बनाए गए जिनसे विनिमय दर 1 शि. 4 पे. पर बनी रहे। इस प्रकार स्वर्ण विनिमय मान ही स्थापित किया जा सका क्योंकि इन व्यवस्था में सोने के सिक्के चलन में नहीं

धे, सोना केवल विदेशी भुगतान के लिए ही मिल सकता था और विदेशों में स्वर्ण कोप निर्मित किया गया। इस प्रकार स्वर्ण मान स्थापना के प्रयत्नों को परिस्थितियों ने ऐसा मोड़ दिया कि वह स्वर्ण मान न रहकर स्वर्ण विनिमय मान बन गया। विनिमय दर के परिवर्तनों को रोकने के लिए रिजर्व कौंसिल बिल का प्रयोग किया जाता था। इसका लाभ यह था कि लन्दन में इन बिलों को बेचने से काफी स्वर्ण कोप प्राप्त हो जाता था और भारत से ब्रिटेन में 'होम चार्ज' (Home charges) की रकम का सोना नहीं भेजना होता था इसलिए इसका परिवहन व्यय बच जाता था। साथ ही विनिमय दर भी स्थायी बनी रहती थी। परन्तु 1907-8 में भारत का निर्यात बहुत कम हो जाने से विनिमय दर गिरने लगी जिसे स्वर्ण और स्टर्लिंग ड्राफ्ट बेचकर रोकने का प्रयत्न किया गया। फलतः स्वर्ण कोप बहुत कम हो गया। इस स्थिति का सामना करने के लिए भारत ने अनुरोध किया कि स्वर्ण कोप का अधिकारश भाग भारत में ही रहना चाहिए और इन्हे प्रतिमूर्तियों में विनियोग नहीं किया जाना चाहिए। यह भी माग की गई कि पत्र मुद्रा कोप भी स्वर्ण में रखा जाना चाहिए।

इन प्रस्तावों में से अधिकांश भारत सचिव को मान्य नहीं थे जिसकी तीव्र आलोचना की गई। परिणाम यह हुआ कि सभी बातों की जांच करने के लिए चेम्बरलेन आयोग गठित किया गया।

चेम्बरलेन आयोग (Chamberlain Commission)

इस आयोग का गठन 1913 में किया गया। लार्ड क्रींस भी इस आयोग के एक सदस्य थे। इस आयोग ने भारतीय मुद्रा पद्धति का विस्तृत अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट फरवरी 1914 में प्रस्तुत की। आयोग की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थी—

1. भारत के लिए स्वर्ण विनिमय मान सर्वथा उचित है और स्वर्ण चलन मान की कोई आवश्यकता नहीं है।

2. स्वर्ण के टकन के लिए टकसाल की आवश्यकता नहीं, परन्तु यदि भारतीय जनता की भावना को सन्तुष्ट करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो तथा टकसाल का व्यय भारत सरकार उठाने को तैयार हो तो सावरेन अथवा अर्द्ध सावरेन के टकन के लिए टकसाल स्थापित की जा सकती है।

3. आंतरिक मुद्रा के पीछे पर्याप्त स्वर्ण कोष रखा जाना चाहिए।

4. स्वर्ण कोष (Gold Standard Reserve) के संचित की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है तथा रुपए के टकण का लाभ कम से कम कुछ समय तक पूर्ण रूप से इसी कोष में जमा किया जाना चाहिए।

5. स्वर्ण कोप का अधिकांश भाग लंदन में स्वर्ण के रूप में रखा जाना चाहिए तथा स्वर्ण कोप की भारतीय शाखा को समाप्त कर देना चाहिए ।

6. प्रतिभूतियों के आधार पर अधिक माना में नोट जारी करके मुद्रा पद्धति को अधिक लोचपूर्ण बनाना चाहिए तथा 500 रु० के नोटों को सभी स्थानों पर मान्य घोषित किया जाना चाहिए ।

7. भारत सरकार को यह उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए कि वह लंदन पर 1 शि 3 $\frac{1}{2}$ पे. की दर पर विलो को बेचेगी ।

इस आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि कुछ ही समय बाद प्रथम महायुद्ध छिड़ गया । फिर भी सिफारिशों के अनुसार स्वर्णमान कोप की भारत शाखा समाप्त कर दी गई और ऊपर दी गई सातवीं सिफारिश भी लागू कर दी गई ।

प्रथम महायुद्ध (First World War):—युद्ध के प्रारम्भ में व्यापार एवं वाणिज्य अस्त व्यस्त स्थिति में आ गया तथा फलस्वरूप मुद्रा एवं विनिमय की स्थिति भी कमजोर हो गई । सरकार ने तत्काल स्थिति का सामना करने के उपाय किए । बचत खातों से रुपया निकाला जाने लगा था और अधिक मात्रा में नोट परिवर्तन के लिए प्रस्तुत किए जाने लगे थे, परन्तु सरकार ने हड़ता से इन मांगों को पूरा किया जिससे जनता का विश्वास बनाए रखने में सहायता हुई । इस क्रिया में सरकार को हानि भी उठानी पड़ी तथा अगस्त 1914 में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण देना बन्द कर दिया गया । वास्तव में 1916 के अन्त में भारतीय मुद्रा व्यवस्था में उलझने पैदा होने लगी । भारत का आयात संकुचित होता गया और निर्यात बढ़ता गया और व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में हो गया । इसके कारण रुपए की मांग बढ़ी और सरकार ने बहुत बड़ी मात्रा में चांदी खरीदकर रुपए की मांग को पूरा किया । इसका परिणाम यह हुआ कि चांदी का मूल्य बढ़ गया और विनिमय दर 1 शि. 4 पे पर बनाए रखना कठिन हो गया प्रत्येक चांदी की मूल्य वृद्धि के साथ विनिमय दर भी बढ़ानी होती । इस प्रकार स्वर्ण विनिमय मान की समाप्ति हो गई ।

बैबिंगटन स्मिथ समिति

(Babington Smith Committee)

युद्ध का तनावपूर्ण वातावरण जब सामान्य हुआ तो विनिमय दर को स्थाई रखना अर्थ व्यवस्था के सहज संचालन के लिए आवश्यक हो गया । मई 1919 में भारत सचिव ने एक समिति नियुक्त की जिसका उद्देश्य भारतीय मुद्रा व्यवस्था पर युद्ध के प्रभावों का अध्ययन करना और सुधार के सुझाव प्रस्तुत करना था । इस कमेटी ने निम्नलिखित सुझाव रखे—

1. स्वर्ण देश की प्रधान एव असीमित विधि ग्राह्य मुद्रा बना रहे और इसका विनिमय मूल्य स्टैलिग में न रखकर स्वर्ण में रखा जाय । रुपए का मूल्य 2 शि. स्वर्ण ग्रथथा 11.30016 ग्रेन शुद्ध सोना रखा जाना चाहिए ।

2. स्वर्ण सरकार के पास संचित रहना चाहिए जिससे विदेशी भुगतान किया जा सके । यदि आवश्यक हो तो थोड़ी मात्रा में सावरेन की ढलाई की जानी चाहिए ।

3. व्यक्तिगत चांदी का आयात एव निर्यात प्रतिबन्ध रहित कर दिया जाना चाहिए ।

4 सरकार को सावरेन के बदले रुपए देने का दायित्व समाप्त कर देना चाहिए ।

5. स्वर्ण का आयात निर्यात स्वतंत्र कर दिया जाना चाहिए ।

6 रुपए के टकन से प्राप्त लाभ स्वर्णमान कोष में जमा होता रहना चाहिए एव इसका अधिकांश भाग स्वर्ण के रूप में होना चाहिए । स्वर्णमान कोष में संचित सोना का एक भाग (आधा से अधिक नहीं) भारत में ही रहना चाहिए ।

7. पत्र मुद्रा जारी करने के लिए 40 प्रतिशत धात्विक कोष रखने का कानून बना देना चाहिए । यह धात्विक कोष भारत में ही रखा जाना चाहिए ।

8 भारत सचिव व्यापारियों द्वारा माग करने पर कौंसिल बिल वेच सकता है । भारत सरकार को भी बिना भारत सचिव के परामर्श के रिजर्व कौंसिल बिल वेचने का अधिकार दिया जाना चाहिए ।

उपरोक्त सिफारिशें समिति ने बहुमत से की थी । भारतीय सदस्य सर दादिवर मेरवान जी दलाल ने इन सुझावों से असहमति प्रकट की और अपना विपरीत मत प्रकट किया । उनके अनुसार विनिमय दर को 1 शि. 4 पे. ही रखना उचित था क्योंकि चांदी का मूल्य स्थायी रूप से नहीं बढ़ा था । विनिमय दर 2 शि होने से व्यापार सतुलन भी भारत के विपक्ष में हो जायगा और सस्ते विदेशी मालों के आयात के कारण देशी व्यापार को हानि होगी ।

भारत सरकार ने बहुमत की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाए । विनिमय दर 2 शि. स्वर्ण रखा गया परन्तु कुछ ही समय बाद जब भुगतान सतुलन विपक्ष में हो गया तो यह महसूस किया गया कि यह दर बनाए रखना अत्यन्त कठिन है । इसी समय चांदी का मूल्य भी गिरने लगा था जिससे स्थापित और गम्भीर हो गई और विनिमय दर गिरकर 1 शि. स्वर्ण पर पहुँच गई । परन्तु 1922 में जब पुनः व्यापार शेष पक्ष में हो गया तो विनिमय दर बढ़ने लगी और 1924 में बढ़कर 1 शि 6 पे हो गई । इसके बाद

विनिमय दर को मुद्रा संकुचन की नीति अपनाकर इसी स्तर पर रखने का प्रयत्न किया गया ।

हिल्टन यंग आयोग (Hilton Young Commission)

अगस्त 1925 में भारतीय मुद्रा पद्धति का विस्तृत विवेचन करने और सुधार सम्बन्धी सुझाव देने के लिए हिल्टन यंग आयोग की नियुक्ति की गई । इस आयोग को मुख्य रूप से तीन प्रश्नों पर विचार करना था—(1) मौद्रिक मान का प्रश्न, (2) मौद्रिक अधिकारी का प्रश्न तथा (3) विनिमय दर का प्रश्न । इस आयोग की रिपोर्ट अगस्त 1926 में प्रस्तुत की गई । आयोग के भारतीय सदस्य सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास आयोग की रिपोर्ट से असहमत थे और उन्होंने अपनी असहमति रिपोर्ट (minute of dissent) प्रस्तुत की ।

आयोग ने सुझाव देने के पूर्व तत्कालीन मुद्रा पद्धति के निम्नलिखित दोषों की ओर भी संकेत किया—

1. उस समय देश में तीन प्रकार के कोष रखे जाते थे—स्वयंमान कोष तथा बैंकिंग कोष । परन्तु जिन सिद्धान्तों पर उन्हें रखा जाता था वे केवल मारन सचिव की सुविधा के अनुसार बदल जाते थे । इन कायों के कारण मुद्रा एवं साख नियन्त्रण का उत्तरदायित्व भी विभाजित हो गया और उसका परिणाम लाभदायक नहीं हुआ ।

2. भारतीय मुद्रा पद्धति जलभी हुई थी । दो प्रकार की साकेतिक मुद्राएं चलन में थी—सिक्के तथा कागजी नोट । दूसरी तरफ पूर्ण मूल्य सावरेन भी मुद्रा पद्धति का अंग था यद्यपि वह चलन में नहीं था । पत्र मुद्रा सिक्के में परिवर्तनीय होने के कारण मुद्रा पद्धति बहुत खर्चीली हो गई थी ।

3. भारतीय मुद्रा पद्धति में लोच का नितांत अभाव था । देश का आंतरिक व्यापार अपनी वित्तीय आवश्यकता नकद साख द्वारा पूरी करता था । मौद्रिक अधिकारी बंधानिक नीर पर केवल 12 करोड़ के नोट हुडियों के आधार पर जारी कर सकता था । देश में उचित हुडियों की कमी के कारण अतिरिक्त नकद उपलब्ध नहीं हो पाता जिसके कारण नकद साख (Cash Credit) भी नहीं मिलती । इस प्रकार लोच की कमी थी ।

4. भारतीय मुद्रा पद्धति का एक दोष यह भी बताया गया कि इसमें स्वयंचालिता नहीं है । अर्थात् मुद्रा की मात्रा स्वतः व्यापारिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार घटती अथवा बढ़ती नहीं थी ।

5. इन कमियों का परिणाम यह था कि भारतीय मुद्रा पद्धति में जनता का विश्वास अधिक नहीं था। आयोग का मत था कि भारतीय मुद्रा पद्धति में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है : "The evolution of Indian economic system has now reached the stage when her currency can and should be placed upon a more simple certain and stable basis"

मौद्रिक मान के प्रश्न पर विचार करते समय आयोग ने स्वर्णमान की सभी किस्मों पर विचार किया। तत्कालीन स्टलिंग विनिमय मान के सम्बन्ध में आयोग का मत था कि यद्यपि इसके दोषों को दो कोषों के स्थान पर एक कोष रखकर दूर किया जा सकता है परन्तु इस पद्धति में जो निहित दोष हैं उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता। अर्थात् रुपए का भाग्य स्टलिंग के ऊपर निर्भर करेगा, इसलिए यह उपयुक्त नहीं है।

स्वर्ण विनिमय मान के सम्बन्ध में आयोग की यह धारणा थी कि इनमें जनता का विश्वास नहीं रहता इसलिए तत्कालीन परिस्थितियों में भारत के लिए यह भी उपयुक्त नहीं था।

स्वर्ण चलन मान के सम्बन्ध में एक योजना श्री एच. डेनिंग द्वारा प्रस्तुत की गई। इस योजना में यह आशा प्रकट की गई थी कि स्वर्ण चलन मान भारतीय मुद्रा पद्धति की सभी कमियों को दूर कर देगा। परन्तु कमीशन की राय में यह भी उपयुक्त नहीं था क्योंकि इसके लिए भारत द्वारा सोने की अधिक मांग की जायगी। इसे पूरा करना कठिन होगा। दूसरे स्वर्णमान देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कमीशन ने यह विचार व्यक्त किया कि जब अन्य देश स्वर्ण चलन मान का परित्याग करके मितव्ययिता लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हों तो भारत में स्वर्ण चलन मान की स्थापना की बात करना उचित नहीं है। स्वर्ण चलन मान अपनाने का चांदी बाजार पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा।

आयोग के समक्ष अब केवल स्वर्ण पिंडमान का विकल्प शेष था और इसने इसे ही अपनाने का सुझाव दिया। आयोग ने यह मत व्यक्त किया कि इस प्रकार के स्वर्ण पिंडमान में देश के अन्दर पहले की तरह पत्र मुद्रा और प्रतीक सिक्कों का चलन रहेगा परन्तु मुद्रा का मान स्वर्ण होगा। दश की मुद्रा एक निश्चित दर पर 1065 सोने के स्वर्ण पिंडों में परिवर्तनीय होगी। इसी दर पर सरकार सोना खरीदने की भी बाध्य होगी। इसके कारण मुद्रा पद्धति में स्वयंचालिता का गुण आ जायगा तथा जनता का विश्वास भी प्राप्त हो जायगा। इसके सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए—

1. सावरेन को विधिग्राह्य मुद्रा नहीं रखा जाय।

स्टर्लिंग पावने के रूप में भारत ने जो इतनी बड़ी रकम जमा करली थी उसका एक साथ भुगतान करना इंग्लैंड के लिए प्रायः असम्भव था। इंग्लैंड के कई राजनीतिज्ञ इतने मत के समर्थक थे कि भारत को इस ऋण का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि युद्ध का व्यय भारत के रक्षार्थ भी हुआ है। कई लोग इस रकम को घटाने का सुझाव दे रहे थे क्योंकि उनके अनुसार जो माल भारत ने बेच कर यह पावना एकत्र किया है वह युद्ध के कारण बहुत ऊँची कीमत पर बेचा है। इस विचारधारा की भारत में बड़ी आलोचना भी हुई और ऐसे ब्रिटिश नेताओं और विद्वानों को वृत्तन्त कहा गया क्योंकि भारत ने जनहित की उपेक्षा करके युद्ध-व्यय वहन करने के लिए जो माल भेजा वह वास्तव में बाजार भाव से भी कम मूल्य पर भेजा। इसके परिणामस्वरूप भारत में मुद्रा प्रसार को स्थिति पैदा हो गई थी और लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा परन्तु इंग्लैंड में जो लोग सत्ताह्वय थे उन्होंने सर्वे न्याय संगत हल अपनाया और आश्वासन दिया कि इंग्लैंड स्टर्लिंग पावना का भुगतान करने में प्रयत्नशील रहेगा।

स्टर्लिंग पावनों के प्रयोग का सर्व प्रथम एक अल्पकालिक समझौता 1947 की जुलाई में हुआ जिसके अनुसार 65 करोड़ पाँड का तत्काल प्रयोग किया गया। जुलाई 1948 में एक समझौते के अनुसार इंग्लैंड द्वारा खरीदे गए युद्ध के सामानों को भारत ने स्टर्लिंग पावना की रकम में से 10 करोड़ पाँड देकर खरीद लिया। अंग्रेज कर्मचारियों की पेंशन आदि का भुगतान करने के लिए 14.75 करोड़ पाँड का प्रयोग किया गया। भारत ने रक्षा-व्यय योजना के अन्तर्गत इस रकम में से 55 करोड़ पाँड का इंग्लैंड को भुगतान किया। सन् 1951 की जून तक रिजर्व बैंक को 16 करोड़ पाँड के प्रयोग का अधिकार दिया गया। स्टर्लिंग पावने में से 434 करोड़ रुपये के बराबर भाग पाकिस्तान को दिया गया। जुलाई 1951 में एक अन्य समझौता किया गया जिसके अनुसार भारत को जून 1957 तक 3½ करोड़ पाँड प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। 31 करोड़ पाँड की रकम रिजर्व बैंक के मुद्रा कोष के रूप में जमा करने की व्यवस्था की गई। परन्तु वास्तव में स्टर्लिंग पावनों का प्रयोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में विदेशी विनिमय के संकट काल में उपभोग वस्तुओं के भुगतान के निमित्त किया गया। तृतीय योजना काल के अन्त तक पाँड पावना केवल इतिहास की बात रह गया।

साम्राज्य डालर कोष (Empire Dollar Pool) : द्वितीय महायुद्ध की अवधि में अमेरिका ही प्रधान निर्यातक था इसलिए डालर की मांग बढ़ती गई और वह दुर्लभ मुद्रा बन गया। इस दुर्लभ मुद्रा को उत्तम ढंग से प्रयोग करने के उद्देश्य से ब्रिटिश साम्राज्य के देशों में एक समझौते के अनुसार उनके द्वारा अर्जित डालरों को एक ही कोष में जमा करने की व्यवस्था की गई। यही कोष साम्राज्य डालर कोष कहा जाता है।

इस कोप का प्रयोग करने में बड़ी मितव्ययिता रखना था। इस कोप का संचालन बैंक आफ इंग्लैंड के हाथ में था। अनिवार्य होने सदस्य देश इस कोप से डालर प्राप्त कर सकते थे। युद्ध के प्रारम्भिक कुछ वर्षों तक भारत का भी इस कोप में महत्वपूर्ण सहयोग रहा परन्तु बाद में भारत अमेरिका से आयात अधिक करने लगा और भुगतान के लिए डालरों की आवश्यकता पड़ी इसीलिए कुल सहयोग की मात्रा कम हो गई।

युद्ध के बाद के वर्षों में डालर प्राप्त करना और इसकी पूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप तथा विश्व बैंक से उधार लेकर की जाने लगी। अन्य अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मौद्रिक संस्थाओं की स्थापना के बाद से इस कोप का महत्व निरन्तर कम होता जा रहा है।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके सकेत

(1) द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् भारतीय मुद्रा तथा विनिमय प्रणाली में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं ?

(आगरा 1962, राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल, 1969)
अथवा

सन् 1947 से सन् 1960 के बीच की भारतीय मुद्रा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

[सकेत—द्वितीय महायुद्ध के बाद मौद्रिक क्षेत्र में होने वाली प्रमुख घटनाओं—मुद्रा स्फीति, भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन, स्टर्लिंग सम्पत्तियों का अत्यधिक संग्रह तथा विनिमय नियन्त्रण आदि—का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।]

(2) द्वितीय महायुद्ध के भारतीय चलन तथा विनिमय प्रणाली पर हुए प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

(राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल 1968)
[सकेत—द्वितीय महायुद्ध का भारतीय चलन तथा विनिमय प्रणाली पर मुद्रा स्फीति, स्टर्लिंग सम्पत्तियों के अत्यधिक संग्रह तथा विनिमय नियन्त्रण आदि के रूप में जो प्रभाव पड़ा, उसका विस्तारपूर्वक विवेचन कीजिए।]

भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली (The Present Monetary System of India)

“Economic stability cannot be achieved by monetary policy alone.”

George N. Halm

भारत की वर्तमान मौद्रिक व्यवस्था की व्याख्या करते समय हमें भारतीय मुद्रा पद्धति की प्रधान विशेषताओं पर विचार करना होगा। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि भारत में इस समय किस प्रकार का मौद्रिक मान अपनाया गया है, मौद्रिक नीति किस प्रकार की है तथा मौद्रिक नियन्त्रण की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है।

मौद्रिक मान (Monetary Standard) :

यहाँ भारतीय मौद्रिक मान के दोनो पक्षों—आन्तरिक एवं बाह्य, पर विचार किया जायगा। भारत की आन्तरिक मौद्रिक व्यवस्था 'पत्र-मान' (Paper Standard) पर आधारित है। देश की सीमाओं के अन्दर पत्र-मुद्रा तथा साकेतिक सिक्कों का चलन है तथा वे विधिग्राह्य हैं। आन्तरिक क्षेत्र में रुपया किसी धातु से सम्बन्धित नहीं है। रुपए का मूल्य किसी भी धातु के सदृश में स्थिर नहीं रखा जाता है। मुद्रा की मात्रा एवं मूल्य, मुद्रा की मांग तथा रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर निर्भर करता है। चलन में नोटों का बाहुल्य है। रुपए का सिक्का भी चलन में है परन्तु वह प्रामाणिक सिक्का नहीं है। यह केवल हिसाब की इकाई मात्र है। रुपया भारत की प्रधान मुद्रा है। प्रधान मुद्रा के अतिरिक्त सहायक मुद्रा भी चलन में प्रयोग की जाती है।

भारत में नोट जारी करने की जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें रिजर्व बैंक तथा सरकार दोनो ही भागीदार हैं। एक रुपए के नोटों को जारी करने का अधिकार सरकार को है परन्तु इसके अलावा अन्य नोटों को जारी करने का एकाधिकार रिजर्व बैंक को है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर युक्त प्रतिज्ञा की गई रहती है कि धारक को अक्रिय रुपए का भुगतान रिजर्व

बैंक मागने पर करेगा। जब से नए नोटों पर हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में यह प्रतिज्ञा अंकित की जाने लगी है तब से 'मागने पर' शब्द हटा दिया गया है। अब इस प्रकार की प्रतिज्ञा होती है—“मैं धारक को...रुपए अदा करने का वचन देता हूँ” (I promise to pay the bearer the sum of Rupees...)। यहाँ यह स्पष्ट रूप से समझ लेना आवश्यक है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा दिए गए वचन का तात्पर्य यह नहीं है कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नोट परिवर्तनशील हैं क्योंकि इन नोटों के बदले रिजर्व बैंक केवल एक रुपये के नोट देने का वचन देता है जो सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और जिन पर किसी प्रकार की प्रतिज्ञा अंकित नहीं होनी। परिवर्तनशील उस समय कहा जाता जब इनके बदले धातु देने का वचन दिया जाता। इसलिए भारतीय पत्र-मुद्रा अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा है।

किसी देश की मौद्रिक प्रणाली के अध्ययन में नोट जारी करने की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होती है। भारत में सन् 1935 से अक्टूबर 19 6 तक 'मानुपातिक कोष प्रणाली' के आधार पर नोट जारी किए जाते थे। अधिनियम के अनुसार जारी किए गए नोटों के 40 प्रतिशत के बराबर स्वर्ण, स्वर्ण निक्के या विदेशी प्रतिभूतियाँ रखना अनिवार्य था। इस प्रणाली का प्रमुख दोष यह था कि इसके अन्तर्गत उपयुक्त लोच का अभाव था। मुद्रा को सुविधापूर्वक बढ़ाया नहीं जा सकता था। भारत ने 1951 से नियोजित आर्थिक विकास का सक्लप कर लिया था। अतः मुद्रा प्रणाली में सापेक्षता एवं लोच होना आवश्यक था। इसलिए रिजर्व बैंक अधिनियम में अक्टूबर 1956 में संशोधन किया गया और नोट जारी करने की 'न्यूनतम कोष प्रणाली' अपनाई गई। संशोधन से पूर्व सोने का मूल्य 21 24 रुपये प्रति तोला के हिसाब से निश्चित था परन्तु इसके बाद 62 50 रुपये प्रति तोला की दर पर निश्चित किया गया। अक्टूबर 1956 से अक्टूबर 1957 तक भारत में नोट जारी करने के लिए रिजर्व बैंक को कुल 515 करोड़ रुपये का न्यूनतम कोष रखना अनिवार्य था जिसमें स्वर्ण या स्वर्ण निक्के का न्यूनतम कोष 115 करोड़ तथा विदेशी प्रतिभूतियाँ का न्यूनतम कोष 400 करोड़ निश्चित किया गया था। विशेष संकट की स्थिति में सरकार की पूर्ण अनुमति से प्रतिभूतियों का कोष 300 करोड़ तक घटाया जा सकता था परन्तु इससे (300 करोड़ रुपये) कम प्रतिभूतियाँ किसी भी हालत में नहीं हो सकती थी। 1957 में पुनः रिजर्व बैंक अधिनियम में परिवर्तन किया गया। स्मरण रहे कि उस समय भारत में विदेशी विनियम का संकट था और इसका समाधान करने के लिए विदेशी प्रतिभूतियों की आवश्यकता थी। इस स्थिति का ध्यान में रखकर न्यूनतम कोष 200 करोड़ रुपये कर दिया गया जिसमें स्वर्ण या स्वर्ण निक्के की न्यूनतम सीमा 115 करोड़ और शेष विदेशी प्रतिभूतियाँ रखना था। याद रहे कि विदेशी प्रतिभूतियों की न्यूनतम सीमा समाप्त कर दी गई।

सवट की स्थिति में सरकार की पूर्ण अनुमति से प्रतिभूतियों को पूर्णरूप से समाप्त किया जा सकता है।

सहायक सिक्को की डलाई भारत में अप्रैल, 1957 से दशमिक प्रणाली के अनुसार की जाती है। ये सभी साकेतिक सिक्के हैं। रुपए का $\frac{1}{2}$ भाग अर्थात् 50 पैसे का सिक्का 1 रुपये के सिक्के की तरह असीमित विधि ग्राह्य है तथा अन्य सिक्के सीमित विधि ग्राह्य हैं। प्रारम्भ में 'नया पैसा' सहायक मुद्रा की इकाई के रूप में माना गया परन्तु जून 1964 से 'नया पैसा' के स्थान पर 'पैसा' सहायक मुद्रा की इकाई बन गया है। आजकल 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25 और 50 पैसे के सिक्के सहायक सिक्को के रूप में चलन में हैं। दशमिक प्रणाली अपनाने से हिसाब-किताब रखने में पर्याप्त सुविधा हो गई है।

भारतीय मौद्रिक मान का दूसरा पक्ष उसका बाह्य रूप है। दूसरे देशों की मुद्राओं से भारतीय रुपए का सम्बन्ध किस प्रकार स्थापित किया जाता है, यही रुपए का बाह्य पक्ष है। सितम्बर 1931 से फरवरी 1947 तक भारत के रुपए का बाह्य मूल्य पौण्ड स्टर्लिंग से सम्बद्ध था। इस अवधि में भारत में स्टर्लिंग विनिमय मान लागू था और 1 रुपया, 1 शि० 6 पे० के बराबर माना जाता था। मार्च 1947 में भारत के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनते ही भारतीय मुद्रा प्रणाली में एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ और स्टर्लिंग विनिमय मान की समाप्ति हो गई।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता स्वीकार करने के बाद भारतीय रुपए का समता मूल्य (Par value) स्वर्ण तथा अमेरिकी डालर में व्यक्त किया गया। उसी समय से रुपए का बाह्य मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नियमों के अनुसार नियन्त्रित होता है। प्रारम्भ में भारतीय रुपए का समता मूल्य 0 268601 ग्राम शुद्ध सोना तथा 30 225 अमेरिकी सेण्ट निर्धारित किया गया। 1949 में जब पौण्ड स्टर्लिंग के अवमूल्यन के फलस्वरूप रुपए का भी अवमूल्यन कर दिया गया तो समता मूल्य बदलकर 0 186621 ग्राम शुद्ध सोना तथा 21 अमेरिकी सेण्ट हो गया। 5 जून 1966 को पुन रुपए का अवमूल्यन हो जाने से रुपए का समता मूल्य अब 0 118516 ग्राम शुद्ध सोना तथा 13 33 अमेरिकी सेण्ट रह गया है। अब रुपया अपने समता मूल्य के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी सदस्य देशों की मुद्राओं से स्वतन्त्र रूप से सम्बन्धित है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया केवल स्टर्लिंग का ही नहीं अपितु सभी सदस्य देशों की मुद्राओं का क्रय-विक्रय करता है। यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि भारत में विदेशी मुद्राओं का प्रथम विक्रय स्वतन्त्रता पूर्वक नहीं किया जाता। द्वितीय महायुद्ध काल से ही भारत में कम अधिक मात्रा में विनिमय नियन्त्रण की नीति अपनाई गई है। विनिमय नियन्त्रण का कार्य भार रिजर्व

बैंक को सौंपा गया है। भारत ने जब से आर्थिक विकास को नियोजित ढंग से करने की नीति अपनाई है उस समय से हमारी विदेशी विनिमय की भाग निरन्तर बढ़ती रही है। बढ़ती हुई विदेशी विनिमय की आवश्यकता के कारण विदेशी विनिमय पर नियन्त्रण दिन-प्रति-दिन कड़ा होता जा रहा है। विनिमय नियन्त्रण के अध्याय में आपको यह बताया जा चुका है कि भारत में विनिमय नियन्त्रण की क्या व्यवस्था है।

मौद्रिक अधिकारी और व्यवस्था (Monetary Authority and Management)

रिजर्व बैंक भारत का केन्द्रीय बैंक है। केन्द्रीय बैंक होने के नाते इसे नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। यही सरकार तथा व्यापारिक बैंकों के बैंक एवं अन्तिम ऋणदाता का कार्य करता है। देश की मौद्रिक व्यवस्था को संचालित एवं नियन्त्रित करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की ही है। इसलिए देश हित को ध्यान में रखते हुए साल एवं मुद्रा का नियन्त्रण करना रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य है। इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए इसे मुद्रा बाजार पर नियन्त्रण रखना भी आवश्यक होता है।

भारतीय मुद्रा बाजार के दो रूप हैं—संगठित तथा असंगठित। जहां तक मुद्रा बाजार के संगठित अंग—स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, व्यापारिक बैंक, विनिमय बैंक, आदि, का प्रश्न है उन पर अक्रुण रखने में रिजर्व बैंक को पर्याप्त सफलता मिलती है। परन्तु ग्रामीण भारत में जिन वित्तीय स्रोतों का महत्व है वे भारतीय मुद्रा बाजार के असंगठित अङ्ग में शामिल हैं। इस अङ्ग पर नियन्त्रण करने में रिजर्व बैंक पूर्ण-रूप में सफल नहीं हो पाता। रिजर्व बैंक साल नियन्त्रण के उन सभी तरीकों का प्रयोग करता है जो किसी केन्द्रीय बैंक को उपलब्ध हैं—बैंक दर, खुले बाजार की त्रियाएँ, नकद कोष में परिवर्तन, ऋण नीति में परिवर्तन, नैतिक प्रभाव एवं प्रचार आदि। रिजर्व बैंक सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार से साल नियन्त्रण करता है।

वर्षों से यह महसूस किया जा रहा था कि व्यापारिक बैंक कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में उचित हाथ नहीं बटा रहे हैं। बैंकों के सामाजिक दायित्व के महत्व की चर्चा करते हुए समय-समय पर उनके राष्ट्रीयकरण की मांग की जा रही थी। सरकार ने 1968 के अन्त में कानूनी तौर पर बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण लागू कर दिया है। आशा है बैंक अब भारतीय अर्थव्यवस्था में पहले से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। मुद्रा और साल नियन्त्रण के क्षेत्र में भी बैंकिंग अधिनियम में परिवर्तन ला कर रिजर्व बैंक के हाथों को मजबूत किया गया है। आशा है कुछ वर्षों में रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार पर पूरा नियन्त्रण रखने में सफल हो सकेगा।

मौद्रिक नीति (Monetary Policy)

किमी भी अर्थ-व्यवस्था में सरकार द्वारा उसके आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चलन में मुद्रा की मात्रा के प्रसार एवं संकुचन की व्यवस्था को मौद्रिक नीति कहा जाता है। स्पष्टतः मौद्रिक नीति का सम्बन्ध किसी आर्थिक लक्ष्य से है। भारत एक विकासशील देश है और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से, विशेषकर आर्थिक नियोजन के प्रारम्भ से, इसका आर्थिक लक्ष्य, आर्थिक विकास एवं अधिकतम सामाजिक कल्याण की व्यवस्था करना है। इसलिए भारतीय मौद्रिक नीति इस आर्थिक लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होनी चाहिए। मौद्रिक नीति सदैव इस बात को ध्यान में रख कर बनाई जाती है कि विकास कार्यों में बाधा न पड़े। योजनाओं को पूरा करने के लिए उचित समय पर उचित मात्रा में साख और मुद्रा उपलब्ध हो सके, यही हमारी मौद्रिक नीति का निर्देशक तत्व है। परन्तु साथ ही मौद्रिक नीति के निर्धारण में कीमती स्तर के नियन्त्रण एवं बाह्य मूल्य की स्थिरता पर भी ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार मौद्रिक नीति में जहाँ एक ओर विकास की गति को तीव्र करने के उद्देश्य से मौद्रिक प्रसार की व्यवस्था है वहाँ दूसरी ओर अत्यधिक मुद्रा प्रसार के दुष्परिणामों से बचने का प्रयत्न भी शामिल है।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संकेत

1. भारत की वर्तमान नोट निर्गमन प्रणाली का वर्णन कीजिए। इसके लाभ तथा हानिया क्या हैं ?
(राजस्थान बी० काम, 1962)

[संकेत—प्रथम भाग में भारत की वर्तमान न्यूनतम कोप नोट निर्गमन पद्धति का सविस्तार वर्णन कीजिए। दूसरे भाग में इसके लाभ तथा हानिया बताइये।]

2. भारत की वर्तमान चलन पद्धति की संक्षिप्त विवेचना कीजिए।

(राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल, 1966, 1967)

[संकेत—भारत की वर्तमान चलन पद्धति का वर्णन कीजिए।]

रुपए का अवमूल्यन (Devaluation of Rupee)

"The case of devaluating when there is internal inflationary pressure and external deficit, is that this remedy will tend to correct both disequilibria. The case against devaluating when there is internal inflationary pressure and external deficit is that even if the devaluation has a remedial effect on the external balance, it will increase the internal inflationary pressure."

R. F. Harrod

1949 में रुपये का अवमूल्यन (Devaluation of Rupee in 1949)

युद्ध के बाद की मौद्रिक घटनाओं में अवमूल्यन सबसे अधिक महत्व रखता है। अवमूल्यन का सूत्रपान इंग्लैंड ने किया। 18 सितम्बर 1949 को इंग्लैंड ने स्टर्लिंग का 30.5 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया। स्टर्लिंग के अवमूल्यन के कारण स्टर्लिंग क्षेत्र से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने वाले देशों में भी अवमूल्यन की एक लहर सी आ गई और भारत वर्ष भी इस प्रभाव से बच नहीं सका। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहमति से भारत ने भी उसी समय रुपए का स्वर्ण मूल्य 0.268601 ग्राम से घटा कर 0.186621 ग्राम कर दिया और रुपए का 30.5 प्रतिशत अवमूल्यन हो गया।

अवमूल्यन के कारण (Causes of Devaluation)

यद्यपि स्टर्लिंग तथा रुपए आदि का अवमूल्यन एक आकस्मिक घटना थी फिर भी इसके कई महत्वपूर्ण कारण थे। युद्ध के बाद की आर्थिक परिस्थितियों ने अवमूल्यन करने को बाध्य कर दिया था। इन महत्वपूर्ण कारणों में निम्नलिखित मुख्य हैं—

1. द्वितीय महायुद्ध काल में नोटों की मात्रा में जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई उसके कारण जो मुद्रा प्रसार की भयानक स्थिति सामने आई उससे सरकार सकुते की हालत (embarrassing position) में आ गई थी।

2. एक रुपए के नोट जारी किए जाय तथा अन्य नए नोट भी जारी किए जाय परन्तु उन्हें चादी में परिवर्तनीय न रखा जाय बल्कि स्वर्ण पिंडों में परिवर्तनीय बनाया जाय ।

3. नए रुपयों की ढलाई कुछ समय के लिए बन्द कर दी जाय ।

4. स्वर्णमान कोप तथा पत्र मुद्रा कोप को अलग न रखकर एक में मिला दिया जाय ।

5. मौद्रिक अधिकारी 21 रु० 3 आने 10 पाई प्रति तोला की दर से 1065 तोले या अधिक के स्वर्ण पिंडों का क्रय-विक्रय करने का दायित्व लेवे ।

दूसरा प्रश्न जिस पर इस आयोग ने विचार किया वह मौद्रिक अधिकारी का था । आयोग ने इस बारे में विचार किया कि मौद्रिक मान को संचालित करने का भार किसे सौंपा जाय । इस सम्बन्ध जो व्यवस्था उस समय लागू थी वह उपयुक्त नहीं थी क्योंकि नोट जारी करने का कार्य सरकार के हाथ में था और साख नियन्त्रण बैंक के हाथ में । आयोग का मत था कि किसी भी मौद्रिक व्यवस्था का सफल संचालन तभी हो सकता है जब मुद्रा और साख दोनों पर नियन्त्रण रखने का उत्तरदायित्व एक ही सस्था के ऊपर हो । इसलिए आयोग ने शीघ्र ही भारत में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो । इसी बैंक को स्वर्ण पिंड मान संचालित करने का अधिकार सौंपा जाना चाहिए । नोट जारी करने का अधिकार भी इसी बैंक को प्राप्त होना चाहिए । नोट जारी करने के लिए आनुपातिक कोप प्रणाली अपनाने का सुझाव दिया गया ।

तीसरा प्रश्न रुपए की विनिमय दर के सम्बन्ध में था यद्यपि आयोग की नियुक्ति के समय रुपए की विनिमय दर 1 शि० 6 पे० थी परन्तु विनिमय दर के सम्बन्ध में युद्धोत्तर काल से ही विवाद चल पड़ा था । कुछ लोग विनिमय दर 1 शि० 4 पे० रखने के पक्ष में थे और कुछ लोग 1 शि० 6 पे० । आयोग ने विनिमय दर 1 शि० 6 पे० रखने का सिफारिश की और इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए—

1. वर्तमान विनिमय दर 1 शि० 6 पे० पर स्थिर हो चुकी है और इसमें परिवर्तन करने से नई विनिमय दर परिस्थितियों से सामंजस्य लाने में कठिनाई होगी ।

2. प्रचलित विनिमय दर 1 शि० 6 पे० पर कीमती और मजदूरी में भी सामंजस्य स्थापित हो चुका है । इस लिए इसे भंग करना उचित नहीं होगा ।

3. आयोग ने स्वीकार किया कि 1 शि० 6 पे० विनिमय दर होने से दीर्घकालिक प्रसविशे पर बुरा प्रभाव पड़ेगा परन्तु इससे अधिक नुकसान नहीं होगा क्योंकि

कीमतों की वृद्धि इसे कम कर देगी। आयोग ने यह मत व्यक्त किया कि यह कठिनाई निम्नी भी विनिमय दर को स्थाई बनाने से पैदा हो सकती है।

4 1 शि० 6 पे० के स्थान पर 1 शि० 4 पे० को विनिमय दर बनाने से भारतीय राजस्व पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। सरकार की आय में कमी हो जायगी जिसको पूरा करने के लिए कर आदि को बढ़ाना होगा। यदि कर आदि को बढ़ा दिया गया तो उसके परिणामस्वरूप व्यापार-व्यवसाय में स्थिरता नहीं रह सकेगी और निश्चित आय-वर्ग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनका जीवन यापन-व्यय बढ़ जाएगा।

यद्यपि भारत सरकार द्वारा आयोग के बहुमत को स्वीकार किया गया और विनिमय दर 1 शि० 6 पे० रखी गई, परन्तु आयोग के सदस्य सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने इसका कड़ा विरोध किया एवं विनिमय दर 1 शि० 4 पे० रखने का आग्रह किया। यहाँ 1 शि० 4 पे० के पक्ष में दिए गए तर्कों का उल्लेख करना भी आवश्यक है :

1. 1 शि० 4 पे० ही भारत के लिए उपयुक्त एवं स्वाभाविक विनिमय दर है क्योंकि यह दर 1893 से 1917 तक बनी रही। युद्ध के प्रभाव वश ही यह दर कायम नहीं रह सकी। युद्ध के बाद के शांत वातावरण में उसे ही पुनः लागू करना उचित और स्वाभाविक है।

2 युद्ध के बाद स्वर्णमान ग्रहण करने वाले सभी देशों ने युद्ध के पूर्व की या उसमें भी कम विनिमय दर को अपनाया है इसलिए भारत को भी युद्ध के पूर्व की विनिमय दर ही अपनानी चाहिए।

3. 1 शि० 6 पे० विनिमय दर रखने से कीमतें गिरेगी और कीमतों तथा मजदूरी में सामंजस्य लाने में काफी समय लगेगा।

4. विनिमयदर 1 शि० 4 पे० रहने पर दीर्घकालिक प्रसविदाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने 1 शि० 6 पे० के विरुद्ध निम्नलिखित तर्कों प्रस्तुत किये—

1. 1 शि० 6 पे० कृत्रिम विनिमय दर है। यह स्वाभाविक विनिमय दर नहीं कही जा सकती क्योंकि इसकी मुद्रा संकुचन की नीति द्वारा बनाए रखा जा रहा है।

2. 1 शि० 6 पे० पर भारतीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में सामंजस्य होने में अभी पर्याप्त समय लगेगा।

3. इस विनिमय दर से मजदूरी का भी सामञ्जस्य स्थापित नहीं हो सका है। कीमतों के गिरने पर भी मजदूरी नहीं घटी है। यदि मजदूरी घटा कर सामञ्जस्य लान का प्रयत्न किया गया तो पूंजीपति और मजदूरों में सघर्ष पैदा हो जायेगा।

4. 1 शि० 6 पे० की दर दीर्घ कालिक प्रसविदाओं के लिए हानिकर है क्योंकि इसी ऋणी व्यक्तियों का बोझ बढ जायगा।

परन्तु, जैसाकि पहले बताया जा चुका है, बहुमत 1 शि० 6 पे० के पक्ष में था इसलिए वही विनिमय दर अपनाई गई। सरकार ने आयोग की अन्य सिफारिशों को भी स्वीकार किया और उसे कार्य रूप देने के लिए एक एक्ट पास किया। सावरेन तथा अर्द्धसावरेन विधिग्राह्य नहीं रहे। नोट, रुपया एवं अठनी अनीमित विधि ग्राह्य मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाने लगी। सरकार को स्वर्ण पिंड बेचने-खरीदने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। परन्तु सरकार को यह अधिकार भी दिया गया कि यह इंग्लैण्ड में मुग्तान करने के लिए जनता को स्टर्लिंग भी बेच सकती है। इस प्रकार स्वर्ण पिंड मान तथा स्टर्लिंग विनिमय मान का मिला-जुला रूप अपनाया गया। केन्द्रीय बैंक की स्थापना सम्बन्धी सिफारिश को लागू नहीं किया जा सका।

इस एक्ट से लगभग ढाई वर्ष तक अर्थ-व्यवस्था में सामान्य सुधार के लक्षण दिखाई देते रहे परन्तु 1929 की विश्व व्यापी मंदी के कारण सामान्य कीमत स्तर गिरने लगा तथा व्यवसाय एवं व्यापार में अप्रत्याशित मन्दी छा गई। प्रारम्भ में मुद्रा सकुचन किया गया और ट्रेजरी बिलों की भारी बिक्री की गई। परन्तु यह सब बेकार रहा। भारतीय निर्यात को बड़ा धक्का लगा। भारत से पूंजी का पलायन होने लगा। 1931 में जब ब्रिटन ने स्वर्णमान का त्याग कर दिया तो गवर्नर जनरल ने भी एक अध्यादेश जारी करके रुपए का स्वर्ण एवं स्टर्लिंग दोनों से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया। वास्तव में रुपए का सम्बन्ध पत्र मान पर आधारित स्टर्लिंग से स्थापित हो गया और उसका मविध्य भी उसी पर निर्भर हो गया। यही पत्र मुद्रा विनिमय मान 1931 से 1939 तक बना रहा। भारत स्टर्लिंग क्षेत्र का सदस्य बन गया और इसका सम्बन्ध सदस्य दशों से घनिष्ठ होता गया। इस अवधि में भारत से बहुत बड़ी मात्रा में स्वर्ण निर्यात होता रहा और रुपए के अवमूल्यन की माग की जाने लगी।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संकेत

(1) हिल्टन यंग कमीशन की मुख्य सिफारिशों की विवेचना कीजिए। इन सिफारिशों को सरकार ने कहा तक स्वीकार किया ?

(राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल, 1963, 1965)

(गोरखपुर 1959)

(विन्म भी० काम०, 1959)

अथवा

हिल्टन यग कमीशन के मुख्य सुझावों का विवेचन कीजिए । क्या 1926 के बाद भारतीय चलन प्रणाली उसी आधार पर विकसित हुई ?

(राजस्थान बी० काम०, 1961)

[संकेत—प्रथम भाग में हिल्टन यग कमीशन के मुख्य सुझावों का विस्तार-पूर्वक विवेचन कीजिए । दूसरे भाग में यह बताइये कि कैसे तो 1927 का एकट पारित कर सरकार ने कमीशन के सभी सुझावों को मान लिया परन्तु कमीशन द्वारा प्रस्तावित स्वर्ण पिंडमान के स्थान पर सरकार ने स्वर्ण पिंडमान तथा स्टर्लिंग विनिमय मान का मिलाजुला रूप अपनाया ।]

(2) किन कारणों के आधार पर हिल्टन यग कमीशन ने रुपये के 18 पेन्स के अनुपात की सिफारिश की ?

(नागपुर बी० ए०, 1959)

[संकेत—हिल्टन यग कमीशन द्वारा रुपये की 1 शि० 6 पे० की दर के पक्ष में दिए गये मुख्य तर्कों का विस्तारपूर्वक विवेचन कीजिए ।]

भारतीय चलन का इतिहास (2)

(1939 के बाद)
(History of Indian Currency)
(After 1939)

"Among the various war-time developments in the sphere of Indian currency, the enormous expansion of currency overshadows all others."

D. K. Malhotra.

द्वितीय महायुद्ध का सामान्य प्रभाव अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक ही रहा। किसानों की हालत में सुधार हुआ। उत्पादन, कीमत स्तर तथा विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। परन्तु मुद्रा और विनिमय सम्बन्धी कई समस्याएँ भी सामने आईं। इन समस्याओं में अत्यधिक मुद्रा-प्रसार, स्टॉलिंग सम्पत्तियों का अत्यधिक सग्रह तथा विनिमय नियन्त्रण प्रमुख हैं।

युद्ध के प्रारम्भिक काल में जनता का सरकार के स्थायित्व में विश्वास कम हो जाने के कारण नोटों की रूपरेखा में बदलने की मांग बहुत बढ गई। लोग डाक-खानों के सेविंग्स खाते से पैसे निकालने लगे और कॅश सर्टिफिकेट मुताने लगे। प्रथम नौ महीनों में 43 करोड़ से अधिक ६० के नोट सिक्कों में बदले गए। कुछ समय तक सिक्के प्रीमियम देकर नोटों के बदले प्राप्त किए जाते रहे। रेजगारियों का अत्यन्त प्रभाव दिखाई देने लगा क्योंकि लागू उन्हे जमा (Hoard) करने लगे। इस परिस्थिति का सामना करने के लिए सर्व प्रथम सरकार ने जून 1940 में एक विज्ञप्ति द्वारा रिजर्व बैंक को नोटों के बदले सिक्के देने के दायित्व से मुक्त कर दिया। सिक्कों की कमी को पूरा करने के लिए जुलाई 1940 में एक अध्यादेश द्वारा सरकार ने एक रूपये के नोट जारी करने का अधिकार प्राप्त किया। ये नोट असीमित विधिग्राह्य परन्तु अपरिवर्तनीय थे। इसी वर्ष कम चाँदी के सिक्के, अठन्नी, और चवन्नी जारी की गई। सरकार ने प्रामाणिक सिक्कों को चलन से बाहर कर देना उचित समझा और फलस्वरूप 31 मई 1941 के बाद विक्टोरिया रुपया और अठन्नी विधिग्राह्य नहीं रही। अगले दो वर्षों में क्रमशः एडवर्ड VII तथा किंग जार्ज

V तथा VI के रुपये और अठन्निमा भी विधिग्राह्य मुद्रा के श्रेणी में नहीं रही। फरवरी 1944 से रिजर्व बैंक ने दो रुपये के नये नोट भी जारी करना प्रारम्भ कर दिया।

मुद्रा प्रसार (Inflation)

युद्धकालीन मौद्रिक प्रभावों में मुद्रा प्रसार बहुत अधिक महत्व रखता है। सितम्बर 1939 में चलन में नोटों की मात्रा 182.13 करोड़ थी जो अक्टूबर 1945 में बढ़कर 1159.85 करोड़ हो गई। इन आंकड़ों की तुलना करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 1939 से 1945 के बीच चलन में नोटों की मात्रा में 53.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। इस अवधि में रुपये के सिक्के और रेजगारी की खपत को भी यदि मुद्रा की मात्रा में शामिल किया जाय तो कुल चलन की मात्रा और भी अधिक हो जाती है। यहाँ यह याद रखना आवश्यक है कि चलन में मुद्रा की मात्रा में तो बहुत अधिक वृद्धि हुई परन्तु मुद्रा के चलन वेग में कभी आई क्योंकि जमा (Hoarding) करने की इच्छा बढ गई थी।

इस प्रकार के मुद्रा प्रसार का परिणाम यह हुआ कि कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हुई। 1939 में जो निर्देशांक 100 था वह 1943 में 349 तक पहुँच गया। लोगों की वास्तविक आय में कमी हुई। वस्तुओं के उत्पादन में मुद्रा के परिमाण की अपेक्षा कम वृद्धि हुई। मुद्रा स्फीति का निश्चित आय वाले वर्ग पर अत्यन्त हानिकारक प्रभाव पड़ा। तत्कालीन स्फीति की भयानक स्थिति का संकेत श्री डी० के० मल्होत्रा के निम्नलिखित उद्धरण से मिलता है—

“Among the various war-time developments in the sphere of Indian currency, the enormous expansion of currency overshadows all others by its spectacular character, its wide sweep and its direct impact on the daily life of the common man. Its actual effects have been fairly serious, but of greater moment perhaps was the potential threat that it at one time held of disrupting the entire future of Indian economy”¹

मुद्रा स्फीति के कई कारण थे जिनमें सरकारी व्यय में वृद्धि तथा अनुकूल व्यापार शोष प्रमुख हैं। अकेले सुरक्षा पर 1939 से 1945 के बीच कुल 3450 करोड़ रुपये व्यय किये गये। इसके लिए करोड़ों और जनता से लिए गये ऋणों में वृद्धि की गई। सुरक्षा व्यय में ब्रिटिश सरकार की ओर से जो व्यय किया गया उसने स्फीति और गम्भीर हो गई क्योंकि वह नोट जारी करके ही किया गया।

¹ D. K. Malhotra . *History and Problems of Indian Currency*, pp. 122-3

अनुकूल व्यापार शेष के परिणाम स्वरूप जो स्टॉलिंग प्राप्त हुआ उसके आधार पर रिजर्व बैंक ने नोट जारी किए जिससे स्फीति और बढ़ी।

युद्ध काल में जो स्फीति प्रारम्भ हुई वह युद्ध के बाद भी निरन्तर बढ़ती ही चली गई। मुद्रा परिमाण जो मार्च 1945 में 1922 करोड़ रुपया था वह मार्च 1948 में 2316 करोड़ हो गया। युद्धोत्तर काल में भी सरकार का व्यय देश के विभाजन, हैदराबाद तथा काश्मीर की समस्याओं तथा विकास के कार्यों के कारण बढ़ता ही रहा। विनियोगों की मात्रा बढ़नी चली गई, उपभोग की वस्तुओं की कीमतें बढ़ती गई क्योंकि युद्ध के बाद में उपभोग बहुत बढ़ गया। उत्पादन क्षमता में उतनी वृद्धि नहीं हुई।

प्रारम्भ से ही भारत सरकार मुद्रा प्रसार को रोकने के लिए प्रयत्नशील थी। 1948 में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों से सरकार मुद्रा स्फीति रोकने के उपायों के बारे में परामर्श किया। उस समय स्फीति को रोकने के लिए जो सुझाव दिए गये उनमें सरकारी भाव को बढ़ाने तथा व्यय कम करने का प्रयत्न, नोट-निर्गमन में कमी, कीमतों पर नियन्त्रण, उत्पादन-विशेषकर कृषि उत्पादन, बढ़ाने के उपाय तथा अन्न के आयात प्रमुख हैं। सरकार ने इन सुझावों को कार्यरूप देन का भी प्रयत्न किया। उसी अवधि में जब भुगतान शेष प्रतिकूल होने लगा, और सुधार के सभी उपाय विफल रहे तो 1949 में रुपये का अवमूल्यन कर दिया गया। अवमूल्यन का अध्ययन अगले अध्याय में विस्तार से किया गया है। सरकार ने खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भी कम कर दी और कीमत नियन्त्रण को प्रभावशाली बनाने की चेष्टा की परन्तु कीमत स्तर बढ़ता ही चला गया। 1947 में निर्देशांक 362, 1950 में 391 तथा 1951, 458 हो गया। इस कीमत वृद्धि का एक प्रमुख कारण कोरिया का युद्ध था।

अप्रैल 1951 के बाद कीमतों में कमी होने लगी और दिसम्बर 1951 में निर्देशांक 433 तथा अप्रैल 1952 में 377 रह गया। इसका प्रमुख कारण कोरिया की शांति वार्ता थी। साथ ही रिजर्व बैंक ने बैंक दर बढ़ा कर साख निर्माण पर भी नियन्त्रण किया और ऋण देने की नीति भी कठोर कर दी। इस अवधि में उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। इन सब के सम्मिलित प्रभाव वश कीमतें गिरने लगी और मन्दी के लक्षण दिखने लगे। सरकार ने व्यापार की व्यवस्था को विश्र खलित होने से बचाने के लिए कई वस्तुओं से कन्ट्रोल हटा लिया तथा अन्य कदम उठाये। परन्तु यह स्थिति थोड़े समय तक ही रही। निर्देशांक पुन 1952 के अन्तिम चरण से बढ़ने लगे और 1954 में निर्देशांक 402 हो गया। फिर कीमतों में कुछ कमी हुई और निर्देशांक मई 1955 में 342 हो गया जिसका प्रमुख कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी।

1955 के बाद कीमतों में सामान्यतया बढ़ने की ही प्रवृत्ति रही है। इस वर्तमान स्फीति का प्रमुख कारण विकास की योजनाएँ और घाटे की अर्थव्यवस्था (Deficit & Financing) है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 415 करोड़, द्वितीय योजना काल में 948 करोड़ तथा तृतीय योजना काल में लगभग 1100 करोड़ का हीनार्थ प्रबंधन किया गया। उसके बाद योजना अवकाश काल में भी हीनार्थ प्रबंधन बन्द नहीं किया जा सका है। 1951 में चलन में मुद्रा और बैंक साल मिलकर 1824 करोड़ रुपया थी जो तृतीय योजना के अन्त में 5168 करोड़ हो गई। इस अवधि में मुद्रा की अपेक्षा साल मुद्रा में अधिक वृद्धि हुई। इन्हीं कारणों से कीमतें बढ़ती रही।

विनिमय नियन्त्रण (Exchange Control)

द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होते ही भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत विनिमय नियन्त्रण लागू किया गया था, जो आज तक विद्यमान है। इस सम्बन्ध में विदेशी विनिमय भाग के विनिमय नियन्त्रण अध्याय में विस्तार से उल्लेख किया जा चुका है।

स्टर्लिंग पावना (Sterling Balances)

युद्ध प्रारम्भ होने के पहले भारत ब्रिटेन का ऋणी था परन्तु युद्ध काल में परिस्थितियों के परिवर्तित हो जाने के कारण ब्रिटेन भारत का ऋणी बन गया। इसका कारण यह था कि भारत ने इंग्लैंड को युद्ध-व्यय सहन करने के लिए भारी मात्रा में माल आदि भेजा जिसका भुगतान उसी समय नहीं किया गया और वह इंग्लैंड के ऊपर भारत का ऋण बन गया। इस ऋण को स्टर्लिंग में व्यक्त किया जाता था, इसलिए भारत के लिए यह स्टर्लिंग पावना कहलाया। 1939 से 1946 के बीच भारत ने अपने पुराने ऋणों का भुगतान करने के बाद 1658 करोड़ रुपये के मूल्य का स्टर्लिंग पावना एकत्र कर लिया था। बैंक ऑफ इंग्लैंड में भारत सरकार के नाम यह रकम स्टर्लिंग प्रतिभूतियों तथा अन्य अल्पकालीन विनिमय पत्रों के रूप में जमा होती रही। इन प्रतिभूतियों का आशय यह था कि इनका भुगतान भारत को भविष्य में स्टर्लिंग के रूप में किया जायगा। रिजर्व बैंक इन स्टर्लिंग पावनों को प्राप्त कर इनके आधार पर नोट भी जारी करता था। स्टर्लिंग पावना अर्जित होने के कारणों में भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन की ओर से किया गया युद्ध-व्यय भारत को अन्य मित्र राष्ट्रों से निर्यात के बदले प्राप्त स्टर्लिंग पावना, डालर प्रतिभूतियों के बदले प्राप्त होने वाली स्टर्लिंग आदि प्रमुख हैं।

2. भारतवर्ष को उस समय विदेशी विनिमय के अभाव का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ यह याद रखना आवश्यक है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद हमारे देश में पुनर्निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का निश्चय किया गया था। औद्योगिक विकास के लिए विदेशों से पूँजी-सामग्री मगाने की आवश्यकता थी और अमेरिका से भारत का व्यापार शेष विपक्ष में होने के कारण भारत को डालर के अभाव का सामना करना पड़ रहा था।

3. अत्यधिक मात्रा में खाद्य सामग्री का आयात करना देश के विभाजन का स्पष्ट परिणाम था। शरणावियों को पुन. बसाने और खाद्य सहायता देने के कारण हीनार्थ प्रबन्ध एक स्थायी साधन बन गया था, जिससे सरकार अत्यधिक परेशान थी।

4. भारत ने द्वितीय महायुद्ध काल में स्टलिंग पावना की बहुत बड़ी मात्रा एकत्र कर ली थी।

5. भारत का निर्यात अधिकांशतया कच्चे माल के रूप में होता था जिसका उती पँमाने पर निर्यात करते रहने से औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता।

6. भारत के आयातों को कम करना भी सम्भव नहीं था क्योंकि आयातों में औद्योगिक कच्चा माल, मशीन तथा खाद्य पदार्थ मुख्य मदे थी और इन्हें कम करने का देश के आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता।

इन परिस्थितियों के प्रभाव वश भारत ने रुपए का अवमूल्यन किया। वास्तव में अवमूल्यन करना इसलिए अनिवार्य हो गया क्योंकि स्टलिंग का भी अवमूल्यन किया गया था। चूँकि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार स्टलिंग क्षेत्र से ही होता था इसलिए यदि रुपए का अवमूल्यन नहीं किया जाता तो भारत का निर्यात व्यापार बहुत कम हो जाता। परिस्थितियों से बाध्य होकर ही भारत ने अवमूल्यन किया यह बात तत्कालीन वित्त मन्त्री के निम्नलिखित वक्तव्य से स्पष्ट है—

“ to act on conviction, not necessarily born of logic, but so to speak, by the compulsion of events ”

भारत ने वास्तव में अपने हिनो की रक्षा तथा रुपया और स्टलिंग की दर बनाए रखने के उद्देश्य से अवमूल्यन किया था। इस बात का उल्लेख भारत सरकार की तत्कालीन घोषणा में किया गया था—

“Over and above the pure economic factors of relative competitive position, current expectation that India could not be able to postpone devaluation in the face of the act on taken by other coun-

tries would have acted as a powerful psychological barrier to any transaction at the old rate of exchange, and trade might have been brought to a stand still. There was thus no alternative for India but to follow the other sterling area countries, and devalue the rupee as a defensive measure”

प्रभाव (Effects) .

अवमूल्यन के पश्चात् अनेक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ने लगी। भारत और अमेरिका के बीच के व्यापार में शामिल वस्तुओं में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से व्याप्त थी। इस स्फीतिक समस्या को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कुछ वायवाही की और वनस्पती, तिलहन, लाल, तम्बाकू आदि पर निर्यात कर लगा कर इनके भावों को अधिक बढ़ने से रोकना। कपास तथा पटसन के निर्यात को उचित मूल्य पर उपलब्ध करने की व्यवस्था द्वारा इनके निर्यात को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करने तथा अवमूल्यन को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से तत्कालीन वित्त मंत्री डा० जॉन मथाई ने 5 अक्टूबर 1949 को एक अष्ट-सूची योजना प्रस्तुत की। इस योजना का सक्षिप्त प्रारूप निम्न प्रकार से था।

1. बचन की वृद्धि द्वारा विनियोगों को प्रोत्साहित किया जायगा तथा इसके लिए यदि आवश्यक हुआ तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का विस्तार किया जायगा।

2. खाद्य सामग्री तथा अन्य आवश्यक निर्मित वस्तुओं के खुदरा मूल्यों (retail prices) में 10 प्रतिशत कमी की जायगी।

3. अधिक विदेशी विनिमय प्राप्त करने के उद्देश्य से दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जायगा।

4. आवश्यक वस्तुओं के आयातों को नियमित एवं नियंत्रित करके विदेशी विनिमय के व्यय को कम करने का प्रयास किया जायगा।

5. सरकारी खर्च में मितव्ययिता ला कर चालू वर्ष में 40 करोड़ तथा अगले वर्ष में 80 करोड़ की बचत की जायगी।

6. साल सुविधाओं को नियमित एवं नियंत्रित करके तथा कानून द्वारा सट्टे के कारगर होने वाली कीमतों की वृद्धि को रोक जायगा।

7. मुद्रास्फीति लामो पर लगाए गए करो के सम्बन्ध में स्वेच्छा से समझौता करने की सुविधा दी जायगी।

8. जिन देशों की मुद्राओं का मूल्य रुपए की तुलना में बढ़ गया है उन देशों से औद्योगिक सामग्री का आयात करते समय अपनी नय शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जायगा कि उनका अधिक मूल्य न देना पड़े।

इन उपायों का प्रभाव अच्छा पडा तथा रुपए का अवमूल्यन भारत के लिए हितकर सिद्ध हुआ। अर्थ व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर रुपए के अवमूल्यन का निम्नलिखित ढंग से प्रभाव पडा—

1 भुगतान सतुलन में सुधार . जैसी आशा की गई थी रुपए के अवमूल्यन के फलस्वरूप भारत के निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि हुई। 1949 में कुल निर्यात 425.8 करोड़ रुपए का था जो 1950 में 540 करोड़ रुपए का हो गया। यही नहीं आयातों में भी कमी हुई क्योंकि 1949 में आयात 628.3 करोड़ था और 1950 में 500.5 करोड़। इस प्रकार 1949 में जो भुगतान कोष विपक्ष में था वही 1950 में पक्ष में हो गया। यह स्मरण रखना होगा कि इस सुधार का सम्पूर्ण श्रेय अवमूल्यन को ही नहीं दिया जा सकता। इसके लिए आयात-निर्यात पर नियंत्रण की नीति भी उत्तरदायी है।

2 औद्योगिक उत्पादन में ह्रास . अवमूल्यन के कारण उन देशों से आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई जिन्होंने अवमूल्यन नहीं किया था। उदाहरण के लिए पाकिस्तान ने अपने रुपए का अवमूल्यन नहीं किया था और परिणाम यह था कि भारत कपास और जूट का कच्चा माल निर्यातित रूप से नहीं पाता था। इसलिए इन उद्योगों को धक्का लगा। इसी प्रकार डाबर क्षेत्रों से मगाया जाने वाला माल महंगा पड़ता था और आर्थिक विकास एवं औद्योगिक उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता था।

3 कीमत स्तर में वृद्धि . युद्ध काल में ही स्फीति का प्रकोप फैल गया था। फिर अवमूल्यन द्वारा निर्यात को बड़ा कर और आयात को कम कर भुगतान सतुलन को पक्ष में किया जा सका परन्तु मांग बढ़ने और वस्तुओं की कमी तथा पाकिस्तान से, अवमूल्यन के कारण, व्यापारिक गतिरोध ने कीमतों को और बढ़ने में सहायता दी। जो अष्ट सूत्री योजना कीमतों को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से बनी थी उसका प्रभाव अल्पकालिक ही रहा।

4 विदेशी विनियोगों में वृद्धि . अवमूल्यन के फलस्वरूप डालर के सदम में प्रतिभूतिदा सस्ती हो जाने के कारण विदेशी विनियोग, विशेषकर अमरीकी विनियोग, बढ़न लगा। यहाँ भी यह स्मरण रखना आवश्यक है कि विदेशी विनियोग में वृद्धि का कारण कवल अवमूल्यन ही नहीं था। इसके अलावा अन्य राजनैतिक और आर्थिक कारण भी थे।

5 रहन सहन का स्तर . अवमूल्यन का भारतीयों के रहन-सहन पर बुरा प्रभाव पडा क्योंकि खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हुई, अन्य अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में भी, आयातों के कम होने से वृद्धि हुई तथा बपड़े की कीमतों में अभूत पूर्व वृद्धि

हुई। बीमारी में वृद्धि के साथ उनकी आय में वृद्धि न होने के कारण उनका जीवन दूमर हो गया।

6. स्टर्लिंग पावना की हानि जो स्टर्लिंग पावना डालर देशों से माल मगाने के लिये प्रयुक्त हुआ उस पर भारत को 30 5 प्रतिशत की हानि हुई।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि रुपए के अवमूल्यन से व्यापार श्रेय में सुधार हुआ परन्तु वह अस्थायी था एवं बहुत ही महंगा था। अवमूल्यन के लाभों की अपेक्षा हानियां शायद अधिक थीं। अवमूल्यन की नीति बहुत सफल नहीं रही।

रुपए के अवमूल्यन के सम्बन्ध में कुछ विचारकों का यह मत था कि जिस अर्थ में रुपए का अवमूल्यन किया गया वह आवश्यक नहीं था। यदि अवमूल्यन उनसे कुछ कम अर्थ में किया जाता तो अवमूल्यन अधिक और स्थाई रूप से सफल होता, क्योंकि भारत का व्यापार अमेरिका से बढ़ने लगा था और अवमूल्यन के कारण डालर महंगा पड़ने लगा। डालर अर्जित करने के लिए अवमूल्यन का कम अर्थ में होना ही उचित था। कुछ लोगों का यह भी मत था कि भारत को भी पाकिस्तान की भांति कुछ वर्षों तक अवमूल्यन नहीं करना चाहिए था। परन्तु भारत और पाकिस्तान को एक ही स्तर पर रखना उचित नहीं है क्योंकि दोनों की परिस्थितियां भिन्न थीं। कोरिया के युद्ध में स्थितिक प्रवृत्तियों को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया। ऐसे समय में कड़ लोगों ने रुपए के पुनर्मूल्यन की मांग करना प्रारम्भ कर दिया। पुनर्मूल्यन की मांग के समर्थक भूतपूर्व वित्तमन्त्री डा. जॉन मथाई भी थे। परन्तु सरकार ने इस मांग को देण हित में वाज्यीय न कह कर रद्द कर दिया। इस सम्बन्ध में तत्कालीन वित्तमन्त्री डा० सी० डी० देशमुख ने सदन में निम्नलिखित बयान दिया :

"We are not satisfied that a revaluation of our currency is likely to be, in the present circumstances, in the interests of the country."

1966 में रुपए का अवमूल्यन (Devaluation of Rupee in 1966)

राष्ट्रीय रुपए का 6 जून 1966 को दूसरी बार अवमूल्यन किया गया। इस बार रुपए का स्वर्ण मूल्य 0.186621 ग्राम से कम करके 0.118516 ग्राम और 21 सेंट से कम करके 13 33 सेंट कर दिया गया है। इस प्रकार रुपए का 36.5 प्रतिशत अवमूल्यन हो गया है। विदेशी मुद्राओं (डालर और पाँण्ड) का रुपए के सम्बन्ध में 57.5 प्रतिशत अधिमूल्यन हो गया है।

इस बार भी अवमूल्यन से उत्पन्न समस्याओं का सामना करने के लिए सरकार ने साथ ही साथ कुछ अन्य उपाय भी किए जिनमें निम्न उल्लेखनीय हैं—

1. निर्यात कर : अवमूल्यन के फलस्वरूप भारत का निर्यात विदेशों में सस्ता पड़ेगा और उन्हें (विदेशियों को) लाभ होगा। इसलिए ऐसी वस्तुओं पर, जिनकी मांग पर विशेष प्रभाव पड़ने की आशा नहीं थी, सरकार ने निर्यात कर लगा दिया। इन वस्तुओं में चाय, पटमन, कहवा, कपाम, अन्नक, चमड़ा, कच्चा ऊन आदि उल्लेखनीय हैं।

1. निर्यात सब्सिडी धोखना की समाप्ति अवमूल्यन से पूर्व सरकार ने निर्यात उद्योगों को विशेष छूटें दे रखी थी। अवमूल्यन के बाद इन्हें समाप्त कर दिया गया तथा निर्यात कर में छूट आदि देना बंद कर दिया गया।

3 आयात कर में छूट : सरकार ने अनेक वस्तुओं—जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक हैं, के आयात करों में छूट देने का भी आश्रय दिया। इसका उद्देश्य निर्यात के लिए वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना था जिसे विदेशी विनिमय की अधिक प्राप्ति हो सके। सरकार ने उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनावश्यक नियंत्रणों को भी हटाने का विचार व्यक्त किया।

कारण (Causes) —

1. कीमत स्तर में वृद्धि भारतीय रुपए के अवमूल्यन का प्रमुख कारण भारत में कीमत स्तर में निरंतर होने वाली वृद्धि थी। विगत दशक में कीमतों में 80 प्रतिशत वृद्धि हो गई थी और कीमतों को कम करने के सरकार के सभी प्रयत्न असफल हो गए थे। अन्य देशों में भी कीमत स्तर बढ़ा था परन्तु भारत की अपेक्षा कम। भारतीय माल महंगा होने का कारण विदेशों में प्रतियोगिता नहीं कर पाता था और हमारा निर्यात बहुत कम हो गया था।

2 प्रतिभूल भुगतान शेष : भारत का भुगतान शेष लम्बे अर्थों से विपक्ष में था। 1951 में भारत का व्यापार शेष 49 करोड़ रुपये से विपक्ष में था जो 1966 में 604 करोड़ रुपए हो गया था। भुगतान शेष की स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक था कि निर्यातों को बढ़ाया जाय तथा आयातों को कम किया जाय। इस कार्य के लिए अवमूल्यन को उपयुक्त उपाय समझा गया।

3 निर्यात सम्बन्धित नीति की असफलता भारत सरकार ने निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यातों को आर्थिक सहायता, निर्यातों को कच्चा माल आयात करने में सुविधा, निर्यात करों में छूट आदि के द्वारा प्रयत्न किया परन्तु इसका परिणाम निराशा पूर्ण ही रहा। इसलिए निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार के पास अवमूल्यन के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।

4. विदेशी सहायता में कमी भारत अपना अधिकांश विकास कार्य विदेशी सहायता के आधार पर करता था। परन्तु भारतीय अर्थव्यवस्था की सतत अन्त

व्यस्तता एवं दुर्बलता को देख कर विदेशी पूँजी भी भारत में सक्रिय होने लगी। पाकिस्तान और भारत के युद्ध के बाद अमेरिकी सहायता और भी कम हो गई। विश्व बैंक, मुद्रा कोष एवं अमेरिका आदि ने भारतीय रुपये के प्रवृत्तयन का सुझाव दिया और आश्वासन दिया कि अवमूल्यन से पैदा होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए वे उदार सहायता देंगे। इसलिए भारत को रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा।

आशाएँ (Expectations)

रुपए का अवमूल्यन इस बार भी एक आकस्मिक घटना थी क्योंकि उसके पूर्व बार-बार सरकार की ओर से अवमूल्यन न करने की घोषणा की जा चुकी थी। वित्त मंत्री ने अवमूल्यन की घोषणा करते हुए बताया कि आर्थिक अवस्था अवमूल्यन की मांग करती है और अवमूल्यन से निम्नलिखित लाभ होने की आशा है --

1. निर्यात में वृद्धि - अवमूल्यन से प्रमुख आशा निर्यात वृद्धि की थी क्योंकि इससे भारतीय वस्तुएँ विदेशों में सस्ती पड़ेंगी और विदेशी बाजार में प्रतियोगिता कर सकेगी। यहाँ निर्यात वृद्धि का तात्पर्य था कि निर्यातों में 36.5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होगी क्योंकि उससे कम वृद्धि होने पर वास्तविक निर्यात पहले से भी कम रहेगा। वास्तविक वृद्धि सभी हो सकती है जब निर्यातों में इन्से कहीं अधिक वृद्धि हो। सरकार की यह आशा थी कि वास्तविक निर्यात वृद्धि अवमूल्यन में सम्भव है।

2. पूँजी विनियोग में वृद्धि : आयातों के महंगा हो जाने के कारण उनका आयात घटता जायेगा और वह क्षेत्र भारतीय विनियोजकों के लिये आकर्षक हो जायेगा। भारतीय विनियोजक उन क्षेत्रों में लाभपूर्ण विनियोग कर सकेंगे। विदेशी पूँजी को भी भारत में विनियोग करने में लाभ होगा। इस प्रकार आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी।

3. आयात प्रस्थापन - आयात महंगा होने के कारण आयातित वस्तुओं की स्थानापन्न (substitute) वस्तुओं का आविष्कार किया जायेगा और उनका उत्पादन किया जायेगा। इससे औद्योगिक और तकनीकी विकास के साथ-साथ उत्पादन आय एवं रोजगार में वृद्धि होगी। साथ ही विदेशी विनिमय की भी बचत होगी।

4. भुगतान सतुलन में सुधार - अवमूल्यन के कारण कई ऐसी आर्थिक गति-विधियाँ जन्म लेंगी जिनके फलस्वरूप भुगतान सतुलन में सुधार होगा। प्रथम, अवमूल्यन के कारण भारत में आने वाले विदेशी भ्रमणार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी और भारत की विदेशी मुद्रा की आय बढ़ेगी। द्वितीय, भारत के जो नागरिक विदेशों

मे खाता रहते हैं वे अधिक रुपया पाने के लिए विदेशी मुद्रा भारत लायेंगे। तृतीय, भारत से विश्व जाने वालों की संख्या कम होगी जिससे विदेशी विनिमय बचेगा। चतुर्थ, भारत में अधिक विदेशी पूंजी आयेगी। पंचम, विदेशी विनियोजक भारत से अर्जित लाभ को पुनः भारत में ही लगाने में रुचि लेंगे।

5. सरकार की आय में वृद्धि : अवमूल्यन से सरकार की आय में भी वृद्धि होने की आशा की गई थी (1) अवमूल्यन के साथ निर्यात सब्सिडी योजना समाप्त हो जाने से सरकार को बचत होगी (2) जिन वस्तुओं पर निर्यात कर लगाया गया है उनसे आय प्राप्त होगी (3) विदेशी सहायता का मूल्य रुपए में बढ़ जायगा।

6 विदेशी सहायता में वृद्धि : अर्थ व्यवस्था के स्थिर हो जाने के कारण एव पाक-भारत युद्ध के कारण जा विदेशी सहायता कम हो गई थी वह पुनः बढ़ जान की आशा थी। बिना सहायता के चौथी योजना लागू होना सम्भव नहीं था।

7 अवाछनीय क्रियाओं का अन्त : अवमूल्यन से यह आशा की गई थी कि विदेशी व्यापार की अनेक बुराइयाँ-निर्यातों को बीजक में कम बताना आयातों को बीजक में अधिक दिखाना, आयात निर्यात लाइसेंसों की चोर बाजारी एव दुष्प्रयोग तथा तस्करी आदि को समाप्त किया जा सकेगा। इसका कारण यह है कि इन सब अवाछनीय क्रियाओं से जो लाभ प्राप्त होता था वह समाप्त हो जायगा और लोगों को इन क्रियाओं में किसी प्रकार का आकर्षण शेष नहीं रह जायगा।

उपरोक्त तर्कों के आधार पर सरकार ने अवमूल्यन के औचित्य की व्याख्या की। वित्त मंत्री के अवमूल्यन की घोषणा का अन्तिम अंश इस सम्बन्ध में उद्धृत करने योग्य है—

“To sum up, devaluation would provide a better corrective to the price rise and distortion of the past than the remedial measures we have pursued so far. Even more important, it will facilitate a better allocation of our resources and strengthen our foreign exchange position on an enduring basis. With renewed determination and discipline on the part of all of us to hold inflationary pressures firmly in check, it would be a major ally in our march towards self reliance.”

अवमूल्यन के विरुद्ध दिए गए तर्क

अवमूल्यन से जिन लाभों की आकांक्षा की गई थी उनकी वास्तविकता एव व्यावहारिकता के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। सत्तेप में यहाँ पर अवमूल्यन के विरुद्ध दिये गये तर्कों का उल्लेख किया जायगा।

1. आयात निर्यात : अवमूल्यन का एक प्रमुख उद्देश्य निर्यातों को बढ़ाना तथा आयातों को कम कराना होता है। भारत में जब अवमूल्यन की नीति अपनाई

गई उस समय आयातों पर अनेक नियन्त्रण पहले से ही लगे हुए थे। सरकार ने अत्रमूल्यन द्वारा आयात कम करने की निध्या घोषणा की थी क्योंकि अत्रमूल्यन के साथ ही सरकार ने उदार आयात की नीति की घोषणा भी की थी जिससे उद्योगों को आवश्यक कच्चा माल प्राप्त हो सके और वे अपनी पूर्ण क्षमता (Full capacity) के अनुसार उत्पादन कर सकें।

जहाँ तक निर्यात-वृद्धि का प्रश्न है, अधिक निर्यात केवल कीमतों के कम हो जाने मात्र से सम्भव नहीं है। निर्यातों की वृद्धि के लिये पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त माल का उत्पादन (Exportable surplus) होना आवश्यक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो निर्यातों को बढ़ाने के लिए आवश्यक है वह वस्तुओं का गुण (Quality) है। इसलिए वस्तुओं के गुण में सुधार करना आवश्यक है। यदि अत्रमूल्यन के कारण कीमत कम हो जाय और निर्यात में कीमतों में कमी के अनुपात से अधिक वृद्धि न हो तो निर्यातों की प्राप्ति पूर्ववत् या उससे कम होगी। इसलिये निर्यातों को अधिक बढ़ाने के लिए अत्रमूल्यन नहीं, उत्पादन-लागत (Cost of Production) कम करने की आवश्यकता है। जब तक निर्यात-योग्य अतिरिक्त (Exportable surplus) का उत्पादन कम लागत पर नहीं किया जाना, तब तक निर्यातों की वृद्धि की आशा करना केवल मृगतृष्णा है।

2. कीमतों में वृद्धि : अत्रमूल्यन के पक्ष में यह भी तर्क दिया गया था कि भारत में पिछले दशक में कीमतों में भारी वृद्धि हुई जबकि अन्य प्रमुख देशों में उतनी वृद्धि नहीं हुई है। भारत में आन्तरिक कीमत स्तर बढ़ने से रुपये का बाह्य मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और निर्यातों को घबका लगा है। कीमन नियन्त्रण के सभी प्रयत्न विफल रहे हैं इसलिये अत्रमूल्यन करना आवश्यक हो गया है। परन्तु भारत ही एक ऐसा देश नहीं था जहाँ कीमतें बढ़ी थीं। सभी विकासशील देशों की कीमतों में वृद्धि हुई थी और कई देशों में तो भारत से भी अधिक वृद्धि हुई थी। भारत की कीमतों की तुलना विकसित देशों से नहीं करनी चाहिये।

3. विदेशी पूँजी - अत्रमूल्यन के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि इससे अधिक विदेशी पूँजी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यह सत्य है कि विदेशी विनियोक्तों को भारत में रुपये के रूप में अधिक पूँजी एकत्र होगी। परन्तु यह केवल एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। विनियोक्त अल्पकालीन प्रभावों को अधिक ध्यान में रखेगा। पूँजी पर मिलने वाला लाभार्थ विनियोक्तों की मुद्रा में अत्रमूल्यन के कारण कम हो जाता है और विनियोजित पूँजी यदि वापस ली जाय तो उस पर भी हानि होती है। यही विचार अत्रमूल्यन के समय 'कानफेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इन्डस्ट्री' द्वारा निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया गया था—

“In the short run devaluation has damaging side effects for Britain, for it devalues the sterling worth of British industry's substantial investment stake in India and all permitted profits.”¹

जहा तक विदेशों से प्राप्त ऋणों का प्रश्न है, अवमूल्यन के कारण उनके व्याज और मूलधन के भुगतान का भार बढ़ जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि पुराने ऋणों के लिए यदि अधिक रुपये के भुगतान करने पड़ते हैं तो दूसरी ओर नए ऋणों से अधिक रुपए की प्राप्ति भी होती है। इसलिये एक की हानि दूसरे के लाभ से पूरी हो जाती है। परन्तु वास्तव में भारत के पुराने ऋणों की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण हानि की मात्रा बहुत अधिक होगी।

4 आयातों की मूल्य-वृद्धि : भारत को अपने विकास क्रम को चालू रखना आवश्यक है तथा इसके लिए लम्बे समय तक आयात करने होंगे और उनकी मात्रा बढ़ती जायगी। ऐसी परिस्थिति में अवमूल्यन करने से आयातों का मूल्य बहुत बढ़ जायगा और भारत का आयात बिल बहुत बड़ा हो जाने की सम्भावना है।

5 अवमूल्यन विकसित अर्थव्यवस्था के लिए ही उपयुक्त : अवमूल्यन विकसित अर्थव्यवस्थाओं का अस्त्र है। विकासशील देशों की समस्या का समाधान अवमूल्यन के आधार पर नहीं किया जा सकता। विकासशील देशों की समस्या का समाधान उत्पादन एवं उत्पादकता की वृद्धि, लागत में कमी और अपने अप्रयुक्त साधनों के अनुकूलतम प्रयोग में निहित है।

अवमूल्यन के प्रभाव (Effects of Devaluation)

वास्तव में अवमूल्यन से लाभान्वित होने के लिये भारत सरकार को दो दिशाओं में प्रयत्न करना आवश्यक था—(1) कीमत स्तर पर नियन्त्रण रखना तथा (2) निर्यात योग्य आधिक्य प्राप्त करना। यह चिन्ता का विषय है कि सरकार इन दोनों ही दिशाओं में असफल रही है।

1. आयात निर्यात : अवमूल्यन के पश्चात् तुरन्त ही कीमत स्तर में तेजी से वृद्धि प्रारम्भ हो गई। निरन्तर कीमतों के बढ़ते रहने के कारण महंगाई भत्ता तथा वेतन वृद्धि की मांग भारतीय आर्थिक जीवन की एक अंग बन गई है। इनमें (महंगाई तथा वेतन आदि) वृद्धि होने से निर्यात वस्तुओं की लागत बढ़ने लगी और इनका निर्यात अवमूल्यन के बाद बढ़ने के स्थान पर कम हो गया। अवमूल्यन से यह आशा की गई थी कि भुगतान सतुलन में स्थायी रूप से सुधार किया जा सकेगा तथा निर्यात बढ़ने से विकास की गति तीव्र होगी और देश आत्म निर्भरता का लक्ष्य

¹ Quoted by Prof. B.N. Ganguli . *Devaluation of the Rupee*, p. 87

शीघ्रता से प्राप्त कर लेगा। परन्तु अवमूल्यन के बाद के आयात निर्यात के आकड़े यह स्पष्ट कर देते हैं कि भारत को विदेशी व्यापार में लाभ के स्थान पर हानि हुई है क्योंकि आयातों के मूल्य में वृद्धि तथा निर्यात में कमी हुई है। जून 1966 से मई 1967 की अवधि में भारत के निर्यात व्यापार में जून 1965 से मई 1966 की अवधि के निर्यात की अपेक्षा 206 मि० डालर की कमी हुई। इस गति से निर्यात में कमी होना भारत के विदेशी व्यापार के इतिहास में अभूतपूर्व घटना थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि अवमूल्यन के बाद निर्यात बिल बढ़ाने के लिये निर्यात की मात्रा में 57.5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की आवश्यकता थी जो भारत के लिए प्रायः अगम्य था। भारत का निर्यात 1967-1968 में काफी बढ़ा परन्तु साथ ही आयात में उसने भी अधिक वृद्धि हुई जिससे भुगतान शेष का असंतुलन और अधिक बढ़ गया। (भारत का निर्यात 1966-67 में 967 22 करोड़ रु० से बढ़कर 1967-68 में 1197 04 करोड़ और आयात 1966-67 में 1607 89 करोड़, स बढ़कर 1967-68 में 1950.47 करोड़ हो गया) अप्रैल 1968 से नवम्बर 1968 तक के निर्यात में 1967 के अप्रैल से नवम्बर तक के निर्यात की अपेक्षा वृद्धि हुई है। परन्तु निर्यातों की वृद्धि को अवमूल्यन का ही परिणाम नहीं कहा जा सकता। भारत ने निर्यात बढ़ाने के बहुमुखी प्रयत्न किये हैं।

2 निर्यात संबर्द्धन अवमूल्यन के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया गया था कि अवमूल्यन के पश्चात् निर्यात संबर्द्धन पर व्यय करने की आवश्यकता नहीं होगी और इस प्रकार सरकारी आय में एक प्रकार से वृद्धि होगी परन्तु अवमूल्यन के बाद धीरे-धीरे निर्यात संबर्द्धन योजनाएँ पुनः लागू की जाने लगीं। अगस्त 1966 में ही निर्यात सम्बर्द्धन योजना अपने सुधरे हुए रूप में पुनः सामने आ गई। इसलिये यह आशा कि बिना निर्यात सम्बर्द्धन पर संच किए ही निर्यातों को बढ़ाया जा सकेगा, पूरी नहीं हो सकी है।

3 मूल्यों में वृद्धि अवमूल्यन के लाभों को प्राप्त करने के लिए कीमत स्तर पर नियन्त्रण रखना आवश्यक था परन्तु अवमूल्यन के बाद कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होती रही है और मजदूरी-कीमत की वृद्धि का चक्र चलता रहा है। यही स्थिति यदि बनी रही तो पुनः अवमूल्यन का सहारा लेना पड़ सकता है।

4 योजना व्यय में वृद्धि तथा बजट घाटा आयातों के मूल्यों में 57.5 प्रतिशत वृद्धि हो जाने के कारण भारतीय योजनाओं के व्यय में वृद्धि हो गई। यही नहीं सरकार का वार्षिक व्यय भी बढ़ गया है।

5 विदेशी पुस्तकों आदि की कठिनाई अवमूल्यन के कारण विदेशी पुस्तकों भारतीयों के लिए महंगी पड़ने लगी क्योंकि उनके लिए 57.5 प्रतिशत अधिक मूल्य देना पड़ता है।

6 विदेशी ऋण-भार में वृद्धि • जैसा पहले कहा जा चुका है कि विदेशी ऋणों का भार अवमूल्यन के कारण बढ गया है क्योंकि व्याज और मूलधन के रूप में पहले से अब अधिक रकम देनी पड रही है ।

भारत को दूसरे अवमूल्यन से बचाने के लिए प्रयत्न करना ही अब व्यावहारिक है क्योंकि जून 1966 का अवमूल्यन अब भूतकाल की बात है । इसके लिए अर्थशास्त्री उसी समय से हीनार्थ प्रवन्धन को बन्द करने का सुझाव दे रहे हैं परन्तु सरकारी घोषणाओं के बावजूद भी हानाथ्र प्रवन्धन बन्द नहीं हो सका है । इसी प्रकार कीमत वृद्धि को रोकने के लिए सरकारी व्यय में कमी करना आवश्यक है जो दुर्भाग्य से प्रतिवर्ष बढता चला जा रहा है । मूल्यो और साख व्यवस्था पर, पूर्ण नियंत्रण के अभाव में भारतीय विदेशी व्यापार की समस्या का समाधान सम्भव नहीं है । दूसरी तरफ उत्पादन लागत को कम करने एवं उत्पादन तथा उत्पादकता को बढाने की आवश्यकता है । भारत को निर्यात के लिए नये क्षेत्र खोजना भी आवश्यक है । केवल परम्परागत निर्यातों के आधार पर आयात निर्यात की खाई नहीं मरी जा सकती । नई वस्तुओं के लिए विदेशी बाजार बनाना आवश्यक है । आयातों की प्राथमिकता बड़ी सूक्ष्म ढङ्ग के साथ निर्धारित की जानी चाहिये और जहाँ तक सम्भव हो आयातों का स्थापन्न किया जाना चाहिये ।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संकेत

1 क्या मुद्रा अवमूल्यन किसी देश के भुगतान असतुलन को दूर करने का सही उपाय है ? अपने उत्तर को भारतीय मुद्रा के 1966 के अवमूल्यन के सन्दर्भ में समझाइये ।

(राजस्थान टी०डी०सी फाइनल, 1969)

[संकेत—विस्तारपूर्वक समझाइये कि मुद्रा अवमूल्यन से किस प्रकार निर्यात प्रोत्साहित और आयात हतोत्साहित होते हैं । साथ ही अन्य दृष्टियों से विदेशी विनिमय की बचत होती है । परिणामतः भुगतान असतुलन ठीक हो जाता है । भारतीय रुपये के 1966 के अवमूल्यन से उदाहरण तथा आंकड़े दत्त हुए इसे सिद्ध कीजिये । इस मत के विरुद्ध भी तर्क दीजिये ।]

2. मुद्रा अवमूल्यन के कारणों का विश्लेषण कीजिये और उसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर हुए प्रभावों का परीक्षण कीजिये ।

(राजस्थान टी०डी०सी० फाइनल, 1968)

[संकेत—प्रथम भाग में मुद्रा अवमूल्यन का संक्षेप में अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके उद्देश्यों का विस्तार विवचन कीजिये । दूसरे भाग में 1966 के भारतीय

रुपये के अवमूल्यन के भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर हुए प्रभावों का आंकड़े देते हुए वर्णन कीजिये ।]

3. सितम्बर 1949 में किन कारणों से भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ ? इसका क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा, समझाइये ।

(राजस्थान टी०डी०सी० फाइनल, 1963)

[संकेत—प्रथम भाग में द्वितीय महायुद्ध के फलस्वरूप मुद्रा स्फीति, विदेशी विनिमय का अभाव, खाद्यान्नों के आयात इत्यादि कारणों का विवेचन कीजिये जिससे भारत सरकार को 1949 में रुपये के अवमूल्यन के लिए बाध्य होना पड़ा । दूसरे भाग में आंकड़ों के प्रमाण देते हुए अवमूल्यन के अर्थ-व्यवस्था पर पड़े प्रभावों का वर्णन कीजिये ।]

4. भारतीय रुपये के सन् 1966 के अवमूल्यन के कारणों की पूर्ण व्याख्या कीजिये । इसके प्रमुख अपेक्षित लाभ क्या थे ?

(आगरा बी०काम०, 1967)

[संकेत—प्रथम भाग में 1966 के अवमूल्यन के मुख्य कारणों का विवेचन कीजिये । दूसरे भाग में इससे जिन लाभों के प्राप्ति की आशा की गई थी उनका वर्णन कीजिये और यह भी बताइये कि वे कहा तक प्राप्त हुए ।]

भाग ६

Part Six

"The low proportion of bank deposits to national income and of demand deposits to money supply in India are primary indicators of the fact that the message of commercial banking is yet to reach a majority of people. Cost inflation and profit squeeze have again impaired the manoeuvrability of commercial banks in reaching out to new areas and new people and serving them through novel ways. The measures of social control over banks will be devoid of any meaning and purpose unless the banking reform is carried out to its logical conclusion by finding out a remedial action for the chronic problems besetting the progress of the nation's banking industry."

भारतीय बैंक-व्यवस्था
(Indian Banking System)

भारतीय मुद्रा बाजार (The Indian Money Market)

“A fully coordinated system of credit possessing different types of complementary institutions can never exist without its indispensable concomitant, a well developed and reasonably planned money market. The development of one leads to the other and vice versa. The money market is the groundwork of the country's national finance whose main flexibility depends on a fine division of labour and capacity for adjustment to changing conditions of society”

B R Rao

साख वाणिज्य का जीवन रक्त है। एक समन्वित साख बाजार के अभाव में समाज की वृद्धि तथा साहस प्रवृत्ति का अपव्यय होता है। एक संगठित साख बाजार उधार देय कोषों के विनियोजन को सुरक्षा प्रदान करता है तथा जटिल उत्पादन के लिए धन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करता है। जी० एन० हॉलम (G N Halm) के शब्दों में 'साख बाजार वह बाजार है जहाँ दावों (claims) का ध्वपाप होता है। उधार देय कोषों की पूर्ति का प्रतिनिधित्व दावों के क्रय द्वारा होता है तथा उधार देय कोषों की मांग दावों के विक्रय का स्वरूप ग्रहण करती है।¹ इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि साख बाजार का मुख्य उद्देश्य उधार देय कोषों की मांग तथा पूर्ति का सम्बन्ध स्थापित करना है। साख बाजार को दो भागों में बाटा जा सकता है—(1) मुद्रा बाजार तथा (2) पूंजी बाजार।

मुद्रा बाजार (Money Market),

एक सुविकसित मुद्रा बाजार प्रभावी मौद्रिक नीति का आधार है। प्रो० वी० रामचन्द्र राव के शब्दों में “मुद्रा बाजार” वह स्थान है जहाँ समाज की चल

¹ A credit market is “a market in which claims are traded, the supply of loanable funds is represented by purchase of claims while the demand for loanable funds takes the form of sales of claims”

पूँजी, उस समय तक के लिए जब उसकी आवश्यकता हो, रोजगार पाने के लिए आकर्षित होती है।¹ दूसरे शब्दों में “मुद्रा बाजार वह केन्द्र है जहाँ मुख्यतः अल्पकालीन प्रकृति की मौद्रिक परिसम्पत्तियों में व्यवहार होता है। यह ऋणी लोगों की अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा ऋण दाताओं को तरल या नकद कोष उपलब्ध करता है। यह वह स्थान है जहाँ अल्पकालीन विनियोग कोष वित्तीय तथा अन्य सस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा ऋणी व्यक्तियों तथा सस्थाओं या स्वयं सरकार को दिए जाते हैं।² सरल शब्दों में मुद्रा बाजार वह स्थान है जहाँ अल्पकालीन मुद्रा का क्रय विनय होना है।

नेडलर, हेल्डर तथा शिपमेन के अनुसार मुद्रा बाजार “वह केन्द्र है जहाँ अल्पकालीन पूँजी की माग तथा पूर्ति का समायोजन होता है। मुद्रा बाजार का शब्दानुसार अर्थ किसी वास्तविक स्वान का सकेत नहीं करता है। यह शब्द उस सम्पूर्ण व्यवस्था का सूचक है जिसके द्वारा अल्पकालीन कोषों का विनियोजन तथा उन्हें उधार दिया जाता है तथा जिसके माध्यम से देश के अधिकतर वित्तीय सौदे तय किये जाते हैं। मुद्रा बाजार एक समाशोधन केन्द्र है जहाँ राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सौदे होते हैं, यह वह स्थान है जहाँ राष्ट्र तथा अन्य राष्ट्रों की उधार देय पूँजी रखी जाती है तथा अल्पकालीन कोष शीघ्रतापूर्वक उधार लिए तथा दिए जाते हैं।

“यद्यपि सामान्यतः मुद्रा बाजार केवल अल्पकालीन कोषों के उधार लेन देन से सम्बन्धित होता है परन्तु इसका पूँजी तथा वस्तु बाजारों जैसे अन्य बाजारों से भी घनिष्ठ सम्बन्ध होता है जो इस पर वित्तीय सुविधा के लिए आश्रित होते हैं। विस्तृत अर्थ में मुद्रा बाजार शब्द में सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं की वित्त व्यवस्था सम्बन्धी सुविधाओं का समावेश होता है। कहीं भी कोई महत्वपूर्ण सौदा जिसमें अल्पकालीन या दीर्घकालीन उधार देय कोषों का हस्तान्तरण होता है,

¹ “Money market is the place to which the floating capital of the community gravitates to find employment till the time when it is needed” — B.R. Rau, *Present Day Banking in India*, p. 2

² Money market is “the centre for dealings mainly of short term character in monetary assets, it meets the short term requirements of borrowers and provides liquidity or cash to the lenders. It is the place where the short term surplus investible funds at the disposal of financial and other institutions and individuals are bid by borrowers again comprising institutions and individuals and also the government itself”

राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार के एक भाग में ही सम्पन्न होता है। सङ्चित धन में, जिसमें इसका सामान्यतः प्रयोग होता है, मुद्रा बाजार में लगभग प्रमापित साख से सम्बन्धित व्यवहार जैसे अल्पकालीन ऋण (call loan) तथा वाणिज्य पत्र, स्वीकृतिया तथा कोपागार विपत्र जैसे साख पत्र जिनमें ऋणदाता तथा ऋणी के व्यक्तिगत सम्बन्धों का बहुत कम महत्व होता है, सम्मिलित होते हैं। सामान्य समयों में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का मुद्रा बाजार सप्ताह के सभी देशों से अल्पकालीन कोष आकर्षित करता है तथा उसका सप्ताह के विभिन्न देशों के उधार लेने वालों में पुनर्वितरण करता है। इन कोषों का तरल विनियोजन अमेरिका में स्वीकृति बाजार, वाणिज्यिक पत्र बाजार, कोपागार-विपत्र बाजार तथा अल्पकालीन मुद्रा बाजार जैसे संगठित बाजारों द्वारा होता है।¹

¹ "A money market may be defined as centre where the demand for and supply of short term funds meet. In the literal sense there is actually no such place as a money market. Rather, the term connotes the entire machinery for the investment and borrowing of short term funds and the medium through which a large part of the financial transactions of a country are handled. A money market, such as New York market, is a clearing centre for numerous financial commercial transactions, both national and international, a place where the loanable funds of the nation and other nations are held and where short term funds can be quickly borrowed and lent."

While the money market normally is concerned only with borrowing and lending of short term funds, it is closely related to a number of other markets, such as the capital and commodity markets which rely on it for financial accommodation. Broadly concerned, the term includes all the facilities employed in financing economic activity of all types. Any major transaction, wherever consummated, involving the transfer of loanable funds, long term as well as short term, may be said to have taken place in a part of a nation wide or international money market. In the narrower sense in which the term is generally used, however, a money market embraces only dealings in more or less standardised type of credit, for example call loans and credit instruments (such as commercial paper, acceptances and treasury bills) in which personal relations between lender and borrower are of negligible importance. During normal times money market of international scope attracts short term funds from all over the world and redistributes them among borrowers in many countries. These funds require liquid investments

Continued

उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर यही कहा जा सकता है कि मुद्रा बाजार वह बाजार है जहाँ अल्पकालीन पूँजी का क्रय विक्रय किया जाता है। मुद्रा के नेता ऋणी, व्यवसायी तथा उद्योगपति होते हैं जिन्हें उत्पादक कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर मुद्रा के विक्रेता जैसे जीवन बीमा निगम, औद्योगिक निगम व्यापारिक बैंक तथा ऋणदाता होते हैं जो अपने कोषों का विभिन्न क्षेत्रों में विनियोजन करते हैं। जिस प्रकार वस्तु बाजार में वस्तु की माग तथा पूर्ति द्वारा वस्तु का मूल्य निश्चित होता है उसी प्रकार मुद्रा बाजार में मुद्रा की माग तथा पूर्ति की स्थितियों द्वारा मुद्रा का मूल्य (अर्थात् ब्याज-दर) निर्धारित होता है।

विस्तृत अर्थों में मुद्रा बाजार में पूँजी बाजार उसके एक अंग के रूप में सम्मिलित रहता है परन्तु सङ्कुचित अर्थ में मुद्रा बाजार में पूँजी बाजार को सम्मिलित नहीं किया जाता। मुद्रा बाजार में अल्पकाल के लिए ऋण लिए तथा दिये जाते हैं परन्तु पूँजी बाजार में दीर्घकालीन पूँजी का क्रय-विक्रय होता है। मुद्रा बाजार तथा पूँजी बाजार के इस भेद का यह अर्थ नहीं है कि दोनों बाजार एक दूसरे से पूर्णतः अलग हैं बल्कि वे एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित हैं तथा एक की प्रवृत्ति में दूसरे को प्रभावित करती है। एक बाजार में कार्य करने वाले पक्ष दूसरे बाजार में स्वतन्त्रतापूर्वक आते-जाते हैं।

मुद्रा बाजार का महत्व (Importance of Money Market)

किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा बाजार का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग का विकास एवं सुसंगठित मुद्रा बाजार के ऊपर निर्भर है। इंग्लैंड, अमेरिका तथा अन्य पाश्चात्य देशों की औद्योगिक प्रगति बहुत कुछ वहाँ के सुसंगठित मुद्रा तथा पूँजी बाजारों के कारण हुई है। आधुनिक औद्योगिक संगठन बहुत जटिल है और उसके लिए विकसित मुद्रा बाजारों की बड़ी आवश्यकता है। मुद्रा बाजार ऐसे लोगों से जिनके पास धन है परन्तु व्यापारिक कार्यों में नहीं प्रयोग कर सकते, ऐसे लोगों के पास धन पहुँचाने में सहायता करते हैं जिनके पास व्यापारिक योग्यता तथा कुशलता है परन्तु धन का अभाव है। इस

which in the United States are provided by organised market such as the acceptance market the commercial paper market, the treasury bill market and the call money market”

—Nadler, Heller and Shipman . *The Money Market and its Institutions*, 1955, p.p. 3 4.

प्रकार ऋणी तथा ऋणदाता के बीच मुद्रा बाजार के माध्यम से ही सम्बन्ध स्थापित होता है ।

मुद्रा बाजार केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के सफल कार्यान्वयन में सहायता करता है । संगठित मुद्रा बाजार के विभिन्न अंगों में सहयोग तथा सामंजस्य न हो तो मौद्रिक नीति की सफलता की आशा नहीं की जा सकती । मुद्रा बाजार में व्यापारिक बैंक अपने अत्यधिक कोषों का अल्पावधि के लिए विनियोजन कर लाभ कमाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर सस्ती ब्याज की दर पर शीघ्र ऋण प्राप्त करते हैं । मुद्रा बाजार के माध्यम से व्यापारिक बैंक अपनी परिसम्पत्तियों में पर्याप्त आवश्यक तरलता रखने में सफल हो जाता है और जमाकर्ताओं की मांग पर सुगमता तथा शीघ्रता से भुगतान कर देता है । बर्गस (Burgess) के अनुसार 'देश के लिए मुद्रा बाजार का महत्व केवल उसके आकार में नहीं है, वह वास्तव में उसकी तरलता तथा कुछ घटो की सूचना पर देश के किसी भाग को नकदी पहुँचाने की योग्यता में है । व्यक्ति के लिए जो महत्व बैंक-खाते का है, वही महत्व देश की साख व्यवस्था में मुद्रा बाजार का है ।'²

मुद्रा बाजार के माध्यम से सरकार अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण प्राप्त करनी है । मुद्रा बाजार के ही माध्यम से मुद्रा की मांग तथा पूर्ति में सतुलन स्थापित किया जा सकता है और देश की मुद्रा इकाई के मूल्य में स्थिरता लाई जा सकती है । मुद्रा बाजार के संगठन से बचत कर्ताओं को बचत करने की प्रेरणा मिलती है और उन्हें यह विश्वास रहता है कि वे अपनी बचतों का सुरक्षित तथा लाभदायक विनियोजन कर सकेंगे । इस प्रकार मुद्रा बाजार देश की आर्थिक प्रगति का सूचक है और देश की अर्थव्यवस्था में उसका महत्वपूर्ण स्थान है ।

भारतीय मुद्रा बाजार (Indian Money Market)

भारतीय मुद्रा बाजार के अंग (Constituents of Indian Money Market) भारतीय मुद्रा बाजार का एक महत्वपूर्ण लक्षण उसकी द्विशाखिता (Dichotomy) है । उसमें एक है संगठित या आधुनिक भाग (Organised or Modern Sector) तथा दूसरा है असंगठित या स्वदेशी भाग (Unorganised

² "The importance of money market for the nation does not lie solely in its size. It lies rather in its liquidity, in its capacity for furnishing cash to any part of the country at a few hours notice. What a bank balance is to the individual, the money market is to the country's credit system."

or Indigenous Sector) इन दोनों बाजारों में व्याज दर के ढांचे भिन्न हैं। मुद्रा बाजार के संगठित या आधुनिक भाग के अंतर्गत रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विदेशी विनिमय बैंक तथा भारतीय व्यापारिक बैंक आते हैं। इनके अतिरिक्त अर्ध-सरकारी संस्थायें तथा बड़ी बड़ी संयुक्त स्कांध कॉर्पोरेशियाँ मुद्रा बाजार की प्रक्रियाओं में भाग लेती हैं। इसके अतिरिक्त दलाल (Brokers) होते हैं जैसे अक्विजिशन लोन (Call loan) के दलाल, (General Financial and Stock Brokers) भारतीय मुद्रा बाजार का केन्द्र 'अंतर बैंक अक्विजिशन मुद्रा बाजार' (Inter bank Call Money Market) है। यद्यपि इस बाजार में प्रयुक्त राशि की मात्रा बैंकों के जमा साधनों की तुलना में अधिक नहीं है परन्तु यह मुद्रा बाजार का सबसे शीघ्र प्रभावित होने वाला भाग है। यद्यपि भारत में बिलो तथा स्वीडिटी बाजारों का अभाव है परन्तु फिर भी भारतीय मुद्रा बाजार "कार्यों के संगठित सम्बन्धों तथा विशेषोपयोगों की दृष्टि से अपेक्षित सुविकसित है।"¹

मुद्रा बाजार के असंगठित या स्वदेशी भाग में साहूकार, महाजन मारवाड़ी, सराफ आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इस बाजार में अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन वित्त तथा वित्त के उद्देश्यों में भी स्पष्ट भेद नहीं होगा। मुद्रा बाजार के दोनों भागों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है और उनमें सहयोग तथा सामंजस्य का अभाव है। यद्यपि भारतीय मुद्रा बाजार का ढाँचा शिथिल है किन्तु वह बिल्कुल असम्बन्धित नहीं है। स्वदेशी बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा अन्य व्यापारिक बैंकों से पुनः बड़ा की मुविधाय प्राप्त है। सहकारी बैंकों की स्थिति मुद्रा बाजार के संगठित तथा असंगठित भागों के मध्य में है परन्तु यह बैंक स्टेट बैंक के राष्ट्रीयकरण के बाद व्यापारिक बैंक व्यवस्था के निःफट सम्पर्क में लाई जा रही है।

भारतीय मुद्रा बाजार के संगठित भाग पर तो रिजर्व बैंक का लगभग पूर्ण नियंत्रण है परन्तु असंगठित भाग पर रिजर्व बैंक का पूर्ण नियंत्रण नहीं है। स्वदेशी बैंकों पर रिजर्व बैंक के नियंत्रण के सभी प्रयत्न असफल रहे हैं।

भारतीय मुद्रा बाजार में क्रियाशील संस्थाओं का विस्तृत वर्णन सम्बन्धित अध्यायों में किया गया है।

भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताएँ (Characteristics of Indian Money Market) भारतीय मुद्रा बाजार के अध्ययन से उसकी निम्न विशेषतायें स्पष्ट होती हैं —

¹ Monthly Review of the Federal Reserve Bank of New York, July 1957.

(1) द्विशाखिता—संगठित तथा असंगठित भागों में विभाजित (Dichotomy—Divided into Organised and Unorganised Sectors) जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि भारतीय मुद्रा-बाजार का मुख्य लक्षण उसी द्विशाखिता (Dichotomy) है। भारतीय मुद्रा बाजार संगठित तथा असंगठित दो भागों में विभाजित है। इन दोनों भागों में पूर्ण सम्पर्क तथा सहयोग का अभाव है।¹ इसी कारण इन दोनों भागों में प्रचलित व्याज दरों में बड़ा अन्तर होता है।

व्यापारिक बिलों (Commercial Bills) अथवा कोपागार विपत्रों का भी वास्तविक अर्थों में बाजार नहीं है। इसके साथ साथ कुछ अन्य दोषों के होते हुए भी भारतीय मुद्रा बाजार “कार्यों के विजिप्टीकरण तथा संगठित सम्बन्धों की दृष्टि से अपेक्षाकृत पर्याप्त विकसित है।”²

(2) अंतर-बैंक अविलम्ब मुद्रा बाजार का महत्वपूर्ण स्थान (The Inter-bank Call Money Market is the core of the Indian Money Market): जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है भारतीय मुद्रा बाजार में अन्तर बैंक अविलम्ब मुद्रा बाजार का केन्द्रीय स्थान है। यद्यपि इस बाजार में प्रयुक्त राशि की मात्रा अधिक नहीं है फिर भी मुद्रा बाजार का यह सबसे अधिक संवेदनशील भाग (most sensitive sector of the money market) है।

(3) असंगठित भाग पर रिजर्व बैंक के नियंत्रण का अभाव (Absence of Reserve Bank's control over the unorganised sector): मुद्रा बाजार के असंगठित या स्वदेशी भाग पर रिजर्व बैंक का कोई नियन्त्रण नहीं है और उसमें कार्यशील स्वदेशी बैंकर पूर्णतः स्वतंत्र हैं। स्वदेशी बैंकरो को नियन्त्रण में लाने की रिजर्व बैंक की सभी योजनायें उनकी हठिधायिता तथा हठधर्मी के कारण असफल रही हैं।

(4) विकसित बिल बाजार का अभाव: (Lack of a well developed Bill Market): भारतीय मुद्रा बाजार में एक विकसित बिल बाजार का सर्वथा

¹. “The outstanding characteristic of Indian money market is its dichotomy, it comprises organised and unorganised markets with a divergence in the structure of interest rates. The organised and unorganised sectors are not wholly unconnected with each other, but there is no complete integration of the two in a single system.”

². “Indian Money Market is comparatively well-developed in terms of organised relationships and specialisation of functions.”

—Monthly Review of the Federal Reserve Bank of New York, July, 1957.

अभाव है। निम्नलिखित बाधाओं के कारण भारत में संगठित बिल बाजार विकसित नहीं हो पाया है :

- (i) देश के विभिन्न भागों में बिलों के आकार प्रकार में विभिन्नता ।
- (ii) व्यापारियों द्वारा बैंकों से नकद साख के माध्यम से ऋण लेने का अधिक प्रचलन ।
- (iii) बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में अधिक विनियोग ।
- (iv) कृषि उपज की मंडार सुविधाओं का अभाव तथा सावधि बिलों पर ऊँचा मुद्राश कर (Stamp duty) आदि ।

(5) चलन के प्रवाह की मौसमी प्रकृति (Seasonal character of movements of Currency) : चलन के प्रवाह की मौसमी प्रवृत्ति हमारी अर्थ-व्यवस्था की प्रकृति तथा उसमें नकद के अधिक लेन देनों के कारण है। हमारी अर्थ-व्यवस्था कृषि प्रधान होने के कारण फसल कटने तथा व्यापारियों द्वारा उनका क्रय-विक्रय होने के समय मुद्रा की अतिव्यवश्यकता होती है। नवम्बर से अप्रैल मई का यह काल व्यस्त काल (Busy Season) कहलाता है। फिर नई फसल की भाशा में व्यापारी माल बेच देते हैं और मुद्रा वापिस बैंकों के पास आ जाती है। जून से अक्टूबर तक का समय शिथिल काल (Slack Season) कहलाता है। इस प्रकार व्यस्त काल में बैंकों से व्यापारियों तथा शिथिल काल में व्यापारियों से बैंकों के पास मुद्रा का प्रवाह रहता है। योजना काल में अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर विनियोजन के कारण चलन की मांग में मौसमी परिवर्तन कुछ कम हो गये हैं।

(6) विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं जैसे बट्टा गृहों तथा स्वीकृति गृहों का अभाव (Lack of specialised financial institutions like Discount Houses and Acceptance Houses) भारत में एक विकसित बिल बाजार के अभाव के कारण इगनैड के बट्टा गृहों (Discount Houses) तथा अमेरिका के स्वीकृति गृहों जैसी विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं का विकास नहीं हो पाया है। इसके प्रतिरिक्त उन देशों का जैसी विक्रय वित्त कंपनियाँ (Sales Finance Companies), साख-सघ (Credit Unions) तथा ऋणदाता वित्त कंपनियाँ (Hire-Purchase Finance Companies) का भारत में विकास नहीं हो पाया है।

(7) अर्द्ध सरकारी संगठनों, बड़ी बड़ी सयुक्त पूँजी कंपनियों तथा दलालों का होना (Participation of semi government organisations, big joint stock companies and brokers). भारतीय मुद्रा बाजार के क्रिया कलापों में अर्द्ध सरकारी संगठन तथा बड़ी बड़ी सयुक्त पूँजी कंपनियाँ भी ऋणदाताओं के रूप में भाग लेती हैं। उनके द्वारा दिए गये ऋण गृह मुद्रा (House Money)

कहाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के वित्तीय मध्यस्थ जैसे अविलम्ब ऋण दलाल (Call Loan Brokers) सामान्य वित्त तथा स्क्रिप्ट दलाल (General Finance and Stock Brokers) भी मुद्रा बाजार में क्रियाशील रहते हैं।

भारतीय मुद्रा बाजार की आधुनिक प्रवृत्तियाँ (Changing Pattern of the Indian Money Market)

पिछले वर्षों के आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर हुए विनियोजन के कारण भारतीय मुद्रा बाजार के संगठन में कई परिवर्तन हुए हैं उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं —

(1) मुद्रा बाजार के एकीकरण की प्रवृत्ति (Tendency towards integration of the Money Market) . पिछले वर्षों में जनता के पास मुद्रा की पूर्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई है। 1951-52 में जनता के पास मुद्रा की मात्रा केवल 1,848 करोड़ रुपये थी जो 1967-68 में बढ़कर 5,350 करोड़ रुपये हो गई जबकि कुल मुद्रा से जमा मुद्रा के अनुपात में कम वृद्धि हुई है यह निम्न तालिका से स्पष्ट है :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	जनता के पास चलन	जमा मुद्रा	जमा मुद्रा का कुल चलन में अनुपात
1951-52	1 286	563	43 5
1964-65	2,769	1,311	47 3
1966-67	3 197	1 752	54 5
1967-68	3,376	1 976	58 5
1968-69	3,680	2,084	56 9

जमा मुद्रा का कुल चलन से अनुपात जो 1951-52 में 43 5 था 1967-68 में बढ़ कर 58 5 हो गया। इस प्रकार कुल चलन में जमा मुद्रा का प्रतिशत बढ़ रहा है। यह प्रवृत्ति मुद्रा बाजार के एकीकरण (Integration) की द्योतक है।

(2) मुद्रा बाजार के मौद्रिक भाग का बढ़ता महत्व (Growing Importance of monetised sector of the Money Market) : आज से 40 वर्ष पहले केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति (Central Banking Enquiry Committee) के अनुसार देश के कुल आन्तरिक व्यापार के 90 प्रतिशत भाग की वित्त व्यवस्था मुद्रा बाजार के असंगठित भाग (Unorganised Sector) द्वारा होती थी परन्तु अब यह प्रतिशत घटकर 50 ही रह गया है। अब अर्थव्यवस्था में मौद्रिक भाग का महत्व बढ़ रहा है। इसका प्रमाण मुद्रा पूर्ति के अन्तर्गत चलन वृद्धि की तुलना में जमा मुद्रा में अधिक तीव्र गति से हुई वृद्धि है जो निम्न तालिका से प्रकट है :

जनता के पास मुद्रा पूति में परिवर्तन
(Variations in Money Supply with the Public)
(करोड़ रुपयों में)

वर्ष के अंतिम शुक्रवार को	चलन में परिवर्तन	जमा मुद्रा में परिवर्तन	जनता के पास मुद्रा पूति में परिवर्तन
1951-52	+ 82	+ 27	+ 109
1955-56	+ 194	+ 68	+ 262
1960-61	+ 167	+ 32	+ 199
1961-62	+ 103	+ 74	+ 177
1962-63	+ 178	+ 86	+ 264
1963-64	+ 226	+ 216	+ 442
1964-65	+ 164	+ 165	+ 328
1965-66	+ 265	+ 184	+ 449
1966-67	+ 163	+ 257	+ 420
1967-68	+ 179	+ 223	+ 403
1968-69	+ 304	+ 109	+ 413

(3) देश के साख-यन्त्र पर रिजर्व बैंक का बढ़ता नियन्त्रण (Growing Control of the Reserve Bank on the Credit machinery) - विद्यमान वर्षों में रिजर्व बैंक के अधिकारों में वृद्धि तथा अनुसूचित बैंकों की धन के लिए रिजर्व बैंक पर बढ़ती निर्भरता के कारण देश की साख प्रणाली पर रिजर्व बैंक का नियन्त्रण बढ़ गया है।

भारतीय मुद्रा बाजार के दोष
(Defects of Indian Money Market)

भारतीय मुद्रा बाजार के संगठन तथा कार्य प्रणाली में निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं :

(1) विभिन्न भागों में पर्याप्त सम्बन्ध का अभाव (Inadequate connection between the component parts) : भारतीय मुद्रा बाजार दो भागों में बटा हुआ है - संगठित तथा असंगठित। दोनों भागों में कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं में पर्याप्त सहयोग तथा सम्बन्ध का अभाव है। सरकार से विशेष सुविधाएँ प्राप्त इम्पीरियल बैंक को व्यापारिक बैंक सदा प्रतिदोशी के रूप में देखते रहे और स्टेट बैंक के प्रति उनके दृष्टिकोण में कोई सुधार नहीं हुआ है। वे विनिमय बैंकों को भी प्रतिस्पर्धी के रूप में देखते हैं। स्वदेशी बैंकर स्वयं असंगठित हैं और इसी-लिए बम्बई में मुल्तानी, भारवाड़ी तथा गुजराती बाजार अलग-अलग हैं। स्वदेशी

बैंकरो तथा महाजनो मे भी अग्रिक सम्पर्क नही है और वे सामान्यत स्टेट बैंक मे खाते नही रखते । सहकारी बैंको का स्वदेशी बैंकरो तथा महाजनो से काई सम्बन्ध नही है । इस प्रकार मुद्रा बाजार के सगठित तथा असगठित भागो मे ही प्रतियोगिता नही होटी, वल्कि दोनो भागो के सदस्यो मे भी आपस मे प्रतियोगिता होती है । यह श्रवण्ययी प्रतिस्पर्धा भारतीय मुद्रा बाजार का मुख्य दोष है ।

(2) मुद्रा बाजार मे व्याज दरो की भिन्नता (Different Money Rates) भारतीय मुद्रा बाजार के असगठित होने तथा उसके विभिन्न अगो मे पर्याप्त सम्बन्ध के अभाव के कारण व्याज दरो मे बडी भिन्नता रहती है । न्यूयार्क तथा लंदन मुद्रा बाजारो मे विभिन्न व्याज दरे घनिष्ट रूप से सम्बन्धित है और वे दरे बैंक-दर पर निर्भर रहती है । परन्तु भारत मे बैंक-दर, अविलम्ब मुद्रा दर, निक्षेप दर, बाजार दर इत्यादि मे बडी विभिन्नता रहती है । लगभग 40 वर्ष पहल भारतीय मुद्रा बाजार मे व्याज दरो की विभिन्नता के सम्बन्ध मे केन्द्रीय बैंकिंग जाच समिति (Central Banking Enquiry Committee) का कयन आज भी लागू होता है "मुद्रा बाजार मे एक साथ $\frac{3}{4}$ प्रतिशत अविलम्ब दर, 3 प्रतिशत हुडो दर, 4 प्रतिशत बैंक दर, $6\frac{3}{4}$ प्रतिशत छोटे व्यापारियो के लिए बाजार दर तथा छोटे व्यापारियो की हुडियो पर 10 प्रतिशत कलकत्ता बाजार दर प्रचलित होना विभिन्न बाजारो के बीच पूँजी की अति मद गति को सूचित करता है ।"¹

(3) मुख्य केन्द्रो पर व्याज दरो मे भिन्नता (Disparity in Rates at Principal Centres) भारतीय मुद्रा बाजार का तीसरा दोष यह है कि बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के प्रमुख केन्द्रो पर भी व्याज दरो मे विभिन्नता रहती है जिमका वस्तुओ के प्रवाह (Movement of goods) पर प्रभाव पडता है और प्रतिभूतियो की कीमतो मे उच्चावचन होन लगने हैं । रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक द्वारा सस्ती दर पर घन स्थानान्तरण की सुविधायो (Remittance facilities) दिए जाने के बावजूद व्याज दरो की भिन्नता समाप्त नही हुई है । दिसम्बर 1968 मे बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास मे अविलम्ब मुद्रा व्याज दर क्रमश 3.25, 4.06 तथा 3.45 प्रतिशत तथा बाजार विल दर क्रमश. 15, 13.50 तथा 21.00 प्रति शत थी ।

¹ "The fact that a call rate of $\frac{3}{4}$ per cent, a hundi rate of 3 per cent, a bank rate of 4 per cent, a Bombay Bazar rate for bills of small traders of $6\frac{3}{4}$ per cent and a Calcutta Bazar rate for bills of Small traders of 10 per cent can exist simultaneously indicates an extra ordinary sluggishness in the movement of credit between the various markets"

याचना राशि तथा बाजार बिल दरों में पिछले कुछ वर्षों में विभिन्नता निम्न तालिका से स्पष्ट है :

भारतीय मुद्रा बाजार में व्याज दरें

वर्ष	स्टेट बैंक की छाड़कर अन्य अनुसूचित बैंकों द्वारा याचना राशि दर			बाजार बिल दर		
	बम्बई	कलकत्ता	मद्रास	बम्बई	कलकत्ता	मद्रास
1955-66	2.75	3.16	2.95	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$ 11	12
1960-61	4.26	4.30	3.74	9.00-12.00	9.50-13.00	12.00-13.92
1965-66	6.26	6.81	6.06	12.00-15.00	15.00	17.40-19.80
1966-67	5.16	5.51	4.57	15.00	15.00	19.80
1967-68	4.95	4.80	4.09	15.00	15.00 13.50	19.80-21.50
1968-69	3.75	4.05	4.06	15.00	13.50	21.60-21.00

पिछले कुछ वर्षों में बैंकों के निलेपो पर व्याज दर में उनके बीच इस सम्बन्ध में हुए समझौते के कारण समानता आ गई थी परन्तु अब वह समझौता भी रिजर्व बैंक ने समाप्त कर दिया है।

(4) विशिष्ट वित्त संस्थाओं का अभाव (Lack of Specialised Institutions) : भारत में बट्टा गृह (Discount Houses) स्वीकृति गृह (Acceptance Houses) आदि विशिष्ट वित्त संस्थाओं का अभाव है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले तक यहाँ कोई औद्योगिक बैंक भी नहीं थे जिससे उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में वित्त सहायता नहीं प्राप्त होती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो औद्योगिक वित्त निगमों की स्थापना हुई है और वे सफलतापूर्वक कार्य भी कर रहे हैं परन्तु देश की आवश्यकतानुसार उनके द्वारा दी जान वाली सहायता पर्याप्त नहीं है। विशिष्ट संस्थाओं का अभाव भारतीय उद्योग तथा वाणिज्य के विकास में एक प्रमुख बाधा रही है।

(5) मुद्रा की मौसमी कमी (Seasonal Monetary Stringency) : हमारी अर्थ व्यवस्था की विशिष्ट प्रकृति के कारण व्यस्तकाल (नवम्बर से अप्रैल-मई) में जब फसलों की कटाई तथा बिक्री इत्यादि होती है अल्पकालीन मुद्रा की मांग बढ़ जाती है और कोषों का अभाव अनुभव होने लगता है। परिणाम स्वरूप व्याज दरें बढ़ जाती हैं। रिजर्व बैंक द्वारा कृपि बिलों के बट्टा की सुगम शर्तों के कारण मुद्रा की मौसमी कमी की दृष्टि से कुछ सुधार तो हुआ है परन्तु यह कमी पूरी तरह से दूर नहीं हो पायी है।

(6) संगठित बिल बाजार का अभाव (Lack of Organised Bill Market) : किसी देश के साख संगठन के सफलतापूर्वक कार्य कराने तथा मुद्रा

बाजार में व्यस्त काल की मौद्रिक कमी को लोचहीनता को दूर करने के लिए एक सुसंगठित तथा विकसित बिल बाजार की आवश्यकता होती है। भारत में एक सुसंगठित बिल बाजार का विकास नहीं हो पाया है। इसके विकास में मुख्य बाधाएँ— नवद साख का अधिक प्रचलन, बिलों के आकार-प्रकार में विभिन्नता, बैंको द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग आदि— रही हैं। [भारत में संगठित बिल बाजार न होने के कारणों का विस्तृत विवेचन इसी अध्याय में आगे 'बिल बाजार' के अन्तर्गत किया गया है।] रिजर्व बैंक द्वारा 1952 में बिल बाजार योजना' (Bill Market Scheme) के चालू होने से इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है।

(7) अपर्याप्त बैंकिंग सुविधायें (Inadequate Banking Facilities) : देश के आकार तथा आवश्यकताओं को देखने हुए देश में बैंकिंग सुविधायें अपर्याप्त हैं और उनका विस्तार अपनी तीव्र गति से नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। अमेरिका में 3,737 व्यक्तियों पर एक बैंक है परन्तु भारत में 1,30,000 व्यक्तियों पर एक ही बैंक है। इसके साथ साथ भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का अधिक विस्तार नहीं हो पाया है। यद्यपि स्टेट बैंक ने पिछले वर्षों में ग्रामीण तथा अर्द्धनगरीय केन्द्रों में काफी शाखाएँ खोली हैं और अन्य बैंको ने भी इस दिशा में प्रयत्न किए हैं परन्तु स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। भारत में बैंको का विकास भी असन्तुलित ढंग से हुआ है। उसे ठीक करने के लिए रिजर्व बैंक अब अधिक सचेत तथा क्रियाशील है।

65 वर्षों के अपने जीवनकाल में भी सहकारी आन्दोलन ग्रामीण क्षेत्रों में सहकार-महाजन का स्थान नहीं ले सका है जो अब भी कृषि वित्त व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

भारतीय मुद्रा बाजार में सुधार के उपाय

(Suggestions for improvement in the Indian Money Market)

भारतीय मुद्रा बाजार के संगठन तथा प्रक्रियाओं में सुधार के लिए समय-समय पर अनेक सुझाव दिए गये हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद एक सुसंगठित तथा विकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता का अनुभव किया गया और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रयत्न किए गये। रिजर्व बैंक तथा इम्पोरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण, विशिष्ट वित्त संस्थाओं की स्थापना, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम में समय-समय पर परिवर्तन तथा सशोधन, रिजर्व बैंक के अधिकारों में निरन्तर वृद्धि तथा बैंको का सामाजिक नियंत्रण इत्यादि इस दिशा में किए गये महत्वपूर्ण प्रयास हैं।

भारतीय मुद्रा बाजार के दोषों को दूर करने के लिए तथा उसे अधिक सुदृढ़ आधार पर खड़ा करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं :

(1) देशी बैंकरो पर नियन्त्रण (Regulation and Control of Indigenous Bankers): मुद्रा बाजार के असंगठित भाग पर रिजर्व बैंक का नियन्त्रण होना चाहिए। स्वदेशी बैंकरो को मुद्रा बाजार के संगठित भाग से जोड़कर मुद्रा बाजार में एकीकरण लाया जाना चाहिए। 1937 से लेकर आज तक स्वदेशी बैंकरो को रिजर्व बैंक के नियन्त्रण में लाने के सभी प्रयत्न निष्फल रहे हैं। 1954 में श्राफ समिति (The Shroff Committee on Finance for the Private Sector) की सिफारिशों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। समय की मांग है कि स्वदेशी बैंकर कुछ समूहों में मिलकर बैंकिंग कम्पनियाँ बनायें। उनके द्वारा प्रयुक्त हुडियो को बिलों में परिवर्तित किया जाय। यदि रिजर्व बैंक स्वदेशी बैंकरो को व्यापारिक बैंकों से पुनः वट्टा की सुविधायें सस्ती दर पर उपलब्ध कराने का प्रयत्न करे तो मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में प्रचलित ऊँची ब्याज की दरों को भी घटाया जा सकता है।

(2) सुसंगठित बिल बाजार का विकास (Development of a well organised Bill Market): विकसित मुद्रा बाजार में एक सुसंगठित बिल बाजार बड़ा आवश्यक है। 1952 में रिजर्व बैंक ने 'बिल बाजार योजना' प्रारम्भ कर इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाया। उसके बाद उसमें समय समय पर सशोधन कर उसे और अधिक लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया गया है। परन्तु फिर भी एक सुसंगठित बिल बाजार का विकास नहीं हो पाया है। इस दिशा में और अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

(3) हुडियो का प्रमाणीकरण (Standardisation of Hundies): भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित हुडियो में एकरूपता का अभाव है। विभिन्न भाषाओं तथा विधियों में लिखी जाने के कारण उनके प्रयोग में बड़ी असुविधा होती है। हुडियो एक अखिल भारतीय बाजार के निर्माण तथा विस्तार के लिए एकरूपता लायी जानी चाहिए और उनका प्रमाणीकरण (Standardisation) होना चाहिए। इससे बैंकों को उनका वट्टा करने में सुविधा होगी।

(4) प्रेषण सुविधाओं का विस्तार (Expansion of Remittance Facilities): देश के विभिन्न भागों में धन की मांग और पूर्ति में सहायोजन स्थापित करने के लिए धन का शीघ्र तथा मितव्ययी स्थानान्तरण बड़ा आवश्यक है। रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दी जाने वाली प्रेषण सुविधाओं में और सुधार होना चाहिए और यह सुविधा स्वदेशी बैंकर्स को भी उपलब्ध होनी चाहिए।

(5) अनुज्ञापित भंडार गृहों का निर्माण (Construction of Licenced Warehouses): भारत में पर्याप्त मात्रा में भंडार गृहों की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं

जिनमे माल जमाकर कृपक तथा व्यापारी उसकी रसीद के आधार पर साख सुविधायें प्राप्त कर सक। ग्रामीण क्षेत्रों में तो इस दिशा में स्थिति बड़ी शोचनीय है। यद्यपि भारत सरकार तथा उसके द्वारा स्थापित भंडार गृह निगमों (Warehousing Corporations) द्वारा भंडार गृहों का निर्माण हो रहा है परन्तु देश की आवश्यकताओं का देखते हुए इस दिशा और अधिक सक्रिय रूप से प्रयत्न की आवश्यकता है।

(6) विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना तथा प्रोत्साहन (Establishment and encouragement to Specialised Institutions) : स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उद्योगों की दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन पूँजी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के औद्योगिक वित्त निगमों की स्थापना की गई है। देश के बढ़ते औद्योगीकरण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके पूँजी साधनों में वृद्धि की जानी चाहिए। अन्य क्षेत्रों में भी विशिष्ट संस्थाओं (Specialised Institutions) की स्थापना होनी चाहिए जिससे मुद्रा बाजार में क्रिया कलाप सुविधापूर्वक हो सकें।

(7) समाशोधन गृहों की स्थापना (Establishment of Clearing Houses) : देश के विभिन्न कस्बों में समाशोधन-गृहों की स्थापना होनी चाहिए जिससे बैंक अपने पारस्परिक दायित्व खाते में प्रविष्टियों द्वारा ही साफ कर सकें। समाशोधन गृहों की कार्य प्रणाली को और अधिक वैज्ञानिक बनाकर उसमें सुधार किया जाना चाहिए।

(8) बैंकिंग का तीव्रगति से बहुमुखी विकास (Speedy Multisided Development of Banking) यद्यपि पिछले दशक में भारतीय बैंक व्यवस्था ने पर्याप्त प्रगति की है परन्तु दश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार तथा ग्रामीण बचतों के शोषण की समस्या अब भी बनी हुई है। देश के सभी क्षेत्रों में बैंकिंग का सतृलित तथा बहुमुखी विकास तीव्र गति से होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक हो तो देश की बैंकिंग व्यवस्था में पुनर्गठन का प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। आशा है इस दिशा में श्री आर० जी० सरैया की अध्यक्षता में नियुक्त बैंकिंग आयोग महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखेगा।

भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 में समय समय पर सशोधन कर, रिजर्व बैंक के अधिकारों में वृद्धि तथा बैंकों का सामाजिक नियंत्रण कर सुधार के प्रयत्न किए गये हैं। आशा है कि आगे इस दिशा में और सुधार होगा।

भारत में बिल-बाजार (Bill Market in India)

जिसी भी देश के मुद्रा बाजार को विकसित होने के लिए एक सुमंगलित बिल बाजार की अति आवश्यकता है। देश की साख व्यवस्था को सफलतापूर्वक कार्य

करने में बिल बाजार बड़ी सहायता पहुँचाता है। (A well organised bill market is an indispensable adjunct of an efficient money market and is essential for the smooth working of the credit system) देश के आर्थिक विकास के लिए पूँजी के विनियोग में बिल बाजार महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा बाजारों में घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करते हैं। बिल बाजार का महत्व निम्न वाक्यों में स्पष्ट किया गया है :

“The bill market which depends upon the existence of dealers who are always ready to buy and sell bills, provides a medium by means of which additional credit from the central bank is obtained in times of monetary strain, and is returned when the stringency is over. It facilitates a freer flow of funds and establishes close relationships between the money markets of the world. It is in addition, a valuable source of employment of foreign exchange reserves of a country.”

पहले हमें बिल बाजार की कार्य प्रणाली को समझ लेना चाहिए। जब कोई व्यापारी किसी दूसरे को माल बेचता है तो वह शीघ्र से शीघ्र भुगतान प्राप्त करना चाहता है और क्रेता भुगतान के लिए कुछ समय चाहता है क्योंकि क्रेता के पास माल पहुँचने में भी कुछ समय लग जाता है। विदेशी व्यापार में क्रेता-विक्रेता बहुत दूर होते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए विक्रेता क्रेता पर एक बिल लिखता है जिसे क्रेता का बैंक स्वीकार कर लेता है। इस बिल को बेच कर विक्रेता भुगतान पहले ही प्राप्त कर लेता है और क्रेता को तुरन्त भुगतान नहीं करना पड़ता है और भुगतान के लिए कुछ समय मिल जाता है। बिल बाजार कृपको को फसलों के स्थानान्तरण के लिए अल्पकालीन ऋण ही नहीं प्राप्त कराता बल्कि बैंकों को अल्पकालीन विनियोगों का अवसर प्रदान करता है।

दुर्भाग्य से भारत में 1952 तक इस प्रकार के बिल बाजार का विकास नहीं हो पाया।

भारत में सुसंगठित बिल बाजार के अभाव के कारण (Causes of lack of a well organised Bill Market in India)

भारत में 1952 तक बिल बाजार के विकास में निम्नलिखित मुख्य बाधाएँ रही हैं :

(1) नकद साख द्वारा ऋण का अधिक प्रचलन (Popularity of borrowing through Cash Credits) : भारत में अधिकतर व्यापारी बिलों का बड़ा अंतर ऋण प्राप्त करने के बजाय नकद साख द्वारा ऋण लेना अधिक पसन्द करते

है। नकद साख प्रणाली की व्यापारिक क्षेत्रों में लाकप्रियता बिलों के प्रचलन में प्रमुख बाधा रही है।

(2) बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में अधिक विनियोग (Large investments in Government Securities by Commercial Banks) : भारतीय बैंक अपनी सम्पत्तियों में तरलता (Liquidity) के लिए अपने धन का अधिकतर भाग सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उनकी धरोहर पर उन्हें रिजर्व बैंक से तत्काल ऋण मिल जाता है। अतः भारतीय बैंक बिलों का बड़ा वर उसमें अधिक धन विनियोजित नहीं करते और बिलों के प्रचलन को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता।

(3) नकद लेन देन की आदत (Cash transaction habit) - व्यापारियों में नकद लेन देन की आदत होने के कारण साख सौदों की मात्रा बहुत कम और उसमें भी बिल बहुत ही कम लिखे जाते हैं।

(4) विशिष्ट संस्थाओं की कमी (Absence of Specialised Institutions) बिलों के प्रचलन को प्रोत्साहन देने वाली विशिष्ट संस्थाओं जैसे स्वीकृति-घृहों (Acceptance Houses), बट्टा-घृहों (Discount Houses) आदि का भारत में अभाव है। विदेशों में स्वीकृति घृहों द्वारा स्वीकृत बिलों को बिना किसी कठिनाई के बाजार में खरीदा-बेचा जा सकता है।

(5) हुडियों के आकार-प्रकार में एकस्यता का अभाव (Lack of uniformity in hundies) . विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित हुडियों के स्वरूप तथा लेखन विधि में बड़ी भिन्नता है जिससे एक अखिल भारतीय बाजार का विकास नहीं हो सका है।

(6) व्यापारिक तथा अनुग्रह बिल में भेद कठिन (Distinction between genuine Trade Bill and Accommodation Bill difficult) : बैंकों के पास बट्टा करने के लिए आने वाले बिलों में यह भेद करना बड़ा कठिन है कि कौन वास्तविक व्यापारिक बिल है और कौन अनुग्रह। अतः वे बिलों में विनियोजित करने में सकोच करते हैं।

(7) बिलों पर ऊँचा मुद्राक कर (Heavy Stamp Duty on Bills) : भारत में साख विनिमय बिलों पर मुद्राक कर की दर बहुत ऊँची है। अनुमानतः यह दर $\frac{1}{2}$ प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक है। इस कारण भी बिलों का प्रचलन कम है।

(8) बिलों के पुनः बट्टा की कठिनाई (Difficulty in Rediscounting of Bills) : रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद भी बैंकों को बिलों का पुनः बट्टा करने

की कठिनाई रही। रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को स्वीकृत प्रतिनूतियों के आधार पर ऋण देना था। अतः बैंक बिलों का पुनः बड़ा करवाना की प्रोत्साहित नहीं होते थे।

मुसंगठित बिल बाजार के निर्माण के लिए सुझाव

(Suggestions for developing an organised Bill Market in India)

भारत में मुसंगठित बिल बाजार के अभाव को दूर करने के लिए निम्न-लिखित सुझाव दिये जाने रहे हैं :

(1) विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना (Establishment of Specialised Institutions) : निगम गृहों (Issue Houses), स्वीकृति गृहों (Acceptance Houses) आदि विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना हानी चाहिए जिससे बिलों की विश्वसनीयता बढ़ सके और उनका प्रचलन तथा बड़ा अधिक भाना में हो।

(2) टुडियों का प्रमाणीकरण (Standardisation of Hundies) : भारत में टुडियाँ क आकार प्रकार तथा लेखन विधि की भिन्नता को समाप्त कर उनका प्रमाणीकरण का सुझाव केन्द्रीय बैंकिंग जाव नसिति ने दिया था। टुडियों को एक ही नाया तथा ऋषि से लिखा जाना चाहिए।

(3) बिलों पर मुद्रा कर में कमी (Reduction in Stamp Duty on Bills) : बिलों का प्रचलन बढ़ाने के लिए इन पर मुद्रा कर में पर्याप्त कमी की जानी चाहिए जिससे बैंक आसानी से उनका व्यव-विन्दय कर सकें।

(4) भंडार गृहों की स्थापना (Establishment of Licenced warehouses) : भंडार गृहों के अभाव को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर अनुज्ञापित भंडार गृहों के निर्माण का कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए जिससे कि उनकी जमा रसीद पर साव प्राप्त की जा सके। प्रामाण्य क्षेत्रों में इस प्रकार के भंडार गृहों की विशेष आवश्यकता है।

(5) केन्द्रीय बैंक की सक्रियता (Active Interest of the Central Bank) : बिल बाजार के विकास तथा संगठन में रिजर्व बैंक का पर्याप्त सक्रिय सहयोग प्राप्त होना चाहिए। रिजर्व बैंक की बिल बाजार योजना उसके प्रयत्नों में दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होनी जा रही है।

रिजर्व बैंक की बिल बाजार योजना

(Reserve Bank's Bill Market Scheme)

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने 1951 में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना आरम्भ कर नियोजित आर्थिक विकास (Planned Economic Development) का मूत्रपात्र क्रिया तो भारतीय मुद्रा बाजार के मुसंगठित करने की आवश्यकता का

बड़ी तीव्रता से अनुभव किया गया। भारत में बिल बाजार के अभाव को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ने नवम्बर 1951 को एक नई बिल बाजार योजना (Bill Market Scheme) की घोषणा की। इससे पहले अनुसूचित बैंक व्यस्त काल की मुद्रा-आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक से स्वीकृत तथा सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण प्राप्त किया करते थे। नवम्बर 1951 में जब साख के अत्यधिक विस्तार को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने बैंक दर को 3 प्रतिशत से बढ़ा कर $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत किया तो साथ में यह भी घोषणा की कि वह अनुसूचित बैंकों की व्यस्तकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अब सरकारी प्रतिभूतियां नहीं खरीदेगा परन्तु सरकारी तथा अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों के आधार पर अग्रिम देता रहेगा। इस प्रकार मौसमी साख विस्तार का केन्द्रीय बैंक द्वारा गुणात्मक नियन्त्रण (Qualitative Control) सम्भव हो सकेगा और मुद्रा बाजार में पर्याप्त लोच आ जायेगी। इसी उद्देश्य से बम्बई और कलकत्ता के बैंकों से परामर्श के पश्चात् रिजर्व बैंक ने 16 जनवरी 1952 को अपनी बिल बाजार योजना को कार्य रूप दिया। प्रारम्भ में योजना प्रयोग स्तर पर शुरू की गई और बाद में उसे विस्तृत किया गया।

बिल बाजार योजना की मुख्य विशेषतायें (Salient features of the Bill Market Scheme) रिजर्व बैंक द्वारा प्रारम्भ की गई बिल बाजार योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थीं

(1) इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित बैंकों को सावधि प्रतिज्ञा-पत्रों तथा अन्तर्देशीय बिलों के आधार पर रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट की धारा 17 (4) (स) के अनुसार ऋण देने की व्यवस्था की गई। प्रयोग के रूप में प्रारम्भ में यह सुविधा 10 करोड़ या उससे अधिक निक्षेप वाले अनुसूचित बैंकों तक ही सीमित रखी गई। इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए बिलों का व्यापारिक बिल (Trade Bill) होना आवश्यक था और उन पर दो हस्ताक्षर आवश्यक थे जिनमें एक किसी अनुसूचित बैंक का हो।

(2) इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों पर बैंक दर ($3\frac{1}{2}$ प्रतिशत) से आधा प्रतिशत कम {3 प्रतिशत} व्याज लेने की व्यवस्था थी। यह बिलों के आधार पर ऋण प्राप्त करने को प्रोत्साहित करने हेतु किया गया था।

(3) व्यापारिक सावधि बिलों को प्रोत्साहन देने हेतु मांग बिलों (Demand Bills) को सावधि बिलों (Usance Bills) में परिवर्तित कराने के मुद्राक कर (Stamp Duty) का आधा भाग रिजर्व बैंक स्वयं वहन करेगा।

(4) योजना के अन्तर्गत बैंकों को दिये जाने वाले ऋण की न्यूनतम सीमा 25 लाख तथा प्रत्येक बिल की सीमा 1 लाख रुपये निर्धारित की गई थी।

योजना में संशोधन (Further amendments in the Scheme) : बैंक प्रतिनिधियों के सुझाव तथा प्राप्त अनुभव के आधार पर जून 1953 में योजना के अन्तर्गत सुविधायें उन बैंकों को भी दी जाने लगी जिनके निक्षेप 5 करोड़ या इससे अधिक थे। 1954 में निजी क्षेत्र के वित्त पर नियुक्त थाक समिति ने अन्य सुझावों के साथ यह सुझाव भी दिया था कि योजना 1 करोड़ या उससे अधिक निक्षेप वाले बैंकों पर भी लागू की जाय। जुलाई 1954 में रिजर्व बैंक ने बिना किसी निक्षेप सीमा के सभी लाइसेंस प्राप्त अनुसूचित बैंकों पर योजना को लागू कर दिया। इसके अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ऋणों की न्यूनतम राशि को 25 लाख से घटाकर 10 लाख तथा एक मिल की राशि को 1 लाख रुपये से घटाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया। 22 फरवरी 1957 से ऋण की न्यूनतम राशि को घटाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया। अक्टूबर 1958 में विदेशी बिलों को भी योजना में सम्मिलित कर लिया गया। निर्यात वित्त अध्ययन दल, 1960 (Study Group on Export Finance, 1960) के सुझाव पर रिजर्व बैंक एक्ट की धारा 17 में संशोधन कर निर्यात बिलों की परिपक्वता अवधि 180 दिन कर दी गई। मार्च 1963 में 'निर्यात बिल साख योजना (Export Bills Credit Scheme) प्रारम्भ की गई जिसके अन्तर्गत निर्यात बिलों की घोषणा तथा केवल प्रतिज्ञा पत्र लिख देने मात्र से रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त हो जाता है।

योजना की प्रगति (Progress of the Scheme) : बिल बाजार योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋणों की राशि 1951-52 में 29 करोड़ रुपये थी जो 1955-56 में बढ़कर 229 करोड़ रुपये हो गई थी। अतः 1 मार्च 1956 के बाद से बैंक दर से प्राधा प्रतिशत की छूट को घटाकर $\frac{1}{4}$ प्रतिशत कर दिया गया और मुद्राक कर सम्बन्धी छूट समाप्त कर दी गई। 21 नवम्बर 1956 को $\frac{1}{4}$ प्रतिशत व्याज दर की छूट को त्रिकुल समाप्त कर ऋण पर व्याज दर बैंक दर के बराबर कर दी गई।

गत वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋणों की राशि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जो अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका से स्पष्ट है :

रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंको को दिए गये ऋण
(धारा 17 [4] [स] के अन्तर्गत)

(करोड रुपये में)

वर्ष	राशि
1951-52	29
1955-56	229
1960-61	255
1961-62	285
1962-63	326
1963-64	254
1964-65	275
1965-66	223
1966-67	418
1967-68	368
1968-69	1354

उपर्युक्त तालिका से प्रकट है कि इस योजना के अन्तर्गत किए गये ऋणों की राशि जो 1951-52 में केवल 29 करोड रुपये थी, 1968-69 में बढ़कर 1354 करोड रुपये के रिकार्ड बिन्दु तक पहुँच गई।

विल बाजार योजना की सफलता के सम्बन्ध में श्री एस० जी० पनन्दीकर (S. G Panandikar) ने लिखा है :

“The scheme appears to have become a permanent feature of the credit system of the country and to have given greater elasticity and autonomy to the money market. It has added considerable flexibility to the operations of the Reserve Bank as lender of the last resort and has helped the Reserve Bank to ensure that the advances made under it are for bonafide trade purpose and for short periods. It has obviated the need for large purchases and sales of securities by the Reserve Bank in order to adjust money supply to seasonal conditions.”

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संकेत

(1) मुद्रा बाजार से आप क्या समझते हैं ? भारतीय मुद्रा बाजार के अग्रे का वर्णन कीजिए।

(राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल, 1964; 1966)

[संकेत—प्रथम भाग में मुद्रा बाजार की विभिन्न परिभाषाएँ देते हुए उसका अर्थ तथा महत्त्व स्पष्ट कीजिए। दूसरे भाग में भारतीय मुद्रा बाजार के

संगठित तथा असंगठित भाग में क्रियाशील विभिन्न बैंको तथा वित्तीय संस्थाओं का वर्णन कीजिए।]

(2) भारतीय मुद्रा बाजार के कौन से दोष हैं ? उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है ?

(राजस्थान, बी० काम, 1961)

(आगरा, 1968)

[सकेत—प्रथम भाग में भारतीय मुद्रा बाजार के मुख्य दोषों का विवेचन कीजिए और बताइये कि भारत में न्यूयाक तथा लंदन जैसे संगठित मुद्रा बाजार का अभाव है। दूसरे भाग में मुद्रा बाजार के दोषों को दूर करने के लिए विभिन्न समितियों तथा विद्वानों ने जो सुझाव दिए हैं उनका वर्णन कीजिए।]

(3) भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताओं का वर्णन करें और इसके दोषों पर दृष्टिपात करें।

(आगरा बी० ए०, 1960)

[सकेत—प्रथम भाग में भारतीय मुद्रा बाजार की मुख्य विशेषताओं जैसे द्विशाखिता (Dichotomy), बिल बाजार का अभाव, चलन के प्रवाह की मौसमी प्रकृति इत्यादि का वर्णन कीजिए। फिर भारतीय मुद्रा बाजार की आधुनिक प्रवृत्तियों का आकड़ों सहित विवेचन कीजिए। दूसरे भाग में मुद्रा बाजार के मुख्य दोषों का उल्लेख कीजिए।]

(4) भारत में बिल बाजार के अभाव के क्या कारण हैं ? उन्हें दूर करने के उपाय बताइये।

(गोरखपुर बी० काम०, 1959)

अथवा
भारत में बिल बाजार के न होने के क्या कारण हैं ? जनवरी 1952 से इस सम्बन्ध में क्या किया गया है ?

(आगरा बी० काम०, 1962)

[सकेत—प्रथम भाग में भारत में सुसंगठित बिल बाजार के अभाव के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए। दूसरे भाग में पहले प्रश्न के उत्तर में तो उन कारणों को दूर करने के उपाय बताइये और संक्षेप में रिजर्व बैंक की बिल बाजार योजना का वर्णन कीजिए। दूसरे प्रश्न के उत्तर में बिल बाजार योजना तथा उसकी प्रगति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।]

रिजर्व बैंक आफ इन्डिया (Reserve Bank of India)

“Central Banking in a planned economy can hardly be confined to the regulation of the overall supply of credit or to a somewhat negative regulation of the flow of bank credit. It would have to take on a direct and active role, firstly, in creating or helping to create the machinery needed for financing developmental activities all over the country and secondly, in ensuring that the finance available flows in the directions needed”

First Five Year Plan.

भारत में बहुत पहले से एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। 1935 के पहले इस और जितने भी प्रयत्न किए गये वे सभी असफल रहे। सबसे पहले 1993 ई० में जनरल बैंक आफ बंगाल एन्ड बिहार (General Bank of Bengal and Bihar) नाम का केन्द्रीय बैंक बनाने का मुझाव दिया गया था। 1913 में चैम्बरलेन आयोग के सदस्य के नाते लार्ड कीन्स ने केन्द्रीय बैंक की स्थापना का प्रश्न फिर उठाया। 1920 में स्वर्णमान की पुनर्स्थापना के लिए ब्रुसेल्स में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन (International Economic Conference) हुआ और उसमें यह प्रस्ताव पास किया गया कि “जिन देशों में केन्द्रीय बैंक नहीं है वहां शीघ्र ही एक केन्द्रीय बैंक स्थापित किया जाय।” भारत सरकार ने स्वर्णमान की योजना को सफल बनाने तथा देश में केन्द्रीय बैंक के अभाव को दूर करने के लिए 1920 में तीनो—बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास—प्रेसीडेन्सी बैंकों को मिलाकर ‘इम्पीरियल बैंक आफ इन्डिया’ की स्थापना की परन्तु उसे नोट-निर्गमन का अधिकार नहीं दिया गया। केन्द्रीय बैंक के रूप में इम्पीरियल बैंक का कार्य सतोपजनक नहीं था और देश की मुद्रा तथा साख व्यवस्था पर दोहरा नियंत्रण (सरकार व इम्पीरियल बैंक का) रहता था, जिसमें देश में एक अलग केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। 1926 में भारतीय मुद्रा तथा वित्त पर शाही आयोग (हिल्टन यंग कमीशन) ने भी यह अनुभव किया कि जब किसी देश में मुद्रा व साख पर दो पृथक् सस्थाओं का नियंत्रण रहना है तो मुद्रा व्यवस्था में

दोष ग्राना स्वामाबिक ही है क्योंकि वे दोनों सस्थायें मित्र नीतिया अपना सकती है। अतः कमीशन ने उक्त दोष दूर करने के लिए एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की। इन सुभावों को क्रियान्वित करने हेतु जनवरी 1927 में सर बेसिल ब्लेकेट (Sir Basil Blackett) ने भारतीय विधान सभा में एक बिल प्रस्तुत किया जो कुछ वैधानिक कठिनाइयों के कारण वापिस ले लिया गया। 1931 में केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति ने केन्द्रीय बैंक की स्थापना पर जोर दिया। 1933 में भारतीय संबंधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र प्रकाशित होने पर यह प्रश्न फिर उठा। श्वेत पत्र के प्राक्कथन के 32 वे अनुच्छेद के अनुसार केन्द्र में ब्रिटेन द्वारा सत्ता का हस्तान्तरण तभी किया जायगा जबकि राजनीतिक प्रभावों से मुक्त एक केन्द्रीय बैंक स्थापित किया जाय। अतः केन्द्रीय विधान सभा में 8 सितम्बर 1933 को एक रिजर्व बैंक आफ इन्डिया बिल प्रस्तुत किया गया जिम पर 6 मार्च 1934 को गर्बेनर जनरल ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार रिजर्व बैंक आफ इन्डिया की स्थापना हुई और बैंक ने 1 अप्रैल 1935 से विधिवत अपना काम प्रारम्भ किया।

भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना के कारण

(Causes of the Establishment of Reserve Bank of India)

भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कई कारणों से की गई थी जिनमें मुख्य निम्नलिखित थे—

1. देश में मुद्रा तथा साख का समुचित प्रबंध (Proper Management of Money and Credit)—केन्द्रीय बैंक के कार्यों को इम्पीरियल बैंक आफ इन्डिया ने अधिक सतोपपूर्ण ढंग से पूर्ण नहीं किया था। साथ-साथ मुद्रा व्यवस्था पर सरकार तथा इम्पीरियल बैंक का दोहरा नियंत्रण था। हिल्टन यंग कमीशन ने व्यवस्था के इस दोष की श्रौर ध्यान आकर्षित किया था। केन्द्रीय बैंक की स्थापना से यह दोष दूर हो सकता था तथा देश में मुद्रा तथा साख का समुचित प्रबंध हो सकता था।

2. रुपये के आंतरिक तथा बाह्य मूल्य में स्थिरता (Stability in the internal and external value of the Rupee) : किसी भी देश की मुद्रा व्यवस्था में जनता का विश्वास उत्पन्न करने के लिए मुद्रा के आंतरिक तथा बाह्य मूल्यों में स्थिरता अति आवश्यक है अतः भारतीय मुद्रा में आंतरिक तथा बाह्य स्थिरता लाने के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।

3. बैंकिंग का विकास (Banking development) : देश में बैंकिंग व्यवस्था का सर्वांगीण विकास करना रिजर्व बैंक की स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य था।

बैंकिंग व्यवस्था के दोषों को दूर कर उसे शक्तिशाली बनाने में केन्द्रीय बैंक का उत्तरदायित्व बड़ा महत्वपूर्ण होता है।

4. कृषि साख व्यवस्था (Providing agricultural credit) : एक कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि के विकास में साख सुविधाओं का अभाव एक मुख्य बाधा थी। अतः कृषि साख की समुचित व्यवस्था करने के लिए रिजर्व बैंक को उत्तरदायित्व सौंपा गया।

5. सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था (Management of Public Debt) सरकार की वित्त व्यवस्था में सार्वजनिक ऋणों का महत्वपूर्ण स्थान है। सार्वजनिक ऋणों को प्राप्त करना, उनकी भुगतान व्यवस्था करना तथा उनका लेखा जोखा रखना सरकारी बैंक का मुख्य कार्य है। यद्यपि यह कार्य इम्पीरियल बैंक करता था परन्तु वह इन्हें समुचित ढंग से नहीं कर पाया था। अतः रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।

6. मुद्रा बाजार का समूह (Organisation of Money Market) रिजर्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य यह भी था कि भारतीय मुद्रा बाजार को सुसंगठित किया जाय तथा उसके दोषों को दूर किया जाय।

7. कोषों का केन्द्रीयकरण (Centralisation of Reserves) विभिन्न व्यापारिक बैंकों के कोषों को इकट्ठा कर उनका बैंकों की सहायता के लिए उपयोग भी रिजर्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य था। केन्द्रीय बैंक के रूप में इन कोषों की सहायता से बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण तथा नियमन किया जा सकता था।

8. अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्पर्क (International Monetary Relations) सप्तर के अन्य देशों तथा उनके केन्द्रीय बैंकों से मौद्रिक सम्पर्क स्थापित करना भी रिजर्व बैंक का उद्देश्य था।

उपर्युक्त कारणों से भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और 1 अप्रैल 1935 से इसने विधिवत कार्य करना प्रारम्भ किया।

इम्पीरियल बैंक को ही देश का केन्द्रीय बैंक क्यों नहीं बनाया गया ?
(Why was Imperial Bank of India not made the Central Bank of the Country ?)

केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक की स्थापना के समय कुछ लोग इम्पीरियल बैंक को ही केन्द्रीय बैंक के रूप में परिवर्तित करन का समर्थक थे। हिल्टन यंग कमीशन के सदस्य सर्व श्री पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास तथा एस० के० मुरजन इम्पीरियल बैंक को ही केन्द्रीय बैंक बनाने के पक्ष में थे परन्तु कुछ कारणोंवश इम्पीरियल बैंक

को केन्द्रीय बैंक नहीं बनाया गया (विस्तृत अध्ययन के लिए 'स्टेट बैंक आफ इन्डिया' अध्याय देखिए)

अशुभकारी बैंक के रूप में स्थापना (Establishment as a Shareholder's Bank) : रिजर्व बैंक आफ इन्डिया की स्थापना से पहले काफी विवाद का विषय रहा कि यह बैंक अशुभकारियों का बैंक हो या सरकारी बैंक हो। अशुभकारियों के बैंक के पक्ष में जा मुख्य तर्क दिए गए वे निम्नलिखित हैं—

1 राजनैतिक प्रभावों से मुक्त शुद्ध आर्थिक सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करने वाला बैंक केन्द्रीय बैंक देश के आर्थिक हितों को ध्यान में रखता है। अतः यह आवश्यक है कि वह राजनैतिक पक्षपात तथा भेद भाव से मुक्त होकर शुद्ध आर्थिक सिद्धान्तों के आधार पर स्वतन्त्रतापूर्वक अपना काम कर सके। यह तभी हो सकता है जब वह अशुभकारियों का बैंक हो।

2 प्रमुख देशों के केन्द्रीय बैंक अशुभकारियों के बैंक : 1934 तक सत्तार के प्रमुख देशों के केन्द्रीय बैंकों का संगठन अशुभकारियों के बैंक के रूप में हुआ था। अतः भारत में भी रिजर्व बैंक अशुभकारियों का बैंक होना चाहिए।

3. सभी हितों का प्रतिनिधित्व तथा उनकी रक्षा सभी व्यापारिक, औद्योगिक तथा अन्य हितों का प्रतिनिधित्व अशुभकारी व्यवस्था में ही हो सकता है तथा उन सभी के सहयोग से जो नीतियाँ निर्धारित हानी के वास्तव में उपयुक्त होंगी। कार्य क्षमता की दृष्टि से भी केन्द्रीय बैंक को अशुभकारियों का बैंक होना चाहिए।

4 जनमत अशुभकारी बैंक के पक्ष में अंग्रेजों के शासन काल में भारत सरकार को मुद्रा नीति राष्ट्र के हितों के विरुद्ध होती थी। अतः जनमत केन्द्रीय बैंक को सरकारी बैंक बनाने के विरुद्ध था।

उपरोक्त तर्कों के आधार पर 1934 में जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई तो उसका संगठन अशुभकारी बैंक के रूप में ही किया गया। रिजर्व बैंक की अधिकृत पूँजी 5 करोड़ रुपये थी जो 100-100 रुपये के 5 लाख अंशों में विभाजित थी। आरम्भ में केवल 2,20,000 रुपये के अंशों को छोड़कर शेष सभी पूँजी निजी अशुभकारियों के हाथों में थी। 1934 के एक्ट के अनुसार बैंक का संचालन एक केन्द्रीय संचालक मंडल द्वारा होता था जिसमें 16 सदस्य होते थे जिसमें गवर्नर तथा 2 डिप्टी गवर्नरों तथा 5 अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा तथा शेष 8 संचालक अशुभकारियों द्वारा चुने जाते थे। केन्द्रीय संचालक मंडल की जब प्रथम बार स्थापना हुई तो सोलहों नियुक्तियाँ गवर्नर जनरल ने की। दो-दो संचालक प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करते और उनका स्थान अशुभकारियों द्वारा निर्वाचित संचालक लेते। इस प्रकार अशुभकारियों द्वारा निर्वाचित संचालक पांच वर्ष बाद पूरे हुए। तब तक

उनके स्थान पर गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्तियां होती रही। इस प्रकार बैंक की रूपरेखा निश्चित करने में ब्रिटिश हितों का अधिक ध्यान रखा गया था।

रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Reserve Bank)

रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न बैंक की स्थापना के समय से ही उठाया जाता रहा है परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इसके पक्ष में जनमत और भी प्रबल हो गया। विभिन्न राजनैतिक तथा आर्थिक परिवर्तनों के फलस्वरूप रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण आवश्यक समझा गया। राष्ट्रीयकरण के पक्ष में मुख्य तर्क तथा कारण निम्न थे—

1. राजनैतिक स्वतन्त्रता तथा नियोजन का प्रारम्भ (Political freedom and planning era) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद तथा आर्थिक विकास के नियोजन की आवश्यकता के सदर्थ में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण आवश्यक समझा गया। ब्रिटिश शासन काल में सरकारी की राष्ट्र विरोधी नीतियों के कारण अशुभकारी व्यवस्था का औचित्य स्वीकार किया जा सकता था परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के सदर्थ में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण उपयुक्त समझा गया।

2. अन्य देशों के केन्द्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of major Central banks) : ससार के विभिन्न देशों में केन्द्रीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने भी भारतीय जनमत पर प्रभाव डाला। 1945 में कामन वेल्थ बैंक आफ आस्ट्रेलिया तथा बैंक आफ फ्रान्स तथा 1946 में बैंक आफ इंग्लैंड का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण के समर्थकों का तर्क था कि जब स्वस्थ प्रजातन्त्रीय परम्परा वाले तथा निजी साहम को पर्याप्त महत्व देने वाले देशों में भी केन्द्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है तो भारत में केन्द्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं हो।

3. आर्थिक तथा मौद्रिक नीतियों में सामन्जस्य (Coordination of economic and monetary policies) : रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण से सरकार की आर्थिक नीतियों तथा केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीतियों में अधिक सामन्जस्य स्थापित किया जा सकेगा जो कि आर्थिक विकास की तीव्र गति के लिए एक अति आवश्यक तत्व है। राष्ट्रीयकरण द्वारा इन दोनों नीतियों में होने वाले टकराव की भाग्यता समाप्त हो गई।

4. राष्ट्रीय तथा सामाजिक हितों की सुरक्षा (Protection of national and social interest) . एक सरकारी सस्था के रूप में ही रिजर्व बैंक सामाजिक

तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकेगा, नहीं तो यह डर सदा बना रहता कि जान या अनजान में बैंक का निजी स्वामित्व ऐसी नीतियों का अवलम्बन करता जो किसी वर्ग विशेष के दृष्टिकोण की प्रतिनिधि होती और राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकर सिद्ध होती।

5. बैंकिंग व्यवस्था पर समुचित नियंत्रण (Proper Control over banking system) : देश की बैंकिंग व्यवस्था पर समुचित नियंत्रण तथा नियमन के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रीय स्वामित्व वाला केन्द्रीय बैंक ही अधिक उपयुक्त होगा, नहीं तो वैधानिक अधिकारों के दुरुपयोग का भय बना रहेगा।

6 लाभ का सामाजिक हित में प्रयोग (Use of profits for the benefit of country) : सांख्यिक ऋणों के प्रयोग तथा मौद्रिक व्यवस्था के प्रवृत्ति से प्राप्त आय का प्रयोग राष्ट्रीय हितों के लिए होना चाहिए न कि निजी अंशधारियों को लाभान्वित करने के लिए। इसलिए बैंक का राष्ट्रीयकरण आवश्यक था।

इस प्रकार रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में अनेक महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए गये। राष्ट्रीयकरण के विरोधी तत्वों ने इसके विरुद्ध भी तर्क रखे— (1) राष्ट्रीयकरण से राजनैतिक हस्तक्षेप का भय रहेगा (2) कार्यक्षमता में कमी होगी (3) व्यापारिक तथा बैंकिंग परम्पराओं की अवहेलना होगी। वास्तव में रिजर्व बैंक अंशधारियों का बैंक होत हुए भी व्यवहार में सरकारी बैंक था क्योंकि गवर्नर, डिप्टी गवर्नर्स तथा सचिवों को नियुक्ति सरकार करती थी। रिजर्व बैंक तथा सरकार में सदा सहयोग रहा और उनकी नीतियों में कभी टकराव उपस्थित नहीं हुआ। अंशधारियों का बैंक होते हुए भी राष्ट्रीय हितों की अवहेलना कर निजी अंशधारियों के स्वार्थों की पूर्ति नहीं की गई। जब बैंक आफ इंग्लैंड तथा बैंक आफ फ्रान्स अंशधारी बैंक थे तो वे अंशधारियों को 12% लाभान्वित करते थे जबकि रिजर्व बैंक ने प्रारम्भ में केवल 3½% तथा बाद में 4% ही लाभान्वित दिया। रिजर्व बैंक के अंशधारी स्वामित्व काल में अंशधारियों को 2½ करोड़ रुपये से कुछ अधिक लाभान्वित मिला जबकि राज्य कोष को 80 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। शायद राष्ट्रीयकरण का मुख्य कारण स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रारम्भ काल में राष्ट्रीयकरण की नीति के प्रति सरकार का अति उत्साह था। राष्ट्रीयकरण से एक विशेषज्ञ संस्था के स्वतन्त्र विचारों तथा निर्णयों का लाभ हमने खो दिया। बैंक आफ इंग्लैंड तथा वाशिंगटन पोस्ट बैंक आफ अस्ट्रेलिया के राष्ट्रीयकरण के बाद भी उनके विचारों की स्वतन्त्रता तथा स्वायत्तता की वैधानिक रूप में रक्षा की गई परन्तु रिजर्व बैंक के सम्बन्ध में ऐसा नहीं हुआ।

राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध उठाई गई आपत्तियों के बावजूद सरकार ने रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया। भारतीय विधान सभा में 1948 में रिजर्व बैंक

(सार्वजनिक स्वामित्व हस्तान्तरण) अधिनियम [Reserve Bank (Transfer to Public Ownership) Act] पारित किया गया और 1 जनवरी 1949 से रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। प्रत्येक 100 रुपये अंश पर 118 रुपये 10 आने की दर से मुआवजा दिया गया जो 3% व्याज दर के दीर्घकालीन प्रतिभा-
पत्रों के रूप में था।

रिजर्व बैंक का वर्तमान संगठन

(Present Organisation of Reserve Bank)

1 पूँजी (Capital) रिजर्व बैंक की अधिकृत पूँजी 5 करोड़ रुपये है जो 100-100 रुपये के 5 लाख अंशों में विभाजित है। राष्ट्रीयकरण से पहले 2,20,000 रुपये के अंशों को छोड़कर शेष सभी अंश निजी अंशधारियों के पास थे। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् सभी अंशों के द्रीय सरकार के पास हैं।

2 प्रबंध (Management) बैंक का प्रबंध एक केन्द्रीय संचालक मंडल (Central Board of Directors) द्वारा किया जाता है जिसकी सदस्य संख्या 20 होती है। इसमें एक गवर्नर तथा चार डिप्टी गवर्नर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चार संचालक चारों स्थानीय मंडलों से मनोनीत किए जाते हैं तथा दस संचालक और एक सरकारी अधिकारी भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दस संचालकों में प्रायः व्यापार, उद्योग वित्त तथा सहकारिता विशेषज्ञ होते हैं और सरकारी अधिकारी भारत सरकार का वित्त सचिव होता है। गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नरों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। स्थानीय मंडलों से मनोनीत सदस्य स्थानीय मंडल की सदस्यता का नाम ही केन्द्रीय संचालक मंडल के सदस्य रह सकते हैं। शेष दस संचालकों का कार्यकाल चार वर्ष का होता है। सरकारी कर्मचारी सरकार द्वारा निर्धारित समय के लिए संचालक बनना रह सकता है परन्तु उसे मतदान का अधिकार नहीं होता।

गवर्नर संचालक मंडल का अध्यक्ष तथा बैंक का प्रधान कार्यकर्ता होता है। केन्द्रीय संचालक मंडल के निर्देशन के अधीन बैंक की समस्त शक्ति गवर्नर में निहित होती है। चार उप गवर्नर, जिनमें प्रत्येक की देखरेख में बैंक के विभिन्न विभागों का कार्य होता है, बैंक के कार्य को ठीक प्रकार चलाने में गवर्नर की सहायता करते हैं। गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर बैंक के पूर्णकालिक अधिकारी (Full time officers) होते हैं और उन्हें निर्धारित वेतन दिया जाता है। शेष संचालक केवल अंशकालिक होते हैं और उन्हें बैंकों में भाग लेने के लिए यात्रा व्यय तथा भत्ता ही दिए जाते हैं।

केन्द्रीय संचालक मंडल के अतिरिक्त चार स्थानीय मंडल (Local Boards) की भी व्यवस्था है जो दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हैं। इनमें 5-5

सदस्य होते हैं और जो भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह मुख्यतः क्षेत्रीय तथा आर्थिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्थानीय मंडल के सदस्य अपने-अपने से एक अध्यक्ष चुन लेते हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और वे पुनर्नियुक्त किए जा सकते हैं। स्थानीय मंडल केन्द्रीय मंडल द्वारा सौंपे हुए कार्यों को चलाने तथा उनकी देखरेख करने का उत्तरदायी है।

रिजर्व बैंक के कार्य

(Functions of the Reserve Bank)

रिजर्व बैंक वे सभी कार्य करता है जिनका उल्लेख केन्द्रीय बैंक के कार्यों के अंतर्गत किया गया है। रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य 'मौद्रिक स्थायित्व की प्राप्ति के लिए नोट निर्गमन को नियंत्रित करना तथा कोषों को रखना है और देश के हित में मुद्रा तथा साख व्यवस्था का संचालन करना है।' ¹ एक विकासशील देश होने के नाते भारत में रिजर्व बैंक को कृषि साख, औद्योगिक वित्त इत्यादि के क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंपा गया है। रिजर्व के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :

1 नोट निर्गमन का एकाधिकार (Monopoly of note issue) देश की मुद्रा तथा साख व्यवस्था पर पूर्ण तथा व्यापक नियंत्रण करने के लिए रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार दिया गया है। नोट निर्गमन के लिए रिजर्व बैंक के दो विभाग हैं—निर्गमन विभाग तथा बैंकिंग विभाग। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 44 के अनुसार रिजर्व बैंक 2, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 तथा 10 000 रुपये के नोट निर्गमित कर सकता है परन्तु बैंक ने 2, 5, 10, 100 1000 तथा 10,000 रुपये के नोट ही निर्गमित किए हैं। 1000 तथा 10,000 रुपये के नोट 1946 में चलन से वापिस ले लिए गये थे परन्तु 1954 में उन्हें फिर निर्गमित किया गया। रुपये के सिक्के एच. रेजगारिया (सहायक सिक्के) भारत सरकार जारी करती है। एक रुपये के नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं और उन्हें एक रुपये के सिक्को की श्रेणी में रक्षित जाता है। रिजर्व बैंक अपने नोटों को सिक्को में और सिक्को को नोटों में बदलने का भी कार्य करता है।

रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 33 के अनुसार 'निर्गमन विभाग को सम्पत्तियां, जिनके आधार पर नोट निर्गमित किए जाते हैं, स्वर्ण के सिक्को तथा पाट, विदेशी प्रतिभूतियों, रुपये के सिक्को, भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों तथा

¹ The main function of the Reserve Bank of India is "to regulate the issue of the bank notes and keeping of reserves with a view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage"

बैंक द्वारा ऋण के लिए स्वीकृत विनिमय बिलो तथा प्रोमजरी नोटो के रूप में रक्खी जानी चाहिए।" 1935 से अक्टूबर 1956 तक रिजर्व बैंक "अनुपातिक कोप प्रणाली" (Proportional Reserve System) के आधार पर नोट निर्गमित करता था। इस प्रणाली के अन्तर्गत कुल निर्गमित नोटो का 40 प्रतिशत स्वर्ण, स्वर्ण सिक्को तथा विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रखना अनिवार्य था जिसमें 40 करोड़ रुपये का स्वर्ण रखना आवश्यक था। परन्तु पचवर्षीय योजनाओं की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हीनार्थ प्रवन्धन (Deficit financing) करना पडा तथा नोट निर्गमन के पीछे 40 प्रतिशत कोप रखना कठिन हो गया। 5 अक्टूबर 1956 को कुल 1431 करोड़ रुपये के नोट चलन में थे जबकि कोप में केवल 40 02 करोड़ रुपये का स्वर्ण तथा 587 करोड़ रुपये का विदेशी विनिमय शेष रह गया था। इस प्रकार कुल कोप नोटो की मात्रा का केवल 43.80 प्रतिशत रह गया था। अतः 6 अक्टूबर 1956 से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम में सशोधन कर अनुपातिक कोप प्रणाली के स्थान पर "न्यूनतम कोप प्रणाली" (Minimum Reserve System) अपनायी गई। इस सशोधन के अनुसार निर्गमित नोटो के पीछे 515 करोड़ रुपये का न्यूनतम कोप रक्खा जाना था जिसमें 115 करोड़ रुपये का न्यूनतम स्वर्ण रखना आवश्यक था और शेष विदेशी प्रतिभूतियों में। साथ साथ स्वर्ण कोप का पुनर्मूल्यन किया गया और जो स्वर्ण पहले 8 475 12 ग्रेन प्रति रुपया या 21 24 रुपये प्रति तोला की दर से आका जाता था अब अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोप द्वारा स्वीकृत 2.88 ग्रेन प्रति रुपया या 62 50 रुपये प्रति तोला की दर से आका जाने लगा। इस प्रकार 40 02 करोड़ रुपये के स्वर्ण का मूल्य बढ़कर 117 76 करोड़ रुपये हो गया।

विदेशी विनिमय संकट के कारण इतना कोप बनाये रखना भी सम्भव नहीं रह सका। 25 अक्टूबर 1957 को विदेशी विनिमय कोपो की मात्रा घटकर केवल 312 करोड़ रुपये रह गई। अतः रिजर्व बैंक अधिनियम में 31 अक्टूबर 1957 को द्वितीय सशोधन कर निर्गमित नोटो के पीछे रक्खी जाने वाले कोपो की मात्रा घटाकर 200 करोड़ रुपये कर दी गई। अब इस सशोधन के अनुसार रिजर्व बैंक

² नोटो को सिक्को तथा सिक्को को नोटो में बदलने की उक्त क्रिया के आधार पर कुछ लेखको ने यह निष्कर्ष निकाला है कि रिजर्व बैंक के नोट परिवर्तनीय पत्र मुद्रा (Convertible Paper Money) हैं। परन्तु यह दृष्टिकोण भ्रामक है। परिवर्तनीय पत्र मुद्रा तो वह मुद्रा है जिसके बदले में पूर्णकाय धातु मुद्रा (Full bodied metallic Coins) प्राप्न की जा सके। अतः यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित नोट 'अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा' (Inconvertible Paper Money) ही हैं।

को 200 करोड़ रुपये का न्यूनतम कोस रखना अनिवार्य है जिसमें 115 करोड़ रुपये का स्वर्ण तथा शेष की विदेशी प्रतिभूतियां होनी चाहिये। विदेशी प्रतिभूतियों की कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि भारत सरकार की पूर्वाज्ञा प्राप्त कर रिजर्व बैंक विदेशी प्रतिभूतियों को पूर्णतया समाप्त कर सकता है और इस प्रकार केवल 115 करोड़ रुपये के स्वर्ण के आधार नोट निर्गमित किए जा सकते हैं।

मार्च 1969 में रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित नोटों की राशि 3453.50 करोड़ रुपये थी।

(2) सरकारी बैंक के रूप में कार्य करना (Banker to the Government):—रिजर्व बैंक केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बैंक तथा वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की ओर से हथिया जमा करना, उनकी ओर से भुगतान करना, उनकी विनिमय मुद्रा हस्तान्तरण तथा अन्य बैंकिंग प्रक्रियाओं को करना तथा उनके सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था करना रिजर्व का मुख्य कार्य है। इस प्रकार रिजर्व बैंक सरकार के एजेंट के रूप में वे सभी कार्य करता है जो एक बैंक अपने ग्राहकों के लिए करता है। जहाँ रिजर्व बैंक की शाखाएँ नहीं हैं वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में यह सब कार्य करता है।

सरकारों के साधारण बैंकिंग कार्यों के लिए रिजर्व बैंक को कोई कमीशन नहीं दिया जाता। इन कार्यों के करने के बदले रिजर्व बैंक सरकारी खानों में जमा रकम पर कोई ब्याज नहीं देता। रिजर्व बैंक का सरकारी ऋण विभाग (Public Debt Department) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋणों का प्रबन्ध करता है। बैंक सरकारों की ओर से सरकारी प्रतिभूतियां जारी करता है, उनका धन एकत्रित करता है, उन पर ब्याज भुगतान करता है, उनकी प्रवृद्धि पूर्ण होने पर उनका मूल धन वापिस करता है तथा तत्सम्बन्धी हिसाब किताब रखता है। रिजर्व बैंक सरकार के 3 मास के कोषागार विपन्न (Treasury Bills) भी बेचता है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक अस्थायी ऋण (Ways and Means Advances) भी देता है। यह ऋण अधिक से अधिक 90 दिनों के लिए दिए जा सकते हैं और इन पर बैंक दर से एक प्रतिशत कम ब्याज लिया जाता है। उपर्युक्त सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था के लिए रिजर्व बैंक को 2000 रुपया प्रति करोड़ प्रतिवर्ष की दर से कमीशन मिलता है।

रिजर्व बैंक सरकार की विदेशी विनिमय की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जिससे सरकारी खाते में आयात किए गये माल का भुगतान किया जा सके। इस-

लिए सन्दन में भारतीय हाई कमीशन जो विदेशों में भारत का मुख्य क्रेता तथा वित्तीय सस्था है, को पर्याप्त सहायता देता है।

इसके अनिरीक्त रिजर्व बैंक सरकार के मुख्य सलाहकार का कार्य करना है और नये ऋणों के निर्गमन, पुरानों का परिवर्तन, कोषों का विनियोजन, कृषि साख, सहकारिता, बैंकिंग तथा साख, कानून आदि विषयों पर सरकार को सलाह देना है।

(3) बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना (Banker's Bank) :—रिजर्व बैंक वित्तीय तन्त्र का शीर्ष होने के नाते बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। रिजर्व बैंक को भारतीय बैंकिंग अधिनियम के अन्तर्गत बैंक का नियन्त्रण तथा नियमन करने के लिए व्यापक अधिकार दिए गये हैं। रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों (Scheduled Banks) से मीधे सम्पर्क में आता है। अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जिनकी प्रदत्त पूंजी तथा संचित कोष कम से कम 5 लाख रुपये हैं, वह कम्पनी या कारपोरेशन की भाँति पंजीयत है और उसके कार्य जमाकर्ताओं के हितों के विरुद्ध नहीं हैं। ऐसे बैंकों का नाम रिजर्व बैंक आफ इन्डिया एक्ट 134 की द्वितीय अनुसूची (Second Schedule) में सम्मिलित कर लिया जाता है। इन अनुसूचित बैंकों को विधान की धारा 42 के अनुसार अपने काल देयों (Time liabilities) का 2% तथा माग देयों (Demand Liabilities) का 5% रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता था। 1956 के संशोधन के अनुसार रिजर्व बैंक को अनुसूचित बैंकों के इन कोषों की मात्रा को कालदेयों के सम्बन्ध 2% से 8% तक माग देयों के सम्बन्ध में 5% से 20% तक परिवर्तित करने का अधिकार दिया गया। सितम्बर 1962 के संशोधन के अनुसार काल तथा माग देयों के इस भेद को समाप्त कर अनुसूचित बैंकों को उनके कुल देयों (Total liabilities) का 3% रिजर्व बैंक के पास जमा कराना अनिवार्य कर दिया गया। रिजर्व बैंक इस सीमा को बढ़ाकर 15% तक कर सकता है। इसके साथ-साथ अनुसूचित बैंकों को भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक के पास प्रति सप्ताह बैंक की प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में एक विवरण भेजना पड़ता है। उक्त दायित्वों की पूर्ति न करने पर बैंक पर जुर्माना किया जा सकता है तथा उसके विरुद्ध अन्य कार्यवाही की जा सकती है।

उपर्युक्त दायित्वों के प्रतिफल स्वरूप अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक से कुछ सुविधायें प्राप्त हो जाती हैं। (1) रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों द्वारा बढ़ा किए हुए विनिमय पत्रों का पुनः बढ़ा करता है। रिजर्व बैंक प्रथम श्रेणी के ऐसे व्यावसायिक विनिमय पत्रों का कय-विक्रय तथा बढ़ा करता है जिनकी अवधि 90 दिन से अधिक की न हो तथा यदि वे कृषि विनिमय पत्र हैं तो उनकी अवधि 15 मास से अधिक न हो। (ii) स्वीकृत प्रतिभूतियों के आधार पर रिजर्व बैंक अनुसूचित तथा राज्य सह-

कारी बैंकों को 90 दिनों की अवधि तक के लिए ऋण देता है तथा (iii) अनुसूचित बैंको की मुद्रा का सस्ती दर पर स्थानान्तरण करता है। इस प्रकार आपत्ति काल में अन्तिम ऋण दाता (Lender of last resort) के रूप में कार्य करता है और बैंको को कठिनाई के समय ऋण सुविधा देकर उनकी सहायता करता है।

बैंकिंग नियमन अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को बैंको पर यथेष्ट नियन्त्रण रखने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं—

(प्र) लाइसेंस (Licence) :—धारा 22 के अनुसार प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी को रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। लाइसेंस देते समय रिजर्व बैंक यह देखता है कि बैंक की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वह अपने जमा देय धन का पूर्ण भुगतान कर सकता है और उसके कार्य जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।

(ब) शाखा विस्तार (Branch expansion):—अधिनियम की धारा 23 के अनुसार बैंको द्वारा नवीन शाखाएँ खोलने तथा शाखाओं के स्थान परिवर्तन के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

(स) निरीक्षण (Inspection):—अधिनियम की धारा 35 के अनुसार रिजर्व बैंक किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है और अधिनियम की विभिन्न धाराओं के सम्बन्ध में उसकी स्थिति की जांच कर सकता है। धारा 36(1)(d)(v) के अन्तर्गत रिजर्व बैंक यदि, आवश्यक हो तो बैंको के प्रबन्ध में भी परिवर्तन कर सकता है।

(द) विलयन तथा अवसायन (Amalgamation and Liquidation) — अधिनियम की धारा 44 A के अनुसार विलयन से पहले रिजर्व बैंक की आज्ञा लेना अनिवार्य है। विलयन के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक की नीति ऐसे विलयन को प्रोत्साहन देना है जिनमें जमाकर्ताओं के हित सुरक्षित हों तथा उस क्षेत्र में उन बैंको के विलयन से बैंक व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होती हो। जिन बैंको की स्थिति अधिक बिगड़ जाती है उनके अवसायन के लिए रिजर्व बैंक को अधिकार प्राप्त है।

(य) बैंकिंग विकास (Banking Development) :— अक्टूबर 1950 से रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विकास विभाग खोलकर देश में बैंकिंग सुविधाओं के विकास तथा विस्तार में अधिक सहायता देना प्रारम्भ किया है।

इस प्रकार अब रिजर्व बैंक अनुसूचित तथा गैर अनुसूचित बैंको पर पर्याप्त नियन्त्रण तथा नियमन करता है।

(4) विनिमय स्थायित्व की स्थापना (Maintenance of Exchange Stability):—रिजर्व बैंक भारतीय रुपये के विनिमय मूल्य में स्थिरता बनाये रखने

का प्रयत्न करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रिजर्व बैंक के पास विदेशी विनिमय के पर्याप्त कोष रहते हैं तथा विनिमय नियन्त्रण की एक उत्तम व्यवस्था का संगठन करता है।

(5) समाशोधन गृहों का प्रबन्ध (Management of Clearing Houses):—बैंको का बैंक तथा आपत्तिकाल में अन्तिम ऋणदाता के रूप में रिजर्व बैंक समाशोधन गृहों का प्रबन्ध भी करता है। जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक की शाखाएँ नहीं हैं वहाँ स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंक इनका प्रबन्ध करते हैं।

(6) आर्थिक सांख्यिकी का प्रकाशन (Publication of Economic Statistics)—देश की अर्थ व्यवस्था में विभिन्न आर्थिक, वित्तीय तथा मौद्रिक विषयों से सम्बन्धित सांख्यिकी का संग्रह तथा प्रकाशन रिजर्व बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है।

(7) साख नियन्त्रण (Credit Control).—रिजर्व बैंक देश की मुद्रा व्यवस्था के साथ-साथ व्यवस्था पर नियन्त्रण तथा नियमन रखता है जिससे देश की आर्थिक नीतियाँ सफल हो सकें। आगे हम इसी विषय की विस्तार से व्याख्या करेंगे।

साख-नियन्त्रण तथा नियमन (Regulation and Control of Credit)

मुद्रा निर्गमन के साथ-साथ देश की साख व्यवस्था को नियन्त्रित तथा नियमित करने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक का है। डा० डी० काक (Dr De Kock) के शब्दों में—“साख नियन्त्रण ऐसा कार्य है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकिंग नीति के महत्वपूर्ण पक्ष आ जाते हैं तथा व्यवहारिक रूप में इससे सभी अन्य कार्य जुड़े हुए हैं और एक सम्मिलित उद्देश्य की प्राप्ति कराते हैं।”¹ साख नियन्त्रण के कार्य द्वारा केन्द्रीय बैंक देश की मौद्रिक नीति के तीन उद्देश्यों—आन्तरिक कीमत तल में स्थायित्व, विनिमय दर में स्थायित्व तथा ऊँची आय और रोजगार के स्तर पर आर्थिक स्थायित्व की प्राप्ति का प्रयत्न करता है।

रिजर्व बैंक के साख-नियन्त्रण तथा नियमन के अधिकारों का आधार रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट 1934 तथा बैंकिंग नियमन एक्ट 1949 हैं। रिजर्व बैंक द्वारा साख नियन्त्रण के निम्नलिखित अस्त्र प्रयोग में लाये गये हैं

- (1) बैंक दर नीति (Bank Rate Policy)
- (2) खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operations)

¹ “Credit control is the function which embraces the most important questions of central banking policy and the one through which practically, all other functions are united and made to serve a common purpose”
—De Kock

- (3) परिवर्तनशील कोषानुपात (Variable Reserve Ratios)
- (4) प्रवृत्त्य साख नियन्त्रण (Selective Credit Controls)
- (5) नैतिक अनुनय (Moral Suasion)

(1) बैंक दर नीति (Bank Rate Policy)

बैंक दर नीति की परिभाषा है—'विस्तृत दृष्टिकोण से, उन शर्तों तथा दशाग्रो में परिवर्तन करना जिनके अन्तर्गत बाजार चुनी हुई अल्पकालीन परि-सम्पत्तियों का बढ़ा करारकर या रक्षित अग्रिम द्वारा केन्द्रीय बैंक से अल्पकालीन सहा-यता ले सके।'¹ अतः बढ़ा नीति साख की लागत तथा प्राप्यता दोनों को प्रभावित करती है। (Discount policy seeks to affect both the cost and the availability of Credit) रिजर्व बैंक बैंक दर में परिवर्तन कर साख की मात्रा तथा उसकी लागत पर प्रभाव डालकर साख का नियन्त्रण तथा नियमन करता है। बैंक दर द्वारा साख नियन्त्रण की सप्रभाविकता इस बात पर निर्भर करता है कि देश के व्यापारिक बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थायें ऋण लेने के लिए किम सीमा तक केन्द्रीय बैंक पर निर्भर करते हैं।

रिजर्व बैंक की 1935 में स्थापना से लेकर नवम्बर 1951 तक बैंक दर 3 प्रतिशत बनी रही। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बाद में हुए परिवर्तनों तथा उसके कारणों और प्रभावों का विवेचन इस प्रकार है।

प्रथम परिवर्तन (28 नवम्बर 1935): रिजर्व बैंक की स्थापना के 8 महीने बाद बैंक की बैंक दर 3½ प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दी गई। इसका प्रभाव यह हुआ कि इम्पीरियल बैंक की दर में भी कमी हो गई परन्तु बाजार दर दिसम्बर 1935 में 1 प्रतिशत से बढ़ गई।

द्वितीय परिवर्तन (15 नवम्बर 1951): में अत्यधिक साख विस्तार तथा भुगतान शेष के असंतुलन की कठिनाई पर विजय पाने के लिए 15 नवम्बर 1951 को रिजर्व बैंक ने बैंक दर 3 प्रतिशत से 3½ प्रतिशत कर दी। कारिवाई युद्ध के कारण देश के कीमत-तल में लगातार वृद्धि हो रही थी। अनेक दलों ने साख प्रसार

¹ The Bank Rate Policy may be defined as "the varying of the terms and of the conditions, in the broadest sense, under which the market may have temporary access to the central bank through discounts of selected short term assets or through secured advances"

— *The Reserve Bank of India, Functions and Working, 1959,*
p. 28.

को नियन्त्रित करने के लिए बैंक दर में वृद्धि कर दी थी। बैंक दर की इस वृद्धि के साथ रिजर्व बैंक ने यह घोषणा भी की कि वह आगामी व्यस्त काल में बैंको की मौसमी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिभूतियां नहीं खरीदेगा परन्तु उनकी धरोहर पर ऋण देता रहेगा।

बैंक दर में वृद्धि के फलस्वरूप सभी व्याज दरों में वृद्धि हो गई और पिछले चार वर्षों का साख विस्तार नियन्त्रित किया जा सका। ऋण लेना महंगा हो जाने के कारण 1950-51 के व्यस्त काल में अग्रिमों में जो 182 करोड़ की वृद्धि हुई थी, 1951-52 में वह वृद्धि केवल 62 करोड़ रुपये की हुई।

तृतीय परिवर्तन (1 फरवरी 1957) : बैंक दर में तीसरा परिवर्तन उस समय किया गया जब साख-विस्तार तथा भुगतान शेष के असंतुलन की गम्भीर स्थिति से निपटने के लिए सावधि बिलों पर मुद्रा के कर में वृद्धि होने पर धारा 17 (4) (स) के अन्तर्गत बिलों तथा स्वीकृत प्रतिभूतियों की धरोहर पर ऋणों की व्याज दर 1 फरवरी 1957 को बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दी गई। 3 माह तक बैंक दर और षट्ठी दर में अन्तर रहा। 15 मई 1957 से यह अन्तर तब समाप्त हो गया जब बिलों पर अग्रिम-दर भी 3½ प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दी गई। फलस्वरूप अन्य बाजार दरों में तदनु रूप परिवर्तन हुआ।

कोटा स्लेब दर व्यवस्था (Quota-cum-Slab Rate System) : रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर 1960 से एक बैंक दर के बजाय 3 दरें अपनायी। निश्चित अभ्यक्ष तक तो ऋण बैंक दर और उससे अधिक ऋण लेने पर दण्ड स्वरूप अधिक व्याज लिया जाता था। 2 जुलाई 1962 को तीन से चार तथा 31 अक्टूबर 1962 से फिर तीन दरें अपनायी गईं। 3 जनवरी 1963 को इस व्यवस्था में फिर परिवर्तन किया गया।

चतुर्थ परिवर्तन (2 जनवरी 1963) : रिजर्व बैंक ने 2 जनवरी 1963 से बैंक दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 4½ प्रतिशत कर दी। स्लेब दर पद्धति में परिवर्तनों को औपचारिक रूप देने के लिए वृद्धि की गई। चीनी आक्रमण तथा साख विस्तार और मुद्रा स्फीति को नियन्त्रित करने के लिए बैंक दर में वृद्धि आवश्यक हो गई थी।

पंचम परिवर्तन (25 सितम्बर 1964) : 1964-65 के व्यस्तकाल में साख विस्तार को और नियन्त्रित करने के लिए बैंक दर को 4½ प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया। साथ ही ऋण देने की 'कोटा-स्लेब प्रणाली (Quota-cum-Slab Rate System)' के स्थान पर एक नई प्रणाली (Differential System of Interest Rates) अपनायी गई जिसके अन्तर्गत ऋणों पर व्याज दर

बैंक की शुद्ध तरलता स्थिति (Net Liquidity Ratio) से सम्बन्धित कर दी गई। शुद्ध तरल स्थिति को 'बैंको के काल तथा मांग दायित्वों से तरल परिसम्पत्तियों के अनुपात' के रूप में परिभाषित किया गया। 28 प्रतिशत या इससे अधिक शुद्ध तरलता अनुपात तक तो बैंक दर पर और फिर प्रति 1 प्रतिशत तरलता अनुपात की कमी पर कुल ऋण राशि पर $\frac{2}{3}$ प्रतिशत अधिक ब्याज दर ली जाने लगी।

छठा परिवर्तन (17 फरवरी 1965) : साख सकुचन के विभिन्न कदम उठाने के बावजूद कीमत तल तथा विदेशी विनिमय समस्या बनी ही रही। इसी दिशा में फिर 17 फरवरी 1965 को बैंक दर में पूरे एक प्रतिशत की वृद्धि कर उसे 6 प्रतिशत कर दिया गया और शुद्ध तरलता अनुपात को 28 प्रतिशत से बढ़ा कर 30 प्रतिशत कर दिया गया। इस प्रकार साख की लागत में और वृद्धि कर दी गई।

सप्तम परिवर्तन (2 मार्च 1968) : मार्च 1968 में रिजर्व बैंक की बैंक दर नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। 1967 में उद्योगों में मन्दी की प्रवृत्तियाँ दिखाई देने लगी। 1967-68 के व्यस्त काल में कृषि उत्पादन में वृद्धि के कारण कृषिजन्य पदार्थों की कीमतें गिरने लगी। साख का विस्तार अनुमान से कम हुआ। उद्योगों में मन्दी की प्रवृत्तियाँ (Recessionary Trends) चालू रही। फलतः साख उदार नीति (Credit Liberalisation Policy) के अनुरूप आर्थिक उत्तेजना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से (In order to provide more positive stimulus towards economic recovery) बैंक दर को 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया।

इससे पहले वित्त-मन्त्री ने अर्थ व्यवस्था को पुनर्जीवित करने तथा पूँजी निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए 1968-69 के बजट में बहुत सी प्रशुल्क छूटों (Fiscal incentives) की घोषणा की थी। उसी के फौरन बाद आर्थिक सुधार की सामान्य नीति के अनुसार तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि के कारण रिजर्व बैंक ने मौद्रिक क्षेत्र में साख को सस्ता करने के लिए बैंक दर को 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया। बैंक दर में कमी का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अर्थिक क्रय शक्ति उत्पन्न करना था। इस प्रकार यह कमी रिजर्व बैंक की महंगी मुद्रा नीति से सस्ती मुद्रा नीति का प्रारम्भ है। (The significant cut in bank rate no doubt marks a sharp reversal of dear money policy whose virtues the Reserve Bank has sung *ad nauseum* even in the face of deep resentment among industrial circles) अतः रिजर्व बैंक की यह नई मौद्रिक नीति भारत सरकार द्वारा अर्थ-व्यवस्था को पुनरोत्तेजित करने के लिए अपनायी गई कार्रगारी प्रशुल्क नीति के

साथ साथ चलती है। इसके पहले देश में प्रशुल्क तथा मौद्रिक नीतियों का इतना सुन्दर तथा सामयिक समिश्रण कभी नहीं देखा गया (Never in the past had the country witnessed such a harmonious and timely union of fiscal and monetary policies)

बैंक दर में कमी का औद्योगिक तथा वित्तीय क्षेत्रों में बड़ा स्वागत हुआ। बैंक दर में कमी को "welcome shot in the arms for industry" की संज्ञा दी गई।

(2) खुले बाजार की क्रियायें (Open Market Operations)

रिजर्व बैंक आफ इन्डिया एक्ट की धारा 17 (8) के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और स्वायत्त संस्थाओं के द्वारा नियमित किमी भी अवधि की प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय का अधिकार प्राप्त है। धारा 17 (2) (घ) के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को अल्पकालीन विनिमय पत्रों के क्रय विक्रय का भी अधिकार है। इस प्रकार प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय द्वारा रिजर्व बैंक या तो बैंक दर की प्रभाविकता को बढ़ाने या स्वतन्त्र रूप से साख के नियमन का कार्य करता है। प्रारम्भ से ही रिजर्व बैंक खुले बाजार की क्रियायें करता रहा है।

खुले बाजार की क्रियाओं की प्रभाविकता तथा सफलता तीन बातों पर निर्भर करती है - (1) रिजर्व बैंक के साधन (2) उन परिसम्पत्तियों की किस्म तथा मात्रा जिनका रिजर्व बैंक क्रय विक्रय कर सकता है तथा (3) मुद्रा बाजार का समूह जिसमें यह क्रियायें होनी हैं। यद्यपि भारत में न्यूयार्क तथा लन्दन जैसे विकसित मुद्रा बाजार नहीं हैं परन्तु फिर भी बम्बई का मुद्रा बाजार पर्याप्त विकसित है। अमेरिका या इंग्लैंड की तरह भारत में खुले बाजार की क्रियायें मुख्य रूप से कोषागार-विपन्नो में सीमित नहीं हैं। भारत में खुले बाजार की क्रियायें मुख्यतः सरकारी बाण्डों में होती हैं। भारत में अनुसूचित बैंकों को अपने कुल दायिगों का 25 प्रतिशत तरल परिसम्पत्तियों के रूप में रखना होता है और इसलिए अनुसूचित बैंक तरल परिसम्पत्तियों का अधिकांश भाग सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखते हैं। व्यस्त काल में वे बैंक उन प्रतिभूतियों को बेचकर (या उनकी धरोहर पर ऋण प्राप्त कर) उद्योग तथा वाणिज्य की साख-प्रावश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। खुले बाजार की क्रियायें साख की सामान्य स्थिति तथा बैंकों की प्रावश्यकताओं से ही प्रेरित नहीं होती बल्कि सरकार की ऋण प्रावश्यकताओं से भी प्रभावित होती हैं। सरकारी बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक का यह कर्तव्य है कि परम प्रतिभूति बाजार (Gilt Edged Market) में सरकार द्वारा ऋण जन तथा भुगतान के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करे। दूसरी ओर सरकार की ऋण प्रक्रियायें इस प्रकार आयो-

जित हो कि जहाँ तक सम्भव हो, वे मुद्रा तथा पूँजी बाजारों की सामान्य स्थिरा के अनुरूप हो।

द्वितीय महायुद्ध के पहले रिजर्व बैंक की खुले बाजार की क्रियाएँ बहुत क थीं। युद्धोपरान्त खुले बाजार की क्रियाओं की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई। 1948-49 तथा 1950-51 में रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का त्रय विशेष रूप से अधिक था। बैंक की सापेक्षिक रूप से स्वतन्त्र क्रय की इस नीति में नवम्बर 1951 में संशोधन किया गया। यह संशोधित नीति पांच वर्षों तक चलती रही। नवम्बर 1956 से मुद्रा बाजार में वृद्धि के अभाव को दूर करने के लिए सरकारी ऋण पत्र के क्रय की नीति अपनायी गई। ऋण पत्रों के त्रय-वितरण के अतिरिक्त बैंक अन्तर क्रियाएँ (Switch Operations) [अर्थात् एक प्रकार के ऋण पत्रों को बैंक दूसरों को खरीदना] भी करता है। जून-जुलाई 1957 से बैंक ने फिर प्रतिभूतियों को अधिक मात्रा में बेचना प्रारम्भ कर दिया। 1960 में साख की कमी को दूर करने के लिए बैंक ने अधिक मात्रा में प्रतिभूतियों को खरीदा।

(3) परिवर्तनशील कोषानुपात (Variable Reserve Ratios)

रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया एक्ट की धारा 42 (1) के अनुसार अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक के पास अपने मांग दायित्वों (Demand Liabilities) का प्रतिशत तथा काल दायित्वों का 2 प्रतिशत नकद के रूप में जमा करना अनिवार्य था।¹ 1956 में एक्ट के संशोधन द्वारा रिजर्व बैंक को मांग दायित्वों की प्रतिशत सीमा को 5 से 20 के बीच तथा काल दायित्वों की प्रतिशत सीमा को 2 से 8 प्रतिशत के बीच परिवर्तित करने का अधिकार प्राप्त हो गया।

रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया द्वारा परिवर्तनशील कोषानुपात की रीति का प्रयोग सर्वप्रथम 11 मार्च 1960 को किया गया जब कोषानुपात के अतिरिक्त मांग तथा काल दायित्वों में वृद्धि का 20 प्रतिशत अतिरिक्त नकद को रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य हो गया। 6 मई 1960 से इस प्रतिशत को बढ़ाकर 50 कर दिया

¹. बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 18 के अनुसार गैर अनुसूचित बैंकों को भी अपने पास या रिजर्व बैंक के पास अथवा दोनों के पास अपने काल दायित्वों का 2 प्रतिशत तथा मांग दायित्वों का 5 प्रतिशत नकद के रूप में रखना आवश्यक था। सितम्बर 1962 के संशोधन के अनुसार गैर-अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक के पास या अपने पास अपने कुल मांग तथा काल दायित्वों का 3 प्रतिशत नकद रूप में रखना पड़ता है।

गया। अनिरीक्त नकद कोपो पर ब्याज देने की भी व्यवस्था की गई। 11 नवम्बर 1960 से अशत तथा 13 जनवरी 1961 से पूर्णतः प्रतिरिक्त जमा सम्बन्धी व्यवस्था समाप्त कर दी गई।

5 सितम्बर 1962 के सशोधन द्वारा अनुसूचित बैंको को रिजर्व बैंक के पास भवनी कुल जमापो का 3 प्रतिशत अनिवाय रूप से जमा करना पड़ता है तथा रिजर्व बैंक आवश्यकतानुसार इसको बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक कर सकता है। इस प्रकार अब माग तथा काल दायित्वों का भेद समाप्त कर दिया गया है।

(4) प्रवृत्त्य साख नियन्त्रण (Selective Credit Controls)

विशिष्ट उद्देश्यों अथवा आर्थिक क्रिया-क्षेत्रों को दी जाने वाली साख का नियमन प्रवृत्त्य या गुणात्मक साख नियन्त्रण कहलाता है। इसका उद्देश्य आवश्यक तथा विशेष रूप से वाञ्छित क्रियाओं को प्रोत्साहन देना और अपेक्षित, अनावश्यक तथा कम वाञ्छित क्रियाओं को हतोत्साहित करना होता है। परिमाणात्मक साख नियन्त्रण रीतियों की परिसीमाओं के कारण और विशेषकर अर्थव्यवस्था की विशिष्ट प्रकृति के कारण भारत में प्रवृत्त्य साख नियन्त्रण की रीतियों का महत्व बढ़ गया है।

बैंकिंग नियमन अधिविधम की धारा 21, 35 (अ) तथा 36 (1) (अ) के अनुसार रिजर्व बैंक को बैंको द्वारा दिए गये ऋणों का नियन्त्रण करने का अधिकार है। धारा 36 (1) (अ) के अनुसार "रिजर्व बैंक सामान्य रूप से बैंकिंग कम्पनियों को या किसी बैंकिंग कम्पनी को किसी विशिष्ट सौद या किसी श्रेणी के सौदों के बारे में सचेत कर सकता है या उसे रोक सकता है, तथा किसी बैंकिंग कम्पनी को सामान्य रूप से परामर्श दे सकता है।"

उपयुक्त वैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार रिजर्व बैंक ने प्रवृत्त्य साख नियन्त्रणों का प्रयोग आवश्यक वस्तुओं के सट्टे तथा स्टॉक दबाकर रखने के कार्यों के लिए बैंक-साख के उपयोग को रोकने के लिए किया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से भौतिक अधिकारियों के समझ मुत्सय समस्या मुद्रा स्फीति को नियन्त्रित करने की रही है। रिजर्व बैंक ने प्रवृत्त्य साख नियन्त्रणों का प्रयोग सबसे पहल 1956 में प्रारम्भ किया। देश में प्रवृत्त्य साख नियन्त्रणों का उपयोग मुख्य रूप से कृषि जन्य पदार्थों की कीमतों को नियन्त्रित करने के लिए ही किया गया। (The primary objective of Selective Controls has been to prevent speculative hoarding of commodities like foodgrains and essential raw materials so as to prevent or control inflationary pressures in these areas) द्वितीय योजना काल में कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही थी। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र को बैंक साख की

वृद्धि, मुद्रा स्फीति का प्रधान कारण थी। इसीलिए 17 मई 1956 को रिजर्व बैंक ने एक आदेश पत्र द्वारा वस्तुओं की जमानत पर अत्यधिक ऋण देने की मनाही कर दी, विशेषकर धान तथा चावल पर किसी ग्राहक को 50 000 रुपये से अधिक का ऋण देने से मना किया गया था। बैंको को धान तथा चावल पर दिए गये ऋणों का सीमान्तर 10 प्रतिशत बढ़ाने तथा उन पर दिए गये कुल ऋणों को पिछले वर्ष के उसी समय की तुलना में 120 प्रतिशत की सीमा तक घटाने का आदेश दिया गया। सितम्बर 1956 में यह नियन्त्रण भेड़ू चना दालों कागस, कपडा तथा सूत पर भी लागू किए गये। नवम्बर 1956 में धान तथा चावल के सम्बन्ध में नियन्त्रण समाप्त कर फिर 9 फरवरी 1957 को पुनः लागू कर दिये गये। इसी प्रकार जून 1957 सितम्बर 1958, फरवरी 1959 दिसम्बर 1959, फरवरी 1962, जुलाई, अगस्त दिसम्बर 1964 मई 65 अप्रैल 1966 जनवरी 1967 में विभिन्न प्रकार के ऋण सम्बन्धी नियन्त्रण लगाये गये।

हम का विषय है कि रिजर्व बैंक में लाचदार ढंग से इन रीतियों का प्रयोग किया है। इनका समग्र प्रभाव सुधारक की अपेक्षा निवारक अधिक रहा है। (The overall effect of various directives has been more preventive than curative) इन रीतियों के प्रयोग के सम्बन्ध में मुख्य सीमाय इनकी सप्रभाविकता को कम कर देनी है। एक तो बहुत से बैंको पर निर्देशों को लागू करना कठिन है। (Difficulty in Implementation and Enforcement) और दूसरे अन्य स्रोतों (स्वदेशी बैंकरों) से अग्रिम प्राप्त हो जान से प्रवृत्त साख नियन्त्रण प्रभावी नहीं रहते भारत में प्रवृत्त साख नियन्त्रण के सम्बन्ध में यह निष्पत्ति सदा सत्य है

"Selective credit controls have played only a negative part in the sense that they are applied with the sole intention of curbing excessive advances to particular sectors of the economy Recent experiments in advanced countries suggest that they can be used for making credit more purpose oriented

(5) नैतिक अनुनय (Moral Suasion)

साख नियन्त्रण के अन्य साधनों के अतिरिक्त रिजर्व बैंक नैतिक अनुनय (Moral Suasion) की रीति का भी प्रयोग करता है। रिजर्व बैंक द्वारा इस रीति का प्रयोग बैंकरो के बीच अधिक मधुर तथा सहकारी वातावरण बनाने के लिए किया गया जिससे मित्रता पूर्ण ढंग से नियन्त्रण के उपाय लागू किए जा सकें। समय समय पर रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा अन्य अधिकारी मुख्य बैंकरो से मिलकर नीतियों का स्पष्टीकरण करते हैं और उनका सहयोग की आशा करते हैं। सितम्बर 1949

मे भारतीय रुपये के अवमूल्यन के पश्चात रिजर्व बैंक के गवर्नर ने प्रमुख बैंकों की समा कर उनसे सट्टे के लिए अग्रिम न देने का अनुरोध किया। जून 1957 में व्यापारिक बैंकों से कृषि जन्य पदार्थों पर अग्रिम की मात्रा को घटाने का अनुरोध किया गया। इसी प्रकार जून तथा दिसम्बर 1959 तथा मई 1960 में निर्देश दिए गये। समय-समय पर रिजर्व बैंक बैंकों की ऋण तथा अन्य नीतियों को अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप बनाता रहता है।

रिजर्व बैंक का विकासात्मक दायित्व (Developmental Role of Reserve Bank)

केन्द्रीय बैंक के रूप में मुद्रा तथा साख व्यवस्था के संचालन, सरकारी बैंक तथा बैंकों के बैंक के सामान्य परम्परागत कार्य करने के अनिरीक्त रिजर्व बैंक पर देश के आर्थिक विकास के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं। प्रतिबन्धात्मक कार्य (Restrictive Role) के साथ रिजर्व बैंक का (Promotional Role) या विकासात्मक (Developmental Role) भी है। इस सन्दर्भ में रिजर्व बैंक कृषि वित्त व्यवस्था तथा औद्योगिक वित्त व्यवस्था के क्षेत्र में विशेष दायित्व रखता है।

रिजर्व बैंक तथा ग्राम्य वित्त (Reserve Bank and Rural Credit)

भारत की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि होने के कारण इस क्षेत्र के लिए वित्त सुविधायें जुटाने में रिजर्व बैंक का विशेष उत्तरदायित्व है। अप्रैल 1935 में बैंक की स्थापना के साथ ही एक कृषि साख विभाग (Agricultural Credit Department) की स्थापना की गई थी जिसके निम्नलिखित उद्देश्य थे :

(अ) कृषि साख से सम्बन्धित सभी समस्याओं के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ कर्मचारी रखना तथा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, राज्य सहकारी बैंकों तथा अन्य बैंकिंग संस्थाओं को परामर्श देने के लिए उपलब्ध रहना।

(ब) कृषि साख के सम्बन्ध में बैंक की क्रियाओं तथा राज्य सहकारी बैंकों, अन्य बैंकों अथवा कृषि वित्त व्यवस्था में सहाय संस्थाओं के सम्बन्ध में समन्वय स्थापित करना।

ग्रामीण बैंकिंग जाच समिति 1950 तथा ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति 1954 ने ग्रामीण वित्त व्यवस्था की जाच कर उत्तम सुधार के लिए सुझाव दिए। सर्वेक्षण समिति द्वारा बताई गई ग्रामीण साख की समग्र योजना (Integrated Scheme of Rural Credit) में रिजर्व बैंक पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का उत्तरदायित्व नौंपा गया।

रिजर्व बैंक द्वारा सहायता (Assistance provided by the Bank):—

अधिनियम के अनुसार रिजर्व बैंक को कृषकों को प्रत्यक्ष रूप से साख देने का अधिकार नहीं है, वह सहकारी ग्रान्दोलन को वित्त सहायता राज्य सहकारी बैंको के माध्यम से ही देता है। अनुसूचित बैंको की तरह राज्य सहकारी बैंको को रिजर्व बैंक अग्रिम तथा पुन बट्टा की सुविधायें देता है। राज्य सहकारी बैंको को रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17 (2) (अ), (ब) तथा (सस) के अन्तर्गत पुन बट्टा के रूप में सहायता, धारा 17 (4) (स) के अन्तर्गत स्वीकृत बिलों की जमानत पर ऋण तथा धारा 17 (4) के अन्तर्गत सरकारी तथा न्यास प्रतिभूतियों की जमानत पर अग्रिम द्वारा वित्तीय सहायता देता है। रिजर्व बैंक यह सहायता बैंक दर से 2 प्रतिशत कम पर प्रदान करता है। रिजर्व बैंक की यह वित्तीय सहायता अधिकतर अल्पकालीन होती है परन्तु फरवरी 1955 से रिजर्व बैंक मध्यकालीन सहायता भी देता है। अप्रत्यक्ष रूप से रिजर्व बैंक केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंको के ऋण-पत्र खरीदकर दीर्घकालीन सहायता भी देता है।

ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति, 1954 (All India Rural Credit Survey Committee, 1954) : ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति, 1954 के सुझाव पर दीर्घकालीन ग्रामीण साख की पूर्ति हेतु दो कोषों की स्थापना की गई :—

(1) राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन) कोष (National Agricultural Credit [Long Term Operations] Fund):—इस कोष की स्थापना 3 फरवरी 1956 को हुई थी। इस कोष में सरकार ने प्रारम्भ में 10 करोड़ रुपया जमा के रूप में दिया और अगले पांच वर्षों में रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपया जमा करने की व्यवस्था थी। इस कोष का उद्देश्य (1) राज्य सरकारों को 20 वर्ष की अवधि के लिए ऋण तथा अग्रिम देना है जिससे वे सहकारी साख संस्थाओं की अंश पूंजी खरीद सकें, (2) राज्य सहकारी बैंको को 15 माह से 5 वर्ष की अवधि के मध्यकालीन ऋण देना, (3) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंको को अधिक से अधिक 20 वर्षों की अवधि के लिए ऋण देना तथा (4) रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों के ऋण-पत्र खरीदना है।

मार्च 1968 के अन्त तक इस कोष में 131 करोड़ रुपये जमा थे। जून 1968 तक रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों को 31.69 करोड़ रुपये तथा राज्य सहकारी बैंको को 16.47 करोड़ रुपये की राशि इस कोष से ऋण के रूप में दी थी।

(2) राष्ट्रीय कृषि साख (स्थिरीकरण) कोष [National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund] : इस कोष की स्थापना 30 जून 1956 को हुई थी। स्थिरीकरण कोष का प्रयोग राज्य सहकारी बैंको को मध्यकालीन ऋण

तथा अन्निम प्रदान करने के लिए किया जाता है जिससे वे वर्षा की कमी, अकाल तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तियों के कारण आवश्यकता पडने पर अपनी अल्पकालीन साख को मध्यकालीन साख में परिवर्तित कर सकें। जून 1956 से अगले पाँच वर्षों में प्रतिवर्ष 1 करोड रुपया रिजर्व बैंक द्वारा जमा की जाने की व्यवस्था की गई थी। जून 1968 तक इस कोष में 33 करोड रुपये को राशि जमा थी। 1966-67 में 4.68 तथा 1967-68 में 6.43 करोड रुपये के ऋण राज्य सहकारी बैंको को दिये गये थे।

इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक दीर्घकालीन साख की पूर्ति के लिए केन्द्रीय भूमि वधक बैंको के ऋण पत्र खरीदता है।

रिजर्व बैंक ने 1963 में स्थापित कृषि पुनर्वित्त निगम (Agricultural Refinance Corporation) के अण खरीदकर अल्प, मध्यम तथा दीर्घकालीन ऋणों की बहुमुखी व्यवस्था करने में सहायता दी है। अपनी स्थापना से मार्च 1968 तक निगम ने पुनर्वित्त की 75 83 करोड रुपये वाली 95 योजनाएँ स्वीकृत की और वास्तव में 62 20 करोड रुपये स्वीकृत किए।

रिजर्व बैंक सहकारी बैंको का निरीक्षण तथा सहकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करता है।

रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंको को दिये गये ऋणों का विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत है।

रिजर्व बैंक तथा सहकारी साख

(करोड रुपये में)

वर्ष	ऋण (Advance)	ऋण-शेष (Outstanding)
1950-51	5 37	3.39
1955-56	23.00	12 33
1960-61	147.11	89 41
1965-66	293 44	161 72
1966 67	330.94	170.68
1967-68	453.96	196 73
1968-69	484.68	244 18

10 करोड की अधिकृत पूँजी वाले प्रस्तावित उर्वरक साख तथा गारन्टी निगम (Fertiliser Credit Guarantee Corporation) की स्थापना में 60 प्रतिशत पूँजी खरीद कर रिजर्व बैंक महत्वपूर्ण योगदान करेगा।

रिजर्व बैंक तथा औद्योगिक वित्त (Reserve Bank and Industrial Finance)

एक विकासशील अर्थव्यवस्था में औद्योगिक वित्त व्यवस्था का विकास करने की परम आवश्यकता है। देश में बढ़ते हुए औद्योगीकरण तथा आन्तरिक पूँजी बाजार में पर्याप्त सुविधाओं के अभाव के कारण उद्योगों को मध्य तथा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं की स्थापना अनिवार्य है। इसी उद्देश्य से औद्योगिक वित्त निगम की 1948 में स्थापना की गई। औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना के समय उसकी 5 करोड़ रुपये की निर्गमित पूँजी का 20 प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक ने जुटाया था परन्तु 1 अगस्त 1964 से सभी अश रिजर्व बैंक द्वारा उमकी सहायक के रूप में स्थापित औद्योगिक विकास बैंक को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। औद्योगिक वित्त निगम की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार ने निगम में अपन अंशों पर लाभांश न लेना स्वीकार किया। यह लाभांश तब तक एक रक्षित कोष में जमा होता रहगा जब तक कोष राशि 50 लाख रुपये न हो जाय। इसके अतिरिक्त, 1953 में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट में हुए एक संशोधन द्वारा रिजर्व बैंक निगम को अल्प तथा मध्यकालीन ऋण तथा अग्रिम देने का अधिकार रखा है। वित्त निगम द्वारा रिजर्व बैंक से लिए गये ऋणों की राशि 1963-64 में 1.24 करोड़ रुपये थी 1968-69 में बढ़ कर 8.6 करोड़ रुपये हो गई।

मध्यम तथा लघु उद्योगों की मध्यम तथा दीर्घकालीन पूँजी की आवश्यकता-पूर्ति के लिए 1951 में राज्य वित्त निगम अधिनियम पारित किया गया। 18 राज्यों में स्थापित राज्य वित्त निगमों की पूँजी का 10 से 20 प्रतिशत तक रिजर्व बैंक ने जुटाया है और बैंक के पास 2.43 करोड़ रुपये के इन संस्थाओं के अंश हैं। रिजर्व बैंक द्वारा इन राज्य वित्त निगमों को भी ऋण देने की व्यवस्था है।

राष्ट्रीय औद्योगिक साख (दीर्घकालीन) कोष [National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund] : रिजर्व बैंक ने राज्य वित्त निगमों के विकास के लिए 1 जुलाई 1964 से एक राष्ट्रीय औद्योगिक साख (दीर्घकालीन) कोष का प्रारम्भ किया गया है। इस कोष में प्रारम्भ में 10 करोड़ तथा आगे और राशि रिजर्व बैंक द्वारा जमा की जानी थी। 30 जून 1968 तक इस कोष में 55 करोड़ रुपये की राशि जमा थी। इस कोष के मुख्य उद्देश्य हैं—(1) औद्योगिक विकास बैंक को औद्योगिक वित्त निगम या राज्य वित्त निगमों या अन्य वित्तीय संस्थाओं के अंश या ऋण-पत्र खरीदने के लिए ऋण देना। (2) औद्योगिक विकास बैंक के अन्य कार्यों के लिए ऋण देना तथा (3) औद्योगिक विकास बैंक द्वारा निर्गमित ऋण तथा ऋण-पत्र खरीदना।

साख गारन्टी योजना (Credit Guarantee Scheme) लघु उद्योगों को दी जाने वाली वित्त सहायता को प्रोत्साहित करने के लिए 1 जुलाई 1960 से भारत सरकार ने एक साख गारन्टी योजना प्रारम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों से ऋणदाता संस्थाओं को होने वाली हानि को उनमें तथा भारत सरकार में बाटने की व्यवस्था है। जुलाई 1960 से मार्च 1968 तक 70,197 प्रार्थनाएँ प्राप्त हुईं जिनकी राशि 306 करोड़ रुपये थी। इनमें से 63,065 प्रार्थना पत्रों पर 260.6 करोड़ रुपये की गारन्टियाँ दी गईं।

इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने अपनी सहायक के रूप में औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank of India) की स्थापना की है जिसने 1 जुलाई 1964 में कार्य करना प्रारम्भ किया। औद्योगिक विकास बैंक की कुल पूंजी रिजर्व बैंक द्वारा जुटाई गई है और उसका प्रबन्ध रिजर्व बैंक के संचालक मंडल द्वारा ही होता है।

औद्योगिक साख के क्षेत्र में उपर्युक्त सहायता के अनिर्दिष्ट रिजर्व बैंक ने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इन्डिया की पूंजी में भी योगदान किया है। यूनिट ट्रस्ट अपनी नीति निर्धारण में रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन करता है।

रिजर्व बैंक की आलोचना (Criticism of the Reserve Bank)

यद्यपि रिजर्व बैंक ने देश के मुद्रा बाजार तथा बैंकिंग संगठन को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण कार्य किया है परन्तु निम्नलिखित असफलताओं के आधार पर उसकी आलोचना की जाती है :

(1) मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने में असफल (Failure to control Inflation) द्वितीय योजना के प्रारम्भ से देश में अत्यधिक मुद्रा स्फीति के लक्षण प्रकट होने लगे। कुछ अपवादों को छोड़कर तब से कीमत-तल में लगातार वृद्धि हो रही है। देश के सामने प्रमुख समस्या मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने की है। देश ने Growth without inflation के स्यान पर Inflation without growth को प्राप्त किया है। मुद्रा पूर्ति की तुलना में उत्पादन में 'संतोषजनक' वृद्धि नहीं हुई है। इस दिशा में रिजर्व बैंक को विशेष सफलता नहीं मिली है।

(2) मुद्रा बाजार के असंगठित भाग पर नियन्त्रण में असफल (Failure to have control over unorganised sector of the Money Market) - मुद्रा बाजार की द्विशाखिता दूर करने तथा स्वदेशी बैंकरों को देश के संगठित बैंकिंग प्रवाह के अन्तर्गत लाने में रिजर्व बैंक के सभी प्रयत्न असफल रहे हैं।

(3) रुपये के बाह्य मूल्य में स्थिरता बनाये रखने में असफल (Failure to maintain the external value of the Rupee) : रुपये के बाह्य मूल्य में स्थिरता, भुगतान शेष तथा विदेशी विनिमय की समस्याओं का समाधान अब भी नहीं निकल पाया है। 1966 का अवमूल्यन हमारी आर्थिक तथा मौद्रिक नीतियों की असफलता का प्रमाण है।

(4) बैंको को फेल होने से रोकने में असफल (Unsuccessful in preventing failure of Banks) : 1960 में पलाई सेन्ट्रल बैंक तथा लक्ष्मी बैंक के फल हो जाने से देश के बैंकिंग संगठन तथा रिजर्व बैंक की प्रतिष्ठा को एक मनो-वैज्ञानिक आघात लगा। पलाई बैंक की वित्तीय स्थिति की जानकारी होते हुए भी रिजर्व बैंक ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया जो उसकी उदामीनता का परिचायक है। अब रिजर्व बैंक इस दिशा में अधिक सचेत है।

(5) व्याज दरों की विभिन्नता दूर करने में असफल (Failure to bring uniformity of Interest Rates in the Money Market) : भारतीय मुद्रा बाजार में व्याज दरों की विभिन्नता दूर करने में रिजर्व बैंक को कोई सफलता नहीं मिली।

(6) कृषि-वित्त समस्या (Problem of Agricultural Finance) : कृषि वित्त की समस्या के आकार तथा जटिलताओं के कारण जो कुछ भी इस क्षेत्र में हुआ है, बहुत कम है। व्यापारिक बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएँ का विस्तार तथा कृषि वित्त प्रबन्धना करने में उनकी प्रगति बड़ी धीमी है।

उपर्युक्त आलोचनाओं के साथ विल बाजार का अभाव, साख नियन्त्रण नीतियों, लाइसेन्स नीति, सूचनाओं तथा आकड़ों के प्रकाशन के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक की आलोचना की जाती रही है।

रिजर्व बैंक की सफलताएँ

(Achievements of the Reserve Bank)

कुछ क्षेत्रों में रिजर्व बैंक की विफलताओं के बावजूद रिजर्व बैंक ने देश की आर्थिक तथा वित्त व्यवस्था सम्बन्धी महत्वपूर्ण सेवाएँ की हैं। रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किया है :

[1] मुद्रा व्यवस्था का कुशल संचालन (Efficient Management of the currency system) रिजर्व बैंक ने देश की मुद्रा व्यवस्था का सफलतापूर्वक कुशल संचालन तथा प्रबन्ध किया है। देश के योजनात्मक विकास की आवश्यकता-नुसार सरकार की अर्थ नीति के अनुरूप मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की है। मुद्रा की माँग के अनुरूप उसकी पूर्ति में समायोजन कर मुद्रा व्यवस्था में लोच लाने का श्रेय रिजर्व बैंक को है।

(2) साख के नियन्त्रण तथा नियमन मे सफ़तता (Successful Control and Regulation of Credit) : देश की आवश्यकतानुसार साख के मृजन तथा उसके वितरण का नियन्त्रण तथा नियमन कर रिजर्व बैंक ने महत्वपूर्ण सफ़तता प्राप्त की है। अर्थव्यवस्था की विशिष्ट प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रवृत्त साख नियन्त्रण रीतियों का लोचपूर्ण ढंग से प्रयोग किया है। इस प्रकार उत्पादन वृद्धि तथा तीव्र गति से आर्थिक विकास को रिजर्व बैंक ने प्रोत्साहन दिया है।

(3) बैंकिंग विकास तथा नियमन (Development and Regulation of Banking) : देश की बैंक व्यवस्था का नियमन तथा बैंकिंग सेवाओं के विकास और विस्तार मे रिजर्व बैंक ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। बैंकिंग विकास विभाग (Department of Banking Development) के द्वारा रिजर्व बैंक ने ग्रामीण तथा अर्द्ध-नगरीय क्षेत्रों मे बैंकों की शाखाओं का विस्तार कर वहाँ बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध कराने मे सहायता की है। बैंकिंग प्रक्रियाओं के विभाग (Department of Banking Operations) के द्वारा रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमन अधिनियम तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर बैंकिंग व्यवस्था का नियन्त्रण तथा नियमन किया है।

(4) कृषि वित्त तथा औद्योगिक वित्त क्षेत्रों मे सहायता (Assistance in the field of Agricultural and Industrial Finance) : जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है रिजर्व बैंक ने कृषि-वित्त तथा औद्योगिक वित्त सुविधाओं के विकास मे पर्याप्त योगदान देकर देश की आर्थिक प्रगति मे सहायता की है।

(5) सार्वजनिक ऋण प्रबंध (Management of Public Debt) : रिजर्व बैंक ने समय समय पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के लिए ऋण प्राप्त किया है तथा उनका भुगतान किया है।

(6) समाशोधन तथा प्रेषण सुविधायें (Clearing and Remittance facilities) : रिजर्व बैंक ने देश के विभिन्न नगरों मे समाशोधन सुविधाओं तथा बैंकों के कोषों के स्थानान्तरण की सुविधाओं का विस्तार कर देश की बैंक व्यवस्था की बड़ी सेवा की है। इस प्रकार पूँजी की गतिशीलता बढ़ाने मे रिजर्व बैंक ने सहायता की है।

उपसंहार (Conclusion) : रिजर्व बैंक की असफलताओं तथा सफलताओं के विवेचन से स्पष्ट है कि कुछ अग्रवादों को छोड़कर रिजर्व बैंक ने देश की बैंक तथा वित्त व्यवस्था की अभूतपूर्व सेवा की है। श्री सिद मित्र (Sid Mitra) के शब्दों मे :

“.....considering the functional limitations and the institutional framework within which the Reserve Bank had to function—as a versatile and percipient institution, the Bank protected the economy as best as feasible against disturbance of the even tenor of progress through judicious, skilful and pliant employment of the specially devised techniques of monetary management.”¹

फिर भी आज आवश्यकता इस बात की है कि रिजर्व बैंक अपने अधिकारों का पर्याप्त मात्रा में देश हित में प्रयोग करे। बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण व्यवस्था द्वारा रिजर्व बैंक को अब और भी विस्तृत अधिकार प्राप्त हो गये हैं। यह अवश्य है कि रिजर्व बैंक के कार्यों तथा दायित्वों का बोझ अब इतना अधिक बढ़ गया है कि कुछ लोगो ने भारत में अमेरिका की फेडरल रिजर्व व्यवस्था की तरह कोई विकेंद्रित केन्द्रीय बैंक व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया है।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संकेत

1. रिजर्व बैंक के एक केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य की समीक्षा कीजिये। सुधार के लिए सुझाव दीजिए।

(राजस्थान टी०डी०सी फाइनल, 1969)

(विक्रम बी०ए०, 1961)

[संकेत—प्रथम भाग में रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बैंकिंग कार्यों (साख नियमन तथा नियन्त्रण के सहित) का विवेचन कीजिए। दूसरे भाग में उसके केन्द्रीय बैंकिंग कार्यों को और निपुणता तथा सफलतापूर्वक करने के सम्बन्ध में अपने सुझाव दीजिये।]

2. भारत के योजनाबद्ध आर्थिक विकास के काल में रिजर्व बैंक के कार्यों का संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिये।

(राजस्थान टी०डी०सी० फाइनल, 1967)

[संकेत—1951 में योजनाबद्ध आर्थिक विकास के प्रारम्भ से अब तक रिजर्व बैंक के कार्यों (साख नियमन तथा नियन्त्रण सहित) का विवेचन कीजिए तथा साथ-साथ उनकी सफलता का मूल्यांकन भी करिये।]

3. भारत में रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त मुद्रा एवं साख नियंत्रण के विभिन्न तरीकों का विवरण दीजिये।

(राजस्थान टी०डी०सी० फाइनल, 1965)

¹. Sid Mittra : *A New Horizon in Central Banking*, 1967, p 247.

अथवा

इस देश की बैंक व्यवस्था में रिजर्व बैंक क्या भूमिका निभाता है ? देश में मुद्रा तथा साख का नियन्त्रण वह किस प्रकार करता है ।

(राजस्थान बी०काम०, 1961)

[सकेत—रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बैंक के रूप में केवल दो कार्यों का विवेचन कीजिये—मुद्रा निर्गमन का एकाधिकार तथा साख का नियन्त्रण । साख नियन्त्रण के कार्य के अन्तर्गत रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त पांच रीतियों—बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाये, परिवर्तनशील कोपानुपात, प्रवृत्त्य साख नियन्त्रण तथा नैतिक अनुनय का रिजर्व बैंक के सन्दर्भ में विवरण दीजिये ।]

4 व्यापारिक बैंको का नियन्त्रण तथा नियमन करने में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की भूमिका का विश्लेषण कीजिए ।

(राजस्थान टी०डी०सी० फाइनल, 1968)

[सकेत—बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट 1934 के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को व्यापारिक बैंको का नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धी जो अधिकार प्राप्त हैं उनका विवरण दीजिये । लाइसेंस, प्रबन्ध, पूंजी, तरल कोष शाखा-विस्तार, निरीक्षण, अवसायन तथा विलयन इत्यादि सम्बन्धी रिजर्व बैंक के अधिकारों का वर्णन कीजिये । संक्षेप में यह भी बताइये कि इसमें रिजर्व बैंक कहा तक सफल हुआ है ।]

स्टेट बैंक आफ इन्डिया (State Bank of India)

"The establishment of the State Bank of India has marked a significant step in the field of integrated rural credit."

स्टेट बैंक आफ इन्डिया की स्थापना स्टेट बैंक आफ इन्डिया अधिनियम 1955 के अन्तर्गत हुई और इसने 1 जुलाई 1955 से अपना कार्य प्रारम्भ किया। इम्पीरियल बैंक आफ इन्डिया के राष्ट्रीयकरण के बाद यह स्टेट बैंक के नवीन रूप में कार्य कर रहा है। व्यापारिक बैंक के रूप में यह वे सभी कार्य करता है जो इम्पीरियल बैंक किया करता था। इसके अतिरिक्त देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार का विशेष उत्तरदायित्व इस बैंक को सौंपा गया है। अतः इस बैंक का विस्तृत अध्ययन करने से पहले इम्पीरियल बैंक के सम्बन्ध में सक्षिप्त विवरण प्राप्त करना आवश्यक होगा।

इम्पीरियल बैंक आफ इन्डिया (Imperial Bank of India) : इम्पीरियल बैंक आफ इन्डिया का निर्माण बम्बई, बंगाल तथा मद्रास प्रेसीडेन्सी बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक आफ इन्डिया अधिनियम 1920 के अन्तर्गत हुआ था। इम्पीरियल बैंक की अधिकृत पूंजी 11.25 करोड़ रुपये निश्चित की गई थी जिसमें से आधी परिदत्त पूंजी थी और शेष आधी अशुभारियों के रक्षित दायित्व के रूप में। यह पूंजी 500 रुपये के 2 25 लाख अंशों में विभाजित थी। अधिनियम के अन्तर्गत बैंक का प्रबन्ध एक केन्द्रीय संचालक मण्डल (Central Board of Directors) के आधीन था जिसमें 16 संचालक थे जो गवर्नर कहलाते थे। बैंक की नीति निर्धारण का उत्तरदायित्व इसी मण्डल पर था। क्षेत्रीय स्वाधियों की सुरक्षा हेतु केन्द्रीय संचालक मण्डल के आधीन बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में अशुभारियों द्वारा निर्वाचित तीन स्थानीय बोर्डों (Local Boards) का गठन किया गया था।

इम्पीरियल बैंक आफ इन्डिया सरकारी बैंक तथा बैंकों के बैंक के रूप में केन्द्रीय बैंकिंग कार्य किया करता था। 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व यह कार्य इम्पीरियल बैंक ने व्यापक रूप से किए परन्तु रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद

इनमें काफी कमी हो गई। इसके अतिरिक्त व्यापारिक बैंक के रूप में भी साधारण बैंकिंग कार्य यह बैंक करना था।

इम्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंक न बनाने के कारण :

1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की एक केन्द्रीय बैंक के रूप में स्थापना हुई। मात्र 14 वर्षों से केन्द्रीय बैंकिंग कार्य को करने वाले इम्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंक नहीं बनाया गया जिसके निम्नलिखित कारण थे—

1. केन्द्रीय बैंकिंग कार्यों की जटिलता तथा स्वस्थ व नवीन परम्परायें कायम करने की आवश्यकता : केन्द्रीय बैंकिंग एक जटिल तथा कठिन प्रिय है। इसके अपने सिद्धान्त तथा विशेषतायें हैं। अतः इन कार्यों को करने के लिए एक स्वतन्त्र तथा नवीन संस्था होनी चाहिये जो स्वस्थ परम्पराओं का निर्माण कर सके और फिर इम्पीरियल बैंक का इतिहास कोई बहुत सुन्दर इतिहास नहीं था।

2. व्यापारिक कार्य समाप्त करने पड़ते : इम्पीरियल बैंक एक व्यापारिक बैंक था जिसकी शाखाएँ देश भर में फैली हुई थी। केन्द्रीय बैंकिंग सिद्धान्तों के अनुसार केन्द्रीय बैंक की कार्य प्रणाली पूर्णतया सुरक्षित होनी चाहिए और उसे किसी प्रकार का जोखिम वाला व्यापार नहीं करना चाहिए। बैंको के बैंक के रूप में कार्य करने के लिए केन्द्रीय बैंक को अन्य व्यापारिक बैंकों में प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिये। यदि इम्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंक बना दिया गया होता तो इसे अपने व्यापारिक कार्य समाप्त करने पड़ते जिससे देश की बैंकिंग व्यवस्था को हानि पहुँचने की आशंका थी। इण्डिया आफिंस के वित्तीय सचिव श्री किश ने हिस्टोरिकल कमिशन के समक्ष अपनी गवाही में इम्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंक न बनाने का सुझाव दिया था।

3. देश के बैंकों का इम्पीरियल बैंक में अविश्वास : इम्पीरियल बैंक देश के अन्य बैंकों से प्रतिस्पर्धा तथा भेदभाव किया करता था। अतः भारतीय बैंकों का इम्पीरियल बैंक में कोई विश्वास नहीं था। इम्पीरियल बैंक एक व्यापारिक बैंक होते हुए भी एक विशेष स्थिति में था। अतः अन्य बैंक उससे घृणा तथा द्वेष रखते थे। ऐसी परिस्थिति में इम्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंक के रूप में अन्य बैंकों का सहयोग मिलना बड़ा कठिन था और उसकी सफलता संदिग्ध थी।

(4) इम्पीरियल बैंक के संचालक मंडल का विरोध . इम्पीरियल बैंक का संचालक मंडल इस बैंक के साधारण व्यापारिक बैंकिंग कार्यों को छोड़ने के पक्ष में नहीं था।

1. The holder of ultimate reserves of the country should not itself be the channel through which credit was given to individuals & firms"—Mr. Kisch, Financial Secretary at the India Office See Minutes of Evidence of the commission, Vol V, p 132.

(5) चलन व्यवस्था बैंक के स्वार्थों से नियंत्रित होती : यह भी संदेह प्रकट किया गया था कि चलन का प्रबन्ध भी इम्पीरियल बैंक के पास रहता तो वह उसके स्वार्थों से नियंत्रित होती न कि देश हित से ।

वास्तव में इम्पीरियल बैंक एक विदेशी स्वार्थों की रक्षा करने वाला बैंक था और भारतीय बैंकों से वह भेदपूर्ण नीति अपनाता था । इन्हीं सब कारणों से इम्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंक के रूप में परिवर्तित करना उपयुक्त नहीं समझा गया ।

इम्पीरियल बैंक की कार्यप्रणाली में दोष :

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में इम्पीरियल बैंक का महत्वपूर्ण स्थान रहा है । 1935 के अग्रेल में रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद भी रिजर्व बैंक के अधिकारों के रूप में इसकी विशेष स्थिति बनी रही । देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक होते हुए भी इसकी कार्य प्रणाली में निम्नलिखित दोष थे :

(1) विदेशी प्रभुत्व (Foreign domination) : इम्पीरियल बैंक की अधिकांश पूँजी विदेशियों के हाथ में थी तथा इसका प्रबन्ध व संचालन योरोपियनों के द्वारा होता था । बैंक के अधिकांश उच्चाधिकारी विदेशी थे । विदेशी प्रबंधक भारत विरोधी भावनाएँ रखते थे । यह बैंक उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं करता था जिस कारण भारतीयों को उन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते थे । केन्द्रीय जाच समिति के समक्ष बैंक के प्रबंध गवर्नर ने अपनी गवाही में कहा था कि बैंक भारतीयकरण की नीति अपना रहा है, परन्तु इस ओर विशेष प्रगति न हो सकी ।

(2) भेदपूर्ण नीति (Discriminatory policy) : बैंक पर विदेशी प्रभुत्व होने के कारण ऋण देने में जातीय तथा राजनैतिक भेदभाव की नीति अपनाता था । विदेशी व्यापारियों को उनकी आर्थिक सामर्थ्य से अधिक ऋण रियायती दर दिया करता था और भारतीय व्यापारी अपना सम्पत्तिश्रो के अनुरूप ऋण नहीं प्राप्त कर पाते थे । भारतीय बैंकों की अपेक्षा विदेशी विनिमय बैंकों के प्रति यह बैंक अधिक उदारता की नीति अपनाता था ।

(3) अमितव्ययी प्रबंध (Top heavy Management) : इम्पीरियल बैंक का कोई एक केन्द्रीय कार्यालय नहीं था और बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में तीन मुख्य कार्यालय थे जिससे प्रबंध व्यय बहुत अधिक होता था । केवल एक केन्द्रीय कार्यालय स्थापित करके इसमें काफी बचत की जा सकती थी ।

(4) बिल बाजार के विकास में बाधा : बैंक के विरुद्ध यह आरोप भी लगाया गया कि इसने भारतीय मुद्रा बाजार एवं बिल बाजार के विकास में पर्याप्त सहयोग नहीं दिया क्योंकि इसकी अधिकांश साख नकद के रूप में होती थी ।

(5) दीपपूर्ण शाखा-विस्तार नीति : अधिकतर इम्पीरियल बैंक ने अपनी शाखाएँ ऐसे स्थानों पर खोली जहाँ पहले से ही अन्य बैंकों की शाखाएँ थीं। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार होने के स्थान पर भारतीय बैंकों से प्रतियोगिता घटी और उन्हें हानि पहुँची।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों की कीमत पर वित्तीय केन्द्रों को सहायता बैंक पर यह भी आरोप था कि यह अपनी शाखाओं का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों से निक्षेप प्राप्त कर कुछ नगरों के व्यापार की वित्त व्यवस्था करता है।

उपरोक्त कारणों से इम्पीरियल बैंक का विरोध बढ़ता गया और इसके राष्ट्रीयकरण की मांग जोर पकड़ती गई।

इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण

(Nationalisation of Imperial Bank of India)

इम्पीरियल बैंक ऑफ इन्डिया के राष्ट्रीयकरण की मांग स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् और भी तीव्र हो गई। 1948 में भारतीय धारा सभा (Indian Constituent Assembly [Legislative]) में रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के समय तत्कालीन वित्त मंत्री ने इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण की मांग को सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया, क्योंकि यह बैंक एक विशेष अधिनियम के अन्तर्गत कार्य कर रहा है। परन्तु बैंक की शाखाएँ पाकिस्तान, श्रीलंका तथा बर्मा में होने के कारण राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न विभिन्न तकनीकी प्रश्नों की जांच आवश्यक है और बाद में ही क्रियात्मक पग उठाया जा सकता है। इस निर्णय का इम्पीरियल बैंक के संचालक मंडल तथा अशाधारियों ने यह कह कर विरोध किया कि एक विशेष अधिनियम की आवश्यकता बैंक की कार्यप्रणाली के सिद्धांतों के निर्माण तथा सामान्य सुरक्षा की दृष्टि से हुई। सरकारी काम-काज के सम्बन्ध में बैंक का कहना था कि रिजर्व बैंक से नवीनतम समझौते के अनुसार कम पारिश्रमिक पर बैंक यह कार्य कर रहा है और इसमें उसे लाभ के स्थान पर हानि उठानी पड़ रही है। अतः यदि इस आधार पर बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है तो बैंक सरकारी काम-काज छोड़ने को तैयार है और सामान्य बैंकिंग कानून के अन्तर्गत कार्य करने को उद्यत है। यह भी कहा गया कि जनता की बैंक द्वारा की गई सेवाएँ इतनी कुशल हैं और व्यय की दृष्टि से बैंक की कार्यविधि इतनी मित-मयी है कि सरकारी काम-काज छोड़ देने से भी बैंक की स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं आयगा। 1949 में भारत सरकार ने इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का विचार स्थगित कर दिया।

1949 में ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति (Rural Banking Enquiry Committee) के सामने भी इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न उठाया

गया। समिति ने इम्पीरियल बैंक पर अधिकाधिक नियंत्रण रखने तथा इसके विशेष अधिकारों को कम करने के सम्बन्ध में सुझाव दिया तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार हेतु आगामी पांच वर्षों में कम से कम 274 शाखाएँ खोलने का प्रस्ताव किया। परन्तु इस काल में, बैंक केवल 114 शाखाएँ ही खोल सका। क्योंकि अशासित क्षेत्रों का क्षेत्र होने के कारण पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ शाखाएँ खोलने से हानि की अधिक सम्भावना थी, बैंक बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने में असफल रहा।

अगस्त 1951 में श्री ए० डी० गोरवाला की अध्यक्षता में ग्रामीण साख्त सर्वेक्षण समिति की नियुक्ति हुई। इस समिति ने इम्पीरियल बैंक की शाखा विस्तार पर अमतोय व्यक्त किया और दश में ग्रामीण साख्त की समुचित व्यवस्था करने हेतु इम्पीरियल बैंक तथा देशी राज्या में स्थापित अन्य दस बैंकों (1) The State Bank of Saurashtra (2) The Bank of Patiala, (3) The Bank of Bikaner (4) The Bank of Jaipur (5) The Bank of Rajasthan (6) Bank of Indore (7) The Bank of Baroda (8) The Bank of Mysore (9) The Hyderabad State Bank (10) Travancore Bank को मिलाकर एक शक्तिशाली बैंक की स्थापना करनी चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएँ खोलकर बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करे और कृषि साख्त की सही व्यवस्था करे। समिति के शब्दों में :-

The object was "the creation" of one strong, integrated, State sponsored, State partnered commercial banking institution with an effective machinery of branches spread over the whole country, which, by further expansion can be put in a position to take over cash work from non-banking treasuries and sub-treasuries, provide vastly extended remittance facilities for co-operative banks and other banks, thus stimulating the further establishment of such banks"

इस नये बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया रखने का सुझाव इस समिति ने दिया था।

स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया (State Bank of India)

भारत सरकार ने ग्रामीण साख्त सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 16 अप्रैल 1955 को सरकार ने लोक सभा में स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया बिल प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा पारित कर दिया गया। बिल को प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने बताया था कि "सरकार का इरादा व्यक्तिगत वारिज्य

तथा व्यवसाय में अनुचित हस्तक्षेप करने का नहीं है। इसी कारण इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का यह अर्थ नहीं होता कि सभी व्यापारिक बैंकों को सरकारी अधिकार में ले लिया जायगा। इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य उन सत्र अधिकारियों को, जो कि लम्बे काल से भारतीयों को इसके विरुद्ध थी, दूर करना तथा प्रामाण्य साख की समुचित व्यवस्था करना है।”

स्टेट बैंक का संगठन (Organisation of the State Bank) :

स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया एक्ट, 1955 के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया ने 1 जुलाई 1955 से विधिवत कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

स्टेट बैंक की अधिकृत पूंजी 20 करोड़ रुपये निर्धारित की गई जो 100-100 रुपये के 20 लाख अंशों से विभाजित है। बैंक की दत्त पूंजी 5.62 करोड़ रु. है जिसे सरकार की पूर्वानुमति में 12.5 करोड़ रु. तक बढ़ाया जा सकता है। योजनानुसार इम्पीरियल बैंक के अग्र रिजर्व बैंक को हस्तान्तरित कर दिये गये और अग्रधारियों को निम्न दर से मुआवजा दिया गया :

पूर्वदत्त अंश (500 रु.) = 1765 रुपये 10 अंश

अग्र दत्त अंश (125 रु.) = 431 रुपये 12 अंश 4 पाई

यह मुआवजा 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति तक तो नकद में देने की व्यवस्था की गई और शेष के लिए 1965 में 3% सरकारी ऋण पत्र दिए गये। इम्पीरियल बैंक के अग्रधारियों को मुआवजे के बदले स्टेट बैंक के 100 रुपये दत्तपूंजी के अंश को 350 रुपये की बाजार दर खरीदने की सुविधा भी प्रदान की गई। स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार स्टेट बैंक की निर्गमित पूंजी का कम से कम 55% रिजर्व बैंक के पास रहना परन्तु वास्तव में निर्गमित पूंजी का लगभग 92% रिजर्व बैंक के पास है।

अधिनियम में यह भी निश्चिन किया गया कि स्टेट बैंक में कोई भी व्यक्ति स्वयं या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर 200 से अधिक अंश नहीं खरीद सकता परन्तु यह सीमा रिजर्व बैंक या किनी निगम, बीमा कंपनी, स्वायत्त संस्था तथा निजी या धार्मिक ट्रस्ट पर लागू नहीं होती। मताधिकार के सम्बन्ध में स्टेट बैंक की व्यवस्था अत्यन्त प्रजातांत्रिक है क्योंकि किसी भी व्यक्ति या संस्था (रिजर्व बैंक को छोड़कर), चाहे उनके पास कितने भी अंश क्यों न हों, 1 प्रतिशत से अधिक मत देने का अधिकार नहीं होगा।

प्रबंध (Management) —

स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया एक्ट 1955 के अंतर्गत बैंक के केन्द्र मंडल (Central Board of Directors) की संरचना 20 है,

थी जिसमें निजी अंशधारियों को 6 संचालक नियुक्त करने (या चुनने) का अधिकार था। प्रारम्भ में सरकार का कुछ ऐसा अनुमान था कि निजी अंशधारियों के पास अंशों की काफी अधिक मात्रा रहेगी परन्तु निजी अंशधारियों के पास केवल 8 प्रतिशत अंश रहे। अतः 1 दिसम्बर 1964 को स्टेट बैंक एक्ट 1965 में संशोधन कर केन्द्रीय संचालक मंडल इस प्रकार गठित किया गया :

(1) एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष की संचालक मंडल की सिफारिश पर सरकार द्वारा,

(2) अधिक से अधिक दो प्रबंध संचालक (Managing Directors) सरकार के अनुमोदन पर संचालक मण्डल द्वारा,

(3) प्रत्येक स्थानीय मंडल (Local Board) का समापति संचालक मंडल का पदेन (ex-officio) सदस्य, (इनकी संख्या 7 है)

(4) दो संचालकों की नियुक्ति (या चुनाव) निजी अंशधारियों द्वारा, (यदि उनके पास कुल नियमित पूंजी का 20 प्रतिशत से कम भाग है)

(5) कम से कम 2 और अधिक से अधिक 6 संचालक रिजर्व बैंक की सलाह से भारत सरकार द्वारा। ये संचालक सहकारिता, वाणिज्य, व्यापार, उद्योग, बैंकिंग तथा वित्त विशेषज्ञ होंगे।

स्टेट बैंक का केन्द्रीय कार्यालय (Central office) बम्बई में स्थित है। इसके अतिरिक्त सात स्थानीय मंडल (Local Boards) कलकत्ता, कानपुर, बम्बई, अहमदाबाद, नई दिल्ली, मद्रास तथा हैदराबाद में हैं। स्टेट बैंक का अध्यक्ष प्रत्येक स्थानीय मंडल का पदेन अध्यक्ष होता है। स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष श्री वी० टी० दहेजिया हैं।

स्टेट बैंक के कार्य (Functions of the State Bank) :

स्टेट बैंक आफ इन्डिया व्यापारिक बैंक के रूप में उन सभी कार्यों को करता है जो इम्पीरियल बैंक करता था। इस प्रकार देश के उद्योग, व्यापार आदि को जो सेवाएँ इम्पीरियल बैंक उपलब्ध करता था वे सभी सेवाएँ स्टेट बैंक भी उपलब्ध करता है। इस दिशा में स्टेट बैंक आफ इन्डिया एक्ट में उन सभी नियमों का समावेश हुआ है जो इम्पीरियल बैंक आफ इन्डिया एक्ट में उल्लिखित थे।

स्टेट बैंक आफ इन्डिया एक्ट में उन सभी कार्यों की सूची दी गई है जिन्हें स्टेट बैंक कर सकता है। इससे अनुसार स्टेट बैंक के कार्य निम्न लिखित हैं—

(1) रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य (Functions as a agent of the Reserve Bank) : स्टेट बैंक, उन सभी स्थानों पर जहाँ रिजर्व बैंक की शाखाएँ

नहीं है, उसके एक मात्र एजेंट के रूप में कार्य करता है। उन स्थानों पर यह सरकार की ओर से रूपया बसूल करता है, जमा करता है तथा हस्तान्तरित करता है।

(2) व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य (Functions as a Commercial Bank) : स्टेट बैंक देश के अन्य व्यापारिक बैंकों की तरह निम्नलिखित कार्य करता है—

(i) निम्नलिखित प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण, अग्रिम, नकद साख तथा अधिविकल्प देना—

(क) ऐसे स्टाक, निविदा या प्रतिभूतियाँ जिनमें कोई ट्रस्टी अपने ट्रस्ट की रकम विनियोजित कर सकता हो;

(ख) जिला बोर्ड, नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों द्वारा विधानानुसार जारी किए गये ऋण पत्र या अन्य प्रतिभूतियाँ,

(ग) समुक्त स्कंध कम्पनियों के ऋण पत्र, (केन्द्रीय बोर्ड के तत्सम्बन्धी निर्देशों को ध्यान में रखकर),

(घ) विधान द्वारा स्थापित प्रमडलों के अश तथा ऋण पत्र (केन्द्रीय बोर्ड के निर्देशों के अनुसार);

(ङ) माल या माल सम्बन्धी अधिकार पत्र, जो स्टेट बैंक को जमानत के रूप में दिए गये हों,

(च) माल जो स्टेट बैंक के नाम अधिकृत (Hypothecate) किए गये हों,

(छ) स्वीकृत विनिमय पत्र तथा प्रतिज्ञा-पत्र तथा दो या इससे अधिक व्यक्तियों या फर्मों (जिनमें साभेदारी का सम्बन्ध न हो) के समुक्त तथा व्यक्तिगत प्रतिज्ञापत्र,

(ज) समुक्त स्कंध कम्पनियों के पूर्ण दत्त अश या अचल सम्पत्ति अथवा तत्सम्बन्धी अधिकार पत्र,

(ii) दिए गये ऋण, अग्रिम या साख के प्रति जमानत के रूप में प्राप्त ऋण-पत्र, प्रतिज्ञा-पत्र, अश, माल या माल के अधिकार पत्र आदि को उस समय बेचना और उनकी रकम बसूल करना, जब लिए हुए ऋण यथा समय वापिस न किए जाय।

(iii) विनिमय पत्र एवं अन्य परक्राम्य विलेखों को लिखना, सकारना, बढ़ा करना तथा क्रय-विक्रय करना।

(iv) ऊपर (i) में (क) से (ङ) तक की प्रतिभूतियों में अपने कोषों को विनियोजित करना एवं उन विनियोगों को नकद में परिवर्तित करना।

(v) ड्राफ्ट, टेलीग्राफिक ट्रान्सफर एवं अन्य राशि स्थानान्तरण-पत्र (remittances) को अपनी शाखाओं पर जारी करना या उन्हें खरीदना या आज्ञानुसार देय लेटर आफ नेडिट जारी करना ।

(vi) सोने-चाँदी का क्रय-विक्रय करना ।

(vii) जमा स्वीकार करना तथा नकद खाते रखना ।

(viii) सुरक्षा के निमित्त सभी प्रकार के बाण्ड, अधिकार-पत्र अथवा तथा बहुमूल्य वस्तुओं को रखना ।

(ix) ऋण की अदायगी के रूप में प्राप्त हुई चल या अचल सम्पत्ति को बेचना या उनकी राशि वसूल करना ।

(x) विधान के अन्तर्गत पजीयत किमी सहकारी बैंक के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना ।

(xi) ऊपर (iv) के अनुसार जिन अशो, ऋणपत्रों तथा प्रतिभूतियों में बैंक को अपने कोष विनियोजित करने का अधिकार है, उनका अभिगोपन (underwriting) करना ।

(xii) कमीशन लेकर अभिकर्ता का कार्य करना या क्षति पूति (Indemnity) गारंटी या जमानतदारी (Surety ship) की सविदायें करना ।

(xiii) प्रन्दासी (Executor), ट्रस्टी तथा निस्तारक (Liquidator) के रूप में कार्य करना ।

(xiv) विदेशों में भुगतान होने वाले विनिमय पत्र तथा लेटर आफ नेडिट लिखना ।

(xv) कृपि-कार्यों के निमित्त या विदेशों में भुगतान होने वाले बिलों का जो पंद्रह मास से अधिक अवधि के न हों, अथवा अन्य बिलों को, जो छः मास से अधिक के न हों, खरीदना ।

(xvi) अपने व्यवसाय के निमित्त उधार लेना और इस उधार के लिए जमानत में अपनी सम्पत्ति रहन रखना ।

(xvii) भारत में पजीयत किसी कम्पनी या सहकारी समिति को समापन से बचाने के लिए या समापन की सुविधा देने के लिए उसकी सम्पत्ति की जमानत पर ऋण, अग्रिम या नकद साख आदि देना ।

(xviii) रिजर्व बैंक की स्वीकृति से किसी अन्य बैंक को स्थापित करके उसे अपनी सहायक संस्था के रूप में चलाना, अथवा किसी बैंक के अशो का क्रय विक्रय करना अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी वित्तीय संस्था के अशो एवं ऋण पत्रों का क्रय-विक्रय करना ।

(xix) ऐसे अन्य व्यवसायी को करना जिसके लिए रिजर्व बैंक से सलाह कर या केन्द्रीय बोर्ड के सुझाव पर केन्द्रीय सरकार अधिकृत करे।

स्टेट बैंक अन्य व्यापारिक बैंको की भाँति मुद्रा के लेन-देन में मध्यस्थ का कार्य करता है, साख का सृजन करता है तथा अन्य विविध एव एजेन्सी के कार्य करता है। इसके अतिरिक्त देश में बैंकिंग सुविधाओं के प्रसार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-साख की व्यवस्था के सम्बन्ध में इसका विशेष उत्तरदायित्व है।

स्टेट बैंक की शाखा प्रगति (Branch Expansion of State Bank)

स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना है। इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया अधिनियम के अन्तर्गत ही स्टेट बैंक पर यह वैधानिक दायित्व सौंपा गया था कि अपनी स्थापना के प्रथम पाच वर्षों में स्टेट बैंक 400 नई शाखाएँ खोलेगा जिनमें से अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में होगी। जुलाई 1955 से जून 1960 तक की अवधि में 400 नई शाखाएँ खोलने के इस लक्ष्य की पूर्ति स्टेट बैंक ने एक माह पहले ही कर ली, जब 1 जून 1960 को कैराना (मुजफ्फर नगर) उत्तर प्रदेश में स्टेट बैंक की 400 वीं शाखा का उद्घाटन श्री मोरारजी देसाई ने किया। वास्तव में 30 जून 1960 तक 416 शाखाएँ खोली गयीं।

स्थापना के प्रथम दो वर्षों में शाखा विस्तार की गति अत्यन्त धीमी रही परन्तु धीरे धीरे उसमें वृद्धि हुई जो निम्न तालिका से स्पष्ट है—

स्टेट बैंक की शाखा प्रगति (जुलाई 1955 से जून 1960 तक)

वर्ष	शाखाएँ
1955 (जुलाई से दिसम्बर तक)	20
1956	46
1957	91
1958	105
1959	97
1960 (जून तक)	41
योग	400

प्रारम्भिक काल में शाखाओं का विस्तार अधिक तीव्र गति से इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि उपयुक्त भवनो तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों की कठिनाई थी।

विस्तार क्षेत्र 1955-60 के शाखा विस्तार कार्यक्रम की सफलता इस बात में थी कि 400 शाखाओं में से 286 अर्थात् 71 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गयीं। 286 में से 64 ऐसे स्थानों पर शाखाएँ खोली गयीं जहाँ पहले कोई बैंक नहीं था तथा 40 ऐसे स्थानों पर खोली गयीं जिनके 20 भौल के क्षेत्र में कोई बैंक नहीं था।

अनुकूलन एवं विकास कोष (Integration and Development Fund) : स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया अधिनियम के अन्तर्गत स्टेट बैंक द्वारा खोली जाने वाली नयी शाखाओं में होने वाली हानि की पूर्ति करने के लिए एक अनुकूलन एवं विकास कोष की स्थापना की व्यवस्था की गई है। इस कोष में स्टेट बैंक के 55 प्रतिशत अंश (जो रिजर्व बैंक के पास हैं) पर रिजर्व बैंक को मिलने वाला लाभ जमा होगा। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक तथा केन्द्रीय सरकार समय-समय पर रकम डालते रहेंगे। इस कोष की राशि से स्टेट बैंक को नई शाखाओं पर होने वाली हानि की पूर्ति की जाती है।

कव उप-समिति : जून 1960 तक 400 शाखाओं का लक्ष्य प्राप्त करने के बाद भावी विकास के लिए सिफारिशें करने के लिए स्वर्गीय प्रो० डी० जी० कर्वे (Prof. D. G. Karve) की अध्यक्षता में केन्द्रीय बोर्ड उप-समिति (Central Board Sub-Committee) की नियुक्ति हुई जिसने मई 1961 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में आगामी पांच वर्षों में 300 शाखाएँ खोलने का सुझाव दिया गया।

द्वितीय शाखा विस्तार योजना : शाखा विस्तार की द्वितीय योजना के अनुसार 30 जून 1965 तक स्टेट बैंक की 145 तथा सहायक बैंकों की 155 शाखाएँ खोलने का लक्ष्य रखा गया। बाद में इसे परिवर्तित कर स्टेट बैंक की 151 तथा सहायक बैंकों की 221 शाखाएँ खोलने का लक्ष्य बनाया गया। 30 जून 1965 तक स्टेट बैंक की 114 तथा सहायक बैंकों की 190 शाखाएँ खोली गयीं।

तृतीय शाखा विस्तार योजना तृतीय शाखा विस्तार योजना के अन्तर्गत 31 दिसम्बर 1968 तक 319 शाखाएँ खोलने का लक्ष्य रखा गया था जिसे प्राप्त कर लिया गया। वास्तव में 325 शाखाएँ खोली गयीं।

अन्तिम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 31 दिसम्बर 1968 को स्टेट बैंक की शाखाओं की संख्या 1557 तथा सहायक बैंकों की शाखाओं की संख्या 837 (कुल मिलाकर 2394 शाखाएँ) हो गयीं।

स्टेट बैंक तथा ग्रामीण साख

(State Bank and Rural Credit)

ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति, 1954 के सुझाव पर जब स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी तो उसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही था कि बैंक ग्रामीण साख सुविधाओं

के विस्तार में विशेष रूप से सहायक होगा। इसीलिए सहकारी संस्थाओं की आवश्यकताओं के प्रति बैंक अधिक मचेत है। 1958 से बैंक ने सहकारी संस्थाओं को विशेष सुविधायें देना प्रारम्भ किया है। ग्रामीण साल के क्षेत्र में स्टेट बैंक निम्न लिखित सुविधायें प्रदान करता है।

(1) सामान्य सहायता (General financial assistance and Remittance facilities) स्टेट बैंक सहकारी बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों तथा माल की धरोहर पर अग्रिम देने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त राज्य सहकारी बैंकों को धन प्रेषण (Remittance) की भी सुविधा देना है। स्टेट बैंक द्वारा 1958 में राज्य सहकारी बैंकों को लगभग 84 करोड़ रुपये की राशि एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रेषित की जाती थी जो राशि अब बढ़कर 700 करोड़ रुपये हो गई है।

(2) ऋण विक्रय तथा विधायन साल (Credit for Cooperative Marketing and Processing) स्टेट बैंक गैर साव सहकारी संस्थाओं जैसे सहकारी विपणन तथा विधायन समितियों, औद्योगिक तथा उपभोक्ता सहकारी समितियों को भी ऋण देने का व्यवस्था करता है।

(3) भूमिबन्धक बैंकों को सहायता (Financial Assistance to Land Mortgage Banks) स्टेट बैंक केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों को उनके द्वारा निगमित ऋण पत्र खरीदकर तथा ऋण-पत्रों की धरोहर पर उनको ऋण देकर उनकी सहायता करता है। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक भूमि बन्धक बैंकों को ऋण पत्र निगमित होने तक ऋण प्रक्रियाओं को चालू रखने के लिए अन्तरिम सहायता प्रदान करता है। 1966 में स्टेट बैंक के पास भूमि बन्धक बैंकों के लगभग 9 करोड़ रुपये के ऋण पत्र थे जो राशि 1968 में अन्त में बढ़कर 19.6 करोड़ रुपये हो गई। 1968 में स्टेट बैंक ने भूमि बन्धक बैंकों को 6.8 करोड़ रुपये की अन्तरिम सहायता दी।

(4) गोदामों के विकास के लिए सहायता (Support to Warehousing Movement) कृषि व्यवस्था में मालगोदामों के विकास में भी स्टेट बैंक ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। केन्द्रीय माल गोदाम निगम (Central Warehousing Corporation) में स्टेट बैंक ने 1 करोड़ रुपये के अग्रिम खरीद रखे हैं। माल गोदामों की रसीदा के आधार पर स्टेट बैंक ऋण देता है। 1968 में इन ऋणों की स्वीकृत राशि 6 करोड़ रुपये थी।

इसके अतिरिक्त कृषकों को प्रत्यक्ष वित्त के क्षेत्र में स्टेट बैंक महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। स्टेट बैंक ने सफर बीजों के उत्पादन के लिए सहायता दी है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अनुरोध पर बैंक कृषि विकास के एकीकृत कार्यक्रमों को वित्त सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

स्टेट बैंक द्वारा लघु उद्योगों को वित्त (Financing of Small Scale Industries by State Bank)

स्टेट बैंक लघु उद्योगों को भी वित्त सहायता देता है। लघु उद्योगों को एकीकृत वित्तीय सहायता (Coordinated Finance) देने के उद्देश्य से स्टेट बैंक ने अप्रैल 1956 में एक निदेशक योजना (Pilot Scheme) प्रारम्भ की थी। जिसके अन्तर्गत स्टेट बैंक की 9 शाखाओं पर लघु उद्योगों को वित्त सहायता देने की व्यवस्था की गई। 1957 में इस सुविधा को 36 तथा 1958 में 53 शाखाओं पर दी जाने लगी। लघु उद्योगों को ऋण देने सम्बन्धी इस प्रयोग की सफलता के फलस्वरूप 1 जनवरी 1959 से इस निदेशक योजना को सभी शाखाओं पर लागू कर दिया गया। 1960 से इस योजना में सहायक बैंकों ने भी भाग लेना प्रारम्भ कर दिया तथा ऋण देने की प्रणाली को अधिक सरल बनाया गया। इस योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों को उनकी कार्यशील पूँजी की आवश्यकता पूर्ति के लिए कच्चे माल अथवा निर्मित माल की धरोहर पर ऋण दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत स्टेट बैंक द्वारा दी गई वित्त सहायता जो 30 जून 1968 को 124.34 करोड़ रुपये थी, 30 दिसम्बर 1968 का बढ़कर 149.76 करोड़ हो गई।

रिजर्व बैंक की साख गारन्टी योजना (Reserve Bank's Credit Guarantee Scheme).—रिजर्व बैंक द्वारा लघु उद्योगों को दिए जाने वाले ऋणों को गारन्टी करने के लिए एक योजना बनाई गई। स्टेट बैंक ने लघु उद्योगों को दिए जाने वाले ऋणों को इस योजना के अन्तर्गत लाने का निर्णय किया। प्रारम्भ में यह 1 जुलाई 1960 से 22 जुने हुए जिलों में प्रयोग के स्तर पर शुरू हुई और फिर जून 1961 में इसे 52 और जिलों में लागू किया गया। 1 जनवरी 1963 से इसे स्टेट बैंक के कार्यों का अंग बना लिया गया।

साख गारन्टी योजना का मुख्य लक्ष्य व्यापारिक बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विस्तार करना है। इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम स्वीकृत राशि पर $\frac{1}{4}$ प्रतिशत गारन्टी चार्ज (Guarantee Charge) लिया जाता है।

लघु उद्योगों को सहायता की कुछ नवीन योजनाएँ

स्टेट बैंक लघु उद्योगों को सहायता की प्रकृति तथा क्षेत्र का विस्तार करने को निरन्तर उत्सुक है। निम्नलिखित योजनाएँ इसका प्रमाण हैं :

पंजाब की Qualified Entrepreneurs Scheme.—पंजाब सरकार की प्रार्थना पर स्टेट बैंक ने पंजाब में लघु उद्योगों के विकास के लिए एक नई योजना प्रारम्भ की है जिसके अन्तर्गत निर्माण, विधायन या माल के भण्डार से सम्बन्धित

योजना वाले साहसियों को 2 लाख रुपये तक ऋण प्राप्त हो सकेंगे। केवल उनके पास अनुभव, तकनीकी ज्ञान तथा प्रामाणिकता होनी चाहिए। ऋण के लिए कोई जमानत देने की आवश्यकता नहीं होगी।

फुटकर व्यापारियों तथा ट्रक चालकों को सहायता की योजना प्रस्तावित : मई 1969 में स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री आर० के० तलवार की एक घायणा के अनुसार स्टेट बैंक शीघ्र ही छोटे नगरों के फुटकर दुकानदारों तथा ट्रक चालकों (Truck Operators) को 50 हजार रुपये तक की राशि के ऋण देगा।

लघु उद्योगों को अल्प तथा मध्यकालीन वित्त सहायता के अनिश्चित स्टेट बैंक लघु औद्योगिक इकाइयों को कई प्रकार से सहायता देना है जैसे कच्चे माल के आयात के लिए लाइसेंस दिलवाना, अन्य विशिष्ट समस्याओं जैसे राज्य वित्तीय निगमों, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा राज्यों के लघु उद्योग निगमों से सहायता लेने में परामर्श।

स्टेट बैंक की प्रगति (Progress of State Bank)

स्टेट बैंक ने जुलाई 1955 में अपनी स्थापना से अब तक लगातार प्रगति के नये कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देश के बैंकिंग संगठन में स्टेट बैंक का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। स्टेट बैंक की नवीनतम प्रगति निम्न तालिका से ज्ञात होनी है

स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंकों की स्थिति
(28 मार्च 1969)

(करोड़ रुपये में)

	स्टेट बैंक समूह			सभी अनुसूचित बैंक
	स्टेट बैंक	सहायक बैंक	योग	
कायालय सख्या	1,557 (31 12 68)	837 (31 12 68)	2,394	
निक्षेप	950 4	268 1	1,218 5	4,329 0
ऋण तथा अग्रिम	801 2	221 8	1,023 0	3,369 7
विनियोग	294 3	64 8	359 1	1 067 1

स्टेट बैंक की उपर्युक्त स्थिति तथा सतोपजनक प्रगति के आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विकास तथा देश की आर्थिक उन्नति में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संकेत

(1) देश की अधिकोषण प्रणाली में स्टेट बैंक आफ इन्डिया के स्थान की विवेचना कीजिए। दश के ग्रामीण साख विराम में इसका क्या योगदान होगा ?

(राजस्थान टी०डी०सी० फाइनल, 1964)

[संकेत - प्रथम भाग में व्यापारिक बैंको में सबसे बड़े बैंक होने के नाते स्टेट बैंक आफ इन्डिया के महत्त्व तथा प्रगति का वर्णन कीजिए। दूसरे भाग में ग्रामीण साख के क्षेत्र में उसके विशेष योगदान तथा उसमें प्राप्त सफलता की व्याख्या कीजिए।]

(2) स्टेट बैंक आफ इन्डिया के कार्यों की विवेचना कीजिए।

(आगरा ची० काम०, 1962)

[संकेत - स्टेट बैंक आफ इन्डिया के मुख्य कार्यों का विवेचन कीजिए। स्टेट बैंक के ग्रामीण साख तथा लघु उद्योग वित्त के क्षेत्र में विशेष उत्तरदायित्व की व्याख्या कीजिए।]

(3) स्टेट बैंक आफ इन्डिया के ग्रामीण वित्त एवं लघु उद्योग वित्त सम्बन्धी कार्यों का विवेचन कीजिए।

(राजस्थान टी० डी० सी० फाइनल)

[संकेत : स्टेट बैंक की ग्रामीण साख तथा लघु उद्योग वित्त के क्षेत्र में की जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए।]

कृषि-वित्त (Agricultural Finance)

"Indigenous banking is at the cross roads It has to choose between the challenge of change or the threat of elimination It must recognise that the background against which it has to work in future has charged beyond recognition."

भारत जैसे कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व के सम्बन्ध में जितना कहा जाय कम है। कृषि का विकास देश की पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य लक्ष्य रहा है। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कई कारण हैं परन्तु उनमें एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि भारत में अन्य विकसित कृषि प्रधान देशों की तरह संगठित वित्तीय संस्थाओं का अभाव रहा है और कृषकों को कृषि प्रक्रियाओं को करने के लिए पर्याप्त साख प्राप्त नहीं हो पाती।

कृषकों की साख आवश्यकताएँ (Credit needs of the Agriculturists)

कृषकों की साख आवश्यकताएँ कई प्रकार की हो सकती हैं। उद्देश्य की दृष्टि से उनकी साख आवश्यकताओं को कृषि, गैर-कृषि, उपभोग, पुराने ऋण इत्यादि वर्गों में बाटा जा सकता है। कृषि सम्बन्धी साख आवश्यकताओं को अविधि की दृष्टि से तीन भागों में बाटा जाता है—(1) अल्पकालीन आवश्यकताएँ (2) मध्यकालीन आवश्यकताएँ तथा (3) दीर्घकालीन आवश्यकताएँ।

अल्पकालीन साख (Short term credit) : वह साख है जो कृषकों की चालू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ली जाती है। यह साख बीज-खाद खरीदन, लगान बढ़ा करने तथा कृषि प्रक्रियाओं (Agricultural Operations) के व्यय चलाने के लिए आवश्यक होती है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने 15 मास तक के लिए दिए जाने वाले ऋणों को अल्पकालीन ऋण माना है।

मध्यकालीन ऋण (Medium term Credit) : मध्यकालीन ऋणों की आवश्यकता पशु तथा कृषि उपकरण खरीदने तथा भूमि में मुधार के लिए होती है। यह ऋण 15 मास से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए दिए जाते हैं।

दीर्घकालीन ऋण (Long term Credit) : दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता भूमि त्रय करने, महंगे कृषि यन्त्र खरीदने तथा भूमि पर दीर्घकालीन सुधार जैसे सिंचाई व्यवस्था, चकबंदी इत्यादि करने या पुराने ऋणों को भ्रदा करने के लिए प्राप्त किए जाते हैं। यह ऋण 15-20 वर्षों के लिए दिए जाते हैं।

कृषि-वित्त के स्रोत (Sources of Agricultural Finance) :

देश में कृषकों को वित्त सुविधायें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती हैं। कृषि वित्त के मुख्य स्रोत हैं—(1) साहूकार-महाजन (2) स्वदेशी बैंकर (3) सहकारी साख सस्थायें (4) स्टेट बैंक सहित व्यापारिक बैंक (5) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया तथा (6) राज्य इत्यादि। 1954 में ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति (Rural Credit Survey Committee) ने कृषि वित्त में विभिन्न स्रोतों के योगदान के अनुमान इस प्रकार लगाये थे :

(प्रतिशत)

	1951-52	1961-62
व्यावसायिक साहूकार	44.8	13.2
कृषक साहूकार	24.9	36.0
सम्बन्धी	14.2	8.8
व्यापारी तथा कमीशन एजेंट्स	5.5	8.8
राज्य	3.3	2.6
सहकारी सस्थायें	3.1	15.5
जमींदार	1.5	0.6
व्यापारिक बैंक	0.9	0.9
अन्य सस्थायें	1.8	13.9
	100.0	100.0

पिछले 15 वर्षों में उपर्युक्त स्थिति में बड़ा परिवर्तन हो गया है। सहकारी सस्थाओं द्वारा कृषि वित्त में योगदान 3.1 प्रतिशत से बढ़कर 15.5 प्रतिशत हो गया है। भारत सरकार के खाद्य-मन्त्रालय की 66-67 की रिपोर्ट के अनुसार कृषि वित्त में सहकारी सस्थाओं का योगदान 1966-67 में बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया है।

इस अध्याय में हम साहूकारों तथा स्वदेशी बैंकों का विस्तृत विवेचन करेंगे।

साहूकार-महाजन (Money Lender)

कृषि वित्त व्यवस्था में साहूकार का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। साहूकार या महाजन वह व्यक्ति है जो समय-समय पर अपने ग्राहकों को बिना जमानत के ऋण प्रदान

करते हैं। साहूकार दो प्रकार के होते हैं। एक तो पेशेवर साहूकार (Professional Money Lenders) जो लेन-देन के साथ अनाज के ऋय-विक्रय का व्यापार भी करते हैं। दूसरे गैर-पेशेवर साहूकार (Non-professional Money Lenders) जो सम्पन्न कृषको, व्यापारियों, वकीलो, पेन्शन पाने वालो आदि के वर्ग में आते हैं।

पेशेवर साहूकार या तो कहे जादे के द्वारा या व्यक्तिगत जमानत पर अल्प-कालीन ऋण देते हैं तथा भूमि, मकान तथा आभूषण का रेहन (Mortgage) रखकर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ऋण वस्तु या नरुद दोनो रूपों में दिए जाते हैं। परिवर्तित आर्थिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों के कारण साहूकार तथा ऋणियों के सम्बन्ध ठीक नहीं है। ऋणी भुगतान से बचने के लिए काहूनी व्यवस्थाओं की आड लेना चाहते हैं और साहूकार विभिन्न प्रकार की अवाञ्छनीय क्रियाये करते हैं। फेरी वाले साहूकार (Itinerant Money Lenders) जैम उत्तर प्रदेश में रोहिल्ला आदि निर्धन कारखाना श्रमिकों, अल्प वेतन भोगी वनकों जैसे लोगों को रुपया उधार देते हैं। ऋण का भुगतान न होने पर वे न्यायालय में न जाकर घमकी या हिंसा का प्रयोग करते हैं। गैर-पेशेवर साहूकार पेशेवर साहूकारों की तुलना में अधिक बेईमान होते हैं।

साहूकार काम पर लगे तथा वेकार, भूमि स्वामी कृषक तथा कृषि-श्रमिकों सभी को ऋण प्रदान करते हैं। वे उत्पादक तथा अनुत्पादक सभी प्रकार के कार्यों के लिए ऋण देते हैं। कृषक अपनी पारिवारिक तथा कृषि आवश्यकताओं के लिए, व्यापारी व्यापार के लिए, वेतन भागी कमचारी इलाज तथा बच्चों की शिक्षा के लिए तथा अन्य व्यक्ति सामाजिक सभाराही तथा मुकदमेवाजी आदि के लिए साहूकारों से रुपया उधार लेते हैं।

व्यापार की कार्य प्रणाली तथा व्याज दर (Working method of Business and Rate of Interest) साहूकार-महाजनों की कार्य प्रणाली बड़ी सरल तथा लोचदार होती है। ऋणी की उस तक पहुँच (Access) बड़ी आसान होती है। ऋणी की आर्थिक स्थिति तथा चरित्र की उसे पूर्ण जानकारी होती है और उसके द्वारा दिए गये ऋण की रकम डूबने की कोई सम्भावना नहीं होती। उनका हिसाब किताब रखने का ढंग भी बहुत सरल होता है। साहूकारों द्वारा दिए गये ऋणों पर व्याज की दर बहुत उँची होती है। यदि जमानत अच्छी है तो व्याज की दर 12 प्रतिशत से 37 प्रतिशत तक होती है। कभी कभी यह 50 प्रतिशत या इससे भी अधिक होती है।

साहूकारों के दोषपूर्ण कार्य (Objectionable Practices of Money Lenders) : यद्यपि साहूकारों की कार्य प्रणाली अत्यन्त सरल तथा लोचदार है परन्तु उनकी अवाञ्छनीय कार्यवाहियों की सदा से ही आलोचना होती रही है। उनके

सम्बन्ध में लोग विभिन्न विचार रखते हैं। "Some condemn them altogether as unscrupulous usurers, land grabbers and fomentors of factions and law suits, others commend them as the friends of peasants, the traditional guardians of their property and ever present helpers in times of need." कुछ तो उनकी दोषपूर्ण कार्यवाहियों तथा ऋणियों के शोषणकर्ता होने के कारण उनको 'भारतीय शाइलाक' (Indian Shylock) कहते हैं। उनकी कुछ दोषपूर्ण कार्यवाहियाँ निम्नलिखित हैं।

(1) साहूकार ऋण देते समय जितना ऋण देते हैं उससे अधिक राशि का प्रतिज्ञा पत्र भरवा लेते हैं। कभी-कभी खाली कागज पर हस्ताक्षर करा लेते हैं या अंगूठा लगवा लेते हैं और बाद में मनमानी रकम भर लेते हैं।

(2) ऋण की रकम में से ब्याज की रकम अग्रिम काट लेते हैं।

(3) वही खाता में ऋणी का खाता खोलते समय गैर स्वरूप कुछ रकम लेते हैं जिसे 'गिरह खुलाई' कहते हैं। इसके अतिरिक्त कई अनधिकृत पटौतियाँ जैसे धर्मादा इत्यादि काट लेते हैं।

(4) हिसाब-किताब में कई प्रकार की गड़बड़ करते हैं। किस्त का भुगतान करने पर न तो रसीद देते हैं और न ऋणियों को उनका हिसाब भेजते हैं।

(5) कभी-कभी ऋण देते समय ऋणी की दुर्बल स्थिति का लाभ उठाकर उसकी फसल को खरीदने का समझौता कर लिया जाता है जिससे कृषक को काफी हानि होती है।

(6) साहूकार द्वारा ली गई ब्याज की दर बहुत ऊँची होती है और इस प्रकार ऋणियों का अधिकतम शोषण होता है। जिन परिस्थितियों में साहूकार ऋण देता है उनमें ब्याज दर का अधिक होना कुछ तो स्वामाविक ही है परन्तु फिर भी ब्याज दर बहुत ऊँची होती है।

(7) कहीं-कहीं ऋणियों से बेगार भी ली जाती है।

साहूकारों के कार्यों पर नियंत्रण (Regulation of Money Lender's activities) : साहूकारों के दोषपूर्ण तथा अवाञ्छनीय कार्यवाहियों का नियमन करने के लिए समय समय पर विभिन्न नियम तथा अधिनियम बनाये जाते रहे हैं। 1918 में (Usurious Loan Act) द्वारा सभी राज्यों में अधिक ब्याज वाले ऋणों की जाँच तथा ब्याज कम करने की व्यवस्था की गई। विभिन्न राज्यों में पारित नियमों द्वारा साहूकारों द्वारा हिसाब-किताब रखना आवश्यक कर दिया गया है। पंजाब, बिहार, आसाम, उत्तर-प्रदेश आदि में ब्याज की अधिकतम सीमा निश्चित की गई है। विभिन्न राज्यों में ऋणी को तय करने के सम्बन्ध में नियम (Debt Conciliation Acts) पारित किए गए। पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि प्रान्तों में ऋण सम्बन्धी मामलों में कृषक की सम्पत्ति को बेचने से रोकने के लिए नियम बनाये गये।

साहूकारों की क्रियाओं को नियन्त्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के नियम तो बनाये गये हैं परन्तु उनका पालन न होने के कारण साहूकारों की दोषपूर्ण कार्य-वाहियाँ रोकने में कोई विशेष सफलता नहीं मिली है।

स्वदेशी बैंकर

(Indigenous Bankers)

देश के आन्तरिक व्यापार की वित्त व्यवस्था करने में स्वदेशी बैंकर्स का महत्वपूर्ण स्थान है। वे अप्रत्यक्ष रूप से कृषि वित्त व्यवस्था में योगदान करते हैं।

परिभाषा (Definition) : स्वदेशी बैंकर्स की ठीक परिभाषा करना बड़ा कठिन है क्योंकि इन्हें साहूकार महाजन से पृथक् करना कठिन होता है। स्वदेशी बैंकर्स से हमारा तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो जमा राशि प्राप्त करते हैं, हुण्डियों का लेन-देन करते हैं तथा धन उधार देते हैं। केन्द्रीय बैंकिंग जाच समिति (Central Banking Enquiry Committee) 1929 के अनुसार "इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया, विनिमय बैंक, व्यापारिक बैंक तथा सहकारी समितियों को छोड़कर जो फर्म हुण्डियों का व्यवहार करती हो, जनता से जमा प्राप्त करती हो तथा ऋण देती हो, स्वदेशी बैंकर्स कहलाती हैं।"¹

डा० एल० सी० जैन (Dr L C Jain) के अनुसार "स्वदेशी बैंकर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तिगत फर्म है जो ऋण देने के साथ ही जमा स्वीकार करती है या हुण्डियों में व्यवहार करती है या दोनों कार्य करती है।"² सक्षेप में, स्वदेशी बैंकर उन लोगों को कहते हैं जो हुण्डियों का व्यावसाय करते हों, निक्षेप स्वीकार करते हों एवं हथिया उधार देते हों। साधारणतया स्वदेशी बैंकर बैंकिंग तथा व्यापार दोनों ही कार्य करते हैं और बैंकिंग तथा अन्य व्यापार में लगी उनकी पूंजी में कोई भेद नहीं होता।

देश के विभिन्न भागों में इनके भिन्न भिन्न नाम हैं। बंगाल में इन्हे सेठ व बनिया, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में साहूकार, महाजन व सूत्री, बम्बई में सर्राफ व मारवाडी तथा मद्रास में चेट्टी कहा जाता है। स्वदेशी बैंकिंग व्यवसाय एक पारि-

¹ "All bankers other than the Imperial Bank of India, Exchange Banks, the Joint Stock Banks and Cooperative Societies and the expression includes any individual or private firm receiving deposits and dealing in Hundies or lending money"

—Central Banking Enquiry Committee, 1929

² "Any individual or private firm which in addition to making loans, either receives deposits or deals in Hundies or both"

—Dr. L C Jain : *Indigenous Banking in India*,

वारिक व्यवसाय है। यह लोग अपने लेखे जनता को नहीं दिखाते, इनके लेन-देन के हग गुप्त रहते हैं और इनकी व्याज की दर बहुत ऊँची होती है।

स्वदेशी बैंकर तथा साहूकार में भेद (Difference between Indigenous Bankers and the Money Lenders) स्वदेशी बैंकरो तथा साहूकारो में कुछ महत्वपूर्ण भेद इस प्रकार हैं

(1) स्वदेशी बैंकर ऋण देने के अतिरिक्त निक्षेप प्राप्त करते हैं और हुंडियो में व्यवहार करते हैं जबकि साहूकार केवल ऋण ही देते हैं।

(2) स्वदेशी बैंकर अधिकतर व्यापार तथा उद्योगों की वित्त व्यवस्था करते हैं जबकि साहूकार अधिकतर कृषि कार्यों तथा उपभोग के लिए ऋण देते हैं।

(3) स्वदेशी बैंकर साहूकार की तुलना में कम व्याज की दर लेता है।

(4) स्वदेशी बैंकर मुख्यतः बैंकिंग कार्य करता है परन्तु साहूकार लेन देन के कार्य के साथ व्यापार भी करता है और व्यापार उसका मुख्य धन्धा होता है।

(5) स्वदेशी बैंकर अपने स्वयं के लोगों के अतिरिक्त निक्षेपों से भी ऋण देते हैं जबकि साहूकार अपने निजी धन से ही ऋण देते हैं।

स्वदेशी बैंकर्स के कार्य (Functions of Indigenous Bankers) . स्वदेशी बैंकर संगठित बैंकिंग प्रणाली तथा राशि उधार लेने वालों के उस वर्ग के बीच एक अनिवार्य कड़ी का काम करते हैं जिस वगैरे संगठित बैंक किन्हीं कारणों से प्रत्यक्ष रूप में नहीं पहुँच पाते। स्वदेशी बैंकर्स के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं

(1) जनता से निक्षेप स्वीकार करना (Accepting of Deposits) स्वदेशी बैंकर जनता से निक्षेप प्राप्त करते हैं। इन निक्षेपों पर वे सहकारी सस्थाओं तथा आधुनिक बैंकों से अधिक व्याज देते हैं। निक्षेप की राशि तथा अवधि के अनुसार वे 3 से 9 प्रतिशत तक व्याज देते हैं। निक्षेप खाता पैदा पद्धति के अन्तर्गत प्राप्त किए जाते हैं।

(2) ऋण देना (Lending of Money) स्वदेशी बैंकर मुख्यतः व्यापार, उद्योग आदि के कार्यों के लिए ऋण देते हैं। कभी-कभी वे उपभोग के कार्यों के लिए भी ऋण देते हैं। अच्छी जमानत के ऋण पर 6 से 18 प्रतिशत तथा अपर्याप्त जमानत के ऋण पर 18 से 39 प्रतिशत और कभी कभी 50 प्रतिशत तक व्याज लेते हैं। वे व्यापारियों तथा लघु उद्योगपतियों से घनिष्ट सम्बन्ध रखते हैं और कृषि जन्य तथा औद्योगिक पदार्थों को ग्रामीण क्षेत्रों से बाजारों तथा मण्डियों में लाने में सहायता करते हैं।

(3) हुंडियों में व्यवहार करना (Dealing in Hundies) हुंडियों में लेन-देन करना स्वदेशी बैंकर्स का महत्वपूर्ण कार्य है। वे विभिन्न प्रकार की हुंडिया जारी करते

हैं तथा उनका श्रय विनय करते हैं। इसके अतिरिक्त वे व्यापारियों की वृद्धियों का बढ़ा भी करते हैं। मुद्रतानी बैंकर बड़े पैमाने पर वृद्धियों का व्यवहार करते हैं।

(4) अन्य व्यापार (Other Businesses) स्वदेशी बैंकर उक्त बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त कुछ गैर बैंकिंग कार्य भी करते हैं। बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग कार्य साथ-साथ चलते हैं। स्वदेशी बैंकर व्यापार या दूकानदारी करते हैं तथा व्यापारिक फर्मों के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं।

स्वदेशी बैंकरो के दोष (Defects of Indigenous Banking)

यद्यपि स्वदेशी बैंकरो का कृषि, आन्तरिक व्यापार तथा उद्योगों की वित्त-व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण स्थान है परन्तु इनकी काय प्रणाली तथा संगठन में अनेक दोष हैं जिनमें मुख्य निम्नलिखित है—

(1) बैंकिंग व्यापार के साथ अन्य व्यापार (Banking business combined with other businesses) स्वदेशी बैंकर बैंकिंग व्यापार के साथ साथ व्यापार या दूकानदारी या सट्टा जैसे गैर-बैंकिंग कार्य भी करते हैं जिनका हिसाब किताब अलग नहीं रखा जाता। स्वस्थ बैंकिंग सिद्धान्तों के अनुसार बैंकों को व्यापार नहीं करना चाहिये।

(2) धोखेबाजी तथा अनुचित व्यवहार (Dishonesty) स्वदेशी बैंकर हिसाब किताब के मामले में धोखाधड़ी तथा अनुचित व्यवहार करते हैं। ग्राहकों की अज्ञानता का लाभ उठाकर वे कई प्रकार से उनका शोषण करते हैं।

(3) ऊँची ब्याज दर (High Rate of Interest) स्वदेशी बैंकरो द्वारा ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज की दर बहुत ऊँची होती है।

(4) कार्यशील पूँजी का अभाव (Inadequacy of Working Capital) स्वदेशी बैंकरो के पास पूँजी साधन अपर्याप्त होते हैं क्योंकि अधिकतर वे अपने निजी साधनों पर निर्भर रहते हैं और अन्य बाह्य साधनों से पूँजी नहीं प्राप्त करते।

(5) कार्यविधियों में भिन्नता (Diversity in working) स्वदेशी बैंकरो की कार्यविधियों में बड़ा भिन्नता पाई जाती है जिससे इनके बैंकिंग कार्यों की जांच तथा अन्वेषण में बड़ी कठिनाई आती है।

स्वदेशी बैंकरो में सुधार के सुझाव (Suggestions for Improvement)

स्वदेशी बैंकरो के संगठन तथा कार्यप्रणाली में सुधार करने की बड़ी आवश्यकता है। इस दिशा में निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं—

(1) रिजर्व बैंक का नियन्त्रण (Control of Reserve Bank) : स्वदेशी बैंकरो को मुद्रा बाजार के सगठित भाग के अन्तर्गत लाने तथा उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए उन पर रिजर्व बैंक का नियन्त्रण होना चाहिए। रिजर्व बैंक द्वारा उन पर पूँजी, निक्षेप तथा कार्यविधि के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाये जाने चाहिये। बिना रिजर्व बैंक के लाइसेंस के कोई भी स्वदेशी बैंकर बैंकिंग व्यवसाय न कर सके। इसके बदले में रिजर्व बैंक को उन्हें पुनः बट्टा (Re discount) की सुविधा देनी चाहिये।

(2) अन्य कार्य समाप्त करें (Shedding of non-banking business) : स्वदेशी बैंकरो को बैंकिंग कार्य के साथ व्यापार तथा सट्टा जैसे गैर-बैंकिंग कार्यों को समाप्त करना चाहिये।

(3) ब्याज दर नियन्त्रित की जाय (Rate of Interest should be Controlled) : स्वदेशी बैंकरो द्वारा ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज की ऊँची दर का कम किया जाना चाहिये। सगठित स्वदेशी बैंकरो को रिजर्व बैंक या व्यापारिक बैंको द्वारा रियायती दर पर पुनः बट्टा की सुविधायें मिलने पर ब्याज दरों में कमी आ सकती है।

(4) हुडियो को बिलों के समकक्ष माना जाय (Hundies may be transformed into Bills) : रिजर्व बैंक द्वारा हुडियो को भी असीमित परक्राम्यता (Negotiability) प्रदान करने के लिए उनको बिलों की तरह अत्यधिक तरल सम्पत्ति माना जाय। हुडियो को बिलों में परिवर्तित करने की सुविधा उपलब्ध की जाय। स्वदेशी बैंकरो को केवल व्यापारिक बिलों (Trade Bills) में ही व्यवहार करने तथा हुडियो को प्रामाणित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आफ समिति ने इस दिशा में बड़े उपयोगी सुझाव दिये थे।

(5) स्वदेशी बैंकरो को स्वयं मिलकर बैंकिंग कम्पनिया बनानी चाहिये या व्यापारिक बैंकों में मिल जाना चाहिये (Should, in appropriate groups, either form banking companies or merge with existing banks) : स्वदेशी बैंकरो को स्वयं मिलकर बैंकिंग कम्पनियों के रूप में सगठित हो जाना चाहिये या व्यापारिक बैंकों में मिल जाना चाहिये। देना, सिन्डीकेट, आर्द्र तथा कनारा बैंक इस दिशा में अनुकरणीय उदाहरण हैं।

(6) आधुनिक सगठन तथा कार्यपद्धति अपनाना (Should adopt modern organisation and working methods) : समय की मांग है कि स्वदेशी बैंकर आधुनिक सगठन तथा पद्धतिया अपनानें।

उपर्युक्त सुझावों के अतिरिक्त 1954 में आफ समिति ने उनकी कार्य-प्रणाली, सगठन तथा आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए विस्तार से सिफारिशें की थीं। उन सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाय।

रिजर्व बैंक तथा स्वदेशी बैंकर
(Reserve Bank and Indigenous Bankers)

रिजर्व बैंक ने स्वदेशी बैंकरो को समग्र क्षेत्र के अग्रगण्यतं लाने तथा उन पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए कई बार प्रयत्न किए हैं, परन्तु इस दिशा में उसके प्रयत्न सफल नहीं हुए हैं। सर्वप्रथम रिजर्व बैंक ने 1937 में स्वदेशी बैंकरो से सद्यः स्थापित करने की एक योजना प्रस्तुत की जिसमें स्वदेशी बैंकरो को (1) गैर-बैंकिंग कार्यं समाप्त करने (2) हिसाब-किताब ठीक प्रकार से बनाने तथा (3) अपने व्यापार के नियमन तथा निरीक्षण का रिजर्व बैंक का अधिकार स्वीकार करने की व्यवस्था थी। इन शर्तों की पूर्ति पर रिजर्व बैंक से उन्हें पुनः ऋण, पुनर्वित्त, प्रेषण (Remittance) तथा प्रतिभूतियों के आधारे पर अग्रिम इत्यादि की सुविधायें प्राप्त होनी थीं। परन्तु स्वदेशी बैंकरो को यह प्रस्ताव मान्य नहीं थे। 1941 में बम्बई आफ सच की प्रार्थना पर यह प्रश्न फिर उठा। इस बार रिजर्व बैंक ने अन्य व्यापार समाप्त करने की शर्तें न रखकर प्रारम्भ में उन्हें बैंकिंग व्यवसाय से पृथक् करने तथा निश्चित अवधि के बाद समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। यह भी स्वदेशी बैंकरो को अमान्य रहा। 1946 में बैंकिंग कम्पनी बिल सम्बन्धी प्रवर समिति ने इन समस्या के सभी पक्षों पर विचार किया। समिति ने स्वदेशी बैंकरो के प्रत्यक्ष एकीकरण की प्रक्रिया में कई वैधानिक कठिनाइयाँ बताईं। 1950 तथा 1951 में फिर इस प्रश्न पर पुनर्विचार हुआ परन्तु कोई सफलता नहीं मिली।

आफ समिति के सुझाव (Shroff Committee's Recommendations):
निजी क्षेत्र के लिए वित्त समस्या का अध्ययन करने के लिए आफ समिति (The Shroff Committee on Finance for the Private Sector) ने 1954 में स्वदेशी बैंकरो को रिजर्व बैंक से सम्बद्ध करने के लिए अनेक सुझाव दिए—

(1) रिजर्व बैंक को सन्तुष्ट होकर इस प्रश्न पर ध्यान देना चाहिये तथा शर्तों से विचार विमर्श करना चाहिये।

(2) जब तक स्वदेशी बैंकर रिजर्व बैंक से सम्बद्ध न हो जाय तब तक जो शर्तों दर्शनी हुईयों में व्यवसाय करते हैं, वे 90 दिनों की मुदती हुईयों में व्यवसाय करने के प्रश्न पर विचार करें। हुईयों के प्रचलन को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार को इन पर मुद्रांक कर में कमी करनी चाहिए।

(3) रिजर्व बैंक स्वदेशी बैंकरो के सावधि बिलों को अनुसूचित बैंकरो के माध्यम से पुनः बट्टा करे। रिजर्व बैंक को अनुसूचित बैंकरो को स्वदेशी बैंकरो के अनुमोदित बिलों के आधारे पर अग्रिम देना चाहिये।

(4) शर्तों को अपने लाने राष्ट्रभाषा या अंग्रेजी में ठीक प्रकार से बनाने चाहिए। शर्तों को एक अखिल भारतीय सच बनाना चाहिये जिसका विधान रिजर्व बैंक से स्वीकृत कराया जाय।

(5) चूँकि शर्माफ अधिकतर व्यापार तथा उद्योग की वित्त व्यवस्था करते हैं इसलिए उन पर ऋण कानून लागू नहीं होने चाहिये ।

दुख का विषय है कि श्राफ समिति के उपर्युक्त रचनात्मक सुझावों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । 1961 में फिर अखिल भारतीय श्राफ सम्मेलन ने रिजर्व बैंक से प्रत्यक्ष सम्बद्ध रखने का प्रस्ताव किया परन्तु कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण प्रत्यक्ष एकीकरण कठिन लगा । रिजर्व बैंक श्राफ समिति के कथनानुसार विल बाजार योजना के अन्तर्गत प्राथमिक एकीकरण के लिए तैयार था परन्तु शर्माफ सभ की ओर से ढील के कारण इसमें कुछ भी प्रगति न हो सकी ।

स्वदेशी बैंकरो का भविष्य (Future of Indigenous Bankers) :
स्वदेशी बैंकर परिवर्तित परिस्थिति के अनुसार अपने को परिवर्तित करने में असमर्थ है । व्यापारिक तथा सहकारी बैंकों के भौगोलिक तथा कार्यात्मक क्षेत्र में लगातार विस्तार होने के कारण स्वदेशी बैंकरो के व्यापार में काफी कमी हो गई है । ऊँची व्याज दर, परिवर्तन की योग्यता तथा इच्छा के अभाव तथा सार्वजनिक दृष्टि में उनकी अच्छी कल्पना न होने के कारण भावी वर्षों में अपने अस्तित्व के लिए स्वदेशी बैंकरो को काफी प्रयत्न करना होगा । यह विचार कि भविष्य में स्वदेशी बैंकर समाप्त हो जायेंगे पूर्णतया अतिरिक्त है । आधुनिक व्यापारिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों के विस्तार के बावजूद अर्थव्यवस्था में स्वदेशी बैंकरो का स्थान बना रहेगा । छोटे-छोटे ऋणियों की बढ़ती मांगों की पूर्ति सगठित संस्थाएँ नहीं कर सकेंगी और यह कार्य स्वदेशी बैंकरो को ही सम्पन्न करना होगा । यदि स्वदेशी बैंकर समय का रक्त पहचान कर अपने में आवश्यक सुधार कर सकें तो उनका भविष्य निश्चित ही उज्वल है ।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संकेत

1. भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में स्वदेशी बैंकरो का क्या महत्व है ? देश के लिए उन्हें अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्या उपाय किये जाने चाहिये ।

(विजय वी० काम०, 1959)

[संकेत—प्रथम भाग में स्वदेशी बैंकरो द्वारा व्यापार तथा उद्योग को दी जाने वाली वित्त सुविधा को चर्चा करते हुए भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में उनके महत्व का विवेचन कीजिये । दूसरे भाग में उनके सुधार के सुझाव दीजिये । इस सन्दर्भ में श्राफ समिति की सिफारिशों का उल्लेख कीजिये ।]

2. स्वदेशी बैंकरो तथा उनकी कार्य प्रणाली पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये । उनके दोषों को दूर करने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं ?

(राजपूताना, 1958)

[संकेत—प्रथम भाग में स्वदेशी बैंकरो की परिभाषा, कार्यप्रणाली तथा महत्व की विवेचना कीजिये । दूसरे भाग में उनके दोषों को दूर करने के सुझाव दीजिये । इस सन्दर्भ में श्राफ समिति की सिफारिशों का विवेचन कीजिये ।]

सहकारी तथा भूमि बंधक बैंक (Cooperative and Land Mortgage Banks)

"If co operation fails, there will fail the best hope for rural India."

Royal Commission on Agriculture (1927)

सहकारी बैंको की परिभाषा (Definition of Co-operative Banks)

"सहकारी बैंक इस प्रकार की एजेन्सी है जो छोटे आदमियों से उन्हीं की शर्तों पर व्यवहार करती है। बिना धनिकों के संरक्षण के उनके पाम जो जमानत होती है उसे वे स्वीकार कर लेती है। यह एजेन्सी दान बाटन या राज्य कोषों से छोटे साधनों के व्यक्तियों को सहायता देने के लिए नहीं बरन् भौतिक सहायता के साथ नैतिक विकास तथा चरित्र शक्ति की वृद्धि के लिए है।"¹ डिवाइन के शब्दों में "सहकारी बैंक एक पारस्परिक संस्था है जो श्रमिक वर्ग के द्वारा ही निर्मित तथा नियंत्रित होती है तथा जहाँ बचत को प्रोत्साहित किया जाता है और ब्याज तथा भुगतान की सरल शर्तों पर छोटे ऋण स्वीकार किए जाते हैं।"² सहकारी बैंक की एक उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है जिसमें सहकारी साख के सभी तत्वों का समावेश हो — "यह असीमित सदस्यता तथा सामूहिक स्वामित्व साधनों वाला व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संगठन है जिसका निर्माण प्रजातन्त्रीय आधार पर छोटे उत्पादकों तथा

¹ "Co operative banking is an agency which is in a position to deal with small man on his own terms, accepting the security he has and without drawing on the protection of the rich. That agency must not be a channel for pouring charity or subsidising the small man out of the public funds, instead the material help must be backed by moral improvement and a strengthening of the fibre"

—Henry Wolff, *Co operation in India*.

² "Co-operative bank is a mutual Society formed composed and governed by working people themselves by encouraging regular saving and granting small loans on easy terms of interest की ई repayment"—Devine.

श्रमिकों द्वारा किया जाता है, जिसमें सदस्यों की वचतों को जमा कर व्याज तथा भुगतान की सरल शर्तों पर साख्त दी जाती हैं, अल्पधिक धन संचित कोष में रख लिया जाता है या उसे जमाकर्ताओं, ऋणियों तथा अशनारियों में बांट दिया जाता है। बाह्य स्रोतों से सदस्यों के लिए ऋण प्राप्त करते समय सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रयोग किया जाता है।¹ इन परिभाषाओं से सहकारी बैंकों के दो आवश्यक तत्व प्रकट होते हैं—एक तो इनका निर्माण सहकारिता के सिद्धान्तों के आधार पर हो और दूसरे इनका उद्देश्य साख्त की सुविधाएँ प्रदान करना हो।

सहकारी साख्त आन्दोलन का प्रारम्भ (The origin of the Co-operative Credit movement) भारत में सहकारिता को प्रारम्भ करने का विचार सर्व प्रथम सर हेनरी स्टार्क ने किया। यह वास्तव में बेल्जियम में लियोन से (Leon Say) इटली में लियोने वॉलेमबर्ग (Leonie Wollemborg) तथा फ्रान्स में प्रो० टेनविरे (Prof Tanviray) द्वारा किए गये प्रारम्भिक प्रयत्नों का प्रभाव ही था। 1892 में मद्रास सरकार ने सर फ्रेडरिक निकलसन को मद्रास में भूमि तथा कृषि बैंकों की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए नियुक्त किया और अध्ययन करते-करते योरोप भेजा तथा 1895 में अपनी रिपोर्ट² में उन्होंने रेफीमन समितियों की स्थापना का सुझाव दिया। उसी समय उत्तर प्रदेश में ड्यूपर्ने (H Duperne) ने पीपुल्स बैंक स्थापित करने का प्रयत्न किया। लार्ड कजन ने एक समिति नियुक्त की। 1901 के अकाल कमीशन ने भी पारस्परिक साख्त समितियों (Mutual Credit Associations) के निर्माण का सुझाव दिया। 1901 में सर एडवार्ड लो की अध्यक्षता में एक समिति ने विचार किया और इसी के सुझाव पर 1904 में सहकारी साख्त समिति अधिनियम पारित किया गया जिसका उद्देश्य कृषकों, कारीगरों तथा छोटे साधनों के व्यक्तियों में मितव्ययिता, स्वालम्बन तथा सहकारिता को प्रोत्साहन देना था। इस अधिनियम में गैर साख्त समितियाँ तथा केन्द्रीय बैंक बनाने की व्यवस्था नहीं थी अतः 1912 में एक नया अधिनियम पास कर इन दोनों को

1. "It is a voluntary association of individuals with unrestricted membership and collectively owned resources formed by small producers or wage earners, conducted on a democratic basis by accumulating the savings of the members and granting them credit on easy terms of interest and repayment, surplus being placed to reserve or distributed between depositors, borrowers and shareholders, the association also using the joint responsibility of its member as a security for loans obtained for its members from outside sources"—N Barou : *Co operative Banking*

Report regarding the Possibility of Introducing Land and Agricultural Banks into the Madras Presidency.

दूर किया। 1915 में मैक्लागन समिति (Maclagan Committee on Co-operation) ने सहकारी समितियों के पुनर्गठन का सुझाव दिया। 1919 के मानटेग्यू-चेल्मस्फोर्ड सुधारों के अंतर्गत सहकारिता प्रान्तीय सरकारों के अधीन कर दी गयी। अतः प्रान्तों में अलग-अलग अधिनियम बनाये गये। 1929 के बाद की मदी में सहकारिता आन्दोलन की ठेस लगी परन्तु कुछ समय बाद मूल्यों में वृद्धि से आन्दोलन को प्रोत्साहन मिला। 1939-45 के द्वितीय महायुद्ध काल में मूल्य वृद्धि तथा राशनिंग इत्यादि के कारण सहकारिता का विकास हुआ। 1946 में सहकारी नियोजन समिति (सरँय्या समिति) नियुक्त हुई जिसने प्राथमिक साख समितियों को बहुउद्देश्यीय समितियों के रूप में पुनर्गठित करने का सुझाव दिया। 1951 में रिजर्व बैंक ने श्री ए० डी० गोरवाला की अध्यक्षता में एक ग्रामीण जाच सर्वेक्षण समिति नियुक्त की जिसने 1955 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में ग्रामीण साख की एकीकृत योजना (Integrated Scheme of Rural Credit) प्रस्तुत की। इसी के सुझावों पर आन्दोलन आगे बढ़ा। पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया।

सहकारी बैंकों का संगठन (Organisation of Co-operative Banking)

भारत में सहकारी साख का संगठन सघीय (Federal) आधार पर हुआ है। इसे स्तूपान्कार व्यवस्था (Pyramidal Structure) भी कहते हैं। इस आधार पर सहकारी बैंकों को तीन वर्गों में बाटा जा सकता है।—

(1) प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ (Primary Co-operative Credit Societies)

(2) केन्द्रीय सहकारी बैंक अथवा बैंकिंग यूनियन (Central Co-operative Banks or Banking Unions)

(3) राज्य सहकारी बैंक या शीर्ष बैंक (State Co-operative Bank or Apex Bank)

(1) प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ (Primary Co-operative Credit Societies)

इन समितियों को दो भागों में बाटा जा सकता है : प्राथमिक कृषि साख समितियाँ जो कृषि कार्यों के लिए साख व्यवस्था करती हैं और अिनका कार्यक्षेत्र बहुधा ग्राम होता है। दूसरी आर, ग्रँर कृषि साख समितियाँ हैं जो मिल मजदूरों, बेतन भोगियों तथा नगरीय वर्गों के लिए कार्य करती हैं और इनका कार्यक्षेत्र कोई नगर या कस्बा होता है।

(अ) सगठन : किसी ग्राम अथवा क्षेत्र के कम से कम दस व्यक्ति मिल कर प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। इन समितियों का सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (Registrar of Cooperative Societies) से पंजीयन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रार समिति का पंजीयन तभी करता है जब वह सदस्यों या अशधारियों के हितों की समानता तथा सहकारिता के सिद्धांतों में उनकी निष्ठा से आश्वस्त हो जाता है। ऐसी समिति का कार्यक्षेत्र सीमित ही होता है जिससे सदस्य एक दूसरे को जान सकें, उनके कार्यक्रमों पर दृष्टि रख सकें, किसी व्यक्ति विशेष के प्रभुत्व को रोक सकें और सुविधापूर्वक निरीक्षण हो सके। अचिन्तित कृषि साख समितियों का गठन रेफीसन प्रणाली पर किया जाता है। जिसमें सदस्यों का दायित्व असीमित होना है जिससे वे सहयोगी सदस्यों का चयन करने तथा उन्हें ऋण देने में सतर्क रहें और भुगतान समय पर कराने में कठोर रहें। बैंक-कृषि साख समितियों का गठन बहुधा सीमित दायित्व के आधर पर किया जाता है।

(ब) पूँजी (Capital resources) प्राथमिक समितियों की चालू पूँजी (Working capital) चार साधनों से प्राप्त होती है—(क) अशो द्वारा (ख) संचित कोष (ग) जमा तथा ऋण (घ) शुल्क।

(क) अशो द्वारा सभी समितियाँ अश जारी नहीं करती। जहाँ अश जारी किए जाते हैं उनका मूल्य बहुत कम रकमा जाना है तथा खामाश तथा एक सदस्य द्वारा खरीदे गये अशों की अधिकतम संख्या सीमित कर दी जाती है। प्रत्येक सदस्य को चाहे उसके पास कितने भी अश क्यों न हों एक ही मत देने का अधिकार होता है। 'एक व्यक्ति-एक मत' का प्रजातंत्रीय सिद्धांत अपनाया जाता है जिससे पूँजी की शक्ति से कुछ साधन सम्पन्न व्यक्ति समिति पर अपना प्रभुत्व न स्थापित कर लें।

(ख) संचित कोष (Reserve Fund) प्रत्येक समिति को अधिनियम के अनुसार अपने लाभ का अधिकांश भाग संचित कोष में हस्तांतरित करना पड़ता है। रेफीसन प्रणाली में तो पूरा लाभ संचित कोष में जमा होता रहता है और लाभ तभी बाटा जा सकता है जब कि संचित कोष की रकम अश पूँजी के बराबर हो जाय और रजिस्ट्रार से लाभ बाटने की आज्ञा ले ली जाय। जो समितियाँ अश जारी नहीं करती वे पूरा लाभ संचित कोष में हस्तांतरित कर देती हैं। कुछ समितियाँ संचित कोष का उपयोग सदस्यों को ऋण देने के लिए करती हैं और कुछ उसे केन्द्रीय बैंक में जमा कर देती हैं।

(ग) जमा तथा ऋण (Deposits and loans) इन समितियों की चालू पूँजी का अधिकांश भाग केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा सरकार से ऋण लेकर प्राप्त होता है। समितियों को प्रायः अपनी सम्पूर्ण चालू पूँजी के दुगुने से लेकर चार गुने तक ऋण मिल सकता है। 1958 से मेहता समिति की सिफारिश के कारण अश

पूँजी की बाकी रकम राज्य सरकार देती है। समितिया सदस्यो तथा गैर सदस्यो से जमा भी प्राप्त करती हैं परन्तु इस दिशा में उन्हें अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रवेश शुल्क (Entrance fees) कुछ समितिया सदस्यो से प्रवेश शुल्क भी लेती हैं परन्तु इसका उनका आय स्रोतों में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है।

(ग) प्रबन्ध (Management) समिति का प्रबन्ध करने के लिए एक प्रबन्ध समिति का प्रतिवर्ष निर्वाचन साधारण सभा द्वारा होता है जिसमें अध्यक्ष तथा सचिव को मिलाकर 4 से 9 सदस्य तक होते हैं। प्रबन्ध समिति का मंत्री जो बहुधा अर्बतनिक होता है, समिति के दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अनिश्चित सभी सदस्यो की साधारण सभा होती है जो नीति निर्धारण का कार्य करती है। इसकी बैठक वर्ष में प्रायः एक बार होती है।

(द) ऋण नीति (Lending Policy) प्राथमिक समितिया अपने सदस्यो को ही ऋण देती हैं। ऋण की मात्रा सदस्य की व्यक्तिगत सम्पत्ति के एक निश्चित अनुपात (सामान्यतः आधा) तक ही दी जा सकती है और इस सीमा में भी ऋण देते समय ऋण लेने के उद्देश्य तथा उनकी भुगतान सामर्थ्य को ध्यान में रखा जाता है। ऋण उत्पादक तथा कभी कभी अनुत्पादक कार्यों के लिए दिए जाते हैं परन्तु सट्टेबाजी तथा अपव्यय के लिए नहीं दिए जा सकते। ऋण सामान्यतः बीज, खाद तथा बैल आदि खरीदने, लगान भुना करने भूमि को सुधारने तथा पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिए दिए जाते हैं। ऋण व्यक्तिगत जमानत पर दिए जाने हैं। कुछ राज्यों में भूमि को धरोहर के रूप में रक्खा जाता है और कुछ अन्य राज्यों में व्यक्तिगत जमानत के अतिरिक्त दो अन्य व्यक्तियों की जमानत मांगी जाती है। विभिन्न राज्यों में ऋण पर ली जाने वाली व्याज की दर 8 से 12 प्रतिशत के बीच है।

प्राथमिक साख समितियों की ऋण नीति सम्बन्धी नियम राज्य के सहकारिता विभाग द्वारा बनाये जाते हैं जिनका पालन करना समितियों के लिए आवश्यक होता है।

(य) प्रगति (Progress) प्राथमिक साख समितियों की सरया में पिछले कुछ वर्षों से कमी हुई है क्योंकि सगठन के सुदृढ करने के लिए कमजोर तथा अर्थात् क्षीण समितियों को समाप्त किया गया। इन समितियों के प्रगति के आँकड़े इस प्रकार हैं।

भारत में प्राथमिक कृषि साख समितियों की प्रगति

मदे	1950-51	1966-67
1. सरवा (लाखों में)	1 15	1 79
2. सदस्य (करोड़ों में)	0 52	2 67
3 दत्त पूँजी	8 40	128 61
4 कोष	8 86	36 88
5. निक्षेप	4 48	39 09
6 ऋण शेष (Outstanding)	29 13	477 46
7 बाकी (Loans overdue)	6 38	160 14
8. (Percentage of overdues to outstanding)	21 90	34 00

प्राथमिक कृषि साख समितियों द्वारा 1966-67 वर्ष में 365 2 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए जो पिछले वर्ष से 8 प्रतिशत अधिक थे। इन समितियों की कुल कार्यशील पूँजी 1966-67 के अंत में 625 20 करोड़ रुपये थी।

(2) केन्द्रीय सहकारी बैंक (Central Co-operative Bank)

प्रत्येक जिले में प्रायः एक केन्द्रीय सहकारी बैंक होता है जो उस क्षेत्र की प्राथमिक साख समितियों को आर्थिक सहायता पहुँचाने का कार्य करता है। केन्द्रीय सहकारी बैंक दो प्रकार के होते हैं एक तो वे जिनमें केवल प्राथमिक समितियाँ ही सदस्य होती हैं। ये 'बैंकिंग यूनिट' कहनायी हैं। दूसरी वे जहाँ प्राथमिक समितियों के अतिरिक्त दूसरे व्यक्ति भी सदस्य होते हैं। भारत में अधिकतर ऐसे ही मिश्रित सदस्यता वाले बैंक हैं। कुछ केन्द्रीय बैंक अपने काय क्षेत्र में शाखाएँ भी खोलते हैं। नगरीय या कस्बों में स्थित होने के कारण ये बैंक व्यापारिक बैंकों के कार्यों को भी करते हैं परन्तु कम मात्रा में। मुख्य रूप से केन्द्रीय बैंक प्राथमिक साख समितियों को ऋण देना है और उनकी अतिरिक्त कार्यशील पूँजी अपने महा जमा रखना है। केन्द्रीय बैंक जनता से निक्षेप भी स्वीकार करता है। कुछ राज्यों में अर्ध सरकारी संस्थाएँ जैसे नगर पालिकाएँ, जिला परिषद, विश्वविद्यालय इत्यादि के अतिरिक्त कोष अर्पण महा जमा करता है। केन्द्रीय बैंक प्राथमिक समितियों के कार्यों की देख रेख रखना है और उनका निरीक्षण तथा निपटारा करता है। अतः केन्द्रीय बैंक प्राथमिक साख समिति तथा शीप बैंक के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है।

(अ) पूँजी (Capital resources)—केन्द्रीय बैंक के मरिय पूँजी के साधन चार हैं—(1) अर्ध (2) संचित कोष (3) समितियों तथा जनता के निक्षेप और (4) ऋण। वार्षिक लाभ का कम से कम एक चौथाई संचित कोष में जमा

होता रहता है। जमा तीन प्रकार के खातों द्वारा प्राप्त होती है—चालू खाता, बचत खाता सावधि जमा खाता। जमा के रूप में प्राप्त रकम कार्यशील पूँजी का लगभग 40.6 प्रतिशत होती है। अपने वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा अन्य व्यापारिक बैंकों अधिकांशतः राज्य सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करते हैं। राज्य सहकारी बैंकों से उन्हें इनकी अंश पूँजी तथा संचित कोषों के दस गुने तक ऋण मिल सकते हैं।

(ब) प्रबन्ध (Management)—इन बैंकों का प्रबन्ध एक संचालक मंडल द्वारा होता है जिसके सदस्य प्राथमिक समितियों के प्रतिनिधि तथा प्रभावशाली और व्यापारिक योग्यता के व्यक्ति होते हैं। वे समय-समय पर अपनी बैठकों में नीति सम्बन्धी निर्णय तथा दिशा सवेत करते हैं। इन बैंकों के सभी कर्मचारी वैननिक होते हैं।

(स) ऋण-नीति (Lending policy)—केन्द्रीय बैंक मुख्य रूप से सदस्य समितियों को ऋण देते हैं। समितियों को प्रायः 6 से 8 प्रतिशत व्याज पर ऋण दिया जाता है। प्रत्येक समिति की ऋण लेने की अधिकतम सीमा के भीतर ही ऋण दिया जाता है। यह ऋण एक वर्ष में तीन वर्ष के लिए होने हैं।

(द) प्रगति (Progress)—द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल से ही केन्द्रीय बैंक व्यवस्था को सुदृढ़ आधार पर खड़ा करने के लिए बैंकों का एकीकरण कर प्रत्येक जिले में एक मजबूत केन्द्रीय बैंक के निर्माण की योजना को कार्यान्वित किया गया है। इसीलिए उनकी सरमा घट रही है परन्तु उनका संगठन अधिक सुदृढ़ होता जा रहा है। केन्द्रीय बैंकों की प्रगति के कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं—

भारत में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की प्रगति

(करोड़ रुपये में)

मद	1951-52	1966-67
1. सख्या	505	346
2. सदस्य (लाखों में) समितियाँ व्यक्ति		2.54 99
3. दत्त पूँजी	4 04	85 99
4. कोष	4 79	20 64
5. निक्षेप	37 79	259 32
6. ऋण शेष (Outstandings)	34 14	499 35
7. बाकी (Loans over due)	2 96	124 17
8. प्रतिशत (Percentage of overdues to outstandings)	8 67	24 9

केन्द्रीय बैंकों ने 1966-67 वर्ष में 625.4 करोड़ रुपये के ऋण दिए तथा इनकी कार्यशील पूँजी 638.3 करोड़ रुपये थी। इनकी कार्यशील पूँजी में निक्षेपों

का प्रतिशत 40 6 है और यह गुजरात में उच्चतम है। एक करोड़ या इससे अधिक जमा वाली बैंको की कुल संख्या 70 है।

(3) राज्य सहकारी बैंक या शीर्ष बैंक (State Co-operative Bank or Apex Bank)

सहकारी साख व्यवस्था में राज्य सहकारी बैंक सर्वोच्च संस्था है जो राज्य के समस्त सहकारी बैंको के संगठनों का नियंत्रण तथा नियमन करती है। अतः इसको शीर्ष बैंक (Apex Bank) भी कहते हैं। यह बैंक दो प्रकार के है। एक तो ऐसे जिनमें केन्द्रीय बैंक ही सदस्य है, इन्हें शुद्ध बैंक (Pure Banks) कहा जाता है। पंजाब, पश्चिमी बंगाल, आन्ध्र एव मसूर राज्यों में इसी प्रकार के शुद्ध बैंक हैं। दूसरे प्रकार के वे बैंक हैं जहाँ केन्द्रीय बैंको के अतिरिक्त व्यक्ति भी सदस्य बन सकते हैं। अन्य राज्यों में दूसरी श्रेणी के बैंक हैं। देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्य सहकारी बैंक स्थापित है। इनकी संख्या 25 है। कुछ राज्यों में यह बैंक उन स्थानों पर शाखाएँ भी खोलते हैं जहाँ केन्द्रीय बैंक नहीं है। केन्द्रीय बैंको को ऋण देने के अतिरिक्त वे व्यक्तियों को भी ऋण देते हैं और व्यापारिक बैंकिंग कार्य भी करते हैं। कुछ राज्यों में इन बैंको ने सहकारी उपभोक्ता भंडारों तथा औद्योगिक व विपणन समितियों के गठन में भी योग दिया है।

(अ) पूँजी साधन (Capital resources)—राज्य सहकारी बैंक अपनी पूँजी अथवा संचित कोष, केन्द्रीय बैंको तथा व्यक्ति के निक्षेपों तथा व्यापारिक बैंको, स्टेट बैंक तथा रिजर्व बैंक से ऋण लेकर प्राप्त करती है। इसका अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार से भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 19 (2) (घ) 17 (2) व तथा 4 (स) के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के ऋण रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंको को देता है।

(ब) प्रबन्ध (Management)—राज्य सहकारी बैंको का प्रबन्ध एक संचालक मंडल (Board of Directors) द्वारा होता है जिसमें केन्द्रीय बैंको के प्रतिनिधि तथा बैंकिंग का ज्ञान रखने वाले अन्य व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। इन बैंको का कार्य व्यापारिक सिद्धान्तों के आधार पर होता है। कुछ राज्यों में सहकारिता विभाग का रजिस्ट्रार संचालक मंडल का सदस्य होता है।

(स) ऋण-नीति (Lending Policy)—राज्य सहकारी बैंक सरकारी प्रतिभृतियों तथा कृषि विनियम पत्रों की धरोहर पर ऋण देते हैं। ऋण प्रायः अल्पकाल के लिए ही दिए जाते हैं परन्तु आवश्यकता पड़ने पर मध्यकाल के लिए भी दिए जाते हैं। इनके द्वारा दिए गये ऋणों की व्याज की दर 4 से 6 प्रतिशत होती है।

(द) प्रगति (Progress)—राज्य सहकारी बैंको की कुल सखा 25 है जिनमे 13,167 बैंक तथा समितिया और 8290 व्यक्ति सदस्य है। राज्य सहकारी बैंको की वर्तमान स्थिति तथा प्रगति निम्न तालिका से विदित होनी है—

भारत मे राज्य सहकारी बैंको की प्रगति

मर्दे	1950-51	1966-67
1. सख्या		25
2. सदस्य		
(अ) बैंक		13,167
(ब) व्यक्ति		8,290
3 दत्त पूजी	1 58	31 16
4. सवित काप	2 22	10 24
5. निक्षेप	22 08	147 38
6. ऋण शेष (Outstanding)	17 90	315 16
7 बाकी (Loans over due)	2 15	16.92
8 प्रतिशत (Percentage of overdues to out-standing)	12 01	5.20

तालिका से स्पष्ट है कि राज्य बैंको की ऋण शेष लगभग 18 गुन हो गय है। राज्य सहकारी बैंको मे महाराष्ट्र सहकारी बैंक सबसे बडा है जिसकी कार्यशील पूँजी 91 90 करोड रुपय तथा ऋण शेष 75 31 करोड रुपय है।

सहकारी साख आन्दोलन के दोष

(Defects in the Co-operative Credit Movement)

भारत म सहकारी आन्दोलन को 64 वर्ष बीन गये हैं और यह इतिहास एक सीमित साख आन्दोलन का इतिहास ही है फिर भी अपन इन सीमित उद्देश्य—प्राप्तीय ऋणप्रस्तता तथा साख की समस्या का पूर्ण रूप से समाधान करन म यह असफल रहा है विभिन्न कमीशनो तथा समितिओ न सहकारी आन्दोलन के दोष बताये है जिनमे कुछ मुख्य इस प्रकार हैं—

(1) सहकारी साख अपर्याप्त है (Co-operative Credit inadequate) प्राप्तीय जाच सर्वेक्षण समिति (1951-54) के ये शब्द आज भी उतने ही सही हैं "The agricultural credit that is supplied, falls short of the right quantity, is not of the right type, does not serve the right purpose, and by the criterion of need (not overlooking the criterion of creditworthiness) often fails to go to the right people" इसी कारण कृषक को अन्त मे साहूकार महाजन की शरण मे ही जाना पडना है जिनमे बचाना

ही सहकारिता का उद्देश्य है। कुन वृषि साख का ध्राज भी केवल 40 प्रतिशत सहकारी सस्थाओ द्वारा दिया जाता है।

(2) अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप (Excessive official control)—ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति इस कथन से सहमत थी कि "Co operation in this country is like a plant held in position with both hands by the government since its roots refuse to enter the soil" भारत में सहकारी आन्दोलन सरकारी आन्दोलन के रूप में रहा है हालांकि सरकार की नीति गैर सरकारी लोगों को बढ़ावा देने की है।

(3) सहकारिता के सिद्धान्तों से अनभिज्ञता (Lack of understanding of cooperative principles)—समितियों के अधिकांश सदस्य सहकारिता के सिद्धान्तों तथा ग्रामीण साख के आवश्यक तत्वों से अनभिज्ञ हैं। वे यह नहीं समझते कि समिति की शक्ति सदस्यों का ईमानदारी, पारस्परिक विश्वास और सहयोग पर निर्भर करती है। इनका मुख्य कारण संपत्तियों का अज्ञान होता है।

(4) कुशल तथा प्रभावपूर्ण निरीक्षण का अभाव (Lack of effective and efficient supervision and inspection)—बहुतेरे प्रबंध समितियाँ अज्ञान हैं दायर भावना से कार्य करती हैं और साधारण सभायें उन पर ठीक प्रकार से नियंत्रण नहीं रखती। बिना सच्चे मर्मके सदस्य बना लिए जाते हैं और जरा बिना मत्कला से स्वीकृत कर दिए जाते हैं। समितियों की व्यवस्था का ठीक प्रकार से निरीक्षण नहीं होता।

(5) अवांछित तत्वों का प्रभुत्व (Control of undesirable elements)—कभी-कभी समितियों पर कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों का प्रभुत्व हो जाता है जिससे साधनहीन लोगों को हितों की कीमत पर कुछ प्रभावशाली लोग लाभ उठाते हैं। राजनीतिज्ञ सहकारी समितियों पर अधिकार कर रहे हैं और अपने लोगों को अधिकाधिक श्रेणियाँ दिनाते हैं। इन अवांछित तत्वों के कारण सहकारी सस्थाओं में घन के दुष्प्रभाव, जान भागी, गहन इत्यादि काफी बढ़ गये हैं।

(6) समितियों की ब्याज दर ऊँची है (Societies rates of interest are high)—प्राथमिक साख समितियों द्वारा दिए गये ऋणों पर 8 से 12 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है जो अधिक है। कुछ तो साख व्यवस्था के सघीय संगठन के कारण ऐसा है परन्तु फिर भी इसमें कमी की गुंजाइश है।

(7) सहकारी सस्थायें ग्रामीण बचतों को आकर्षित करने में असफल रही हैं (They have failed to attract rural savings)—सहकारी आन्दोलन ग्राम

सहायता तथा स्वालम्बन के ऊपर आधारित है परन्तु ग्रामीण कार्यशील पूँजी जुटाने के लिए सहकारी सस्थायें अधिक मात्रा में राज्य सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक तथा सरकार से ऋण लेती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मितव्ययिता को प्रोत्साहित कर जमा आकर्षित करने में प्राथमिक समितियाँ असफल रही हैं। उनकी कुल कार्यशील पूँजी में निक्षेपों का प्रतिशत कम ही है।

(8) ओवरड्यूज का ऊँचा प्रतिशत (High percentage of overdues) — प्राथमिक साख समितियों में ऋण धेपों का प्रतिशत ऊँचा है और यह साख संगठन की बहुत बड़ी कमजोरी है। इसके मुख्य कारण आवश्यकता से अधिक साख, ऋण देते समय उद्देश्य की जाच न करना, ऋणी की देय क्षमता का ध्यान न रख कर ऋण-स्वीकृति ऋण उपयोग पर देख रेख न होना और ऋण वसूली में अनावश्यक ढील देना है।

(9) दोषपूर्ण अन्वेषण (Defective audit) — समितियों का अन्वेषण होना अनिवार्य हाते हुए भी अनेक समितियों का अन्वेषण हाता ही नहीं या उसमें सावधानी नहीं बरती जाती। खातो इत्यादि में जो दोष बताये जाते हैं उन्हें वर्षों तक ठीक नहीं किया जाता।

1946 में सहकारिता नियोजन समिति ने आन्दोलन की सीमित प्रगति के कारणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा था — The causes are “the laissez faire policy of the state, the illiteracy of the people and the fact that the movement did not, especially in its initial stages, take the life of the individual as a whole. Amongst the other causes, are the small size of the primary unit and undue reliance on honorary services for even day-to-day work with resultant inefficiency in management” ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति 1951-54 के शब्दों में its main causes may be found in “the functional structural and administrative defects, dearth of suitable personnel, lack of training, a background of illiteracy, the grave and chronic deficiency in roads, storage and other vital economic requirements”

सहकारी साख आन्दोलन में सुधार के उपाय

(Suggestions for Improvement in the Co operative Credit Movement)

सहकारिता आन्दोलन को अधिक उपयोगी बनाने तथा उसकी स्थिति सुधारने के लिए समय-समय पर विभिन्न कमीशनो तथा समितियों ने सुझाव दिए हैं। उनके अनुसार निम्नलिखित दिशाओं में सुधार किया जाना चाहिए —

(1) सरकारी हस्तक्षेप कम होना चाहिए (Official control should be lessened) सरकार के सहकारी विभागों का कार्य केवल शिक्षा, देना रख तथा अकेलण के नियन्त्रण तक ही सीमित होना चाहिए और समितियों को उनकी आंतरिक कार्य प्रणाली, ऋण तथा जमाओं के लिए स्वयं उत्तरदायी बनाना चाहिए। इससे सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना का उदय होगा।

(2) प्राथमिक समितियाँ केवल अल्प तथा मध्यकालीन ऋण दें (Primary Credit Societies should finance only short term and intermediate credit needs) - प्राथमिक समितियों को अल्प, मध्य तथा दीर्घकालीन ऋणों में भेद करना चाहिए और केवल अल्प तथा मध्यकालीन ऋण देना चाहिए क्योंकि उनको अल्प या मध्यकाल के लिए धन मिलता है।

(3) अधिक कायकुशल तथा पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था हो (Efficient and adequate training) सहकारी विभाग व अधिकारियों, कर्मचारियों तथा सहकारी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण व्यवस्था में सुचारु किया जाय तथा सहकारिता के व्यवहार सम्बन्धी योग्यता विकसित की जाय जिनसे सस्थाएँ ठीक ढंग से चल सकें।

(4) सहकारिता की शिक्षा का प्रचार हो (Expansion of co operative education) सहकारिता के सिद्धांतों तथा शिक्षा का प्रसार किया जाय जिससे सदस्यों में प्राप्तीय भाव का आवश्यक तत्वों का ज्ञान हो और उनमें सहकारिता की भावना पैदा हो। परन्तु इस दिशा में वास्तविक उन्नति तो तभी हो सकेगी जब जनता शिक्षित होगी।

(5) प्राथमिक साख समितियों को बहु-उद्देश्यीय समितियों में परिवर्तित कर देना चाहिए (Primary credit societies should be converted into or associated with multi purpose societies) सहकारिता निधाजन समिति 1946 ने सुझाव दिया था कि प्राथमिक साख समितियों को बहु-उद्देश्यीय समितियों में परिवर्तित कर देना चाहिए या उन्हें बहु-उद्देश्यीय समितियों से सम्बन्धित कर देना चाहिए जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार हो तथा सदस्यों को सुविधा हो।

(6) अकेलण तथा निरीक्षण में सुधार हो (Improvement in audit supervision and inspection) प्राथमिक साख समितियों का निरीक्षण तथा अकेलण अधिक सगठित तथा सावधानी पूर्वक किया जाय।

सहकारी आन्दोलन की सफलताएँ

(Achievements of Co operative Movement)

सहकारी सस्थाओं की सहायता से निर्धनों तथा कृषकों की स्थितियों में सुधार हुआ है। मोल्टन (Moulton) के शब्दों में :

“Where ever the credit unions have been properly established and encouraged, they have regenerated and accelerated agriculture, commerce and industry or any other department of human activity to which their principles have been applied. They have stamped out usury and raised millions of human souls from the depths of despair to lives of hopefulness and service. They have supplanted shiffliness by industry, improvidence by sobriety, selfishness by neighbourliness, individual effort by concerted action — in fact they have proved to be one of the most potent moral, educational and social forces in the history of civilisation and in the enrichment of the life of the common people ”

यद्यपि पूर्ण रूप से इस दिशा में भारत में सफलता नहीं मिली है फिर भी अर्थ-व्यवस्था पर सहकारी आन्दोलन ने प्रभाव डाला है। कुछ सीमा तक उसकी सफलताएँ निम्नलिखित हैं :

(1) आन्दोलन ने सभी दिशाओं में ब्याज की दरों को कम किया है।

(2) साख की सुविधायें देकर कृषि का सुधार करने में कृषकों की सहायता की है।

(3) आत्म सहायता तथा स्वावलम्बन से उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है। सहयोग तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास हुआ है। विस्तीय मामलों को चलाने की योग्यता बढ़ी है।

(4) कुछ सीमा तक बचत तथा विनियोग की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया है।

(5) सहकारी महाजन पर कृषकों की निर्भरता कुछ कम हुई है।

सहकारिता के महत्व को पंजाब प्रांतीय समिति ने इन शब्दों में प्रकट किया था :

“A scheme of Government of joint stock bank finance might reduce the rates of interest, but only co operation can teach the peasant to borrow at the right time, and in the right amounts and for right ends, and to repay on right dates, and only co-operation can teach him to save so that he may not have to borrow at all’.

कुछ क्षेत्रों में सहकारिता आन्दोलन ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है परन्तु सहकारी क्षेत्रों में व्याप्त अव्यवस्था, धन का दुरुपयोग, ऋणों की बाकी इत्यादि के

आधार पर यह सभी स्वीकार करते हैं कि सहकारी संस्थाएँ अपने मूलभूत उद्देश्य में असफल रही हैं। सहकारी साख के सीमित क्षेत्र में भी इसकी उपलब्धता बहुत गौरवपूर्ण नहीं रही है।

कृषि वित्त तथा रिजर्व बैंक (Agricultural Finance and Reserve Bank)

कृषि वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में रिजर्व बैंक का महत्वपूर्ण योगदान है। इसका विस्तृत विवेचन 'रिजर्व बैंक आफ इन्डिया' अध्याय में किया गया है।

भूमि-बन्धक बैंक (Land Mortgage Banks)

जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि सहकारी बैंक कृषकों की दीर्घकालीन साख की आवश्यकताओं जैसे भूमि खरीदना, बीमारी कृषि यन्त्र खरीदना, भूमि सुधार आदि की पूर्ति नहीं करती क्योंकि उनके साधन अल्पकालीन होते हैं। व्यापारिक बैंक तथा स्वदेशी बैंक भी दीर्घकालीन साख प्रदान नहीं कर सकते क्योंकि वे भी दीर्घकालीन ऋणों में अपनी पूँजी अटकाना नहीं चाहते। कृषकों की दीर्घकालीन साख की आवश्यकता की पूर्ति विशिष्ट संस्थाओं (Special Institutions) द्वारा ही हो सकती है। यह संस्थाएँ भूमि बन्धक बैंक कहलाती हैं और वे कृषकों का भूमि का बन्धक रखकर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती हैं।

भूमि बन्धक बैंक (Land Mortgage Banks) वे संस्थाएँ हैं जो कृषकों की भूमि का बन्धक रखकर उन्हें दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती हैं।¹ भूमि बन्धक बैंक तीन प्रकार के हो सकते हैं: (1) सहकारी भूमि-बन्धक बैंक (The Co-operative Type): ये शुद्ध सहकारी आधार पर गठित किए जाते हैं। (2) निम्न पूँजी वाले भूमि बन्धक बैंक (The Commercial Type) (3) अर्ध-सहकारी भूमि बन्धक बैंक (The Quasi-Cooperative) यह पहले दो प्रकार के बैंकों का मिश्रण होता है। भारत में इसी प्रकार के बैंकों की स्थापना हुई है।

भूमि-बन्धक बैंकों का संगठन (Organisation of Land Mortgage Bank): भारत में भूमि बन्धक बैंकों का संगठन द्वि-स्तरीय है। प्रत्येक राज्य में तो एक केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक (Central Land Mortgage Bank) है जो प्राथमिक भूमि बन्धक बैंकों के सघ के रूप में कार्य करता है। केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंको

¹ "Land Mortgage Banks are the associations of borrowers and non-borrowers created for the purpose of granting loans to members to enable them to redeem their past debts, for enabling them to make long term improvement in land."

की पूँजी सरकार प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक, सहकारी बैंक तथा कृषको द्वारा जुटायी जाती है। दूसरी ओर महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों में प्राथमिक भूमि बन्धक बैंकों की स्थापना की गई है। प्राथमिक भूमि बैंकों की पूँजी सदस्यों द्वारा जुटायी जाती है।

भूमि बन्धक बैंकों के साधन (Resources of Land Mortgage Banks):

भूमि बन्धक बैंक अपनी कार्यशील पूँजी अग्रे तथा ऋण-पत्रों को बेचकर, जमाओं तथा व्यक्तियों, समितियों और बैंकों से ऋण लेकर प्राप्त करती हैं। उनके अधिकांश पूँजी साधन राज्य सरकारों द्वारा गारन्टी किए गये ऋण-पत्र (Debentures) बेचकर प्राप्त की जाती है। ऋण-पत्र केवल केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों द्वारा ही जारी किए जाते हैं।

भूमि बन्धक बैंक 20 वर्ष तक की अधिकतम अवधि के लिए ऋण देते हैं। पुराने ऋणों को अदा करने तथा भूमि में सुधार और भूमि खरीदने के लिए भूमि का बन्धक रखकर कुछ राज्यों में तो बन्धक भूमि की कीमत का 50 प्रतिशत तक तथा कुछ अन्य राज्यों में भूमि पर देय लगान का 30 गुना तक ऋण दिए जाते हैं। ऋण स्वीकृत करने के पहले प्रार्थी के भूमि स्वामित्व, उसकी भुगतान योग्यता तथा ऋण की आवश्यकता आदि बातों का विचार किया जाता है। केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक प्राथमिक बैंकों से 6-50 प्रतिशत तथा प्राथमिक बैंक सदस्यों से 7.50 प्रतिशत ब्याज लेते हैं।

भूमि बन्धक बैंकों की प्रगति तथा वर्तमान स्थिति (Progress and Present position of Land Mortgage Banks): भूमि बन्धक बैंकों ने दीर्घकालीन साख सहायता देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भूमि बन्धक बैंकों की प्रगति तथा वर्तमान स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट है:

भूमि बन्धक बैंकों की स्थिति

(लाख रुपये में)

	केन्द्रीय		प्राथमिक	
	1950-51	1966-67	1950-51	1966-67
1. सख्या	5	19	287	707
2. सदस्य	9848	7 73 लाख	2.15 लाख	21.57 लाख
3. प्रदत्त पूँजी	21	1,890	53	1,414
4. स्वीकृत ऋण		5,885		4 084
5. ऋण शेष	598	20,737	626	15,467

उपयुक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि देश में कृषि सम्बन्धी दीर्घकालीन ऋणों को देने में पर्याप्त प्रगति हुई है। परन्तु दुःख वा विषय है कि आन्ध्र-प्रदेश, मसूर,

मद्रास, महाराष्ट्र, पंजाब इत्यादि कुछ राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में इनकी प्रक्रिया यों सीमित है और उनकी प्रगति सन्तोषजनक नहीं है।

कृषि पुनर्वित्त निगम (Agricultural Refinance Corporation)

देश की अर्थ-व्यवस्था में कृषि के महत्त्व को स्वीकार कर कृषि कार्यों के लिए वित्त सुविधायें सहकारी तथा भूमि बन्धक बैंको द्वारा दी जाती हैं। व्यापारिक बैंको द्वारा कृषि कार्यों के लिए वित्त व्यवस्था की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। अतः कृषि वित्त व्यवस्था के सगठन में कमियों को दूर किए बिना कृषि-क्रान्ति का आना असम्भव था अतः कृषि वित्त की संरचना में कमियों (Gaps) को पूरा करने के लिए एक अखिल भारतीय निगम की आवश्यकता थी। इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु कृषि पुनर्वित्त निगम (Agricultural Refinance Corporation) की स्थापना की गई।

कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत हुई। 1 जुलाई 1963 से विधिवत निगम ने कार्य करना प्रारम्भ किया।

निगम के उद्देश्य तथा कार्य (Objects and Functions) - कृषि पुनर्वित्त निगम का उद्देश्य पुनर्वित्त व्यवस्था द्वारा कृषि विकास तथा अन्य कार्यों जैसे कृषि, पशु-पालन, डेरी फार्मिंग, मुर्गी पालन इत्यादि के लिए मध्यम तथा दीर्घकालीन साह की व्यवस्था करना है। निगम सभी कृषि विकास परियोजनाओं की पुनर्वित्त व्यवस्था करेगा जिनकी वित्त व्यवस्था केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक या राज्य सहकारी बैंक पर्याप्त रूप से नहीं कर सकते।

निगम से निम्नलिखित योजनाओं के लिए सहायता प्राप्त की जा सकती है :

(i) भूमि को तोड़न तथा तैयार करने के लिए जिसमें सिंचाई सुविधाओं का पूर्ण प्रयोग किया जा सके।

(ii) बाज्र, नारियल, कालीमिर्च आदि विशेष फसलों की वित्त व्यवस्था के लिए।

(iii) यांत्रिक कृषि के विकास नलकूपों तथा पम्पिंग सेटों द्वारा विद्युत शक्ति के प्रयोग आदिके लिए।

इसके अतिरिक्त स्वीकृत सस्थाओं द्वारा विदेशों से पूँजीगत माल के आयात सम्बन्धी विलम्बित भुगतान को गारन्टी भी कर सकता है।

अधिनियम के अन्तर्गत निगम द्वारा जिन सस्थाओं को पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध होगी वे हैं (1) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक (2) राज्य सहकारी बैंक (3) अनुसूचित बैंक तथा (4) सहकारी सस्थाएँ। निगम पुनर्वित्त या अन्य रूप में अनु-

मोदित सस्याओं को ऋण तथा अग्रिम दे सकता है तथा उनके ऋण-पत्र खरीद सकता है ।

निगम के पूँजी-साधन (Capital Resources of the Corporation) .

निगम की अधिकृत पूँजी 25 करोड़ रुपये की है जो 10-10 हजार रुपये के 25,000 अंशों में विभाजित है । निगम की निर्गमित पूँजी 5 करोड़ रुपये की है क्योंकि प्रारम्भ में निगम ने 10-10 हजार रुपये के 5,000 अंश ही निगमित किए । निगम की 5 करोड़ रुपये की निर्गमित पूँजी निम्नलिखित सस्याओं द्वारा जुटायी गई है

(करोड़ रुपये में)

सस्या	अंशों की संख्या	राशि
1 रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया	2,954	2 95
2 केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक तथा राज्य सहकारी बैंक	1,356	1 36
3. अनुसूचित बैंक, जीवन बीमा निगम, बीमा तथा विनियोग कम्पनियाँ आदि	690	69
योग	5 000	5 00

केन्द्रीय सरकार ने निगम के अंशों पर मूलधन के भुगतान तथा 4½ प्रतिशत वार्षिक लाभांश की गारन्टी दी है । भारत सरकार ने निगम को 5 करोड़ का बिना शर्त का एक ऋण दिया है जिसका भुगतान 15 वर्ष बाद प्रारम्भ होगा । निगम को जमा प्राप्त करके तथा बाण्ड और ऋण पत्र निर्गमित कर अपने साधनों का विस्तार करने का अधिकार है । निगम द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा प्रदत्त पूँजी तथा कोषों के 20 गुने तक सीमित है ।

निगम का प्रबन्ध (Management of the Corporation) निगम का प्रबन्ध एक संचालक मण्डल (Board of Directors) द्वारा हाता है जिसमें प्रबन्ध संचालक (Managing Director) सहित 9 सदस्य होते हैं । कृषि साख से सम्बन्धित रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर संचालक मण्डल के अध्यक्ष होते हैं । अन्य संचालक भारत सरकार रिजर्व बैंक, केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित बैंक, जीवन बीमा निगम तथा बीमा और विनियोजक कम्पनियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ।

कृषि पुनर्वित्त निगम की प्रगति (Working of the Corporation): निगम ने 30 जून 1968 तक अपने कार्यकाल में 75 83 करोड़ रुपये व्यय वाली 95 योजनाओं पर 62.20 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है जिसका विवरण अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में दिया गया है ।

कृषि पुनर्वित्त निगम की प्रक्रियायें

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	सहायता प्राप्त परि- योजनाओं की संख्या	परियोजनाओं पर कुल व्यय	निगम द्वारा सहायता
1964-65	5	20.62	16.94
1965-66	26	15.47	12.29
1966-67	13	11.83	9.58
1967-68	61	34.83	29.00

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि निगम ने कृषि वित्त व्यवस्था को सुधारने तथा उसमें अभावों की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। राज्य सरकारों की सामान्य कृषि नीति का अंगुरूप निगम ने भी लघु सिंचाई योजनाओं को अधिक महत्व देने की नीति अपनाई है। पिछले वर्ष निगम ने जो सहायता दी उसमें अधिकतर नलकूप पम्पिंग सेट तथा सिंचाई नालियों के निर्माण की लघु सिंचाई परियोजनायें थीं। निगम अत्र दीर्घकालीन भूमि विकास परियोजनाओं के स्थान पर शीघ्र फलित होने वाली योजनाओं को महत्व दे रहा है।

व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषि वित्त को प्रोत्साहन देने हेतु निगम ने अपनी पुनर्वित्त स्वीकृति की नीतियों तथा नियमों में काफी ढील दी है। फरवरी 1968 में निगम ने चाय तथा काफी बागानों के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों को पुनर्वित्त ऋण देने की एक योजना प्रारम्भ की है। इसके अतिरिक्त निगम ने अनुसूचित बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों द्वारा कृषि पदार्थों के आधुनिक भण्डार गृहों के निर्माण के लिए पुनर्वित्त ऋण देना स्वीकार कर लिया है।

निगम की सहायता को प्रभावी बनाने के लिए पुनर्वित्त सहायता की वैधानिक विधियों को सरल बनाया जाना चाहिए।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संकेत

1. कृषि वित्त में सहकारी साख के स्थान का वर्णन कीजिये। उन्नति के लिये सुझाव दीजिये।

(राजस्थान टी०डी०सी० फाइनल, 1968)

[संकेत—प्रथम भाग में भारत की कृषि वित्त व्यवस्था में सहकारी साख के सापेक्षिक महत्व का वर्णन कीजिये तथा सहकारी बैंकों द्वारा दी गई सहायता का आंकड़ों सहित विश्लेषण कीजिये। दूसरे भाग में सहकारी साख व्यवस्था में सुधार के उपाय बताइये।]

2. भारतीय सहकारी बैंको के सगठन एव कार्य प्रणाली के सम्बन्ध मे एक सक्षिप्त आलोचनात्मक निबन्ध लिखिये ।

(राजस्थान टी०डी०सी० फाइनल, 1965)

[सकेत—प्रथम भाग मे भारतीय सहकारी बैंको के स्तूपाकार सगठन तथा उनकी कार्यप्रणाली व प्रगति का आकडो सहित विवेचन कीजिये । दूसरे भाग मे उनके सगठन तथा कार्यप्रणाली के मुख्य दोषो की व्याख्या कीजिये ।]

3 सहकारी बैंक कहा तक अपने उद्देश्यो मे सफलीभूत हुए हैं तथा उनकी सहायता के लिये रिजर्व बैंक आफ इडिया क्या कर सकता है ?

(राजस्थान टी०डी०सी० फाइनल, 1964)

[सकेत—प्रथम भाग मे सहकारी बैंको के उद्देश्य बताते हुए उनकी प्राप्ति मे सफलता का मूल्यांकन कीजिये । सफलता तथा असफलता दोनो पक्षो का विवेचन कीजिये । दूसरे भाग मे कृषि वित्त व्यवस्था मे रिजर्व बैंक के योगदान का वर्णन कीजिये ।]

औद्योगिक वित्त (Industrial Finance)

"During the post independence period concerted efforts have been made at the government level to remove the bottlenecks in the path of economic progress. The establishment of special financial institutions was one such step aimed at removing the financial bottlenecks and easing the flow of finance to the needy sectors of the economy."

उद्योगों को दो प्रकार की वित्त आवश्यकता होती है। एक तो स्थिर पूँजी की आवश्यकता जैसे भूमि, भवन, यन्त्र इत्यादि खरीदने के लिये। दूसरे कार्यशील पूँजी जैसे कच्चा माल खरीदने, माल की बिक्री के खर्च, मजदूरी तथा अन्य दिन-प्रतिदिन के खर्चों के लिए। स्थिर तथा कार्यशील पूँजी का अनुपात प्रत्येक उद्योग में भिन्न-भिन्न रहता है।

औद्योगिक वित्त के स्रोत (Sources of Industrial Finance)

भारत में औद्योगिक संस्थानों को निम्नलिखित स्रोतों से वित्त सुविधायें प्राप्त होती हैं (1) जनता (2) प्रबन्ध अभिकर्ता (3) व्यापारिक बैंक-बीमा कम्पनियाँ तथा विनियोजक प्रत्यास (4) देशी बैंकर (5) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें (6) विदेशी पूँजी तथा (7) विविध वित्तीय संस्थायें।

जनता औद्योगिक कम्पनियों के अग्र तथा ऋण पत्र खरीदकर उनमें विनियोजन करती है। जनता द्वारा विनियोजन उनकी बचाने की योग्यता तथा इच्छा और विनियोजन की सुविधाओं पर निर्भर करती है। भारत में उद्योगों को वित्त सहायता पहुँचाने में प्रबन्ध अभिकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे केवल औद्योगिक कम्पनियों के अग्र और ऋण पत्र ही नहीं खरीदते बल्कि कम्पनियों को आवश्यकता पड़ने पर ऋण भी देते हैं। कुछ उद्योगों में इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है परन्तु फिर भी औद्योगिक वित्त के साधन के रूप में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

भारत में व्यापारिक बैंकों द्वारा उद्योगों को केवल अल्पकालीन ऋण दिये जाते हैं क्योंकि भारतीय बैंकों का दृष्टिकोण अधिक परम्परावादी है और सम्पत्ति के

मूल्यांकन के साधनों का अभाव है। भारत में उद्योगों को व्यापारिक बैंकों से बहुत अपर्याप्त वित्त सहायता प्राप्त हुई है। यद्यपि व्यापारिक बैंकों द्वारा पर्याप्त वित्त सहायता न दिये जाने के कई कारण हैं फिर भी इस दिशा में व्यापारिक बैंकों ने कुछ नवोन करने का साहस नहीं दिखाया। इसी कारण भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक को विशिष्ट वित्त सस्थाओं का संगठन सड़ा करना पड़ा।

विशिष्ट वित्त सस्थाएँ

(Special Financial Institutions)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद औद्योगीकरण के विकास की वित्त व्यवस्था करने के लिए कुछ विशिष्ट वित्त सस्थाओं की स्थापना की गई है जिनका वणन यहाँ दिया जा रहा है।

(1) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

(Industrial Finance Corporation of India)

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत स्थापित इस निगम की स्थापना 1 जुलाई 1948 में हुई जिसका प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक सीमित दायित्व वाली कम्पनियों तथा सहकारी समितियों को माल के निमाण व विधायन (Processing) हेतु खनन अथवा विद्युत अथवा अन्य किसी प्रकार की शक्ति उत्पन्न करना व वितरित करने वाली आवस्ययिक इकाइयों को ऋण देना है।

निगम की पूँजी (Capital of the Corporation) इस निगम की अतिकृत पूँजी 10 करोड़ रुपये है जो पाच पाच हजार रुपये के 20,000 अंशों में विभक्त है। निगम की 30 जून, 1968 तक, प्रदान पूँजी 8 346 करोड़ रुपये थी। इसमें से 5 करोड़ रुपये के अंशों पर भारत सरकार द्वारा न्यूनतम 2½% वार्षिक लाभांश की प्रत्याभूति दी गई है, शेष पर न्यूनतम लाभांश प्रत्याभूति (Guarantee) की दर 4% है।

पूँजी पर विभिन्न सस्थाओं का स्वामित्व है। रिजर्व बैंक तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनियोजित पूँजी औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना पर विकास बैंक द्वारा ले ली गई। आगे भारतीयों में निगम का पूँजी पर विभिन्न सस्थानों का अधिकार प्रदर्शित किया गया है—

1 'It is expedient to establish an I F C for the purpose of making medium and long term credit more readily available to industrial concerns in India, particularly in circumstances where normal banking accommodation is inappropriate or recourse to capital issue methods is impracticable'

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम : पूँजी-स्वामित्व

अशदाता	पूँजी स्वामित्व (% में)	लिये गये अशो की सख्या
1. औद्योगिक विकास बैंक	50	8 346
2. अनुसूचित बैंक	20	3,405
3. बीमा कम्पनिया	22	3,586
4. सहकारी बैंक	8	1,355
योग	100	16,692

निगम का प्रबन्ध (Management of the Corporation) : पहले

निगम का प्रबन्ध करने के लिए 12 सदस्यीय सचालक मण्डल होता था जिसका अध्यक्ष भारत सरकार द्वारा अर्बन्तनिक पदाधिकारी होता था। कालान्तर में, सुचेता कृपलानी समिति (1952) के प्रतिवेदन की सस्तुति (recommendation) पर अर्बन्तनिक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाने लगी तथा सचालकों की सख्या भी बढ़ कर 13 हो गई। इन 13 सचालकों में से औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 4, केन्द्रीय सरकार द्वारा 2, अनुसूचित बैंकों द्वारा 2, सहकारी बैंकों द्वारा 2 तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा 2 सचालक नियुक्त किये जाते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति, निगम के परामर्श से, भारत सरकार करती है।

उपर्युक्त सचालक मण्डल के अतिरिक्त दैनिक कार्य-कलापो के सचालन के लिए निगम में एक 5 सदस्यीय केन्द्रीय समिति (Central Committee) है। इसके अलावा 5 अन्य परामर्शदात्री समितिया भी हैं जिनमें 41 सदस्य हैं। इन समितियों का कार्य इन्जीनियरिंग, धस्त्र, रसायन, चीनी व अन्य उद्योगों को ऋण देने से पूर्व उचित परामर्श देना है।

निगम के कार्य (Functions) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रमुख कार्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

(i) प्रत्याभूति (Guarantee) प्रदान करना : 21 दिसम्बर, 1957 से निगम का औद्योगिक संस्थाओं द्वारा विदेशों से पूँजीगत माल आयात करने के स्थगित भुगतान की गारन्टी करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। इस प्रावधान के पश्चात् भारतीय उद्योगों द्वारा अब विदेशों से मशीनें, यन्त्र तथा अन्य उपकरण आयात करने में कठिनाई नहीं होती।

विदेशी आयातों के भुगतान को गारन्टी देने में पूर्व निगम योजना की लागत, राष्ट्रीय महत्त्व, सामार्जन क्षमता, उपयुक्त अनुज्ञापत्र (Licence) की प्राप्ति, आयातित माल पर बंधक की स्थिति आदि तत्वों पर विचार करता है।

प्रायातित माल के भुगतान के अतिरिक्त विदेशी वित्तीय संस्थानों से प्राप्त मुद्रा ऋणों की भी निगम गारन्टी प्रदान करता है। 30 जून 1968 तक निगम ने 29 54 करोड़ रु० के 6 प्राथना पत्रों पर 23 47 करोड़ रुपये के विदेशी ऋण की गारन्टी की है।

(ii) अभिगोपन (Underwriting) : निगम ने सर्वप्रथम 1957-58 में औद्योगिक साख व विनियोग निगम (ICICI) तथा जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ-साथ 1.6 करोड़ रुपये के ऋण पत्रों का अभिगोपन किया। तब से आज तक निगम इस कार्य को निरन्तर करता रहा है। 30 जून, 1968 तक 22 91 करोड़ रुपये के दायित्व का अभिगोपन किया गया जिसमें से 9.70 करोड़ रु० के सामान्य अंशों, 6 18 करोड़ रुपये के पूर्वाधिकार अंशों व 7 03 करोड़ रुपये के ऋण पत्रों का अभिगोपन किया गया था। 30 जून, 1968 के अन्त तक निगम ने अभिगोपन-क्रिया में 17.39 करोड़ रुपया निर्गमित किया है।

(iii) ऋण देना : औद्योगिक निगम उद्योगों को मध्य कालीन तथा दीर्घ-कालीन ऋण देता है। ऋण स्वीकृति से पूर्व प्राथमिक सस्या की आर्थिक स्थिति, योजना (जिसके लिए ऋण मांगा जा रहा है) की उपयुक्तता, प्रबन्ध-व्यवस्था की कुशलता, लाभ-अर्जन की शक्ति तथा भुगतान की सम्भावनाओं आदि पर विचार किया जाता है।¹

निगम द्वारा अधिकतम 1 करोड़ रुपये के ऋण दिये जाते हैं। यदि किसी संस्थान को इससे अधिक का ऋण स्वीकार किया जाता है तो केन्द्रीय सरकार पूर्वानुमति आवश्यक होती है। इसी प्रकार निगम 10 लाख रुपये से कम के ऋण भी नहीं देता। 10 लाख रुपये से कम के ऋण सम्बन्धित राज्य के वित्त निगम द्वारा दिये जाते हैं। ये ऋण नई मशीन अथवा भूमि क्रय करने, सस्या का विस्तार करने तथा

1. "The principal factors that are taken into account are the relative industrial and national priority of the project in the economy of the country, sources and availability of raw materials whether imported or indigenous, the technical, financial and economic viability of the project, the market for the products to be manufactured, profit earning capacity of the project, the experience and probity of the promoters and their financial contribution towards the cost of the project, and the quality of the management and the adequate and competence of the technical and administrative personnel likely to be available for the completion and operation of the project."

मुद्रा तथा बैंकिंग

नवीनीकरण करने हेतु प्रदान किये जाते हैं जिनके लिए ऋणों की स्थायी सम्पत्ति, कच्चा या निर्मित माल आदि को धरोहर के रूप में रखना पड़ता है।

अपने कार्यकाल के 20 वर्षों में 30 जून, 1968 तक निगम ने 408.59 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता स्वीकृत की (Gross financial assistance sanctioned)। 103.45 करोड़ रुपये के वापिस तथा रद्द हुए ऋणों का समाप्त्य जन करने के बाद निगम की शुद्ध स्वीकृतियाँ 305.05 करोड़ रुपये की थीं।

नीचे की सारणियों में निगम द्वारा दिये गये ऋणों का विवरण प्रस्तुत है :

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिये गये (कुल) ऋण
(करोड़ रुपये में)

अवधि	शुद्ध स्वा- कृतियाँ	वितरित राशि
1 प्रथम योजना से पूर्व (1948 से 1951)	8.13	5.79
2 प्रथम योजना काल	27.02	10.94
3 द्वितीय योजनाकाल	50.09	40.62
4 तृतीय योजना काल	104.73	86.32
5 1 जुलाई 66 से 30 जून 68 तक	38.32	52.45
योग	228.79	196.12

उद्देश्यानुसार स्वीकृत ऋण
(30 जून 1968 तक)

(करोड़ रुपये में)

योजना	योजना की लागत	स्वीकृत राशि
1 नये सस्थान	181.05	140.62
2 पुराने सस्थान		
(अ) नवीन दिशा में परिवर्तन	19.88	5.94
(ब) विस्तार	422.72	74.27
(स) नवीनीकरण व पुनर्स्थापन	26.56	5.73
(द) चालू पूंजी	—	2.23
योग	1250.21	228.79

निगम द्वारा दिए गये ऋणों का उद्योगानुसार वितरण
(30 जून 1968 तक)

(करोड़ रुपये में)

उद्योग	इकाइयों की संख्या	शुद्ध स्वीकृति
1 चीनी (सहकारी क्षेत्र 52 66 क रु०)	82	60 50
2 रासायनिक	37	33 54
3 बरतन	70	31 06
4 नान फेरस मेटलस	6	27 62
5 खाद	5	21 89
6 धातु उत्पाद	49	20 62
7 बागज	22	20 30
8 सीमेंट	27	18 85
9 मशीनरी	18	11 83
10 बिजली उपकरण	30	9 31
11 अटोमोबाइलस	15	9 09
12 रबर उत्पाद	7	8 05
13 सेरामिक्स तथा ग्लास	20	6 71
14 लोहा व स्पात	6	6 11
15 पेट्रोलियम व गैस	4	4 89
16 कृत्रिम रेशे	7	4 46
17 होटल	5	3 47
18 अन्य	33	6 75
योग	443	305 05

निगम द्वारा स्वीकृत ऋणों का क्षेत्रानुसार वितरण
(30 जून 1968 तक)

(करोड़ रुपये में)

राज्य	इकाइयों की संख्या	शुद्ध स्वीकृति
1 महाराष्ट्र	92	59 18
2 तामिलनाडु	51	44 08
3 प० बंगाल	55	32 66
4 आन्ध्र प्रदेश	28	22 32
5 गुजरात	36	21 90
6 उत्तर प्रदेश	32	21 83
7 बिहार	24	17 97
8 मैसूर	32	17 53

राज्य	इकाइयों की संख्या	शुद्ध स्वीकृति
9. राजस्थान	13	16 29
10. केरल	14	11 19
11. मध्य-प्रदेश	13	8 34
12. हरयाणा	17	7 92
13. उड़ीसा	13	7.43
14. आसाम	6	6 68
15. पंजाब	11	6 39
16. दिल्ली	4	2.63
17. पांडीचेरी	1	0 60
18. अडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	0 11
योग	443	305 05

उपरोक्त सारिणियों पर दृष्टिपात करने से निम्न तथ्य सामने आते हैं—

- (i) सर्वाधिक ऋण नये उद्योगों की स्थापना हेतु स्वीकृत किये गये हैं तथा पुराने संस्थानों के विस्तार के लिए प्रदत्त ऋण राशि का स्थान दूसरा है।
- (ii) लगभग 20% ऋण चीनी उद्योगों को दिये गये हैं जिसमें 85% ऋण सहकारी क्षेत्र में दिये गये हैं।

(iii) दुख द सत्य होते हुए भी स्पष्ट है कि विकसित राज्यों को स्वीकृत ऋण अविकसित राज्यों का स्वीकृत ऋण से कहीं अधिक है।

औद्योगिक जगत में सहकारिता के तीव्र विकासार्थ इस क्षेत्र की समितियों को निगम ने 30. 6. 68. तक 62 चीनी मिलों, 7 सूती कटाई मिलों तथा 1 वनस्पति तेल मिल को क्रमशः 52 66 करोड़, 3.96 करोड़ व 0.23 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किये।

निगम द्वारा 30. 6 68 तक 113 प्रार्थना पत्रों पर (कुल 135 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए) 32 54 मिलियन डालर (23 98 करोड़ रु०) 66.99 मिलियन मार्क (12 55 करोड़ रु०) तथा 12 26 मिलियन फ्रैंक (1 86 करोड़ रु०) के विदेशी मुद्रा ऋण दिये गये

ब्याज दर :

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋणों पर ब्याज दर (प्रतिशत में)

वर्ष	1948	1953	1957	1962	1965	1969
दर	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0

उपरोक्त बढ़ती हुई ब्याज दर के प्रतिफल से स्पष्ट है कि निगम से लिये ऋणों पर 8% ब्याज देना पड़ता है जो कुछ लोगों के अधिक अनुसार है।

निगम के साधन (Resources of the Corporation) :

निगम अपनी पूँजी (जिसका विवरण दिया जा चुका है) के अतिरिक्त भारत सरकार से ऋण लेकर तथा ऋण-पत्र बेचकर पूँजी एकत्रित करता है। निगम को अपने निजी कोषों के 10 गुने तक ऋण लेने की अनुमति है। निगम के आर्थिक साधन निम्न तालिका से स्पष्ट हैं :

**निगम के आर्थिक साधनों का व्यौरा
(30 जून 1968 को)**

(करोड़ रुपये में)

राशि का वितरण	राशि	अर्थ-स्रोत	राशि
1. रुपया ऋण Rs. 167 58		1 पूर्ण दत्तपूँजी	8 35
2. विदेशी चलन ऋण Rs. 28 54	196 12	2. सचय कोष	9 45
3. अग्निगोपन	17 39	3 बाइस निगमन द्वारा प्राप्त ऋण राशि	43.29
4 प्रत्यक्ष अशदान	1.91	4. केन्द्रीय सरकार से ऋण	72 25
		5. विदेशी साख (credits)	28.54
		6 रुपया ऋण का भुगतान तथा विनियोगों की बिक्री	53 54
	215 42		215.42

निगम की आलोचना (Criticism) :

औद्योगिक वित्त निगम की ऋण नीतियों तथा कार्य प्रणाली की काफी आलोचनाये हुई हैं। आलोचकों के अनुसार निगम की ब्याज दर ऊँची है। मार्च 1968 में बैंक दर में कमी हो जाने के बाद यह आशा की जानी थी कि निगम की शुद्ध ब्याज दर (जो रुपया ऋणों पर 8 प्रतिशत है) में कुछ कमी होगी परन्तु निगम ने ब्याज दर में कोई कमी नहीं की है कुछ लोगों का कहना है कि निगम ने बड़े बड़े उद्योगपतियों तथा विकसित राज्यों को अधिकतर ऋण दिए हैं। निगम की ऋण-नीति के कारण उद्योगों का सतुलित विकास नहीं हुआ है। 30 जून 1968 तक निगम द्वारा स्वीकृत ऋणों का 45 प्रतिशत केवल 3 राज्यों—महाराष्ट्र, तामिलनाडु तथा पंजाब—को दिया गया है। विकसित राज्यों जैसे उड़ीसा का कुल ऋणों का 2 राजस्वान को 5 असम को 2 मध्य प्रदेश को 3 प्रतिशत भाग ही प्राप्त हुआ है।

निगम की उपर्युक्त आलोचनायें अशत ही सत्य हैं। निगम प्रयत्नशील होने हुए भी कुछ कारणोंवश अपनी ब्याज दर 8 प्रतिशत से कम करने में असमर्थ है। निगम अब अधिक उदारतापूर्वक ऋण देने की नीति अपना रहा है और आशा है कि निगम देश के सतुलित औद्योगिक विकास में पर्याप्त योगदान करेगा।

(२) राज्य वित्त निगम (State Financial Corporations)

औद्योगिक वित्त निगम की कार्य-परिधि म मध्यम व लघु उद्योगो की दीर्घ-कालीन साख की आवश्यकताओ की अभिपूर्ति न आ सकी अतः २८ सितम्बर, 1951 को भारतीय लोक सभा द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनियम पारित किया गया जिसके अधीन प्रत्येक राज्य ने राज्य वित्त निगमो की स्थापना की है। केवल मद्रास राज्य मे 'मद्रास औद्योगिक निवेश निगम लि०' है जो भारतीय प्रमडल अधिनियम के अन्तर्गत पजीकृत हुआ है। इस समय राज्या के स्थापित निगमो की सख्या १८ है।

राज्य वित्त निगम अधिनियम के अनुसार प्रत्येक राज्य के निगम की अधिकृत पूँजी 50 लाख रुपये से 5 करोड रुपये है। व्यवहार म, अधिकाश 1 निगमो की अधिकृत पूँजी 2 करोड रुपये तथा प्रदत्त पूँजी 1 करोड रुपया है। भारत के सभी राज्यों के निगमो की 'कुल प्रदत्त पूँजी' 20.01 करोड रुपये है। निगमो की पूँजी पर राज्य सरकारो, रिजर्व बैंक, अनुसूचिन बैना, सहकारी बैंको तथा बीमा कम्पनियो का स्वामित्व सर्वाधिक है। जनता न कुल पूँजी मे 4% भाग विनियोजित किया है। राज्य सरकारो द्वारा सम्बद्ध राज्यों के निगमो द्वारा वितरित लाभाश की न्यूनतम दर (3 से 4 प्रतिशत वार्षिक) निर्धारित कर दी है। यदि कोई निगम न्यूनतम लाभाश नहीं दे सकेगा तो उसकी पूँजि के लिए सरकार उत्तरदायी है। साथ ही, कोई राज्य निगम 5% से अधिक लाभाश वितरित नहीं कर सकता।

कार्य (Functions) .

राज्य वित्त निगम निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं:—

- (1) औद्योगिक संस्थानो को 20 वर्षीय ऋण प्रदान करना अथवा उनके ऋण पत्र क्रय करना।
- (2) औद्योगिक संस्थानो द्वारा (20 वर्षीय अवधि के) लिये ऋणो की गारंटी करना, एव
- (3) औद्योगिक संस्थानो द्वारा जारी किये गये अशो, बाड्स तथा ऋण पत्रो का अभिगोपन करना एव इस कार्य को करने से कुछ अश आदि खरीदने पडे तो 7 वर्ष के अन्दर-अन्दर उन्हे बेचना।

मद्रास निगम के अतिरिक्त अन्य किसी भी निगम ने अभिगोपन करने व ऋणपत्रादि क्रय करने के कार्य सम्पन्न नहीं किये हैं। राज्य वित्त निगम 15 हजार रु० से 20 लाख रुपये तक के ऋण दे सकते हैं।

1 केवल जम्मू-कश्मीर, मद्रास तथा आन्ध्र प्रदेश के वित्तीय निगमो को प्रदत्त पूँजी क्रमशः 0.5 करोड रु०, 2.35 करोड, 1.5 करोड रु० है।

ये निगम तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम भी रिजर्व बैंक को अपनी क्रियाओं से सम्बन्धित कुछ नियतकालिक विवरण देते हैं। बैंक को अपनी वार्षिक रिपोर्ट तथा अकेलित खातों के विवरण देने के अतिरिक्त निगमों के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक वित्त निगम प्रति वर्ष तथा राज्य वित्त निगम वर्ष में चार बार, अथवा उतनी बार जितनी कि बैंक चाहे, अपने ऋण तथा निवेशों, गारंटी प्रहृत ऋण तथा अभिगोपन के वर्गीकरण का विवरण बैंक को दें।

राज्य वित्त निगमों की ऋण क्रियाएँ

वर्ष	ऋण स्वीकृतियाँ	ऋण वितरित	ऋण शेष
1955-56	3 02	1 54	2 76
1960-61	9 16	4.75	17 13
1965-66	23 25	16 07	59 94
1966-67	20 0	17 3	—
1967-68	18 8	15 3	80 3

सन् 12 वर्षों में वार्षिक ऋण स्वीकृतियाँ 6 गुनी, वितरित ऋणों की राशि 10 गुनी तथा शेष ऋणों की मात्रा 29 गुनी हो गई है। राज्य सरकारों ने इन निगमों को उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम (State Aid to Industries Act) के अंतर्गत दिये जाने वाले ऋणों के लिए अभिकर्ता (Agent) नियुक्त किया है।

विविन्न वित्त निगमों के कार्यों के साथ बैंक के निकट सम्पर्क ने उनकी क्रियाओं में कुछ सीमा तक समन्वय स्थापित कराने में सहायता दी है। इस प्रकार एक प्रथा स्थापित हो गई है जिसके अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सामान्यतः 10 लाख रु० से अधिक रकम वाले प्रार्यना पत्रों को लेता है तथा राज्य वित्त निगम उनके विधानों द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर तथा किसी भी दशा में केवल 10 लाख रु० तक की मांगों पर ही विचार करत हैं।

इन निगमों की स्थापना से निःसन्देह ही उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में कुछ सहायता मिली है। किन्तु देश में औद्योगिक वित्त की उपलब्धि के सव्यानात्मक कला विन्यास को दृढ़ करना होगा, विशेषतः जहाँ तक मध्यकालीन वित्त का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में वार्षिण्य बैंक का योग, उनके उद्योग एवं वार्षिण्य के साथ विस्तृत सम्पर्क तथा उनकी क्रियाओं के लोचदार होने के कारण, विशेष महत्त्व रखता है।

3 भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम

(Industrial Credit And Investment Corporation of India, Ltd)

भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम लि० की स्थापना भारत सरकार, अमेरीका सरकार तथा विरज बैंक के पारस्परिक विचार विमर्श के फलस्वरूप

हुई। निगम की स्थापना निजी उद्योगों (Private Sector) के विकास में सहायता देने के लिए 5 जनवरी 1955 को हुई। निगम भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयत है।

निगम की पूंजी तथा अन्य साधन (Capital and other Resources) :

निगम की अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रु० (25,000 सामान्य अंश 1000 प्रति अंश) है। विनियोग निगम इंग्लैंड, अमरीका तथा भारत—उद्देशों तथा विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों द्वारा स्थापित हुआ। भारत सरकार ने भी इसे 7.5 करोड़ रुपये का व्याज मुक्त ऋण 15 वर्षों के लिए दिया। इसके वर्तमान वित्तीय साधन इस प्रकार हैं (31 दिसम्बर, 1968) :

अंश पूंजी (निर्गमित व प्रदत्त)	7.50 करोड़ रु०
काप	4 99
ऋण लेने की क्षमता	49 99
भारतीय मुद्रा	136.90
विदेशी मुद्रा	198.39
	Rs

निगम के कार्य (Functions of the Corporation) .

भारतीय औद्योगिक साख एव विनियोग लि० के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :

- (1) उद्योगों को मध्यम तथा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना।
- (2) कंपनियों के नये निर्गमित अंशों तथा प्रतिभूतियों का अभिगोपन कार्य करना।
- (3) उद्योगों को प्रबन्ध सम्बन्धी तकनीकी (Technical) तथा अन्य प्रकार का परामर्श देना।

साख एव विनियोग निगम केवल निजी क्षेत्र (Private Sector) के औद्योगिक संस्थाओं को वित्त सहायता देता है। यदि किसी निजी औद्योगिक संस्थान को सरकार से कोई वित्त सहायता प्राप्त हुई है तो वह निगम से सहायता प्राप्त करने की अयोग्यता नहीं है। निगम अधिकतर बृहद् उद्योगों (Large Scale Industries) को ऋण देता है।

निगम द्वारा दिये जाने वाले ऋण की व्याज दर, अभिगोपन तथा गारंटी का कमिशन तथा प्राविधिक सहायता आदि के शुल्क, सहायता देने के समय ही निश्चित कर लिये जाते हैं।

निगम के कार्यों का 31 दिसम्बर 1968 तक का विवरण आगे दी गई तालिका में दिखाया गया है।

भारतीय श्रीद्योगिक साख एवं विनियोग निगम का कार्य विवरण
(31 दिसम्बर 1968 तक) (लाख रु० मे)

भेद	कम्पनियो की संख्या	शुद्ध स्वीकृति की राशि	वितरित राशि
1. ऋण व प्रत्याभूति रूपया मे	134	4,885	3,503
विदेशी मुद्रा मे योग	328	13,188	8,842
	462	18,073	12,345
2. अभिगोपन सामान्य अश	116	1,596	780
पूर्वाधिकार अश	76	958	505
ऋणपत्र योग	47	1,779	1,172
	239	4,333	2,457
3 प्रत्यक्ष अशदान (Subscription) सामान्य अश	55	429	418
पूर्वाधिकार अश	7	66	61
ऋणपत्र योग	2	150	150
	64	645	629
कुल योग	765	23 051	15 431

निगम द्वारा दिये गये ऋणो का उद्योगानुसार तथा राज्यवार (state wise) वर्गीकरण प्रस्तुत तालिकाओं मे दिखाया गया है, :

निगम द्वारा दिए गये ऋणो का उद्योगानुसार वितरण
31 दिसम्बर 1968 तक (लाख रुपयो मे)

उद्योग	शुद्ध स्वीकृति की रकम (लाख रु०)	कुल स्वीकृति का %
1. ग्रॉटोमोबाइल्स	1,681	7.3
2. सीमेन्ट	1,325	5.7
3. रसायन एवं रासायनिक पदार्थ	4,571	19.8
4. विद्युत् उपकरण	1,966	8.5
5. विजली, गैस व स्टीम	545	2.4
6. खाद्य-उत्पाद (चीनी के अतिरिक्त)	284	1.2
7. काच के सामान, इत्यादि	677	2.9
8. मशीनरी	2,597	11.3
9. धातु पदार्थ-फेरस	3,655	15.9
10. धातु पदार्थ-नान फेरस	281	3.6
11. पल्प, पेपर तथा पेपर उत्पाद	1,104	4.8

उद्योग	शुद्ध स्वीकृति की रकम (लाख रु०)	कुल स्वीकृति का %
12 रबड़ उत्पाद	568	2.5
13. जहाजरानी	839	3.6
14. चीनी	267	1.2
15. सूतीवस्त्र	1,451	6.3
16. छुड़, कार्क, हाई बोर्ड	181	0.8
17 विविध	519	2.2
योग	23,051	100

सारिणी से स्पष्ट है कि इम किगम द्वारा 'रसायन' तथा 'धातु' उद्योगों को सबसे अधिक ऋण सहायता प्रदान की गई है। दूसरी ओर यह सहायता चीनी, रबड़ बिजली गैस आदि उद्योगों में अत्यल्प है।

निगम द्वारा दिए गये ऋणों का क्षेत्रानुसार वितरण (31 दिसम्बर 1968 तक)

(लाख रुपये में)

राज्य	कंपनियों की संख्या	शुद्ध स्वीकृत राशि लाख रु०	कुल स्वीकृति का प्रतिशत
1 आन्ध्र प्रदेश	13	943	4.1
2. आसाम	3	190	0.8
3 बिहार	17	1,739	7.5
4 गुजरात	74	2,698	11.7
5 हरयाणा	14	630	2.7
6 केरल	11	223	1.0
7 मध्य प्रदेश	6	318	1.4
8 तामिलनाडु	46	2,376	10.3
9. महाराष्ट्र	178	8,433	36.6
10. मंसूर	24	1,408	6.1
11. उड़ीसा	8	469	2.0
12 पंजाब	2	15	0.1
13. राजस्थान	6	545	2.4
14. उत्तर प्रदेश	18	904	3.9
15 प० बंगाल	60	1,855	8.1
16 केन्द्र शासित राज्य	6	305	1.3
योग	486	23,051	100.0

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि राज्यों को प्रदत्त आर्थिक सहायता में अत्यंत विषमता है। निगम ने महाराष्ट्र, तामिलनाडु, गुजरात तथा पश्चिमी बंगाल में 66.7% ऋण दे रखे हैं जबकि अन्य राज्यों में केवल 32.3% ऋण ही दिये हैं।

निगम ने अपने कार्यकाल में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। आशा है कि भविष्य में निगम नवीन क्षेत्रों में जोखिम उठाकर देश के सम्बलित औद्योगिक विकास में पर्याप्त योगदान देगा।

4. औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank of India)

भारत में उद्योगों की वित्त व्यवस्था के लिए 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI), 1951 में राज्य वित्त निगम (SFCs) तथा 1955 में औद्योगिक साध तथा विनियोग निगम (ICICI) की स्थापना के बाद भी औद्योगिक वित्त की पूर्ति आवश्यकताओं की तुलना में बड़ी अपर्याप्त थी। विशेषकर पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास की प्रस्तावित तीव्र गति के कारण देश में औद्योगिक वित्त के पुनर्गठित तथा एकीकृत सत्यागत ढाँचे के एक भाग के रूप में एक नयी सस्था की आवश्यकता अनुभव की गई। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के अन्तर्गत 1 जुलाई 1964 को औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई।

विकास बैंक के उद्देश्य (Objects of IDBI)

देश में औद्योगिक वित्त सस्थाओं के एकीकृत संगठन के शीर्ष सस्थान के रूप में कार्य करने और इस दिशा में भावी दायित्व को निभाने के उद्देश्य से औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई। अन्य वित्तीय सस्थाओं के¹ साधनों में योगदान देना भी इस बैंक का उद्देश्य है। इस प्रकार यह बैंक पूर्व स्थापित पुनर्वित्त निगम (जिसका इसमें 1 सितम्बर 1964 से विलोनीकरण हो चुका है) के उद्देश्यों को अपने में समाविष्ट करता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर के शब्दों में, 'बैंक यह प्रयत्न करेगा कि योजनाओं में प्राथमिकता प्राप्त कार्य भी औद्योगिक सस्थान वित्तीय अभाव के कारण कठिनाई अनुभव नहीं करे।'

1. 'Industrial Development Bank of India was started as an apex institution coordinating and supplementing the operations of other institutions providing term finance to industry and as an agency for providing direct financial assistance by filling in the gaps that remain after taking into consideration the assistance available from other institutions.'

औद्योगिक विकास बैंक बिल प्रस्तुत करते हुए 30 अप्रैल 1964 को तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा था

"We are envisaging the new Industrial Development Bank as a central co ordinating agency, which ultimately will be concerned, directly or indirectly, with all problems or questions relating to the long and medium term financing of industry, and will be in a position, if necessary, to adopt and enforce a system of priorities, in promoting future industrial growth"

बैंक के साधन (Resources of the Bank)

औद्योगिक विकास बैंक की अधिभूत पूँजी 50 करोड़ रुपये है जिसे रिजर्व बैंक भारत सरकार की स्वीकृति में 100 करोड़ तक बढ़ा सकता है। विकास बैंक की निर्गमित तथा दत्त पूँजी 20 करोड़ रुपये की है। (1) पूँजी तथा कोष 24 16 करोड़ रुपये (2) भारत सरकार से प्राप्त ऋण : 119 करोड़ रुपये (जिसमें पुनर्वित्त निगम द्वारा लिए गये 33.5 करोड़ रुपये का ऋण सम्मिलित नहीं है) (3) रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋण : 6 करोड़ रुपये।

विकास बैंक रिजर्व बैंक से दो प्रकार के ऋण प्राप्त कर सकता है। एक तो 90 दिन की अवधि तक के लिए ट्रस्टी प्रतिभूतियों की धरोहर पर और दूसरे 5 वर्ष तक की अवधि के लिए प्रमाणित व्यावसायिक विलों तथा प्रतिज्ञा पत्रों की धरोहर पर ऋण प्राप्त किए जा सकते हैं।

विकास बैंक को दीर्घकालीन साधन उपलब्ध कराने के लिए उसकी स्थापना के साथ ही रिजर्व बैंक अधिनियम में सहायक कर एक राष्ट्रीय औद्योगिक साख (दीर्घकालीन) कोष [National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund] का निर्माण किया गया है। इस कोष का प्रयोग रिजर्व बैंक द्वारा विकास बैंक के बाण्ड या ऋण पत्र खरीदने तथा विकास बैंक को अन्य वित्तीय सहायकों के अग, बाड या ऋण पत्र खरीदने के लिए ऋण देने के लिए किया जाता है।

बैंक के कार्य (Functions) .

इसके कार्य अन्य वित्तीय संस्थानों की अपेक्षा अधिक लोचपूर्ण हैं। इस बैंक द्वारा उन सभी संस्थानों को आर्थिक सहायता दी जा सकती है जो, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हों या निजी क्षेत्र में, निर्माण (Manufacturing) विधायन (Processing) सभी प्रकार की शक्ति के उत्पादन व वितरण, खनन, परिवहन आदि से सम्बन्धित हैं। प्रमुख रूप से इसके कार्यों का विवरण निम्नलिखित है—

(1) **अन्य वित्तीय संस्थाओं की सहायता :** संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋणों का पुनर्वित्तीकरण (Refinancing), उन संस्थाओं में प्रत्यक्ष पूंजी लगाने तथा उनके द्वारा अभिगोपन के कार्यों को गारंटी करने के प्रमुख कार्य इसी निगम द्वारा किये जाते हैं। पुनर्वित्त के ऋणों की अदायगी IFC, SFCS तथा ICICI से 3 से 25 वर्ष तक तथा अनुसूचित व राज्य सहकारी बैंकों से 3 से 10 वर्ष के अन्दर की जाती है। निर्यात साख का भी 6 माह से 10 वर्ष तक के लिए निगम पुनर्वित्तीयकरण करने की सुविधा देता है।

(ii) **औद्योगिक वित्त संस्थाओं को प्रत्यक्ष सहायता :** जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, तथा भारतीय साख व विनियोग निगम की यह अधोलिखित रूपों में सहायता देता है—

(अ) ऋण व अग्रिम (Loans & Advances) स्वीकृत करना,

(ब) अथ, वाइस या ऋण-पत्रों में धन विनियोजित करना, ऋय करना तथा अभिगोपन करना,

(स) अन्य पक्ष के प्रति औद्योगिक संस्थानों को देय स्थगित भुगतान (Deferred Payments) की गारंटी करना,

(द) व्यापारिक-प्रपत्रों को भुनाना, स्वीकृत करना तथा पुनः भुनाने की सुविधा देना।

(iii) **विपणन-शोध (Marketing Research) तथा विनियोजन सर्वेक्षण और तकनीकी अध्ययन (Technical-Economic Studies) की व्यवस्था करके प्रेरणात्मक क्रियाएँ (Promotional activities) सम्पन्न करना, आदि।**

कुछ समय पूर्व निगम द्वारा दीर्घकालीन ऋण देने के अतिरिक्त पटसन तथा सूती वस्त्र उद्योग को ऋणवक्रय (Hire purchase) आधार पर भारत में निर्मित मशीनों देना आरम्भ कर दिया है। इस योजना के अन्तर्गत ऋण-आर्थी को मशीन की लागत का 25 प्रतिशत अग्रिम जमा कराना पड़ता है तथा प्रबन्ध अभिकर्ताओं (Managing Agents) की गारंटी दिलानी पड़ती है। यदि गारंटी दिलाने की व्यवस्था न हो सके तो मशीन की लागत का 40 प्रतिशत अग्रिम जमा करना पड़ता है। ऋणी संस्था द्वारा कुल ऋण पाच किस्तों में चुकाना पड़ता है और शेप राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना पड़ता है। अन्य उद्योगों के लिए भी इस प्रकार की सुविधा की व्यवस्था अपेक्षित है।

विकास बैंक द्वारा स्वीकृत एवं वितरित ऋण

वर्ष	शुद्ध स्वीकृति	वितरित राशि (करोड़ रु० में)
1964-65		
1965-66	21.3	18.7
1966-67	69.3	35.6
1967-68	57.9	49.8
	27.9	41.7

इस बैंक ने अपनी स्थापना से 31 मार्च 1968 तक 209.9 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता स्वीकृत की जिसमें से 170.4 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। इसी अवधि में बैंक ने 29.7 करोड़ रु० के ऋणों तथा बिलम्बित भुगतानों की गारन्टी की। 1967-68 वर्ष में उद्योगों में मदीजग्य परिस्थितियों के कारण बैंक द्वारा उद्योगों को दी जाने वाली सहायता में लगभग आधी रह गई। (1966-67 में कुल स्वीकृति 71.3 करोड़ रु० की थी जो 1967-68 से मात्र 36.5 करोड़ रुपये की रह गई।)

अन्य निगम तथा प्रभ्यास (Other Corporations and Trusts)

भारतीय जीवन बीमा निगम

(Life Insurance Corporation of India)

भारतीय जीवन बीमा निगम वित्तीय साधनों की दृष्टि से भारत की बहुत सशक्त संस्था है। निगम अपने कोपो का विनियोजन विभिन्न क्षेत्रों में करता है। निगम को प्रीमियम आदि के रूप में जो रकम प्राप्त होती है वह दीर्घकाल के लिए ही प्राप्त होती है अतः निगम उसका दीर्घकाल के लिए विनियोजन कर सकता है। जीवन बीमा निगम के 31 मार्च 1968 को कुल साधन 1400 करोड़ रुपये के थे। निगम के कोपो का विभिन्न क्षेत्रों में सापेक्षित विनियोजन इस प्रकार है :

(1) सावजनिक क्षेत्र	72.6 प्रतिशत
(2) सहकारी क्षेत्र	7.8 "
(3) समुक्त क्षेत्र	0.6 "
(4) निजी क्षेत्र	19.0 "

निगम ने औद्योगिक प्रतिभूतियों में अपने कोपो का बहुत कम भाग विनियोजित कर रखा है। निजी क्षेत्र की औद्योगिक प्रतिभूतियों में कुल कोपो का केवल 20 प्रतिशत भाग ही विनियोजित किया गया है। 1959-69 के दस वर्षों में निगम का कुल कोपो (Total Life Fund) में 90 करोड़ रुपये की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है जबकि औद्योगिक प्रतिभूतियों में केवल 12 करोड़ रुपये की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। यदि निगम को पंजी बाजार में अधिक महत्वपूर्ण योगदान

करना है तथा दीर्घकालीन पूंजी निर्माण का प्रोत्साहित करना है तो उसकी विनियोग नीति में अधिक लोच लाना होगा।

विनियोजन के अतिरिक्त निगम औद्योगिक कम्पनियों के अंशों तथा ऋण-पत्रों का अभिगोपन (under writing) भी करता है जिससे उद्योगों में पूंजी विनियोग सुविधापूर्वक हो जाता है।

यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया (Unit Trust of India)

अल्प बचतकर्ताओं की अपनी बचतों के उपयुक्त ऋणों में विनियोजन की ओर साहज देने हेतु 1 फरवरी 1964 को यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया की स्थापना हुई।¹ ट्रस्ट 10-10 रुपये की इकाइया (units) बेचकर राशि का एकत्रीकरण करता है और फिर विवकपूर्ण ढंग से उद्युक्त तथा लाभदायक क्षेत्रों में उनका विनियोजन करता है।

ट्रस्ट की प्रारम्भिक पूंजी 5 करोड़ रुपये है। इसकी पूंजी में 250 करोड़ रुपये रिजर्व बैंक, 75 लाख रुपये जीवन बीमा निगम तथा 75 लाख रुपये स्टेट बैंक समूह ने लगाय है तथा शेष 1 करोड़ रुपये अनुसूचित बैंकों तथा अन्य वित्त संस्थाओं ने लगाय हैं।

ट्रस्ट द्वारा किए गये विनियोगों का सापेक्षिक अन्वयन निम्न तालिका से दिया जा सकता है।

यूनिट ट्रस्ट के विनियोग (30 जून 1968)

प्रतिभूतिया	राशि करोड़ रुपये में	कुल का प्रतिशत
1 सामान्य अंश	18.7	38.40
2 पूर्वाधिकार अंश	7.7	15.81
3 ऋण पत्र	19.9	40.86
4 सावजनिक निगमों के बाण्ड	0.9	1.85
5. ऋण पत्रों तथा पूर्वाधिकार अंशों के लिए अग्रिम	1.1	2.26
6 याचना राशि	0.1	0.21
7 कोषागार विपन	0.3	0.61
	48.7	100.00

¹ "The object of the Unit Trust of India Act, 1963 was to provide for establishment of a corporation with a view to encouraging saving and investment and participation in the income, profits and gains accruing to the corporation from the acquisition, holding, management and disposal of securities."

मुद्रा तथा बैंकिंग

उपर्युक्त आकड़ों से स्पष्ट है कि पूँजी के निर्माण तथा उसके विनियोजन में यूनिट ट्रस्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विनियोग करने के अतिरिक्त ट्रस्ट औद्योगिक कम्पनियों को अमिगोपन सुविधायें भी उपलब्ध करता है।

ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री आर. एस. मट्ट की एक घोषणा के अनुसार इकाइयों के विनय तथा बचत को प्रोत्साहन देने के लिए ट्रस्ट 1 जुलाई 1969 से दो नई योजनाएँ प्रारम्भ करने जा रहा है (1) ऐच्छक बचत योजना (Voluntary Savings Plan) तथा (2) शिशुओं को उपहार योजना (Children's Gift Plan)। भाषा है कि ये योजनाएँ अधिक लोकप्रिय होंगी।

ट्रस्ट द्वारा पहली बार जुलाई 1969 में इकाइयों (units) का विक्रय मूल्य 10 20 रुपये रखा गया है जो ट्रस्ट की आर्थिक सुदृढता तथा उसमें जनता के विश्वास का प्रमाण है। 1968-69 वर्ष में ट्रस्ट ने 7 10 प्रतिशत लानांश की घोषणा की है।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संकेत

(1) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के उद्देश्यों तथा प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। यह निगम अपने उद्देश्यों में कहा तक सफल हुआ है ?

[संकेत प्रथम भाग में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के उद्देश्यों तथा कायकलापों का सविस्तार वर्णन कीजिए। दूसरे भाग में निगम की सफलता का मूल्यांकन कीजिए और उसकी आलोचना भी कीजिए।]

(2) 'भारत में औद्योगिक वित्त' पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए।

[संकेत भारत में औद्योगिक वित्त के प्रमुख स्रोतों तथा विशिष्ट वित्त निगमों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में कठिनाइयों तथा उनको दूर करने के उपाय बताइये।]

(3) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank of India) के उद्देश्यों तथा कायकलापों पर प्रकाश डालिए। औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में शीघ्र सस्था के रूप में बैंक कहा तक सफल हुआ है ?

[संकेत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना के उद्देश्यों, उसकी पूँजी, प्रबन्ध तथा कार्यकलापों का विवरण दीजिए और बताइये कि वह अपने उद्देश्यों में कहा तक सफल हुआ है।]

व्यापारिक बैंक (Commercial Banks)

"Banking in India may have developed on unplanned and uncontrolled basis in the past, it has assumed a course of regulated and well planned development in recent years."

व्यापारिक बैंक वे बैंक होते हैं जो व्यापार की वित्त व्यवस्था करे तथा अन्य सामान्य बैंकिंग कार्य करें। वैसे तो विनिमय बैंक तथा स्टेट बैंक भी व्यापारिक बैंकिंग कार्य करते हैं और व्यापारिक बैंक ही है परन्तु व्यापारिक बैंको से सामान्यतया सात्वय विनिमय बैंक तथा स्टेट बैंक को छोड़कर भारतीय कम्पनी कानून के अन्तर्गत पंजीयत अन्य उन बैंको से लिया जाता है जो व्यापार की वित्त व्यवस्था करते हैं, जमा राशि स्वीकार करते हैं तथा सामान्य बैंकिंग सेवाएँ करते हैं। कमी-कमी उन व्यापारिक बैंको को सयुक्त पूँजी बैंक या मिश्रित पूँजी बैंक भी कहा जाता है क्योंकि उनका संगठन मिश्रित पूँजी आधार पर किया जाता है अर्थात् इनके अंश निर्गमित किए जाते हैं और पूँजी जनता द्वारा जुटायी जाती है। अतः परम्परा के आधार पर सामान्य रूप से व्यापारिक बैंक तथा मिश्रित पूँजी बैंक को पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त किया जाता है। भारत के प्रमुख व्यापारिक बैंको के नाम उनके महत्व के अनुसार इस प्रकार हैं - (1) सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया (2) पंजाब नेशनल बैंक (3) बैंक आफ बरोडा (4) बैंक आफ इन्डिया (5) युनाईटेड कामर्शियल बैंक आदि।

व्यापारिक बैंको का वर्गीकरण

(Classification of Commercial Banks)

भारत में व्यापारिक बैंको को दो वर्गों में बाँटा जाता है : (1) अनुसूचित बैंक (Scheduled Banks) तथा (2) गैर-अनुसूचित बैंक (Non scheduled Banks)

(1) अनुसूचित बैंक (Scheduled Banks) : अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जिनका नाम रिजर्व बैंक आफ इन्डिया एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची (Second Schedule) में सम्मिलित कर लिया जाना है। रिजर्व बैंक दूसरी अनु-

सूची में उन्हीं बैंकों के नाम सम्मिलित करता है जो निम्नलिखित शर्तों पूरे करते हों :

(i) बैंकों की दत्तपूँजी (Paid up Capital) : तथा सुरक्षित कोष मिलाकर 5 लाख रुपये से कम नहीं होने चाहिये ।

(ii) रिजर्व बैंक को यह सतोष हो जाय कि बैंक का कार्य संचालन इस प्रकार से नहीं हो रहा है जिससे जमाकर्ताओं के हितों को हानि हो ।

अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक के पास अपने कुल देयों (Total Liabilities) का 3 प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा कराना पड़ता है । अनुसूचित बैंकों को प्रति सप्ताह अपनी स्थिति का विवरण रिजर्व बैंक को भेजना पड़ता है । अनुसूचित बैंकों द्वारा इन विशेष दायित्वों की पूर्ति के बदले रिजर्व बैंक उनको कुछ विशेष सुविधायें भी देता है जैसे बिलों के पुनः बट्टा की सुविधा तथा प्रेषण सुविधायें (Remittance facilities) । अनुसूचित बैंक ए, बी, सी, श्रेणियों में विभाजित हैं ।

(2) गैर अनुसूचित बैंक (Non-scheduled Banks) जो बैंक अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में नहीं आते उन्हें गैर-अनुसूचित बैंक (Non scheduled Banks) कहा जाता है । अनुसूचित बैंकों की तुलना में इनके दायित्व कम होते हैं तथा रिजर्व का नियंत्रण भी कम होता है । परन्तु इन बैंकों के लिये भी यह व्यवस्था है कि वे अपने कुल देयों का 3 प्रतिशत भाग अपने पास या रिजर्व बैंक के पास नकद कोष में रखें ।

व्यापारिक बैंकों की वर्तमान स्थिति (Present Position of Commercial Banks)

पिछले दशक में व्यापारिक बैंकों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है । अनुसूचित बैंकों की कुल संख्या जो 1950-51 में 93 थी, 1968-69 में घटकर 73 रह गई है । अनुसूचित बैंकों की संख्या में कमी मुख्य रूप से बैंकों के एकीकरण (Amalgamations) के कारण रही है । दुर्बल बैंकों का सशक्त बैंकों के साथ एकीकरण बैंक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक उपयुक्त प्रवृत्ति है ।

भारतीय अनुसूचित बैंकों की प्रगति तथा वर्तमान स्थिति का अनुमान अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका से लगाया जा सकता है ।

अनुसूचित बैंको की स्थिति

(करोड रुपये में)

वर्ष (अन्तिम शुक्रवार)	बैंको की संख्या	निक्षेप (अन्तर बैंक जमाघ्रा के अतिरिक्त)			कुल बैंक ऋण	ऋणों का कुल जमाघ्रां से अनुपात
		माग	काल	कुल		
1960-61	89	719 72	1,026 34	1,746 06	1,319 54	75.6
1961-62	83	788 76	1,133 11	1,921 87	1,460.61	73.2
1962-63	79	867 11	1 175 14	2,042 26	1,588 01	77.8
1963-64	78	1,071 10	1,124 00	2,285 10	1,816 46	78.5
1964-65	76	1,239 35	1,343 95	2,583 30	2,033 70	78.7
1965-66	76	1,426 86	1,522 97	2 949 8	2,088 14	77.6
1966-67	75	1,649 96	1,775 77	3 424 72	2,692 47	78.6
1967-68	73	1,846 02	2,011 44	3,857.46	3,032 63	78 6
1968-69	73	1,922 34	2,406 70	4,329 04	3,369 66	77 8

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अनुसूचित बैंको के कुल निक्षेप जो मार्च 1961 में 1,746 06 करोड रुपये के थे, मार्च 1969 में बढ़कर 4,329.04 करोड रुपये हो गये अर्थात् उनके निक्षेप इस काल में लगभग डार्ले गुने हो गये। अनुसूचित बैंको द्वारा दिये गये ऋणों में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। उनके कुल ऋण जो मार्च 1961 में 1319 54 करोड रुपये थे, मार्च 1969 में बढ़कर 3369 66 करोड रुपये हो गये। इस काल में कुल ऋणों में 250 प्रतिशत वृद्धि हुई।

गैर अनुसूचित बैंको की प्रगति तथा वर्तमान स्थिति निम्न तालिका से प्रकट होती है।

गैर अनुसूचित बैंको की स्थिति

(करोड रुपये में)

वर्ष (अन्तिम शुक्रवार)	बैंका की संख्या	निक्षेप			कुल बैंक ऋण	ऋणों का कुल निक्षेपों में अनुपात
		माग	काल	कुल		
1960-61	256	11 43	31 30	42 73	29 11	68.1
1961-62	212	10.04	7 57	37 61	25 38	67.5
1962-63	211	10 53	26 78	37 31	20 88	56 0
1963-64	183	9 49	20 96	30 45	20 20	66 3
1964-65	103	9 20	17 73	26 93	17 48	64 9
1965-66	33	8 13	15 69	23 82	14 14	59 4
1966-67	24	9 00	14 75	23 75	14 05	59.2
1967-68	19	10 07	15 09	25.16	14 21	56 5
1968-69	17	10 54	16 07	26 61	13 07	49 1

(जनवरी 1969)

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि गैर-अनुसूचित बैंकों की संख्या लगातार घट रही है। गैर-अनुसूचित बैंकों की संख्या जो 1960-61 में 256 थी, जनवरी 1969 में घटकर 17 रह गई है। इसका मुख्य कारण बैंकों में एकीकरण की प्रवृत्ति है। इन बैंकों के कुल निक्षेप जो 1960-61 में 42.73 करोड़ रुपये थे जनवरी 1969 में घटकर 29.61 करोड़ रुपये रह गये। इन बैंकों के द्वारा दिये गये ऋण भी 1960-61 के 21.11 करोड़ के अंक से घटकर जनवरी 1969 में 13.07 करोड़ ही रह गये।

व्यापारिक बैंकों के दोष तथा कठिनाइयाँ

(Defects and Difficulties of Commercial Banks)

हमारे देश की व्यापारिक बैंकों के संगठन तथा क्रियाकलापों में कई प्रकार के दोष पाये जाते हैं। उनके स्वस्थ तथा सतुलित मावी विकास के मार्ग में कई प्रकार की कठिनाइयाँ तथा अड़चने हैं। व्यापारिक बैंकों के मुख्य दोष तथा कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं—

(1) बैंकिंग संस्थाओं का असंतुलित विकास (Imbalanced Development of Banking Institutions) : आयोजन काल में भारतीय व्यापारिक बैंकों का पर्याप्त विकास हुआ है परन्तु खेद का विषय है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में बैंक सुविधाओं का विस्तार बड़े असंतुलित तथा असमान रूप से हुआ है। जहाँ केरल, गुजरात, मद्रास, मैसूर और पंजाब आदि राज्यों में बैंकिंग सुविधाओं का विकास बड़ी तीव्रगति से हुआ, वहाँ दूसरी ओर उड़ीसा, असम, बिहार, कश्मीर, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान आदि राज्यों में बैंकिंग विकास बहुत कम हुआ। ये राज्य तो पहले ही से बैंकिंग सुविधाओं की दृष्टि से पिछड़े हुए थे। बैंकों की शाखा विस्तार नीति इतनी दोषपूर्ण रही है कि बैंकों ने बहुत सी शाखाएँ ऐसे स्थानों पर खोली जहाँ पहले से ही बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध थीं। इससे बैंकों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा में ही वृद्धि हुई है।

(2) विनियोग की दोषपूर्ण नीति (Defective Investment Policy) : भारतीय व्यापारिक बैंकों ने अपने विनियोगों का अधिकतर भाग सरकारी प्रतिभूतियों में लगा रखा है जिससे उनके बोधों में तरलता पर्याप्त मात्रा में रहे। परन्तु इसका एक परिणाम यह हुआ है कि बैंकों द्वारा बिली तथा हुडियों के प्रति उदासीनता के कारण भारत में एक सुसंगठित बिल बाजार का विकास नहीं हो पाया है।

(3) अपर्याप्त पूँजी तथा कोष (Inadequate Capital and Reserves) : भारतीय व्यापारिक बैंकों की दत्त पूँजी तथा काप उनके उत्तरदायित्व की तुलना में बहुत कम है। परिणामतः वे अपने कार्यकलाप अधिक उपयुक्त तथा मित-व्ययी ढंग से नहीं चला पाते।

(4) प्राथमिक क्षेत्रों को अपर्याप्त साख (Inadequate Credit to Priority Sectors) : भारतीय व्यापारिक बैंकों ने कृषि, लघु उद्योगों तथा निर्यात के प्राथमिक

कता प्राप्त क्षेत्रों में अपर्याप्त साख सहायता प्रदान की है। यह जीक है कि कुछ समय पहले तक कृषि साख का उत्तरदायित्व सहकारी बैंको न ही माना जाता था परन्तु फिर भी व्यापारिक बैंक सदा से ही लकीर के फकीर रहे हैं और देश के विकास की दृष्टि से प्रेरित न होकर सदा लाभ के परम्परागत दृष्टिकोण से ही कार्य क्षेत्रों का चयन करते रहे हैं। यही कारण है कि बैंको के राष्ट्रीयकरण की वटती माग के अनुरूप बैंको के सामाजिक नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत साख सहायता के क्षेत्र में बाह्य अनुशासन लागू कर बैंको को आवश्यक क्षेत्रों में कार्य करने के लिए बाध्य किया गया है।

(5) अकुशल बैंकिंग सेवार्थ तथा कर्मचारी (Inefficient Banking Services and personnel) : भारतीय व्यापारिक बैंको द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवार्थ बडी अकुशल तथा असतोपजनक हैं। देश के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त अकुशलता से बैंक भी अछूने नहीं रहे हैं। बैंको की कार्य प्रणाली तथा रीतिया परम्परागत तथा प्राचीन हैं और नये युग के साथ उनमें बहुत कम परिवर्तन हुआ है। ग्राहको को भुगतान लेन के लिए काफी प्रतीक्षा करनी पडनी है।

(6) बैंको का फेल होना (Bank Failures) : देश के समय समय पर बैंकिंग सकट के कारण बहुत से बैंक फेल हुए हैं जिसके फलस्वरूप बैंको में जनता का पूर्ण विश्वास नहीं है। इसी कारण व्यापारिक बैंक जनता से निक्षेप प्राप्ति में उतने सफल नहीं हो सके जितना उनसे आशा की जाती थी। 1960 में पलाई सेन्ट्रल बैंक जो एक अनुसूचित बैंक था फेल हो गया और बैंक की आन्तरिक स्थिति का ज्ञान होते हुए भी रिजर्व बैंक ने अपने अधिकारो का प्रयोग नहीं किया। बैंको के फल होने से बैंक व्यवस्था की टुल्लता ही प्रकट होती है। यह अवश्य ही सान्त्वनादायक है कि 1960 के बाद बैंक फेल होने की कोई घटना नहीं हुई।

(7) बैंकों में परस्पर प्रतिस्पर्धा (Competition among Banks) : बैंको में परस्पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्वागत योग्य है क्योंकि इससे बैंको की कार्यक्षमता बढती है परन्तु भारतीय व्यापारिक बैंक आपन में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा करते हैं। बैंको ने निक्षेप पर व्याज दरों के सम्बन्ध में समझौता किया था जो सिन्डिकेट बैंक की नीति के कारण चल नहीं सका। इसी कारण अब रिजर्व बैंक स्वयं निक्षेप दरों को नियन्त्रित करने का विचार कर रहा है।

(8) बैंकों के लाभ तथा उत्पादकता में कमी (Decline in Profitability and Productivity) : पिछले वर्षों में व्यापारिक बैंको की बढती लागतों तथा घटते प्रतिफलो के फलस्वरूप उनके लाभों तथा उत्पादकता में अत्यधिक कमी आयी है। 1961-67 काल में जहा अनुसूचित व्यापारिक बैंको के कार्य-व्ययो (Working

Expenses) में 35.8 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई है वहा उनकी कुल आय में वृद्धि की दर 29.5 प्रतिशत ही रही है।

(9) विदेशी भाषा का प्रयोग (Use of foreign language) - बैंक अपने ग्राहकों से प्रतिदिन का व्यवहार में अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं जिसे देश की अधिकांश जनता नहीं समझती। इससे बैंक ग्राहकों में एकाकार नहीं हो पाता और बैंक ग्राहकों के सम्बन्ध खोलत रहत हैं।

भारतीय बैंक व्यवस्था को उन्मुक्त दोष तथा कठिनाइयाँ बैंकों के विकास में बाधा हैं और उन्हें दूर करना ही होगा।

व्यापारिक बैंकों में सुधार के उपाय (Suggestions for Improvement in Commercial Banks)

व्यापारिक बैंकों के संगठन तथा उनके द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अर्पण प्राप्त साधन देना आदि दावों का दूर करन के लिए 1 फरवरी 1969 से बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण की व्यवस्था लागू की गई है जिससे सुधार की पर्याप्त आशा है। फिर भी व्यापारिक बैंक व्यवस्था में सुधार के लिए निम्नलिखित दिशाओं में प्रयत्न किया जाना चाहिए।

(1) बैंकिंग की तीव्रगति से समुचित क्षेत्रीय विकास हो (Speedy and balanced regional Development of Banking) बैंकिंग सुविधाओं के विकास का और भी अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ाना चाहिए। बैंकों के विस्तार में क्षेत्रीय असंतुलन का दूर किया जाना चाहिए। उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान ऐसे अविकसित राज्यों में बैंकिंग शाखाओं का विस्तार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दा या दा से अधिक बैंकों को मिलकर इन राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में सहायक बैंकों का गठन करना चाहिए। कुछ विद्वानों ने बैंकिंग विकास में क्षेत्रीय असंतुलन बनाने के लिए बैंकों को राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय बैंकों में वर्गीकृत करने का सुझाव दिया है।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का शीघ्र विकास (Early extension of banking facilities in rural areas) जैसे तो स्टेट बैंक की स्थापना, रिजर्व बैंक की शाखा विस्तार नीति तथा बैंकों के सामाजिक नियन्त्रण के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार तथा कृषि क्षेत्रों के लिए वित्त की व्यवस्था को पर्याप्त बन मिला है परन्तु इस दिशा में प्रगति की गति बड़ी धीमी है। यदि इसी मन्द गति से ग्रामीण बैंकिंग विकास का विकास हुआ तो इसमें पचीसो वर्ष लग जायेंगे। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं का तीव्र गति से विकास होना चाहिए। 'एक व्यक्ति शाखा, चलता बैंक' इत्यादि रीतियों से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का प्रारम्भ होना चाहिए। कुछ विद्वानों ने द्वि-बैंकिंग पद्धति (Dual System

of Banking) एक ग्रामीण क्षेत्र तथा दूसरा नगरीय और औद्योगिक क्षेत्र के लिए—के विकास का सुभाव दिया है जिसकी सफलता में सदेह है। शायद इन दिशा में क्षेत्र—विकास दृष्टिकोण (Area Development Approach) अधिक उपयुक्त सिद्ध हो सकें जिनके अन्तर्गत एक बैंक को कुछ चुने हुए जिले नियोजित कर दिए जाते हैं जिनका विकास उसी बैंक का दायित्व होता है।

[3] कर्मचारियों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार (Expansion of Education and Training of Banking personnel) बैंक कर्मचारियों की निपुणता बढ़ाने के लिए उनकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। छोटे छोटे बैंक तथा सहकारी बैंक को मिलाकर देश में लगभग 20,000 बैंक अधिकारी हैं और बैंकों में प्रतिवर्ष 2,000 नये अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। परन्तु बैंकिंग सम्बन्धी वर्तमान प्रशिक्षण संस्थाओं की क्षमता केवल 1 650 व्यक्ति को प्रशिक्षण देने की है। आवश्यकता तथा पूर्ति में अन्तर को शीघ्र पाटा जाना चाहिए। हर्ष का विषय है कि रिजर्व बैंक द्वारा निम्बर 1967 में नियुक्त बैंकिंग उच्च कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा विकास पर बैंकिंग ग्रुप जिसके अध्यक्ष उप-गवर्नर श्री बी० एन० आदरकर थे, के द्वारा प्रस्तावित 'बैंक प्रबन्ध का राष्ट्रीय संस्थान' (The National Institute of Bank Management)—N I B M) की स्थापना कर दी गई है।

(4) बैंकिंग कार्य-प्रणाली में सुधार हो (Improvement in Working Methods) : बैंकों को अपनी कार्य प्रणाली में आधुनिकतम विधियों का समावेश करना चाहिए। बैंकिंग रीतियों तथा व्यवहारों में अनुसंधान कर बैंकों को नया खोजें (Innovations) करनी चाहिए। जहां तक सम्भव हो कुछ प्रक्रियाओं का मन्त्रीकरण भी करना चाहिए।

(5) भारतीय भाषा का प्रयोग (Use of National Languages) : जनता से निकट सम्पर्क स्थापित करने तथा अधिक से अधिक व्यक्तियों को बैंक की ओर आकर्षित करने के लिए बैंकों का कार्य भारतीय भाषाओं में होना चाहिए। इस दिशा में सबसे पहले ग्राहकों द्वारा प्रयुक्त फार्मों, पास बुकों इत्यादि को भारतीय भाषाओं में छापा जाना चाहिए।

(6) साख का उचित वितरण (Proper Distribution of Credit as between Regions and Sectors) बैंक द्वारा दी जान वाली साख का वितरण इस प्रकार हो कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों जैसे कृषि, लघु उद्योग तथा निर्यात को

² Report of Working Group on the Training and Development of Higher Banking Personnel under the chairmanship of Mr B N Adarkar, Deputy Governor, RBI, July 1968

पर्याप्त मात्रा में साल उपनब्ध हो सके। बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण का मुख्य रूप से यही उद्देश्य था। राष्ट्रीय साख परिषद् (National Credit Council) की स्थापना से अब यह आशा है कि व्यापारिक बैंको द्वारा साल का उचित तथा न्यायपूर्ण वितरण सम्भव हो सकेगा।

(7) रिजर्व बैंक का अधिक प्रभावी नियन्त्रण (Effective Control of Reserve Bank over Banking System) : देश की बैंका क नेता के रूप में रिजर्व बैंक को अपनी मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन तथा बैंक व्यवस्था के प्रभावी नियन्त्रण के लिए अधिक सजिय होना चाहिए।

व्यापारिक बैंकिंग की वर्तमान प्रवृत्तिया (Present Trends in Commercial Banking)

भारतीय व्यापारिक बैंक व्यवस्था पिछली दशान्द्री की तुलना में अधिक सुदृढ तथा शक्तिशाली है। व्यापारिक बैंको की वर्तमान प्रवृत्तियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है -

(1) निक्षेपों में वृद्धि (Increase in Deposits) : स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बैंको के निक्षेपों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। कुल बैंक निक्षेपों की राशि जो 19 0-51 में 880 6 करोड़ रुपये थी वह 1960 में बढ़कर 1855 करोड़ तथा 1968-69 में और बढ़कर लगभग 4450 करोड़ रुपये हो गई। पिछले कुछ वर्षों में बैंक निक्षेपों में वृद्धि का अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है

बैंक निक्षेपों में वृद्धि

वर्ष अन्तिम शुक्रवार	अनुसूचित बैंक		(करोड़ रुपया में)	
	माग	काल	गैर अनुसूचित बैंक	
			माग	काल
1950-51	578 38	2 7 44		
1955-56	599 44	405 10		
1960-61	719 72	1,026 34		
1965-66	1,426 86	1,522 97	11 43	31 30
1968-69 ¹	1 954 51	2,460 91	8 13	15 69
			10 54 ²	16 07 ²

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अनुसूचित बैंको के निक्षेपों में तो लगातार वृद्धि हुई है, गैर-अनुसूचित बैंका के निक्षेपों में वृद्धि भी होती गई है यद्यपि 1968-69 में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। इसका कारण छोटे बैंको का बड़े बैंको के साथ एकीकरण है।

¹ Provisional

² Figures are for January 1969.

(2) ऋण तथा अग्रिमों में वृद्धि (Increase in Loans and Advances) गत वर्षों में बैंकों के ऋण तथा अग्रिमों में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। अनुसूचित बैंकों द्वारा दी गई कुल साख में वृद्धि निम्न तालिका से स्पष्ट है :

अनुसूचित बैंकों द्वारा दी गई कुल साख

(करोड रुपये में)

वर्ष	कुल साख (Total Bank Credit)	कुल साख का कुल निक्षेपों से अनुपात
1950-51	458 90	53.6
1955-56	632 46	63 0
1960-61	1,319 54	75 57
1965-66	2,288 14	77 57
1968-69	3 369 66 ¹	77 84 ¹

उपर्युक्त आकड़ों के अनुसार अनुसूचित बैंकों द्वारा दी गई कुल साख (ऋण, अग्रिम तथा विलो का क्रय और वट्टा) की राशि जो 1950-51 में 458 90 करोड रुपये थी, 1968-69 में बढ़कर 3369.66 करोड रुपये हो गई। इन्हीं वर्षों में साख-निक्षेपों का अनुपात भी 53.6 से बढ़कर 77.84 प्रतिशत हो गया।

(3) दत्त पूँजी तथा कोषों का निक्षेपों से अनुपात (Declining ratio of Paid-up Capital and Reserves to Deposits) भारतीय व्यापारिक बैंकों की दत्त पूँजी तथा कोषों का निक्षेपों से अनुपात निरन्तर घट रहा है जो इस बात का परिचायक है कि बैंकों में जनता का विश्वास अधिक दृढ़ होता जा रहा है।

भारतीय बैंकों की दत्त पूँजी तथा कोषों का निक्षेपों से अनुपात निम्न तालिका से स्पष्ट है :

बैंकों की पूँजी तथा कोषों का निक्षेपों से अनुपात

(प्रतिशत)

वर्ष	अनुसूचित बैंक	अन्य बैंक	कुल
1951	9	22	10
1956	7	16	7
1961	4	17	4
1966	4	15	4

उपर्युक्त प्रवृत्तियों के अतिरिक्त व्यापारिक बैंको का निरन्तर शाखा विस्तार हो रहा है। बैंको में विलय आन्दोलन भी बैंकिंग संगठन तथा ढांचे को अधिक सुदृढ़ बनाने में योगदान कर रहा है। बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण योजना के कारण व्यापारिक बैंक अब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों कृषि, लघु उद्योग तथा निर्यात—को अधिक साहज उपलब्ध करने में क्रियाशील हो रहे हैं।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संकेत

(1) भारतीय बैंक व्यवस्था के मुख्य दोष क्या हैं ? उसमें सुधार के सुझाव दीजिए।

[संकेत : प्रथम भाग में भारतीय बैंक व्यवस्था के दोषों का विवेचन कीजिए। दूसरे भाग में उसमें सुधार के लिए सुझाव दीजिए।]

बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण (Social Control of Banks)

"The objective of social control as envisaged in India is to ensure, without actual take over of banks into public ownership, the achievement of those social ends that nationalisation could conceivably secure"

Deputy Governor, R B I

किसी भी देश में उद्योग-धंधों के समुचित विकास हेतु अच्छी बैंक व्यवस्था का होना अत्यन्त आवश्यक है। अल्प विकसित देशों में तो पूँजी अभाव के कारण इस बात की आवश्यकता और भी अधिक होती है। बैंक व्यवस्था के द्वारा देश के उपलब्ध साधनों को एकत्रित कर उनको उपयुक्त उद्योगों में प्रयोग किया जा सकता है। इसी कारण देश के आर्थिक क्लेवर में उसकी उपयोगिता होती है। आर्थिक आयोजन के सदर्भ में बैंक व्यवस्था कुशल होने के साथ-साथ ऐसी होनी चाहिये ताकि आर्थिक व सामाजिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। अतः भारतीय बैंक व्यवस्था में व्याप्त दोषों तथा कमियों को यथा शीघ्र दूर किया जाना बड़ा आवश्यक है। भारत की बैंक व्यवस्था को सुधारने तथा उसे परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल बनाने हेतु उठाये गये अनेक कदमों में से एक कदम इस पर सामाजिक नियन्त्रण का भी है। यह स्मरणीय है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात उठी थी जिसने बाद में काफी जोर भी पकड़ा था। चार अर्थशास्त्रियों द्वारा बैंकों के कार्य की आलोचनाओं तथा मविष्य में उनका राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष में एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई है। परन्तु कुछ राजनैतिक कारणों से तथा कुछ अन्य कठिनाईयों के कारण ऐसा सम्भव न हो सका।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में निम्न तक दिए जाते हैं

1. बैंकों द्वारा बड़े-बड़े व्यापारिक संगठनों को ऋण देकर असमानता का व्यवहार किया गया है और इनसे आर्थिक शक्ति के कन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है।

2. बैंकों ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों [Priority Sectors] जैसे कृषि कार्यों, लघु उद्योगों, सहकारिता तथा नियामक के लिये वित्त की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है, अतः इनके साधनों का उपयोग पूर्णतया सही ढंग से नहीं हुआ है।

3 बैंको ने आर्थिक विकास के लिये निर्धारित की जानेवाली प्राथमिकताओं के अनुरूप ऋण की व्यवस्था नहीं की है।

4 ग्रामीण क्षेत्रों में बैंको ने अपनी सेवाओं का विस्तार अच्छे ढंग से नहीं किया है, बैंको का कार्य क्षेत्र शहर तथा ग्रह-शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है।

5. प्रजातान्त्रिक समाजवाद को ध्यान में रखते हुये भी इनके राष्ट्रीयकरण को उचित समझा गया है।

6. बैंको के संचालक मंडलों का गठन भी अनेक दृष्टियों से दोषपूर्ण रहा है, इनमें विभिन्न क्षेत्रों व हितों से सम्बन्धित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व भी ठीक से नहीं रहा है।

7. बैंको के द्वारा कई अवाछनीय कार्य किये जाते हैं। केन्द्रीय बैंक के नियन्त्रण के होते हुये भी इनके कार्य-कलापो में अनेक दोष सामने आते रहे हैं। बैंको की ऋण नीति बैंको के संचालकों के हितों को ध्यान में रखते हुये निर्धारित की जाती है तथा अधिकांश ऋण उन औद्योगिक इकाइयों को मिल पाते हैं जिनमें किसी न किसी रूप में बैंक के संचालकों का आर्थिक हित होता है। इसी प्रकार इन्होंने ऋण एवं बचत की दृष्टि से क्षेत्रीय भेदभाव किया है। इनके कार्यों से मुद्रा बाजार में अस्वाभाविक प्रवृत्तियाँ पनपी हैं।

उपरोक्त तर्कों में से कतिपय को वास्तविक बताते हुये कुछ व्यक्तियों का कथन है कि बैंको के राष्ट्रीयकरण से देश की अर्थव्यवस्था को कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है। उनके अनुसार राष्ट्रीयकरण की मांग आर्थिक कारणों पर न की जाकर राजनैतिक विचारों से प्रभावित हुई दिखालाई पड़ती है। बैंक अगर अवाछनीय कार्य करते हैं तो उन पर ठीक नियन्त्रण की व्यवस्था नहीं है और व्यवस्था है भी तो उसका पालन नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार अगर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार नहीं किया है अथवा कृषि, उद्योगों आदि का पर्याप्त साख प्रदान नहीं की है तो इन विपक्षियों का कहना है कि उनको उचित मांग दर्शन नहीं मिला है। इस प्रकार ये कमियाँ ता कानून में सशोधन वर नियन्त्रण को और कड़ा करके बिना राष्ट्रीयकरण को भी दूर की जा सकती है। राष्ट्रीयकरण से सरकार पर इनक प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था का भार भी पड़ेगा। सरकार स्टेट बैंक की प्रशासन व्यवस्था के लिये ही उचित व्यक्तियों की कठिनाई अनुभव करती है तो फिर सभी बैंको के राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना और भी कठिन होगा। 'आर्थिक दृष्टि से राष्ट्रीयकरण से सम्पूर्ण साख ढाँचा अद्यवस्थित हो जायगा तथा साख का सगठित से असगठित क्षेत्रों में हस्तान्तरण होगा इससे राजनैतिक दबाव अधिक बढ़ेंगे और साख प्रणाली का

व्यापारिक स्वरूप समाप्त हो जायेगा। प्रशासकीय दृष्टि से राष्ट्रीयकरण में प्रति-योगिता के अभाव में कुशलता चली जायेगी एवं नियमों व लाल-फीताशाही में वृद्धि होगी। वित्तीय दृष्टि से राष्ट्रीयकरण से क्षतिपूर्ति में ही काफी साधन खप जायेंगे तथा विदेशी व्यापार व विदेशी सहायता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगे।¹ इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुये यह सही प्रतीत होता है कि स्वामित्व में परिवर्तन लाने से पूर्व उनकी कार्यविधि में परिवर्तन लाना अधिक आवश्यक है। कुछ मध्यम मार्ग अपनाकर ही बैंक व्यवस्था को सुधारा जाना चाहिये जिससे वर्तमान दोष दूर हो और बैंक आर्थिक प्रगति में अपना अपेक्षित योगदान दे सकें। बैंको पर सामाजिक नियंत्रण इसी दिशा में किया जाने वाला प्रयास है।

देश के आर्थिक ढांचे की बैंकिंग व्यवस्था महत्वपूर्ण कुजी है। हमारा देश कृषि प्रधान है और कृषि की उन्नति पर ही हमारी आर्थिक प्रगति निर्भर है। देश में मानव धन पर्याप्त है जिसका अनुकूलतम उपयोग आवश्यक है। निर्यात व्यापार का भी देश की अर्थव्यवस्था के लिये बहुत महत्व है। इन सभी क्षेत्रों की उन्नति के लिये आवश्यक है कि साख सुविधाओं को समय पर पर्याप्त मात्रा में प्रदान किया जाय। भारत के व्यापारिक बैंकों ने कृषि, लघु उद्योग तथा निर्यात आदि को पर्याप्त मात्रा में साख उपलब्ध नहीं की है और बैंक साख का अधिक भाग बड़े और मध्यम श्रेणी के उद्योगों तक ही सिमित रहा है। कृषि क्षेत्र देश की राष्ट्रीय आय में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान करता है किन्तु उसे बैंक साख का केवल 0.2 प्रतिशत मिलता है। इसी प्रकार लघु उद्योग देश के औद्योगिक उत्पादन में 35 प्रतिशत के लगभग योग देते हैं किन्तु उन्हें औद्योगिक साख का केवल 6 प्रतिशत मिलता है जबकि बड़े उद्योग बैंक साख का 65 प्रतिशत प्रयोग करते हैं। इस सब का यह अभिप्राय नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े उद्योगों का महत्व कम समझा जाय परन्तु आर्थिक विकास की दृष्टि को ध्यान में रख कर देखे तो कृषि, लघु उद्योग तथा निर्यात भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय आय में योगदान, रोजगार सम्बन्धी अवसरों को प्रदान करना, आर्थिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण आदि तत्वों के कारण वे सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। फिर बैंको की प्रवृत्त व्यवस्था में व्यापारिक व औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों का ही बाहुल्य है और साख सम्बन्धी निर्णयों में छोटे उद्योगपतियों, कृषकों आदि की कोई आवाज ही नहीं है। अतः बैंको के द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का अधिक बड़ा भाग इन बड़ी संस्थाओं को ही पहुँचता है और इनमें भी उनको जिनमें संचालकों का आर्थिक हित होता है। इन सभी कारणों से सामाजिक नियंत्रण को ठीक समझा गया है।

1. श्री एम. के मेहता "बैंको पर सामाजिक नियंत्रण" आर्थिक समीक्षा, 10 अप्रैल 1969, p, 14.

सामाजिक नियन्त्रण क्या है ? (What is Social Control)

सामाजिक नियन्त्रण का अर्थ है स्वामित्व में परिवर्तन किये बिना सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैंकिंग पद्धति का अतिरिक्त नियन्त्रण करना। अतिरिक्त नियन्त्रण इसलिये कि नियन्त्रण तो पहले से ही पर उससे निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी है। सामाजिक नियन्त्रण का अभिप्राय बैंकिंग साहस (Banking entrepreneurship) का विकास तथा बैंक प्रबन्ध का वैज्ञानिक ढंग के पुनर्गठन से भी लिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया के अध्यक्ष श्री आर. के. तलवार के अनुसार बैंको का सामाजिक नियन्त्रण दश के आर्थिक नियोजन की आवश्यकताओं का बैंक व्यवस्था से व्यावहारिक सम्बन्ध का साधन है जिससे बचत का सुन्दर सञ्चलन तथा बैंक साल का सउद्देश्य वितरण सम्भव हो सके।¹ दीना बैंक के अध्यक्ष श्री पी. वी. गान्धी के अनुसार सामाजिक नियन्त्रण बैंकिंग सम्बन्धी विचारों तथा परम्पराओं, ऋण नीतियों, शाखा विस्तार, प्रबन्ध, प्रशिक्षण व अन्य क्षेत्रों में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों से सम्बन्धित बहुमुखी क्रान्ति की ही एक प्रक्रिया है।² एम. चौकसी सामाजिक नियन्त्रण को एक ऐसा बैंकिंग सुधार मानते हैं ताकि बैंक व्यवस्था देश के आर्थिक विकास में अनुकूल हो सके।

बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण के निम्न उद्देश्य बतलाये गये हैं

(1) बैंक साल का अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में समुचित वितरण किया जाए अर्थात् बैंक के द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में कृषि, लघु उद्योगों आदि क्षेत्रों को पर्याप्त राशि प्राप्त हो सके।

(2) बैंको की नीति तथा व्यवहार के द्वारा राज्य नीति के सामाजिक व आर्थिक उद्देश्यों का प्राप्त किया जाय जैसे प्रजातान्त्रिक समाजवाद का विकसित होना, पंचवर्षीय योजनाओं का सफल होना, आदि।

¹ Shri R. K. Talwar chairman, State Bank of India, looks upon social control as a means of better alignment of the banking system to the needs of economic planning through a more purposeful distribution of credit & effective mobilisation of savings.

—Commerce, May 3 1969 p 866.

Shri P. V. Gandhi, Chairman of Dena Bank defines social control as "the process of a multipronged revolution signalling momentous changes in the fields of banking concepts and traditions, lending policies, branch expansion, management, personnel training & a host of other things"

—Commerce, May 3 1969 p, 866.

(3) बैंको के संचालक मंडलो का व्यापक आधा र पर गठन किया जाय तथा साख सम्बन्धी नियुयो मे भी व्यापक प्रतिनिधित्व स्थापित किया जाय ।

(4) ग्रामीण क्षेत्र मे व्यापारिक बैंको का विस्तार, छोटे लोगो का अधिक साख सुविधा, निर्यात व्यापार को प्रोत्साहित करना, साख सम्बन्धी प्रयत्नूलनो को दूर करना आदि बातो की ओर ध्यान दिया जाय ।

(5) बैंकिंग व्यवस्था का समुचित अध्ययन करने हेतु एक बैंकिंग आयोग की नियुक्ति जी जाय ।¹

बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण की चर्चा सर्व प्रथम कांग्रेस दल न अपने 1966 से चुनाव घोषणा मे की थी । विचार विमश के पश्चात् सामाजिक नियन्त्रण के सम्बन्ध मे श्री मारारजी देसाई ने भारतीय ससद मे 14 दिसम्बर 1967 को इसके लामो को बतलाते हुये एक व्यक्तय दिया । 23 दिसम्बर 1967 को सामाजिक नियन्त्रण के लिये एक बिल, जिसे बैंकिंग कानून (सशधित) बिल 1967 कहा गया, ससद मे प्रस्तुत किया गया । जो 1968 मे पास हुआ । 1 फरवरी 1969 से इसे लागू किया गया है ।

सामाजिक नियन्त्रण योजना की विशेषतायें (*Special Features of Social Control Scheme*)

सामाजिक नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाय ह ।

1. राष्ट्रीय साख परिषद का गठन (National Credit Council) - सामाजिक नियन्त्रण की योजना मे राष्ट्रीय साख परिषद महत्वपूर्ण स्थान रखती है । इसे देश के लिये साख नीति निर्धारित करने हेतु निम्न ढग से गठित किया गया है ।

1 अध्यक्ष, जो भारत सरकार के वित्त मन्त्री होंगे ।

1 उपाध्यक्ष, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर होंगे ।

3 स्थाई सदस्य, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वित्तमन्त्रालय के आर्थिक मामलो के विभाग क विशेष सचिव और कृषि पुनर्वित्त मण्डल के अध्यक्ष ।

20 अन्य सदस्य, जो व्यापारिक बैंक, सहकारी क्षेत्र, बडे, मध्यम तथा छोटे उद्योगो, कृषि व्यापार व व्यवसाय को प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे । इन सदस्यो का कायकाल अधिकतम तीन साल तक का रह सकता है ।

कुल सदस्यो की सह्या ।

1 श्री आर. जी सरैया की अध्यक्षता मे बैंकिंग आयोग नियुक्त कर दिया गया है जिसने माच 1969 से अपना कार्य शुरू कर दिया है । यह आयोग अपना प्रतिवेदन 1970 के अन्त तक देगा ।

इस परिपद के निम्न कार्य हैं

1. निश्चित समयवधि के लिये विभिन्न स्रोतों में बैंक साख सम्बन्धी माँग का अनुमान लगाना ।
2. प्राथमिक स्रोतों विशेषतया कृषि, छोटे उद्योग व निर्यात, की आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुये विनियोग हेतु दिये जाने वाले ऋणों और अग्रिमों की प्राथमिकताओं को निश्चित करना । प्राथमिकताओं का निर्धारण करते समय परिपद उत्पादन क्षमता को वित्तीय महत्त्व का आधार मानेगी जबकि अब तक वास्तविक परिमम्पदा को आधार माना जाता रहा है ।
3. उपलब्ध साधनों का अधिकतम अच्छे उपयोग हेतु विभिन्न व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों तथा अन्य विशिष्ट संस्थाओं द्वारा अपनायी जाने वाली ऋण व विनियोग नीतियों में समन्वय स्थापित करना ।
4. अन्य सम्बन्धित बातों पर विचार करना जो कि अद्यक्ष प्रयत्न उपाध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित की जाय ।

योजना के उद्देश्यों व राष्ट्रीय नीति के अनुकूल साख के उचित वितरण में यह परिपद भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक को सहायता करेगी । परिपद की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक आवश्यक रूप से होगी । परिपद के निर्णयों के अनुसार बैंक कार्य करते हैं अथवा नहीं, इसकी देखा-भाली का कार्य रिजर्व बैंक के द्वारा होगा ।

2. बैंकों के संचालक मंडल का पुनर्गठन (Reconstitution of Banks, Board of Directors) : व्यापारिक बैंकों के संचालक मंडलों का पुनर्गठन भी इस योजना के अन्तर्गत किया जायगा । यह इस ढंग से होगा कि इन मण्डलों में बहुमत ऐसे लोगों का हो जिन्हें हिमाव किनाब, बैंक व्यवसाय, कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था सहकारिता, वित्त, लघुउद्योग अर्थशास्त्र व कानून का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है । बैंकों के संचालक मंडल का समापति पूर्ण-कालिक व्यक्ति ही होगा जिसकी नियुक्ति रिजर्व बैंक की अनुमति से पाच वर्ष तक की अवधि के लिये की जाएगी । संचालक मण्डलों के समापति उद्योगपति नहीं हो सकेंगे, केवल व्यावसायिक बैंकर ही इस पद पर नियुक्त किये जा सकेंगे । यह इसलिये किया गया है जिससे प्रबन्धीय निर्णयों में बैंकिंग हित सर्वोपरी रह सकें । संचालकों का बड़े-बड़े प्रयत्न मध्यम स्तर के औद्योगिक या व्यापारिक संगठनों में महत्वपूर्ण हित निहित नहीं होना चाहिए और नहीं उनसे मन्त्रिय सम्बन्ध ही ।

3. विदेशी बैंकों के प्रबन्ध मंडलों का पुनर्गठन — इसके के लिये अभी कोई व्यवस्था इस योजना के अन्तर्गत नहीं की गयी है । ये बैंक सलाहकार बोर्ड बना सकेंगे (जिनमें भारतीय सदस्य होंगे) जिनके द्वारा राष्ट्रीय साख परिपद के निर्णयों की

जानकारी इन बैंको को दी जा सकेगी। तथा इन्ही बोर्डों की देखरेख में ये बैंक अपनी ऋण नीतियों को निर्धारित करेंगे।

4. केन्द्रीय बैंक का कड़ा नियन्त्रण (Stricter Control by Central Bank). सामाजिक नियन्त्रण की योजना के अन्तर्गत व्यापारिक बैंको पर केन्द्रीय बैंक के नियन्त्रण को कड़ा करने की व्यवस्था है। अब तक जमाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर ही रिजर्व बैंक को नियन्त्रण सम्बन्धी अधिकार प्रदान किये गये थे पर इस योजना के अन्तर्गत रिजर्व बैंक मौद्रिक स्थिरता, आर्थिक वृद्धि, बैंको के साधनों का उचित विवरण आदि को ध्यान में रखकर आदेश जारी कर सकता है। जैसा कि बताया जा चुका है सचालक मंडलों के सभापति की नियुक्ति केन्द्रीय बैंक की अनुमति से ही होगी, उसको केन्द्रीय बैंक द्वारा अपदस्थ भी किया जा सकता है। बैंक के सचालक मण्डल में केन्द्रीय बैंक पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर सकता है। प्रस्तावित नियमों का उल्लंघन करने पर केन्द्रीय बैंक सम्बन्धित बैंक को उचित दण्ड भी दे सकता है।

5. अन्य व्यवस्थाएँ (Other provisions) : (1) बैंको के सचालकों को तथा उन सस्थाओं को जिनमें इन सचालकों का हित निहित हो किसी भी प्रकार के ऋण तथा अग्रिम देने पर कानूनी प्रतिबन्ध है। ऐसे वर्तमान ऋण वरारों को इस कानून के लागू होने के 1 वर्ष की अवधि में अर्थात् फरवरी 1970 तक वसूल (liquidate) किया जायगा।

(11) आवश्यकता पडने पर किसी बैंक को सरकार अपने नियन्त्रण में ले सकती है परन्तु ऐसी परिस्थिति में बैंक को मुआवजा देने की व्यवस्था है।

बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण सम्बन्धी प्रगति (Progress of Social Control on Banks)

यद्यपि सामाजिक नियन्त्रण सम्बन्धी कानून 1 फरवरी 1969 से लागू किया गया है पर यह कार्य वास्तव में 1967 से ही शुरू हो गया जबकि इस सम्बन्ध का बिल सदन के समक्ष रखा गया था। 1968 में हुई राष्ट्रीय साख परिषद की दो बैठकों में विभिन्न क्षेत्रों की साख मांग का अनुमान लगाया गया एवं व्यापारिक बैंको द्वारा प्राथमिक क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। इनमें मिली सफलता की जाच के लिये रिजर्व बैंक ने एक विशेष जाच समिति (Special Review Committee) नियुक्त की जिसने बताया कि सामाजिक नियन्त्रण काफी सफल रहा है। यह कहना उपयुक्त ही है कि :

"The banks have structured themselves to the new pattern of social control with such a facile grace that most of the goals set for them will be reached long before the appointed time"

मुद्रा तथा बैंकिंग

(1) राष्ट्रीय साख पर परिपद ने जुलाई 1968 से जून 1969 तक के लिये व्यापारिक बैंको द्वारा कृषि और छोटे उद्योगों को दिये जाने वाले अनिरीक्त ऋण का लक्ष्य क्रमशः 35 करोड़ तथा 60-70 करोड़ रुपये का रखा था। परन्तु मार्च 1969 को समाप्त होने वाले नौ महीनों में ही 20 प्रमुख व्यापारिक बैंकों द्वारा अतिरिक्त साख सीमा 190 करोड़ रुपये के लगभग कृषि के लिये तथा 106 करोड़ रुपये के लगभग छोटे उद्योगों के लिये मंजूर कर दी गयी है जिससे लगता है कि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति आसानी से हो जायगी।¹ अत्र व्यापारिक बैंकों की ऋण नीति का आधार "किस पर ऋण" (What You Lend against) की जगह किम लिये ऋण' (What you are Lending for) बन रहा है ताकि प्राथमिक क्षेत्रों को साख-सुविधा आसानी से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध की जा सके।

(2) व्यापारिक बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधाओं को पहुँचाने के लिये शाखा विस्तार कार्य का भी अपनाया है। 1968 में उनके द्वारा कुल 675 शाखाएँ खोली गयीं (जिनमें से 488 अर्द्ध-शहरी व ग्रामीण केन्द्रों में और उनमें से भी 364 के लगभग ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पहले कोई बैंक शाखा नहीं थी) जब कि 1967 में कुल 405 तथा 1966 में 479 शाखाएँ खोली गयीं थीं।² यह ध्यान रहे कि राष्ट्रीय साख परिपद की मार्च 1969 में हुयी बैठक में यह निश्चय किया गया कि 1970 तक उन सभी क्षेत्रों में जो जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 10000 से अधिक की आबादी वाले क्षेत्र हैं, किसी व्यापारिक बैंक की शाखा हानी चाहिए। व्यापारिक बैंक न रिजर्व बैंक को आश्वासन दे दिया है कि यह लक्ष्य निर्धारित समय तक पूरा कर लिया जायगा।

(3) संचालकों और उनसे सम्बन्धित सस्थाओं को दिये गये ऋणों के लिये जो नियम बनाया गया है उसमें भी सफलता मिली है। 16 प्रमुख भारतीय बैंकों के 1968 के दिसम्बर के अन्त तक क आकड़ों को देखने से पता चलता है कि इस तरह के ऋणों का प्रतिशत 10.1 की जगह 3.1 रह गया है। (यान यह ऋण राशि 224 करोड़ रुपये से घटकर 78 करोड़ रुपये हो गई है) आशा है 1970 तक ये ऋण पूर्णतया समाप्त कर दिये जा सकेंगे।

(4) बैंकों के संचालक मंडलों के पुनर्गठन का कार्य भी काफी सम्पन्न हुआ है। वे सभी बैंक जिनकी जमा 25 करोड़ रुपये से ऊपर है इस कार्य को नये कानून लागू होने से पूर्व ही कर चुके हैं। 13 विदेशी बैंकों ने सलाहकार बोर्डों का गठन कर दिया। इस प्रकार बैंकों की कुल जमा रकम का 90 प्रतिशत में भी

¹ Commerce May 3 1969 के आधार पर

² Bank of India, Bulletin, May 1969 के आधार पर

कुछ अधिक रखने वाले बैंको ने पुनर्गठन कार्य पूरा कर लिया है। जिन बैंकों की जमा रकम 10 से 25 करोड़ रुपये की है वे भी इस काम को करने लगे हैं और जो समयावधि (तीन साल की) दी गयी है इसमें पूरा कर लेंगे।

उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि सामाजिक नियन्त्रण का प्रारम्भ अच्छा हुआ है। इसी प्रकार प्रगति होती रही तो हमारा सामाजिक नियन्त्रण का उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा।

सामाजिक नियन्त्रण की आलोचना (Criticism of Social Control)

कुछ व्यक्तियों ने सामाजिक नियन्त्रण व्यवस्था से निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति होने के सम्बन्ध में शका व्यक्त की है और इसलिये कुछ आलोचनायें भी की गयी हैं जिनमें से निम्न मुख्य हैं —

(1) विभिन्न क्षेत्रों के जुड़े हुए व्यक्तियों की बैंको के संचालक मंडल में नियुक्ति होने मात्र से ही बैंको की कार्य-विधि में आधारभूत परिवर्तन नहीं लाया जा सकता।

(2) सामाजिक नियन्त्रण योजना से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसमें ग्रामीण महाजनो—साहूकारों को किस ढंग से नियन्त्रण में लाया जाएगा। ये ग्रामीण वित्त के महत्वपूर्ण अंग हैं और अपने कार्यों से मुद्रा बाजार को प्रभावित करते हैं। इन्हें आयाजनों के क्षेत्र से बाहर रखकर कुशल साख आयोजन की पद्धति कैसे चालू रखी जा सकती है ?

(3) बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण साख आयोजन की ओर झूरा और आशिक कदम है। "सामाजिक नियन्त्रण को उन तमाम वित्तीय एवं गैर वित्तीय संस्थाओं पर लागू करने की आवश्यकता है जो आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों को पनपान करवाती हैं और अस्वाभाविक प्रवृत्तियों का जन्म देती तथा बढ़ाती हैं।"²

(4) कुछ लोगों के अनुसार राष्ट्रीय साख परिषद का गठन भी अनावश्यक रूप से किया गया है क्योंकि इसके सारे कार्य तो रिजर्व बैंक के द्वारा भी किये जा सकते हैं।

(5) कुछ लोगों के अनुसार सामाजिक नियन्त्रण वास्तव में राज्य नियन्त्रण ही है और यह औद्योगिक विकास के लिये घातक सिद्ध होगा क्योंकि इससे शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता बैंको में नहीं रहेगी। सामाजिक नियन्त्रण को पिछले दरवाजे से राष्ट्रीयकरण करना भी बतलाया गया है।

². पुरुषोत्तम पाण्डेय 'बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण सफल कैसे हो' योजना 21 अप्रैल 1968 p. 26

(6) इस योजना में बड़े और मध्यम स्तर के उद्योगों का अल्पमत में प्रतिनिधित्व दिया गया है; साथ वितरण सम्बन्धी जो असन्तुलन अब तक रहा है उसका इस प्रकार निवारण, दूसरा पलड़ा (कृषि सहकारिता, छोटे उद्योग आदि) मारी कर देने से नहीं होगा ।

सामाजिक नियन्त्रण से सम्भावित लाभ व इसको सफल बनाने वाले मुख्य तत्त्व :

कुल मिलाकर बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण योजना का स्वागत किया गया है । यह आशा व्यक्त की गयी है कि व्यापारिक बैंको सम्बन्धी कमियों का इससे निवारण हो सकेगा । तथा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों की साथ सम्बन्धी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा । लघु उद्योग, कृषि क्षेत्र व नये उद्योगों को अधिक साख प्राप्त होगी; ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधायें बढ़ेंगी, निर्यात व्यापार प्रोत्साहित होगा तथा देश के असन्तुलित विकास को सुधारने में सुविधा होगी । यह कल्पित स्वप्न वास्तविकता में तभी परिणित हो सकेगा जब की यह योजना सफलता पूर्वक चले । इस योजना की सफलता दो बातों पर निर्भर करती है — प्रथम तो यह कि राष्ट्रीय साख परिपद तथा बैंको के संचालक मण्डलों में विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि सही प्रकार से निदेशन कार्य करे । यदि कृषि, सहकारिता और छोटे उद्योगों के प्रतिनिधित्व के नाम पर राजनैतिक लोग परिपद व मण्डलों में प्रवेश पा जाते हैं तो कार्य सुचारु रूप से नहीं चल सकगा । द्वितीय केन्द्रीय बैंक को जो नियन्त्रण सम्बन्धी अतिरिक्त अधिकार दिये गये हैं उनका सही रूप में पालन हो ।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी-बंगलौर अधिवेशन जुलाई 1969 में फिर राष्ट्रीयकरण की मांग ।

जुलाई 1969 में बंगलौर में हुए A. I. C. C के अधिवेशन में प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के आर्थिक नीति विषयक नोट¹ में बैंको का राष्ट्रीयकरण करने का सुझाव दिये गया है । उसमें कहा गया है : "There is great feeling in the country regarding the nationalisation of Private Commercial banks . Either we can consider the nationalisation of the top five or six banks or issue directions that the resources of banks should be reserved to a larger extent for public purposes." साथ ही व्यापारिक बैंको द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग (13 जून 1969 को 24.57 प्रतिशत) को 5 प्रतिशत बढ़ाने का सुझाव दिया गया है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 200 करोड़ रुपये उपलब्ध हो सकेंगे । श्री० मोरारजी देसाई ने अपने

¹ Text of P. M.'s note on Bank Nationalisation . Times of India July 11, 1969

मापण में सामाजिक नियन्त्रण का पक्ष लिया है। श्री चव्हाण ने राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हुए कहा है कि "Social Control without nationalisation is not possible just as nationalisation without Social Control is the greatest fraud"

14 बड़े अनुसूचित बैंको का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of 14 Big Scheduled Banks)

बैंगलौर कांग्रेस महासमिति अधिवेशन में पारित आर्थिक नीति विषयक प्रस्ताव के अनुरूप भारत सरकार ने 19 जुलाई, 1969 को एक अध्यादेश जारी कर 14 बड़े अनुसूचित बैंको का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जिन बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया है उनके नाम हैं—सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया, बैंक ऑफ इन्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कनारा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इन्डिया, देना बैंक सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया, इलाहाबाद बैंक, इन्डियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा इन्डियन ओवरसीज बैंक। 50 करोड़ से अधिक जमा वाले बैंको का ही राष्ट्रीयकरण किया गया है। देश के बैंको में जमा धन का कुल 75 प्रतिशत राष्ट्रीयकरण के अन्तर्गत आ जायेगा। अधिकृत घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय प्राथमिकताओं व लक्ष्यों के अनुकूल अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक का आवश्यक स्वरूप नये निगम के रूप में रखा जायगा। प्रत्येक ऐसे नये निगम की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति करेगा, उसे कस्टोडियन (Custodian) कहा जायगा और वह नये बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। बैंको के अध्यक्षों को ही उनका कस्टोडियन नियुक्त किया गया है।

प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बैंको के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में 19 जुलाई 1969 को अपने रेडियो भाषण में कहा कि बैंको के राष्ट्रीयकरण से सट्टे तथा अनुत्पादक कार्यों के लिए दिए जाने वाले ऋणों पर रोक लगेगी और देश की योजनाओं को क्रियान्वित करने तथा तीव्र गति से आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी।

अधिकांश राजनीतिक दलों तथा श्रमिक सघों और बैंक कर्मचारी सघों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है।

बैंकिंग आयोग (Banking Commission)

"The banking system is at present in the throes of momentous changes. In the years to come it will have to make even more rapid strides both functionally and in terms of geographical coverage with a view to mobilising deposits from all parts of the country and directing the flow of credit to all needy regions and needy sectors. It is hoped that the Banking Commission will evolve appropriate guidelines for the long term development of the banking system in the context of the objectives and requirements of planned economic growth."

बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण की योजना के अन्तर्गत बैंको की कार्य प्रणाली में दीर्घगामी परिवर्तन किए गए जिन्होंने बैंक देश के आर्थिक विकास के उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। इस सन्दर्भ में यह प्रश्न उठा महत्वपूर्ण है कि बैंक व्यवस्था का वर्तमान संगठन तथा ढांचा बैंको के नये सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए बड़ा तक उपयुक्त है। इसीलिए दिसम्बर 1957 में बैंकिंग अधिनियम (मशौघन) अधिनियम को लोक सभा में प्रस्तुत करते हुए उप-प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने बैंकिंग उद्योग के विकास में सम्बन्धित समस्या का अध्ययन करने के लिए एक बैंकिंग आयोग (Banking Commission) की स्थापना का आश्वासन दिया था। उसी के फलस्वरूप जनवरी 1969 में सरकार ने आयोग की नियुक्ति घोषणा की। आयोग ने 1 मार्च 1969 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

आयोग के सदस्य (Composition of the Commission) : आयोग के अध्यक्ष श्री आर. जी. सरैया (R. G. Saraiya) हैं जो प्रतिष्ठित व्यापारी तथा सहकारी बँकर हैं। आयोग के अन्य सदस्य हैं :

श्री एन रामानन्द राव, प्रबन्ध सचालक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
श्री एन. मावतौपदत्त, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, तथा

श्री बी. जी. पेन्डरकर, प्रमुख सलाहकार, रिजर्व बैंक

आयोग का अध्ययन क्षेत्र (Commission's Terms of Reference) के लिए निर्धारित अन्वयन क्षेत्र बड़ा विशद तथा विस्तृत है आयोग विशेष

रूप से बैंको के आकार, कार्य-प्रणाली के क्षेत्र तथा फंडिंग को दृष्टिगत रखते हुये व्यापारिक बैंक व्यवस्था के वर्तमान ढाँचे की विस्तृत जांच करेगा, व्यापारिक बैंकों के भौगोलिक तथा कार्यात्मक क्षेत्र के विस्तार के लिए सिफारिश करेगा तथा बैंको की कार्य सम्बन्धी रीतियों तथा तरीकों में सुधार करने तथा उन्हें आधुनिक बनाने के लिए मुझाव देगा।¹ आयोग सहकारी बैंकों की शिखाओं का सर्वेक्षण करेगा और व्यापारिक तथा सहकारी बैंको के सम्बन्धित विषयों के लिए सुझाव देगा। उसके साथ-साथ आयोग विभिन्न प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं तथा स्वदेशी बैंको का भी अध्ययन करेगा तथा उनके व्यवस्थित विकास के उपाय सुझायेगा। इस प्रकार आयोग "अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों तथा पक्षों की मूल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देश के लिए एक विस्तृत तथा एकीकृत वित्तीय ढाँचे का मुझाव देगा।"²

आयोग के समस्त विचारणीय प्रश्न (Issues before the Commission), जैसे तो बैंकिंग आयोग की नियुक्ति की मांग बार-बार होती रही है परन्तु इसकी नियुक्ति पिछले आयोग के 40 वर्ष व्यतीत होने के बाद हुई। भारतीय बैंक व्यवस्था के समस्त महत्वपूर्ण समस्याएँ हैं और देश के आर्थिक विकास में बैंको के योगदान को प्रभावी बनाने के लिए उनका समाधान आवश्यक है। अतः बैंकिंग आयोग को मुख्य रूप से निम्नलिखित समस्याओं तथा प्रश्नों पर विचार कर अपने सुझाव देने होंगे :

(1) बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण की नीति का मूल्यांकन [Objective assessment of the policy of social control over banks] : आयोग बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण की योजना की प्रगति का मूल्यांकन करेगा। Professionalisation of banking constitutes the core of social control और उस उद्देश्य के प्राप्ति में सामाजिक नियन्त्रण की सफलता सदिग्ध है।

¹ Commission's terms of reference include "a comprehensive enquiry into the existing structure of the commercial banking system, having particular regard to size, dispersion and area of operation, the making of recommendations for extending the geographical and functional coverage of commercial banks as well as suggestions for improving and modernising their operating methods and procedures."

² Thus, the commission is to suggest a comprehensive and integrated financial structure for the entire country, keeping in view the requirements of the different regions and different sectors of the economy,

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विकास (Extension of Rural Banking) आयोग ग्रामीण क्षत्र में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार की प्रगति तथा उसमें सुधार के सुभाव देगा।

(3) बैंक व्यवस्था पुनर्गठन तथा विलय आन्दोलन (Structural Reorganisation of Banking system and Merger Movement) - इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैंक व्यवस्था के संगठन तथा ढांचे में परिवर्तन के प्रश्न पर भी विचार होगा। इस सम्बन्ध में द्वि-बैंकिंग व्यवस्था (Dual System of Banking) तथा क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (Area Development Approach) इत्यादि सुभावा पर विचार करेगा। बैंकिंग के ढांचे के पुनर्गठन के प्रश्न भी जुड़ा हुआ है।

(4) साख का वितरण (Diversification of Credit) बैंको व विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों तथा कार्यों की दृष्टि में साख के वितरण का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। कृषि उद्योग तथा निर्यात के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को साप्यप्त मात्रा में किस प्रकार उपलब्ध हो जिससे देश का आर्थिक विकास तत्ती साध्य हो सक। बैंक इन दिशा में अधिक लागती तथा नई जोलिमों का सामना करे कर, आदि प्रश्नों पर आयोग विचार करेगा।

उपयुक्त प्रश्नों के अतिरिक्त आयोग बैंक व्यवस्था से सम्बन्धित अनेक पक्षों पर विचार करेगा जैसे निक्षेप प्राप्ति (Deposit Mobilisation), शाखा विस्तार (Branch Expansion), सेवाओं में सुधार तथा नवीनीकरण (Improvement and innovation in Services) अथ सम्बन्ध (Staff Management Relation) बैंक तथा रिजर्व बैंक का सम्बन्ध (Appropriate Relationship between Banks and RBI), मौद्रिक नीति का क्रिया-व्ययन, मुद्रा बाजार का एकीकरण इत्यादि।

आशा है कि आयोग उपयुक्त सभी प्रश्नों का विशद् विवेचन कर बैंक व्यवस्था को अधिक सुदृढ करने तथा आर्थिक विकास में बैंक के योगदान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुभाव देगा। आयोग अपना प्रतिवेदन दिसम्बर 1970 तक पेश करेगा।